



# भारत में राजनीति

रजनी कोठारी

सटर फार द स्टडी

प्राफ डेवेलपिंग सासाइटीज

अनुवादक

अशोकजी

(संपादक स्वातंत्र्य भारत नखनऊ)



ओरिएण्ट लॉगमैन

## ओरिएण्ट लाँगमैन लिमिटेड

रजिस्टर्ड कार्यालय ३/१, आसफ अली रोड, नयी दिल्ली १

१७, चित्तरजन एवेन्यू, कलकत्ता १३

निकल रोड बैलाड एस्टेट, बम्बई १

३६ ए मारुण्ट राड मद्रास २

बी २/७ आसफ अली रोड, नयी दिल्ली १

## भारत में मुद्रित

मुजित पटवर्धन, सगम प्रेस लि, १७ काथल्ट पूना २६

द्वारा मुद्रित ओर बा हू पटवर्धन मनेजर ओरिएण्ट लाँगमैन लि

बी ३/७, आसफ अली राड नयी दिल्ली १ द्वारा प्रकाशित

रावजी भाई सी पटेल को  
प्रेरणा के स्रोत और आलोचक



# भारतीय राजनीति

मूल अंग्रेजी पुस्तक इण्डियन पॉलिटिक्स सन १९६८-६९ में लिखी गई थी। तब से भारतीय राजनीति में बहुत से नये अनुभव हुए हैं। इन अनुभवों से अधिकतर इस पुस्तक की सामान्य स्थापनाओं की पुष्टि ही हुई, जैसे राजनीति की स्वतंत्र सत्ता, भारतीय समाज में परिवर्तन लाने में शासन की सत्रिय भूमिका, भारतीय राजनीति की अपनी अलग शैली, जो पश्चिमी ढांचे के वगहिता के समुच्चयीकरण और आर्थिक शक्तियों की सावभौमता के मार्क्सवादी ढांचे, दोनों से भिन्न है, इसके सांस्थानिक विश्लेषण की जिसमें एक दल की प्रधानता को मुख्य स्थान है, देश में आनेवाले सकटों की चुनौती से राजनीति और शासन की कार्यप्रणाली में होने वाले बड़े परिवर्तन, लोकतांत्रिक पद्धति और राज्य की मुख्य नीतियों की सफलता के बारे में आशावादी दृष्टिकोण। यह ही पुस्तक की मुख्य स्थापनाएँ हैं।

भारत में इधर जो घटनाएँ हुई हैं इनसे भारतीय राजनीति की ये म्यायी विशेषताएँ और उदमासित हुई हैं। यदि १९६७ के आम चुनाव से इन विशेषताओं के बारे में कुछ नकाएँ उत्पन्न भी हुई थी, तो इन नई घटनाओं से उनका निराकरण हुआ है। इस पुस्तक में देश की व्यवस्था के जिन बुनियादी तत्वों का निरूपण किया गया था उनको बल मिला है, देश में आत्मविश्वास बढ़ा है तथा आगे जो काम करना है उनके प्रति अधिक चेतना और जिम्मेदारी का भाव आया है। यह भी ध्यान देने की बात है कि हाल में देश के नेतृत्व और नीतियों में जो परिवर्तन हुआ है वह कांग्रेस के प्रभाव में कमी होने से नहीं बल्कि उसकी अपने रंग ढंग को बदलने की क्षमता के कारण हुआ है, जिस पर इस पुस्तक में काफी विस्तार से विचार किया गया है।

साथ ही इन नयी घटनाओं के कारण इस पुस्तक में जिन बातों पर जोर दिया गया था और जो व्याख्याएँ की गई थी, उन में थोड़ा संशोधन भी करना पड़ेगा। जैसे कांग्रेस दल में जो सकट १९६८ में शुरू हुआ और १९७२ में समाप्त हुआ, उस से १९६२ में चीन के आक्रमण और नेहरू के दहात के बाद लोकतांत्रिक

पद्धति में जो सिपिलता आ गई थी, वह और भी उजागर हो जाती है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि पूरा एक दायें तब देना एक सहजिये के रूप में काम नहीं कर रहा था, यद्यपि इसी अवधि में गेती में कुछ बड़ी उपलब्धियाँ हुईं, देश की सुरक्षा-व्यवस्था मजबूत हुई और भाषा-समस्या के समाधान में प्रगति हुई। इस पुस्तक के दो और विरलेपणा में भी संशोधन आवश्यक है। एक नेहरू और सात महादुर शास्त्री के उत्तराधिकारी के चुनाव और दूसरे १९६३ में पामराज योजना के बाद उदित प्रादेशिक नताजा के गुट या समूह के बारे में। अब यह स्पष्ट हो गया है कि यद्यपि दोनों बार नए नेता के मुख्यवर्तित्व के तब चुनाव से यह घना दूर हो गई कि नेहरू के बाद क्या होगा, किंतु जिस प्रकार सहमति की प्रक्रिया द्वारा य दोनों चुनाव हुए उनसे सर्वोच्च स्तर पर सत्ता के लिए ऐसा तब छिन्न गया, जिससे केंद्रीय मत्ता की अस्थिरता और दुर्गलता का एक सन्धा दौर भी गुरु हो गया। इसका अंत तभी हुआ जब इन्दिरा गांधी ने तब और सफ्ट मोल ले कर केन्द्र और काग्रस के शासन पण की प्रधानता को पुनः स्थापित किया।

इस दोहरी प्रक्रिया में भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में नाटकीय परिवर्तन आया और यह प्रकट हो गया कि देश की आंतरिक शक्ति का उसकी बाहरी या अन्तर्राष्ट्रीय क्षमता से बिना घना समर्थ है। इस पुस्तक के दसवें अध्याय में इस तबध का विश्लेषण किया गया है किंतु इस में कुछ कमो और अस्पष्टता रह गई है। अब से भारत के नेता लगातार ऐसी नीतियों के निर्धारण में लगे रहेंगे जिस से देश की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे, वह नई चुनौतियाँ का सामना कर सके और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका अदा कर सके।

अंत में यह प्रश्न है कि व्यवस्था किस प्रकार काम करती है। इस विषय पर काफी विस्तार से (अध्याय ८ से ११) विचार किया गया है। वस्तुतः इसमें मुख्य बात यही है कि राजनीतिक प्रक्रिया के सफल सत्पानीकरण और सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में इसकी अपवाहृत विफलता के कारण एक विराघामास या जतर पण हो गया है और यह समस्या अब बहुत तीव्र हो उठी है। देश के सामने जो विकट समस्याएँ उपस्थित हुई हैं उनमें सुलझा सने में भारत की लोकतंत्री व्यवस्था कहा तक सफल होती है इसी पर इस व्यवस्था का और देश का भविष्य निर्भर है। मूल पुस्तक का यही मुख्य सदेश और स्थापना थी, परन्तु अब इसने ऐसा निश्चित रूप ग्रहण कर लिया है, जो पुस्तक के अंतिम अध्याय में निरूपित निष्कर्षों से आगे चला जाता है।

परन्तु पुस्तक की मुख्य स्थापना अभी भी कायम है और पिछली घटनाओं से उसकी और पुष्टि हुई है। स्थापना यह है कि राज्य और राष्ट्र के निर्माण का जो लोकतंत्री ढांचा भारत ने निश्चित किया है वह सफल हो सकता है और इतिहास में एक उदाहरण कायम कर सकता है, याने भारत के नेतृत्व ने जिस

पद्धति का स्वयं निर्माण किया है, उसकी वास्तविक गतिशील प्रकृति को वह समझे और उसी के अनुसार कार्य करे। सन १९६६ में जब मूल अंग्रेजी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, उसके मुकाबल आज सन १९७२ में जब इसका हिंदी संस्करण निकल रहा है दश इस परीक्षा में सफल होने की कहीं अच्छी स्थिति में है। इसी प्रकार यदि यह विफल हुआ तो हम से ऐसी प्रवृत्तियाँ का जन्म होगा, जिनको सभालना कठिन होगा। इस सीमा तक इस पुस्तक में कुछ प्रश्नों पर जो सदिग्ध रख लिया गया था, उसकी वजाय भारत में लोकतन्त्र की परिणति या फलश्रुति को और स्पष्टता से समझना पड़ेगा।

इस पुस्तक के अंग्रेजी संस्करण की जितनी जाँच-काँच ने ध्यानपूर्वक समीक्षा की है, सावजनिक और विद्या जगत् के जिन लोगों ने उपयोगी विचार प्रकट किए हैं और राजनीतिशास्त्र तथा अन्य विषयों के अध्यापकों ने इस कठिन पुस्तक का, जो पाठ्यक्रम में लगाने के लिए नहीं लिखी गई थी, अध्यापन में जो उपयोग किया है उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। इन्हीं अध्यापकों मित्रों के प्रोत्साहन से इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद हो सका है। इस अनुवाद की व्यवस्था कराने में आरिण्ट लॉन्गमैन् के श्री बा. ह. पटवर्धन ने विशेष रुचि ली है और मेरे सहयोगी डा. रामाश्रय राय ने इसको ध्यान से देखा है, जिस से अनुवाद मूल के अनुरूप हो सके, मैं इन दोनों मित्रों का आभारी हूँ।

रजनी कोठारी





---

## अनुक्रम

---

अध्याय	पृष्ठांक
१ सैद्धान्तिक विवेचन	१
२ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	१७
३ आधुनिकता की ओर	५८
४ समस्या-निर्माण	७४
५ पार्टीप्रणाली और गठजोड़	१०८
६ सामाजिक ढांचा	१५३
७ राजनतिक संस्कार और सामाजिककरण	१७१
८ राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण और राष्ट्रीय एकता	२००
९ विकास की राजनीतिमूलक अर्थनीति	२३०
१० अंतरराष्ट्रीय स्थिति	२५५
११ भविष्य	२७८



## सैद्धान्तिक विवेचन

यदि आधुनिकीकरण हमारे युग की मुख्य प्रवृत्ति है, तो राजनैतिकीकरण इसकी संचालक शक्ति है, और इस शक्ति पर मनुष्य अभी अधिकार नहीं कर पाया है, क्योंकि एक हदतक वह अभी भी दक्खानसी विचारा से अपना पल्ला नहीं छुड़ा सका है। १७ और १८ वीं शताब्दी में मनुष्य के सामने मुख्य चुनौतियाँ थी, प्रकृति की शक्तियाँ पर अधिकार और नैतिक कट्टरता की ओर १९ वीं शताब्दी में जनसंख्या के और आर्थिक प्रवृत्तियों के नियंत्रण की। हमारे समय में मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है सरकार और राजनीति के फैलते हुए क्षेत्र की। राजनीति की कला और विज्ञान पर अधिकार के द्वारा ही मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। यह समस्या राजनीति या समाजशास्त्रियों की ही नहीं, सब श्रेणी के नेताओं और जनमत के निर्माताओं की भी है।

राजनीति की प्रक्रिया का सबंध अनेक वर्गों और संगठनों से है—राजनैतिक दल और चुनाव तंत्र, जनमत के विविध माध्यम (प्रेस, रेडिओ आदि), गैर सांप्रदायिक और सांप्रदायिक विभिन्न हिता के संगठन, बुद्धिजीवियों तथा सफेदपंशा व्यवसायों और सरकारी नौकरों का बढ़ता हुआ वर्ग। आधुनिकता की प्रक्रिया से ये सब वर्ग प्रभावित होते हैं, और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, आकांक्षा और अवसर में जो अंतर है उसका ये अनुभव करते हैं, व्यवस्था से इस आकांक्षाओं की पूर्ति की मांग करते हैं और इस प्रकार उसकी क्षमता और कुशलता की परीक्षा करते हैं।

### राजनैतिक विकास का सदर्भ

नये राष्ट्रों का पद पाने वाली पुरानी सभ्यताओं के विकास या परिवर्तन की प्रक्रिया बड़ी व्यापक, दूरगामी और विषम है। सामाजिक परंपरा और परिवर्तन जय उग्रवादिता में विरोधाभास से हम अनस्थिर स्थिति में स्थिरता का भ्रम नहीं करना चाहिए। मूल बात सामाजिक पुरानी रीति-नीति नहीं बल्कि परिवर्तन की विचारधारा का प्रभाव है। समाज का पुराना ढाँचा, जाति और कबीले की व्यवस्था

थोड़े समय के लिए उपयोगी हो सकती है (भारत में वे हैं भी) परन्तु अंत में उनको परिवर्तन की शक्तियों के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। जिन नए विचारों, सिद्धांतों और नयी समस्याओं को नए राष्ट्र में विधान के द्वारा स्थापित किया गया है, उनके फलितार्थ को स्पष्ट रूप से समझना और स्वीकारना होगा। सोद्देश्य परिवर्तन की योजना बनाने वालों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है क्या उन्हें इनके लिए समय मिलेगा? राजनैतिक और आर्थिक विनाश का बाध एन दिा का नश है। इसमें समय लगता है और आवश्यक नहीं कि यह सीधे रास्ते पर चले और उत्तरोत्तर बढ़ना चने। दूसरी ओर नये मूल्यों और आभाशाभा का प्रसार एक बार शुरू होने पर बड़ी तेजी से होता है और उस पर बाहरी बाधा का प्रभाव पड़ता है। इस कारण आधुनिकीकरण करने वाले सब नये राष्ट्रा के सामने स्थिरता और जन समर्थन की समस्या खड़ी होती है। वही अस्थिरता और उथल-भुथल अधिक होती है वही कम।<sup>१</sup>

स्थिरता या अस्थिरता इस पर निर्भर होती है कि राज्यत्रय या व्यवस्था को क्या काम करना है और समाज की विभिन्न उपव्यवस्थाओं या वर्गों से उसका क्या संबंध रहता है। मुख्यतः दो प्रकार की व्यवस्थाएँ हो सकती हैं—एक अतिकेन्द्रित, जिसमें सारे अधिकार केन्द्रीय नेतृत्व के हाथ में रहते हैं, दूसरी अनेकार्थक और साझेदारी वाली जिसमें अधिकार बँटे रहते हैं और मध्यम व निचले स्तर के नेताओं को भी अधिकार में भाग मिलता है। पर अपन गृद्ध रूप में दोनों व्यवस्थाएँ क्या नहीं पायी जाती।

मुख्य समस्या यह है कि भारत जैसी अपेक्षाकृत सुली राजनैतिक व्यवस्थाओं को ऐसे काम उठाने पड़ते हैं, जिनसे 'उन्नत' राज्यव्यवस्थाएँ भी हिचकिचाती हैं, जबकि इनके पास वे आर्थिक, प्रौद्योगिक और प्रशासनिक साधन नहीं हैं जो उन्नत देशों के पास होते हैं। गैर पश्चिमी राष्ट्रा ने पश्चिमी राष्ट्रा के आदर्शों और सामाजिक आकांक्षाओं को अपना लिया है, लेकिन पश्चिमी राष्ट्रा की तरह इनका पहले अपनी राजनैतिक व्यवस्था को जमा लेने और आर्थिक और बौद्धिक साधना का निर्माण कर लेने का समय नहीं मिला। इस दृष्टि से ससार के सिमटने से इन देशों को कठिनाई हुई है, क्योंकि उन्नत देशों के संपर्क के कारण उनको इनकी सामाजिक, राजनैतिक विचार सरणियाँ अपनानी पड़ी हैं, जबकि उसी के अनुसार स्थिर और सुसंगत परिवर्तन के लिए भौतिक और संस्थागत साधन इनके पास नहीं हैं।

भारत में इस समस्या को स्पष्टतः देखा जा सकता है। यहाँ इतिहास के लंबे क्रम में ऐसे सामाजिक, धार्मिक आंदोलन हुए, जिनसे एक विशिष्ट भारतीय परंपरा

१ यहाँ उम अस्थिरता या उथल-भुथल का अर्थ है जो आकांक्षाओं का पूर्ति न होने से पैदा होती है परिवर्तन के विरोध या उत्कर्ष प्रतिक्रिया से नहीं। यद्यपि ये दोनों ही बातें साथ साथ भी चल सकती हैं।

का निर्माण हुआ, जिसने यहाँ फूट और पृथाना की अतर्निहित प्रवृत्तियाँ पर अंकुश रखा। राजनैतिक स्थिरता की जुजी सामाजिक व्यवस्था थी। अब यह सामाजिक व्यवस्था विगड़ित हो रही है और बदल रही है। नेतृत्व के सामने यह समस्या है कि यदि टूटती हुई सामाजिक संस्थाओं की जगह नयी संस्थाएँ नहीं स्थापित की गयीं, नए व्यवस्था नहीं प्रस्तुत किये गये और नयी मायताओं और मूल्यों की स्थापना नहीं की गयी तो राजनैतिक विकास के अवरोध होने के साथ-साथ राजनैतिक व्यवस्था के टूटने की नींव का पक्की है। इस स्थिति में प्रशासन तंत्र और नई संस्थाओं के निर्माण की ओर ध्यान देना फटिन हा जाता है और इनके बिना व्यवस्था का टिकना ठठिन हो जाता है।

भारत जस उन्नततम राष्ट्र के राजनीति विरासत का अर्थ यह होता है कि एक प्राचीन देश अपनी पुरानी परंपराओं और विविधता को बनाये रखत हुए, आधुनिक युग की सब से अच्छी बातों का ग्रहण करने की राशिग करता है। इस प्रकार भारत ने आधुनिक युग से लोकतंत्र के आदर्श का ग्रहण किया है और इसके त्रिएस्थानीय स्तर में लेकर राष्ट्रीय स्तर तक मस्याएँ म्यापित की हैं तथा पिछले २५ देशों का सब इसका मेल अपनी पुरानी परंपरा से बिठाने का यत्न कर रहा है। स्मरण राष्ट्र के महान नेताओं की पहली पीढ़ी अब समाप्त हो चुकी है और नयी पीढ़ी का उनसे विरासत में एक आर अगर काफी मुदद राज्यतंत्र और स्वीष्टा लक्ष्य व आदर्श मिले हैं, तो दूसरी ओर न तो उसे मानूम है कि आवश्यक समस्याओं का मुलज्ञाने के लिए इस राज्यतंत्र का उपयोग किम प्रकार किया जाए न ही उन में इतनी शक्ति है। इस नए नेतृत्व में माओ या स्टालिन जैसी सक्षम की दृढ़ता और क्रूरता से आगे बढ़ने की ताकत नहीं है, दूसरी ओर उसे बुद्धिवादी विचारधारा में अभी पूरी आस्था नहीं हुई है न वह निश्चय कर पाया है कि भारत का राजनीतिक लक्ष्य क्या हो, जिसमें सबका भला हो। भारतीय समाज का स्वरूप भी अभी तक गैर राजनीतिक है। इस स्थिति में यह नेतृत्व आंतरिक और वैदेशिक समस्याओं को सास्थानिक कुशलता और विवेचित राजनैतिक व्यवस्थाजय अनुभवा से ही निपटाने का यत्न करता है।

भारत में राजनीति, मुख्यतः देश की एकता का बनाये रखने की राजनीति है। यह स्वीकारा जाता है कि देश के विकास का काम जरूरी है मगर देश की एकता से ज्यादा जरूरी नहीं। किसी भी परिवर्तन को इस दृष्टि से देखा जाता है कि उससे देश की एकता को बल मिलेगा या नहीं। नतीजा यह है कि विकास के काम में जल्दबाजी या व्यग्रता नहीं की जानी और हर काम में अनिश्चय, असमजस और जहरत से ज्यादा समझौते की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। राजनैतिक दिशाएँ निर्धारित हो चुकी हैं सिर्फ उस ओर धीरे-धीरे बढ़ने के लिए समय की जरूरत है। मगर समय का ही तो अभाव है। समय का मिलना इस पर निर्भर है कि

सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा जनता में अभाव और गरीबी से उत्पन्न होने वाले क्षोभ और लोकतंत्र से उत्पन्न होने वाली आकांक्षा का विस्फोट का कब तक रोक सकेगी। मुख्य कसौटी यह है कि भारत की पुरानी परंपरा का उसकी नयी स्थापित व्यवस्था से कहाँ तक सामंजस्य या मेल हो रहा है। क्या इस प्रकार का सामंजस्य स्थापित होने के पहले ही आधुनिकता के आघात से पुरानी परंपरा ढह न पड़ेगी? क्या वह आर्थिक विकास में दश के सक्षम होने तक बनी रह सकेगा? नये व पुराने का मेल क्या रूप लेगा और क्या वह भविष्य में बाधक रह सकेगा? भारत की नयी राज्यव्यवस्था की कसौटी सामाजिक परंपरा, राजनैतिक शक्ति और आर्थिक परिस्थितियों की परस्पर प्रतिक्रिया से होगी।

### तुलनात्मक दृष्टिकोण

इससे स्पष्ट है कि भारत जैसे वैविध्यपूर्ण और प्राचीन परंतु आधुनिकता से प्रभावित समाज का विश्लेषण करने में अनेक दृष्टिकोणों का प्रयोग आवश्यक है। यह इस लिए और आवश्यक हो जाता है कि विश्लेषक एक पूर्ण सुसंगठित इकाई का विश्लेषण करता है न कि उसके खंडों का। इस विश्लेषण से ऐसे तथ्यगत निष्कर्ष निकटने जा सकते हैं जो समग्र समाज पर लागू होंगे। ऐसे विश्लेषण में एक समस्या यह होती है कि दृश्यमान वास्तविकता को सैद्धांतिक रूप देना तो आवश्यक है परंतु ऐसा करने में यह लाभ होता है कि निरूपित सिद्धांत से तथ्यगत अनुमान किए जायें। ऐसे प्रलोभन से बचने के लिए सैद्धांतिक दृष्टिकोणों का सहारा लेना चाहिए।

हमने भारतीय व्यवस्था के विकास के विवेचन में तुलनात्मक विश्लेषण के वृत्तात्मक संप्रदाय के तरीके से काम लेने के अलावा अन्य कई दृष्टियों से भी विचार किया है—जैसे ढाँचे में परिवर्तन, राजनैतिक तथा सामाजिक संस्कार, और परंपरा की नयी व्याख्या। संस्थानीकरण और राजनैतिक गठबंधन के महत्त्व को दिखाने के लिए हमने केन्द्र और परिधि (अंतरंग और बाहरी) के संबंध की चर्चा की है और व्यवस्था की कसौटी विभिन्न स्तरों पर समस्याओं को सुनिश्चित करने की उसकी क्षमता को माना है। हमने अपने विवेचन में कुछ प्रचलित धारणाओं को भी अलाचना की है। हमने यह दिखाया है कि विकास के क्रम में प्राचीन और आधुनिक में कोई अंतर्विराट नहीं है। हमने इस पर भी शका प्रकट की है कि अमुक प्रकार की राज्यव्यवस्था अमुक प्रकार के समाज और अमुक प्रकार की स्थितियों में ही संभव है। हमने इस धारणा पर भी शका की है कि इस विकासक्रम में दिशाहीनता का संकट भी उत्पन्न हो। हमने इस सिद्धांत से भी असहमति प्रकट की है जो राजनीतिक दलों या मध्यस्थ संस्थाओं को परस्पर असहमत मानता है और इस दृष्टिकोण की श्रुतियों को भी दिखाया है जो यह मानता है कि राजनैतिक प्रक्रिया से सिक

विभिन्न वर्गहितो का समुच्चयन मान होता है। इस प्रकार हमने राजनैतिक विकास के भारतीय प्रयोग को ठीक ढंग से समझने की कोशिश की है। इससे अन्य विकासमान देशों के राजनैतिक विकास को समझने में भी कुछ मदद मिल सकती है।

जब हम किसी समाज के विकास की प्रक्रिया को अपने सामने होते हुए देखते हैं, तो हमें इसे इस समाज के सदस्या की निगाह से, खासकर उन लोगों की निगाह से देखना चाहिए जो इस विकास-प्रक्रिया के संचालक हैं। इसमें हमें दो बातों पर ध्यान देना होगा, जिनकी अक्सर उपेक्षा कर दी जाती है, एक सस्यागत विश्लेषण और दूसरे नेता या अगुआ वर्ग की भूमिका। इस प्रकार भारतीय व्यवस्था का विवेचन करते समय हमें राजनैतिक सस्याजा की मूल सामाजिक और आर्थिक गतिविधियाँ को समाविष्ट करने वाला एक तरह का ढाँचा मान न समझ लेना चाहिए। इसी तरह यह न समझ लेना चाहिए कि नेताओं का काम जनता की माँगों को सरकार तक पहुँचाना और उनकी पूर्ति कराना मात्र है। वास्तव में सारी प्रक्रिया की शुरुआत एक संवैधानिक और राजनैतिक व्यापक ढाँचे की स्थापना से होती है, जो नेताओं के प्रयत्न से समाज के विभिन्न स्तरों में प्रवेश करती है, और तब क्रमशः उसके जवाब में नीचे से नए गठबंधन या व्यूहों की रचना होती है। इस प्रकार अगुआ या नेता और सस्याएँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन के माध्यम से बन जाते हैं और विभिन्न स्तरों पर नयी चेतना का जन्म देते हैं और नयी शक्तियों का मैदान में लाते हैं। वे राष्ट्रीय व्यवस्था के एकीकरण, संगठन और विविधीकरण में सहायक होते हैं। इस स्थिति में राजनीति एक महान् रचनात्मक शक्ति का काम करती है, जो प्रतिनिधित्व की मशीनरी या तंत्र मात्र नहीं होती जो बाहरी दबाव पर कार्य करे और विभिन्न हिता के समुच्चयन का मोका दे।

तुलनात्मक राजनीति के हाल के ग्रंथों में यह माना तो जाता है कि राजनैतिक प्रक्रिया का सामाजिक ढाँचे और मूल्यों को बदलने में बड़ा हाथ होता है, फिर भी पुरानी भ्रांतियाँ बनी रहती हैं। एक भ्रांति का मूल धर्मनिरपेक्षता का वह अस्पष्ट सिद्धांत है जो जातिसस्या का स्वरूप ठीक से समझने में विफल हो कर यह मानता है कि विकास का क्रम अनिवार्यतः सांप्रदायिक से स्वच्छिक संगठन के रूप में परिवर्तन होने में निहित है।

राजनैतिक दलों को शासनप्रक्रिया से वियुक्त कर मात्र प्रतिद्वंद्वी संगठनों के रूप में देखने के कारण इस बात की उपेक्षा कर दी जाती है कि सरकारी व्यवस्था में भी उनका योग रहता है। सत्ताधारी दल केवल वोट जुटाने और चुनाव लड़ने का ही काम नहीं करते बरन् योजना के कार्यन्वयन और अन्य सरकारी गतिविधियों में योग देकर जनता में प्रवेश करने का यत्न करते हैं और जनता को राजनैतिक



प्रक्रिया में भाग लेने को प्रेरित करत है। कुछ लाग ऐसा समझते हैं कि अतिशयित या अल्पगिहित और सामाजिक दृष्टि में (जातिपाति में) बटे हुए देश में राजनैतिक गतिविधियों के कारण विघटन की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसका एक कारण यह है कि पश्चिम के लोग यह समझते हैं कि गैर पाश्चात्या में चुनाव आदि की दलों की राजनीति में भाग लेने की क्षमता ही नहीं है और दास मनोवृत्ति से प्रभावित होकर गैर पश्चिमी राजनीति में आलोचक भी उपयुक्त आसक्त प्रकट करते हैं। दूसरे, पश्चिमी विचारक यह समझते हैं कि जातीय विकास और सामाजिक संस्कार होने के बाद ही आम लोगों को चोट देने और राजनीति में भाग लेने का अधिकार देना चाहिए। तीसरे, राष्ट्रीयता की ही धारणा का सबसे अधिक या एवमान महत्त्व रख कर इस बात की उपेक्षा कर दी जाती है कि प्रात, भाषा या जाति की अपेक्षाकृत सकीण भावना या निष्ठा भी राजनैतिक संगठन में और राज्य व्यवस्था को स्थापित करने में सहायक होती है और राजनैतिक मांग पर अकुस रखती है। आजकल एक और नारा बहुत चल पड़ा है — बढ़ती हुई आकांक्षा की क्रांति। यह बात भी पश्चिमी देशों पर ज्यादा लागू होती है, जहाँ व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य मांग की पूर्ति है।

विकसित या उन्नत देश, नव स्वतंत्र देशों के द्वार में, खासकर भारत के द्वारे में क्या सोचते हैं इसे भी देखना चाहिए। पश्चिम में यह आम धारणा रही है और पश्चिमी देशों के संबंध में अब भी है, कि जनसाधारण के राजनीति में भाग लेने से व्यवस्था की लोकप्रियता और शक्ति बढ़ती है। लेकिन यह बात कम विकसित देशों के लिए ठीक नहीं समझी जाती और कहा जाता है कि इन देशों में यदि जनता को राजनीति में भाग लेने और मनभेद या विरोध की स्वतंत्रता दी गयी तो इससे विघटन की शक्तियों के उभरने और व्यवस्था के छिन्न भिन्न होने का खतरा है। यद्यपि इस धारणा के लिए बहुत कम प्रमाण हैं क्योंकि ऐसे नए राष्ट्रों की सरया ही इनी गिनी है, जहाँ जनता को राजनैतिक अधिकार प्राप्त हैं, फिर भी यह काफी व्यापक है। यह साम्राज्यवादी देशों की इस धारणा का ही दूसरा रूप है कि पराधीन देश स्वशासन के योग्य नहीं हैं। उपयुक्त विचार के लोग यह भी समझते हैं कि अंत में भारत भी विघटन की शक्तियों का शिकार होगा।<sup>२</sup>

भारत में जब तक लाकतंत्र कैसे चल रहा है और यहाँ की व्यवस्था क्या नहीं टूटी, इसके लिए ये पाश्चात्य आलोचक तरह तरह की सफाई देते हैं। पहले यह

२ मारिंस जोन्स के शब्दों में — भारत के विभ्रम की भविष्यवाणी करने वालों का शायद यह खेदक बड़ा बुरा लगता है कि इतनी भारी कठिनाइयों के सामने भी वह कैसे टिका हुआ है। भारत में अपनी आलोचना की जो प्रवृत्ति है उससे इन अशुभ चिंतकों को बल मिलता है। किंतु भारत की संप्रज्ञा इनकी भूठा सिद्ध कर देती है। 'लेबेन ऐंड रिचन बिदिन इति यूनिटन' - फिलिप मेमन सभा '—डिया ऐंड सीनेन यूनिटी ऐंड हाइवर्सिटी' (१९६०)।

कहा जाता था कि अंग्रेजा का छाडा हुआ 'नीकरशाही का फौलादी ढाचा' भारत को बचाये हुए है, फिर कहा जाने लगा कि यह नेहरू का चमत्कार है, इसके बाद यह कहा गया कि कांग्रेस दल देश को एक में बाँधे हुए है। जब ये सब बातें चूक गयीं, तो लागू चकरा गए। अब भी उनके मन में आशंका है कि भारत की व्यवस्था ज्यादा दिन चलने वाली नहीं और कोई न कोई समस्या ऐसी उठेगी, जो इसे तोड़ देगी, या तो केन्द्र और राज्या में सघप या चीन अथवा पाकिस्तान से पराजय, और कुछ नहीं तो आर्थिक विकास में विफलता। इस प्रकार समझ या सहानुभूति के अभाव से (क्षेत्रीय विशेषज्ञा को छाड़ कर) ये जालोचक भारत की सफलता या विफलताओं का ठीक ठीक जायजा नहीं ले पाते। बल्कि शीत युद्ध की मनोवृत्ति से प्रभावित होकर पहले के प्रशमक भी अब विरोधी बन गये हैं।<sup>3</sup> यह भी एक बिडबना है कि जब सारे ससार में बौद्धिक जागरण फैल रहा है, तब जिन दशों में उसका पहला प्रकाश फैला था, वे इतनी जटिलता और कुठारा के शिकार हैं।

### भारतीय विकास का स्वरूप

भारत के विकास का अनौपचारिक इस बात में है कि आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन और विकास की महत्वपूर्ण बात ऊपर से तय की जाने पर भी लाकतंत्री और स्वतंत्र राजनैतिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्यान्वित की जाती है। इसका अर्थ यह है कि कुछ प्रमुख विचारों के प्रभाव में जो राजनैतिक परिवर्तन हो रहे हैं, उनमें ऐसे तत्त्वों का हाथ है जैसे राजनैतिक स्पर्धा में तीव्रता, शक्ति और प्रभाव का विस्तार तथा राजनैतिक प्रक्रिया में बहुजन वर्ग का भाग लेना। इसमें लोगों को डंडे के जोर पर इच्छित दिशा में हटाने की काशिश नहीं की जाती, बरन उन्हें निर्दिष्ट ढंग से खुद अपना विकास करने को प्रेरित किया जाता है। व्यक्तियों और समूहों को राजनैतिक प्रक्रियाओं और समस्याओं में भाग लेने का अवसर दिया जाता है जिससे व्यवस्था का आधार ज्यादा व्यापक होता है। राज्य के हित को ऊपर रख कर व्यक्ति के हित को कुचलने के बजाय व्यक्ति के हित का राज्य के हित से सामंजस्य किया जाता है। राज्य नेता जनता का समर्थन कर उसे साथ ले चलने का प्रयास करते हैं।

इसके अलावा अधिकार और मत्ता पर किसी अभिजात वर्ग या सीमित शासक

३ पहले आम चुनाव के दो वर्ष बाद मजिस्ट्रेट गार्जियन ने लिखा था—एशिया में समुदाय व्यवस्था सफल नहीं हो सकी है—पेरिशियम ने कहा था कि एथेंस सारे यूनान का शिक्षक है। मि. नेहरू भी इसी तरह बिना सोची बयारे कह सकते हैं कि दिल्ली सारे एशिया का शिक्षक है। (जून ५, १९५४)। इसके करीब १३ वर्ष बाद टाइम्स के भारत स्थित संपादकाला ने कई लेखों में यह कहा कि चाहे आम चुनाव या भारत में आखिरी चुनाव होंगे। इस भविष्यवाणी का पश्चिम में सहानुभूतिपूर्ण स्वागत किया गया।

वर्ग का एकाधिकार नहीं है। 'ये' 'ये' तत्त्वा को सत्ता में भाग लेने का मौका दिया जाता है और सारे समाज को अधिकार या भागीदार बनाने की कोशिश की जाती है। इस विषय में भारत उन पश्चिमी देशों से भिन्न है, जहाँ तीव्र जीवोद्योगिक क्रांति और सामाजिक परिवर्तन के युग में राजनैतिक सत्ता केवल उच्च वर्ग के हाथ में रही। इसी तरह वह उन कम्युनिस्ट तथा गैर कम्युनिस्ट अधिनायकवादी देशों से भी भिन्न है, जहाँ क्रांति के बाद पार्टी की आंतरिक गुटबंदी एवम सैनिक पट्टमंत्र के अलावा राजनैतिक दलों की गतिविधियाँ पर पाबंदी लगा दी गयी और उन्हें देश के विकास में राय देने या भाग लेने से वंचित कर दिया गया। भारत में न तो राजनैतिक गतिविधियाँ पर रोक है न उस पर 'अल्पसंख्यक' उच्चवर्ग का वर्चस्व है। इसके विपरीत आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन सबधी निम्न राजनैतिक वादविवाद और लोकतंत्री प्रक्रिया से किए जाते हैं।

कुछ समय तक यह बात इतनी साफ नहीं थी क्योंकि बालिग मताधिकार और अनेक दलों के होते हुए भी सत्ता या शासन वास्तव में एक छोटे और सुसंगठित समूह या गुट के हाथ में था। किन्तु क्रमशः राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता और चुनाव की प्रक्रिया के प्रसार के कारण अल्पसंख्यक समूह या गुट भी सत्ता के दावेदार हुए। शासन में जनप्रतिनिधित्व का तत्त्व आया, सीमित साधनों के विवरण के लिए विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों से मांग बढ़ी सामाजिक वर्गों और राजनैतिक गुटों या दलों में संघर्ष बढ़ा, पुराने सामाजिक भेदों ने राजनैतिक रूप धारण किया और पद-प्रतिष्ठा के नये मानदंड स्थापित हुए। देश की राजनीति और विकास प्रक्रिया पर इन प्रवृत्तियों का प्रभाव पड़ रहा है।

साथ ही यह भी ध्यान रहना चाहिए कि भारत में विकास का काम प्रशासन के विकसित और सुगठित ढाँचे के अंतर्गत शुरू हुआ। जितने भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम बने, औद्योगीकरण सामुदायिक विकास, शिक्षा क्षेत्रों का विकास, यहाँ तक कि स्थानीय स्वशासन — सब इसी नोकरशाही या प्रशासन तंत्र के द्वारा संचालित थे। अब इसमें राजनैतिक तत्त्वा और मूल्यों का प्रवेश हो रहा है।

इस प्रकार भारत में राष्ट्र निर्माण की दो प्रक्रियाएँ चालू हैं। एक सरकारी प्रशासनिक प्रक्रिया है जो विकास योजना के कार्यों को बढ़ाने और उनमें एकसूत्रता रखने का यत्न कर रही है। दूसरी राजनैतिक प्रक्रिया है जिससे एक ओर केन्द्रीय सत्ता या राजनैतिक केन्द्र की स्थापना हुई है, दूसरी ओर सत्ता का विकेन्द्रीकरण हुआ है और उसमें नए तत्त्वा का प्रवेश हुआ है तथा नये संगठन और संस्थाएँ सक्रिय हो उठी हैं। धीमे धीमे ये दोनों प्रक्रियाएँ एक दूसरे के समीप आ रही हैं और उनका स्वरूप बदल रहा है।

भारत में होने वाला परिवर्तन बहुत सीमा-तक राजनैतिक सरकारी परिवर्तन है। भारत इस सिद्धांत का अपवाद या विरुद्ध प्रमाण है कि आर्थिक — सामाजिक

शक्तियाँ राजनीति और सरकार की नियामक होती हैं। भारत में बहुत हद तक राज्य समाज का नियामक है। इसका यह अर्थ नहीं कि विकास की प्रक्रिया में सामाजिक और आर्थिक शक्तियों का कोई हाथ नहीं। प्रत्युत ऐसा संभव है कि सत्ता के विवेकीकरण से इन शक्तियों का प्रभाव बड़े।<sup>४</sup> ध्यान देने की बात यह है कि सामाजिक हित अधिवाधिक राजनैतिक रूप ले रहे हैं और राजनीति के द्वारा ही संगठित हो रहे हैं।

अक्सर इसका यह अर्थ लगाया जाता है कि एक या अनेक सामाजिक समूह (जाति या संप्रदाय) राजनीति के द्वारा अपनी प्रधानता स्थापित करने और प्रतिष्ठा तथा प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। समय गुजरने के साथ साथ जिस व्यापक संगठन के अंतर्गत यह परिवर्तन-प्रक्रिया चलती है और राजनैतिक तथा प्रशासनिक मानदंड प्रतिष्ठित होते हैं उनके कारण राजनैतिकीकरण की प्रक्रिया परिपक्व हो जाती है। परंतु इससे अंत में समाज के राजनैतिकीकरण में मदद मिलेगी और सामाजिक मूल्य राजनैतिक मूल्य तथा सामाजिक पद-प्रतिष्ठा राजनैतिक पद-प्रतिष्ठा में बदल जाएंगे।<sup>५</sup>

### राजनीति का स्थान

भारत में समाज के विखंडित ढाँचे में राजनैतिक संस्थाएँ, मूल्य और विचारों का प्रवेश हो रहा है। भारतीय समाज-व्यवस्था अराजनैतिक रही है, अब यहाँ एक राजनैतिक केंद्र की स्थापना हो रही है और समाज के विविध वर्गों को राजनैतिक व्यवस्था में स्थान मिला है, उन्हें इसका लाभ और अधिकार मिला है और उन पर इसकी जिम्मेदारियाँ भी आयी हैं। अब तक जो गाँव राजनैतिक व्यवस्था से दूर रहे वे इसके पास आ रहे हैं।

यह एक नयी बात है। अपने हजारों वर्षों के इतिहास में भारत की सबसे बड़ी विफलता यही रही है कि वह एक ठिकाऊ आधिकारिक राजनैतिक सत्ता का निर्माण नहीं कर सका। यह राजनैतिक केंद्र या केन्द्रीय सत्ता का निर्माण नहीं कर सका। इसी से हम भारतीय समाज-व्यवस्था को अराजनैतिक समाज का नाम देते हैं, न कि उसके विशिष्ट साम्प्रदायिक तत्त्वों के कारण। इस पृष्ठभूमि में भारतीय नेता-वर्ग के कर्तृत्व और अभिन्नवृत्तता की मौलिकता और महत्त्व स्पष्ट है। उनका काम एक केंद्र की स्थापना करना और इसे समाज के उपकेंद्रों में फैलाना है। यहाँ

<sup>४</sup> अध्याय ९ में इस पर विस्तार से विवेचन किया गया है।

<sup>५</sup> इसमें न केवल विशेष हितों का संगठन होता है, बल्कि पुरानी निष्ठाएँ और आवश्यकताएँ भी बदलती हैं। एक बार इन प्रकार का राजनैतिक व्यवस्था का कथन होने के बाद हितों के ये संगठन राजनीति को प्रभावित करेंगे। इस बीच 'हित समूह' या 'हित विशेष' के दलों का अधिक महत्त्व नहीं।

सामाजिक परिवर्तन राजनैतिक रूप में हो रहा है।

इसके फलितार्थ को समझ लेना आवश्यक है। आर्थिक विकास का जो सिद्धांत है उसने ऐसा मत प्रतिपादित किया है जो सामाजिक परिवर्तन को एकांगी, एकांगी और प्रमुखतः द्वैधात्मक रूप में देखता है। भारत की जटिल विकास-प्रक्रिया को व्याख्या ऐसे एकांगी सिद्धांत से समझ नहीं। क्योंकि यह स्पष्ट है कि पारस्परिक समाजशास्त्रीय और अर्थशास्त्रीय सिद्धांतों की सहायता से यहां की राजनैतिक प्रक्रिया को नहीं समझा जा सकता। हम एक ऐसे समाज का विश्लेषण कर रहे हैं, जहां परिवर्तन किसी विशिष्ट शक्ति-संतुलन का न तो परिणाम है न उसकी प्रतिच्छाया है। भारत जैसे समाज में राजनीति का आयाम सीमित भी है और स्वायत्त भी है। अनेक प्रकार से राष्ट्रीय लक्ष्य और साधना की प्राथमिकता का निर्धारण राजनैतिक निष्कर्षों से होता है। राजनीति के रूप भी इस सदन में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हालांकि आधिकारिक संस्थाओं की तरह में जो राजनीतिक तत्त्व हैं उसका असली स्वरूप नेतृत्व के सामाजिक संस्कार और गठबंधन के तरीके में प्रतिबिम्बित होता है। फिर भी राजनीतिक संस्थाओं का दृश्यमान रूप अपनी एक गतिशीलता और प्रमुखता प्राप्त कर लेता है और समाज के लक्ष्य को स्पष्ट करता है तथा समाज की वास्तविकता को समाविष्ट करता है। ये दोनों पहलू घुलमिल जाते हैं। नेतृत्व का सामाजिक संस्कार सामाजिक वर्गों के राजनैतिकीकरण से अभिन्न हो जाता है और राजनैतिक व्यवस्था भी आधिकारिकता, सामाजिक रूपों और निष्ठाओं के राजनैतिक नवरूपों पर निर्भर करती है। इस कारण से पारस्परिक विकास के सिद्धांत के बजाय विश्लेषण के नए मानदंड आवश्यक हो जाते हैं।

भारत में लोकतंत्रीय राजनैतिक व्यवस्था के अंतर्गत एक प्राचीन और बड़े विविधतापूर्ण समाज का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसमें क्या सामाजिक और आर्थिक प्रवर्धन करने हैं, यह त्रिकुल स्पष्ट होना चाहिए। वरना देश ने जो संस्था योजना स्वीकार की है, उसका रूप विकृत हो जाएगा। दूसरे, इस पद्धति में विकास के जो परंपरागत लक्ष्य हैं, अर्थात् आर्थिक विकास की दर, विकास के शिक्षा जैसे सामाजिक साधन और नये विचारों व मूल्यों का प्रसार, वे भी काफी हद तक दम पर निर्भर हैं कि राजनैतिक व्यवस्था या राज्यतन्त्र कैसा काम करता है और विकास के द्वारा विभिन्न तत्त्वों को एकता के सूत्र में बांध पाता है या नहीं। इसके लिये यह आवश्यक है कि राज्य के नेता ऊँचे अधिकारी और जनमत के निर्माता वास्तविक स्थिति और लक्ष्य का समझें। सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं को विकास की दिशा में माइ देना आसान काम नहीं है। इसका प्रतिरोध पुराने लोगों की ओर से ही नहीं होगा बल्कि शिक्षित पेशा, सरकारी नौकरा और बुद्धिजीवियों जैसे आधुनिक तत्त्वों की ओर से भी होता है। विकास के पुराने शास्त्रीय सिद्धांत

और पुराने राजनैतिक और सामाजिक विचार विकास की उस पद्धति में बाधक होते हैं, जिसे देश ने अपनाया है। यह पद्धति द्वंद्व के जरिये एकता स्थापित करने की है। ध्यान यह रखना है कि इसमें किताबी सिद्धांत और सरकारी नौकरा की निरकुशता और जनता की भावनाओं की उपेक्षा बाधक न होने पाए।

भारत ने विकास की जिम पद्धति का अपनाया है उसके लिए अविक विवेक पूर्ण संकल्पना की जरूरत है। जब यह अनुभव किया जा रहा है कि आर्थिक विकास महज एक आर्थिक प्रक्रिया ही नहीं है और उसकी सफलता अनेक मोर्चों पर की गई प्रगति पर निर्भर है। अभी तक इसके लिए आर्थिक विकास की आवश्यक पूर्वस्थितियों पर ही जोर दिया जाता है। समझने की मुख्य बात यह है कि जिस राष्ट्र और समाज का विकास अवचेताओं को करना है, अभी उनकी स्थापना नहीं हो पायी है। विकास का अर्थ जनता के कुछ या सब वर्गों की उन्नति ही नहीं करना है, वरन् राष्ट्र का निर्माण भी करना है। लोगों को उत्पादनवृद्धि के काम में लगाने का मतलब केवल बचत करना और उसे आर्थिक काम में लगाना नहीं है, इसमें जनता के प्रोत्साहन, मनोबल, दिलचस्पी और भागो की संतुष्टि के भी प्रश्न उठते हैं। इसमें समाज के वर्तमान ढांचे को बदलने, ऊपर और नीचे के तबका का जोड़ने वाले मध्यवर्तियों के संगठन की जरूरत पड़ती है और समाज को उत्पादन की ओर उन्मुख करना पड़ता है। राजनैतिक ढांचे की कसौटी इन्हीं कार्यों की संपादन-क्षमता होगी। इसके विवेचन के लिए वह धारणा काम नहीं देगी जो आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्रों में महज सबद्धता दिखाती है। विकास की यह ऐसी पद्धति है, जिसमें अब तक बड़े हुए और विभाजित ढंग से सोचने वाले समाज के सामने नये मूल्य प्रस्तुत होते हैं और उसका वास्तव ऐसी नयी संस्थाओं के ढांचे से पड़ता है जिसका उद्देश्य राष्ट्र का एकीकरण और आयोजित उत्पादन है। बदले में समाज के विभिन्न वर्गों को विकास के कार्यों का लाभ और राजनैतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इससे प्रकट है कि सामाजिक परिवर्तन में राजनैतिक व्यवस्था की भूमिका कितने महत्व की है।

यह परिवर्तन आसान नहीं है। पश्चिम में राजनीति के विवेचकों को सरकार के रूप से ध्यान हटा कर समाज में शक्ति, सत्ता और हित के वास्तविक संगठन पर ध्यान देने में कई देर लगे। भारत जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए और जटिल सामाजिक ढांचे वाले देश में नयी राजनैतिक व्यवस्था का विवेचन करते समय शक्ति या सत्ता के ढांचे और उसकी सोद्देश्यता के संबंध में और गहराई में जाना पड़ेगा। जब किसी समाज में विजातीय ढंग की सरकार या शासन-प्रणाली स्थापित की जाती है तो उसकी एक अनोखी प्रतिक्रिया होती है और समाज में नयी चेतना और नयी निष्ठाएं उत्पन्न होती हैं। कमश इनसे सरकारी काम के मूल्यांकन के नए नापदंड स्थापित होते हैं, जिनसे अकमर स्थापित व्यवस्था की

स्थिरता सतर में पड़ जाती है। विकास के दाम्बविक श्रम में पुरानी और नयी दोनों तरह की बात होती है। इसलिए पहले से यह वही निश्चित किया जा सकता कि सवैधानिक सरकार किस रास्ते पर चले।

### सहवर्ती परिवर्तन की समस्या

तार्किक दृष्टि से ऐसा माना जाता है कि समाज जिस प्रकार की समस्याओं को स्थापित करता है उन्हीं के अनुरूप उसे विकास के लक्ष्य भी अपनाने चाहिए। किंतु यह अनिवार्य नहीं। बल्कि भारत में विकास की आरम्भिक अवस्था में स्थापित संस्थाओं और उनके उद्देश्यों में मेल या अनुरूपता की कमी दिखाई पड़ी। स्वतन्त्रता के बाद भारत में जो राजनैतिक और आर्थिक विचारधारा स्वर हुई वह इन बातों पर केन्द्रित है— (१) देश में बालिग मताधिकार पर आधारित संसदीय शासन की प्रणाली की स्थापना करना और जनता को चुनावों के जरिये शासन में अधिक से अधिक भाग देना। (२) विकास की केन्द्रित सरकारी योजना बना कर तेजी से आर्थिक उन्नति करना। विराधाभास के बावजूद क्या ये दोनों लक्ष्य राष्ट्र निर्माण में सहायक होंगे, अथवा संस्थाओं का यह ढांचा इन लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक हो सकता है, यह कुछ महत्वपूर्ण बातों पर निर्भर था।

एक तरीका था अधिनायकवादी ढांचा स्थापित करना जो प्रारम्भ से शासन की पूरी शक्ति विकास में लगाता। यह या तो नीकरशाही का फौलादी ढांचा हो सकता था, जिसे राजनैतिक दबाव की कोई परवाह नहीं होती, या एक दलीय ढांचा होता या दोनों का मिश्रण हो सकता था। यह केन्द्रीयकरण को राष्ट्रनिर्माण की प्रक्रिया का एक अनिवार्य भाग बना देता। इसमें समाज को नये लक्ष्यों की पूर्ति में लगाने के लिए उसका राजनैतिकीकरण किया जाता लेकिन राजनैतिक गति विधि दलों का संगठन और प्रतिद्वन्द्विता को अत्यन्त सीमित एवम् सकुचित कर दिया जाता। स्थानीय लोग और समूहों से परामर्श सिर्फ राजनैतिक कौशल का रूप नेता जिससे जनता को वृद्धि के कार्यों में लगाने की सुविधा होती पर इसको राजनैतिक व्यवस्था में भागीदारी का रूप नहीं दिया जा सकता था। इसी तरह सामाजिक न्याय और समता के लक्ष्य का स्वीकारा तो जा सकता था और साधन उपलब्ध होने पर उनकी पूर्ति का आश्वासन तो दिया जा सकता था, किंतु देश की समृद्धि और प्रगति की भूमि तैयार करने की खातिर लोकहितकारी राज्य के आदेश और उपभोग बढ़ाने की नीति को तब मुनतवी रखा जाता।

भारत ने विकास के इस तरीके को नहीं अपनाया। एक राष्ट्रीय राजनैतिक मोरचा बनाने और सामूहिक या नाक-समर्थित लोकतन्त्र की स्थापना करने के लिए नेताओं को सत्ता की राजनीति पर अर्थात् मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने की आवश्यकता पर ध्यान देना पड़ा और स्वतन्त्रता के बाद इसने त्याग और

सादगी के जिन आदर्शों पर जार दिया था, उन्हें नमश छोड़ देना पड़ा। अब यह स्पष्ट है कि देश की मध्यवर्गी और वंचित जनता को विकास के कार्य में लगाने के लिए नेतृत्व ने उनसे केवल अधिकाधिक धन और साधन खींचने के बजाय उनको विकास के लाभ और राजनैतिक अधिकारों में भाग देने की नीति अपनायी। जनता से देश के विकास के लिए अधिकाधिक धन लेना, अभी भी उसका एक मुख्य लक्ष्य है, मगर इस लक्ष्य की सिद्धि वह जबदस्ती, अथ सब मांगों को कुचल कर नहीं, बल्कि जनता के सामाजिक और राजनैतिक संगठन के द्वारा करना चाहता है।

इस काम में गलतियाँ भी हुई, क्योंकि ऐसा कोई उदाहरण न था, जिसका अनुसरण किया जाता। देश के राजनैतिक और आर्थिक विकास के साथ साथ समाज के पुराने कठुआए हुए ढाँचे को बदलने का काम एक अभूतपूर्व प्रयत्न था। दूसरी ओर यह भी निश्चित नहीं है कि अधिनायकवादी तरीका सफल ही होता, खास कर भारत ऐसे देश में जहाँ केन्द्रीय सत्ता के पतियों का प्रवेश प्रायः या प्रदेशों में नहीं हो सका है और जहाँ प्रांतीय निष्ठाओं को अभी राष्ट्रीय निष्ठा का रूप देकर सघ के स्थायी ढाँचे की स्थापना करना बाकी है। वास्तव में दिल्ली सारे देश पर शासन इसी प्रकार कर सकती है कि वह प्रदेशों का सत्ता में भागीदार बनाये और प्रदेश भी अपने अंतर्गत उपप्रदेशों या स्थानीय इकाइयों को साथ लेकर चले। इस स्थिति में लोकप्रिय राज्य और बालिग मताधिकार को केवल आदर्श और भावना की खातिर नहीं, बल्कि व्यावहारिक कारणा से स्वीकार किया गया, क्योंकि इसके द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण, सामाजिक संगठन और आर्थिक विकास का आधार मिलता था। स्वाभाविक था कि इस पद्धति पर चलने में शुरू में काफी दुविधा और गड़बड़ी होती। पर जैसा कि हम आगे व्यवस्था के काम की समीक्षा सवधी अध्याय में देखेंगे, इस पद्धति से न केवल राजनैतिक केन्द्र की स्थापना और संस्थानीकरण में और उसमें देश के विविध तत्वों को शरीक करने में सफलता मिली, वरन् जब जब आर्थिक और सामाजिक नीतियों में दोष दिखाई दिये, तब तब उन्हें सुधारने में भी मदद मिली।<sup>६</sup>

इस सबब में एक बात और ध्यान देने योग्य है। राष्ट्र या राष्ट्र-निर्माण की धारणा अधिकतर पश्चिमी देशों से ली गयी है जहाँ राष्ट्रों की स्थापना साम्राज्यों, सामंती व्यवस्थाओं और ईसाई चर्च के आधिपत्य के टूटने से हुई थी। इससे सुदृढ़ और सशक्तिशाली केन्द्रीय सरकार का सिद्धान्त प्रचलित हुआ। इसीलिए राष्ट्र की भावना पर इतना जोर दिया जाता है और नये देशों में प्रांतीय या

६ पश्चिम में इस पद्धति के महत्त्व का कुछ कुछ अनुभव अब किया जाने लगा है। देखें-चार्ल्स ए. लिं-जाम के दो अप्रकाशित निबंध 'पोलि डिमोक्रेसी ऐंड डिमिलिटर्ड डेवेलपमेंट्स-द केम ऑफ इंडिया' और 'पॉलिटिक्स, पॉलिनी मेरिंग ऐंड प्लानिंग फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवेलपमेंट'।



भाषा आदि की सकीण प्रवृत्तियाँ पर चिन्ता प्रकट की जाती है। पर यह स्पष्ट नहीं है कि केन्द्रीय सत्ता की शक्तिमत्ता पर इतना ज़ार देना और स्थानीय या प्रांतीय प्रवृत्तियों का दमन नये राष्ट्र का हित में होगा। प्रत्युत इससे एकता के स्थान पर पृथक्ता उत्पन्न हो सकती है। नए देश के नेताओं के सामने काम है केन्द्र की स्थापना, उसके प्रतीका का प्रसार, दूसरे उपभेदों का आश्वासन और सुविधाएँ देकर उनको केन्द्र में शामिल करना और जनता में नयी व्यवस्था के प्रति निष्ठा और अपनापन फैलाकर उनका इसका भागीदार बनाना और इस क्रम में नए राजनैतिक सधायी रूपों की रचना करना। इस काम में राजनैतिक सूक्ष्मता और रचनात्मक प्रतिभा की बड़ी ज़रूरत है। इस दृष्टि से देखने पर भारत के विकास की पद्धति का सही महत्त्व और अर्थ समझ में आएगा।

जब राजनीति के द्वारा देश का आधुनिकीकरण किया जाता है तब सामाजिक और आर्थिक समस्याएँ भी इसमें प्रभावित होती हैं और उनकी स्वायत्तता नष्ट हो जाती है। जिस हद तक राजनैतिक व्यवस्था व्यक्तियों और समूहों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकती है उसी हद तक समाज और अर्थ व्यवस्था पर उसका प्रभाव उपयोगी होता है।

### व्यवस्था की कसौटी काय-संपादन

किसी भी व्यवस्था की उपयोगिता की कसौटी, उसकी कार्यक्षमता है। ऐतिहासिक और सैद्धांतिक कारणों से ही व्यवस्था का औचित्य सिद्ध नहीं हो सकता। उसे लोगों की आकांक्षाओं और समय की माँग को पूरा कर सकने में भी समय होना चाहिए। एक गतिशील और बहुमुखी विकास की पद्धति का मूल्यांकन करने के लिए कुछ कसौटियाँ होनी चाहिए। विकास और परिवर्तन के क्रम में कुछ समस्याएँ स्वभावतः उठती हैं। मगर इन्हें उन समस्याओं का भेद करना चाहिए जो नेतृत्व की भूलों और गलत तरीकों के कारण उठती हैं। हाँ सकता है कि शुरू में अटकलपच्चू काम हो, मगर यथाशीघ्र रास्ते में आने वाली कठिनाइयों की कल्पना की जानी चाहिए और उनका उपाय सोच रखना चाहिए। बेशक सभी समस्याओं और परिस्थितियों की कल्पना नहीं की जा सकती। मगर हर बात की रामझरोखे छोड़ देना और तदयत्ता से काम लेना अर्थात् यह सोच बैठना कि जो होगा सो देखा जाएगा, अवस्था का निमंत्रण देना और बुद्धि का तिलाजलि देना है। इसका अर्थ तो यह होगा कि यहाँ सकट आने पर ही आँख खुलेगी और काम होगा, अथवा नहीं।

भारतीय राज्यतंत्र किस हद तक वर्गहित के बदलते ढाँचे का अधपूर्ण और क्रमबद्ध गूँथना में सगठित और मुखरित करने में समर्थ है, जिससे अनुभूत सामाजिक विभेद और एकात्मकता के द्वारा निरूपित प्रश्न निणय का रूप लेते और देश के

विकास के लिए सहायक बनते ह ?

राजनैतिक प्रक्रियाएँ और सस्थाएँ समाज के लिए उपयोगी होनी चाहिए। उन्हें सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को समझ कर सरकार पर जोर देना चाहिए कि उनको सुलझाने के लिए ममुचित निणय ले और उन्हें ठीक ढग से और समय से ढायावित करे। दूसरी ओर लोगो को सही प्रेरणा देने और ढथायवादी दष्टि की समस्या है। जय एन जटिल और रुद्धिग्रस्त समाज—व्यवस्था में आधुनिक ढग की राजनैतिक व्यवस्था काम करती है तो परिवर्तन और सामजस्य या अनुकलन की बड़ी नाजूक समस्याएँ उठती हैं, जिनको बड़े धीरज तथा दृढ सकल्प से सुलझाना पडता है। समता, विविधता और जनसहभाग की समस्याएँ नया अर्थ ग्रहण कर लेती हैं और उनको समझाने के लिए नये बौद्धिक संस्कार की जरूरत होती है। यदि व्यवस्था इन समस्याओं का सामना न कर सकी, तो इसका नतीजा या तो यह होगा कि या तो लोग विरक्त होकर समझ नें कि स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता, और जो चलता है उसे चलने दो या देश का जो स्वतन्त्रता का वरदान मिला है, उसकी गहरी प्रतिक्रिया हो।

जब राज्यतंत्र के रूप में स्थायित्व आता है तो उसका प्रवेश समाज के हर स्तर में हाता है और उधर से उसकी अनुकूल प्रतिक्रिया होती है। सरकार की सफलता की कसौटी यह है कि प्रचलित सन्ध्याआ और वैधानिक तरीको से वह समाज के विभिन्न वर्गों और स्तरों में मिलने वाले ममथन को संगठित करे और इच्छित दिशा में मोडे। इसके लिए इन बातों का अध्ययन आवश्यक है — (१) राजनैतिक और सरकारी सन्ध्याआ का समाज में प्रसार (२) समाज की ओर से इसकी प्रतिक्रिया और (३) समाज के विभिन्न स्तरों की आवश्यकताओं की पूर्ति में राजनैतिक व्यवस्था की सफलता। इस विवेचन का केन्द्र बिंदु यह होगा कि विकास का जो व्यापक तरीका अपनाया गया है उसने कैसा काम किया है। इन विवेचन के लिए हमें कुछ गहराई में जाना पडेगा जैसे देश की ऐतिहासिक और सामाजिक परंपरा तथा राजनैतिक और सामाजिक संस्कार आदि की समीक्षा करनी पडेगी। इस पुस्तक में हम इन विषयों का उसी हद तक विवेचन करेंगे, जिस हद तक इनका संबंध राजनैतिक व्यवस्था से है। इसलिए हम उतने विस्तार में नहीं जा सकेगे जितना विस्तार इन विषयों पर अलग लिखी पुस्तक में मिलेगा।

प्रस्तुत पुस्तक तीन खंडों में बाटी है — ऐतिहासिक सिंहावलोकन (अध्याय १ से ३), प्रचलित राजनैतिक व्यवस्था का विवेचन (अध्याय ४ से ७), व्यवस्था के ढाय का मूल्यांकन (अध्याय ८ से ११)। हमारा केन्द्र बिंदु है सांस्थानिक विकास तथा सरकार की ढायक्षमता में संबंध। भारत ने जिस प्रकार की पद्धति को अपनाया और जिसकी परिणति दला की पद्धति में हुई, उसने विवेचन पर हमने विशेष ध्यान दिया है। इसी से संबंधित विषय है पुरानी और नयी व्यवस्था का परस्पर संबंध

और इसमें अतर्निहित राजनैतिक संस्कार । पर इस सब विवेचन का मुख्य प्रयोजन है स्थापित व्यवस्था या पद्धति की क्षमता की परीक्षा ।

दूसरी तरफ हमने राजनैतिक विवेचन के कुछ रुढ़ विषयों पर कम ध्यान दिया है । जैसे हमने (अध्याय ५ में) भारत में विभिन्न हिता के सघों की चर्चा करत हुए, श्रमिक या अग्य प्रकार के संगठना या संस्थाओं का इतिहास देने की चेष्टा नहीं की है । इसी प्रकार सामाजिक सेवाओं के प्रसंग में हमने प्रचार के माध्यमों की (रेडियो, अखबार, फिल्म आदि) वसी समीक्षा नहीं की है जैसी पश्चिमी आलाचका के ग्रन्थों में मिलती है । इसी तरह हमने संविधान तथा न्याय और कानून की पद्धति के विकास का इतिहास भी नहीं दिया है । इस प्रकार हमारा विवेचन विकास की प्रक्रिया पर केन्द्रित है ।

## ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्रस्तावना वाले अध्याय में उठाए गए प्रश्न को अधिक अच्छी तरह समझने के लिए हमें भारतीय समाज की ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि को देखना चाहिए और जिन विचारधाराओं और शिल्पिक विधियों ने उस प्रभावित किया है उन पर गौर करना चाहिए। किसी भी देश में लोकतन्त्र कितना सफल होता है या क्या स्वरूप ग्रहण करता है यह इस पर निर्भर होता है कि उसकी परंपरा क्या रही है उसकी समाज-व्यवस्था और आदर्शों व विचारों में नई बातों को ग्रहण करने की कितनी शक्ति है, उस पर बाहर के क्या प्रभाव पड़े हैं और इतिहास को किन परिस्थितियों में उसने नए प्रभावों का ग्रहण किया है।

काफी लंबी अवधि से भारत पर जो विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़े हैं, उन्हीं से उसके वर्तमान राजनीतिक रूप की रचना हुई है। इसमें तीन बातें मुख्य हैं। एक है हिंदू समाज जो भारतीय जीवन की आधारशिला और उसकी एकता का सूत्र है। दूसरा है अंग्रेजी राज, जिसकी कानून और शासन व्यवस्था सारे देश का एक केन्द्रीय सत्ता के अधीन ल आई। यही नहीं इसने हमारी राजनीतिक विचारधारा और पद्धति पर भी गहरा प्रभाव डाला है। तीसरा है स्वतन्त्रता के पहले का हमारा रचनात्मक राष्ट्रवाद। यह राष्ट्रवाद विदेशी शासन के प्रभाव और उसके द्वारा सप्रेषित नए युग की चुनौती से उत्पन्न हुआ। इस राष्ट्रवाद का उद्देश्य लोकतन्त्री व्यवस्था के अंतर्गत देश की राजनीतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति और समाज का सुधार था। आगे हम इन्हीं तीन प्रभावों के अंतर्गत आधुनिक भारत के विकासक्रम का विवरण करेंगे।

### हिंदू समाज

भारत का इतिहास हजारों वर्षों का है। यहां बड़े साम्राज्यों से लेकर छोटे राज्य और गणराज्य, जैसे अनेक प्रकार के राजतन्त्र रहे हैं। जिसे हम हिंदू युग कहते हैं वह ईसा से पहले १५ वीं शताब्दी और दसवीं शताब्दी के बीच स्थिर हुआ। इनो

अवधि में मध्य एशिया से आने वाली आय जातियाँ नए देश के उत्तरी और पश्चिमी भागों में अपनी बड़ी बड़ी बस्तियाँ स्थापित कीं। उन्होंने यहाँ के आदिम निवासियों को हराकर अपने अधीन कर लिया और बहुतों को दक्षिण की ओर धकेल दिया। ईसा पूर्व १५ वीं सदी से लेकर ईसा की १० वीं सदी के बीच यहाँ उत्तर में मौय, गुप्त वंश तथा हर्ष के और दक्षिण में चोल और पल्लव वंश के बड़े साम्राज्य कायम हुए। दसवीं सदी के बाद भी जब भारत में मुसलमानों के आक्रमण होने लगे तब के कुछ भागों में हिंदू राज्य बने रहे। पश्चिम भारत में १६ वीं सदी में मराठे मुगलों से लोहा लेते रहे और बाद में उन्होंने जंगलों से भी टक्कर ली। लेकिन १० वीं, ११ वीं सदी के बाद से देश में हिंदू शक्ति का क्षय होने लगा और धीरे-धीरे देश में मुस्लिम आक्रमणकारियों की सत्ता कायम हो गई।

हिंदू युग में स्थापित बड़े बड़े साम्राज्यों के काल में देश में महान कलाकृतियाँ, मंदिरों, पुराण, इतिहास, काव्य और शास्त्रों की रचना हुई। महाभारत, रामायण और अन्य काव्य तथा कलाकृतियों ने भारतीय मानस पर गहरा और स्थायी प्रभाव डाला है। अतीत की इस गौरवमय परंपरा ने आधुनिक युग में देश के जागरण में योग दिया। इसका राजनीतिक महत्त्व है। किंतु इसका असली महत्त्व यह है कि इसने ऐसी सामाजिक व्यवस्था तथा ऐसी परंपरा और मूल्यों का निर्माण किया, जिन्होंने बाद के युगों पर भी स्थायी प्रभाव डाला।

इस हिंदू समाज-व्यवस्था के विकास के क्रम का हमें ठीक ठीक पता नहीं। विनायक क्षेत्र में फैले, राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के केंद्रों से दूर, तथा एक केन्द्रीय राजनीतिक सत्ता और परंपरा से विहीन भारतीय आर्यों ने ऐसी समाज-व्यवस्था का विकास किया जो उनकी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी। यह थी चार पदानुक्रमिक वर्णों की व्यवस्था, जो आर्यों के आगमन के पहले से चली आई आदिम और ढीली ढाली जातियों की व्यवस्था के ऊपर स्थापित कर दी गयी थी। यह व्यवस्था विवाह और कुटुंब के संबंधों पर आधारित थी और बहुत से गौण कार्यों को सम्भालती थी। इसमें शराब के निपटारे का कार्य भी था जो राजनीतिक कार्यों की श्रेणी में आता है। यह वर्ण-व्यवस्था कम या कामधे के बंटवारे पर आधारित थी और प्रत्येक धे के साथ उसकी मान-प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई थी। धीमे धीमे छोटी-बड़ी जातियाँ और वर्णों का यह ढाँचा कठोर होता गया और उसका एक दार्शनिक आधार और आचार भी विकसित हो गया।

### जाति-व्यवस्था

सिद्धांत रूप में चार वर्ण, गुण-क्रम के अनुसार हैं। ब्राह्मण का कार्य ज्ञान, शत्रु का रक्षा, वैश्य का उद्योग और शूद्र का श्रम है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। यथार्थ स्थिति बहुत जटिल है। जाति या विरादरी जन्मगत होती है और

विवाह-संवध जाति के अंदर ही होता है। ज्यादातर जातियाँ स्थानीय या एक क्षेत्र में सीमिती होती हैं, यद्यपि अनेक जातियाँ दूर दूर तक भी फैली मिलती हैं। इस प्रकार जातियों की संख्या चार नहीं हजारों है। हर जाति की अपनी पचायत होती है, जो जाति के नियम और आचार-विचार का नियमन करती है। गाँव की पचायत या पंच विभिन्न जातियों के भी हो सकते हैं। ऊँची जातियाँ से अलग, नीचा घटा करने वाले और अछूत समझे जाने वाले अत्यंत, हरिजन या अनुमूर्च्छित जातियाँ के लोग हैं। ये भी अनेक एक दूसरे से नीची-ऊँची जातियों में बँटे हुए हैं। अथवा होत हुए भी ये हिंदू समाज के ही अंग हैं। हिंदुआ में ही नहीं आदिवासी कबीला, विशेष अल्पसंख्यकों (जैन, सिख आदि) यहाँ तक कि ईसाइयाँ और मुसलमानों में भी जाति-व्यवस्था पायी जाती है। सब मिला कर जाति की व्यवस्था ने भिन्न भिन्न वृत्तियों के और विभिन्न नस्ल के लोगों का—जैसे आदिवासी, बाहर से आकर बसने वाले या आक्रमण करने वाले और विभिन्न मजहबों के लोगों को, एक साथ, एक धर्मनिरपेक्ष या बहुधर्मी समाज और संस्कृति के ढाँचे में लाने का कार्य किया है। छठे अध्याय में हम देखेंगे कि किस प्रकार यह कार्य, अब राजनीति में संस्थापित कर रहीं हैं। फिर भी जाति-व्यवस्था की इस भूमिका को ध्यान में रखना जरूरी है।

फिर भी अधिकांश जातियों को वर्ण के अनुसार बाँटा जा सकता है। इधर राजनीतिक उद्देश्य से कई जातियों का एक वर्ण से संगठित करने की प्रवृत्ति देखी पड़ी है। अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अनेक जातियाँ किसी ऊँचे वर्ण की होने का दावा करती हैं। इससे आधुनिक युग में भी जातिव्यवस्था के महत्त्व का पता चलता है।<sup>१</sup> ध्यान रखने की बात यह है कि जाति की व्यवस्था ने स्थानीय सामाजिक ढाँचा प्रस्तुत किया, जिसका संगठन प्रारंभिक समूहों के आधार पर हुआ जिनकी जीविका और कार्य एक दूसरे पर निर्भर थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का पद और काम जन्म से ही निश्चित होता था और जिससे आपसी झगड़ा के निपटारे की व्यवस्था के द्वारा सामाजिक एकता को बल मिलता था। ऐसी ही व्यवस्था समय के थपेड़ों, निरंतर युद्ध, बाहरी जातियों और संस्कृतियों के आक्रमण और राजनीतिक परिवर्तनों को झेल सकती थी। सैकड़ों वर्षों में जातियों के परस्पर संघर्ष या पद-पर्याया में परिवर्तन भी होते रहे। ये परिवर्तन कभी आर्थिक कारणों

१ छठे अध्याय में हमने आधुनिक लोकतंत्रीय राजनीति के प्रभाव से जातिव्यवस्था में आने वाले परिवर्तन पर विचार किया है। १९ वीं सदी में भी जनगणना करने वालों और गजेटियर का संकलन करने वालों ने छोटी जातियों में अपने को ऊँचे वर्ण की बताने का प्रयत्न देखा था। वास्तव में वह प्रवृत्ति और भी पुरानी रही होगी। १९११ की सेंसस रिपोर्ट में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और सिक्किम के विवरण में बताया गया है कि गणना अधिकारियों के पास सेकण्डे अनियॉर्ड आरिजिनमें छोटी जातियों ने अपने को क्षत्रिय या वैश्य जैसे ऊँचे वर्ण में दर्ज करने की प्रार्थना की थी।

से हुए कभी राजनीतिक कारणा से या युद्ध से, कभी प्रशासनिक कारणा से, जैम मुगला या अंग्रेजा के राज्य मे किसी जाति विशेष का राजस्व उगाटने का काम मिला, इससे उनकी प्रतिष्ठा बढ गयी । मगर जाति-व्यवस्था ने मैकडा वर्षों क इन परिवर्तना को बेला, बाहर स आने वाले नये तत्त्वा का, नए विचारो को, और नए विश्वासा को पचाया और आज भी यह ऐसी वास्तविकता है, जिसकी उपक्षा भारत की कोई भी राजनीतिक व्यवस्था नहीं कर सकती ।

### अराजनीतिक समाज

जाति-व्यवस्था पर ऊपर जा विचार किया गया, उससे पुराने भारत में समाज और राजनीति क परस्पर सम्बन्ध क एक महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश पड़ता है । इस पद्धति के द्वारा भारत में एक परिवर्तनशील और अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था तथा एक अत्यन्त स्थिर और पक्की समाज-व्यवस्था में एक हीसा सामञ्जस्य स्थापित किया गया । यह समाज-व्यवस्था (जाति-प्रथा) अधिकतर एक या अनेक गावा तक सीमित हान हुए नी स्थिरता तथा सुरक्षा प्रदान करती थी । दूसरी ओर राज्यस्तर विज्ञान क्षेत्र, विपुल सैन्यशल एवम् राजमहिमा से मडित हुए हान भी अस्थिर और अव्यवस्थित रहता था । जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा, भारत की एक बड़ी विफलता यह थी कि वह एक स्थिर केन्द्रीय राज्यतन्त्र की स्थापना न कर सका । इस दृष्टि मे भारत की परंपरागत समाज-व्यवस्था अराजनीतिक ही बनी जाएगी ।

इसका अर्थ यह नहीं कि पुराने जमाने के भारत मे राजनीति थी ही नहीं । गावा में राजनीति चलती थी, लेकिन दूसरी तरह की । यह राजनीति गाव की मुखियागिरी और दलबंदिया की था, और इसका आधार कुटुंब और बिरादरी होती थी । दूसरी राजनीति देश या प्रदेश के शासन या राज्य व्यवस्था मे संबध रखती थी जिसमें अप्रत्याशित उत्पट फेर हुआ करता था । शासन या राज्य का दमल गावा के मामलो मे हाना ना, यह झगडो का निपटारा करता था और जातिया का पद-पर्यादा में समय समय पर परिवर्तन मे भी इसका हाथ रहता था । इस प्रकार की व्यवस्था विभिन्न समूहा क परस्पर संबधा का नियन्त्रण तो करती थी, किन्तु यह एकतापद्ध राजनीतिक ढांचे का निर्माण न कर सकी ।

### स्थानीय एकता

इस प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था ने पुगने भारत में एक विशिष्ट प्रकार के आचार, प्रगल्भ विचार और मूरत का जन्म दिया, जोर उहा स गति भी ग्रहण की । इससे स्थानीय एकता की दृढ़ भावना उत्पन्न हुई । इस एकता क दो रूप थे — एक प्राथमिक समूह के प्रति निष्ठा, अर्थात् अपने परिवार

और सबधियो का साथ देना और दूसरा इससे बड़े समूह, अर्थात् गाव, कबीले या जाति के प्रति निष्ठा। इस बड़े समूह का अधिनार आर व्यवहार के प्रतिमान उस पर लागू होने थे और वह रह मानता था। प्रत्येक व्यक्ति का स्थान जन्म से ही उसकी जाति और कुल के द्वारा निश्चित रहता था। बड़े समूह में भी उसका स्थान, उसके परंपरागत पक्ष, जाति और गाव के प्रति उनके मन्त्र और परिवार के प्रति उसकी जिम्मेदारी, के द्वारा निश्चित रहता था।

उसने कतव्य भी सुनिश्चित थे। समाज ने उसे जो जिम्मेदारियाँ सौंपी थीं उनका पूरा करने के बंदे उसे सुरक्षा मिलती थी। व्यक्तिगत कमजोरियों और विशिष्टता का समूह स्थान रखता था। समूह की स्थिति पर ही उसकी स्थिति निर्भर थी। उसी के साथ वह उठती या गिरती थी। इस प्रकार समूह के अंतर्गत व्यक्तियों के पारम्परिक मान्य एवम सहयोग का आधार निर्मित होता था। प्राथमिक समूह यानी परिवार और सबधियों के अलावा बड़े समूह या समाज से भी सबध निश्चित थे। मध्यवर्ती समूह और नेता, जिस पंचायत राजस्व उगाहने वाला अधिकारी, गाव का मुखिया या पटेल आर गाव के दम्तकार, जमींदार आर वास्तकार, बनिया, धावी, भगी आदि विभिन्न वर्ग या व्यवसायी समूह भी अपना अपना काम करते थे। किसका क्या करना है यह किसी किताब में नहीं लिखा था फिर भी सबका मान्य था। सामाजिक वर्गन बहुत मजबूत थे क्योंकि ये गून के रिश्ते पर आधारित थे, जो मनुष्य के सबसे मजबूत बंधनों में हैं। सामाजिक आचार या व्यवहार इन प्रकार रिवाज या परंपरा पर आधारित था। शताब्दियों तक राजनीतिक अस्थिरता के कारण भारत में ऐसी स्थायी राजनीतिक व्यवस्था नहीं कायम हो पाई, जिसे भारतीय जनता अपना सकती, इस कारण भारतीय समाज में छोटे छोटे समूहों का प्राधान्य स्थापित हुआ जो आज भी नष्ट नहीं हो सका है।

### धर्म या नैतिक व्यवस्था

रीतिरिवाज और परिवार तथा समाज के बंधन को धर्म या नैतिक व्यवस्था से और बल मिला। धर्म शब्द अंग्रेजी के "रिलिजन" से अधिक व्यापक है। इसमें व्यक्तिगत, सामाजिक, नैतिक और धार्मिक सभी प्रकार के कतव्य आ जाते हैं। इसमें यह सब आ जाता है कि कितनी स्थितियों में आदमी किस प्रकार व्यवहार करे, अपने रिश्तेदारों और अन्य लोगों के प्रति, बड़े और छोटे के प्रति, पति पत्नी के प्रति, गरीब, वृद्ध, असहाय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, जमींदार चमार, भगी, नौकर, धर्म, ईश्वर और स्वयं अपनी आत्मा के प्रति क्या व्यवहार करे। हर स्थिति का, हर व्यक्ति का निश्चित व्यवहार, धर्म है। सबके लिए और सब स्थितियों के लिए एक-सी नैतिक संहिता की कल्पना हिंदू जीवन पद्धति से नहीं होती। धर्म का अर्थ विभिन्न परिस्थितियों में सही व्यवहार है, यही सदाचार का आधार





के कारण इस व्यवस्था को बल मिला, क्योंकि इनके कारण देश में स्थिरता आई, उद्योग व गित्त को बढ़ावा मिला। मठों और नहरों वनी, कला, साहित्य और धर्म के क्षेत्र में बड़े बड़े काम हुए। राजनीतिक और सांस्कृतिक उत्कर्ष के इन युगों में ब्राह्मणों का भी शक्ति बढ़ी और मनुस्मृतिको माहित्य की समृद्धि में उसने बहुत योगदान दिया। ब्राह्मण ही हिंदू समाज के नेता थे इसलिए इनके उत्कर्ष ने हिंदू समाज-व्यवस्था की मजबूती बढ़ी।

### उच्चका की भूमिका

ज्ञान और मनुस्मृति के प्रकार में ब्राह्मणों की भूमिका अत्यंत महत्व की रही है। समाज में उच्चका स्थान सब से ऊँचा था। यह परिवार का पुरोहित था, वही विद्यादान करता था, गान्धर्व, स्मृतियाँ और परंपरागत नियमों और विधिविधानों की वही व्याख्या करता था, पीढ़ी दर पीढ़ी यह पुरानी परंपरा और आचार विचार को जीवित रखता था। समाज के नेता, शिक्षक, स्मृतिदाता और व्यापारिक के रूप में ब्राह्मण वर्ग का जो ऊँचा स्थान, प्रतिष्ठा और प्रभाव प्राप्त था, उससे विभिन्न जातियों के समूहों में बड़े अनेकार्थक हिंदू समाज का एक सामान्य सामाजिक पद्धति, प्रतीक और परंपरा मिली। इस उच्चका की आंतरिक एकरा किसी शास्त्रीय सिद्धांत के बल पर नहीं, उनके विशिष्ट जन्म, शिक्षा-दीक्षा, समाज के नेतृत्व और इन कारणों से समाज में उसकी उच्च स्थान और प्रतिष्ठा के बल पर कायम थी। उसकी प्रतिष्ठा ज्यादातर शास्त्र और दर्शन की व्याख्या में प्रकट होती थी। उसकी व्यवस्था या नियम का बहुत सम्मान किया जाता था। ऐसे बौद्धिक और शिक्षक वर्ग के नेतृत्व के कारण सैकड़ों वर्षों तक हिंदू समाज आपस में बँधा रहा और सान सौ वर्षों के विदेशी शासन के धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व के घत्ता को घेन सका।

### सुधार और परिवर्तन

ब्राह्मणों ने हिंदू समाज की रक्षा की, किंतु उनमें कट्टरता और रुढ़िवाद की प्रवृत्ति भी आ गयी और वे समय के अनुसार आवश्यक परिवर्तन और सुधार की व्यवस्था न कर सका। यह कार्य जोरा ने किया। इनमें क्षत्रिय जाति के बुद्ध और महावीर प्रमुख थे। इनके समय से लेकर आधुनिक काल तक धर्म सुधारकों की एक अटूट परंपरा चली आई है। धर्म-सुधार के इन आंदोलनों और इनके फल-स्वरूप स्थापित अगणित मतमतान्तरों ने भारतीय सभ्यता के संवर्धन में ही नहीं उसकी जीवित रखने में भी योग दिया है। इनसे हिंदू समाज की प्राणशक्ति बढ़ी है और उसे नई बातों और भिन्न विचारों को ग्रहण करने की सामर्थ्य मिली है। इससे हिंदू समाज के बुनियादी ढाँचे में मजबूती और लचीलापन आया है।

गामक जाग पुराहित वगैरे प्रभाव से हिन्दू धर्म में जो कमकाड़ और आडंबर आ गया था उसमें विरुद्ध इन सुधारकों ने आवाज उठाई। इन आंदोलनों में आधुनिक काल के लिए सबसे महत्वपूर्ण भक्ति आंदोलन था। इस आंदोलन के नेता सत और भक्त थे जिनमें से अनेक बहुत गरीबी की जातियाँ के थे। ये सत देश के सभी भागों में हुए इनमें छोटे और गरीब लोग व स्त्रियाँ भी थी। इनमें मीरा वगैरे जैसी राजरानी भी थी जो महाना का छोटा भक्ता के साथ राह-बाट की खाक छानती फिरी। भक्ति-आंदोलन के फलस्वरूप अनेक नए पथ व संप्रदाय चले जिनमें बहुत बड़ी संख्या में साधारण जनता शामिल हुई। ऐसा ही एक पथ 'सिख' पथ था जिसने अत्याचारा का सामना करने के लिए सैनिक रूप धारण किया और जिसके जनसामान्यों ने भारत में आधुनिक अखिल भारतीय प्रसार में बहुत योगदान दिया है। भक्ति-आंदोलन के अनेक प्रवर्तक दक्षिण भारत में भी हुए जिनके उपदेश भारतीय मानस में जग है। प्रादेशिक सीमाओं का नाश और संस्कृति के वजाय लोकभाषा का सहारा देने के कारण भक्ति-आंदोलन ने सांस्कृतिक और राजनीतिक एकता की भावना पैदा की जो विरोध के आन्दोलन के लिए दुर्लभ बात है। जात-पात का विरोध करके और मनष्य की समानता पर जोर देकर भक्ति-आंदोलन ने आधुनिक युग में समानता के सिद्धांत का रचना तैयार किया।

इस प्रकार अपनी समाज व्यवस्था पुनर्गठित और महाकाव्यों के आदर्श ब्राह्मण वगैरे के नतत्व और महान धार्मिक आन्दोलनों के कारण हिन्दू धर्म में एकता और निरंतरता का भावना बनी रमा। भारत एक राष्ट्र बन ही न बन सका हो कि उसने एक समाज और सभ्यता का निमाण अंश किया और भारतीयों में यह भावना काफ़ी व्यापक था। इस गहरी एकता और आत्मबोध या अस्मिता के बिना अग्रज गानका और राष्ट्रीय नेताओं का निर्गमन की राजनीतिक एकता की स्थापना आसान न होगी। दूसरी ओर इस एकता की भावना के बावजूद और इसके विशिष्ट स्वभाव के कारण पूरे हिन्दू युग के दौरान समाज और राजनीति का पाषण्य बना रहा। इसका अर्थ यह था कि राष्ट्रपरिवर्तन का प्रभाव समाज के जीवन पर ज्यादा नहीं पड़ा था। साम्राज्य का उत्थान और पतन होता रहा लेकिन भारतीय समाज का अधिकांश अपने रास्ते पर चलता रहा। एक केन्द्रीय सत्ता और निष्ठा की स्थापना का कार्य अधूरा ही रहा। मुस्लिम आक्रमण और उनके लंबे शासन ने इस व्यवस्था में गड़बड़ी जरूर पड़ी थी, किंतु बुनियादी तौर पर वह इस बदल न सका।

मुस्लिम प्रभाव

मुसलमानों (जैसे अफगान, मुगल) के छिटपुट आक्रमण ८वीं शताब्दी में सिंध में शुरू हुए। १० वीं और ११ वीं सदी में ये आक्रमण तेज हो गए और

१२०६ ई में दिल्ली सल्तनत कायम हुई। मुस्लिम सत्ता का चरम उत्कृष्ट मुगल साम्राज्य (१५२६ ई - १७०७ ई) में हुआ। १८५७ तक नाम के लिए मुगल बादशाह कायम रहे। सन् १८६२ में मुगल शासन का विधिवत अंत हो गया।

इस युग की चार बातें ध्यान योग्य हैं। पहली यह है कि मुस्लिम राज्य बुनियादी रूप में सैनिक शासन था, यद्यपि इमने देश में नागरिक शासन की भी अच्छी व्यवस्था की। मुस्लिम शासन काफी समय तक कायम रहा फिर भी यह सारे देश को एक राजनीतिक सत्ता के अधीन न ला सका। राज्य के विस्तार के लिए निरंतर युद्ध होते रह, जिससे बड़ी बरबादी और अन्यवस्था पैदा हुई। यद्यपि १६७७ से लेकर १७०७ तक मुस्लिम सल्तनत काफी मजबूत और स्थिर रही, किंतु इसके साथ ही गद्दी के लिए पड़यत्न और लड़ाइयां जारी रही और बादशाहत को राज-पूना और मराठा के अलावा विद्रोही मुस्लिम मूबेदारों की चुनाती का सामना करना पड़ा।

दूसरी बात यह है कि मुसलमानों का मजहब और समाज-व्यवस्था हिंदुओं से बिल्कुल भिन्न थी। यद्यपि अधिकांश मुस्लिम शासक चाहते थे कि दोनों मजहब साथ साथ रहें, शास कर अकबर हिंदू मुस्लिम मेल का सबसे बड़ा समर्थक था, फिर भी मुस्लिम मजहब अपनातेवालों को फायदा होना था और मुस्लिम धर्म-प्रचारक, सूफिया और मौलवियों को धर्मांतरण कराने की खुली छूट थी। खास कर उत्तर भारत में मुस्लिम धर्म का काफी प्रचार हुआ। बीच बीच में बटुटर मुस्लिम शासकों के राज में धार्मिक अत्याचारों की लहर उठती थी और इसके कारण दोनों मजहबों में झगडा और नफरत फैलती थी। भारत की परंपरागत धर्म-सहिष्णुता को इससे धक्का लगता था। और दोनों मजहबों में सामाजिक व्यवहार और एकता स्थापित न हो सकी। फिर भी दोनों मजहबों ने एक दूसरे को प्रभावित अवश्य किया। मुसलमानों में भी खास खास पंगु वाली जातियां बन गईं और इससे वे हिंदुओं के ज्यादा नजदीक आए—खास कर मुस्लिम सत्ता के कमजोर होने के बाद। दूसरी ओर हिंदुओं ने भी मुसलमानों के बहुत से तौर तरीके, कला-कारीगरी, शासनपद्धति, दरबारी शिष्टाचार आदि अपनाए। मुगल शासन में राजपूत सेनानायकों और हिंदू दीवानों का बड़ा सम्मान था। शहर मुस्लिम साहित्य, स्थापत्य और कला के केन्द्र बन गए और शिक्षित हिंदुओं ने इस सभ्यता में योगदान किया। लेकिन इसके बावजूद दोनों धर्म और समाज एक दूसरे से अलग रह, क्योंकि मुस्लिम सत्ता की नींव धर्मपरिग्रत नगर सैनिक बल के ऊपर कायम थी।

तीसरी बात भारत में मुस्लिम शासन पद्धति के विकास से संबंध रखती है। इन्होंने एक विशिष्ट राजनैतिक पद्धति एक आधिकारिक केन्द्र और व्यापक एवं काय-कुशल शासन-प्रणाली स्थापित की जिसमें केन्द्रीय सत्ता के अंतर्गत सूबों और जिलों में राजस्व की वसूली और प्रशासन के लिए बड़े और छोटे अधिकारीतन्त्रात किए

गा। इनका पद सैनिक होता था और इनको शासन में बाकी स्वतन्त्रता रहनी थी। इससे अक्सर ये अपनी ताकत बढ़ा कर खुदमुस्तार बन बैठते थे। अंग्रेजों ने मुस्लिम शासन-व्यवस्था को बहुत सी बातों का जारी रखा, लेकिन उन्होंने इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। यह था सैनिक शासन को नागरिक शासन से अलग कर देना और नागरिक या दीवानों शासन में अधिक एकरूपता लाना। ये दोनों बात अंग्रेजों की राजनीतिक परंपरा में थी।

चौथी बात यह है कि मुस्लिम प्रभुत्व और शासन व्यवस्था का प्रभाव गांधी में रहने वाली जनता की रहन सहन, रीति रिवाज और उनकी सम्प्रादाय पर बहुत कम पड़ा। अधिकतर पुराना सामाजिक और व्यावसायिक ढांचा बचता रहा। गांधी का प्रबंध पंचायतों के हाथ में बना रहा। नए शासक और मालगुजारी के बंदोबस्त से संप्रति होने के कारण कुछ जातियाँ और वर्गों की पद-मर्यादा घटी बढ़ी किन्तु इन प्रकार का सामाजिक परिवर्तन पहले भी होता रहता था। इससे समाज और राज्य के ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होता था। वैदेशीय सत्ता स्थानीय सम्प्रादाय के अधिकांश पायों में कोई दखल न देती थी। गांधी में रहने वाली मुस्लिम जनसंख्या ने भी इस पद्धति का अपना लिया और उनमें भी अलग अलग पैग़ाब हिमाय से जातियाँ और पंचायत बन गई। मुसलमान शासकों ने मालगुजारी के बन्दोबस्त तहसील आदि के लिए प्रशासन की बाकी अच्छी व्यवस्था का विकास किया, फिर भी यह देश की जड़ तक या माथारण जनता तक न पहुँच सकी। परदेही होने के कारण मुस्लिम शासन ज्यादातर बाहरी में केंद्रित रहा। दूसरे स्थानीय गांधी इतनी मजबूत से जमी हुई थी कि उन्होंने बंदीय शासन को अपने ऊपर हावी न होने दिया। तीसरे मुसलमानों ने क्षत्रियाँ जैसी पुरानी शासन जाति का विकास न किया। यह सातताना तिराज या कर लेकर, सूबा और जिला का शासन और फौजी प्रबंध ज़मींदारों या सूबेदारों का सौंप दत्त थे, जो समय समय पर बदला करते थे।

### हिंदू धर्म पर प्रभाव

मुस्लिम शासन की स्थापना में हिंदू प्रजाती का आंतरिक समुत्पन्न भग्न हो गया। दंग में जो हिंदू राज्य कायम थे, गायब कर दिये और दखिना में, उनमें मुगल साम्राज्य के अन्तर्गत मुद्रा हासिल रहे। इन मुद्रा से और इनके पाम्पहण होना बाकी गुटसाट, अन्धकार मंत्रियों का साहचर्य आदि से माथारण जगता भग्न रहती था। जगता में अन्धकार और दंग में अस्थिरता और भय बराबर बना रहता था। भग्न हिंदू समाज का शोषण अग्रगण्य हुआ गया और उसके धार्मिक व सामाजिक नेता आत्मसंश्लेषण से बँटे। दंग स्थिति में जब हिंदू समाज की रक्षा करने वाली राजनीतिक शक्ति न रही जाति और विराटों के बीच। उन कुछ महात्मा जिन्होंने

पराजित और लाछिन हिंदू जाति ने भगवान का सहारा लिया और परनोक पर ध्यान लगाया। उसकी जीवनी शक्ति, दूसरा का आत्मसात कर लेने की क्षमता मारी गयी, जान-पात के ढाँचे में बड़ी कठोरता आ गयी और उसकी दृष्टि निराशावादी और भाग्यवादी हो गई।

मुस्लिम प्रभुत्व का घबका बड़ा जबदम्न था किन्तु इसका प्रभाव स्थायी न रहा, सिवा इसके कि देश भर में मुसलमानों की संख्या बहुत बढ़ गई। गहरी प्रभाव या घबके की झेलने का हिंदू समाज का अपना तरीका है। या तो वह बाहरी तत्वा को अपने भीतर पचा लेता है, या जहाँ ऐसा संभव नहीं है, यह उसका सीधा मुकाबला करने के बजाय अपने हाथ पाव सिकाड़ कर, उनके वेग को अपने आप खतम होने का इंतजार करता है। २ ब्रिटिश प्रभाव का भी उसने इसी प्रकार खेलने का प्रयत्न किया। मुस्लिम घबके ने जो अव्यवस्था और आंतरिक अगाति फैली थी उसको अंगरेजी राज ने अपनी सुव्यवस्थित शासन प्रणाली में दूर दिया।

मुस्लिम राज के स्थायी प्रभावों में एक ही सांप्रदायिक समस्या। मुसलमानों का प्रभुत्व के समय दोनों संप्रदायों के नेताओं में शत्रुता और द्वेष का भाव था, यद्यपि साधारण जनता एक दूसरे के पास आ रही थी। अंग्रेजी राज्य में स्थिरता आई, और हिंदू मुसलमान साथ साथ रहना सीख गये उनके अपने अपने काम धंधे और प्रभाव क्षेत्र बन गए और अनेक क्षेत्रों में वे साथ मिल कर काम करने लगे। लेकिन अंगरेजी राज के उत्तराध में राष्ट्रीय स्तर पर विरोध और अन्याय पैदा हुआ और सांप्रदायिक संघर्ष विगड़ गए। इसी में सांप्रदायिक अन्याय का समस्या पैदा हुई। इसका अध्ययन इसी अध्याय में हम करेंगे।

मुस्लिम प्रभुत्व का दूसरा परिणाम उसका पतन के बाद हिंदुओं में उसकी प्रतिक्रिया या हिंदू जागरण के रूप में प्रकट हुआ। इस जागरण में अंग्रेजी राज का भी योग था और पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति का भी प्रभाव था। अंग्रेजी शासन में शांति और स्थिरता कायम हुई और पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार हुआ। इसी के साथ साथ संस्कृत अध्ययन का भी बल मिला और देश की प्राचीन संस्कृति के लिए गौरव का भाव बढ़ा। इसमें संस्कृत का मूलापीय विद्वानों ने भी योग दिया। हिंदू पुनर्जागरण के साथ साथ पाश्चात्य संस्कृति का भी प्रभाव बढ़ा। मुसलमानों जमाने की अव्यवस्था और दमन के बाद ये दोनों धाराएँ हिंदू जागरण और पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार, सुविष्ट और आगे का मार्ग स्वर आदि।

### अव्यवस्था का युग

कृत मिला कर मुस्लिम युग का प्रभाव बहुत गहरा या व्यापक नहीं रहा।

२ राजाजी वर्मा और जीतेंद्री जीने गिन विचार वाले ने उसे न इस प्रशंसा का पत्रा बो है। शास्त्री का, 'हिंदू संस्कृति का संस्कृत' (पूना १९६१) और 'हिंदू संस्कृति का संस्कृत' (दुर्गा, १९६६)

सामाजिक परंपरा या अधिकांग जनता व मन में इसकी जड़ गहरी न जा सकी।<sup>3</sup> किंतु सामाजिक ढांच, शासनात्मक, कला व साहित्य तथा उच्च वर्ग की रहन सहन और सहजीव या शिष्टाचार पर इसका प्रभाव प्रचण्ड है। वास्तव में मुगल साम्राज्य का अंत १७०७ में औरंगजेब की मृत्यु के समय हो गया और इसी समय से यूरोपीय गतिविधियाँ ने अपने राज्य का प्रसार करना शुरू कर दिया। पुरी १८ वीं और १९ वीं शताब्दी के प्रथम भाग में राजनीतिक गड़बड़ी कायम रही, भारतीय गतिविधियों का पता आज यूरोपीय गतिविधियों का उत्थान होना रहा। १५० वर्ष के मुगल शासन में केन्द्रीय सत्ता की शक्ति बढ़ी किंतु उसे लगातार चुनौतियाँ का सामना करना पड़ा और अंत में मराठा ने प्रतिरोध ने उसे जबरन कर दिया। उसके कमजोर पड़ने ही उसके प्रांतीय सूत्रेदारों और जागीरदारों ने भी मिर उठाया। इस प्रकार मुगल युग के अंत में भारत में कोई केन्द्रीय शक्ति नहीं रही और वह आपस में लड़ने वाले छोटे राज्यों में बँट गया। इस स्थिति में युरोपीय गतिविधियों की वन आई और मुगल साम्राज्य के गल्ले पर अंग्रेजी साम्राज्य कायम हुआ।

### ब्रिटिश प्रभाव

भारत में पश्चिमी प्रभाव कई चरणों में आया। (१) पहला चरण में १५ वीं, १६ वीं और १७ वीं शताब्दी में पुर्तगाली, डच फ्रांसीसी और अंगरेज व्यापारियों ने हिंद महासागर में प्रवेश किया और अपनी व्यापारी कौटिल्याय व वस्तुधारा कायम की। (२) ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसियों का हरा कर (यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध से लाभ उठा कर) यहाँ अपनी प्रधानता कायम की। इसके बाद कंपनी ने जबरन मुगल साम्राज्य से व्यापक व्यापारी मुक्तिवाए बड़े बड़े क्षेत्रों पर आधिकार और प्रशासनिक अधिकार प्राप्त किए। इसके बाद उसने कुछ भारतीय राज्यों से सहायक संधि कर के आर एव एव करके मराठा टीपू सुलतान और अंत में सिंधु को हरा कर, भारत पर अपनी प्रभुता कायम की। (३) १८५७ के विद्रोह के बाद कंपनी के स्थान पर ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन (रानी और पार्लामेंट) स्थापित हुआ। वास्तव में कंपनी और ब्रिटिश सम्राट के शासन को एक ही समझना चाहिए। फिर भी १८५७ के विद्रोह से एक नया युग शुरू होता है।

### १८५७ का विद्रोह

१८५७ का विद्रोह न तो मात्र ब्रिटिश सेना के हिंदुस्तानी सिपाहियों का

३ इसमें कुछ अपवाद भी हैं। उत्तर पश्चिम भारत में जहाँ सरहदों की परंपरा बहुत गहरी नहीं गई थी, इस्लाम ने हिंदू संस्कृति को नष्ट कर दिया और आज भी यहाँ इस्लाम परंपरा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। देखिए डी. आर. चानन, 'सरहदों' पेशान, वेस्टनी इन्डियन रेंड इंडियाज नार्थ वेस्ट' इतिहासिक वीकली, भाग १३, म. ९, भाग ४, १९६१

गदर था न यह स्वतन्त्रता का सपना था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने माल-गुजारी, अदालत, कानून, शासन और आर्थिक संगठन, व्यापार आदि की जा नहीं ब्यवस्था चालू की थी, उससे नए अधिकार प्राप्त वर्गों का उदय हुआ और पुरानी सामंती व्यवस्था की चले हिल गई। इसकी गहरी प्रतिक्रिया १८५७ के विद्रोह में हुई। इस विद्रोह में अधिकतर उत्तर भारत के मुस्लिम, नवाब, जागीरदार और तालुकेदार वर्ग के लोग शामिल थे, जिनकी शक्ति और प्रभाव फिरंगियों ने छीन लिया था। अवश्य ही इस विद्रोह में अनेक हिंदू राजा और तालुकेदार भी थे। विद्रोह विफल रहा और अंग्रेजों ने बड़ी कूरता से विद्रोह का दमन किया, इससे अंग्रेजों के प्रति बहुत कटुता, खासकर मुसलमानों में पैदा हुई। अंग्रेजों ने भी १८५७ के तुरंत बाद मुस्लिम विरोधी हथ्थ अपनाया। फिर भी इस विद्रोह का जितना प्रभाव अंग्रेजों के मन पर हुआ, उतना भारतीयों पर नहीं। उत्तर भारत के बलावा शेष भाग में इसका प्रभाव नहीं पड़ा था। इस विद्रोह से अंग्रेजों के मन में यह भाव आया कि उनका राज्य स्थायी नहीं है और वे भारतीयों पर शक और अविश्वास करने लगे। भारत में सुधार और नई व्यवस्था और सम्मति लाने में उनको उत्साह न रहा। भारतीयों के मन में भी १८५७ की याद बनी रही और वे भी यह समझने लगे कि अंग्रेज अजेय नहीं हैं। यद्यपि १८६७ का विद्रोह पुरानी सामंती व्यवस्था की पराजय का द्योतक था फिर भी उससे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के आंदोलन की प्रेरणा मिली। १८५७ के विद्रोह में अंग्रेजों ने भारतीयों की धार्मिक भावनाओं से छेड़छाड़ न करने का भवक सीखा और सन १८५८ में मलका विकटोरिया की घोषणा में यह आश्वासन दिया गया कि भारतीय जनता की पर-पराया का सम्मान किया जाएगा और शासन की उदार बनाया जाएगा। मगर जितनी ही भारतीय जनता को सन्तुष्ट करने की कोशिश की उतना ही उसका असंतोष बढ़ता गया। १८५७ के बाद अंग्रेजी शासन ज्यादा अच्छा और कुशल हो गया किन्तु जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया और उसकी जड़ें गहरी नहीं जा सकी। १८५७ के विद्रोह ने अंग्रेजी राज्य के विरोधाभास को स्पष्ट कर दिया। यद्यपि इसका प्रभाव प्रातिमर्सी था, फिर भी इसने प्रतिनिध्यावाद और विद्रोह को जन्म दिया।

### अंग्रेजों शासन का प्रभाव

अंग्रेजी राज का प्रभाव प्रातिमर्सी था परन्तु वह गहरा न था क्योंकि वह विदेशी था। फिर भी यह बड़ा गतिविधायी और स्थिर था। जगले अध्याय में हम भौतिक-वैज्ञानिक या विदेशी शासन के प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि भारत की उसकी क्या देन रही।

राष्ट्रीय सत्ता की स्थापना — अंग्रेजों ने पहली बार मारे दंग में एक दिनांक



के द्वीय शासन स्थापित किया, जिसके जतगत बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से मुक्ति मिली। यद्यपि देश के एक तिहाई भाग में देशी राजा-जा का राज्य कायम रहा, पर वे भी पूरी तरह ब्रिटिश प्रभुसत्ता के अधीन थे। यह बहुत बड़ी सफलता थी और अंगरेजी राज्य ने भारत में और जो कुछ किया, उसकी यही बुनियाद थी। भारत की राष्ट्रीय एकाता भी इसी बुनियाद पर निर्मित हुई।

### कानून और व्यवस्था

मुस्लिम काल में निरंतर लड़ाइयाँ के कारण देश में बड़ी अशांति और भय छा गया था। अंगरेजी शासन की स्थापना के बाद शांति और कानून की व्यवस्था हुई। इसलिए बहुत से लोगो ने जीर लेखकों व कवियों ने भी अंगरेजी राज का स्वागत किया।

प्रशासन और 'पाय की नई पद्धति — अंगरेज पहली बार सारे देश को एक सत्ता के नीचे लाने में सफल रहे। मुगलों के समय में जिस तरह देश सूबों और जिलों में बंटा था, अंगरेजों ने उसको कायम रखा और उसे एक नया रूप दिया। सबसे महत्त्व का सुधार उन्होंने यह किया कि इसको उठाने नागरिक या असेनिक रूप दिया। जिले का अधिकारी केंद्रीय शासन का नौकर था। उसे कोई सैनिक अधिकार न था, न वह प्रजा का शोषण करने अपना अधिकार बढ़ा सकता था। अंग्रेजों ने भारत में आधुनिक ढंग की नौकरशाही या अधिकारीवर्ग कायम किया, जिसमें नियुक्ति योग्यता के आधार पर खुली परीक्षा लेकर होती थी। ब्रिटेन से भी पहले भारत में यह तरीका लागू किया गया। इसके फलस्वरूप आई सी एस (इंडियन सिविल सर्विस) की सृष्टि हुई। पहले इसमें सब अंगरेज अफसर होते थे, बाद में भारतीयों को भी लिया जाने लगा। इनका चुनाव बड़ी सावधानी से होता था और योग्यता तथा विद्या-बुद्धि के साथ ऊँचे कुल का भी विचार किया जाता था इन लोगों का जिला में अमन कानून बनाए रखने का, राजस्व वसूली का और 'पाय का भार सौंपा गया।

आई सी एस के आदमी जिले के शासक ही नहीं थे वे 'पाय भी करते थे। धीमे धीमे ब्रिटिश 'पाय के सिद्धान्त, नियम नज़ीर और प्रक्रिया पर आधारित अदालतों की नई व्यवस्था स्थापित की गई। इसके बाद जनता की भलाई के उद्देश्य से सामाजिक और आर्थिक प्रशासन का भी ढाँचा खड़ा हुआ और अत्यधिक अन्धायपूर्ण विषमता का घटाने के लिए कुछ सुधार भी किए गए। ४ इससे शासन में नए विचार और नई दृष्टि आने लगी जो बदलते हुए समय के ज्यादा अनुरूप थी।

४ यह धारणा ठीक नहीं है कि भारत में अंग्रेजी शासन का महत्व केवल शांति और कानून की व्यवस्था करने से था। इस शासन ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी बहुत से काम उठाए जिनका सभी वर्गों पर प्रभाव पड़ा। स्वतंत्रता के बाद जो काम हुए हैं उनमें से अनेक की शुरुआत अंगरेजी राज के समय में ही हो चुकी थी।

मध्यमवर्ग का जन्म - १८३४ में मैकाले के प्रसिद्ध नोट के फलस्वरूप ब्रिटिश राज ने अपना सबसे महत्वपूर्ण निणय किया। यह था अंग्रेजी माध्यम से हाईस्कूल और कालेजों में शिक्षा देने का। इसके पहले भी पारचात्य सभ्यता से आकृष्ट होकर अनेक व्यक्ति अंग्रेजी सीखने और अंग्रेजी के काव्य, साहित्य, कानून और विज्ञान के ग्रंथों को पढ़ने लगे थे। अब ऐसे लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई। ध्यान रहे कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने का फैसला जनता की इच्छा के खिलाफ नहीं किया गया। राजा राममोहन राय और अन्य बहुत से भारतीयों ने इसकी मांग की थी। इस शिक्षा ने अंग्रेजी पढ़े लिखे एक नए वर्ग की सृष्टि की, जो पारचात्य सभ्यता और राजनीतिक विचारों से प्रभावित था और अंग्रेजी अफसरों के नीचे काम करने को तैयार था। बहुत से अंग्रेजी शिक्षितों ने वकालत का पेशा अपनाया। कुछ अध्यापक हुए और कुछ व्यापार, उद्योग में लगे। थोड़े में भारतीय उच्च शिक्षा प्राप्त करके आई सी एस बनने की आकांक्षा में इंग्लैंड भी पहुंचे। अनेक भारतीयों ने डाक्टरों और पत्रकारों की वृत्ति शुरू की और कुछ ने राजनीति में प्रवेश किया। ५

यह भारत का नया मध्यवर्ग था। इस वर्ग के जरिये अंग्रेजों ने भारत पर राज किया। इसी वर्ग के जरिये व्यक्ति की स्वतंत्रता और वैधानिक शासन के विचार फैले और इसी वर्ग से अंग्रेजी राज को चुनौती देने वाले राजनीतिक नेता उठे। इस वर्ग का देश पर व्यापक प्रभाव पड़ा। अंग्रेजी शिक्षा की उपज और स्वतंत्रता, लोकतन्त्र तथा समाजवाद के विचारों से प्रेरित यह वर्ग ब्रिटिश राज की सबसे बड़ी विरोधता है। इसी वर्ग ने अंत में अंग्रेजों से सत्ता ग्रहण की और भारत को स्वतंत्र लोकतन्त्री राष्ट्र घोषित किया।

### सामाजिक सुधार-

भारत में आधुनिकता का प्रचार एक छोटे से अंग्रेजी पढ़े लिखे वर्ग के द्वारा हुआ। इसी से देश की एक बहुत बड़ी समस्या-शिक्षित उच्च वर्ग और साधारण जनता में दूरी की समस्या-पैदा हुई। आगे हम इस पर विचार करेंगे। इस बीच यह बात ध्यान में रखने की है कि इसी वर्ग के साथ साथ भारत में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों की ओर अंत में अंग्रेजी राज से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग भी उठी।

सबसे पहले हिंदू समाज की कुरीतियों को दूर करने का आंदोलन उठा। इस विषय में उदार अंग्रेज शासकों के विचार भारतीय नेताओं से मेल खाते थे। वास्तव में ये सुधारक हिंदू समाज की बुराईयों को दूर करके उसके प्राचीन गौरव

५ इस मध्यवर्ग के उदय के ऐतिहासिक विवरण के लिए देखें-बी.बी. मिश्र, 'द इंडियन मिडिल क्लासेज - देयर ग्रोथ इन मॉडर्न इंडिया' (लंदन, १९६१)

का पुनरुद्धार करना चाहत थे। सुधार के सबसे पहले कदम लाड विलियम बैंटिंक के शासन में उठाए गए जो १८२८ से १८३५ तक यहाँ के गवर्नर जनरल रहे। इन सुधारों के लिए राजा राममाहन राय जैसे भारतीय सुधारकों ने जोर दिया था। इन सुधारों में सती प्रथा और नवजात बच्चा की हत्या का अंत और ठगों का उन्मूलन था। लड़कियों का वध और नरबलि को अपराध घोषित कर दिया गया। अपराधों के फैसलों का काम पचायना के हाथ से ले कर नवस्थापित अदालतों को सौंप दिया गया। स्त्रियों पर अत्याचार पर भी राक लगाई गई।

१८५७ के विद्रोह से अंग्रेज शासकों और भारतीय सुधारकों के जोश पर रोक लगी। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथ में चल गया और उसने लोगों के रीति रिवाज और आचार विचार में दखल न देने की नीति अपनाई। अब से यह नीति चली कि सुधार सरकारी कारवाई के द्वारा नहीं, स्वयं भारतीय नेताओं के प्रयत्नों से किए जाएँ। यद्यपि पहले भी सुधार की कारवाई, भारतीय नेताओं की मांग पर ही की गई थी परन्तु अब सामाजिक और धार्मिक सुधार के क्षेत्र में सरकारी कारवाई उत्तरोत्तर कम होनी गई।

### विदेशी शासन का रवया

ध्यान रखना चाहिए कि भारत में विदेशी सरकार का कार्यक्षेत्र क्रमशः सिकुटता गया। विदेशी शासन के नातिकारी प्रभाव के बावजूद उसमें भारतीय समाज के पुनर्निर्माण की न तो क्षमता थी और न ही इच्छा। इसने आधुनिक नौकरागारी और कुशल शासन-तंत्र की स्थापना की तथा लोक-श्रम-व्यवस्थाकारी शासन का भी बीज डाले, किंतु व्यापक सामाजिक और आर्थिक प्रश्नों पर इसका रुख आँदुवार और दकियानूसी ही रहा। और यह ऐसे समय जब समाज में बड़ी उथल-पुथल हाँ रही थी। १९ वीं सदी के उत्तरार्ध और २० वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ी मगर खेती की पैदावार उतनी नहीं बढ़ सकी। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय भी नहीं बढ़ी, बल्कि, कुछ गिर गई। पुराने घरेलू उद्योगधंधे, नई मिलों और बड़े कारखानों के कारण बरबाद हो रहे थे। इन सब से देश में अभाव और कष्ट बढ़ा। इसी अवधि में शहरों का विस्तार हुआ रेल और डाक-तार का सुविधाएँ बढ़ा, विचारों के प्रचार के साधन अखबार और छापाखानों की संख्या बढ़ी मध्यवर्ग का विकास हुआ और नई संस्थाएँ तथा संगठन बने। इस प्रकार समाज के पुनर्निर्माण की जमीन तैयार हुई।

देश में एक जोर अभाव और कष्ट बढ़ रहे थे तो दूसरी ओर उनको दूर करने के अवसर भी प्रस्तुत हो रहे थे, किंतु अंग्रेजी शासन ने कुछ न करने की नीति अपनाई। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि वह राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं सामाजिक क्षेत्र में भी, अकम्प्य और अनुदार है। ब्रिटिश सरकार का यह सोभाग्य था कि

जनता के कष्ट और कमजोरी ने दिखाए कि मांग न पकड़ कर राष्ट्रीय जादानवा का मांग पकण। ब्रिटिश सरकार ने तीन सामाजिक ममन्ताओं की उपाय की, उन्हें मुनताने का भार १९८७ के बाद भारत की स्वतंत्र सरकार पर आया।

### आधुनिकता के प्रयास

आधुनिकता के प्रयासों में राजा राममोहन राय (१७७४-१८३३) प्रमुख थे। वे अरबी, फारसी और मराठी में विद्वान थे तथा ग्रीक और हिंदू भाषाएं भी जानते थे। अंग्रेजी उठाने बाद में पढ़ी। व मूफ़ी मत और बापू म ईसाई धर्म से प्रभावित हुए। उन्होंने हिंदू धर्मनाम, और ईसाई धर्म की अच्छी बातों और पारश्चात्य उदारवाद के तत्त्वों का मिलाने का प्रयत्न किया। वे जातपात और स्त्रियाँ के साथ दुष्प्रवृत्तियों के आलोचक थे। व अंग्रेजी शासन के अयमकन न थे, किंतु यह मानते थे कि उन्ने भारत की नाम हुआ है। उन्होंने अपने देवामिया के बीच पश्चिमी उदारवाद के विचारों और राजनीतिक सिद्धांतों का प्रचार किया। मगर उनका सब से बड़ा काम धार्मिक सुधार में हुआ। उन्होंने ब्राह्म समाज की स्थापना की, जिसमें धार्मिक और उदार सामाजिक विचारों का मेल हुआ। ब्राह्म समाज ने भारत के बौद्धिक और सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और उसकी दगा देखी भारत में अनेक धार्मिक और सामाजिक संस्थाएँ स्थापित हुई।

### संस्था और संगठनों की वृद्धि

राममोहन राय और ब्राह्म समाज के बाद भारत में विशेष कर १९ वीं सदी के उत्तरार्ध में अनेक समाज और धर्मसुधारक हुए और नई संस्थाएँ कायम हुईं। सब का नाम देने की यहाँ जगह नहीं। इनमें सन १८४८ में स्थापित ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन जैसी राजनीतिक संस्थाएँ भी थी। वक्तव्य, बंबई और मद्रास में प्रेसिडेंसी असासिएशन स्थापित हुए। सन १८७६ में मुरदनाथ दाजी ने वक्तव्य में इंडियन असासिएशन स्थापित किया। सन १८८३ में इंडियन असोसिएशन ने एक नेशनल कांग्रेस (राष्ट्रीय सम्मेलन) का आयोजन किया। इससे एक अविन भारतीय संस्था बनाने का विचार पैदा हुआ जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय (इंडियन नेशनल) कांग्रेस का जन्म हुआ।

दूसरा बड़ा सामाजिक संस्थाओं का है। इनके संगठनशक्ती का विश्वास था कि स्वराज्य के पहले समाज का पुनर्निर्माण जरूरी है जिससे लोग स्वशासन के योग्य बनें। एम आदोलन के नेताओं में राजा राममोहन राय ईश्वरचंद्र विद्यासागर और श्रीनिवास अयंगर जैसे लोग थे। जस्टिस महादेव गोविंद रानडे भी समाज की कुरीतियों के बड़े आलोचक थे। इन्हीं के शिष्य कांग्रेस के नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गांधी हुए, किंतु उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र अपनाया।

तीसरे वग व सुधारक प्राचीन परंपरा के उतने विरोधी न थे, यद्यपि सुधार के लिए व भी उतने ही व्यग्र थे, अतः इनका प्रभाव भी अधिक पड़ा। इनमें सब प्रमुख स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने सन १८७५ में बंबई में आय समाज की स्थापना की। आय समाज ने अपनी मुख्य प्रेरणा वेदों से ग्रहण की और हिंदू समाज व धर्म में घुस आइ बुराइयों को दूर करके विशुद्ध वैदिक धर्म के पुनरुद्धार का आह्वान किया। राष्ट्रवादियों पर इसका प्रबल प्रभाव पड़ा और वे बड़ी सरया में इस में शामिल हुए। इसने हिंदू समाज की बुराइयों से असंतुष्ट विद्रोह पर उतारू तत्त्वा को आश्रय दिया। इसकी शाखाएं देश भर में फैली। इसने शिक्षा का प्रचार किया और देश तथा समाज के पुनरुद्धार के लिए युवक-युवतियों का दल तैयार किया। इसने राष्ट्रीयता की भावना को बल दिया और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए कार्यकर्ता दिए। स्वामी रामकृष्ण के महान शिष्य स्वामी विवेकानंद सनातनधर्म के समर्थक थे। उनके स्थापित रामकृष्ण मिशन ने शिक्षा के प्रसार और समाज सेवा के क्षेत्र में बड़ा काम किया। बाद में कांग्रेस के नेताओं ने अनुभव किया कि राष्ट्रीयता व जातिवाद के रूप में धर्म का महत्व है। इन नेताओं में तिलक और गांधी मुख्य थे।

### राजनीतिक चेतना

१८ वीं और १९ वीं सदी के समाज सुधारक वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रवर्तक थे। उन्होंने शिक्षित नागरिक वर्ग में जागृति फैलायी। उसी ने राजनीतिक चेतना को जन्म दिया जिससे राजनीतिक या राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन हो सका। रानडे से गोखले की पीढ़ी तक आते आते सामाजिक आंदोलन के सभी प्रमुख नेता राजनीतिक क्षेत्र में काम करने लगे थे। बंबई के प्रसिद्ध पारसी नेता दादा भाई नौरोजी जो ब्रिटिश पार्लामेंट के पहले भारतीय सदस्य हुए, अगरजी राज के कठोर आलोचक थे। उनका कहना था कि यह भारत का शोषण कर रहा है और उसे गरीब बना रहा है। वह राजनीतिक कार्य के समर्थक थे। (रानडे भी बोरे समाज सुधारक न थे। वह यह मानते थे कि स्वराज्य के पहले समाज सुधार आवश्यक है) इनके अलावा बंगाल और अन्य स्थानों में उग्र राजनीतिक आंदोलन कारियों के वर्ग का उदय हुआ जो विदेशी शासन को उखाड़ना चाहते थे। सारे देश में असंतोष की भावना सुलग रही थी और प्रकट होने का रास्ता चाहती थी।

यह रास्ता सन १८८५ में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से मिला। यह, भारत की आधुनिक राजनीति की ऐतिहासिक घटना थी। इसकी स्थापना प्रायः आकस्मिक ही हुई और गुरु में इसे अंग्रेजों का सहयोग और अधिनारिया की सहभाषना मिली। इसने एक विराट संगठन का रूप धारण किया और राष्ट्रीय आंदोलन को संगठित नेतृत्व प्रदान किया। कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रधारा की नरम

और गरम दो विरोधी प्रवृत्तियों के बीच का रास्ता अपनाया (जो अब भी इसका यही रवैया है) नरम दल के लोग अंगरेजी राज से समझौता करने के और नरम वैधानिक उपायों से राजनीतिक कार्य करने के समर्थक थे। गरम विचारधारा अंगरेजी राज्य के विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन से लेकर नातिकारी कार्यों तक अनेक उग्र रूपों में प्रकट हुई। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं को ब्रिटिश विधानवादियों से भी समर्थन मिला। वैधानिक आंदोलन का रास्ता छोड़ने के बाद कांग्रेस की ब्रिटिश राज से सीधी टक्कर हुई। वैधानिक और प्रत्यक्ष संघर्ष दोनों उपायों से काम लेकर कांग्रेस ने अंत में अपना लक्ष्य सिद्ध किया। इस नम में उसने ससदीय कार्य का और विस्तृत देशव्यापी संगठन तथा कार्यकर्ताओं का दल बनाने का अनुभव प्राप्त किया तथा उसे विभिन्न वर्गों का समर्थन मिला और जनता में जड़ जमी।

भारत में स्वायत्तता की समस्या का विकास अंगरेजी शासन और भारतीयों के आंदोलन दोनों के प्रभाव से हुआ। यदि यहाँ किसी ऐसी विदेशी शक्ति का शासन होता, जिसके अपने देश में लोकतंत्रीय संस्थाएँ न होतीं और जिसमें अंगरेजी की तरह राजनीतिक समझौते की प्रवृत्ति न होती तो यहाँ के राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप कुछ और होता। इसका साथ ही भारतीयों की जो बौद्धिक और सांस्कृतिक परंपरा थी, जिसने कारण उ होने अंग्रेजी शिक्षा तथा प्रशासनिक और राजनीतिक संस्थाओं को ग्रहण किया, उससे अंग्रेजी को भी यहाँ शासन चलाने में आसानी हुई।

प्रायः शुरू से ही यहाँ दूरदर्शी और उदार अंग्रेज अधिकारी भी रहे, जो भारतीयों की भावनाओं को समझते थे। ये लोग उस दिन का कल्पना करते थे जब भारतीय अपना शासन खुद करने लगेंगे और इस पर भी सावधानीपूर्वक विचार करते थे कि किस प्रकार उनका उन्हें इससे लिए तैयार किया जाए। किन्तु लगभग १६ बीसवीं के अंत तक इस पर कोई ठोस विचार नहीं किया गया, कि भारतीयों को किस क्रम से अधिकार दिए जाए। (मिफ स्थानीय स्वशासन या म्युनिसिपल शासन के क्षेत्र में कुछ कारवाई की गई और इसमें भी बाई खास सफलता नहीं मिली)।<sup>६</sup>

स्वशासन की मांग — इस दशक में भारत में ससदीय शासन के विकास के पीछे कई शक्तियाँ काम कर रही थीं। एक तो कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन से सहयोग और मित्रता का जो हाथ बढ़ाया, उसका उधर से उत्तर नहीं मिला, इससे कांग्रेस में क्रोध बढ़ा और उसका रुख बढ़ा होने लगा। गोखले जैसे नरम दली नेता के अलावा

६ लॉड रिपन स्थानीय स्वशासन की राजनीतिक शिक्षण का साधन मानते थे और उन्होंने स्थानीय स्वायत्त बोर्डों की स्थापना के लिए १८८२ का प्रसिद्ध प्रस्ताव किया। विदेशीकरण संबंधी राष्ट्रीय कमिशन ने भी १९०२ में इस प्रस्ताव का समर्थन किया मगर कोई खास नतीजा नहीं मिला, यद्यपि गांवों के मुन्सिफ शहरों में स्थानीय बोर्डों की ज्यादा सफलता मिली। लॉड रिपन उदार शासन समर्थक थे। मद्रास में पंचायती राज की स्थापना संबंधी रिपोर्ट में लॉड रिपन का प्रशंसात्मक उल्लेख है।



बढ़ता हुआ अस तोप

इस शती के शुरू के दशकों में भारत के राजनीतिक परिवर्तन में जो परिवर्तन आया उस समय की जल्दबाजी है। सामाजिक और राजनीतिक सुधार की भावना अब स्वतंत्रता की आकांक्षा में बदल गयी। अंगरेजों से सहयोग की प्रवृत्ति के बदले लोगो में इस भावना ने जोर पकड़ा कि अंग्रेज निरंकुश विदेशी शासक हैं जो जनता की भावनाओं की कोई परवाह नहीं करते। बंगाल के विभाजन ने अंगरेजी नेताओं का भी झुंझ कर दिया। दादाभाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासन पर भारत के शासन का जो दमनाम लगाया, उसने मध्यवर्ग के नेताओं को बहुत प्रभावित किया और इससे राष्ट्रीय आंदोलन को विदेशी शासन का विरोध करने के लिए प्रबल शक्ति मिली। बंग भंग ने स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया। तिलक ने इस आंदोलन का बड़ी कुशलता से नेतृत्व किया और इससे स्वदेशी कपड़ा मिलाने की स्थापना को सहायता मिली। इससे व्यापारी वर्ग ने इस आंदोलन का समर्थन किया। पहले अंग्रेजों की यह दलील सही मानी जाती थी कि भारतीयों को स्वायत्तता देने के पहले उनकी शिक्षा पूरी करनी होगी, अब इस अपमानजनक समझा गया। भारतीय राष्ट्रवाद ने अब ज्यादा उग्र रूप पकड़ा। कांग्रेस का रुख पहले अंग्रेजी शासन से सहयोग और समझौते का था अब वह स्वशासन के लिए सशक्त राष्ट्रीय मोर्चा बन गई।

यह सब स्वाभाविक था। शिक्षा और राजनीतिक विचारों के प्रसार तथा वर्तमान स्थिति से असंतोष के बढ़ने के साथ-साथ भारत और अंग्रेजी सरकार के हितों का विरोध स्पष्ट होना अनिवार्य था। वास्तव में कुछ ऐसी शक्तियाँ काम कर रही थी, जिन्होंने भारतीय राजनीति का रूप ही बदल दिया। पहली बार भारत में एक संगठित केन्द्रीय नेतावर्ग का उदय हुआ जो देश की समस्याओं पर व्यापक और राष्ट्रीय स्तर पर विचार करने लगा। पहले अलग-अलग स्थानों में प्रमुख व्यक्ति सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के लिए काम करते थे, अब इनकी जगह राष्ट्रीय नेतावर्ग और राष्ट्रीय संगठन ले ली। कांग्रेस के रूप में देश की राष्ट्रीय मंच मिली। राष्ट्रीय चेतना और भावना का उदय और इसके प्रचार के लिए राष्ट्रीय संगठन का जो भारत की इतिहास की क्रांतिकारी घटना थी। ब्रिटिश राज ने भारत में स्थिरता और प्रशासनिक एकराता स्थापित करके राष्ट्रीयता के विकास के लिए आधार प्रस्तुत किया किन्तु भारतीय राष्ट्र का जन्म तब हुआ, जब विदेशी शासन की प्रतिक्रिया में राष्ट्रीय भावना का रूप दिया और राष्ट्रीय संगठन को जन्म दिया।

राष्ट्रीय संगठन के द्वारा जब राष्ट्रीय नेतावर्ग काम करने लगा, तब राष्ट्रीय आंदोलन का राजनीतिक आयाम भी स्पष्ट होने लगा। प्रश्न केवल सुधार और शिक्षा का नहीं बल्कि एक शक्तिशाली साम्राज्य से लड़ने और बड़ी लड़ाई का था।



यह समझना मूल्यता की बात थी कि साम्राज्य अपने से अपना जन करने को राजी हो जाएगा। इंग्लिश तिरक ने कहा कि स्वराज्य के लिए मध्य करना पड़ेगा। विदेशी शासन से राजनीतिक सुधार की मांग का नतीजा निराशाजनक रहा।

### नए मतभेद

जैसे जैसे समस्या की विशालता का बोध हुआ, तब तब उसको मुक्ताने के उपायों के बारे में मतभेद भी पैदा हुए। नरम दल की नीति से असंतुष्ट होकर तिलक के नेतृत्व में गरम दल ने मंगलूर पर बका करने की काशिश की। यद्यपि मूरत कांग्रेस (१८०७) में उनकी हार हुई फिर भी राजनीतिक रूप में चैन्य बग में उनका बढ़ता गया। तिरक के जेल से छूटने और १८११ में गोखले के देहात के बाद गरम दल का प्रभाव स्थापित हो गया। तिलक भी उग्र राजनीतिक आदर्शनकारी से चतुर राजनीतिज्ञ के रूप में परिणत हुए। इसमें राष्ट्रीय आदर्शन में नए उग्र नस्वों का प्रभाव जम गया जोर इ ही के प्रभाव से कांग्रेस ने १८१६ के सुधार को ठुकरा दिया।

इस प्रकार बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों सरकार और राष्ट्रवादियों के बीच तनाव बढ़ता गया यद्यपि अंग्रेजों ने १८०८ और १८१६ में कुछ राजनीतिक सुधार देकर और १८११ में बंगाल के विभाजन का रद्द करके भारतीय जनमत को संतुष्ट करने की कोशिश की। भारत के राजनीतिक वातावरण में गरमी जा गयी। अंग्रेजों ने राष्ट्रीय नेताओं का जेल और निर्वासन का दंड देकर और इससे भी अधिक रोलट ऐक्ट बना कर और १८१६ में जलियानवाला बाग में निहत्थी भीड़ पर गोली चला कर भारत में असंतोष को मजबूत करने में योग दिया। देश की तरह कांग्रेस के भीतर भी तनाव था। १८०७ में नरम दल के कारण तिलक के दल का कांग्रेस से अलग होना पड़ा था। अब तिलक और गरम दल की प्रधानता हो जाने के बाद नरम दली लिबरल लोग कांग्रेस से अलग हो गए और उन्होंने अपनी अलग समस्या निर्धारण फेडरेशन बनाई।

मगर ऐसा लगता था कि न तो नरम दल की समस्या का कोई उपाय सूझता था, न गरम दल का। कांग्रेस महज वादविवाद सभा बन गई थी। सरकार को राजनीतिक सुधारों के लिए राजी करने की नरम दल की चेष्टा विफल हो गयी थी। दूसरी ओर गरम दल के आंदोलन से भी स्वायत्तता प्राप्त करने में कोई सफलता न मिल पाई थी। इनके दुक्के अंग्रेजों की हत्या और बम फेंकने का नतीजा यही हुआ कि सरकारी दमन और बढ़ गया। एक प्रकार का गतिरोध पैदा हो गया था। असल में कांग्रेस का मंगलूर जनता में न फल सका था और उससे कोई शक्ति न प्राप्त कर सकता था। कांग्रेस के नेता बाहर के पड़ लिये लोग थे। उनकी मारी बातचीत अंग्रेजी भाषा में होती थी जिसे माधारण जन न समझता था। चिन्ता

जनता से उनको कोई व्यापन समथन नहीं मिल पाता था । नरम और गरम दोनों पक्षों के नेता जनता का सगठन करने में विफल रहे और इससे देश की राजनीति में एक खालीपन और गतिरोध आ गया था ।

### जननायक का आविर्भाव

इस गतिरोध को दूर किया मोहनदास करमचंद गांधी ने । वह भारतीय राजनीति को जनता के समीप ले आए । दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह\* चलाया था । सन १९१५ में वे भारत लौटे । भारत की समस्या का अन्वयन करने के लिए उन्होंने सार देश का दौरा किया । गांधी ने अनुभव किया कि स्वराज्य की लड़ाई बहुत लंबी होगी और केवल अंग्रेजों से ही नहीं, भारतीयों को खुद अपने से भी लड़ना होगा । उन्होंने समझ लिया कि अकेले शहरी मध्यवर्ग में काम करने से जनता में जागरण नहीं आ सकता । जनता को आलस और अव्यवस्था से जगाना होगा, उनमें आत्मविश्वास और प्रगति की चाह पैदा करनी होगी । अंग्रेजों को यह दिखाना होगा कि उनका मुकाबला नरम दिल के थोड़े से दबू नेता और अंगरेजियत में डूबे शिक्षित वर्ग के लोगों से नहीं । भारत भर की करोड़ों जनता के संगठित आंदोलन से है । गांधी यह भी जानते थे कि उनका प्रतिपक्षी भौतिक बल से डरने वाला नहीं है, साथ ही उस पर नैतिक बल का प्रभाव पड़ सकता है, यदि उसके पीछे जनता का संगठन हो । इसलिए सब से पहला काम जनता को जागृत करके, संगठन की जड़ उनमें फैलाना है ।

गांधी स्वयं असाधारण नैतिक शक्ति से प्रेरित थे । उन्होंने कांग्रेस को एक नई दिशा दी और उसे जनता का संगठन बनाया । उन्होंने समाज के सभी वर्गों के स्त्री-पुरुषों को एक सामान्य कार्यक्रम के लिए प्रेरित करने के लिए नए उपायों का सहारा लिया । उन्होंने जनता को सत्य और धर्म के लिए त्याग करने का ललकारा । उन्होंने सन १९२१, १९३० और १९३२ में सरकार के खिलाफ अहिंसात्मक असहयोग के जबदस्त आंदोलन चलाये । ये तोड़फोड़ या उपद्रव के नहीं, अत्याचार के नैतिक प्रतिरोध के रूप में चलाए गए और इनमें सरकार के आदेशों और कानूनों की शांतिपूर्वक अवज्ञा की गई । यही सत्याग्रह का तत्त्व था । सरकार को अत्याचार से विरत करने के लिए उन्होंने कई बार आमरण अनशन ठाने । इसमें कई बार उनको सफलता मिली और इनके द्वारा उन्होंने अपने दंगवासियों में गहरी भावना उत्पन्न की और विदेशों को भी प्रभावित किया ।

गांधी स्थिति को देख कर उसी के अनुरूप उपाय निकालते थे । जब आंदोलन

\* दक्षिण अफ्रीका के गोरे शासक भारतीयों से भेदभाव करते थे । उन्होंने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नो नेताओं ने भी अपने नागरिक अधिकार के लिए आंदोलन में गांधीजी के सत्याग्रह के तरीके का प्रयोग किया । किंतु इसका प्रभाव अस्थायी रहा ।

स्थगित हो गया तो उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम तैयार किया। इसमें अस्पृश्यता निवारण खादी, ग्रामोत्थान, आदिवासियों की सेवा, पिछड़े लोग की भलाई, शिक्षा का प्रचार और कांग्रेस से संबद्ध स्त्रियाँ, युवा, मजदूर और दलित जाति मध्धी संगठन में काम शामिल था। पहले समाज सुधार हो या राजनीतिक संगठन इस बहस को गांधी ने खतम कर दिया। उन्होंने कहा कि ये दोनों काम एक ही कार्यक्रम के अंग हैं। रचनात्मक कार्यक्रम कांग्रेस कार्यकर्ताओं का काम में लगाए रखने का बहुत अच्छा तरीका था, जो जयया आंदोलन स्थगित हो जाने से निरंतर जाते। इस प्रकार अगले आंदोलन के लिए कार्यकर्ताओं की फौज तैयार रही।

### नए प्रतीक

गांधी ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत गहरा और व्यापक रूप दिया और उस नए शक्तिशाली प्रतीक दिये। जनता उन्हें महात्मा कहती थी। उन्होंने अपने महान व्यक्तित्व के जादू से जनता को एक ढाँचे में ढाला। उन्होंने अपने जीवन का राष्ट्र के सामने आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। उनके त्याग, सादगी और सत्य की साधना का देश पर गहरा प्रभाव पड़ा। दूसरे उन्होंने समाज की अत्यंत जटिल समस्याओं के लिए चमत्कारी सूत्र प्रस्तुत किए। उन्होंने अछूतों को 'हरिजन' नाम दिया और उनकी भलाई के काम को कांग्रेस कार्यक्रम का अंग बनाया। उन्होंने राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदुस्तानी (हिंदी और उर्दू का मेल) के प्रचार का देश-व्यापी कार्यक्रम चलाया, उन्होंने स्त्रियों की स्थिति सुधारने का आंदोलन चलाया और स्त्रियों को पुरुषों के समान पद देने की जबदस्त बकालत की, उन्होंने हिंदू-मुस्लिम एकता का राष्ट्रीय एकता का साधन बनाया। गरीब जनता को जीविका देने के लिए उन्होंने चर्खे को प्रतीक बनाया और खादी को राष्ट्रीय पोशाक बनाया। नमक पर कर जैसी छोटी-सी बात को उन्होंने अंग्रेजी सरकार के विरोध का प्रतीक बनाया और हजारों आदमियों ने नमक कानून तोड़ कर विदेशी सत्ता को चुनौती दी। हर रोज अपनी शाम की प्रार्थना में वह देश की समस्याओं पर अपनी राय देते थे। इस प्रकार अपनी प्रार्थना सभा को उन्होंने सांस्कृतिक महत्व की वस्तु बना दिया। अखबारों में उनकी प्रार्थना सभा की रिपोर्टें थीं, और सब खबरों से अधिक महत्व मिलता था। गांधी ने ब्रिटिश सरकार से अपनी लड़ाई को सत्य के प्रयोग का नाम दिया।

तीसरे, गांधी ने अहिंसा और सत्य जैसे धार्मिक शब्दों और प्रतीकों को साधन का हथियार बनाया और उनके द्वारा कांग्रेस को जबदस्त अनुशासनबद्ध संगठन और ठोस कार्यक्रम दिया। इस प्रकार वह विभिन्न विचारों, वर्गों और संप्रदायों के लोगों को कांग्रेस में ले आए। गांधी सभी वर्गों के लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन में साथ रखने को बहुत महत्व देते थे और इस खातिर वह मतभेदों को सहन करते

ये । इसने कांग्रेस में अनेक तरह और विचारों के लोग भार और उतारे दृढ़ता  
 लचीलपन और स्थिति के अनुसार अपने को ढाल लेने की क्षमता साई । यद्यपि  
 देशों में स्वतंत्रता आंदोलन में जो मानेंद और फूट उभरत हुई उससे भारत का  
 राष्ट्रीय आंदोलन बचा रहा । तबनि हिंदू मुसलमानों में पड़ की गोपी भणी पूरी  
 कोणिका के दावजूद न रोय सके ।

### प्राचीन परम्परा को नया रूप

गांधी ने सैकड़ों वर्ष पुरानी धारणाओं को नया आयु दिया । वे गांव  
 और शहर के लोग को एक साथ ले आए । आत्मशास्त्र, अहिंसा, जैसे पुराने आदर्शों  
 और सामाजिक तथा व्यक्तिगत कृत्यों की पुरानी धारणाओं को उठोने आयुधिका  
 स्थिति के अनुरूप नये ढांचों में राष्ट्रीय आंदोलन में प्रयोग किया । उन्होंने शहर  
 के लोग का प्रेरित किया कि वे गांवों में जाए और ग्रामीण जाति की सेवा कर,  
 सादगी, पवित्रता और गरीबी का जीवन बिताएं और देश की जगता के सामने  
 ऊंचा आदर्श पेश करें । उन्हें अपने व्यक्तिगत उदाहरण से प्रभावित कर गरीब देश  
 को ऊपर उठाने के लिए आत्मसमर्पण और अनुशासनपूर्ण राय की भलाई के लिए  
 एक होकर काम करना चाहिए । अपनी जरूरत कम से कम और अपना परिवार  
 छोटा रखना चाहिए । उन्होंने धन को ट्रस्ट या धरोहर समझते, पैसा धराने और  
 धन से अपना घटा करने के पुराने आदर्शों की दुहाई देकर व्यापारी और धनवा  
 वर्ग को अपने रचनात्मक काम में सहयोग देने को प्रेरित किया । उन्हें सामाजिक  
 और राजनीतिक काम में नैतिकता और धर्म का समावेश किया और इस प्रकार  
 पुराने विचारों के लोग को अपने आंदोलन में आकर्षित किया । शहर और गांव  
 में, पुराने और नए विचारों में मेल मिला कर गांधी ने राष्ट्र निर्माण में बहुत  
 महत्वपूर्ण योग दिया ।

गांधी ने केवल पुराने विचारों को नया रूप ही नहीं दिया । पुरानी गड़ी गरी  
 छड़िया पर भी उन्होंने निमग्नता से चाट की । एक बार उन्होंने आत्म संयम और  
 धन को परमाय में नगाने के पुराने आदर्शों का प्रचार किया, दूसरी बार उन्होंने  
 जात पात और ऊंच नीच के भेदभाव को खरीखार किया । शारीरिक श्रम का  
 छोटा या नीचा और दिमागी काम को ऊंचा समझा का उन्होंने गढ़ा किया । यह  
 नहीं मानते थे कि मनुष्य को सामाजिक या गृहस्थिक कृत्यों का शिवांगिक दक्ष  
 अपनी आत्मा के कल्याण में लग जाना चाहिए और गरीबी का पूर्व जन्म का कर्म  
 का परिणाम समझ कर घंट जाना चाहिए । हिंदू विचारधारा की जा गंधक बड़ी  
 कमी थी नागरिक कृत्य और सामूहिक सावधानी भावना का अभाव, उम  
 उन्होंने दूर किया । यह आत्मसमर्पण और व्यक्तिगत नैतिकता का गायत्री का  
 में प्रतिष्ठित करने से भी बड़ा काम था । गदाचार और धर्म का नगरी का उदा

हरण प्रस्तुत किया, उससे अधिक महत्व का काम, उन्होंने सस्था बनाने और संगठन के अनुशासन की शिक्षा देकर किया ।

### सस्था-निर्माण

गांधी ने देश भर में बड़े विशिष्ट कार्यक्रमों का दान तैयार किया और उनको कांग्रेस के विभिन्न कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी । इन्हीं लोगों ने बाद में स्वतंत्रता प्राप्त होने पर सरकार और कांग्रेस संगठन की बागडोर संभाली । उन्होंने कांग्रेस सस्था के विकास के लिए बड़ी बुद्धिमानी के कदम उठाए । उन्होंने कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की स्थापना की और उसको बड़ी सक्तिशाली सस्था बनाया । इसे कांग्रेस हाईकमांड कहा जाने लगा और यह राष्ट्रीय आंदोलन की सूत्रधार मानी जाने लगी । इसने सामूहिक नेतृत्व की परंपरा डाली और कांग्रेस महाममिति से अधिक महत्व प्राप्त कर लिया । कांग्रेस महाममिति (आल इंडिया कमेटी) में तो जबरन मतभेद दिखाई पड़ने थे, किंतु उसे अंत में कार्यसमिति की बात माननी पड़ती थी ।

गांधी कांग्रेस कार्यसमिति को बहुत ऊंचा दर्जा देते थे ( यद्यपि वह कभी उसके वाक्यांशों में नहीं रहता ) और अपने सभी निणयों की पुष्टि उससे कराते थे । जब उन्होंने असहयोग आंदोलन का अचानक संचालित कर दिया और उनके इस कार्य का चारा और से विरोध और आलोचना होने लगी तब इसकी ओर ऐसे ही अन्य निणयों की पुष्टि वह हाईकमांड से कराते थे । १९३६ में जब गांधीजी की इच्छा के विरुद्ध कांग्रेस महासमिति ने सुभाष बाबू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना, तब गांधीजी से प्रभावित कांग्रेस हाईकमांड ने सुभाष से सहयोग नहीं किया और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा । इस गांधी की तानाशाही कहा गया और उनको कटु आलोचना हुई, मगर अंत में गांधी की ही चली । जैसा कि उन्होंने कभी पहले कहा था, कांग्रेस को मेरे स्थान पर दूसरा नेता चुनने का अधिकार है, किंतु जब तक वह मुझे नेता बनाती है, जो मैं कहूँगा वही होगा । वह नेतृत्व की एकता और अनुशासन पर बेहद जोर देते थे । मगर वह अपनी तानाशाही चलाने के बजाय हाईकमांड के जरिये काम करते थे । इससे जनता में हाईकमांड की बड़ी मान्यता और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई । उसकी बात कानून मानी जाती थी । इस प्रकार भारत ने इतिहास में पहली बार ऐसी अधिकारी सस्था का निर्माण हुआ जो राष्ट्र की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती थी और उसकी ओर में काम करती थी । भारतीय राष्ट्र को संस्थागत रूप देना, गांधी का एक महान् कार्य था ।

गांधी ने कांग्रेस संगठन का आधार व्यापक बनाने की कोशिश की । उन्होंने देश भर में जिला कांग्रेस कमेटियाँ स्थापित की और उनके जरिये जनसाधारण को कांग्रेस का सदस्य बनाया । जिला कांग्रेस कमेटियों को गांधी हमेशा जनता

का मुख्य सगठन मानते थे। इसके अलावा उन्होंने स्त्रियाँ, हरिजन, आदि-वासियाँ, मजदूरों आदि में काम करने के लिए जलजल सस्थाएँ बनाई। उन्होंने शुरू में ही ऐसी सस्थाओं की जरूरत का अनुभव किया, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता उस समय लगे रहें जब राजनीतिक आंदोलन न चल रहा हो। उन्होंने जनता में अपने विचारों के प्रचार और देश की समस्याओं पर निरंतर चर्चा जारी रखने के महत्त्व को भी समझा। उन्होंने यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन आदि पत्र निकाले। इनके जरिये वह अपने अनुयायियों का निरंतर पत्रप्रदान करते रहते थे। इन तरीकों से गांधी राष्ट्रीय आंदोलन को सुसंगठित करना चाहते थे। स्वभाव से वह दलतत्र या कठोर पार्टी सगठन के विरुद्ध थे, किंतु अपने इन तरीकों से उन्होंने ऐसे जलदस्त सगठन का निर्माण किया, जिसकी शाखा-प्रशाखाएँ देश भर में फल गईं। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने जनता को संगठित करने के लिए जोर भी अनेक एजेंसियाँ स्थापित की, किंतु उसका साधारण ढांचा वही रहा, जिसे गांधी ने बनाया था। आज भी उसका यही ढुनियादी ढांचा है और अजय राजनीतिक पार्टियाँ ने भी इसी को अपनाया है।<sup>८</sup>

### गांधी के नेतृत्व के कुप्रभाव

एक आदमी की इतनी अधिक प्रधानता से कुछ बुराईयाँ भी पैदा होती हैं। गांधी के एकछत्र नेतृत्व का यह नतीजा तो नहीं हुआ कि उनके बाद देश को नेताओं का अभाव रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की एक बहुत बड़ी पूजा थी, हर स्तर पर देश भर में योग्य नेताओं की मौजूदगी। गांधी के नेतृत्व का बुरा असर अजय दिशाओं में हुआ। एक तो यह था कि गांधीजी ने राजनीति में नैतिकता, सत्य, अहिंसा, आदि पर इतना जोर दिया कि वह असलियत से दूर हो गई। उन्होंने इतने ऊँचे आदर्श रखे कि वे व्यवहार में न आ सके। राजनीति-ज्ञता का स्थान उपदेशबाजी ने ले लिया। गांधी की वास्तविकता की अच्छी पकड़ थी, फिर भी उन्होंने मनुष्य की कमजोरियाँ का कोई ध्यान नहीं रखा। लाकतंत्री राजनीति का गुरु गांधी की पकड़ में न आ सका और आज भी उनके बहुत से अनुयायियों की यही कमजोरी है। नेहरू में यह कभी न थी, क्योंकि उनका मानसिक और बौद्धिक वातावरण भिन्न था और यह उनकी विशेषता थी कि इस विषय में वे गांधीजी के प्रभाव से बचे रहें।

गांधी जी के जीवनकाल में भी उनके अनुयायियों के लिए अक्सर उनकी बात या नीति को समझना कठिन हो जाता था। वह तात्कालिक प्रश्नों का अक्सर सिद्धान्त थी बातों से मिला देते थे। राजनीतिक प्रश्नों को नैतिक प्रश्नों से मिला

<sup>८</sup> कमिश्नर सगठन के विकास के लिए दें - गोपाळरूप 'द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एन ए मास आर्गनाइजेशन', जर्नल ऑफ एशियन स्टडीज, मई १९६६, २५, नं ३।

दने से दूसरी पार्टीया चक्कर में पड़ जाती थी। उनके अनुयाईं जार प्रतिपक्षी दल तथा अंग्रेजी सरकार नहीं समझ पाते थे कि वह क्या कर बैठेंगे। इसका नतीजा यह होता था कि अपने ही शब्दों में वह 'हिमालय जैमी गलतिया' कर बैठते थे और उनकी नीति अचानक पतटा खा जाती थी। इससे भी अधिक गंभीर त्रुटि यह थी कि उनकी रीति नीति से राष्ट्रीय आंदोलन में फूट पड़नी न स्वी वल्लि भीर बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए महान प्रयत्न किया पर राजनीतिक समझाते के दावपेंच में वे चूक जाते थे। उदाहरण के लिए सांप्रदायिक समस्या सुलझाने के लिए उन्होंने भावनाओं से काम लेने पर भरोसा किया और खिलाफत आंदोलन तथा हिंदुस्तानी प्रचार जैसे उपायों का सहारा लिया। लेकिन नींग से समझौता करने और उनको मिला कर मजबूत मोर्चा बनाने की ओर ध्यान न दिया। बातचीत के समय अक्सर उनका रंग बढा कटटर और अनम्य हो जाता था। उनकी बात दूसरे दल के नेताओं को पुराणपथी लगती थी और उनके मन में कांग्रेस की असली मशा के बारे में शक पैदा कर देती थी। मगर इस आलोचना का यह अर्थ नहीं कि गांधीजी की नीति बिगड़ल गलत थी। बहुत सी समस्याएँ तो जनिवाय थी। कुछ समस्याएँ राष्ट्रीय जागरण के फलने के कारण उठा। अनेक समस्याओं को सुलझाने में गांधीजी ने बड़ी सूझबूझ का परिचय दिया, खास कर राजनीतिक समाज के निर्माण में। उनकी महानता यह थी कि वे अपनी विफलताओं का स्वीकार कर लेते थे और मुराब काय को जारी रखते थे।

### अथ राजनीतिक दल

सभी लोग गांधीजी की नीति को नहीं स्वीकार करते थे। जब गांधीजी लीगा को अहिंसात्मक प्रतिरोध के लिए तैयार करने पर जार द रह थे, कुछ प्रमुख कांग्रेसजना न स्वराज्य पार्टी को स्थापना की। ये लोग कोसिला का चुनाव लड़ कर होमोनियम स्टेटस (जोपनिवेशिक स्वराज्य) के लिए राजनीतिक आंदोलन करना चाहते थे। १९२७ में मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने एक प्रस्ताव पाम किया जिसमें कहा गया कि कांग्रेस का ध्येय 'स्वतंत्रता' है। स्वराज्य दल ने १९२८ में एक सब दली सम्मेलन आयोजित किया। इमने एक कमेटी नियुक्त की, जिमने भारत में पूर्ण प्रतिनिधि शासन और स्वतंत्र ब्रिटिश उपनिवेशों के पद की मांग की। जवाहरलाल नेहरू और सुभाषचंद्र बोस के नेतृत्व में युवकों का एक दल पूर्ण स्वतंत्रता के लिए उग्र कार्रवाई करने के पक्ष में था। १९२९ में लाहौर कांग्रेस में इस दल को सफलता मिली और गांधीजी ने स्वयं 'पूर्ण स्वतंत्रता' का प्रस्ताव पेश किया। एक इससे भी ज्यादा उग्र वामपक्षी दल ने कांग्रेस समाजवादी दल का गठन किया। इसी बीच कुछ प्राता में कांग्रेस से बाहर कुछ राजनीतिक दल काममें हुए। इनमें से कुछ अंग्रेजी सरकार से सहयोग

कर रहे थे। इनमें मद्रास की 'जस्टिस पार्टी' थी, जो वाद की 'द्रविड कज्जगम' और 'द्रविड मुनेत्र कज्जगम' की पूर्ववर्ती थी। दूसरी थी पंजाब की 'यूनियनिस्ट पार्टी'। इनके अलावा मुस्लिम नेता थे, जिनमें से अधिकतर गांधीजी और कांग्रेस के खिलाफ थे। मुस्लिम नेताओं में भी दो वर्ग थे, एक था पुराना कट्टर वर्ग जो समझता था कि हिंदू-मुसलमानों का फर्क बुनियादी है और इसलिए यह कांग्रेस के विरुद्ध था। दूसरा वर्ग जिन्ना जैसे प्रगतिशील मुसलमानों का था जो गांधी और उनके तौर-तरीके को दक्षिणानुसी समझता था। इन दोनों को मिलाने की गांधीजी ने बड़ी कौशलों की लेकिन वे विफल रही।

गांधीजी इस बात के विरुद्ध नहीं थे कि स्वराज्य हासिल करने के लिए और तरीके काम में लाए जाएं। कांग्रेस के द्वारा जनता को संगठित करने और असहयोग और सत्याग्रह आंदोलन चलाने के साथ साथ वह वैधानिक सुधारों से उदासीन न थे और समय समय पर ब्रिटिश सरकार से समझौते की बातचीत भी करते थे। आंदोलन के बीच-बीच कुछ सुस्ताने के लिए वह अंग्रेजी सरकार से सुलह भी कर लेते थे। गांधीजी अंग्रेजी सरकार के कुछ कानूनों को तोड़ने आंदोलन जरूर करते थे, लेकिन वह यह नहीं चाहते थे कि देश में अराजकता फैले, और जब कभी आंदोलन उनके नियंत्रण से बाहर जाता दीखता वह उसे रोक देते। कई बार अपने समयको के बड़ विरोध के बावजूद उन्होंने अंग्रेजी सरकार से समझौते किये।

इस प्रकार सन १९२८ में चोरीचोरा में पुलिस और जनता में संघर्ष के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन को रोक दिया, यद्यपि जवाहरनाथ और अन्य अनुयायियों ने इसका घोर विरोध किया। इसी प्रकार १९३१ में जेल से छूटने के बाद उन्होंने ब्रिटिश प्रधान मंत्री के इस आश्वासन का स्वागत किया कि भारत को पूर्ण उत्तरदायी शासन की ओर अग्रसर किया जाएगा। इस आश्वासन के आधार पर वाइसराय लार्ड इरविन ने समझौता किया तथा कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में लंदन में दूसरी गोलमेज कान्फ्रेंस में भाग लिया।<sup>९</sup> मगर गांधीजी ने देखा कि अंगरेजी सरकार सांप्रदायिक समस्या को और उभाड़ रही है (इस विषय पर हम इस अध्याय में और विचार करेंगे) और वे खाली हाथ वहां से लौट आए। उनके लौटने के पहले ही अंग्रेजी सरकार ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को और हजारों अन्य आदमियों को जेल में बंद कर दिया था।

### घमनिरपेक्षता का प्रश्न

गांधीजी यह समझते थे कि अंत में अंग्रेजी सरकार से समझौता करना होगा,

<sup>९</sup> पहली कान्फ्रेंस १९३० में हुई थी जब गांधीजी और अन्य कांग्रेस नेता नमन सत्याग्रह के सिलसिले में जेल में बंद थे।



किंतु दुनियादी वाता पर झुबने को वह तैयार न थे। उन्होंने हरिजन। को पृथक् निर्वाचन का अधिकार देने के विरोध में आमरण अनशन छेड़ दिया और इसको बदलवा कर ही दम लिया।

अब गांधीजी और कांग्रेस के सामने सवाल था कि थगला बंदम क्या है। सन १९३१ के गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट से वह मनुष्य न थे, यद्यपि इममें बहुत बड़ी सरया को वोट का अधिकार दिया गया था और प्राना में उत्तरदायी सरकार तथा केन्द्र में सभ को व्यवस्था की गई थी इसमें दली रियासत भी शामिल हो सकती थी। परंतु इस ऐक्ट में राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक-मेलजोनों में कोई मदद न मिलती थी। फिर भी कांग्रेस ने इस ऐक्ट के अंतर्गत सन १९३७ के चुनावों में भाग लेने का फैसला किया और आठ प्रांता में उसके मंत्रिमंडल स्थापित हुए।

दा वष तक शासन करने के बाद प्रिना भारतीय नेताओं की राय लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को १९३६ के विद्रोह युद्ध में घसीटने के निणय के विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने पदत्याग कर दिया। नेहरू और जय पासिस्ट विरोधी लोग युद्ध के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन रोक देने और जमनी के विरुद्ध ब्रिटेन और उसके मित्र राष्ट्रों को मदद देने के पक्ष में थे, लेकिन गांधीजी इसी क्षण पर मदद करने को तयार थे कि भारत को तुरंत स्वतंत्रता दी जाये। ब्रिटिश सरकार ने गांधीजी और कांग्रेस के नेताओं को समझाने के लिए सर स्टेफन क्रिप्स को भेजा और आश्वासन दिया कि युद्ध खतम होते ही भारत में सविधान सभा बुलाई जाएगी। लेकिन क्रिप्स को सफलता न मिली और कांग्रेस ने तुरंत पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। सन ४२ में कांग्रेस ने 'भारत छोड़ो' आंदोलन शुरू किया। कांग्रेस के सार नेता जोर हजारा आदमी बंद कर लिए गए। गांधीजी ने जेल में फिर अनशन छेड़ा, जिसमें उनकी जान जात जाते बची। सन १९४५ में इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार बनी और कांग्रेस नेता जेल से छोड़े गए। दुनिया की स्थिति एकदम बदल चुकी थी और अंग्रेज सरकार तथा कांग्रेस में फिर बातचीत चली, लेकिन कोई समझौता न हो सका। इस पर और चर्चा करने के पहले हमें देखना चाहिए कि स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता के मांग में मुख्य बाधा क्या थी।

### सांप्रदायिक समस्या और राष्ट्रीय एकता

राष्ट्रीय आंदोलन के मांग में सबसे बड़ी बाधा थी 'सांप्रदायिक समस्या'। राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति और दुनिया की बदली स्थिति का देखते हुए अब इसमें कोई सदेह नहीं रह गया था कि भारत की स्वतंत्रता मिल कर रहेगी। प्रश्न बचल यह था कि सत्ता किसको दी जाये और भारत की सरकार का भावी रूप क्या हो। मुख्य समस्या मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग की थी।

सांप्रदायिक समस्या की गुरुआत मुस्लिम युग से हुई। लेकिन पिछले कई सौ

वर्षों से हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहते आए थे और उनमें काफी सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान और एकता पैदा हो गई थी। आज भी देश के बटवारे के बाद भी एकता के ये बंधन टूटे नहीं। साथ साथ रहने से भाषा, साहित्य, इतिहास, सभ्यता और शिष्टाचार की उनमें एक सी परंपरा बनी। घम या मजहब का अंतर हात हुए भी, इस्लाम के 'सब मनुष्या के भाईचारे' और हिंदू धर्म के 'सब रास्ते एक ही मजिल की ओर जाते हैं' सिद्धांतों के कारण, यहाँ एक खास तरह की सहिष्णुता और मेलजोल पैदा हो गया था, जो भारत की अपनी विशेषता है।

ब्रिटिश शासन से जहाँ भारत को कई लाभ पहुँचे वहाँ एक नुकसान यह हुआ कि उससे सांप्रदायिक द्वेष को उत्तेजना मिली। इसमें ब्रिटिश राज, कांग्रेस और मुस्लिम राजनीतिक नेता सब का दोष है। यह भी एक विचित्र विडवना है कि प्रतिनिधि और सेकुलर या धर्मनिरपेक्ष शासन के जिस सिद्धांत ने भारत में आधुनिकता का प्रचार किया उसी ने सांप्रदायिक समस्या को भी उभाड़ा।

### असमान विकास

शुरु में अंग्रेजों का सब मुसलमानों के खिलाफ जान पड़ता था। चूँकि उन्होंने मुगलों से सत्ता छीनी थी इसलिए वे मुसलमानों को शक्ति या प्रभाव की जगहा से दूर रखते थे। खास कर उन इलाकों में जहाँ अब भी उनका जोर था (इसी प्रकार का व्यवहार वे राजपूतों के साथ भी करते थे, जहाँ उन्होंने अंग्रेजों से टक्कर ली थी)। हमारे, अंग्रेजी शासन से हिंदुओं ने शुरू में ज्यादा फायदा उठाया। ब्राह्मणों और ऊँची जाति के हिंदुओं ने अंग्रेजी शिक्षा लेकर सरकारी नौकरियाँ और ऊँचे पदों में प्रवेश किया, जबकि मुसलमान अंग्रेजी शिक्षा से दूर रहे और नौकरियाँ आदि में पिछड़ गए। आर्थिक दृष्टि से भी पुरानी दस्तकारी और घड़ों की वर-वादी से मुसलमान कारीगरों को ज्यादा नुकसान हुआ। जमीन के नए बंदावस्त से मुसलमान जमीनदारों का हानि हुई। उधर हिंदू महाजनों और व्यापारियों ने तरक्की की। मुसलमानों को अपना अल्पसंख्यकों का दर्जा भी खलता था, क्योंकि उनको मुगलिया सल्तनत की याद आती थी जब सभ्यता में थोड़े होने पर भी वे राज करते थे।

यह भी याद रखना चाहिए कि अंग्रेजों के राज्य में जो सुव्यवस्था कायम हुई उससे पुरानी सभ्यता, और सभ्यता विद्या तथा हिंदू धर्म में एक नया जागरण आया। हिंदू जो अब तक मुसलमानों हुकमत में दबे हुए थे, पुन सिर उठाने लगे। उनके इस जागरण में अंग्रेजी शिक्षा और उससे प्राप्त होनेवाली सरकारी नौकरियाँ और बकालत, डाक्टरी आदि ने बड़ा योग दिया। इसका एक नतीजा यह हुआ कि शुरू में कई दशकों तक राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व हिंदुओं के हाथ में रहा जिनमें से अनेक प्राचीन हिंदू सभ्यता से प्रेरणा ग्रहण करते थे।

## मुसलमानों में प्रतिनिधित्व

दूसरी ओर अंग्रेजी शिक्षा और राष्ट्रीय जागृति का प्रभाव बहुत थाड़े से मुसलमानों पर पड़ा।<sup>१०</sup> ये शिक्षित मुसलमान अनुभव करते थे कि प्रशासन और राजनीति में हिंदुओं की प्रधानता से मुसलमानों को खतरा है। सर सैयद अहमद साहिबी में से थे। उन्होंने मुसलमानों को हिंदुओं से और कांग्रेस से अलग रहने और अंग्रेजी पढ़ने तथा अंग्रेजी सरकार से सहयोग करने को कहा। सर सैयद ने १८७७ में अलीगढ़ में ऐंग्लो जोरियटल कालेज कायम किया (बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी) और मुसलमानों का अंग्रेजी के पास लाने की कोशिश की। उन्होंने मुस्लिम एजुकेशनल कानफ्रेंस कायम की और हर साल उसका जुलसा करने लगे।

मुसलमानों की अव्यवस्था रोकने का यह प्रयत्न १९ वीं सदी के दूसरे भाग में हुआ परंतु इसने किसी राजनीतिक विचारधारा या कार्यक्रम को जन्म नहीं दिया। मुसलमानों में सत्ता से सघप या विरोध की कोई जोरदार भावना नहीं थी। सर सैयद आदि की कोशिश से अंग्रेजी का मुसलमानों पर अविश्वास घटा और मुसलमान सरकारी नौकरियों में जाने लगे। अलीगढ़ आंदोलन से मुसलमानों में शिक्षा का प्रचार हुआ और लखनऊ, पटना, इलाहाबाद, अलीगढ़ और हंटराबाद जैसे पुराने संस्कृति-केन्द्रों में नयी स्फूर्ति पैदा हुई और शिक्षित मुसलमान व हिंदू दोनों सामाजिक गतिविधियों में साथ साथ भाग लेते थे। अपने अपने रीतिरिवाज और परंपरा से उनका लगाव था, लेकिन वे एक दूसरे का ख्याल रखते थे और उनमें कोई द्वेष भाव नहीं था।

## फूट के बीज

फिर भी मुसलमानों के मुकाबले हिंदुओं की ज्यादा प्रगति, राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदुओं और हिंदू विचारों और प्रतीकों का प्रभाव और अंग्रेजी का साम्प्रदायिक पक्षपात, इनमें साम्प्रदायिक फूट के बीज बतमान थे। साधारणतः लोग इस बात को नहीं समझते कि आधुनिकता के विकास से खास कर शिक्षा और नगरीकरण के कारण अपनी अलग या विनिर्दिष्ट सत्ता या अस्मिता का बोध पैदा होना है, समाज में पद प्रतिष्ठा के पुराने पैमाने टूट जाते हैं, और सत्तावादी तथा संगठित प्रयत्न आगे बढ़ने में सहायक होते हैं। जैसे जनता के नए अवसर गुलते हैं पुराने सघप और विरोध पुनर्जीवित हो जाते हैं नए गठजोड़ और जाड़तोड़ का मत्तहूत्र बन जाता है। भारत में राजनीतिक जागृति के साथ एकता के साथ साथ फूट की प्रवृत्तियाँ भी

१० यह प्रभाव सब जगह एक सा नहीं था। जहाँ मुसलमानों की अधिक संख्या गाँवों में रहती थी और रानी या माली करता था, वहाँ उनमें अंग्रेजी शिक्षा नहीं पड़ी। उत्तरप्रदेश और बंगाल में जहाँ मुसलमान अधिकतर शहरों में रहते थे और उच्च वर्ग के थे वहाँ उनमें अंग्रेजी शिक्षा ज्यादा होती थी। लेकिन गोरे की उन्नति नहीं मिलनी हिंदुओं में।

पैदा हुई और अतः में दूसरी प्रवृत्ति की ही जीत हुई। आइये, इन पर एक नजर डालें।

### प्रतिनिधित्व की पद्धति

भारत में सांप्रदायिक भावनाओं को राजनीतिक रूप मिलने का एक कारण यह प्रतिनिधि या निर्वाचित संस्थाओं की स्थापना थी। इसके साथ-साथ प्रतिनिधित्व की ब्रिटिश धारणा भी इसके लिए जिम्मेदार थी। अंग्रेज लोग प्रतिनिधित्व का अर्थ, अलग-अलग समूहों, वर्गों, हिंदू, क्षेत्रों, संस्थाओं और संप्रदायों का प्रतिनिधित्व समझते हैं। उनके यहां प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास के पहले एक राष्ट्र बन चुका था, इसलिए वह राष्ट्रीय एकता को स्वयंसिद्ध मान कर चलते हैं। उन्होंने भारत के अनेक संप्रदायों और जातियों की समस्या को इनके स्वाभाविक अस्तित्ववोध और एक दूसरे से समझौते की समस्या समझा और उसका उपाय अलग-अलग वर्गों या समूहों को प्रतिनिधित्व देना समझा।

इसलिए उन्होंने भारत में सांप्रदायिक और विशेष वर्गों के प्रतिनिधित्व की पद्धति शुरू की। शुरू में ही उन्होंने गवर्नर की काउंसिलों में म्युनिसिपल टिया और वाणिज्य सभों को प्रतिनिधित्व दिया। सन १९०६ में उन्होंने जमींदारों और मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया। १९१६ के विधान से सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों के ऊपर पृथक् सांप्रदायिक और 'विशेष' निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए। १९३३ में अछूतों के अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव किया गया। इसके विरोध में गांधीजी ने अनशन किया, जिस पर इसमें संशोधन किया गया। इसके बाद १९३५ के विधान में और बाद में भारत की स्वतन्त्रता विषयक बातचीत में भी अंग्रेज सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और अल्पसंख्यकों को 'वेटेज' अर्थात् उनकी संख्या से अधिक स्थान देने पर ही जोर देते रहे। कांग्रेस सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के विरुद्ध थी, किंतु अंत में इसे मानना पड़ा।

यह जरूरी नहीं था कि मुसलमानों में राजनीतिक जागृति का परिणाम देना का बटवारा ही होता। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अर्थ यह था कि बहुसंख्य वर्ग अल्पसंख्यकों को राष्ट्रीय ढांचे में उचित स्थान दे। दोनों ओर से इसका रास्ता निकालने की लगातार कोशिशें भी हुईं। सन १९०६ में मुस्लिम लीग की स्थापना 'मुसलमानों में अंग्रेजी सरकार के प्रति बफादारी' पैदा करने के उद्देश्य से हुई।<sup>११</sup> किंतु जल्दी ही लीग में एक वर्ग ऐसा भी उठ खड़ा हुआ जो अंग्रेजों की इस चापलूसी के खिलाफ था और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के पक्ष में था। मुहम्मद अली जिन्ना और भी मुहम्मद अली और शीखतजली जैसे प्रगतिशील नेताओं के प्रभाव से लीग ने सन १९१३ में यह प्रस्ताव पास किया कि हमारा मकसद,

११ लीग की स्थापना के समय आगा खॉं और अन्य मुसलमान नेताओं की अंशों से उद्धृत।

‘अंग्रेजी राज के अतगत स्वशासन प्राप्त करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना और इस मकसद के लिए दूसरे संप्रदायों से सहयोग करना है।’ कांग्रेस ने उसी वषर दिसंबर के अधिवेशन में इसका स्वागत किया। दोनों सगठनों में मेल बढ़ा और १९१६ में दोनों के बीच प्रसिद्ध ‘लखनऊ पैक्ट’ हुआ। लीग के राष्ट्रीय हित के बदले कांग्रेस ने पथक संप्रदायिक निर्वाचन, अल्पसंख्यकों को अधिक स्थान और ऐसे कानूनों को रोकने का अधिकार देना स्वीकार किया, जो उनके हितों के विरुद्ध हैं।

कांग्रेस और भी आगे गई। उसने खिलाफत (तुर्की के सुल्तान से राज्य और उनके मुसलमानों के खलीफा पद की रक्षा) आंदोलन का समर्थन किया। गांधी ने इस अवसर का उपयोग हिंदू मुसलमानों को एक झंडे के नीचे लाने में किया। नतीजा यह हुआ कि जब १९२१-२२ में गांधीजी ने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध पहला जन आंदोलन या असहयोग शुरू किया तो मुसलमानों ने उसका पूरा साथ दिया। मौलाना, जवाहर, डाक्टर अन्सारी और दूसरे प्रमुख मुसलमान नेता आंदोलन में शामिल हुए। जिन्ना गांधी को पुराणपथी समर्थक थे और वह इस आंदोलन में नहीं शामिल हुए। लेकिन वे राष्ट्रीयता के समर्थक रहे और मुस्लिम लीग को आधुनिक राष्ट्रीय या सेकुलर लाइन पर चलाने की कोशिश करते रहे।

## विरोध बढ़ा

मगर स्थिति ऐसी पैदा हुई कि कांग्रेस और लीग की एकता कायम न रह सकी और लीग को प्रगतिशील ढंग से चलाने की जिन्ना की चेष्टा भी विफल हुई। जब असहयोग आंदोलन पूरी तेजी पर था और जनता में गहरी उत्तेजना थी, भीड़ द्वारा चौरीचौरा में पुलिस थाने में आग लगा दिए जाने से क्षुब्ध होकर गांधीजी ने आंदोलन का रोक दिया। उनके इस निणय से लोग क्षुब्ध हुए। इसके बाद गांधीजी कैद कर लिए गए। असहयोग के साथ ही खिलाफत आंदोलन और हिंदू मुसलमानों का सहयोग भी खत्म हो गया। लिबरल और नरम दल कांग्रेस से पहले ही अलग हो चुके थे और उनका नया सगठन अभी दृढ़ न हो पाया था। एक और राजनीतिक दृष्टता थी, दूसरी ओर कई स्थानों पर हिंदू-मुसलमानों में दंगे हो गए। इससे स्थिति और खराब हो गई। १९२७ में जब साइमन कमीशन वैधानिक सुधारों के बारे में सुझाव देने के लिए भारत की स्थिति की जांच करने भारत आया, तब मुस्लिम लीग दो दलों में बंट गई थी। एक दल के नेता जिन्ना थे, जो हिंदू-मुसलमानों के संयुक्त निर्वाचन के पक्ष में थे और साइमन कमीशन के धाकड़ों के कांग्रेस के साथ थे। दूसरा दल सर मुहम्मद शफी का था जो पृथक् निर्वाचन के पक्ष में था और साइमन कमीशन के काम में सहभाग देना चाहता था। सन १९२८ में स्वराज्य पार्टी वाला ने एक मजदूर सम्मेलन बुलाया। जिन्ना का गुट इसमें शामिल हुआ।

और भारत का रिपान बनाने के लिए इसने जो कमटी बनाई, उसके काम में हाथ बटाया। सभी गुट ने इस कमटी की रिपोर्ट का नामजूर कर दिया। आगा खा की अध्यक्षता में दिल्ली में मुसलमानों का सत्रदा सम्मेलन हुआ, उसमें भी इस रिपोर्ट को जल्दीनार किया। इन तरह जिन्ना अकेले पड गए और हताश होकर भारत छोड कर इंग्लड चले गये।

सांप्रदायिक समस्या का कोई समाधान नहीं दीरता था। अब यह दो दला के समनोने का प्रश्न न रह कर राजनीतिक एक्ता का प्रश्न बन गया था। इस समस्या का उलझाने में अग्रज सरकार का भी हाथ था। अग्रज सांप्रदायिक समस्या की असतियत का अनुभव करते थे, साथ ही अपनी सत्ता की रक्षा के लिए सांप्रदायिक विराज का उभाडना भी चाहते थे। उनसे हाथ में अधिकार या इतलिए यह अल्प-संख्या का प्रलाभन देकर अपनी जार सीध सकते थे। गिलाफत आंदोलन के एकाएक खतम हो जाने में मुसलमान भी काग्रेस से निराश हो रहे थे। गांधीजी का साथ और अहिंसा पर अत्यधिक आग्रह था, जो बहुत अशा में हिंदू धर्म के आदर्शों में प्रेरित था और उह महात्मा या धार्मिक नेता का पद दिला चुका था। इसमें बुद्धिकारी मुस्लिम नेता उन खिलाफ हो गए। यह एग विडवना थी कि पुराने ग्यास के मुस्लिम नेता कटटर मजहरी दृष्टि के थे और संकुलर या धमनिर-पेश राजनीति के विरुद्ध थे और जिन्ना जस प्रगतिशील मुसलमान गांधीजी के राजनीतिक तरीका और सामाजिक आदर्शों के विरुद्ध थे। इस प्रकार अंग्रेजों की चाल-चाजी, मुस्लिम कट्टरवादियों के दुराग्रह और कोई नया रास्ता निकालने में काग्रेस की असमयता के कारण पूरी जिज पैदा हा गई। अत में हताश होकर भारत छोडने वाले जिन्ना ने ही नयी चाल चनी।

### सांप्रदायिक निणय

१८२- में सांप्रदायिक राजनीति ने पलटा खाया। जिन्ना भारत लौटे। उनके विचार बदल चुके थे। जिस सांप्रदायिक विचारधारा का वह अबतक विरोध कर रहे थे उसे अब वह पूरी तरह अपना चुके थे। उन्होंने मुस्लिम लीग के सामने अपना १४ सूत्री कार्यक्रम पेश किया। इसमें मुसलमानों के जनग निर्वाचन, अधिक स्यान और अपने हितों के प्रतिकूल कानूनों का रोकने के अलावा नई बात यह थी कि कुछ प्राता का हमेशा के लिए मुस्लिम बहुमत क्षेत्र घोषित किया जाये। पहली और दूसरी गोलमेज कांफ्रेंस में मुस्लिम मांगा का आधार यही १४ सूत्री कार्यक्रम था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने सांप्रदायिक निणय (कम्यूनल अवाड) की घोषणा की। इसमें मुसलमानों की सब मांगें मान ली गयी थी। जिन्ना के नये रूप ने भारत की सांप्रदायिक राजनीति को भी एक नया रूप दिया। अभी तक लीग का जनता में कोई संगठन न था। १९३७ के चुनावों में

उसे बंगाल और गु. पी. में कुछ स्थान मिले थे लेकिन वास्तव में वह बुरी तरह हारी थी। उसे चार मुस्लिम बहुमत प्रांत, बंगाल, पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, में से एक में भी बहुमत न मिल सका था। दूसरी ओर कांग्रेस ने मुस्लिम जन संपर्क आंदोलन शुरू किया था और मुसलमानों में पंजाब में युनियन-निस्ट पार्टी और सरहद में खा अब्दुल गफ्फार खा और उनके भाई खान साहब के खुदाई खिदमतगार संगठन का ज्यादा जोर था। ऐसा लगता था कि कांग्रेस और पंजाब, सरहद और बंगाल की मुस्लिम पार्टियाँ वे मुकाबले मुस्लिम लीग टिक न सकेगी। जिन्ना को यह श्रेय है कि उन्होंने लीग को इस दयनीय स्थिति में उबारा और ताकतवर बनाया और १९४५-४६ के चुनावों में जबरन सफलता दिलाई। इन चुनावों में लीग को ४९६ मुस्लिम सीटों में से ४४६ सीटें प्राप्त हुई।

### पृथक निर्वाचन से पृथक राज्य

चुनावों में विफलता होने के बाद मुस्लिम लीग का दिमाग दूसरी दिशा में दौड़ने लगा। पृथक निर्वाचन से अब वह पृथक राज्य की मांग पर आ गई। इस मौके पर कांग्रेस की राजनीति भी चूब गई। १९३७ में कांग्रेस सरकारों की स्थापना के समय, उसमें मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों को शामिल करने की बात चली। जिन्ना भी इसके पक्ष में थे। किंतु जिन्ना के शब्दों में 'अधिकार के मद में' कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कांग्रेस ने यह शत लगायी कि लीग के सदस्यों को कांग्रेस की 'हिवप' को मानना होगा। इससे जिन्ना और उनका दल कांग्रेस से बहुत नाराज हो गया। यह सही है कि चुनावों के नतीजे से लीग के इस दावे का समर्थन नहीं होता था कि वह मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि है, किंतु इस दावे को कांग्रेस ने १९१६ में स्वीकार किया था और तभी से ऐसा माना जाता था। इस दावे को अब न मानने का अर्थ यह होता था कि मुसलमानों को अपना राजनीतिक संगठन करने का हक नहीं है।<sup>११</sup>

लीग के नेताओं ने अब अपनी नीति एकदम बदल दी और मुसलमानों के लिए संरक्षण या विशेषाधिकार के बजाय मुसलमानों के अलग राज्य की मांग पेश की। इस मांग ने हिंदू मुस्लिम संघर्ष के सदर्भ को ही एकदम बदल दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रांतीय सरकारों में हिंसा न मिलने के कारण मुस्लिम लीग का रुख उग्र और लड़ाकू बन गया। इसी समय से जिन्ना दो राष्ट्रों के सिद्धान्त और देश के घटवारे के बटूर समर्थक बन गये। जिन्ना की तीव्र और मजबूत बुद्धि के नेतृत्व में लीग का सारा ध्यान एक ही बात में केन्द्रित हो गया और पिछले बीस वर्षों के असमंजस से निकल कर उसने नयी ताकत पकड़ी।

१२ इस विषय के लिए देखें, श्री अब्दुल क़लाम खान, 'शिया बिस्स प्रीडम' (कम्प्यूट, १९५९)

## पाकिस्तान की माग

पाकिस्तान की बात सबसे पहले डा मुहम्मद इकबाल ने इनाहावाद में मुस्लिम लीग के सालाना अधिवेशन में सन १९३० में छेड़ी थी। उन्होंने पंजाब, उत्तर-पश्चिम सीमाप्रांत, निध और बलूचिस्तान को मिला कर अलग मुस्लिम राज्य कायम करने का प्रतिपादन किया था। मगर बहुत दिनों तक पाकिस्तान का यह विचार धुंधला विचार मात्र रहा। अब चुनावों में कांग्रेस की सफलता और अपनी विफलता के कारण लीग को एक नये प्रोग्राम की जरूरत थी और उसने पाकिस्तान के विचार को आंदोलन का रूप दिया। इस बीच आधुनिकता की प्रक्रिया ने मुसलमानों को भी प्रभावित किया। शिक्षा के प्रसार, शहरीयत के विकास और अखबारों व साहित्य की प्रगति ने मुसलमानों में आत्म गौरव और अपनी विशिष्टता का भाव फैलाया। लोकतंत्री राजनीति से निराशा के कारण उनमें पथक्ता का भाव बढ़ा। १९४० में लीग ने मुसलमानों के अलग स्वतंत्र राज्य का प्रस्ताव पास किया और जिन्ना ने साफ कहा कि हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र के अंग नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि न केवल हिंदू और मुसलमानों का अलग धर्म और संप्रदाय है बल्कि उनकी सभ्यता, उनका इतिहास, उनका समाज और उनका राष्ट्र अलग अलग है। उन्होंने कहा, मुसलमानों की अपनी मातृभूमि, अपना इलाका और अपना राज्य अलग होना चाहिये। यही उनका दो राष्ट्रों का सिद्धान्त था जिसके आधार पर देश के विभाजन की माग उठी और विभाजन हुआ।

यह नहीं कहा जा सकता कि १९३७ और १९४० के बीच लीग की नीति में जो परिवर्तन हुआ उसी ने आगे आने वाली घटनाओं का क्रम निर्धारित किया, क्योंकि अभी भी देश की सबसे बड़ी और ताकतवर सत्ता कांग्रेस थी और विभिन्न वर्गों में उसी का सबसे अधिक प्रभाव था। लेकिन लीग ने ऐसे मौकों पर अपनी नयी नीति और आंदोलन चालू किया जब घटनाएँ बड़ी तेजी से घट रही थीं और कांग्रेस मुसलमानों के इस नये आंदोलन का कोई प्रतिकार न कर सकी। सन १९३९ में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया और कांग्रेस मंत्रिमंडल ने पदत्याग कर दिया। इसके बाद कांग्रेस की अंग्रेजी सरकार से टक्कर हुई, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स का समझौता का प्रयत्न विफल रहा, भारत छोड़ो आंदोलन चला और कांग्रेस के सारे नेता युद्ध की समाप्ति तक जेलों में बंद कर दिये गये।

इससे भारत में राजनीतिक शक्तियों का संतुलन बदल गया। देश भर में कांग्रेस का संगठन अस्तव्यस्त हो गया। कांग्रेस के नेताओं के जेल में बंद हो जाने से मुस्लिम लीग का मैदान खाली मिल गया। इस अवधि में उसने अपना संगठन और बल काफी बढ़ा लिया। जब लंडन के बाद अंग्रेजों से राजनीतिक बातचीत शुरू हुई तब लीग का स्थिति और सीढ़ी बनने की शक्ति काफी मजबूत हो चुकी थी।

बहुत से लोग का ख्याल है कि १९३८ में पदत्याग करने कांग्रेस ने गलती की।



वी पी मेनन ने अपनी किताब 'ट्रांसफर आफ पावर इन इंडिया' (भारत में सत्ता परिवर्तन) में लिखा है कि यदि प्राता में कांग्रेस मंत्रिमंडल इस्तीफा न देते तो भारत के इतिहास का क्रम कुछ दूसरा ही होना। पदत्याग करके कांग्रेस ने दूरदर्शिता और राजनीतिक वृद्धि के शोचनीय अभाव का प्रदर्शन किया। <sup>१३</sup> यदि कांग्रेस के लोग जेल में होने के बजाय सरकार में और निर्वाचित क्षेत्रों में रहते तो अगले चुनावों के समय, उनको लाभ होता, खास कर बंगाल और पंजाब में जिनकी विधान सभाओं में बटवारे की योजना का फैसला हुआ। यह बात कुछ हद तक सही है, लेकिन जिन बातों ने घटनाओं का क्रम निर्धारित किया, वे कुछ और थी।

### ब्रिटिश नीति

अमली बात दो थी - कांग्रेस के प्रति अंग्रेजों का रुख और भारतीय राष्ट्र के भविष्य की कांग्रेस की अपनी कल्पना। युद्ध के बाद भारत की स्वतंत्रता के बारे में जो चानचीत शुरू हुई उससे यह स्पष्ट हो गया। सन १९४५ में लाड वेवल ने शिमला में देश के प्रमुख राजनीतिक दलों का सम्मेलन बुलाया। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग में पूरा मतभेद दीया और कोई नतीजा न निकला। जनवरी १९४६ में ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रतिनिधि मंडल आया। मानच में ब्रिटिश मंत्रिमंडल का मिशन आया। लीग और कांग्रेस में समझौता न हो सकने पर कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना प्रस्तुत की। इसमें देश के बटवारे की बात नहीं मानी गयी और यूनियन आफ इंडिया नाम से एक ढीले सघ की व्यवस्था की गई। इसको रक्षा, परराष्ट्र सघ और संचार के विषय सीपे गए। शेष सारे विषय और अधिकार प्राता के हाथ में रहे। प्राता को यह भी अधिकार दिया गया कि दस वर्ष बाद विधान सभा के साधारण बहुमत से वह इस व्यवस्था में परिवर्तन की मांग कर सकता था। प्राता को समूह बनाने का अधिकार दिया गया। इन समूहों की विधान सभा और कार्यकारिणी अर्थात् सरकार हो सकती थी। हर प्रात के हर सप्रदाय के प्रतिनिधियों की संविधान सभा की व्यवस्था की गई, जिससे प्राता के तीन समूहों के अनुसार तीन खंड हागे और यह देश का संविधान बनाएगी। यह योजना बहुत कुछ सन १९३५ की सघ व्यवस्था से मिलती थी। इसमें त्रुटि यह थी कि वे शीघ्र सघ बहुत कमजोर या और इससे किसी भी समय यह व्यवस्था ठप हो सकती थी। स्पष्ट था कि प्रस्तावित संविधान सभा जो व्यवस्था करती वह बहुत कमजोर सघ या अघ-सघ (कानफेरेन्स) होना। अंग्रेजों की यह याजना कांग्रेस के विचारों के बिल्कुल विपरीत थी। स्पष्ट था कि वास्तविक समस्या का सामना करने के बजाय ब्रिटिश मंत्रियों ने उसे संविधान सभा के माथे टाल दिया। इसमें भय यह था संविधान सभा सघष का जवाब देन जाती और उससे भग होने की नीजत जा जाती। यद्यपि

कांग्रेस ने इस योजना को मित्रात रूप में स्वीकार कर लिया पर इमका कोई अर्थ नहीं था। क्योंकि कांग्रेस के सामने दश के बटवारे या कमजोर और पगु, राष्ट्र का प्रश्न आता तो वह बटवारे को ही पसंद करती जैसा उसने अंत में किया भी। लीग ने इस योजना को पहले स्वीकार करके बाद में अस्वीकार कर दिया और १९४६ में निर्वाचित सविधान सभा का बहिष्कार किया (यद्यपि वह जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में शामिल हुई)। यह भी अच्छा हुआ। इससे देश उस वैधानिक गतिरोध, अराजकता और सेना के बल पर सरकार पर कब्जा करने के सतरे से बच गया, जो इस स्थिति में दूसरे कई देशों में हुआ।

अंतिम दौर बड़े तनाव का रहा। ब्रिटिश प्रधान मंत्री एटली ने पार्लियामेंट में फरवरी २०, १९४७ को घोषित किया कि वे ज्यादा से ज्यादा जून १९४८ को भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंप देंगे। उसने यह भी घोषित किया कि लाड लुई मोटवेटन वाइसरॉय बना कर भारत भेजे जा रहे हैं और उनको इस घोषणा को कार्यान्वित करने का अधिकार सौंपा गया है। इस प्रकार जिम्मेदारी भारतीय नेताओं पर आ गयी। दूसरी ओर इस घोषणा से लीग का होसला बढ गया क्योंकि इसका अर्थ साफ था कि यदि भारतीयों में समझौता न हो सके तो अंग्रेज उसके विभाजन के लिए तैयार हैं। इससे लीग की अलग राज्य की मांग ने और भी जोर पकड़ा। लाड वेवल अंग्रेजों के हटने की कोई तारीख तै करने के विरुद्ध थे। वर्षों बाद में मौ० आजाद ने लिखा 'शायद इतिहास यह सिद्ध करेगा कि लार्ड वेवल की बात ज्यादा समझदारी की थी।' १४

एटली की जल्दी निपटारा करने की इच्छा को लाड मोटवेटन की जबदस्त कर्मठता और दृढ़ निश्चय का बल मिला। उन्होंने कांग्रेस और लीग दोनों पार्टियों को कोई निणय पर पहुँचने को बाध्य किया। मोटवेटन में दूसरों को प्रभावित करने की अपूर्व क्षमता थी। उन्होंने प्रत्येक कठिनाई को सर किया और देश के बटवारे की शल्यक्रिया को बिना समय खोए या आसू गिराए पूरा किया। उन्होंने महात्मा गांधी को एक तरफ कर दिया और वह ऐसे राजनीतिक तत्त्वा को सामने से आए जो वास्तविक स्थिति को देख कर आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा बटवारा करने को तैयार हो गए।

### रक्तपात

एटली सरकार का निश्चय और मोटवेटन का निमम सक्ल्प भी शायद कांग्रेस नेताओं को देश के बटवारे के लिए तैयार न कर पाता, यदि घटनाओं ने भयानक रख न पकड़ा होता। पहले बंगाल में, फिर पंजाब में और बाद को दश के अर्थ भागा में अभूतपूर्व सांप्रदायिक दंगे, सामूहिक हत्याकांड और अराजकता ने कांग्रेस

१४ मौ० आजाद-पूर्वांकित।

नेताओं को देश का विभाजन स्वीकार करने की विवश कर दिया। इस प्रकार दो राष्ट्रों के सिद्धांत की जीत हुई। गांधीजी ने विभाजन का जोरों से विरोध किया मगर उनका न चली। उनके मरने बड़े अनुपाई नेहरू ने दुखी दिल में और पटेल ने दब सक्त्पूवक गांधीजी की वान न मानी।<sup>१५</sup> महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक दंगों की आग को शान करने लिए प्राणा की बाजी लगा दी। उन्होंने पूव बंगाल के दगाग्रस्त नाजाखाली इलाकें में पदयात्रा करके हिंदू-मुसलमानों को शांति का संदेश दिया, दिल्ली में मुसलमानों की रक्षा के लिए पटेल और नेहरू की सरकार के विरुद्ध अनशन किया और मुसलमानों का पक्ष लेने के कारण अंत में एक सुदृष्ट हिंदू आतंतायी की गाली के शिकार हुए। उनके बलिदान ने देश को जियोड कर रख दिया और सारे देश में सांप्रदायिक दंगा को एकदम से शांत कर दिया।<sup>१६</sup>

एक जोर अंग्रेज भारत से जल्दी हटने पर तुले हुए थे, दूसरी ओर वह कांग्रेस-नियंत्रित केन्द्र को सत्ता सौंपने के अनिच्छुक थे। वितु भयानक दंगा ने देश को बटवारे को अनिवार्य बना दिया। कमजोर और ढीला ढाला मध्य देश में और अराजकता पदा बरता। मुसलमानों का कड़ाई से दमन करने का नीतीजा भी अंत में अच्छा न होता। दोनों में से किसी भी हालत में राष्ट्र-निर्माण का वह काम संभव न होता जा भारत में सन १९४७ से हो रहा है।<sup>१७</sup> तथ्य यह है कि घटनाओं ने, जो कुछ हुआ उसके अलावा और कोई रास्ता छोड़ा नहीं।

बटवारे में देर न लगी। भारत और पाकिस्तान की सीमा का निश्चय करने के लिए विधान सभाओं में वाट लिए गए और विवादग्रस्त क्षेत्रों में जनमत लिया गया। दोनों राज्या में मेला, सरकारी सेवाओं, संपत्ति तथा दाने पावने का बटवारा हुआ। यह सब काम बड़ी शीघ्रता से हुआ। ब्रिटिश पार्लामेंट में भारत स्वतंत्रता बिल ४ जुलाई १९४७ को पेश हुआ और १२ दिना के अंदर पास कर दिया गया। १४ अगस्त १९४७ को इंडिया (प्राविजनल कांस्टिट्यूशन) आडर १९४७, पास हुआ और दूसरे दिन भारत और पाकिस्तान दो नए उपनिवेशों की स्थापना हुई और उनको सत्ता सौंप दी गई। अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य अनायास कायम किया

१५ इस फैसले पर भी आजाद के क्षोभ के लिए उन्नी पूर्वोक्त पुस्तक को देखें।

१६ महात्मा गांधी के जीवन के अंतिम ६ महानों में उनके व्यक्तित्व का चमत्कार दिखाई पड़ा। जिस निमयता से उन्होंने मित्रों सरकार की शक्ति को चुनौती देने के लिए दांगी कृच किया था उमा निमयता से सांप्रदायिक दंगों को शांत करने के लिए नोआरान्गी, कलकत्ता और बिहार में वह रक्तपात के बीच कूद पड़े। आइन्स्टायन के शब्दों में आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए यह विश्वास करना बठिन होगा कि वास्तव में ऐसा आदमी क्या भरती पर था।

१७ बटवार ने इस पहलू के बारे में, जिसमें संवृत्त केन्द्र की स्थापना और राज्य मशीनरी तथा राज्य के निमाण में सहायता मिली, आठवें अध्याय में 'अनेकता की रस' शीर्षक से विचार किया गया है।

था और बड़ी जल्दबाजी में उसे खतम कर दिया, मानो उन्हें शका थी कि कहीं भारतीय लाय उनसे यह न कह कि आप न जाइए ।

## दो राष्ट्र

भारत की समस्या के समाधान के बारे में अत मे जो बातचीत और फैसले हुए वे सब अभी प्रकाश में नहीं आए हैं । मगर मुख्य बातें स्पष्ट है । देश के बंटवारे से हवा तो साफ हुई, मगर इसके परिणामस्वरूप बड़ी सांप्रदायिक कटुता और अनेक राजनीतिक समस्याएँ बनी रही । दोनों देशों को और उनकी हिंदू मुस्लिम जनसंख्या को अभी बहुत दिनों तक इन समस्याओं का सामना करना होगा । दूसरी ओर जिस प्रकार ब्रिटिश मजदूर दल की सरकार ने ब्रिटिश साम्राज्य का खातमा किया उससे भारत में उसके प्रति बड़ा सदाभाव पैदा हुआ और उसने ब्रिटिश कामनवेल्थ में बने रहने का फैसला किया । बाद में भारत ने गणतंत्र का रूप धारण करने पर भी ब्रिटिश महारानी को कामनवेल्थ के प्रधान रूप में स्वीकार किया । इस पर ब्रिटिश कामनवेल्थ से ब्रिटिश विशेषण हटाकर उसे 'कामनवेल्थ ऑफ नेशन्स' या राष्ट्रमंडल का नाम दिया । इस परिवर्तन का श्रेय जवाहरलाल नेहरू को है ।

इस प्रकार भारत का बंटवारा हुआ और भारत तथा पाकिस्तान के दो राज्य कायम हुए । भारत में कांग्रेस के हाथ में सत्ता आई और ब्रिटिश राज का उत्तराधिकारी कांग्रेस राज हुआ ।

## आधुनिकता की ओर

वर्तमान भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विचार करने से हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि उगवा राजनीतिक विचार किन परिस्थितियों में हुआ। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य पहलुओं पर विचार करने के पहले यह समझना चाहिए कि इस पृष्ठभूमि का भारत का वर्तमान और भविष्य की कल्पना के लिए क्या महत्व है। जैसा पहले कहा जा चुका है भारत ने अपने विकास का ऐसा ढंग चुना है जिसमें अनेक स्रोतों से प्रेरणा ग्रहण की गई है और जिसमें अनेक तथ्यों को एक साथ सिद्ध करने की कोशिश की गई है। इसमें परंपरा और आधुनिकता के सामंजस्य की भी कोशिश की गई है। हमें देना है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ने विकास की इस पद्धति का किम प्रचार प्रभावित किया है।

### पृष्ठभूमि का महत्व

इस पृष्ठभूमि का मुख्य तत्त्व है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की लचीली अवधि और गहराई। इस बात में भारत एशिया और अफ्रीका के सभी नव स्वतंत्र देशों से अलग है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना सन १८८५ में हुई थी, और यह उन्नीसवीं शताब्दी में होने वाले बौद्धिक जागरण और सामाजिक सुधार की प्रवृत्ति का परिणाम है। परोक्ष रूप से यह अंग्रेजी शासन, शिक्षा, कानून और संचार की प्रणाली का भी परिणाम था।

कांग्रेस की स्थापना के ६० वर्ष बाद भी भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन जारी रहा। इस आंदोलन ने देश को बहुत बड़े बड़े नेता दिए और भारतीयों को सामाजिक और आर्थिक सुधार तथा राजनीतिक संगठन की शिक्षा और राजनीतिक विचारधारा दी। इस लचीली अवधि में आंदोलन कई चरणों में गुजरा। शुरू में करीब ३० वर्ष का समय बौद्धिक आंदोलन और वादविवाद का था। इसी अवधि में आंदोलन के आधुनिकतावादी लक्ष्य निश्चित हुए। गुरु में यह आंदोलन शहर के मध्यवर्ग में चला, फिर यह देश भर में फैला, इसका संगठन व्यापक बना,

इसके हजारों कार्यकर्ता तैयार हुए और उन सबको एक सूत्र में बांधने वाले आदर्श, प्रतीक और विचारधारा विकसित हुईं। इन कार्यकर्ताओं की राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य का व्यावहारिक शिक्षण और अनुभव मिला। हमने पिछले अध्याय में बताया है कि तिलक और गांधी जैसे महान नेताओं ने इस आंदोलन को शक्तिशाली विचार दिए, जिनसे इसका सबव भारत के शानदार अतीत से जुड़ा और जिससे समाज के परंपरावादी और नए विचार वाले, दोनों प्रकार के लोग इस आंदोलन की ओर आकृष्ट हुए। देश के सभी भागों में, शहरों और गांवों में सैकड़ों कार्यकर्ता तैयार हुए जो तिलक और गांधी, नेहरू और पटेल के मधु संस्करण थे। उनके आत्मत्याग और निस्वार्थ प्रयत्नों से यह आंदोलन जनता में फैला। इस आंदोलन की विचारधारा, आदर्श, तथ्यों और साधनों को सबने स्वीकार किया। गांधीजी ने साधनों की शुद्धता पर जोर देकर जनता और सरकार दोनों पर इसके औचित्य का सिक्का जमा दिया। अगर आंदोलन इतना दीर्घकालीन न होता और केवल शहरों तक सीमित रहना ना इसमें इतनी शक्ति और व्यापकता न आ पाती।

मगर कांग्रेस के गांवों तक पहुंचने के प्रयत्नों के बावजूद, बहुत बड़ी जनसंख्या फिर भी इससे अप्रभावित रही और राजनीति से उदासीन रही। कांग्रेस की सफलता यह थी कि वह देश में इतनी दूर तक पहुंची जितनी दूर तक हिंदू या मुगल साम्राज्य नहीं पहुंच सका था। इसमें यह बात भी सहायक हुई कि सारे देश में एक या अंग्रेजी प्रशासन कायम हुआ। स्कूल, अदालत, डाकघर खुले और रेल पहुंची। आवागमन के साधनों के विकास के फलस्वरूप भौगोलिक दूरी कम हो गई। १८ वीं सदी के अंत तक सारा देश अंग्रेजी सत्ता के अधीन आ चुका था। इसके बाद अंग्रेजों का शासन दृढ़ होता गया। उन्होंने जमीन का बंदोबस्त किया और राजस्व की वसूली का नया प्रबंध किया। प्रांता और जिला के प्रशासन का पुनर्संगठन किया, प्रशासन में भारतीयों को भी स्थान दिया, नयी शिक्षा की व्यवस्था की तथा एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था के मूल्यों द्वारा नैतिकता का संस्कार हुआ। अंतिम चरण में भारतीयों को कॉमिलो आदि के चुनाव का और पदग्रहण का भी अवसर मिला और शिक्षा, उद्योग तथा अन्य व्ययसाधनों में भी ऊंचे स्थान मिले। अंग्रेजों ने जो व्यवस्था विकसित की उसका प्रभाव भारतीयों के राजनीतिक संगठन और आंदोलन पर पड़ा। अंग्रेजी शासन-व्यवस्था और भारतीयों में उसकी राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रतिक्रिया दोनों में एक प्रौढ़ता आ गई जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रौढ़ता प्रदान की। बहुत कम नए स्वतंत्र देशों में इसे प्रकार की परिस्थिति थी।

आंदोलन की लंबी अवधि से कुछ और लाभ हुए। राजनीतिक चेतना के सारे मुख्य तत्त्वों के कांग्रेस में संगठन से संस्था और उसके नेतृत्व तथा उसके कार्यक्रम और उसकी विचारधारा के प्रति निष्ठा पैदा हुई। गांधीजी का जनता पर जो

क्षेत्रों में दूसरी जातियाँ भी आगे आईं। किंतु आधुनिक काल के भारतीय पुनर्जागरण के प्रारंभ में ब्राह्मणों के इस नेतृत्व ने नये राष्ट्र को एक सूत्र में बाँधे रखा और पुरानी परंपरा से संबंध ताँडे बिना परिवर्तन को आने दिया।

भारतीय परंपरा की कुछ और विशेषताओं की भी संक्षेप में चर्चा जरूरी है। जाति प्रथा में शासक से लेकर साधारण जनता तक के काम बँटे हुए थे। शासक वर्ग का काम शासन करना और दूसरा का काम राजकीय मामलों में उनका अधिकार मानना था। इस प्रकार उच्च वर्ग या नेता और शासक वर्ग के अधिकार को परंपरा से मान्यता मिली हुई थी। इनके अलावा भारतीय विचारधारा में त्याग और आत्मसमर्पण या कम से कम उपभोग को सदा से ऊँचा स्थान दिया गया है और इसे आत्मोद्धार या आत्मोपलब्धि का साधन माना गया है। इस कारण भारतीय जनता अपने शासकों से ज्यादा मांग या अपेक्षा नहीं करती थी। ब्राह्मण परंपरा के प्रभाव से ज्ञान को हमेशा ऊँचा स्थान दिया जाता था। इसके साथ ही जो वर्ग राजनीतिक या प्रशासनिक मत्ता प्राप्त करता था, उसका समाज में ऊँचा स्थान मिलता था। इससे राष्ट्रीय नेतृत्व का अधिकार जीर दब हुआ। अन्य धर्मों की तरह हिंदू धर्म का कोई कलमा या अपरिवर्तनीय परिभाषा नहीं थी। इस कारण नेता वर्ग धर्म और नीति की व्याख्या देश काल के अनुसार कर सकता था, और जो बातें नये युग के लिए उपयोगी थी, उनका ले सकता था और शेष को छोड़ सकता था। इसी कारण धर्म और समाज में सुधार संभव हो सका और सभ्यता की धारा में किसी व्यक्तिक्रम के बिना उसमें नयी बातें जुड़ती गईं।

इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन और हिंदू सभ्यता की लंबी परंपरा नए भारत की एकता में सहायक हुई और उसने नयी व्यवस्था को गहराई और परिवर्तन तथा ग्रहण करने की शक्ति दी। पुरानी परंपरा और लोकतंत्री व्यवस्था में निरंतर आदान-प्रदान होता रहा। पुरानी परंपरा विभिन्नता और मतभेदों के प्रति सहनशीलता धरती थी और नई लोकतंत्री व्यवस्था विचार तथा काम की स्वतंत्रता का समर्थन करती थी और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहती थी, फलस्वरूप दोनों के मेल में कोई कठिनाई नहीं हुई। यदि राष्ट्रीय आंदोलन इतना लंबा न चला होता और जनता में इतनी अँड़ गहरी न गयी होती, तो स्वतंत्रता के समय नई और पुरानी परंपरा में यह सामंजस्य न हो पाता।

दूसरी ओर राष्ट्रीय आंदोलन के इतना लंबा चलने के कारण कुछ कठिनाइयाँ भी पैदा हुईं। स्वतंत्रता के मिलने का नतीजा यह हुआ कि भारत ने जब देश के आर्थिक और राजनीतिक निर्माण का काम उठाया, उस समय आंतरिक और बाहरी दोनों समस्याएँ काफी उग्र हो उठी थीं। दूसरे देशों को अपने विकास का और अपनी व्यवस्था को आधुनिक रूप देने का काफी समय मिला। भारत को यह समय नहीं मिला कि वह

करे। उसे सब काम एक

साथ करने पड़े। सब काम एक साथ करने का अर्थ यह हुआ कि आर्थिक समस्या पर सब से अधिक ध्यान देना पड़ा जबकि और समस्याएँ कम महत्त्व की न थी। इस कारण काफी गड़बड़ी हुई। अतः मैं एक रास्ता निकाला गया और कौन से काम पहले किए जाएँ इसका एक क्रम भी निर्धारित हुआ पर इस बीच बहुत-सा समय और साधन बरबाद हुए, जनता की आशा और विश्वास को धक्का लगा, जिससे सरकारी ढाँचे में बड़ी अस्थिरता आई। अतः मैं विकास का जो ढाँचा बना उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे।

इसी प्रकार अंग्रेजी शासन की लचीली अवधि से लाभ और हानि दोनों हुए। अंग्रेजी शासन के दौरान प्रशासन आदि का जो ढाँचा बना, वह स्वतन्त्रता के बाद देश की राजनीतिक एकता और आर्थिक विकास का भी आधार बना। किंतु अंग्रेजी शासन में जो नौकरसाही का ढाँचा, शिक्षा व्यवस्था, कानूनी मशीनरी, कानून बनाने की पद्धति, कारवाई में ढीलापन और सुस्ती तथा कुछ स्वार्थी वर्गों का निर्माण हुआ, वह तेजी से परिवर्तन लाने में बाधक हुआ। समस्याओं को सुलभाने, निणय लेने और नीति निर्धारित करने में यहाँ जो अत्यधिक देर लगती है और बाल की खाल निकाली जाती है, उसका कारण अंग्रेजी शासन काल में पड़ी सोचने की आदत, शिक्षा की पद्धति और प्रशासक का ढंग है।

इसी तरह हम यह भी कह सकते हैं कि हमारी प्राचीन सभ्यता की परंपरा जहाँ नये और पुराने के सामंजस्य में सहायक हुई, वहाँ उसकी कुछ त्रुटियाँ भी हैं। शास्त्रों की ब्रह्मवाक्य समझने की हमारी आदत, हमारे सामाजिक ढाँचे की कठोरता या जड़ता, सामूहिक चेतना का अभाव, सांसारिक या लौकिक कार्यों की उपेक्षा, राष्ट्रीय भावना और संगठन का अभाव, समस्याओं और अप्रिय प्रश्नों का सामना करने के बजाय उसको टालने की प्रवृत्ति, हमें इसी प्राचीन परंपरा से मिली है और इसी कारण से हमारे यहाँ सबल लौकिक, गैरमजहूरी राष्ट्रीय सृष्टि कायम नहीं हो सकी है।

हिंदू सृष्टि, राष्ट्रीय आंदोलन और विदेशी औपनिवेशिक शासन की अनेक बातें स्वतन्त्रता के बाद भी चली आई हैं और आधुनिक विचारों, मूल्यों और समस्याओं से इनकी परस्पर प्रतिप्रिया हुई है। हम स्वतन्त्रता के पहले और बाद में इस प्रतिप्रिया का विस्तार करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि प्राचीन परंपरा की आधुनिक प्रवृत्तियों ने किस प्रकार प्रभावित किया है और आधुनिकीकरण की चुनौती के प्रति भारत का रुख सामान्यतः क्या रहा है।

**आधुनिकीकरण का स्वरूप**

भारत में आधुनिकता के प्रभाव से जो प्रतिप्रिया हुई, उन्हीं पुरानी परंपराओं और सृष्टि के प्रति नया बोध उत्पन्न हुआ, उन्हीं पुनर्जागरण और पुनरुत्थान के प्रयत्न हुए तथा नए नए रूप देने की कोशिशें की गयीं। आधुनिकता के प्रतिप्रिया-



स्वरूप भांगतीयता की भावना बढ़ी और इसे नया अर्थ और रूप देने का यत्न किया गया।

भारत में यह बात नहीं स्वीकार की गई कि आधुनिकता का अर्थ पुरानी बातों को जड़मूल से पट्ट करके एकदम नई बातों को अपनाना है। दूसरी ओर यहाँ यह दृष्टि भी नहीं रहा कि नई बातों में कोई तत्त्व नहीं और पुरानी परंपरा और पुराने मूल्य ही शास्वत और सही हैं।<sup>१</sup> अगर कहें कि भारत ने मध्यमांग ग्रहण किया और कुछ पुरानी बातों को बनाए रखने के साथ साथ नई बातों को भी स्वीकार किया यह भी भारत में हुई प्रतिक्रिया का गही यत्न नहीं। कुछ लोगों ने इनका या कहा है कि भारत में प्राचीन परंपरा को सार्वजनिक रूप दिया गया।<sup>२</sup> अगर इस मत में प्राचीन परंपरा को अत्यधिक महत्व दिया गया और इस पर सही ध्यान नहीं दिया गया कि आधुनिक मूल्यों और संस्थाओं ने पुरानी परंपरा का प्रतिगौरव के भाव को जगाने और उसे आधुनिक अर्थ देने में कितना योग दिया। पुरानी परंपरा या ही स्वयं नहीं जीवित हो गई। इसलिए हमें पुरानी परंपरा और आधुनिकता को अलग अलग न लेकर उनसे परस्पर संबंध पर, उस प्रक्रिया पर, जिस से ये संबंध बने और एक दूसरे के लिए उनकी उपयोगिता पर विचार करना चाहिए। जब एक प्राचीन समाज अपनी समृद्ध परंपरा और विविधता को त्यागने बिना, अर्थात् मे नये युग के अनुरूप परिवर्तन करके अपने का जीवित रखने का प्रयत्न करता है तो नए और पुराने का यह मिश्रण क्या रूप धारण करता है, इसे समझना आवश्यक है।

परिवर्तन कब शुरू हुआ इसकी कोई तारीख या समय बताना कठिन है खान कर भारत के लिए, क्योंकि यहाँ के समाज की यह विशेषता है कि इसका कुछ अंश तो एकदम जड़ हो गया और कुछ अंश गतिशील बना रहा। यह कहना हान्यस्पद है कि भारत का समाज एकदम जड़ और निर्जीव हो चुका था, और विदेशी शासन के धक्के से इसमें फिर चेतना आई। हमने देखा है कि मुस्लिम शासन और मुगल शासन की स्थापना ने पुरानी व्यवस्था को गहरा धक्का दिया।<sup>३</sup> बाद विदेशी अंगरेजों का औपनिवेशिक शासन स्थापित हुआ, जिससे अतृप्त व देश में एक केन्द्रीय सत्ता स्थापित हुई, कानून और व्यवस्था कायम हुई<sup>४</sup> सामाजिक और बौद्धिक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए, जिससे विदेशी शासन

१. मैने इन विरोधी मतों पर अपनी 'डिडिशन ऐंड माइनिटी सिचिनेस' गवर्नेट डेड ब

जिशन, ३, स ३, १९६८ अध्याय, में विचार किया है।

२. देखें लायड आर स्टोल्क और ससन ऐंड स्टोल्क, 'माइनिटी ऐंड डिडिशन (सि १९६७) स मान्यत इस विचार से मनमोद रखने पर भी हम इसकी बहुत सी बातों से हैं, खास कर जाति-प्रथा और नस्ल संबंधी। परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व को हम ५ नहीं स्वीकार किया गया, यह एक अच्छी बात है।

लेकर आधुनिकता की पूरी पद्धति को स्वीकार कर लिया गया। वास्तव में देश के सामने जो नए आदर्श और लक्ष्य रखे गए, वे भी एक नहीं थे। उनमें से अनेक विकल्प परस्पर विरोधी भी थे। उदाहरण के लिए, देश में व्यवस्था रखने और अनुशासनपूर्वक विकास के लिए शक्तिशाली एकतंत्री व्यवस्था बनाम व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर आधारित प्रतिनिधित्वपूर्ण लोकतन्त्र, मजबूत केन्द्रित सत्ता बनाम स्वायत्त इकाइयाँ का ढीला ढाला सघ, दला की प्रतिद्वंद्विता और बहुमत का राज्य अथवा अल्पमण्डल का या विशेष हितों का प्रतिनिधित्व, अथर्व्यवस्था पर सरकारी स्वामित्व या राष्ट्रीयकरण बनाम निजी उद्योग, उनमें औद्योगिक देशों के लिए कच्चे माल का उत्पादन और निर्यात करके उनसे सहायता और विशेष व्यवहार प्राप्त करना या खुद पूरी तेजी से उद्योगीकरण करना, और ऊँचे सुसंस्कृत वर्ग की शिक्षा-प्रणाली या समाज में समानता को बढ़ावा देने वाली सब साधारण की शिक्षा। भारतीयों में ससदीय लोकतन्त्र की पेचीदा प्रणाली को चलाने की योग्यता है या नहीं, इस पर भी अंग्रेजों को संदेह था और कुछ भारतीय भी उनसे सहमत थे। महत्त्व की बात यह है कि जतन में भारत ने कौन-सा रास्ता चुना और किस विचारधारा की जीत हुई।

इस चुनाव को ब्राह्मण की उदार विचार की प्रवृत्ति और विचारों की विभिन्नता के प्रति सहिष्णुता की हमारी परंपरा दोनों ने प्रभावित किया। कुछ पुरानी दूषित परंपराओं को त्याग दिया गया, जैसे समाज में ऊँच नीच, धोर असमानता तथा कट्टर सक्तीयता की। दूसरी ओर पुरानी परंपरा ने यह आत्मविश्वास उत्पन्न किया कि भारत के लोगों में विवेक और बुद्धि का माग ग्रहण करने की क्षमता है। इस बात पर भी सहमति थी कि भारतीय सम्यता की समृद्ध परंपरा का बनाये रखने के लिए ऐसी शासन व्यवस्था को अपनाना चाहिये, जिससे देश के सभी मतों और संप्रदायों की स्वतन्त्रता सुरक्षित रहे। जाधुनिक अधिनायकतन्त्र या तानाशाही की व्यवस्था न तो इतने बड़े देश की एकता कायम रख सकती थी और न उसकी भाषा, धर्म और संस्कृति की विविधता की धरोहर की रक्षा कर सकती थी।

यह चुनाव सहज ही या स्थायी रूप से नहीं हो गया। उदाहरण के लिए बहुत से नेता मजबूत केन्द्रित एकात्मक सरकार के पक्ष में थे (और हैं) जो देश की केन्द्र-विरोधी गतिविधियों पर अकुण्ठ रह सकें। देश के विभाजन ने ढीले ढाले सघ के पक्ष में (जिसमें हिंदू बहुमत और मुस्लिम बहुमत प्रांतों का बहुत स्वायत्तता होती) सबसे बड़े तक का खतम कर दिया, और 'शक्तिशाली केन्द्र' का पक्ष और मजबूत कर दिया। लेकिन दूसरी ओर विकेंद्रित व्यवस्था की धारणा भी बड़ी मजबूत थी और प्रभावशाली प्रांतीय नेता जिन्होंने राष्ट्रीय जादालन को मजबूत बनाया या केन्द्र का सारे अविवार दे देने के विरुद्ध थे। विवादी परंपरा केन्द्रीकरण के विरुद्ध थी और गांधी का राष्ट्रीय शासन बनाना या गरीब और

घोषित ग्रामीण जनता को देश की स्वतंत्रता से हाने वाले लाभों का उचित हिस्सा देना चाहनी थी। देश के नवियुवाओं के निमानाश को इन दाना विराधी विचार-धाराओं में सामंजस्य करना था, जत उन्होंने ऐसी व्यवस्था की जिसमें केन्द्र को व्यापक क्षेत्र और शक्ति-साधना में प्रमुख भाग और अवशिष्ट अधिकार दिये गए। साथ ही राज्यों का भी काफी अधिकार प्राप्त हुए। आगे चल कर एक ओर बात की गई जिससे भारतीय राज्यव्यवस्था के सदीय स्वरूप को और बल मिला। यह थी पंचायती राज (लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण) की व्यवस्था। इसका आधार पुरानी परंपरा और गांधी-विचारधारा में था, लेकिन इसे लागू करने का श्रेय जवाहरलाल नेहरू को था। इस पद्धति पर जोर भारतीय सभ्य व्यवस्था के साधारण स्वरूप पर हम जागे के अध्यायो में विचार करेंगे। यहां हम यह देनेगे कि केन्द्र और परिधि (राज्य) के संबंध को निश्चित करने में, परंपरा और आधुनिकता की प्रवृत्तियां, उनके प्रभाव से निर्मित राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधारा, देश की परिस्थितियां तथा नेताओं की दूरदर्शिता और विचार-इन सब का प्रभाव पड़ा।

इस नई व्यवस्था का चलाने में सबसे महत्वपूर्ण भाग था एक मध्यवर्ती नेतृत्व का जो सबसे ऊपर के राष्ट्रीय नेताओं में और सबसे नीचे के ग्रामीण नेताओं में संबंध जोड़ता है। इन बीच के आदमियों ने प्राचीनता और आधुनिकता में समझौता कराने में बड़ी योग्यता का परिचय दिया है। भारत में राजनीतिक सोदेबाजी या मोल भाव की इस नई प्रणाली को कुछ राजनीतिक आलोचक लक्ष्य नहीं कर सके।<sup>४</sup> ऊपर के नेताओं और जनता के जगुआ में यह मोलभाव सीधा नहीं, अपर्युक्त मध्यस्थ वर्ग के जरिये होता है। यह मध्यस्थ वर्ग जिला या निवाचन क्षेत्र के स्तर पर काम करता है। ये मध्यस्थ दलाना की भांति महज सोदा ही नहीं पटात, बल्कि ये दोनों पक्षों का एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं, और बताते हैं कि उन्हें क्या अवसर मिल रहे हैं। इस तरह वे नई व्यवस्था के सर्वोत्तम संचालक और सगठक सिद्ध होते हैं।

पश्चिमी लोकतंत्र में विभिन्न हिता का समुच्चयन या एकीकरण राष्ट्रीय स्तर पर होता है जबकि पुराने ढंग की राजनीतिक व्यवस्था में हित व निष्ठाएं अलग अलग खंडों में बंटी होती हैं। भारत में जो नई प्रणाली विकसित हुई है, वह इस से भिन्न है। इस में शक्ति बिखरी हुई या अकेन्द्रित है और विकसित हुई है एक व्यापक व्यवस्था के अंतर्गत अनेक स्वतंत्र छोटी व्यवस्थाओं का रूप धारण करता है।

४ माइरन वानर, 'द पॉलिटिक्स ऑफ स्केयर्स'। पब्लिक प्रेशर ग्रैंड पॉलिटिकल रेस्पॉन्स इन इंडिया (शिफांगो १९६२)। इसका सारांश देते हुए भूमिका में मेथ्रियल आमंड का कहना है कि भारत में सोदेबाजी का प्रणाली का प्रभाव है। मगर वानर ने इस बात पर जोर दिया है कि यहाँ साम्यवाद की परिपाटी नहीं। हमने इस विषय पर अ. याय ५ में सविस्तर विचार किया है नेतृत्व में साथी सोदेबाजी का उभरती हुई प्रवृत्ति के लिए देखें अ. याय ८।

इन छोटी व्यवस्थाओं से स्थानीय हिता की रक्षा होती है। पुराने समय में स्थानीय सामंत या मुखिया और उनकी जायित प्रजा में जो सन्ध होता था कुछ बसा ही इस मध्यवर्ती व्यवस्था का भी है। इसके साथ ही आधुनिक राजनीतिक क्रिया-कलाप में भी ये हाथ बटाती है। इस प्रणाली का हम मध्यवर्ती समुच्चयन वह सकते हैं। आगे के अध्याय में हम प्रशासनिक और दलीय प्रणाली में इस मध्यवर्ती गत्य के स्थान पाने पर विचार करेंगे। इस समय इतना ही कहना काफी है कि पुराने और अनेकात्मक समाज में राष्ट्रनिर्माण की क्रिया इस प्रकार की मध्यवर्ती प्रणाली का जन्म देती है, जो केन्द्र और इकाइया में पुरानी और नई व्यवस्था में सन्ध जोड़ती है।<sup>५</sup> इस मध्यवर्ती प्रणाली का मुख्य काम नेता और जनता, सरकार और प्रजा, केन्द्र और प्रदेश या जिला के बीच मध्यस्थता करना है।

परपरा और परिवर्तन की प्रवृत्तियाँ की परस्पर क्रिया पर विचार करते समय राजनीतिक विकास संबंधी कुछ और प्रश्न उत्पन्न हैं। एक तो यह कि परपरा और आधुनिकता की इस दुहरी प्रणाली की केन्द्रीय प्रतीक कहा तक प्रभावित कर सकते हैं। नई शिल्प विधियाँ और राजनीतिक तंत्र के सामने पुराने आदर्श और प्रतीक डगमगा रहे हैं। इस स्थिति में यह प्रश्न महत्व का है। दूसरा प्रश्न यह है कि ऐसे अनेकात्मक समाज में राष्ट्रीयता का सच्चा बोध कहा तक हो सकता है। तीसरा, यदि नई अस्मिताएँ या निष्ठाएँ उदय होती हैं तो उसके साथ कौन से नए संघर्ष और अंतर उत्पन्न होते हैं। तीसरे, ऐसी दोमुहों (आगे और पीछे देखने वाली) व्यवस्था में भविष्य की ओर देखने की प्रवृत्ति कैसे लाई जा सकती है, जिससे आगे उठने वाली समस्याओं को देखा जा सके और उनका उपाय किया जा सके और उनको भविष्य के भरोसे न छोड़ा जाए।

राजनीतिक संस्कार और नई व्यवस्था की सफलता संबंधी अध्याय में हम इन प्रश्नों पर विचार करेंगे। यहाँ हम कुछ संकेत करेंगे।

## केन्द्र और परिधि

प्रत्येक सम्यता में कुछ केन्द्रीय प्रतीक होते हैं जो पूरे समाज को बाँधे रहते हैं। भारत में भी इसी प्रकार के संस्कारों की एक जटिल परपरा थी, जो विभिन्न प्रदेशों

---

<sup>५</sup> बर्क, दुखान, टाउबिन्, टोनान तथा अन्य लेखकों के ग्रंथों में मध्यवर्ती समूहों और उप-व्यवस्थाओं का महत्व स्वीकारा गया है। इधर एडवर्ड शॉल्स तथा राबर्ट टाल ने इस विषय पर विचार किया है। भारत में आर. भास्करन ने इस विषय पर काफी लिखा है। पश्चिम के इस साहित्य की समाक्षा के लिए देखें 'मारिंस पिना', 'मास सेन्सार्सी एंड पालिटिक्स' मूवमेंन्स-ए-थू फामुलेशन (द एनुअल अमेरिकन नैशनल आफ सोसियोलॉजी, मई १९६८) तथा आर. भास्करन 'सेमिगोएला' आफ पालिटिक्स (बंबई १९६८)

मे विभिन्न स्थानीय समाजा की विचार-धारा का निमाण करनी थी। भारत की यह विशेषता थी कि यहाँ की परंपरा के निमाण करने वाले ये प्रतीक कि सी राजनीतिक व्यवस्था से घटे नहीं थे।<sup>१</sup> इस परंपरागत व्यवस्था पर आधुनिकता की प्रवृत्तिया का प्रभाव पड़ा जिसके साथ नई संस्थाएँ, मूल्य और प्रतीक आए। इन नए प्रतीकों ने पुराने विश्वासों को बिना नष्ट किए, पुरानी निष्ठाओं और प्रतीकों का नया रूप दिया और पुरानी और नई व्यवस्थाओं में मेल मिलाया। इस प्रक्रिया ने नए मध्यस्थ वर्ग को जन्म दिया, जो राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था और स्थानीय समाजों का जोड़ता है। यह मध्यस्थ वर्ग नए राजनीतिक प्रतीकों का जनता में प्रचार करता है। जमा कि कहा जा चुका है ये नए प्रतीक बिल्कुल नए नहीं हैं, इन्होंने पुराने प्रतीकों और विचारों में से बहुत कुछ ग्रहण किया है। इस प्रकार भारतीय समाज की विविधता नई व्यवस्था में भी बनी रही। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है, इसके द्विआत्मक रूप की उम्मेद नहीं की जा सकती। नए केन्द्रीय प्रतीक उन्नीसवीं तक साथ-साथ होते हैं, जिस हद तक वे परंपरागत विविधता को बनाये रखते हैं। यह जरूरी नहीं कि परंपरा हमेशा पुरानी ही हो। नई परंपरा भी तभी से बनती रहती है। स्मरण रखना चाहिए कि एक लगातार चली आई सम्यक्ता में आधुनिकता तभी जीवित रह सकती है जब वह स्वयं परंपरा बन जाए।<sup>२</sup> पुराने प्रचलित परंपरा के ढाँचे में मिल कर ही नए केन्द्रीय प्रतीक पूरे समाज में व्याप्त होते हैं। इसी प्रकार वे केन्द्रीय बनते हैं।

जो बात प्रतीकों पर लागू होती है, वही राष्ट्रीय निष्ठा पर भी लागू होती है। इस विषय में भारत का तरीका पश्चिम में भिन्न है। यदि पश्चिम की तरह यहाँ भी सब लागू पर एक ही निष्ठा लादने की कागिरी की जाती, तो या तो यह चेष्टा विफल होती या यह देश को टुकड़े टुकड़े कर देती। छोटी छोटी आदिम निष्ठाएँ राष्ट्रीय व्यवस्था पर तनाव कम करती हैं। साथ ही राष्ट्रीय निष्ठा, विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी निष्ठाओं पर ही आधारित होती है। भारत जन्म विशाल और विविधतापूर्ण देश में ही नहीं, किसी भी देश में एक अस्पष्ट और अमूर्त राष्ट्र के प्रति तादात्म्य या निष्ठा समभव नहीं। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन को लंबी अवधि और गहराई ने यहाँ राष्ट्रीय निष्ठा के निर्माण के लिए आधार

६. रॉय रेडफोर्ड 'सिविलाइजेशन ऐन कंवरल स्ट्रक्चर्स' सत्र फार एडवार्ड स्ट्रॉड इन डिसेम्बर १९३६ स्थान फोड में दिया गया भाषण तथा बनावट प्रम कोन और मेन्किम मैरियट 'नेटवर्क ऐंड समी' इन द इंडियन आफ इंडियन सिविलाइजेशन, जर्नल ऑफ मासल रिस्च (रांचा) १ सित १९५८

७. राजनीति और संस्कृति के इस अलगाव पर अन्वय ७ में विचार दिया गया है।

८. आधुनिकता के परंपरीकरण पर मेरे, 'ट्रैडिशन ऐंड माडर्निटी सिविलिजेशन' में विचार दिया गया है।

रामा । राष्ट्रिय आंदोलन पुरानी निष्ठाओं और प्रतीकों का सहारा न ले कर ही सदा ही सना । स्मरता व बाद भी यही प्रेम जारी है ।

जब हम इन निष्ठाओं के स्वरूप पर विचार करते हैं तो हम परंपरा और परिवर्तन का परस्पर क्रिया का ज्ञान होता है । अगर यह कहा जाता है कि पुराने समाज में काया का विभाजन ठीक नहीं होता, जबकि नए समाज में यह विभाजन बूझ और जटिल होता जाता है । पर भारत के उदाहरण से इस धारणा का खंडन होता है । छठे अध्याय में हम देखेंगे कि न सिर्फ भारत की प्राचीन समाजव्यवस्था में काया का बंटवारा बूझ और जटिल था, बल्कि यह व्यवस्था स्थिति के अनुसार बदलती भी रहती थी । आधुनिक युग में एक तरफ जाति, मजदूर भाषा और प्रदेश व पुराने विभाजनों ने जातीय प्रादेशिक और भाषिक साठना और संस्थाओं का रूप लिया है दूसरी ओर एक ओर नए विस्मय के विभाजन भी पदा हुए हैं और नई सत्ता और पद की व्यवस्था के जग बन गए हैं । ये नए विभाजन नए ढंग के व्यवसायिक गान्धर्व व्यापारों और विपुल राजनीति साठना हैं । अगर इन नए वर्गों के संतुल्य पुनर्गठन परंपरागत वर्गों के ही बराबर हाथ है । जग देने के बाद समाज में नए पक्षों का प्रवेश ने नए पेशे का जपनाया, पुराने व्यापारी घराना के सड़क ने नए उद्योग-प्रतिष्ठान कायम किए और वाणिज्य मंच की स्थापना की सना में पुराने पांडा वर्गों के सागा का प्रमुख स्थान रहा । जहां इस प्रकार का विनम्रता रहा रहा और विलकुल नए लोग का उदय हुआ, वहां उनकी भी समाज के पुराने ढांच में ऊंचा स्थान दिया गया ।

इस प्रकार जो वर्ग सत्ता और पद के दावों के बाहर रहते थे उनका भी अंदर जाने का मोहा मिला । पिछड़ी जातियों के लिए सरकारी नौकरियां, शिक्षा संस्थाओं और विधानसभाओं में स्थान सुरक्षित किए गए । सभी राजनीति संगठन विभिन्न जातियों का जग रखने का महत्त्व समझते हैं । इससे पुरानी व्यवस्था की यह त्रुटि दूर हुई कि सारी जाति का एक ऊंची जाति का हा गया में रक्षा था और सारी जातियों का दूसरा दबा निम्नता था तथा व एक तरह से राष्ट्र की संस्था में बंटा रहती थी । मनुका राज्य जगता जग उभरा राष्ट्रों ने भी यही सुरक्षा था । भारत में वर्ग-समस्या के इस रूप के प्रसरण का एक कारण यह भी है कि वहां बहुत-सी जातियां हैं इस कारण वहां जाति वर्ग को अंदर जाने का मोहा मिला रहा और व्यवस्था की तीव्रता रहा जग गई । जाति प्रथा का जगता रहा है एक विशेषता बाहर से जाने का मनुका का । इस सना में स्थापित स्थान दूर निम्नता के की प्रगति रहा है । भारत में पुराने और नए समाज में जाति और वर्ग की द्विक अवस्था समाज के जग वर्ग का टकरार रहा है । जातिवाद और वर्गवाद का वर्ग का टकरार रहा है । जातिवाद और वर्गवाद का टकरार रहा है । जातिवाद और वर्गवाद का टकरार रहा है ।

नेहरू के वस्तुनिष्ठ और लचीले दृष्टिकोण और प्रतिनिधित्व की प्रणाली में उनकी आस्था से भी इस प्रक्रिया में बहुत मदद मिली।  
मगर उग्र संपर्प या छद्मीकरण के अभाव का सारा श्रेय पुरानी अनेकनिष्ठ समाज-व्यवस्था को ही नहीं है। स्वतंत्रता के बाद शुरू से ही राष्ट्रीय नेता वग ने भी संपर्प और अततोप के कारणों का दूर करने का प्रयत्न किया। यह उनकी दूरदर्शिता का द्योतक है। इस प्रकार उन्होंने जमींदारी और सामंती अधिकारों का अंत किया, मजदूरों के हित के कानून बनाये पिछड़े वर्गों और हरिजनों को विशेष सरक्षण और अधिकार दिये, हिंदू कोड बना कर स्त्रियों की स्थिति सुधारी संपत्ति के अधिकारों को सामाजिक न्याय के ऊपर स्थान मिले इस उद्देश्य से सविधान में संशोधन किये, भाषाओं के विवाद को सुलझाने के लिए राज्यों का पुनर्गठन किया। संध से अलग होने के आंदोलनों पर राक लगाई तथा राष्ट्र विरोधी और हिंसात्मक प्रवृत्तियों को कड़ाई से दबाया। य सब कारवाइयां शुरू से ही की गईं और इनसे संध और तनाव दूर होने में बड़ी मदद मिली। हो सकता है कि इन सभी कदमों का पहले से न सोचा गया हो, परंतु इन सब की जड़ राष्ट्रीय आंदोलन और नेताओं की विचारधारा में थी। इस प्रकार राष्ट्रीय संगठन में नेताओं की राष्ट्रीय विचारधारा और दूरदर्शिता का भी उनका ही हाथ था जिनका पुरानी सहिष्णुता और समन्वय की परंपरा का।

### परिवर्तन के प्रेरणा स्रोत

परंपरा और परिवर्तन की चर्चा खतम करने से पहले हम चार बातों पर जोर देंगे। एक तो यह कि भारत से सामाजिक और राजनैतिक ढांचे में जो परिवर्तन आया उसकी प्रेरणा नये विचारों, संस्थाओं, शिल्प व उद्योग और संचार के नए साधनों के संपर्क से मिली। परंपरा के लचीलेपन और ग्रहणशीलता पर जोर देते हुए, कुछ लोग पुरानी परंपरा को ही परिवर्तन का स्रोत समझ बैठे हैं।<sup>९</sup> हम इस धारणा का खंडन करते हैं। परंपरा पर परिवर्तन की प्रतिक्रिया होती है वह परिवर्तन को जन्म नहीं देती। इसके प्रमाण हैं कि जब अंग्रेजी राज की शुरुआत हुई उस समय समाज में कुछ परिवर्तन होने लग गये, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि परिवर्तन का मुख्य स्रोत पश्चिम का प्रभाव ही था।<sup>१०</sup> दूसरी बात यह है कि इस परिवर्तन को प्रगल्भ करनेवाला एक नया नेता या सुधारक वग था, यह समाज की केन्द्रीय परिचालक शक्ति था। समाज के निचले और बीच के स्तरों पर भी इसी प्रकार के नेतृत्व का उदय हुआ और इसी ने देश

<sup>९</sup> कृष्णलाल शंकर, पूर्वोक्त और सिंगर, पूर्वोक्त।

<sup>१०</sup> पश्चिमीकरण के नृशास्त्रीय विवेचन के लिए देखें, श्रीनिवास सोशल चेंज इन माडर्न इंडिया' (बर्कले १९६६) अध्याय-२।





पर आयाचित न थी, साथ ही यह अस्पष्ट भी न थी इसमें परस्पर जोर जायुनिकता धुली मिली थी। महान नेताओं की तरह इस संगठन का भी जनता पर चमत्कारी प्रभाव पड़ा। १२ भारत को जायुनिकता की ओर ले जाने वाली यह ऐतिहासिक शक्ति थी। इस राष्ट्रीय संगठन के मामले में भी भारत अन्य जनक देशों से अधिक भागवान रहा।

इस प्रकार भारत की प्राचीन सृष्टि के जायुनिकीकरण में उपयुक्त कई बातें सहायक हुई। ये थी इतिहास के अत्यंत दीर्घजीवी और शक्तिशाली विदेशी शासन के साथ जाया जायुनिक युग का जबदस्त प्रभाव तथा राष्ट्रीय आंदोलन जायुनिक विचारों से जातप्राप्त देशव्यापी प्रभाव वाला राष्ट्रीय नेतावर्ग चमत्कारी व्यक्तित्व वाले महान नेता और व्यापक राष्ट्रीय संगठन। इससे साथ ही हमारी पुरानी परंपरा का लचीलापन और नई बातों को ग्रहण करने की शक्ति ने भी भारत के जायुनिकीकरण में जबदस्त योग दिया।

१२ इस विषय के सैद्धांतिक विवेचन के लिए देखें - एम्बेड शि स, 'द कॉन्फ्रेंशन ऑफ़ डिपेंडेंस ऑफ़ कैपिटलिज्म' ब्रिटेन में लिखित ११ स, १, अक्टूबर १९५८। इसी प्रकार कांग्रेस के बारे में विवेचन के लिए देखें - मेरा निबंध 'नेशन मेकिंग ऑफ़ कान्सेसस द वेस ऑफ़ द इंडियन नेशनल कांग्रेस - सेवेंथ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ़ द इन्टरनेशनल पोलिटिकल साइंस असासिएशन, मुंबई १९६७।

मे नये विचारा ना फलाया और पुराने समाज को नई दिशा और नये उद्देश्य दिये । नई सम्मेलन नए मूल्य और नए तरीका का चालू करने का मुख्य कार्य नए नेताओं ने किया और स्थानीय प्रमुखा और जनसाधारण ने इनका राजनीतिक समर्थन दिया और इनके नेतृत्व को स्वीकार किया ।<sup>११</sup> इस प्रक्रिया का दम दान से भी बल मिला कि नेतावग अधिरत परपरागत प्रमुख वग से ही जाए वे और उन्होंने पुरानी परपरा और मूल्य को ही नए रूप में जारी रखने का प्रयत्न किया था । नई शिक्षा का मजस उत्साहपूर्वक पुराने ब्राह्मण और ऊँची जातिया ने ही अपनाया ( संस्कृत माहिष और चर्दिक अध्ययन की परपरा नई शिक्षा में भी आई ) इस प्रकार परपरागत विद्या के संरक्षक नई विद्या के भी संरक्षक बने । इससे परिवर्तन की क्रिया सहज हुई । फिर भी दश के विभिन्न भागों में इस आधुनिकतावादी शहरी, पौर्व और अग्रणी शिक्षित प्रमुख वग का उदय हुआ, जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता था उसी के कारण आधुनिकीकरण में एकमूयता आई । बाद में निचली और बीच की श्रेणियों में गांधी और कस्बा में भी आधुनिकतावादी नेताओं का उदय हुआ जिनके कारण आधुनिकता का प्रसार हर स्तर पर हुआ ।

तीसरी बात यह थी कि आधुनिकता और सुधार के आंदोलन का कुछ अत्यंत प्रभावशाली और महान व्यक्तित्व के नेता मिले और सोभाग्यवश ये नेता दीपजीवी थे और उन्होंने लगे जबकि तक देश का नेतृत्व किया । गांधी के महान नेतृत्व की अवधि सन १९२० से १९४५ तक थी, नेहरू की १९४७ से १९६४ और पटेल की १९३० से १९६० तक । इनके अलावा भी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक प्रभावशाली नेताओं ने इनके कार्य को जारी रखा और फैलाया । गांधी में नेताओं के निमाण की बड़ी खूबी थी और उन्होंने दश का सफा कमठ कार्यकर्ता दिए, जिन्होंने पुराने विचार के लोगों को भी अपने आंदोलन में खींच लिया । कम देशों को ऐसे महान नेता और उत्साही कार्यकर्ताओं का दल मिलने का सोभाग्य हुआ ।

अतः मैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का महान संगठन भी आधुनिकता की प्रमुख शक्ति सिद्ध हुई । न केवल आधुनिक काल में देश का ऐसे महान नेता मिले जो पुराने इतिहास के वीरों की श्रेणी में रखे जा सकते हैं, बल्कि एक ऐसा महान राष्ट्रीय संगठन भी मिला जिसका ८० वर्ष से ऊपर देश पर अग्रिम प्रभाव रहा । बहुधा नेहरू आदि नेताओं को जिन बातों का श्रेय दिया जाता है, वे बिना इस महान संगठन का सहारा मिले संभव न हो पाती । कांग्रेस एक ऐसा संगठन था जिसने अनेक स्रोतों से प्रेरणा ग्रहण की । इसकी विचारधारा किसी कट्टर मतवादी

११ दक्षिण, इन्टरनेशनल पोलिटिकल साइंस असोसिएशन की सातवीं बैठक कांग्रेस ( नुसेल्ल १९६७ ) में मेरा निबंध ' इण्डियन आफ नेशन बिल्डिंग फार द ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ पोलिटिकल सिस्टम्स ' ।

७  
८  
९

पर आधारित न थी, साथ ही यह अस्पष्ट भी न थी, इसमें परपरा और जायनिष्ठता  
 युती मिली थी। महान नेताओं की तरह इस संगठन का भी जनता पर चमत्कारी  
 प्रभाव पड़ा। १२ भारत की जायनिष्ठता की जार ले जाने वाली यह ऐतिहासिक  
 शक्ति थी। इस राष्ट्रीय संगठन के नाम में भी भारत जय जय देशों से अधिक  
 भाग्यवान रहा।

इस प्रकार भारत की प्राचीन सभ्यता के जायनिष्ठाकरण में उपयुक्त कई बातें  
 सहायक हुई। ये थी इतिहास के अत्यंत दीर्घजीवी और शक्तिशाली विदेशी शासन  
 के साथ आया जायनिक युग का जबदस्त प्रभाव तथा राष्ट्रीय आंदोलन आधुनिक  
 विचारों से आतप्रत देशव्यापी प्रभाव वाला राष्ट्रीय नेतावर्ग, चमत्कारी व्यक्तित्व  
 वाल महान नेता और व्यापक राष्ट्रीय संगठन। इसके साथ ही हमारी पुरानी  
 परपरा का लचीलापन और नई बातों का ग्रहण करने की शक्ति ने भी भारत के  
 जायनिष्ठाकरण में जबदस्त योग दिया।

१२ इस विषय के सैद्धांतिक विवरण के लिए देखें - एडवर्ड शि, 'द कमरे ट्रेडिंग पेंडिंग-  
 रोन आफ कैरिडम' बल्ल पब्लिशिंग ११ स, १, अक्टूबर १९५८। इसी प्रकार कामस के बारे  
 में विवरण के लिए देखें - मेरा निबंध 'नेशन मेकिंग ऐन्ड कान्सेप्स द वेस आफ द इंडियन  
 नेशनल काँग्रेस - सेवेंथ बल्ल कायस आफ द इटरनेशनल पोलिटिकल साइंस असोसिएशन,  
 मुंबई १९६७।



पर लोकतंत्री सत्स्थाभा का लबा चौड़ा ढाचा नी खड़ा कर दिया गया जो अत तक काम कर रहा है। इसका कारण यह है कि मूल बातों पर स्पष्टता के पहले की पीढ़ी एकमत थी और स्वतन्त्रता के बाद की पीढ़ी में भी इन्हीं विचारा को मायता मिली। हम दख चुके हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे क्रम में किस प्रकार सिद्धांत और उद्देश्य पर सुलभ कर विचार हुआ और उन्हें कांग्रेस के प्रस्तावों में ठास रूप दिया गया। सन १९२८ में ही कांग्रेस द्वारा आयोजित सवल्ल सम्मेलन ने भातीलाल नेहरू कमेटी को नियुक्त किया<sup>४</sup> जिम्मे स्वतन्त्र भारत के राजनैतिक ढांचे की रूप-रेखा बनाई। इसने मसदीय और सदीय ढांचे की मिफारिश की थी और मूल अधिकारों की विस्तृत सूची बनाई थी। इस सूची के १६ में ३ अधिकार १९१० में तैंगर सविधान के मौलिक अधिकार आर निर्देशक सिद्धांत सदी अध्याय में करीब करीब उन्ही रूप में ले लिए गए। १९३१ में कराची कांग्रेस में मोतीलाल के पुत्र जवाहरलाल ने प्रसिद्ध कराची प्रस्ताव पेश किया जिसमें कांग्रेस के उद्देश्य को विस्तार से निरूपित किया गया था। कांग्रेस के इतिहास-लेखक डा० सीता रामया के शब्दों में जवाहरलाल का कहना था कि इन बातों पर राष्ट्र का दिमाग बिल्कुल साफ होना चाहिए और जनता में इन्हीं का प्रचार होना चाहिए।<sup>५</sup>

इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पहले से विचार स्पष्ट होने के कारण संविधान सभा में (१९४७-४९) इस पर बहुत ज्यादा बहस-मुबाहसे की जरूरत नहीं पड़ी।

फिर भी इस समय सोचने का मौका था कि देश में किस प्रकार का राज्यतन्त्र कायम हो। संविधान सभा में कुछ लोगों ने कहा कि देश की पुरानी सत्स्थाभा को नए युग के अनुरूप कुछ परिवर्तन के साथ स्थापित किया जाय। कुछ लोगों का स्थान था कि अनपढ़ जनता को वोट और चुनाव का अधिकार देना ठीक नहीं, और ये चीजें देश की पुरानी परंपरा के प्रतिकूल हैं। परन्तु आधुनिकतावादियों की सलाह अधिक थी और उनका कहना था कि भारत का इधर केवल मसदीय लोकतन्त्र का ही अनुभव हुआ है, और मध्यकालीन या प्राचीन राज्य का अनुभव अब काम नही दे सकता क्योंकि आधुनिक युग का तकाजा है कि जनसमूह का दस के शासन में हिस्सा दिया जाय और आर्थिक व सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा की जाय। गरीबी और निरक्षरता के आधार पर जनता को अधिकार से वंचित रखना अंगरेजों के तर्कों को स्वीकार करना है जो स्वयं अपने देश में तो लोकतन्त्र की दुहाई देते थे परन्तु भारतीयों को स्वशासन के अयोग्य मानते थे।<sup>६</sup>

<sup>४</sup> सम्मेलन में ३४ राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। देखें - ग्रेन विल आस्टिन 'द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन' कार्नेर स्टोन आफ द नेशन (एडन १९६६)।

<sup>५</sup> पर्याप्त सातारमैया, 'द इस्ट्री आफ द इंडियन नेशनल काँग्रेस' (बंबई १९४६) - १, पृष्ठ ४६३।

<sup>६</sup> देखें - ई. स्टोन्स, 'द इंग्लिश यूनिवर्सिटिज ऐंड इंडिया' (आक्सफोर्ड १९५६)।

## संस्था-निर्माण

स्वतंत्रता के साथ भारत में परिवर्तन और पुनर्निर्माण का नया दौर शुरू हुआ, किंतु इससे राजनीतिक परंपरा के विकास का चलता हुआ क्रम टूटा नहीं। हिंदू परंपरा पश्चात्य विचारधारा और राष्ट्रीय पुनरुद्धार की भावना की परस्पर प्रति क्रिया से परिवर्तन का जो प्रम शुरू हुआ उसने भारतीय समाज की नींव को आघात पहुँचाए बिना उसे एक नयी दिसा दी। अगस्त १९४७ में सत्ता देश के पुराने और नए नेताओं के हाथ में ही आई। जिस कांग्रेस ने अब तक राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया था उसी ने अब देश का शासन सभाला।<sup>१</sup> विचारा और अनुभवों में नया शासक वर्ग बहुत सी बातों में पुराने शासक वर्ग से मिलता था। ब्रिटिश शासन के अंत के बाद भी, उसके आदमी, संस्थाएँ और विचार बने रहे। इन विचारों और परिपाटियों को संवैधानिक और संस्थागत रूप दिया गया।

### संविधान का निर्माण

एशिया और अफ्रीका के नए स्वतंत्र देशों को अपना संविधान बनाने और उस अमली रूप देने में बहुत कठिनाई हुई है।<sup>२</sup> भारत में ऐसी कोई कठिनाई नहीं हुई। न सिर्फ यहाँ तेजी से विस्तृत संविधान बना लिया गया<sup>३</sup> बल्कि उसके आधार

१ गांधी स्वयं इसके विरुद्ध थे। वह चाहते थे कि राजनैतिक संगठन के रूप में कांग्रेस को भंग करके उसे लोक सेवा के संस्था का रूप दिया जाए। यद्यपि यह उनके आदर्श के अनुरूप था, पर यह राजनैतिक वास्तविकता को न समझ सकने का चेतक था और इसी लिए विनी ने इस पर ध्यान न दिया।

२ एन्वर्ड शिल्स का निबंध 'द फाचून्स आफ कांस्टिट्यूशनल गवर्मेंट इन द पोलिटिकल डेवलपमेंट आफ द न्यू स्टेट्स' ज्ञान इन्स्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित 'डेवलपमेंट फार इंडिया' (दरहम १९४९) तथा सेनगुल पी. इटिंगटन 'पोलिटिकल डेवलपमेंट ऐंड पोलिटिकल डिके बर्ल्ड पोलिटिक्स, १७, स ३ अप्रैल १९६५।

३ दिसंबर १९४६ से नवंबर १९४९ तक १६५ दिन संविधान सभा ने काम किया। जनवरी २६, १९५० को नया संविधान स्वीकार किया गया और भारत को पूर्ण प्रभुतामयन लोकतान्त्रिक गणराज्य घोषित किया गया।

पर लोकतंत्री सन्स्थाओं का लवा चीटा ढांचा भी खड़ा कर दिया गया जो अब तक काम कर रहा है। इसका कारण यह है कि मूल बातों पर स्वतन्त्रता के पहले की पीढ़ी एकरत थी और स्वतन्त्रता के बाद की पीढ़ी में भी इन्हीं विचारों को मायता मिली। हम देख चुके हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे क्रम में किस प्रकार सिद्धांत और उद्देश्यों पर खुल कर विचार हुआ और उन्हें कांग्रेस के प्रस्तावों में ठोस रूप दिया गया। सन १९२८ में ही कांग्रेस द्वारा आयोजित सचदल सम्मेलन ने मोतीलाल नेहरू कमेटी को नियुक्त किया<sup>४</sup> जिसने स्वतंत्र भारत के राजनैतिक ढांचे की रूप-रेखा बनाई। इसने ससदीय और सधीय ढांचे की सिफारिश की थी और मूल अधिकारों की विस्तृत सूची बनाई थी। इस सूची के १६ में से १३ अधिकार १९५० में तैयार सविधान के मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांत सधी अध्याय में करीब करीब उन्हीं रूप में ले लिए गए। १९३१ में कराची कांग्रेस में मोतीलाल के पुत्र जवाहरलाल ने प्रसिद्ध कराची प्रस्ताव पेश किया जिसमें कांग्रेस के उद्देश्यों को विस्तार से निरूपित किया गया था। कांग्रेस के इतिहास-लेखक डा० सीतारामया के शब्दों में जवाहरलाल का कहना था कि इन बातों पर राष्ट्र का दिमाग त्रिलकुल साफ होना चाहिए और जनता में इन्हीं का प्रचार होना चाहिए।<sup>५</sup>

इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पहले से विचार स्पष्ट होने के कारण सविधान सभा में (१९४७-४८) इस पर बहुत ज्यादा बहस-मुवाहसे की जरूरत नहीं पड़ी।

फिर भी इस समय सोचने का मौका था कि देश में किस प्रकार का राज्यतन्त्र कायम हो। सविधान सभा में कुछ लोगो ने कहा कि देश की पुरानी सन्स्थाओं को नए युग के अनुरूप कुछ परिवर्तन के साथ स्थापित किया जाय। कुछ लोगो का ख्याल था कि अनपढ़ जनता को वोट और चुनाव का अधिकार देना ठीक नहीं, और ये चीजें देश की पुरानी परंपरा के प्रतिकूल हैं। परन्तु आधुनिकतावादियों की सन्स्था अधिक थी और उनका कहना था कि भारत को इधर केवल ससदीय लोकतन्त्र का ही अनुभव हुआ है, और मध्यकालीन या प्राचीन राज्य का अनुभव अब काम नहीं दे सकता क्योंकि आधुनिक युग का तकाजा है कि जनसमूह को देश के शासन में हिस्सा दिया जाय और आर्थिक व सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा की जाये। गरीबी और निरक्षरता के आधार पर जनता का अधिकार से वंचित रखना अंगरेजों के तक को स्वीकार करना है जो स्वयं अपने देश में तो लोकतन्त्र की दुहाई देते थे परन्तु भारतीयों को स्वशासन के अयोग्य मानते थे।<sup>६</sup>

<sup>४</sup> सम्मेलन में ३४ राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। देखें - ग्रैन विल आस्टिन 'द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कांर्गर स्टोन ऑफ ए नेशन' (लंदन १९६६)।

<sup>५</sup> पट्टाभि सीतारामैया, 'द इस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस' (बंबई १९४६) - १ पृष्ठ ४६३।

<sup>६</sup> देखें - ई. स्टोक्स, 'द इंगलिश यूटिलिटेरियन्स पेंट शडिया' (आक्सफोर्ड १९५६)।

बहुम के दारान इस बात पर जार दिया गया कि जावनना सम्म्याजा का बिदेगी या बाहर की चीज नहीं समाना चाहिए, यवाकि प्राय एग पीढ़ा स देग में प्रतिनिधि सम्म्याए ताम बरती रही ह और प्रगति राष्ट्रीय नेता तह्ने ये कि इस सम्म्याजा के अधिकार बढ़ाए जाए तब अगरेज सरकार इमता विरोध करती थी। कात्रेस लगातार बालिग मताधिकार और समदीय गानागान की माग करती जाई थी। इससे देश की प्राचीन परंपरा का भी काई खतरा नहा था। जैसा कि एग मदस्य ने कहा — समदीय प्रणाली पर किसी एग देग का एनाधिकार नहा है और इसको ग्रहण करे स हमारी 'भारतीयता' में काई फरक नहीं पडता। भारत को आधुनिक युग की सभी नई विधिया का ग्रहण करके अपने विशिष्ट राष्ट्रीय व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। इन विचारा को सदस्या का अत्यधिक समर्थन मिला और जब जवाहरलाल ने सभ विधान समिति की रिपोर्ट की धारा १० का पग किया जिसमें भारत में मन्त्रिमंडल शासन और समदीय लाकतत्र की स्थापना की सिफारिस की गई थी, तो इसका काई विरोध नहीं हुआ और यह ऐतिहासिक निणय बिना शोरगुल के जासानी स ले लिया गया।\*

किंतु राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान केवल सामान्य सिद्धान्ता पर सहमति हुई थी, जब इनका ठास रूप देने का प्रश्न आया तो काफी मतभेद खड़े हुए और सविधान निभाताजा का विरोधी विचारा में सामंजस्य करना पडा। जिन महत्त्वपूर्ण प्रश्ना पर मतभेद हुए उनमें राज्य और केन्द्र में अधिकारा का बंटवारा, सविधान की व्याख्या करने में यायालय की भूमिका, उचित विधिया जाइज की परिभाषा, नागरिक की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और राष्ट्र की सुरक्षा में सामंजस्य, संपत्ति के अधिकार की सामाजिक याय और जाविक विकास स संगति, सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा अल्पसंख्यका, हरिजना और आदिम जातिया को विशेष संरक्षण के विषय थे।

राष्ट्रीय आंदोलन के समय कुछ विशेष परिस्थितिया थी जिनके कारण कुछ सिद्धांत स्वीकृत किए गए, अब वे परिस्थितिया बदल गई थी। जैसे पहले देग के विभाजन की बात नहीं सोची गई थी, इसलिए मुसलमाना को भरोसा दिलाने के लिए व्यक्तिगत अधिकारा और प्रातीय स्वायत्तता पर बहुत जार दिया गया था। देश के विभाजन और भयांक स्वतन्त्रता के अनुभव के बाद देग का और विभाजन रोकने के लिए केन्द्रीय सत्ता का राज्यो पर नियन्त्रण रखने का अधिकार देने की आवश्यकता प्रतीत हुई। इसी तरह राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार का एह्तियाती नजरबंदी का अधिकार दिया गया यद्यपि यह लोकतंत्र के

---

\* सविधान सभा में इस विषय पर बहस के विवरण के लिए देखिए — डब्लू एच मारिस — जोस, पाथमेट इन इंडिया' (७दन १९५७)



नागरिक की अत्यंत बुनियादी स्वतंत्रता के प्रतिकूल था।<sup>८</sup> इसी तरह न्यायालयों को बुनियादी अधिकारों की रक्षा के अधिकार देते समय यह भी जरूरी समझा गया कि राज्य को आर्थिक और सामाजिक विपन्नता को दूर करने के लिए कारवाई करने का भी अधिकार रहे। इस उद्देश्य से उचित विधि (ड्यू प्रोसेस) सबबी प्रस्तावित धारा में संशोधन किया गया। ये सारी व्यवस्थाएँ बड़ी लंबी बहस मुवाहसे के बाद ही की गईं।<sup>९</sup>

संविधान बनाने में सभी वर्गों की सहमति प्राप्त करने की कोशिश की गई। देश के विभाजन के बाद कांग्रेस का प्रचंड बहुमत हो गया था फिर भी उसने संविधान सभा में सभी मुख्य संप्रदायों और राजनीतिक मतों को प्रतिनिधित्व दिया। उसने सबण हिंदुओं के अलावा हरिजन, मुसलमानों, सिखा, ईसाइया, ऐंग्लो इंडियनों और पारसियों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में निर्वाचित कराया। सभा के ३१ हरिजन सदस्यों में से २६ कांग्रेस के नामजद थे। इसी तरह उसने ऐसे लोगों को भी लिया जिनका कांग्रेस से कभी संबंध न था। इनमें डा. सवपल्ली राधाकृष्णन और गोपाल स्वामी अयंगर जैसे लोग थे। यही नहीं उसने कांग्रेस के विरोधियों को भी स्थान दिया। इनमें जनसंघ के संस्थापक डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी और हरिजन नेता डा. अम्बेडकर जैसे लोग थे। डा. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के सभापति चुने गए और संविधान के रचयिता के नाम से प्रसिद्ध हुए। वास्तव में ड्राफ्टिंग कमेटी के ६ सदस्यों में केवल एक प्रमुख कांग्रेसी श्री कृ. भा. मुशी थे। अल्पसंख्या सबबी कमेटी में न केवल अल्प संख्याओं को पूरा प्रतिनिधित्व दिया गया बल्कि इसमें तो वे लोग भी लिये गये जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, जैसे श्री पी. के. साल्वे (ईसाई), रूपनाथ ब्रह्म (आदिम जाति), एम. बी. एच. कालिस (ऐंग्लो इंडियन) और एम. रत्नस्वामी। मुस्लिम लीग के टिकट पर चुने गए तीन सदस्य भी इस कमेटी में लिए गए। यह संकुलरवाद का दिखावा मान नहीं था। कांग्रेस की ईमानदारी इससे प्रकट है कि संविधान सभा का सून संचालन करने वाली अंतरंग मंडली में भी निंदनीय सदस्या को स्थान दिया

८ देखें - डेविड एच. वेली, 'पब्लिक लिबरेशन इन न्यू स्टेट' (शिकागो १९६४) पृ. २६-३५, तथा उद्देश्य का 'प्रिवेंटिव डिटेन्शन इन इंडिया, ए वेम स्टडी "न उमोनेटिक सोशल कंट्रोल" (कलकत्ता १९६२)

९ आस्टिन (पूर्ववर्त) न-संका बहुत अच्छा वर्णन किया है। संविधान के इतिहास के लिए देखें - शिवराव का 'द फ्रेमिंग ऑफ़ इन्डियन कॉन्स्टिट्यूशन' - ५ खण्डों में (नई दिल्ली १९६६-२८)

१० इस विषय में श्री बशारुद्दीन अहमद के साथ हुए विचार-विनिमय से काफी लाभान्वित हुआ हूँ।

संविधान सभा में बहुमत के बल पर निर्णय लेने के बजाय सबकी सहमति प्राप्त करने की काँग्रेस की गई। नेहरू ने सदस्या से कहा था, 'जाप तत्तमाजी न कर और जहा तक सम्भव हो एक राय से फगले-कर।' इसी भावना से प्रेरित होकर संविधान सभा के अध्यक्ष डा. राजेन्द्रप्रसाद बहम स्वीकृत मसौदा के लिए समय दिया करते थे ताकि 'बिस्ती पर जबरदस्ती न हो।' नेता लोग यह समझते थे कि बहुमत के बल पर बना संविधान टिकाऊ नहीं होता। इस प्रकार राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर मार्गगम बहुत कम समय राजेन्द्र बाबू ने सदस्या से कहा कि—'इस विषय पर जा निर्णय हो, वह यदि पूरे देश को स्वीकार्य न होगा तो उस अमल में लाना बहुत कठिन होगा।' ११ संविधान सभा का सारा काम इसी भावना से ओतप्रोत था। नेताओं का यह मान था कि वे महज कोई दस्तावेज नहीं बना रहे हैं बल्कि एक राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। उद्धाने नाम का मजबूत बनाने में पूरा जोर लगाया।

हमने इस प्रसंग का कुछ विस्तार में वर्णन किया था कि इससे पता चलता है कि नए राष्ट्र की संस्थापना का ढाँचा तैयार करते समय किस प्रकार निर्णय लिए गए। यह संविधान भारत के भविष्य की आधार-शिलावत् था और इसका रचना में नेताओं ने पुराने और नए विचारों में अन्तर से अधिक सामंजस्य लाने का प्रयत्न किया। परिणामस्वरूप संसदीय शासन का सघीय ढाँचा स्वीकार किया गया, जिसमें केन्द्र और राज्यों में मजबूत सरकार बनाई गई और सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के लिए लाभकारी ढंग में काम करने का निर्देश दिया गया। १२ राज्य की संस्थाओं का जो ढाँचा तैयार हुआ, वह स्वरूप में आधुनिक है किंतु राष्ट्रीय एकता और सामाजिक साम्य के ख्याल से उसमें कुछ विशेष व्यवस्थाएँ की गई जिससे वह पश्चिमी नमूने से भिन्न हो जाता है। भारत का राष्ट्रपति केवल नाम का पद है, किन्तु भी उसको राज्यों में कानून और व्यवस्था

१० आर्स्टिन-पृ १८-१९ अंतरंग मंडली के ११ सदस्यों का नाम देता है। इनमें ७ कांग्रेसी थे—राजेन्द्रप्रसाद आजाद, पटेल, नेहरू, पंत, सातारनैया और सत्यनारायणसिंह। अंबेडकर, व. कृ. अय्यर और गोपाळस्वामी अयंगर गैर कांग्रेसी थे। अंबेडकर तो कांग्रेस के कट्टर विरोधी थे। क. मा. मुंशी भी बाद में कांग्रेस से अलग हो गए।

११ यह क्रम पेश किया गया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का निर्णय केवल एक वोट के बहुमत से किया गया था। यह झिज्जुल गप है। केवल कांग्रेस असेंबली पार्टी में अपनी ओर से रखने का निर्णय एक वोट के बहुमत से हुआ था। देखें—आर्स्टिन-पृ २९९-३००। भाषा के प्रश्न पर निर्णय लया बहुत और सेन-देन का बाद किया गया।

१२ इनका वर्णन 'निर्देशक सिद्धांत' के अध्याय में किया गया है। इसमें बड़े ऊँचे आदर्शवाद का झलक है।

भग होने की स्थिति में बहुत अधिक आपत्कालीन अधिकार दिए गए।<sup>१३</sup> राज्या के गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्य की जनता या विधान मंडल नहीं। केन्द्रीय सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति आपत्कालीन अधिकारों का प्रयोग और नियुक्तियाँ करता है। केन्द्रीय सरकार को देश के राजस्व का अधिकांश भाग और राज्यों पर प्रशासनिक और निर्देशक अधिकार दिये गये। समवर्ती विषयों पर और अन्य कई मामलों में केन्द्रीय संसद के अधिकार राज्यों से ऊपर हैं और राज्यों में संवैधानिक मशीनरी के टूट जाने पर, संसद उनके विधानमंडलों और शासन के अधिकार ले सकती है। केन्द्र को अवशिष्ट अधिकार भी दिये गये। इस प्रकार केन्द्र को बहुत शक्तिशाली बनाया गया। दूसरी ओर गांव पंचायतों और स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की स्थापना के द्वारा और राज्यों को शासन के बड़े काम सौंप कर, शासन व्यवस्था को मध्यम रूप दिया गया और शासन में जनता को तथा प्रांता, जिला और गांवों का भी हिस्सा दिया गया।

संविधान की एक विशेषता अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों और पिछड़े वर्गों को संरक्षण देना है। इनके लिए सरकारी नौकरियाँ और विधान मंडलों में स्थान सुरक्षित किए गए हैं। इसी तरह देश की सभी मुख्य भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं का पद दिया गया है। यद्यपि हिंदी का राजभाषा का पद दिया गया किन्तु अहिंदी भाषी राज्यों के विरोध के कारण इसको लागू नहीं किया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया सरल रखी गई ताकि सामाजिक स्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सके। वित्त आयोग और चुनाव आयोग जैसे स्वायत्त प्राधिकरणों को कार्यविधि में महत्वपूर्ण परिवर्तन के अधिकार प्राप्त हैं। यदि न्यायालय समय के विपरीत चले तो संसद को उनको नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया है। विशेष अधिकार-प्राप्त सम्मेलन और आयोगों के जरिये केन्द्र और राज्यों के मतभेद दूर करने की व्यवस्था की गई है।<sup>१४</sup> इसके बावजूद भी संवैधानिक कठिनाइयाँ उठ सकती हैं। इन पर हम राजनैतिक व्यवस्था के काया वयन संबंधी अव्याय में विचार करेंगे।

### स्थिरता और परिवर्तन की समस्याएँ

संविधान की रचना और १९५० में भारत गणराज्य की स्थापना देश में राज-

<sup>१३</sup> इस विषय पर संविधान निमाताओं के विचारों की या या कृष्णमाचारी ने इस प्रकार प्रकट किया “राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के संघर्षों के बारे में हमने एट्टेन की शासन-प्रणाली का अनुकरण किया। हा, हमने अपने संघर्षों के कारण कुछ विशेष व्यवस्था की है।” संविधान सभा के डिबेट-१०, पृ. ९५६। परन्तु इस मत का भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्रप्रसाद तथा कुछ और लोगों ने खंडन किया है।

<sup>१४</sup> आस्टिन - आखिरी अध्याय - ‘कमेंट्स ऑन ए संवैधानिक कार्टिड्यूशन’, पृ. ३०८-३३०।

नीतिक समस्याओं के निर्माण और जनता की सहमति प्राप्त करने की लगातार चाल क्रिया के ही अंग थे। राष्ट्रीय एकमत के और विकास के क्रम में संविधान, नई संस्थाओं के विकास और 'राजनीतिक व्यवस्था के पुनर्निर्माण' के प्रश्न उठे हैं।<sup>१५</sup> नई संस्थाओं की स्थापना से नए जाचारविचार, तीर तरीके व परंपराएँ तथा सत्ता की नई शृंखलाएँ विकसित होती हैं और राजनीति के सामाजिक ढाँचे में परिवर्तन होता है। भारत में सत्ता की यह शृंखला और जनता व शासन में संपर्क दो माध्यमों में स्थापित हुआ। एक है प्रशासन या सरकारी अमला, जिसका विकास मुगला और अंग्रेजों के राज के समय हुआ और राष्ट्रीय योजना के तकाजे से जिसका और विकास हुआ। दूसरा है कांग्रेस दल का ढाँचा, जिसका विकास राष्ट्रीय आंदोलन के समय हुआ। स्वतंत्रता के बाद सरकारी सत्ता व अधिकार तथा चुनावों के कारण इसका बहुत विस्तार हुआ है। इन दोनों के द्वारा और इनके परस्पर प्रभाव के कारण भारतीय राज्यतंत्र का वर्तमान रूप स्थिर हुआ। इस बीच संविधान द्वारा स्थापित ढाँचे में भी परिवर्तन हुए हैं, कुछ तो वर्तमान ढाँचे की खाँियों सुधारी गईं और कुछ सामाजिक पुनर्निर्माण और प्रतिनिधि शासन के नए विचारों के प्रभाव से नये उपाय किये गये।

स्वतंत्रता के साथ नई समस्याएँ आईं। सांप्रदायिक दंगों और उपद्रवों के शमन के साथ साथ पाकिस्तान से उदवासित लाखों आदिमियों का बसाने का कठिन कार्य तथा तेलंगाना में कम्युनिस्ट प्रेरित किसानों का बलवा, निजाम हैदराबाद के खिलाफ पुलिस कारवाई। सरकार को अंग्रेजों जमाने के सरकारी नौकरों और सेनाओं का विश्वास और वफादारी प्राप्त करनी थी। इसके अलावा सांप्रदायिक शक्तियों को भी दबाना था, जो देश के विभाजन के बाद उमड़ आई थी। असंतुष्ट प्रादेशिक और राजनीतिक समूहों को संतुष्ट करना था। सबसे बड़ा काम था देशी रियासतों को मिलाने का।<sup>१६</sup> इसमें राजनीतिक कुशलता और सगठनपटुता की जरूरत थी। संक्षेप में नेताओं के सामने यह काम था कि देश को विघटित होने से बचाएँ और उसके विभिन्न भागों और तत्त्वों को मिला कर एक राष्ट्र की रचना करें।

नेताओं की समझदारी और दूरदर्शिता की तारीफ है कि उन्होंने इन कठिन समस्याओं को काफी जल्दी सुलझा लिया। भारत के प्रथम गृहमंत्री बल्लभभाई पटेल

१५ यह जयप्रकाश नारायण के एक लेख का शीर्षक है। हम इस पर दलों में सहयोग विषयक अंतर्गत में विचार करेंगे।

१६ भारत का जो भाग अंग्रेजों के साथे शासन में था उसे ब्रिटिश भारत कहा जाता था। इसके अलावा देशी राजाओं के शासन में करीब ५०० छोटी बड़ी रियासतें थीं। ये स्वतंत्र राज्य नहीं, ब्रिटिश आधिपत्य के अंतर्गत थे। किंतु अंग्रेजों के हटने से भारत और पाकिस्तान का अपने आप इनके ऊपर आधिपत्य नहीं मिला। इसलिए देशी रियासतों को देश-देश में मिलाने की देशी समस्या पैदा हुई।

ने देशी रियासतों को भारत में मिलाने का काम बड़ी खूबमूरती से पूरा किया। इससे भी बड़ी सफलता उन्होंने देश में शांति और व्यवस्था स्थापित करने और प्रशासकीय और सैनिक सेवाओं की निष्ठा प्राप्त करने में पाई। स्वतंत्रता आंदोलन के समय भारतीय अधिकारियों को देशद्रोही और अंगरेजों का गुलाम कहा जाता था, इस कारण स्वतंत्रता आने पर वे लोग घबराए हुए थे। पटेल ने सरकारी नौकरी को आश्वासन दिया कि उनकी स्थिति वही रहेगी जो पिछले शासन में थी और उन्होंने राजनीतिक लोगों से कहा कि वे सरकारी कर्मचारियों के काम में दखल न दें। उन्होंने देश में स्थिरता कायम करने में भारतीय सिविल सर्विस की योग्यता का बहुत अच्छा उपयोग किया। सेना के प्रति भी उनका यही रुख था।

नेताओं ने बड़े प्रश्नों पर दृढ़ता दिखाने के साथ साथ विरोधी और भिन्न मतों के साथ समाधान करने की भी कोशिश की। इस नीति से उन्हें उपर्युक्त समस्याओं को सुलझाने में बड़ी मदद मिली। स्वतंत्रता के बाद के दशक में उनकी यही सामान्य नीति रही। अपना कार्यक्रम निवारित करने में वे जहां तक हो सके सघन वृत्त में थे। नेहरू ने सन १९५२ में इस बात को या कहा था, “इस नाजुक समय में मैं देश की एकता को सर्वोपरि समझता हूँ। जब तक इस एकता की नींव पक्की नहीं जाए, हमें ऐसी कार्रवाई से बचना चाहिए जो इसमें बाधा हो”।<sup>१७</sup>

देश की एकता और मजबूती के साथ साथ नेताओं सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए भी उत्सुक थे। तात्कालिक समस्याओं के समाधान और नये संविधान के लागू होने के बाद भारत सरकार ने योजना कमिशन की स्थापना की। इसका पंचवर्षीय योजनाएं बनाने, सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम की प्राथमिकता निर्धारित करने और आर्थिक विकास की रूपरेखा तैयार करने तथा उसको कार्यान्वित करने के लिए साधन जुटाने के उपाय सुझाने का काम सौंपा गया। बहुत थोड़े समय में ही विकास के आयोजन, मूल्यांकन और सलाह मांगिरे के लिए केन्द्रीय मशीनरी का विकास कर लिया गया।<sup>१८</sup> स्मरण रहूँ कि संविधान में योजना आयोग का जिक्र भी नहीं था। इसकी स्थापना नेहरू के इस दृढ़ विचार के कारण हुई कि राजनीतिक को मजबूत बनाने के लिए शुरू में ही देश के आर्थिक

१७ ‘स्पेसिज आफ जवाहरलाल नेहरू १९४९-५३’ (भारत सरकार, दिल्ली १९५४) सघन बचाने के विषय पर ‘सेमिनार’ (नई दिल्ली) ६३, नवंबर १९६४ में देखिए पितेन्द्र सिंह का लेख ‘ए न्यू लेनिनिस्म’।

१८ सरकार का योजना और तथ्य-संकलन की मशीनरी के बारे में देखिए - विलफ्रेड मैडल-वाम, ‘हू डूज द प्लानिंग? और मेरिल आर गुडल का लेख- आर्गनाइजेशन आफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोडक्शन इन द फाइव ईयर प्लान्स, रिचर्ड एल पार्क और इरेन टिकर द्वारा संपादित ‘एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोडक्शन इन इंडिया में’ (प्रिंटिंग १९५९), पृ ३०१-२८। राज-नीतिक प्रक्रिया के रूप में योजना के विशद अध्ययन के लिए देखें - ए एच ई-सन ‘द प्रोसेस आफ प्लानिंग’ (लंदन, १९६६)।

विकास की नीति से कर लेनी चाहिए। इसी के साथ केन्द्रीय सरकार ने ससद स अस्पश्यता निवारण जस अनेक समाज हित और सुधार के कानून नी पास कराए । राज्यों में भी जमींदारी उमूलन के कानून बनाए गए और गरीब व दलित वर्गों को सरक्षण व सुविधाए दी गई । इन कानूना को अदालत में चुनौती न दी जा सक इस हेतु सविधान में सगोधन किए गए । इसस प्रकट होता है कि नेताओं को यह ध्यान था कि राष्ट्रीय एकता केवन झगडे की बातों को टालते रहने से नहा बनी रह सकती उसके लिए सघष के कारण को दूर करने के लिए रचनात्मक कारवाई करनी भी जरूरी है जिसस एकता की शक्तिया ना बल बडे ।

स्वतन्त्रता कं तुरत बाद की इस अवधि में कुछ काय ऐसे हुए, जिनस एकता को बल मिला । यद्यपि ये काय आर्थिक और सामाजिक विकास के उद्देश्य से किए गए, फिर ना इनस सघष के कुछ ऐसे कारण दूर हुए, जो उप्र होकर देश की एकता को नुकसान पहुंचा सकते थे । श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए जो कानून बनाए गए तथा कांग्रेसजनों ने मजदूर सघा के काय में जो सचि ली, उससे जातीय सघषों को राकने में मदद मिली । उसी तरह अनुसूचित जातिया और पिछडे वर्गों की शिक्षा और सरकारा शौकरियों में जो विशय सरक्षण दिए गए और उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारने की जा कारवाइया की गई, उससे ऊंची जातिया से उनका सघष टला । जमींदारी और मामती अधिकारों के उमूलन से भी सघष का एक बडा कारण दूर हुआ ।

स्वतन्त्रता के प्रथम दशक में देश के सूत्रधारों ने एक और महत्वपूर्ण काय किया । यह था भाषा के आधार पर राज्या का पुनर्गठन । अंग्रेजों ने सामाजिक और सांस्कृतिक आधारों की उपेक्षा करके केवल शासन की सुविधा के रयाल से प्रातों का निमाण किया था ।<sup>१९</sup> राष्ट्रादिमा को यह बात पसद न थी और राष्ट्रीय अदालत के समय कई बार कांग्रेस ने भाषावार प्रातों की स्थापना का निश्चय प्रकट किया था । १९२१ में कांग्रेस ने अपनी प्रदेश शाखाए इसी आधार पर स्थापित की थी । लेकिन स्वतन्त्रता के बाद जो कठिन समस्याए आई उनके कारण कांग्रेस राज्या क इस प्रकार पुनर्गठन पर ध्यान न दे सकी और कुछ यह भी ऊहापोह होने लगा कि भाषावार राज्या बनाना उचित है या नहीं । यद्यपि नवंबर १९४७ में नेहरू ने सविधान सभा में भाषावार राज्या के सिद्धांत को स्वीकार किया था, लेकिन सविधान सभा द्वारा नियुक्त भाषावार प्रात कमीशन (घर कमीशन) ने भाषा के

१९ इस शताब्दी में अंग्रेजों ने प्रातों का रचना भाषा और संस्कृति के आधार पर करण के सिद्धांत के महत्त्व को स्वीकार किया और बिहार, उड़ीसा, आसाम और सिंध (अब पाकिस्तान में) के नए प्रात इसी प्रकार क थे । १९१८ का मॉन्टेगु-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट और १९३० की साइमन कमाशन की रिपोर्ट में भाषावार प्रातों की स्थापना की सिफारिश की गई थी ।

प्रातः स तलुगु भाषी जिला को अलग करके आंध्र प्रदेश की स्थापना के जादोलन  
 ने उग्र रूप पकड़ा। अतः १९४६ में कांग्रेस कायसमिति ने इस मांग को स्वीकार  
 कर लिया। लेकिन केन्द्रीय सरकार जब भी हिचक रही थी क्योंकि उस डर था  
 कि इससे इसी प्रकार के और राज्या की स्थापना की मांग उठेगी। सरकार का  
 यान था कि एस राज्या के निर्माण से भाषावाद जार पकड़ेगा और राष्ट्र की  
 कता बमजार होगी। इस प्रश्न पर कांग्रेस में मतभेद हो गया। कांग्रेस ने जादेश  
 का कि कांग्रेसजन भाषावाद राज्या के आदालत से अलग रहें किंतु इस जादेश  
 पालन नहीं किया गया और सभी दल इस आदालत में शामिल हुए। आंध्र  
 की मांग के समथन में पोत्ती श्रीरामुलु न अनशन करके प्राण दे दिये। इससे  
 आंध्र का निर्माण हुआ। इससे भाषावाद राज्या की मांग ने जोर पकड़ा।  
 पर विचार करने के लिए सरकार ने निसर १८४३ में राज्या पुनगठन  
 की नियुक्ति की। इसने खूब जाच पड़ताल के बाद सन १८५२ में अपनी  
 ही। इसने भाषा के आधार पर राज्या के पुनगठन का सिद्धांत स्वीकार  
 र राज्या के तदनुसार पुनगठन की सिफारिश की। कुछ हेरफेर के साथ  
 इस स्वीकार की गई और १९५६ में इसके अनुसार राज्या का पुनगठन  
 कुछ बहुभाषी राज्य अब भी छूट गए। सन १९६० में द्विभाषी बवई  
 गडकर महाराष्ट्र और गुजरात राज्या की स्थापना की गई और १८६६  
 र हरियाणा को अलग किया गया।  
 र भारत में सहानुभूति रखने वाले राजनीतिक पयवेक्षका की आश-  
 वावजूद पुनगठन से भारत का राजनीतिक नकसा अधिक सुसंगत  
 राष्ट्र की एकता को भी खास नुकसान नहीं पहुंचा। २१ वल्कि इससे  
 ने असे यथार्थवादी आलाचक्र को भी इस विषय में आशका थी। आंध्र  
 क्षेत्रों के दाय-दाए पड। देश उनकी पालमेंट इन इडिया (८ दन १९५७)।  
 त्यों में दे रहा कामत का प्रभाव है जो इन वगडा पर अडुर रखता है।  
 कारण आंध्र में किसान वग के नेताओं को उभारने का मौका मिला है। इससे  
 में में धवराइट है जो अन्ध को देश की परता का सूत्र समझता है। इस  
 के लिए शेरिए-सलिंग हरिसन 'इडिया द मोर डेवरम जिन्स  
 'न में राज्यों की तान थणिया थी - ए म भूतपूर्व अयन शमन र  
 देशा रियासतें तथा सी म केन्द्र शासित प्रदेश। राज्यों के पुनगठन के  
 ए रा-व और सपशासित क्षेत्र।

लाभ यह हुआ, कि पगड़े का एक कारण दूर हुआ और राज्या का वास्तव ऐसी भाषा में होना समझ हुआ, जिस जागृतापूर्ण समझ पर। प्रतिपक्ष न अनुभव से तो यह कहा जा सकता है कि भाषा जाड़नेवाली गति निम्न है।<sup>१२</sup> यदि इसन गई जागृता की बात है तो यही कि उपभाषाओं और स्थानीय संस्कृतियों का आधार पर राज्या के टुकड़े न हो जाए।<sup>१३</sup>

इस प्रकार पहले दशक में भारतीय राष्ट्र का संघानिर प्रादुर्भाव और विकास का ढांचा तैयार किया गया। जहाँ संविधान की व्यवस्था में संशोधन का जल्दतर पड़ी रहा संशोधन किए गए जैसे राज्या का पुनर्गठन योजना आयोग की स्थापना और भूमिसुधार के लिए संपत्ति संपत्ति अनुच्छेद का संशोधन। ब्रिटिश युग तकली आई और विपन्नता का अंत किया गया। योजनापूर्वक विकास का क्रम चालू किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना १९५६ में पूरी हुई और दूसरा उनसे बड़ी योजना शुरू की गई। १९५५ में जावड़ी अधिवक्ता में कांग्रेस दल ने समानता की दावे का ध्येय स्वीकार किया। उद्योगों के बारे में पहले १९४८ में नीति का घोषणा की गई। १९५६ के उद्योग नीति प्रस्ताव में इस आग वयाव तथा व्यापक रूप दिया गया। इससे साथ ही गांधी के विकास और ग्रामीणा को राजनीतिक कार्य की शिक्षा देने के लिए १९५२ में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू किये गये और दस मर में विकास सभा का जाल बिछाया गया। बाद में पंचायती राज या लोकतंत्री विकेंद्रीकरण का सूत्रपात हुआ। इस विषय के लिए नियुक्त अध्ययन बोली की रिपोर्ट सन १९५७ में प्रस्तुत हो चुकी थी।<sup>१४</sup> इस बीच (१९४७-५७) दो आम चुनाव और बीसिया स्थानीय चुनाव हो चुके थे और कांग्रेस पार्टी की प्रधानता स्थापित हो चुकी थी।

२२ भाषा के प्रश्न के कुछ और पहलू हैं जो राष्ट्र की एकता के लिए खतरनाक हैं। इनमें से महत्व का प्रश्न है राजभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं का द्वंद्व और अमेच का स्थान। इस विषय का विवेचन आठवें अध्याय में है।

२३ राज्य पुनर्गठन आयोग ने जनभावना का ख्याल रखते हुए एक भाषा के एक राज्य का सिफारिश की। (। नदी भाषा राज्यों को छोड़कर)। वास्तव में इसका कोई कारण नहीं कि हिंदी राज्यों की तरह अन्य भाषा-क्षेत्रों में भी एक से अधिक राज्य क्यों न हों। बाद के अनुभव से पता चला है कि भाषा के अलावा अन्य बातें भी हैं जो राजनीतिक एकता, प्रशासनिक कुशलता और आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं। इस विषय पर देखें- श्रीनिवास, 'द फ्यूचर आफ फिशन', टाइम्स आफ इंडिया नवंबर १६ १९६७ और रत्नो कोठारी, 'नेशनल यूनिटी इन डिवर वेस फार स्मालर यूनिट्स', टाइम्स आफ इंडिया, फर १०, १९६८। हम इस प्रश्न पर अध्याय ८ में विचार करेंगे।

२४ योजना कमिशन - 'कमेटी ऑन ग्रान प्रोजेक्ट्स, रिपोर्ट आफ द ग्रीम फार द स्टडी आफ कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स ऐंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस' (नई दिल्ली १९५७) इस बलवत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट भी कहा गया। इस रिपोर्ट का ग्राम-विकास और ग्राम-लोकतंत्री संबंधी विचारों पर काफी प्रभाव पड़ा है।



इस प्रकार इस अवधि में राजनीतिक एकता और संस्थाओं की स्थापना की दिशा में काफी काम हुआ, जिस कारण देश जागे आने वाले दशक में और कठिन समस्याओं का सामना कर सका। तनाव और कठिनाइयों के बावजूद देश में एक हृदय की स्थिरता बनी रही। विकास जारी रहा और संविधान द्वारा जो संस्थाएँ कायम हुई उन्हें जड़ जमाने का मौका मिला। जागे जो विकास हुए, वे इसी ढाँचे में हुए। उनसे ये संस्थाएँ गतिशील हुई और जनता के सपने में आईं। हम इस विकास की मुख्य धारा की चर्चा करेंगे।

### केन्द्र और परिधि

संविधान द्वारा स्थापित संघीय शासन-नظام के अंतर्गत केन्द्र राज्य और जिलों के संबंध स्थिर हुए। केन्द्र और राज्यों में शासन का ढाँचा करीब-करीब एक ही तरह का है। एक यह है कि राष्ट्रपति का चुनाव संसद और राज्यों के विधान मंडलों के सदस्यों द्वारा होता है जबकि राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्व-धार्मिक शासन के पिछले अनुभव, ब्रिटिश राजनैतिक परंपरा, जनमत और केन्द्र तथा राज्यों के प्रभावशाली नेताओं की राजनैतिक समझ ने केन्द्र और राज्यों के संबंध का प्रभावी क्रिया है। इन संबंधों पर निम्न राजनैतिक प्रवृत्तियाँ नेताओं और विभिन्न हितांशों के समूहों का भी प्रभाव पड़ा है। सबसे बड़कर इन पर इस बात का प्रभाव पड़ा है कि स्वतंत्रता के बाद के दशकों में केन्द्र में तथा लगभग सभी राज्यों में लगातार एक ही दल का शासन रहा है।

राज्यों के हाथ में देश के शासन का बहुत बड़ा भाग है। यद्यपि उन्हें आर्थिक साधनों के लिए केन्द्र पर निर्भर रहना पड़ता है और विकास कार्यों का संचालन भी केन्द्र करता है, फिर भी राज्यों में अपने अधिकारों पर जोर देने की प्रवृत्ति है और देश के शासन में अधिक जागरूकता चाहते हैं। सबसे मुख्य बात है राज्यों के मुख्य मंत्रियों की महत्वपूर्ण स्थिति। मुख्य मंत्री न केवल राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है, बल्कि राष्ट्रीय क्षेत्र में भी उसका महत्व बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव जैसे महत्वपूर्ण मामलों में उनकी राय ली जाती है।<sup>१५</sup> इस प्रकार उन्होंने राष्ट्रीय नेताओं की स्थिति प्राप्त कर ली है। मुख्य मंत्रियों का यह महत्व उनकी शक्ति और उनके महत्वपूर्ण पदों के कारण प्राप्त हुआ है।

शासन दल के भीतर भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति काम कर रही है। राज्य कांग्रेस कमिटी और राज्य चुनाव कमिटी का महत्व बढ़ रहा है। राज्य कांग्रेस का

---

१ १९५५ में नेहरून धर्मनिरपेक्षता का पद छोड़ दिया। तब से एक बार की छोड़कर जब शक्ति प्राप्त हुई, धर्मनिरपेक्षता के अर्थ में राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने भी ही चुन जाने रहे हैं। प्रधानमंत्री के चुनाव में मुख्य मंत्रियों के हाथों के बरतने का साथ आठ दलों ने।

जहाँ जहाँ जय नाम का हुआ तो कांग्रेस का असली सरदार<sup>२६</sup> बड़ा शक्तिशाली होता है और जयभी बात के द्रीय नेताओं से भी मनवा लेता है। कांग्रेस के अलावा जय दला में भी इसी प्रकार राज्य के सघटना की सक्ति पड़ी है।

भारत में सरकारी नीतियाँ और विकास कार्यक्रम को जमल में लाने का काम राज्य सरकार और नीचे के अधिकारियों का है। संविधान में केन्द्र और राज्यों के कार्यों का जो बंटवारा किया गया है वह यथास्थिति का बोधक नहीं है। मंत्रिपरिषद् की जाँचवी अनुसूची में कार्यों की तीन सूचियाँ दी गई हैं - (१) सघ सूची (२) राज्य सूची और (३) समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों में बहुत पासमल है। साम कर कई काम समवर्ती और राज्य सूची दोनों में मिलने हैं। संविधान में यह भी व्यवस्था है कि कुछ स्थितियों में ससद समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है और राज्यसभा दो तिहाई बहुमत से ससद को राज्य सूची के भी किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। केन्द्रीय सरकार को अनेक विषयों पर राज्य सरकार को निर्देश देने का भी अधिकार है। इनमें से कुछ विषय राज्य सूची के भी हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति को कुछ हालातों में राज्यों के शासन में हस्तक्षेप का अधिकार है। वह राज्य का विधान सभा को भंग कर सकता है, राज्य के शासन को अपने हाथ में ले सकता है और राज्य के विधान-मंडल में विचाराधीन विधेयकों पर राज्यपाल स रिपोर्ट माग सकता है। इन प्रकार केन्द्र को राज्यों के क्षेत्र में हस्तक्षेप का अधिकार है। इस कारण कुछ प्रमुख जाली चक्रा ने यहाँ तक कह डाला कि भारत नाम के लिए सघ है।<sup>२७</sup>

परंतु स्वतंत्रता के बाद से अब तक भारत में प्रशासन और सरकार की गति विधि का समीक्षा से इस विचार का खडन होता है। अक्सर राज्य सरकारों केन्द्र पर दबाव डालने में और उससे अपना बात मनवाने में सफल रही हैं। केन्द्र के लिए सुरक्षित क्षेत्रों में भी राज्यों ने घुसपट्टी है और दूसरों देशों से व्यापारसंबंध भी स्थापित किए हैं।<sup>२८</sup> कई राज्यों के मुख्य मंत्री बड़े शक्तिशाली हैं और प्रधान मंत्री

२६ बंगाल कायम पर एक दशन से भी अधिक समय तक (१९६२ तक) अनुत्पन्न धान का राज्य रहा। अनुत्पन्न धान का राज्य सरकार या राज्य कांग्रेस में कोई पद नहीं था। निरुत्पन्न धान नेताओं पर उनका बड़ा प्रभाव था।

२७ संविधान विशेषज्ञ के सी. हीर ने भारत की अर्थ सघ कहा है - 'फेडरल गवर्नमेंट (एडन १९५३)। केन्द्र द्वारा राज्यों के अधिकारों के अवहरण के बारे में दोषों - 'द इंडियन जर्नल ऑफ पोलिटिक्स साइंस अक्टूबर-नवंबर १९३३ में के. सी. राव का 'सेक्टर-स्टेट रिलेशनस इन थियरी ऐंड प्रैक्टिस'।

२८ पश्चिम बंगाल के शक्तिशाली मुख्य मंत्री बा. बिपिनचंद्र राय ने एक विज्ञापन के साथ अपने राज्य का भारत से व्यापार समझौता किया था। पश्चिम पर, बिहार के नेहरू पर उनके प्रभाव के कारण इस मामले को नजरअंदाज किया गया। लखनऊ में जब केन्द्र के एक मंत्री और मद्रास के मुख्य मंत्री ने वार्ता तथा कुछ पश्चिमी देशों के साथ व्यापार के बारे में बात-बात की, तब स्वयं बिपिनचंद्र मुरारजी ऐसाई ने कहा कि राज्य सरकारें यदि अपना व्यापार बढ़ाने का प्रयत्न करना ईंता हयें तो कोई उराह नहीं।

को इनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। जैसा कि पाल ऐपिलजी ने कहा है कि, भारत की शासन प्रणाली ऐसी है जिसमें प्रशासन के सार महत्वपूर्ण कार्य राज्य सरकारें करती हैं, और योजना की कार्यावधि के लिए केंद्र को उही पर निर्भर रहना पड़ता है। केंद्रीय सरकार में सब जफसर हैं, कोई मिपाही नहीं इसका मतलब यह है कि क्षेत्र में काम करने वाले सब अधिकारी राज्य सरकारों के अधीन हैं। राज्य सरकारें समझती हैं कि केंद्र खर्चमार कर उन्हें आर्थिक सहायता देगा और उनके घाटे को पूरा करेगा। अनुदान देने की प्रणाली में केंद्र को राज्यों के काम की जांच और देखरेख का जो अधिकार रहता है इससे वह व्यर्थ-सा हो गया है। एपिलबी यहाँ तक कह गए कि भारत में राज्य सरकारों के सामने केंद्रीय सरकार की कुछ नहीं चलती। २०

ये दोनों ही विचार एकांगी हैं। सघ प्रणाली की समस्याओं को हमेशा सघ और राज्य के द्वंद्व के चरमों से न देखना चाहिए। भारत में सघीय प्रणाली का विकास यहाँ की राजनीतिक स्थिति के अनुसार हुआ है। ३०

भारत में राजनीतिक शक्ति के बंटवारे को प्रभावित करने वाला एक नया तत्व है, निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं और स्थानीय नेताओं का बढ़ता हुआ महत्त्व। इसके कारण राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ है। जिला और राज्यों के नेताओं की शक्ति बढ़ी है और राष्ट्रीय नेता उनसे सलाह करने लगे हैं। योजना आयोग की राष्ट्रीय विकास समिति में सभी राज्यों के मुख्य मंत्री सदस्य हैं और योजना बनाते समय और उसे कार्यावधि करते समय राज्यों के नेताओं से पूरा पूरा सलाह मशविरा किया जाता है और उनकी बात काफी मानी जाती है।

कांग्रेस के चुनाव-यंत्रण पर राज्य और जिलों के नेताओं का बहुत हद तक नियंत्रण रहता है। इसका एक कारण तो यह है कि इतने बड़े देश में केंद्रीय नेता अधिकांश जनता के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आते। दूसरा, चुनाव की जीत हार बहुत हद तक गांवों के प्रमुख लोगों पर निर्भर होती है। इस कारण राज्यों की कांग्रेस कमेटियों का महत्त्व बढ़ गया है, जसे योजना और विकास कार्यों के कारण राज्य सरकारों का महत्त्व बढ़ा। नये नेता भी स्वभावतः राज्यों से ही आते हैं। राजनीति

२९ पाल एच ऐपिलवा, 'पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया-रिपोर्ट ऑफ ए सव' (दिल्ली १९५३)

३० वाद-राज्य संबंध के बारे में इन विरोधी मतों का समीक्षा के लिए मेरे फाम डेंड सार्वेस इन इंडियन पालिटिक्स शर्पक पढ़के लेख को देखें-इकनामिक वार्ल्ड १३, स १७ और १८, अप्रैल २९ और मई ६, १९६१। वाट्स के मत से यह प्रणाली एकरा और विभिन्नता का प्रतिलिपि में स्तुलन लाती है। 'न्यू पॉटेंशियल-एकमपरिमेंट्स इन द कामनवेल्थ' (आक्सफोर्ड १९६२)। वाट्स ने भारत की सघीय प्रणाली पर विस्तृत विचार किया है।

का जनता में फैलाव और नए राजनीतिक दला का उदय राज्या में हुआ है और राज्या से ही राष्ट्रीय क्षेत्र में नये नये नेता आए हैं ।

इसके साथ ही एक प्रवृत्ति भी चालू है । राष्ट्रीय नेता वग, राज्या में होने वाले राजनीतिक झगडा में जगजग बीच-बचाव और निपटारा करते रह रहे हैं । कांग्रेस कायवारिणी (हाईकमान) और केंद्रीय सरकार के प्रमुख सदस्य राज्य कांग्रेस क वगडा में समझौता कराते हैं और यह त करत हैं कि नेतृत्व का सहारा जिसके सिर पर बंधे । कांग्रेस हाईकमान की शक्ति का यही स्रोत है । कांग्रेस की दलबद्धिया पर गौर करने से पता चलेगा कि राज्या के वगडा को निपटाने या भडकाने में केंद्रीय नेताओं का बडा हाथ होता है । राज्या के नेता जक्सर यह शिकायत करत हैं कि यदि ऊपर से इशारा न मिले तो ये वगडे इतने न बढें । वास्तव में इन हथकडा से केंद्रीय नेता प्रातीय राजनीति पर अपना नियंत्रण और प्रभाव कायम रखते हैं और इसी पर कद्राय और प्रातीय नेताओं की शक्ति निर्भर रहती है । साधारणतः केंद्रीय नेतृत्व का रुख यही रहता है कि विरोधी गुटा का बराबर रख । उन्हें आपस में निपटने दे, जब कोई गुट बहुत प्रबल होने लगे तब बीच बिचाव करे, हवा का रुख देखते रह और हर हालत में आपसी फसला हाईकमान के हाथ में रहे । राज्या में नए राजनीतिक दला के प्रादुर्भाव के कारण, अस्थिरता पैदा हो गई है और केंद्रीय नेताओं को हस्त में और मध्यस्थता के, जिसमें राष्ट्रपति और ससद द्वारा सवधानिक कारवाई भी शामिल है, और मौके मिल गए हैं ।

कहा जाता था कि केंद्र और राज्या में एक ही पार्टी के सत्तारूढ होने के कारण केंद्रीय सरकार की सत्ता बहुत बढ गई थी और जहा यह स्थिति बदली केंद्रीय सरकार की सत्ता कम हो जाएगी । किंतु केंद्र राज्य सवधा पर पार्टी के प्रभाव के जरा गहरे अध्ययन से पता चलेगा कि बात उलटी है । जब तक राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी मुख्य मंत्रियों का केंद्र पर बहुत अधिक प्रभाव था और आज भी जहा कांग्रेस मुख्य मंत्री हैं, उनका केंद्र पर प्रभाव है । दूसरी ओर जहा दूसरे दल की सरकार होती है, उसके मुख्य मंत्री का केंद्र पर वह प्रभाव नहीं होता और चाहे वित्तीय सहायता हो, या विकास परियोजनाओं को लगाने का प्रश्न हो, या खाद्य की सप्लाई हो, राज्य को केंद्र का मुह जोटना पडता है । केंद्रीय सरकार पर गैर-कांग्रेसी मुख्य मंत्रियों का उससे बहुत कम प्रभाव पडता है, जितना कांग्रेसी मुख्य मंत्रियों का, जो कांग्रेस मगडन में भी प्रभाव रखते हैं ।

## राज्यों की राजनीति

पार्टी प्रथा के विकास के सिलसिले में हम राज्या की राजनीति और केंद्र-राज्य सवधा पर जगले अध्याय में विस्तार से विचार करेंगे । यहा हम प्रादेशिक

राजनीति के मुख्य तत्त्वा पर एक नजर डालेंगे तब तो राष्ट्रीय राजनीति का भी समझ आएगा।<sup>31</sup>

राज्या की प्रवृत्तियाँ को चार मुख्य बातों ने प्रभावित किया है - स्वतन्त्रता के पहले का राजनीतिक स्वरूप, कांग्रेस के विराधी या प्रतिपक्षी तत्त्वा का स्वरूप और गति, राज्या की कांग्रेस की राजनीति पर प्रभाव डालने वाले जातिगत विरोध या विभिन्नता और विभिन्न प्रदेशों के सामाजिक ढाँचे में अंतर।

यह याद रखना चाहिए कि कांग्रेस को जनता का समर्थन मिलने के बावजूद अनेक क्षेत्रों में इसका जोर नहीं फल सका था। इन क्षेत्रों में दूधरे दला का जोर था। इनमें बंगाल, पंजाब और मद्रास प्रधान थे। अनेक देशी रियासतों में छिटपुट आंदोलन चल रहे थे, मगर मजबूत दला का विकास नहीं हुआ था। इनमें केरल, मैसूर राजस्थान, मध्यप्रदेश का बड़ा भाग, पटियाला और पंजाब की रियासतें, सौराष्ट्र थे। उड़ीसा और आसाम के आदिवासी-बहुल प्रांत भी इसी श्रेणी में आते थे। १९८७ के बाद यहाँ की राजनीति अलग-अलग ढंग से विकसित हुई। बंगाल और पंजाब का देश के विभाजन से गहरा घबका लगा था, किंतु बिधानचंद्र राय और प्रतापसिंह कौर जैसे विशिष्ट नेताओं के कारण यहाँ कांग्रेस की सत्ता स्थापित हुई और सूबे की उन्नति हुई। मद्रास (तमिलनाडु) में कांग्रेस की मुख्य प्रतिद्वंद्वी ब्राह्मण जस्टिस पार्टी थी। कामराज के नेतृत्व के उदय से मद्रास कांग्रेस ब्राह्मणों के हाथ से निकल गई। राजस्थान सौराष्ट्र और मैसूर के प्रजा आंदोलनों का कांग्रेस से निकट संबंध रहा और स्वतन्त्रता के बाद राजाओं के विरोध के बावजूद इनमें कांग्रेस की प्रधानता कायम हो गई और केन्द्रीय सत्ता को इनसे बल मिला। दूसरी ओर मध्यप्रदेश, उड़ीसा और आसाम में अस्थिरता रही तथा कांग्रेस में दलबंदी और आदिवासियों और सामंती तत्त्वा की ओर से विरोध बना रहा। केरल में वामपक्षी प्रवृत्तियों का जार रहा और कांग्रेस वहाँ जड़ न जमा सकी।

प्रांतों के राजनीतिक विकास पर मजबूत और योग्य नौकरशाही के होने या न होने का भी असर पड़ा। मद्रास और पश्चिम बंगाल बहुत दिनों तक अंगरेजी प्रशासन में रहे और वहाँ नौकरशाही शासन की मजबूत परंपरा थी, इससे राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास में मदद मिली। मैसूर और बड़ोदा जैसे रियासतों में भी प्रशासन प्रगतशील और अच्छा था। किंतु मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश

३१ प्रादेशिक राजनीति के अध्ययन के लिए अनेक ग्रंथ हैं। माइरन वानर द्वारा संपादित 'स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया' (प्रिंटन १९६७), इरवाल नारायण, संपादित 'स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया' (मेरठ १९६७) पाल त्राम, 'फैशनल पॉलिटिक्स इन ऐन इंडियन स्टेट-द काँग्रेस पाटन इन उत्तर प्रदेश' (बंगलूर और लॉस एंजेलिस १९६६) बलदेवराव नायक 'माइनरिटी पॉलिटिक्स इन पंजाब' (प्रिंटन १९६६) एफ. जे. बेरी, 'पॉलिटिक्स ऐंड सोशल चेंज-उड़ीसा इन १९५६' (बंगलूर ऐंड लॉस एंजेलिस १९६२) सेलिग एस. हैरिसन, 'कास्ट ऐंड द आर्थिक कम्युनिस्म' - अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू, ५०, नं० जुलाई १९५६।

और उड़ीसा में इस प्रकार की अच्छी प्रशामन परंपरा नहीं, इसलिए वे पिछड़े रहे और वहाँ राजनीतिक अनक्य भी रहा।

महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र जैसे प्रदेशों में जहाँ कांग्रेस का जार रहा, उसने जल्दी जड़ जमा ली और उसका शासन भी लगातार रहा। इनमें नए क्षेत्र शामिल हुए, जैसे गुजरात में सौराष्ट्र और आंध्र में हैदराबाद और तेलंगाना, इनमें विकास काय भी अच्छा हुआ। इन राज्यों में जो सघन हैं, उनकी जड़े स्वतंत्रता के पहले से चली आ रही हैं, जैसे गुजरात में सौराष्ट्र और आंध्र में तेलंगाना का आंदोलन। बिहार और उत्तरप्रदेश में यद्यपि हाल तक कांग्रेस सत्तारूढ़ रही, लेकिन सामंती परंपरा और राजनतिक अनक्य के कारण वहाँ गुटबंदी और व्यक्तिगत राजनतिक प्रतिद्वंद्विता का जोर है, जिसका नतीजा राजनतिक अस्थिरता है और जल्दी जल्दी सरकार बदलती रही।

इन प्रांतों की स्थिति पर वहाँ के सामाजिक ढाँचे का भी प्रभाव पड़ा। मद्रास और महाराष्ट्र में ब्राह्मणों के संगठन, गुजरात और आंध्र में वीच की जातियों की राजनतिक शक्ति और मसूर में भी जातिविशेष के जोर के कारण, वहाँ की राजनीति और शासन में स्थिरता रही। दूसरी ओर उत्तर में बिहार और उत्तर प्रदेश और दक्षिण में केरल जैसे राज्यों में जातियों में स्पर्धा के कारण राजनतिक गठजोड़ नहीं पाए और अस्थिरता बनी रही। पश्चिम बंगाल के ऊपर कलकत्ता छाया हुआ है, इसलिए वहाँ की राजनीति में शहरीपन आ गया। वहाँ वामपंथी दला का जोर है और बजाय एक दल की प्रधानता के संयुक्त दल की राजनीति का चलन है। इसके विपरीत आन्ध्र प्रदेश में खेती की प्रधानता है और भूस्वामी वर्ग का जोर है। इसने छोटी किसान जातियों का अपने साथ मिला लिया है और इस प्रकार वहाँ आश्रयदाता — आश्रित वर्गों का गठजोड़ बन गया है। मध्यप्रदेश, आसाम और उड़ीसा में कांग्रेस और गैरकांग्रेस दलों की जोड़ तोड़ में आदिवासी कबीलों का हाथ रहा है।

इस प्रकार इन प्रांतों की सामाजिक, प्रशासनिक पृष्ठभूमि का राज्य की राजनीति और केंद्र-राज्य संबंधों पर प्रभाव पड़ा है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस सरकार कायम होने पर भी वहाँ शहरी वामपंथी दला की ओर से संयुक्त विरोध की परंपरा रही। इसी प्रकार केरल में भी दलित एजवा जाति से कम्युनिस्टों को समर्थन मिला। इसके साथ शिक्षितों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ उनमें बेकारी भी बढ़ी, वहाँ गांवों और नगरों में भी धना संकट बना रहा। बंगाल और केरल दोनों जगह कांग्रेस और कम्युनिस्ट नेतृत्व में संयुक्त मोर्चों के बीच सीधा मुकाबला या ध्वंसीकरण हुआ। आंध्र प्रदेश में कम्युनिस्टों का जोर था, इसे रेडडी और कामा जातियों के दृढ़ संघ मिले। बाद में कांग्रेस की गठजोड़ नीति के कारण दोनों जातियाँ कांग्रेस सरकार और संगठन में आ गई और विरोध हैदराबाद और तेलंगाना

जैसे क्षेत्रों से उठा, जो राज्य में बाद में शामिल हुए वे जोर अभी तक उसमें घुल-मिल न सकें थे। पंजाब और मद्रास में कांग्रेस के पुराने विरोधी अकाली और अराष्ट्रिय तत्त्वा ने पुनः सिर उठाया और राजनीति का प्रभावित किया। उड़ीसा आगाम और मध्यप्रदेश के आदिवासी-बहुल प्रदेशों में और सामंती पूर्वी यू० पी० और बिहार में चाहें कोई पार्टी सत्ता में रहे, वहाँ व्यक्तिगत स्पर्धा और जाड़तोड़ चलता रहता है।

इस प्रकार हमने देखा कि राज्या में राजनीति की गतिविधि का सध की राजनीति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यह बात भी ध्यान योग्य है कि केन्द्रीय सरकार का, विशेषकर राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय समाज के विस्तर तत्त्वा को राष्ट्रीय राजनीतिक ढांचे में एक साथ लाने में बहुत हाथ रहा है। इसी के साथ ही सघीय शासनतंत्र का विकास और सत्ता का विकेंद्राकरण हुआ है। जगले अध्याय में हम यह देखेंगे कि एक दल कांग्रेस के वजाय अनेक दलों के जोर पकड़ने से किस प्रकार केन्द्र-राज्य संस्था का और स्पष्टीकरण हुआ है और सघीय व्यवस्था किस प्रकार विभिन्न प्रदेशों और जातियों के राजनीतिक दलों का सामना कर रही है।

### विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया

स्वतन्त्रता के बाद स शासन की संस्थाओं और राजनतिक अभिकारों का प्रसार नीचे तक हुआ है। चार बातों ने इस क्रिया को प्रभावित किया है। पहली बात यह है कि योजना के कार्यक्रमों की पूर्ति नीचे के लोगों पर निर्भर है। राज्य का शासन केन्द्र एवम् राज्य के नीति निर्णयों का विशेष कार्यरूप देने और जिले और उससे निम्न स्तर पर वायावयन के लिये इन कार्यों का वितरित करने के जलावा कुछ अधिक नहीं करता। अंग्रेजों ने भी इसी प्रकार जिलों के शासन को राज्य की इकाई बनाया था। स्वतन्त्रता के बाद विकेंद्रीकरण के और कदम उठाए गए। योजना को चलाने के लिए जिला विकास बोर्डों की स्थापना की गई, सामुदायिक विकास खंड, विस्तार एजेंसियां, ऋण सहकारी समितियां और पंचायतें स्थापित की गईं। ये प्रशासनिक और राजनतिक विकेंद्रीकरण की नई संस्थाएँ थीं।<sup>३२</sup>

दूसरे लोगों को लाभ पहुंचाने और इस प्रकार अपना प्रभाव जमाने के जरिया

३२ स्वतन्त्रता के पहले भी स्थानीय बोर्ड और सहकारी संगठन मौजूद थे और बंधन व मद्रास जैसे उन्नत प्रांतों में अच्छा काम कर रहे थे। अवश्य ही ये सरथाएँ प्रारंभिक अवस्था में थीं और अभिकारों - विभागों के उत्साह पर निर्भर रहता था। जनता का सहयोग भी इनमें कम था। इस विषय पर देखें - बाबे कोआपरेटिव इस्टाब्लिशमेंट्स के 'फिफ्थ इयर्स आफ कोआपेरेशन' - म के बा नाथन का - इन्शियल स्ट्रेजिज ऑफ आर्गनाइजेशन (१९०४-१९१२)। स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के विकास के बारे में देखिए ह्यू टिंकर 'द फाउन्डेशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया पाकिस्तान पेंड बमा' (लंदन १९५४)।

की रखला स्थापित हो गई। नए राजगार व नौकरिया तथा ऋणा का बटवारा, गावा में ऋण और मिट्टी के तेल, शक्कर आदि बाटने वाली संस्थाएँ तथा स्कूलों के खुलने से पहुँच व प्रभाव तथा अर्थोन्नति के नए जरिये प्रस्तुत हो गए। इनसे सरकारी मशीन को नया महत्व मिल गया और पुराने समाज का नई राजनीतिक व प्रशासनिक संस्थाओं से रोज और प्रशिक्षण काम पड़ने लगा।

राज्या के नेताओं ने लाभों के वितरण का यह सिलसिला शुरू किया। अपना पद बनाये रखने के लिए, इनको गावा के छोटे-छोटे ज़रूरत थी। इसलिए इन्होंने अपने प्रभाव का जाल फैलाया और स्थानीय संस्थाओं, स्कूलों, विकास की संस्थाओं आदि पर कब्जा किया, जिससे लोगों को नौकरी दे कर और फायदा पहुँचा कर, उनका समर्थन प्राप्त किया जा सके। नतीजा यह हुआ कि सत्ता नीचे का ओर जाने लगी और जिला व नगरों में ऐसे लोग ऊपर आए जिन्होंने लाभकारी संस्थाओं पर और राजनीतिक दलों के पदों पर कब्जा जमाया और धीमे-धीमे प्रभाव और शक्ति प्राप्त की। ये लोग छोटे-छोटे गावा और तहसीलों के नेता थे, और जनता के बीच से आए थे। ये देश के परंपरागत समाज से उठे थे और उसकी मनोवृत्ति को समझते थे। ये व्यावहारिक और दबंग आदमी थे। नए विचारों से इनको बहुत मतलब नहीं था, परन्तु इन्होंने नई व्यवस्था को फैलाने में योग दिया। ये लोग स्थानीय गुटबंदी और दावपच में माहिर थे और अपनी शक्ति को जानते थे। चुनाव के समय राज्यों के नेताओं का इही स्थानीय नेताओं पर भरोसा करना पड़ता है, जिनके हाथ में स्थानीय संस्थाओं की बागडोर हानी है और जो आर्थिक और सामाजिक शक्ति रखने वाले वक्ता हैं। इनमें से कुछ लोकप्रिय नेता होते हैं और कुछ दादागिरी में माहिर, लेकिन जनता के वोट इनके हाथ में होते हैं। इन लिए शक्ति भी इनके हाथों में आ गई है।<sup>२३</sup>

तीसरी बात है चुनाव प्रणाली का अत्यधिक विस्तार। भारत में अनेक स्तर पर निर्वाचित संस्थाएँ हैं — राष्ट्रीय संसद, राज्य विधान सभा, जिला परिषद, ब्लॉक और गावा पंचायत। इसके अलावा वे निर्वाचित संस्थाएँ हैं जिनके हाथ में थोड़ी आर्थिक शक्ति होती है, जैसे जिला सहकारी बैंक, नकदी फसलों के उत्पादन और बिक्री की सहकारियाँ, और जिला पंचायत की आर्थिक समितियाँ।<sup>२४</sup> इनमें से कुछ का सीधा जनता द्वारा चुनाव होता है, कुछ नीचे की संस्थाओं के प्रति-

२३ मैं ने राष्ट्रीय और राज्य नेताओं में स्थानीय नेताओं के हाथ में जाने के कारणों का विवेचन इनामिक वीकली १४, विस्तार जुलाई १९५२ में अपने अर्थ 'स्थिति' १ पोलिटिकल टुडे आफ में किया है।

२४ राजनीति में सदनारी संस्थाओं के महत्व के लिए देखिए—ए. एम. नाथिंगर, 'कोऑपरेटिव एंड पोलिटिक्स' इनामिक वीकली-१२ नं० १२, मार्च १९५२, १९५८।



निधिया द्वारा चुनी जाती है, और कुछ के सदस्य ही चुनते हैं जा विभिन्न श्रेणिया में आते हैं। कुछ लोग रईस व्यापारी व सदस्य होते हैं लेकिन साधारणतः राज्य की विधान सभा के उम्मीदवार नीचे की मध्यम वर्ग के नेताओं पर निर्भर करते हैं।

चौथे, बालिग मताधिकार के कारण राजनीति में नए नए वर्गों का प्रवेश हुआ है। जो जानिया अब तब राजनीति को ग्राह्य और क्षत्रिय जैसी ऊँची जातियाँ का क्षेत्र समझती थी, उनको अब मध्यम वर्ग का महत्त्व प्राप्त हो गया है और वे भी संगठित हो रही हैं। उनकी समस्याएँ और नेता भेदान में आ रहे हैं। राजनीतिक दलों की स्पर्धा और जायिक योजनाओं व जनता के मतों के कामों के चालू होने से जातियों के मुनियोजना का महत्त्व बढ़ गया है और राजनैतिक नेताओं को इनसे व्यवहार करना पड़ता है। इस प्रकार गाँव के सामाजिक ढाँचे का राजनीतिकीकरण हो रहा है और शासन तथा राजनीतिक दलों का नीचे की ओर फटना हो रहा है, जिससे भारतीय समाज के शक्ति के ढाँचे में परिवर्तन आ गया है।

लेकिन गाँव के इस फटना से गांधीजी की कल्पना के स्वावन्धी ग्राम समाज का स्थापना नहीं हुई है। राजनीतिक संगठन या शासन की इकाई के रूप में गाँव का महत्त्व घटा है। ग्राम सुधार या सामुदायिक विकास योजना की इकाई भी गाँव न होकर विकास खंड है। शिक्षा प्रचार, यातायात, जातीय संगठनों आदि के द्वारा गाँव ऊपर के स्तर से प्रभावित होते हैं। गाँव के झगड़ों को छोड़ कर गाँव की राजनीति क्षेत्र की राजनीति का अंग होती है। नेतृत्व के लिए केवल गाँव का समयन नहीं, गाँव के बाह्य से समयन प्राप्त करना जरूरी है। केवल बहुत बड़े गाँव इसके अपवाद हैं, जैसे केरल में। जो गाँव बाहर से मतलब नहीं रखते और अपने में ही सिमटे रहते हैं, उनका राजनीति में ज्यादा महत्त्व नहीं।

### जिले का महत्त्व

क्षेत्र की गतिविधियाँ का केन्द्र जिला होता है। बहुत वर्षों से जिला प्रशासन का आधार रहा है। जिले की जनसंख्या करीब १५ लाख, प्रशासन के लिए आदर्श है। इसी प्रकार उसका रकबा भी अच्छे प्रशासन और विकास कार्य के लिए आदर्श होता है। सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के लिए भी जिला अच्छा कार्यक्षेत्र होता है। योजना के कार्य जिले के स्तर से ही शुरू होते हैं। मुगला के जमाने से लेकर आज तक शासन की इकाई के रूप में जिले ने राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी एक व्यक्तित्व प्राप्त कर लिया है। जिले का कलेक्टर जनता की आँखों में शासन और अधिकार का प्रतीक होता है।

राजनीति में भी जिला कांग्रेस कमेटी शक्ति की धुरी होती है। जिलों के नेताओं के बल पर राज्य के मंत्रिमंडल और राज्य कांग्रेस का संगठन निर्भर होता है। महाराष्ट्र

और गुजरात में एक एक मंत्री के जिम्मे कई जिले लगा दिए हैं वह लोगों के प्रतिनिधियों से मिलता है, उनकी शिकायतें सुनता है और जिले के हित की देखरेख करता है। राज्या के मंत्रिमंडल में जिले प्रतिनिधित्व का दावा करने लगे हैं। यद्यपि सभी जिला का दावा स्वीकार नहीं किया जाता, पर राज्य की राजनीति में उनका महत्व स्पष्ट है।

जिला आर्थिक और सामाजिक जीवन का भी केंद्र बन गया है। लोग अपना परिचय देते समय अपने जिले का नाम लेते हैं। जातियों के संगठन भी जिलावार होते हैं। राजनीतिक और जातीय गुट भी जिला के हिसाब से बनते हैं। जिलों के केंद्र में नगरों का रूप लिया है। जिलों के केंद्र में ही कचहरी, स्कूल, कालेज, बाजार, जिला सहकारी बैंक, भूमिबचक बैंक, लाइसेंस के दफ्तर, खेती और वन विभाग के दफ्तर, जिला पुलिस, जिला बोर्ड और जिला कलेक्टर के कार्यालयों के कारण क्षेत्र की सभी गति विधि वहां केन्द्रित हो जाती है। इसमें जिला मजिस्ट्रेट और जिला कांग्रेस नेता का भी प्रमुख स्थान होता है।

कलेक्टर या जिलाधीश के पद का भारत में अपना अलग महत्व है। स्वतंत्रता के बाद बदले हुए वातावरण में जिलाधीश के महत्व को कम करने की प्रयत्न हुए, लेकिन ब्रिटिश शासन की यह ऐसी परंपरा है जो टूट नहीं सकी। अधर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष विकास अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। हो सकता है इससे जिला कलेक्टर का एकछत्र प्रभाव कम हो जाए, किन्तु जिले का प्रशासनिक महत्व तब भी बना रहगा।

जिले का सबसे बड़ा महत्व राजनीतिक संस्थाओं और नेतृत्व के विकास में है। जिले में अनेक नई संस्थाएँ और विभाग खोले गए हैं। गुरु में बहुत सी विकास की और अग्र-सरकारी एजेंसियाँ स्थापित की गईं। इनमें कज देने की संस्थाएँ, स्वास्थ्य की एजेंसियाँ, स्कूल और कालेज थे, जिनसे नेताओं के हाथ में लोगों का फायदा कराने के साधन आए। इसके बाद सामुदायिक विकास और पंचायती राज की संस्थाएँ कायम हुईं। इनसे स्थानीय नेताओं के प्रभाव और शक्ति की वृद्धि हुई। यद्यपि सामुदायिक विकास खंड जिला से छोटे थे लेकिन इनको टेक्निकल सलाह और साधन जिले से ही मिलते थे। जिला और ब्लॉक अधिकारियों को महत्वपूर्ण कार्य और अधिकार सौंपे गए। इससे जिले के नेताओं की शक्ति और बढ़ गई। जिले के निर्वाचित प्रमुख होने लगे, जिनको सावजनिक कोष से वेतन मिलता था। ये लोग ज्यादातर धनी भूस्वामी वर्ग के होते हैं, इनको अपने क्षेत्र का राई रत्ती हाल मालूम होता है और ये जनता का नेतृत्व करने तथा संस्थाओं को चलाने में निपुण होते हैं। ये जनता से ही नहीं, जिले के और ऊपर के अधिकारियों से भी बड़े विद्यासंपूर्ण व्यवहार करते हैं। इस प्रकार शासन के विकेंद्रीकरण और नई स्थानीय संस्थाओं की स्थापना से जिलों के बाड़े में प्रमुख व्यक्तियों के हाथ में

आर्थिक और राजनैतिक शक्ति भी आई है, पार्टों की मशीन का विस्तार हुआ है और स्थानीय आंदोलनों और मधर्पा के संचालन की पद्धति विकसित हुई है।

इस प्रकार भारत में स्वतंत्रता के बाद एक पीढ़ी के अंदर ही शासन और राजनीति का तन अनेक स्तरों पर काम करने लगा। स्थानीय स्तर पर विकास और राजनीतिक संगठन की अनेक संस्थाएँ काम करने लगी, स्थानीय लोगों से सलाह, जांच पड़ताल और निणय लेने की व्यापक प्रणाली विकसित हुई, जो एक राष्ट्रीय शखला से जुड़ी हुई है। इससे आधुनिकता और परंपरा, पुरानी और नई राजनीतिक व्यवस्था का अंतर मिट रहा है।<sup>३५</sup>

### पंचायती राज का महत्त्व

राष्ट्रीय नेतृत्व का एक दूरदर्शितापूर्ण कार्य था पंचायती राज की स्थापना। इसका व्यापक महत्त्व भाषावार राज्यों के गठन और योजना कमिशन की स्थापना से अधिक है। इससे भारतीय राज्यव्यवस्था का विकेद्रीकरण हो रहा है और देश में एक ही स्थानीय संस्था के निमाण से उसकी एकता भी बढ़ रही है। संभव है कि इस कदम का दूरगामी महत्त्व नेताओं ने उस समय न समझा हो। प्रशासनिक और वौद्धिक क्षेत्रों में इसकी सफलता में सदेह था और इसका मजाक उड़ाया गया था। इसकी शुरुआत का श्रेय जवाहरलाल नेहरू को है।<sup>३६</sup> उनका लोकतंत्र के तरीका में अटूट विश्वास था। उन्होंने पंचायती राज और सामुदायिक विकास दोनों पद्धतियों का जोरा से समर्थन किया था।<sup>३७</sup>

सामुदायिक विकास कार्यक्रम १९८५२ में आरंभ हुआ। इसमें काफी सरया में सरकारी कर्मचारी रखे गए और लंबे चौड़े दावे किए गए। पर यह सरकारी तंत्र और ग्रामीण जनता के बीच की दूरी कम करने का मुख्य उद्देश्य में विफल

३५ इसके लिए देखें—सी एम विलिप्स स्थापित—‘पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी इन इंडिया’ (न्यूयार्क १९३६) में मारिंस जोन्स का ‘इंडियाज पोलिटिकल इंडियम। उन्होंने यह देखिये—‘पार्लामेंट इन इंडिया’ पृ ३७-४०। और भा उशिथन पाइ और सिटनी बर्वा-सथा ‘पोलिटिकल कल्चर एंड पोलिटिकल डेवलपमेंट’ (प्रिंसटन १९९५) में मास्टरन वानेर का ‘इंडियन टू पॉलिटिकल वर्ल्ड्स’।

३६ लेखकों का इसमें सदेह था। देखिये—पूर्वोक्त ‘पार्थ एंड सबस्टंस में मेरा दिवाय लेख। इसमें इस कार्यक्रम की सफलता की समाक्षा भी की गई है और इस विषय के सदस्य-मंत्रों का उल्लेख किया गया है।

३७ ‘गावा के लोगों को अधिकार सौंपना चाहिए। इनको काम करने दो चाहे वे दलालों की तरह हों। इसमें परमाने की जरूरत नहीं। पंचायतों को अधिकार दो।’ एम्नेस्टी—‘ए सिपे बियम’ (दिल्ली १९६१) में जवाहरलाल नेहरू।

रहा। ३८ इस विफलता का एक कारण यह था कि इसे सरकारी महकमे की तरह चलाया गया और गावों के विकास के बजाय सामुदायिक विकास की मशीनरी के विस्तार पर ही ज्यादा जोर दिया गया। ३९ सरकारी तंत्र के जरिए गावा के लोगों की मनोवृत्ति को बदलने की आशा की गई, नतीजा यह हुआ कि गावा की उन्नति के लिए खुद प्रयत्न करने के बजाय ग्रामीण जनता सरकार का मुंह जोहती रही। ४०

दूसरी बात यह थी कि इस कार्यक्रम के सारे कमचारी और भाषण जुटाने का काम सरकार ने जोड़ लिया और सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता उद्योगों के विकास को दी इनलिए इस कार्य के लिए बहुत कम साधन और कमचारी जुटाए जा सके। तामरे, सरकारी तंत्र की प्रभावता और साधनों की कमी के कारण सामुदायिक विकास कार्यक्रम में प्राथमिकता का क्रम बिल्कुल उल्टा हो गया। ब्लाकों में कार्यालय की इमारत बनाने और सरकारी कमचारी भर्ती करने में तो बड़ी तत्परता दिखाई गई पर खेती की तरक्की और जनता में स्वावलंबन और स्वयं काम करने की भावना पैदा करने पर कम ध्यान दिया गया। ४१ चौथे, आर्थिक विकास की व्यापक रीतिनाति में इस कार्यक्रम के लक्ष्य गावा के कार्यावली का कोई सबब नहीं स्थापित किया गया। इस कार्यक्रम पर काफी खर्च हो चुकने और इसकी सफलता के लंबे चौड़े दावों के बाद इसको जांच के लिए एक कमेटी नियुक्त की

३८ सामुदायिक विनास का सबसे बड़ा कमजोरी उसका सरकारी स्वरूप और नेताओं का लक्ष्य था। एक तरफ इस कार्यक्रम के सूत्रधार जनता से आगे आने का आशा करते थे, दूसरी ओर उनका विश्वास था कि सरकारी कारवाई से ही नतीजा निकल सकता है। कार्यक्रम जनता को चलाना था लेकिन वे बनाये ऊपर से जाते थे। इस समस्या पर रेनहार्ड बर्न्क्स, 'नेशन विल्डिंग एंड मिटिगेशन' (न्यूयार्क १९६४) पृ २६६-८३ में बहुत अच्छा विचार दिया गया है।

३९ जितना तेजी से सामुदायिक विनास खड़ा और विस्तार एजेंसियां खोली गईं उससे इसके सरकारी रूप का पता चलता है। सन १९५३ में सारे देश में इसे फैलाया जा निर्णय हुआ और १९५६ तक १२०० ब्लॉक खोले दिए गए जिनके अंतर्गत देश की एक चौथाई ग्रामीण जनसंख्या आता था। १९६३ तक सारे देश में यह फैल गया। संयुक्त राष्ट्र के एक मिशन ने यह राय दी कि इतने तेज विस्तार से सबब विनास नहीं हो पाएगा। यू एन कमिशनर फार टेक्निकल असिस्टेंस, रिपोर्ट आफ ए कम्युनिटी डेवलपमेंट एवैलुएशन मिशन इन इंडिया १९५८-५९ (दिल्ली-१९६१)

४० स्वयंसेवक साठन की जिम्मेदारी भी सरकार ने ली। योजना कमिशन की जनसहयोग कमेटी और आयोग के उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नन्दा की प्रेरणा से भारत सेवक सभाओं जिसके सरक्षक नन्दा और नेहरू थे, लोक-कार्यक्षेत्र खेलन के लिए रूपया दिया गया। इसके मूल्यांकन के लिए दक्षिण-योजना कमिशन ए स्टडी आफ द लोक कार्यक्षेत्र आन द भारत में सेवक सभा (नई दिल्ली-१९६०)

४१ मेहता कमेटी रिपोर्ट, खंड १, पृ ४ प्लानिंग कमिशन, प्रोग्राम एवैलुएशन आर्गनाइजेशन, एवैलुएशन रिपोर्ट आन वॉरिंग आफ कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स पैड एन ६ एस ब्लॉक (दिल्ली-१९५९)

गई। इसने सरकार को बताया कि इस कार्यक्रम की बुनियादी नुस्ति यह है कि जनता का इस में सहयोग नहीं मिला। इस रिपोर्ट में तथा अन्य जांच रिपोर्टों में यह कहा गया कि जब तक स्थानीय नेताओं को जिम्मेदारी और अधिकार नहीं सौंप जात, सबिधान क निर्देशक सिद्धांतों का राजनतिक और विकास सबधी लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। ४२

इसलिए लोकतयी प्रणाली के विकेद्रीकरण और विकास कार्यक्रमों में जनता का सहयोग लने क उद्देश्य स पचायती राज की शुरुआत की गई। इसके स्वरूप में विभिन्न राज्या में कुछ अंतर हैं, मगर कुछ बात एक सी ह। ४३ एक तो पचायती राज की तीन सीढियाँ हैं - गाँव पचायत, तबड़ में पचायत समिति और इसके ऊपर जिला परिषद। इनक लिए विकास कमचारिया की भखला है जो राज्य स्तर स शुरु हो कर गाँव तक फली हुई है। इस प्रणाली में स्थानीय लोग को काम करने की आजादी है और दखरेल ऊपर स है। अर्थात् इसका वही ढग है जो केन्द्र और राज्य के सबध का। दूसरे, सामुदायिक कार्यक्रम की तरह यह सरकारी मशिनरी का अंग नहीं है। पचायती राज की सत्थाएँ निर्वाचित हाती हैं और इसके कमचारी निर्वाचित प्रतिनिधिया क अधीन काम करते हैं। ४४ तीसरे, साधन जुटाने और जनसहयोग संगठित करने का भी इन सत्थाओं को अधिक अधिकार है। य कार्य ले कर केद्रीय सरकार तक निरंतर प्रसासनिक और राजनीतिक परपरा सुचारु रूप से नहीं काम कर रही है, परंतु प्रवृत्ति स्पष्ट लक्षित होती है। पचायत बहुत पुराने जमाने में भी वनमान थी, मगर वतमान पचायती सत्था इस माने में नई हैं कि उनको काफी अधिकार, साधन और जिम्मेदारिया सौपी

४२ योजना कमिशन द्वारा प्रकाशित प्रोग्राम एवेलुएशन रिपोर्टों को देखिए - कमिशन ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम से असतोष प्रकट किया और राष्ट्रीय विकास परिषद से उसका जांच कराने को कहा। तदनुसार मेइता कमेटा नियुक्त हुई और १९५७ में इसने बहुत बनी रिपोर्टें दा। इसका मुख्य गुणाव यह था कि विकास काम में स्थानीय जनता को लगाने के लिए एक प्रतिनिधि सत्था का स्थापना की जाए।

४३ इस प्रणाली के विविध रूपों के बारे में देखें - सेंटर फार द स्टडी आफ डेवलपिंग सोसाइ-टाज - 'ए नाफ इन्फ्रिक्शन आफ लोकल सलफ गवर्नमेंट सिस्टम इन गुजरात, महाराष्ट्र, उड्ड उत्तरप्रदेश (मिथि १९९६)।

४४ अर्थों की पचायत समितियों में ग्राम पचायतों के प्रधान हाते हैं। अधिकांश राज्यों में विश परिषदों का चुनाव पचायत समिति द्वारा करती हैं। बाद में महाराष्ट्र और गुजरात में निष्पक्ष परिषदों का प्रत्यक्ष निवाचन हाने लगा। इन सत्थाओं में अधिकारियों का उपस्थिति या शिरकात क बारे में भी अलग अलग परिपाटी है। पूरे विवरण के लिए देखें उपयुक्त पुस्तक।

गई है। नाम पुराना है मगर सस्था नई है। ४५ इन सस्थाओं ने नए स्थानीय नेताओं को जन्म दिया है जो आगे चल कर राज्य और केन्द्रीय सभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों से अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। कांग्रेस और अन्य दलों के राजनीतिक इन सस्थाओं के महत्व को समझने लगे हैं। अब वे राज्य विधान मंडल के वजाय पंचायत समिति और जिला परिषदों और जिला सहकारी बैंक और जिला परिवहन अधिकरण के पदों को तरजीह देने लगे हैं। इन पदों पर रहकर वे प्रशासन और प्रबंध में निपुणता प्राप्त कर लेते हैं। ये सरकारी पदाधिकारी स्थानीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था के बीच की कड़ी हैं। ४६ इन स्थानीय पदाधिकारियों के बिना ऊपर से प्रारम्भ किए हुए राष्ट्रनिर्माण के क्रियाकलापों का चलना मुश्किल हो जाता। इन लोगों के सहयोग के बिना सरकारी अधिकारियों का काम भी मुश्किल हो जाता। गैर सरकारी कार्यकर्ताओं की शक्ति केवल प्रशासनिक और वितरण सस्थाओं के पदों के कारण नहीं, बल्कि समाज के शक्तिशाली वर्गों के समर्थन के कारण है। इस प्रकार पुरानी व्यवस्था धीमे धीमे नई व्यवस्था के पास आ रही है।

### विचरवाई लोग

इस क्रिया ने एक दलाल विचरवाई वर्ग को जन्म दिया है। गैर सरकारी राजनीतिक, स्थानीय समाज के समर्थन के बल पर ही अपना काम कर सकता है। उसे विभिन्न तत्वों के प्रभावशाली लोगों का समर्थन प्राप्त करना पड़ता है। इन प्रभावशाली लोगों में जातीय और धार्मिक नेता, विभिन्न सस्थाओं के नेता, शिक्षक, वकील, डॉक्टर आदि व्यवसायों के प्रमुख, राजनीतिक पेशेवर या चुनाव के दलाल और स्थानीय गुंडे भी होते हैं जो लोगों को बल में रखते हैं और सौदा हो जाने पर दगाबाजी नहीं कर सकते। हो सकता है कि कहीं एक जादमी विभिन्न हिता और वर्गों को काबू में रखता है और कहीं कई विभिन्न हिता के अलग-अलग नेता

४५ योजना कमिशन, 'द विलेन पंचायत एंड पैटर्न ऑफ विलेन डेवलपमेंट' जुलाई १९५४-नवम्बर १९५५ तरलोवसिंह (मामियो)। किंतु इन सस्थाओं के कार्यों के बारे में कुछ दुविधा थी। कुछ अफसरों के विचार से इन्हें स्थानीय स्वशासन की वास्तविक सस्था होनी चाहिए और कुछ की राय थी कि इन्हें केन्द्रचालित योजनाओं को चलाने की एजेंसी मात्र होना चाहिए। देखें - मेइता वमेरी रिपोर्ट। विदेशी विशेषज्ञ में भी मतभेद था। डेनियल थार्नर इन्हें केन्द्रीय एजेंसी बनाने के पक्ष में थे और अल्बर्ट मेयर स्थानीय स्वायत्त शासन सस्था के पक्ष में। देखिये जान टी हिवरान, 'संग्रही प्लाट रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया' इकनामिक वॉक १३ मार्च, १९६१।

४६ गैर सरकारी शब्द अंग्रेजी जमाने में बना था, जब महत्त्व सरकारी लोगों का था।

होत ह । हर हालत म य महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं । ४७

सबध की य शखलाए पुराने जाति-विरादरी के मुखिया, सरकारी अधिकारियों से काम निकलवाने वाले चुनाव के दल और गुट, सब एक सावजनिक व्यवस्था के अंग बन गए ह । ससद और विधानसभाओं के चुनावों से राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने का सबसे बड़ा मौका मिलता है । पचायती राज के चुनाव कांग्रेस के उम्मीदवारों का चयन और कांग्रेस कमिटिया के चुनावों से राजनीतिक गतिविधिया में भाग लेने का और मौका मिलता है । इसके अलावा भी और मौके ह, जैसे विकास, अनुदान और खेती के लिए ऋणों के बटवारे चीनी, तेल आदि के वितरण, स्कूल, सड़क, ट्यूबवेल, दवाखानों आदि के निर्माण में वातचीत और जोर दबाव के मौके मिलते हैं । इन सब गतिविधियों का स्थानीय महत्त्व बहुत अधिक होता है । पचायती राज के चालू होने से जनसहयोग की इन शखलाओं का सबध ऊपर के राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण करनेवाले स्तरों से जड़ जाएगा और गावा के लोगों का महत्त्व बढ़ जाएगा । भारत की पुरानी ग्रामीण समाज-व्यवस्था का शासन और राजनीति में सहयोग, भारत के विकास की पद्धति में निहित है ।

यहां आधुनिकतावादी और आधुनिकता के प्रचारक में जो फर्क है उस को जान लेना चाहिए । आधुनिकतावादी शहरों के बौद्धिक और राजनीतिक विचारक लोग हैं । ये आधुनिक भारत के आदर्श और विकास के लक्ष्यों का निरूपण करते हैं । ये सैद्धांतिक बातें करते हैं, जनसाधारण की आकांक्षाओं और भावों से ये मतलब नहीं रखते । दूसरी ओर आधुनिकता के प्रचारक जनसाधारण में काम करते हैं । ये सिद्धांत के प्रजाय व्यवहार पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ये आधुनिक लक्ष्यों के लिए जनता का समर्थन प्राप्त करते हैं । साथ ही वे नीति-निमाता लोगों का असलियत की जानकारी देते हैं । वे ही राष्ट्र निर्माण के कार्य को गति देते हैं । कालांतर में ये आधुनिकतावादियों का स्थान ले लेते हैं । लोकतंत्रीकरण की इसी व्यापक प्रक्रिया को सरल रूप में शहर से गावा की ओर शक्ति के परिवर्तन का नाम दिया जाता है ।

४७ यह परिवर्तन या सन्नति काल की विशेषता है । बेरूल, मद्रास महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में जहां राजनीतिक दल और सरकारी एजेंसिया एकदम नीचे तक पहुंच गई हैं, बिच वश्यों का जल्दतर कम होती जा रही है । लोग सीधे राजनीतिज्ञों या अप्सरों से व्यवहार करते हैं । अफिन कम विनसित शर्कों में बिचवश्यों के जरिये ही, यह बातचीत होती है । देखें-आर चंदीदाम 'द फोर्थ जनरल इलेक्शनस' में 'प्रदेश, ए वेस स्टडी' इन्फार्मिक ऐंड पोलिटिकल वाक्वी २, स ३३-३५ बिरोपाक अगस्त १९६७ । इस बिषय पर सामान्य बिचार के लिए जयंत लेले, 'लोकल मोवर्स ऐंड नेशनल एडर्स' ए स्टडी आफ सपोर्टिंग एजेंसिज इन द डेवलपिंग पालिस्ता, अमोरेविन पोलिटिकल साइंस असोसिएशन की वार्षिक बैठक में पढ़ा गया लेख, सितंबर १९६८ (मीमियो) ।

## राजनीतिक विकास और नौकरगाहो

भारत सरकार ने गांधी तक पहुँचने और देशव्यापी सस्थाओं की शक्ति बनाने का जो विशाल प्रयत्न किया उससे यह पता चलता है कि जनता का समर्थन मिलने के बावजूद राष्ट्रीय आंदोलन समाज में गहरा नहीं जा सका था। गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को शहरी मध्यम वर्ग के सकीण दायरे से निकाल कर जनता में पहुँचाया था और ग्रामों के पुनर्निर्माण को उसका लक्ष्य बनाया था। लेकिन इस पर काम स्वतंत्रता के बाद ही शुरू हुआ।

दूसरे, स्वतंत्रता के बाद जो कुछ काम हुआ है उसके बावजूद भारत में एकरूप राजनीतिक समाज का निर्माण नहीं हो सका है। अभी भी यहाँ बहुत विषमताएँ और अंतर हैं। अभी बहुत दिनों तक यहाँ का समाज अनेकात्मक रहेगा, जिसमें अनेक स्वायत्त उपसमाज बने रहेंगे।

अब तक हमने जनता में राजनीतिक सस्थाओं के प्रसार पर जोर दिया है। साथ ही हमने बताया है कि प्रशासन और आर्थिक योजना का इस प्रक्रिया में क्या हाथ रहा है। बिना इन के राजनीतिक सस्थाओं का प्रसार न हो पाता। यहाँ हम इस विषय पर और विचार करेंगे।

## अंग्रेजों की विरासत

अंग्रेजों ने इस महादेश का शासन करने के लिए एक नमूने की जिला शासन प्रणाली की रचना की थी जिसके अधिकारी एक अखिल भारतीय सिविल सर्विस के सदस्य होते थे और जो शासन के समान सिद्धांत पर चलते थे। यही शासन प्रणाली हमको अंग्रेजों से विरासत में मिली।<sup>४८</sup> अंग्रेजी शासन में महत्वपूर्ण राजनीतिक और विकास संबंधी निश्चय सरकारी ढंग से किए जाते थे। यही परिपाटी भारतीय नेताओं ने भी अपनाई। इस परिपाटी को चार बड़े परिवर्तनों का मुकाबला करना पड़ा। एक तो शासन के कार्यों में बेहद विस्तार हुआ, दूसरे शासन के हर स्तर पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं का प्रभुत्व हुआ और नीति तथा नियम इन के हाथों में आया। तीसरे, जिले और नीचे के स्तरों पर लोकतंत्री सस्थाओं को अधिकार दिया गया, और चौथे, आर्थिक आयोजन, नियंत्रण और संयोजन की अनेक सस्थाएँ कायम हुईं तथा सामाजिक क्षेत्र का अपार विस्तार हुआ।

हमने देखा है कि स्वतंत्रता के पहले सहकारी अधिकारियों और राष्ट्रीय नेताओं में विरोध और कटुता के संबंधों के बावजूद स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने सरकारी नौकरों की स्थिति बरकरार रखी और इस प्रकार उनका विश्वास प्राप्त किया। यही नहीं उन्होंने भविष्य के सारे परिवर्तनों और नई नीतियों का भार भी सर-

<sup>४८</sup> हमने अध्याय २ में आई सा एस पर विचार किया है। आई सी एस की उत्तराधिकारी नई आई ए एस है, जिसके अधिकार प्रायः पूर्व सेवा जैसे हैं।



कारो सञ्चाया पर डाल दिया । सारी आर्थिक जोर राजनीतिक गतिविधिया का संचालन सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाता है । देशव्यापी चुनावों का प्रबंध, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सरकारी संगठनों की स्थापना व संचालन स्वयंसेवक संस्थाओं का भी संगठन, विशालकाय सरकारी कारखानों और कारपोरेशनों की व्यवस्था, बड़ी बड़ी परियोजनाएँ जिस में बहुत रुपये और टेकनिकल ज्ञान लगता है, अनुसंधान और विकास की बहुत बड़ी योजनाएँ, पंचायती राज जैसी राजनैतिक संस्थाओं के संगठन और संचालन और दुर्लभ वस्तुओं पर कंट्रोल और वितरण, यह सारा सरकारी नौकरों के जिम्मे है, और इन हेतु स्वतन्त्रता-पूव नौकरशाही का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है ।

परिवर्तन में नौ पुराने ढाँचे का बनाए रखने का कुपरिणाम भारत के प्रशासन तंत्र में नज़र आता है । फिर भी आवश्यक है कि गाड़ी चलनी रही । याद रहे कि भारतीय प्रशासन सेवा की ऊँची श्रेणियों में अधिकारियों की संख्या अधिक नहीं । आइए इस के करीब केवल ३००० आदमी केंद्र और राज्यों के प्रायः सारे शासन का चलाते हैं । दूसरे यह विकेंद्रित सेवा है ( निगमों पर जमने का काम केवल जिला स्तर पर गुरु होता है) । तीसरे, इस सेवा के सदस्य विशेषण न होकर एक काम से दूसरे काम पर जाते रहते हैं । इससे यह प्रश्न और महत्व का हो जाता है कि प्रशासनिक ढाँचे का नए सिरे से पुनर्गठन करने बजाय, पुराने ढाँचे को ही क्या बनाए रखा गया । <sup>४९</sup> भारत ने न तो समाजवादी देशों की भाँति शासन व ममानांतर राजनैतिक मशीन का निर्माण किया, न पश्चिमी देशों की भाँति जायिक विकास को निजी उद्योग के हाथ में छोड़ दिया । उसने देश के प्रशासन को विकास प्रशासन से अलग भी नहीं किया और कट्टरता की पेचीदा प्रणाली से काम चलाया ।

## नए विकास

स्वतन्त्रता के बाद आर्थिक गतिविधियों के समन्वय के लिए कबिनेट सचिवालय से लेकर नीचे के स्तर तक अनेक संस्थाओं का निर्माण हुआ । एक ओर योजना कमिशन और उसकी समितियाँ तथा जांच पड़ताल की एजेंसियाँ तथा दूसरी ओर

---

<sup>४९</sup> पुनर्गठन का बात बराबर चलनी रहता है । सरकार ने इनके लिए कई बार जांच पड़ताल कराई है । देखें, गाल एपिलवा, पूर्वोक्त, और 'रिपब्लिकानिजेशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम' ( दिनांक १९६६ ) और ए. डी. गोरवाला, 'रिपोर्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन' ( दिल्ली १९५१ ) । जमा हाल में प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस विषय पर कई रिपोर्टें दाय हैं । इनमें भारतीय प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी और उसके पुनर्गठन के लिए व्यापक सुझाव दिए गए हैं । उन पर अमल किया जाएगा या नहीं यह और बात है । इनके बारे में पिछला अनुभव अच्छा नहीं रहा है ।

केन्द्रीय मन्त्रालय ने सरकारी कपनियाँ और तारपारगना तथा विभागीय उद्योगों का एक जाल बिछा दिया। केन्द्र और राज्यों में सलाह मशविरों की प्रणाली चालू की, तथा आर्थिक और मानवीय साधनों के उपयोग के लिए जाल पड़ताल, दख रेख और नीति निर्धारण की व्यवस्था की। विकास समर्थी अनेक मन्त्रालयों के मन्त्री विशेषज्ञ लोग हैं, ५० और विभागों में विशेषज्ञ और टेक्निकल कार्यकर्ता रहे गये। राज्यों में भी यही हो रहा है। यहाँ समस्त अनुभवों अधिकारी मुख्य सचिव और विकास आयुक्त जैसे सबसे महत्व के पदा पर रखे जाते हैं और वे राज्य का आर्थिक और प्रशासनिक सून संचालन करते हैं। इन्हीं अधिकारियों पर और इनके राजनैतिक मालिकों या मन्त्रियों पर, जो काफी समय तक उन्हीं महकमों को सभालते हैं, विकास कार्यों का मुख्य भार पड़ता है। ये लोग एक-सा दृष्टिकोण और टेक्निकल बातों का गहरा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इन लोगों पर इतना अधिक भार लादना मुख्यवस्था के सिद्धांतों के खिलाफ है, मगर इससे लाभ यह होता है कि नीति और कार्य में एक रूपता बनी रहती है। ५१

जिला के स्तर में अधिकार दो अधिकारियों के हाथ में रहते हैं। प्रशासन और जिले की देखरेख का काम जिले का कलेक्टर करता है और उसी के समबन्ध पद का विकास अधिकारी जिला, ब्लॉक और गावों के विकास कार्य की देखरेख करता है। ५२ ये अधिकारी निर्वाचित गर सरकारी पदाधिकारियों के मातहत काम करते हैं जो स्वयं निर्वाचित ब्लॉक व जिला परिषदों के प्रति जिम्मेदार होते हैं। केन्द्रीय सरकार, योजना कमिशन और राष्ट्रीय विकास परिषद यह अनुभव कर रहे हैं कि प्रशासन के निचले स्तर से ढिलाई है, अतः इन संस्थाओं की स्थापना शासन की निचली श्रेणियों को चुस्त बनाने के उद्देश्य से की गई है। ये सम्प्राप्त अपने उपर अनेक काम ले लेती हैं और प्रशासन को जनता की जरूरतों के मुताबिक चलाने की कोशिश करती हैं। स्थानीय प्रशासन राष्ट्रीय और राज्य सरकार की नीकरशाही पर स्थानीय विकास के कार्यों और आर्थिक जरूरतों

५० उदाहरण हैं सी टा देशमुख, के एल राव एम सी चागला, वि कर व राव एस चन्द्रशेखर और त्रिगुण सेन। अशोक मेहता भी इसी श्रेणी में हैं। सा सुब्रमनियम भाबड़े टेक्निकल विषयों के मन्त्री रहे, इशरात तथा साध, कृषि और इनमें उन्होंने राजनीतिज्ञों के बजाय विशेषज्ञों की भाँति काम किया।

५१ भारत में बहुत थोड़े ऊपर के आदमी बहुत ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं इस भावना के लिए देंगे—पाल पविलनी, 'पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन'। लोकतन्त्र की स्थिरता के लिए स्पष्ट विचार वाले संगठित अधिकारी वर्ग के महत्त्व के लिए देखें—एटवड शिखर, 'पोलिटिकल डेवलपमेंट्स इन द यू स्टेट्स ऑफ़ इंडिया' इन सोसाइटी ऑफ़ डिस्ट्री, २, १९६०।

५२ प्रशासनिक और विकास संबंधी कार्यों में अंतर करना कठिन है। कलेक्टर के हाथ में भी विकास के अनेक कार्य होते हैं, जैसे नये उद्योगों का विकास और बन तथा खनिज संपदा की रक्षा।

की पूर्ति के लिए दबाव डालता है।

इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ऊपर के अधिकारी नीचे के स्तरों को अधिक प्रभावित कर पाते हैं, और अभाव या कष्ट के समय जनता की सहायता करते हैं, खेती की उन्नति और अन्य सुझावों की प्रेरणा देते हैं और आर्थिक सहायता और अन्य प्रकार के समयन का आश्वासन देकर उनके निणयों को प्रभावित करते हैं। दूसरी ओर ऊपरके लोगों को स्थानीय हालतों की जानकारी मिलती रहती है और जनता की भावनाओं का पता चलता रहता है।<sup>५३</sup> इससे सरकार और जनता में परस्पर संपर्क बढ़ता है।

### व्यवहारिक कठिनाइयाँ

नई संस्थाओं की स्थापना या पुरानी के सुधार के साथ-साथ उनका उपयोग भी ठीक-ठाग से होना चाहिए और नीति भी परिस्थिति के अनुरूप गतिशील होनी चाहिए। जब प्रगतिशील नेतृत्व का साविका अप्रगतिशील समाज से पड़ता है तो अक्सर नीतियाँ अव्यावहारिक हो जाती हैं। नेता लोग विकास की अपनी धारणा बना लेते हैं और ठोस कार्रवाई के बजाय कितनी बातों, सिद्धांतों और नाराओं से सतोंप कर लेते हैं और समझ बैठते हैं कि उनके अमुक कदम का अमुक परिणाम होना ही चाहिए। जब उनको गहरी विफलता मिलती है, तब स्थिति पर पुनर्विचार किया जाता है और नीति बदली जाती है। भारत में यही बात हुई।

पहली पंचवर्षीय योजना की सफलता के बाद बड़े पैमाने पर भारी उद्योगों के विकास की योजना बनाई गई। गांवों के लिए सामुदायिक विकास, भूमि सुधार के कानून और सहकारी खेती की बड़ी कितानी या अव्यावहारिक योजना बनाई गई।<sup>५४</sup> भारी उद्योगों के विकास में ही देश के अधिकांश साधन — जो पहले

---

५३ सभी जगह इस प्रकार का परस्पर संपर्क नहीं स्थापित हो सका है। अक्सर पंचायतों में जाति या वर्ग का बोझा रहता है और सब वर्गों के हितों की देखरेख नहीं हो पाता। निश्चित पदाधिकारी सरकारी अधिकारियों पर गलत दबाव भी डालते हैं। फिर भी कुछ बातें स्पष्ट हैं। एक तो चुनावों के कारण ऊँची जाति वालों को नाचू जातियों से मेल करना पड़ता है। दूसरे, ऊपर की शाखा का अंग होने के कारण पंचायतों में ज्यादा जिम्मेदारों का रहना है और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारों और शाखाओं को अब जनता की माँगों पर ध्यान देने और मनबूर होना पड़ता है। देखें — ए. हेन्सम। इस प्रणाली की संभावनाओं और चुनावों का भूमिका के लिए देखें — एस. सी. जैन 'कम्युनिटी डेवलपमेंट बेंड पंचायतों राउंड इन इंडिया' (कलकत्ता और बर्मा १९६७)।

५४ इस में शांतिनाथ अधिक था, ठोस कार्रवाई कम। भूमि सुधार कानूनों में भी राजनीतिक कारतव्यता की उपेक्षा की गई। सहकारी खेती के मामले में भी वास्तविकता का ध्यान नहीं रखा गया। नागपुर प्रस्ताव द्वारा कांग्रेस दल ने 'सहकारी लोकतंत्र' की स्थापना का ऐलान

[आगे के पृष्ठ पर]

ही से कम थे - लग गए जोर खेती पर बहुत कम ध्यान दिया जा सका। ५५ जब कि खेती की उन्नति के बिना, देश की दशा में कोई वास्तविक सुधार न हो सकता था। नतीजा यह हुआ कि योजना के लक्ष्य पूरे न हो सके। राज्य सरकार ने, जो योजना कमिशन के पोथी पड़िता के मुकाबले, वास्तविकता को ज्यादा समझती थी भूमिसुधार के कानून बनाने और सरकारी खेती को चालू करने में उत्साह न दिखाए और जनता ने सामुदायिक विकास योजना के निर्माताओं के उपदेशों पर कोई ध्यान न दिया। इस से स्पष्ट हो गया कि केवल लक्ष्य निर्धारित कर देने से ही विकास का काम पूरा नहीं हो जाता।

सामुदायिक योजना की विफलता को शब्दजाल से ढकने का प्रयत्न किया गया और नए नए सुझावों की झड़ी लगा दी गई, जो कभी पूरे नहीं हो सके। ५६ योजना बनाने वालों तथा प्रशासकों ने अपना दोष स्वीकार करने के बजाय किसानों पर अकर्मण्यता का दोष मड़ा। देशी और विदेशी समाज शास्त्रियों ने भी भारतीय जनता की अकर्मण्यता और भाग्य के भरासे रहने की मनोवृत्ति को ही दोष दिया। ५७ इन लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि खेती के साधनों के अभाव और अधिकारियों की खामियाली और कूटमगजी के कारण किसान नए तरीकों की जोखिम उठाने को तैयार न था।

इस बीच लोकतंत्री प्रणाली ने अपना जसर दिखाया। सघीय व्यवस्था, स्थानीय नेता और पार्टी संगठन की गतिविधि जोरा से चालू होने के फलस्वरूप ऐसे नेता

[ पिछले पृष्ठ से ]

किया, मानो कलम की नोक से इसकी स्थापना हो जाएगी। इस प्रस्ताव की गहरी प्रतिक्रिया हुई और फलस्वरूप स्वतंत्र पाठा का जन्म हुआ। प्रस्ताव की अव्यावहारिकता स्पष्ट हो गई और इसको धोरे से खनम कर दिया गया। इस चक्कर में खेती की उन्नति के लिए कोई ठोस काम न किया जा सका।

५५ खेती के विकास की उपेक्षा और आयोजन की सामान्य त्रुटियों के लिए देखें - डॉ. आर. गाडगिल, 'प्लानिंग ऐंड इकनामिक पालिसी इन इंडिया' (पूना १९६१)।

५६ इन सुझावों में सबसे साहसपूर्ण वा नीचे से आयोजन का, अर्थात् गांवों की योजना को राज्य और राष्ट्रीय योजना का आधार बनाने का। इस पर कभी अमल नहीं किया गया, यद्यपि इसे त्यागा भी नहीं गया। देखिए - ह्यूस्तन, पूर्वोक्त का अध्याय 'ग्राम्स रूट्स'। इसमें यह भी बताया गया है कि इस सुझाव को अमल में लाने के लिए क्या कदम उठाए गए।

५७ भारत के बौद्धिक नेताओं के भाषणों और लेखों में भारतीय किसान की अकर्मण्यता की बहुत शिंशायत की जाती है। यू. एन. मिशन रिपोर्ट में भारत के गांवों की प्रगति-हानता के अनेक कारण बताये गये हैं। इस विषय पर विदेशी पाठकों में कुसुम नायर की किताब - 'थमम्स इन द टरट' (लंदन १९६१) काफी मशहूर हुई। भारतीय किसानों की अकर्मण्यता का प्रचार करने वालों में एक डेविड सी. मेकक्लेरेड भी हैं - 'द 'अचैविंग सोसाइटी' (यूजस १९६१)। भारतीय जनता की उद्यमशालता के बारे में बहुत अययन किए गए हैं, इनमें से अधिकांश अमेरिकन संस्थाओं द्वारा कराए गए।

ऊपर आए, जो जनता के वोट का महत्त्व समझते थे और उसकी प्रारम्भिक जरूरत को जानते थे। इसलिए उन्होंने विकास के तरीका के बारे में नए सिरे से सोचने का तैयार थे। राज्यों के मुख्यमंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष कामराज, प्रधान मंत्री लालबहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी तथा कांग्रेस के अन्य यथार्थवादी लोग ने इन पुनर्विचार में योग दिया। सी सुब्रमण्यम जैसे कल्पनाशील मंत्री और उनके निष्ठावान अधिकारियों ने 'नई आर्थिक नीति' की तफसील तैयार की। लगातार दो बार के अकाल और देश की जनता को भोजन देने के लिए विदेशों से भिक्षा मागने की जलालत ने नीति-परिवर्तन को बाध्य कर दिया।<sup>५८</sup> योजना का कार्यक्रम बदल दिया गया, आर्थिक नियंत्रण ढीले किए गए, योजना कमिशन का पुनर्गठन किया गया। (उसको जो जरूरत से ज्यादा महत्त्व मिल गया था, उसे उचित स्तर पर लाया गया।) प्रशासन को निश्चित काम और दिशा दी गई और वास्तविक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम बनाया गया और प्राथमिकताओं का पुनर्निर्धारण किया गया।

अब कांग्रेस में आर्थिक नीति पर राजनैतिक विवाद होने लगे और आर्थिक तथा सामाजिक प्रश्नों को गुटबंदी का आधार बनाया गया। १९६६ में श्रीमती इंदिरा गांधी और कांग्रेस संगठन के नेताओं में जो विरोध हुआ, उसके कारण इंदिराजी ने बैंको के राष्ट्रीयकरण का निश्चय किया और ऋण तथा पूँजी नियोजन के क्षेत्र में राज्य को बहुत अधिक शक्ति मिली। यह कारवाई तेज विकास में याग देगी या सिर्फ नारेबाजी का रूप लेगी, यह तो जाने पता चलेगा, किन्तु इतना तो स्पष्ट हो गया कि राजनैतिक संघर्ष की नीति के प्रश्नों से जोड़ने की प्रवृत्ति की शुरुआत हो गई। इस के कारण देश के लक्ष्यों व उद्देश्यों को ठोस रूप मिलने की आशा हो गई है। इस राजनैतिक संघर्ष से नीति में जो परिवर्तन होंगे उनसे भारत के विकास का राजनैतिक नमूना क्या होगा।

इन प्रश्नों पर हम अध्याय ६ में अधिक विस्तार से विचार करेंगे। यहाँ इतना ही कहना काफी है कि देश ने जिन संस्थाओं का विकास किया है और उनसे जो राजनैतिक प्रवृत्तियाँ चालू हुई हैं, उनके कारण देश के लक्ष्यों को अधिक ठोस शकल मिलती जा रही है और जनता की भावनाओं और जरूरतों के अनुसार नीति में संशोधन किए गए हैं, तथा शासन जनता के अधिक निकट जाया है। अभी भी व्यवस्था में बहुत-सी नुटियाँ हैं, ठोस कार्य के बजाय नैक इरादों से संतोष कर लेने

---

<sup>५८</sup> नीति रीति का यह परिवर्तन केवल नीचे से दबाव के कारण नहीं हुआ। ऊपर के लोग भी ऐसी ही उन्नति की प्राथमिकता देने की जरूरत समझ रहे थे। अंतरराष्ट्रीय दबाव भी पड़ रहे थे। विश्व बैंक, संयुक्त राज्य अमेरिका और सहायता मिशन भी भारत सरकार पर जोर दे रहे थे कि वह विकास की नीति को सुधारे। मगर जैसा कि एक पड़ रिपोर्ट में स्वीकार किया गया उसी के विकास को सब से अधिक राजनैतिक समर्थन भारत के अंदर से मिला।

की प्रवृत्ति बनी है और पुरानी रूढ़िया तथा स्वायत्त राष्ट्रीय प्रगति के आड़े आत है। सर्वसम्मत राजनैतिक विचार अभी सस्था का रूप नहीं ले पाये हैं। विकास काय के लिए सस्थाओं में क्या परिवर्तन होने चाहिए, अभी इसको नेतागण ठीक समझ नहीं पाए हैं। फिर भी ठोस यथाथ का सामना करने और समस्याओं को सुलझाने के लिए नीति और प्रशासन के तंत्र में यथोचित संशोधन करने की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से लक्षित होती है। राजनैतिक विकास की और दिशाओं पर विचार करने के बाद, हम अध्याय ८ से ११ में विचार करेंगे कि विभिन्न समस्याओं को सुलझाने में शासन को कितनी सफलता मिली है।

### सस्था निर्माण और जनता की स्वीकृति

कहा गया है कि विकास प्रक्रिया की कठिनाइयाँ और दवावों के बावजूद भारत में स्थिरता बनी रही इसका मुख्य कारण यहाँ शुरू में ही सस्था निर्माण काय का हो जाना है।<sup>५९</sup> स्वतंत्रता के पहले और बाद में भारतीय लोकतंत्र की सस्थाओं के निर्माण का हमने जो अध्ययन किया है उससे इस मत की पुष्टि होती है। परंतु भारत के राजनैतिक नेताओं ने सस्थाओं के निर्माण में क्या रीति नीति अपनाई इसका तफ़्तील से अध्ययन जरूरी है। हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना होगा कि सस्थाओं के निर्माण के पीछे क्या प्रेरणा थी और सस्थाओं के विकास और उनके मायता व स्वीकृति प्राप्त करने में जनता के सहयोग और संगठन का क्या हाथ रहा।<sup>६०</sup>

चार बातें स्पष्ट हैं। एक तो यह कि भारत में सस्थाओं के विकास की प्रक्रिया काफी समय तक चलती रही। लंबे विदेशी शासन में प्रादेशिक और प्रशासनिक ढाँचे की रूपरेखा निर्मित हुई। फिर राष्ट्रीय आंदोलन भी लंबा चला और उसके लक्ष्यों का विकास हुआ और जनता में उन्हें मायता मिली। फिर दो दशकों तक कांग्रेस का शासन चला जिसमें संविधान के ढाँचे और उसकी प्रक्रिया का निर्माण हुआ और जनता में उनकी जड़ जमी। इन सब से लोकतंत्र की सस्थाओं का ढाँचा मजबूत हुआ। यह प्रक्रिया कभी टूटी नहीं, निरंतर जारी रही और लंबे अनुभव के साथ प्रशासन और राजनीति की लंबी परंपरा भी बतमान रही। मशीन टूटने नहीं पाई।

५९. सैमुअल एच. हर्दिगन, 'पोलिटिकल डेवलपमेंट एंड पोलिटिकल टिफ़े। इनका मत है कि जनता के सहयोग के साथ ही सस्थाओं का निर्माण नहीं हो जाता तो राजनैतिक हास होने लगता है। दूसरों का मत है कि बहुत जल्दी सस्थाएँ बन जाती हैं तो इससे संस्था बढ़ता है और प्रणाली के टूटने की नीव बतती है।

६०. देखिए मेरा - द्रैडिशनल गैट माडर्निटी रिनिशिएट, गवर्नमेंट ऑफ़ अपोनिशन ४, पृष्ठ ३, १९६८ ग्राम्य।

लंबाई के साथ ही इस प्रक्रिया में गहराई भी रही। राष्ट्रीय जादोलन और उसी से उत्पन्न राष्ट्र निर्माण का जादोलन दोनों जनता के समर्पण पर जाधित थे और इसी उद्देश्य से वे जनता में फैलाए गए। राष्ट्रीय नेता अधिक से अधिक जनता को राष्ट्रीय राजनीति में भाग देने से कभी हिचके नहीं। सस्थाओं के विकास के हर चरण पर जनता को उसमें शामिल होने का और उससे लाभ उठान का मौका दिया गया। इससे सस्थाओं की गतिशीलता बनी रही और उनमें जड़ता नहीं आने पाई।

देश में जो विचारों और आदर्शों की एकता फैल सकी, उसका कारण यही था कि नेताओं को भी कुछ आदर्शों में विश्वास था, और इन पर आचरण कर के उन्होंने पहले अपने साथी कार्यकर्ताओं में और फिर जनसाधारण में इनका प्रचार किया। गांधीजी के लेखों और भाषणों के विशाल संग्रह को पढ़िए तो आप यही पाएंगे। उनमें थोड़ी-सी बातों को बार-बार दोहराया गया है, जब तक कि वे राष्ट्र के मन में न समा गई और उसकी विचारधारा का जग न बन गईं। नेहरू ने भी यही किया। लोकतन्त्र समाजवाद, योजना और गुटों से अलग रहने की वह लगातार रट लगाते रहे जिससे इन विचारों ने स्वयंसाध्य तथ्य का रूप धारण कर लिया और वे राष्ट्र के बुनियादी सिद्धांतों में शामिल हो गए। कुछ समय तक इन बातों ने ही ठोस काय का स्थान लिया। किंतु यदि इन बातों का प्रचार न हुआ होता तो राजनीतिक सभ्यता में जड़ता आ जाती और वह सिद्धांतहीन गुट-चंदी के दलदल में फस जाती। इसी विचारधारा के कारण दलगत राजनीति देश की एकता का साधन बन गई।

हमने यह भी देखा है कि संविधान द्वारा जो ढांचा स्थापित हुआ, भारतीय नेता उसमें लगातार नई बातें जोड़ते गए। यह बहुत जरूरी है क्योंकि सस्थाओं का ढांचा जड़ नहीं होता कि एक बार हमेशा के लिए बन गया और उसमें कोई सुधार न हो सके। जैसे जैसे नई समस्याएँ उपस्थित हो, उनमें आवश्यक परिवर्तन होना चाहिए। नए राष्ट्र के एकीकरण और स्थानीकरण का काम एक बार में नहीं होता, उसे बार-बार करना होता है। पुराने मूल्य और उनके सस्थागत रूप, जातिप्रथा, स्थानीय राजनीति प्रादेशिक संगठन, बदलते रहते हैं। यह काम वर्षों तक चलता रहता है। वास्तव में यह कभी रुकता नहीं। यह धारणा कि सस्थाओं को स्थिर होना चाहिए और अस्थिरता की प्रक्रियाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए, भारत जैसे नए और विकासमान राष्ट्र की असंलियत से मेल नहीं खाती।

अतः हम यह कहना चाहते हैं कि यह न समझना चाहिए कि सस्थाओं के निर्माण की यह प्रक्रिया पहले से बनाए गए नमूने के अनुसार होती है। इसकी साधारण रूपरेखा कुछ आदर्शों व प्रयोजना से निर्धारित होती है लेकिन इसका भावी विकास नई परिस्थितियों के अनुसार होता है। नेतावर्ग जो कदम उठाता

है उसका परिणाम क्या होगा यह हमेशा नहीं सोच पाता । यदि सब परिणामों, विफलताओं, सघर्षों और कठिनाइयों की कल्पना पहले से ही कर ली जाए तो बहुत से कदम उठाए ही नहीं जाते । ११

---

नसोच परिणामों के बारे में दक्षिण-अलबर्ट ओ हर्शमैन, 'डेवलपमेंट प्राजेक्ट्स' (वॉशिंगटन डी सी १९६७) ।



## पार्टीप्रणाली और गठजोड़

अब तक हम देख चुके हैं कि भारत को इतिहास से क्या विरासत मिली है, उसने किस प्रकार पुरानी और नई बातों में समन्वय किया और किस प्रकार इसके आधार पर अपने संविधान की और आर्थिक व सामाजिक नीतियों की रचना की। हमने यह भी देखा है कि इन नई समस्याओं और विचारों तथा कुछ प्रतीकों और विधियों के जरिए देश की राजनैतिक व्यवस्था किस प्रकार अपना एक स्वरूप ग्रहण कर रही है।

प्रश्न यह है कि ये समस्याएँ किस हद तक समाज में प्रवेश कर पाई हैं और राजनैतिक व्यवस्था कहाँ तक जनता की स्वीकृति पा सकी है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें इस व्यवस्था के उन अवयवों या तत्वों को देखना होगा जो इसे गति देते हैं। ये तत्व तीन हैं। एक है दल की पद्धति और किस प्रकार यह विभिन्न तत्वा या गुटों से गठबन्धन करके सहमति प्राप्त करने की काशिश करती है। दूसरा है जाति का ढाँचा, जो इस पद्धति का सामाजिक आधार बन गया है और तीसरा है वे राजनैतिक संस्कार और सामाजिक प्रवृत्तियाँ जो प्रथम दोनों तत्त्वों से उत्पन्न होते हैं। इस और अगले दो अध्यायों में इन्हीं तीनों तत्वों का विवचन किया गया है।<sup>१</sup>

<sup>१</sup> भारतीय पार्टी पद्धति पर मेरे पहले के अध्ययन ये हैं—‘पार्टी सिस्टम’, ‘फार्म ऐंड सबस्टेंस इन इंडियन पालिटिक्स’ का पाचवाँ लेख, द इकनामिक वीकली, १३, जून ३, १९६१। ‘द कॉम्रेस सिस्टम इन इंडिया’—एशियन सर्वे ५, नं० १२ दिसंबर १९६४। ‘पार्टी पालिटिक्स ऐंड पोलिटिकल डवलपमेंट’ इकनामिक ऐंड पोलिटिकल वीकली, वार्षिक अंक, फरवरी १९६७। नेशन मेजिंग ऐंड कानशेंसिस—द कैस आफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस—सेवेंथ वल्ड कांग्रेस आफ द इटरनेशनल पोलिटिकल साइंस असोसिएशन, ह्युसेल्स। ‘अपोजिशन इन इंडिया परवेनिव ऐंड चीक—रॉबर्ट डाल संपादित ‘द एमर्जेंस आफ अपोजिशन (न्यू हेवेन १९७०)। ‘कॉम्रेस सिस्टम इन इंडिया शीर्षक लेख, ‘पार्टी सिस्टम ऐंड एलेक्शन स्टडीज’ में छपा है अकेजनल पेपर्स १, सेंटर फॉर द स्टडी आफ द डेवलपिंग सोसाइटीज (नई दिल्ली—१९६७)। इस अध्याय में इन सब लेखों में प्रस्तुत विचारों को और भी विवक्षित किया गया है।

## प्रतिस्पर्धी प्रमुखता

स्पष्ट है कि भारत की वर्तमान राजनतिक सस्थाभा की धुरी काग्रेस है। हमने देखा कि काग्रेस ने देश को एक संगठित नेतृत्व दिया, जा उसकी आर से बालने का दावा कर सकता था। इस क्रिया म काग्रेस वा अपना स्वरूप निखरा और उसने जनता की निष्ठा प्राप्त की। यह भी वाद रतना चाहिए कि काग्रेस ने न केवल विदेशी शासन का विरोध किया बल्कि इसने भारतीय समाज म घुस आई बुराईया का भी विरोध किया। समाज का सुधार और पुनर्निर्माण उसको उतना ही प्रिय था, जितनी देश की आजादी।<sup>२</sup> काग्रेस नेता बार बार यह कहा करते थे कि समाज का पुनगठन आजादी हासिल करने का उपाय है। काग्रेस की यह दाहरी भूमिका—राष्ट्र की ओर से बोलने की और राष्ट्र की कमजोरिया की आलोचना करने और उस बदलने की — आजादी क वाद शासन सभालने पर नी कायम रही। इससे यह जाहिर होता है कि आजादी की प्राप्ति राष्ट्र निमाण क वाय की शुक्-आत है। इसके लिए वर्तमान स्थिति स जमतोप और उसको बदलने की प्रवृत्ति उतनी ही जरूरी है जितनी स्थापित शासन-व्यवस्था को बनाए रखने की। ऐसा न करने के कारण ही एशिया और अफ्रीका की बहुत-सी राष्ट्रीय पार्टिया आजादी के वाद छिन निन हो गईं। पार्टी या दल तन वा विकास तभी हो सकता है जब राष्ट्र के एकीकरण के साथ साथ उसके पुनर्निर्माण का भी प्रयत्न चालू रह। काग्रेस पार्टी एक विशिष्ट पार्टी है। इसका संगठन चुनाव लडने के उद्देश्य से नहीं विदेशी शासन के विरोध के लिए किया गया था और इसे जनता म फलाने के साथ साथ विभिन्न विचारधाराआ और हिता को नी इसम लाने का प्रयत्न किया गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि काग्रेस संगठन म प्रधान या सत्ताधार, गुट के जलावा विरोधी गुट भी रहत थे। जब इसने शासक दल का रूप ग्रहण किया, तब भी इसम विरोधी गुट बने रहे। इससे संगठन की शक्ति ही बढी साथ ही इसके नेतावग को विरोधी गुटा की आलोचना का भी लगातार सामना करना पडा। यह आलोचना राजनतिक और सामाजिक प्रश्ना को ले कर की जाती थी। बालिग मताधिकार के द्वारा काग्रेस ने हर स्तर पर प्रतिद्वंद्विता के लिए अवसर दिया। चुनावो से केद्र म काग्रेस की प्रधानता स्थापित हुई, और राज्या तथा स्थानीय चुनावो मे भी उसकी शक्ति दृढ हुई। उसे देहात क लोगा का समयन मिला। चुनावो और योजना के कार्यक्रमो के द्वारा पहली बार देश की सरकार का गावा

<sup>२</sup> काग्रेस एक नीर अर्थ मे विरोध वा प्रतिनिधित्व करता था। इसके अदर अनेक विचारों के छोटे छोटे दल या समूह थे। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट सभी पार्टिया एक समय काग्रेस के अंग थे। काग्रेस के सत्ताधारी दल से मतभेद हो जाने पर लोग इससे निगल कर अलग पार्टी बना लेत थे और इसमें वापस भा आ जाया करते थे।

म प्रवर्ण हो सका। इसके साथ ही विपक्षी दल भी संगठित होते गए और उन्होंने अनेक स्तरों पर कांग्रेस को चुनौती दी।

### प्रचलित धारणाएँ

उल्लेखनीय है कि भारतीय राष्ट्र के प्रमुख निर्माता भी कांग्रेस संगठन की इस भूमिका को ठीक तरह से नहीं समझ पाए थे कि यह सरकार के समानांतर जनता में राजनैतिक कार्य करने वाला एक व्यापक संगठन है जिसमें विराधी विचारों और गुटों को भी स्थान है। इसका पता इस बात से चलता है कि गांधीजी ने सन १९४८ में यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस का राजनैतिक रूप समाप्त कर दिया जाए और उसके स्थान पर जनता में रचनात्मक कार्य करने के लिए लोक सेवक संघ की स्थापना की जाए। उनका कहना था कि जो लोग सदन या सरकारी पदों के इच्छुक हैं उन्हें कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए और अपना अलग राजनैतिक दल बनाना चाहिए। कांग्रेस को सत्ता और पद की होड़ से अलग रखा चाहिए। इस प्रस्ताव के पीछे यह विचार निहित था कि कांग्रेस जिस आंदोलन की प्रतीक थी वह जारी रहना चाहिये। परंतु कांग्रेस का राजनैतिक रूप समाप्त कर देने का विचार नितांत अव्यावहारिक था और कांग्रेस के नेताओं ने उसको नहीं माना।<sup>३</sup>

दूसरे छोर पर सरदार पटेल थे जो कांग्रेस से सब राजनैतिक गुटों को निकाल कर उसे एक मत का सदृश अनुशासनबद्ध दल बनाना चाहते थे। उन्होंने ही सन १९४८ में कांग्रेस के विधान में संशोधन कराया, जिससे संगठन के अंदर ऐसे दलों के रहने पर रोक लगा दी गयी जिनकी अलग सदस्यता, विधान और कार्यक्रम हो।<sup>४</sup>

इसी संशोधन के कारण कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को कांग्रेस से निकलना पड़ा। मगर पटेल के संशोधन का अभिप्राय इससे भी जागे जाना था। वह कांग्रेस के व्यापक (सब विचारों को समेटने वाले) स्वरूप को बदल कर इसे अनुशासित कार्य-

३ गांधीजी की यह वसीयत उनकी मृत्यु के एक दिन पहले लिखा गया था और यह भारतीय राजनीति के नैतिक स्वर की प्रतीक है। एक ओर इसकी दुहाई वे कांग्रेसजन देते हैं जो दलबंदी से तिर्र होकर कांग्रेस से अलग हो गए, दूसरी ओर जनसंघ और स्वतंत्र दल भी इसी साक्षी देकर यह कहते हैं कि यदि गांधीजी की अच्छा का पालन किया गया होता तो देश में दो या तीन दलों का पद्धति कायम हो सकती थी।

४ १९३० के दशक में कांग्रेस से हिंदू महासभा को निकाला जा चुका था और युद्ध के समय कम्युनिस्टों से, क्योंकि उन्होंने भारत छोड़ो आन्दोलन का विरोध किया था और युद्ध प्रयत्नों में सहयोग किया था। अब कांग्रेस में मुख्य संगठित गिरोह कांग्रेस सोशलिस्ट हो रहा था। मगर कुछ और नए गुट भी उठ रहे थे जैसे कांग्रेस डेमोक्रेटिक फ्रंट और कांग्रेस सोशलिस्ट फारम।

कर्ताओ का सुमगठित दल बनाना चाहते थे।<sup>५</sup> वह यथायवादी व्यावहारिक आदमी थे और वह सब विचारों को साथ लेकर चलने के बजाय, एक नेतृत्व और विचार के मानने पर जोर देते थे। पटेल इस बात को नहीं समझ सके कि शासक दल के रूप में भी कांग्रेस को कई दशका तक अनेक तत्त्वों को साथ लेकर चलना होगा।<sup>६</sup>

नेहरू वचारिक मतभेदों से कम घबड़ाते थे और इस बात को ज्यादा समझते थे कि शासक दल के रूप में कांग्रेस को आंदोलन और राजनीतिक पार्टी, दोनों रूपों में काम करना है। इसका एक कारण यह था कि उनको भरोसा था कि राष्ट्र को किस ओर जाना चाहिए। साथ ही उन्हें यह भी विश्वास था कि इस विषय में उनके विचारों को कांग्रेस स्वीकार कर लेगी। दूसरे, वह पार्टी में खुले मतभेद या झगड़ा से बचते थे।<sup>७</sup> जैसा हम देख चुके हैं, उनकी नीति अप्रिय प्रश्नों या गड़बड़ों की बातों को टालने की रहनी थी। गांधी या पटेल के बजाय नेहरू इस बात को ज्यादा समझते थे कि कांग्रेस में विभिन्न विचारों के लोग हों और उसे सहमति से चलना चाहिए। लेकिन नई स्थिति में कांग्रेस संगठन की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसे वह भी ठीक नहीं समझ सके। यह स्वामाविक था कि स्वतंत्रता के बाद संगठन के बजाय सरकार का स्थान प्रमुख हो जाए और सरकार को देश के राजनीतिक संगठन के नये काम करने पड़े, साथ ही सरकार और जनता की कड़ी के रूप में कांग्रेस संगठन का भी महत्व अभी भी कम नहीं हुआ था। एक तो देश में सशक्त विपक्षी दलों का अभाव था, दूसरे सदन में भी अभी विरोधी मत और लोगों की शिकायतें ठीक ठम से अभिव्यक्त नहीं हो पा रही थी इसलिए कांग्रेस संगठन को यह काम करना था। नेहरू ने संगठन को यह काम नहीं करने दिया,

५ पटेल का उद्देश्य इतना स्पष्ट नहीं था। वह वाम पक्ष के कट्टर विरोधी थे। सन १९४९ में जब नेहरू देश के बाहर थे तब कांग्रेस कार्यकारिणी ने यह निश्चय किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य भी कांग्रेस के सदस्य हो सकते हैं। पटेल ने इस निश्चय का विरोध नहीं किया। बाद में नेहरू के लाटने पर यह निश्चय रद्द हुआ।

६ १९४७ में कांग्रेस के प्रधानमंत्री श्री सूरदास देव को कांग्रेस के असली स्वरूप की अधिक समझ थी। एक सत्रोत्तर में उन्होंने कहा कि आने वाले कठिन समय में देश की एकात्मता और सिरता को बनाये रखने और सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन और विकास के पहले से चले आए अधूरे काम को पूरा करने के लिए एक बड़े राजनैतिक दल के शासन में बने रहने की जरूरत है और कांग्रेस का यही काम करना है।

७ नेहरू सोशलिस्टों को कांग्रेस से निवालेने के इच्छुक नहीं थे। यद्यपि उन्होंने पटेल को ऐसा करने से नहीं रोका (आंदोलन के दिनों में गांधीजी से भी वह इसी तरह दबाव डालते थे और वाम पक्ष का साथ छोड़ देते थे)। लेकिन बाद में उन्होंने सोशलिस्टों को कांग्रेस में फिर से आने की बातचीत चलाई और समय-समय पर कुछ सोशलिस्ट कांग्रेस में वापस आते भी रहे। नेहरू प्रगतिशील तत्त्वों के नेता माने जाते थे। नेहरू और पटेल की प्रवृत्ति और विचारों में अंतर था और कांग्रेस शासन व पार्टी के बारे में उनकी धारणा भी भिन्न थी।

क्योंकि वह अपनी ही प्रमुखता कायम करना चाहते थे। सगठन में अपने विरोधिया या भिन्न मत वालों को उहोने शुरू में ही दबा दिया और सगठन को स्वतंत्र हो कर काम न करने दिया। राज्या में वह सगठन पक्ष को सत्ताधारी पक्ष के प्रति द्वेदी के रूप में काम करने देते थे और इस प्रकार सत्ताधारी गुट पर अकुश रखन थे, किंतु केन्द्र में वह सगठन को अपने प्रतिद्वेदी के रूप में काम नहीं करने देते थे और वागडार अपने हाथ में रखना चाहते थे। उनके अंतिम समय में ही फिर एक बार सगठन की शक्ति बढ़ने लगी और उसमें प्रभावशाली नेता सगठन के पदाधिकारी बने, लेकिन तब तक सामाजिक और राजनैतिक परिवर्तनों की सूत्रधार के रूप में सरकार की शक्ति स्थापित हो चुकी थी।

स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस की भूमिका क्या हो और कांग्रेस सरकार से उसका क्या संबंध हो, इसके साथ ही यह प्रश्न भी था कि उसकी कांग्रेस की प्रमुखता का सामने विराधी दला का क्या स्थान हो। इस विषय पर भी गंभीरता से नहीं सोचा गया। शुरू में विरोधी दलों को आशा थी कि वे कांग्रेस को अपदस्थ कर सकेंगे। लेकिन पहले और दूसरे चुनाव के बाद विराधी दला की बड़ी निराशा हुई और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा बनाने की बात शुरू हुई। बुद्धिजीवी वग द्विदलीय प्रणाला को ही सब से अच्छी समझते थे और प्रमुख कांग्रेसजन भी आशा करते थे कि धीरे धीरे यहा ऐसी पद्धति का विकास होगा। इस बीच कुछ प्रमुख लोग, जिनमें श्री जयप्रकाश नारायण भी थे, इस नतीजे पर पहुँचे कि दलगत राजनीति भारत के लिए उपयोगी नहीं, और व राजनीति से जलग हा गए।<sup>८</sup> दूसरी ओर अशोक मेहता का कहना था कि देश की गरीबी का देखते हुए, देश की सारी प्रतिभा उसे दूर करने में लगनी चाहिए, इसलिए विरोधी पक्षों का कांग्रेस से इस काय में सहयोग करना चाहिए, उनका कांग्रेस का विरोध नहीं, स्वस्थ आलोचना द्वारा उसकी नीतिया में सुधार करना चाहिए।<sup>९</sup> मगर उनकी बात का 'अगूर खट्टे हैं' का उदाहरण समझा गया। नेता लोग यह नहीं समझ पाए कि देश की सत्ता के ढाँचे में विरोधी दला का महत्वपूर्ण स्थान है। ये विराधी दल क्षेत्रीय स्तर पर शक्तिशाली हैं और स्वयं कांग्रेस की आंतरिक स्पर्धा का संरक्षक हैं।

<sup>८</sup> जयप्रकाश नारायण, 'सोशलिज्म टु सर्वार्थ' (वाराणसी १९५६) 'टुवाल्स ए न्यू सोमा री' (नई दिल्ली १९५८), 'ए प्लॉ फार रिक्स्ट्रक्शन आफ इंडियन पालिटी' (वाराणसी १९५९), 'स्वराज फार द पीपुल' (वाराणसी १९६१)।

<sup>९</sup> अशोक मेहता, 'पॉलिटिक्स आफ प्लांड इकानामी' (द्वैराबाद १९५९), 'द अशोजिशन इन द न्यू स्टेट्स-पैपर्स आन द इंडियन सनिनार आन रिप्रेजेन्टेटिव गवर्नमेंट ऐंड पब्लिक लिबर्टी इन द न्यू स्टेट्स' (नई दिल्ली, १९५८)। मेहता ने अपने दल के विरोध सन्मेलन में अपने निरूप पोलिटिक्स कमिशन से आफ बैररट इकानामी में अपने विचार प्रस्तुत किए। देखिए, रिपोर्ट-१९५९ जनरेशन आफ द प्रजा सोशलिज्म पा। (देवू १९५९)।

१९६० के बाद ही कांग्रेस में फूट पड़ने से जोर डा राममनोहर लोहिया क करारे  
व्यंगा से उत्तेजित हो कर विरोधी दला ने विरोध ही एग गुप्तगत पद्धति का विकास  
किया ।

### दलीय प्रणाली का विश्लेषणात्मक स्वरूप

इस प्रकार हमारे देग में भी अज जनेग गंग की तरह दलीय राजनीति में प्रभुता  
सुत्रधार इस क विभिन्न जग के आपसी गवष को ठीक ठीक गमत नहा सक ।  
इसका एग कारण राजनीति को वगदित-भापन का जरिया समझने की धारणा है  
जिसमें दल शासन या सरकार के डांच स जलग चीज समझा जाता है जो मुसर  
वर्गों का हित-भाषा करता है । इहें मसगीय शासन म चुनाव त यन का ए  
जग समझा जाता है गिराफा काम समाज में प्रचलित वर्ग या विचार सवग  
लाभ उठा कर पोटा जोर सीटा का प्राप्ति तरन की वागिदा करना है ।  
इस धारणा म इग बात की नुना दिया जाता है कि सत्ताधारी और विरोधी  
पक्षा क डांचे का मुसलिर करन क निग तरतार और पार्टी या दल दाना एग साथ  
मिल कर काम करन हैं । स्थानीय प्रातीय और राष्ट्रीय विभिन्न स्तरा पर विभिन्न  
इलाका में सरकार का समयन और विरोध सगठित करने में लोगो की राजनीति  
और सावजनिक मामला में लगाने में तथा सरकार या सत्ता स सबय जोड़ने में पार्टी-  
पद्धति का जो हाथ हाता है उसरी भी उग ता कर दी जाती है । यह बात भी भुला  
दी जाती ह कि पाटिया समुच्चयन और गिराडन दोनों काम करती हैं और जनेक  
बीच की मस्याआ और मगठना के जरिये काम करती हुई सपनों का फलने म  
राखती ह और जनता का शासन की विभिन्न सस्थाआ और क्षेत्रा में जंग  
स्थानीय शासन शासन को आपरेटिव जादि में दिलचस्पी लेने को प्रवत्त करती ह  
पार्टी या दल सरकार को विभिन्न क्षेत्रा में बारवाई करने को भी प्रवत्त करत हैं ।  
पाटिया केवल एक दूसरे से स्पर्धा और जनता का प्रतिनिधित्व ही नहीं करती, ये  
इस प्रकार सरकार के पक्ष या विपक्ष म सायन भी प्रस्तुत करती हैं ।  
यदि इस बात का समय लिया जाए तो यह भी समझ में आ जाएगा कि केवल  
दो दला की पद्धति से समाज के विभिन्न हिता और मता को शासन म भाग लेने  
और अपनी आवाज बुलद करने का पूरा अवसर नहीं मिलता । पश्चिम के देगा  
में भी दो दला की पद्धति से असतोप यद रहा है और उससे अल्पमता को अभि-  
व्यक्ति और प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता । यदि पाटिया कइ हा, और विभिन्न  
स्तरा और क्षेत्रों में काम करें तो अल्पमता का प्रतिनिधित्व ज्यादा अच्छा हो  
सकेगा । फिर भी नए राज्या में भी दो दल पद्धति का ही दौरदोरा है । आगे हम  
पार्टी पद्धति का अध्ययन इस दृष्टि से करगे कि सरकारी क्रियाकलाप को उसने  
किस प्रकार प्रभावित किया ह, विभिन्न स्तरा पर उसने कैसा काम किया है और

समाज की ओर से इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई है।<sup>१०</sup>

### मुख्य विशेषताएँ

पहले हम यह देखने कि पार्टी पद्धति के विकास की पृष्ठभूमि क्या है और उसमें सहमति और मतभेद का क्या रूप रहा है।

(१) पार्टी पद्धति का विकास एक सुपरिचित केन्द्र से हुआ, जिसका उदय स्वतंत्रता से अनेक दशक पूर्व हुआ। इस सुपरिचित केन्द्र की अभिव्यक्ति इंडियन नेशनल कांग्रेस के देशव्यापी संगठन और प्रभावशाली नेतृत्व के द्वारा हुई।

(२) ये नेता मुख्यतः अंग्रेजी पढ़े ऊँची जाति के और इस प्रकार सामाजिक रूप से समरूप एक छोटे से वर्ग के थे।<sup>११</sup>

(३) विरोधी दल भी इसी वर्ग से निकले। स्वतंत्रता के पहले भी कांग्रेस के अंदर विरोधी दल या समूह थे। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के अंदर गुटबंदी बढ़ने के साथ-साथ उसके बाहर भी विरोधी पार्टियाँ का संगठन हुआ। अधिकतर विरोधी दलों के नेता पहले कांग्रेस में रह चुके थे और उनकी सामाजिक-शैक्षिक पृष्ठभूमि एक-सी थी।

(४) इस प्रकार राजनीतिक दलों का विकास एक मध्यवर्ती दल के फूटने से हुआ, सामाजिक और आर्थिक हितों के आधार पर नहीं। यह विरोध ससदीय लोकतंत्र की नई संस्थाओं और शालिग मताधिकार के माध्यम से संगठित हुआ और शासन तथा विकास कार्यों के विभिन्न स्तरों पर प्रकट हुआ। यह विरोध सामाजिक या वर्ग संघर्ष का परिणाम नहीं था बल्कि राजनैतिक फट या संघर्ष का परिणाम था।

(५) विरोध की इस पृष्ठभूमि का एक नतीजा यह हुआ कि भारत में सरकार, सरकारी दल में विरोधी या असंतुष्ट गुट, विरोधी दल और विरोधी दलों में असंतुष्ट गुटों में स्पष्ट अंतर नहीं था और विभाजन-रेखा अस्पष्ट थी। सत्ताधारी और विरोधी दोनों दलों में वैचारिक स्पष्टता और एकता का अभाव है। इससे सरकार और पार्टी या दल के बीच रेखा खींचना भी कठिन हो गया।

१० देखें, मेरा 'स्ट्रोकेशन ऑफ़ एलेक्टोरल चेंज इन इंडिया' (नई दिल्ली - सेंटर फॉर स्टडी ऑफ़ डेवलपिंग सोसाइटी १९६०)। माइरन बीनर ने भारतीय पार्टियों का विस्तार से अध्ययन किया है, देखें - उनका पार्टी पोलिटिक्स इन इंडिया, डवलपमेंट ऑफ़ ए मल्टी पार्टी सिस्टम' (प्रिंसटन १९५७) और 'पाटी बिडिंग इन ए न्यू नेशन, द इंडियन नेशनल कांग्रेस' (शिकागो १९६७), बीनर के मत की सरकार के कार्य की दृष्टि से आलोचना के लिए देखें - फ्रांसीस बार फ्रैकल, 'डेमोक्रेसी ऐंड पोलिटिकल डेवलपमेंट, पसपेजिटिव फ्राम द इंडिया प्रक्सपेक्टिवस', नई पोलिटिक्स, ११ स ३, अप्रैल १९६९।

११ गोपाल कृष्ण, 'वन पार्टी डोमिनन - डेवलपमेंट्स, पाटी सिस्टम ऐंड एलेक्शन स्टडीज, अकेजनाल पेपर्स १, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ़ डेवलपिंग सोसाइटी (नई दिल्ली-१९६७)।

(६) सत्ता और अधिकार के बल पर पार्टी या यह ढाँचा टिका हुआ है। सरकारी तन्त्र से सबध रख कर ही नेतावर्ग अपनी स्थिति बनाये रख सकता है। इसके लिए किसी दल और गुट से सबध रखना जरूरी है। जो लोग ऐसा सबध नहीं रख सके, वे प्रभावहीन हो गए, भले ही व्यक्तिगत रूप से उनका वितना ही प्रभाव रहा हो। इसी कारण पार्टी या दल का स्पष्ट वचारिक आधार न होते हुए भी सदस्य या नेता पार्टी की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय राजनीति का केन्द्रबिंदु सरकार है इस लिए यहाँ वे ही जीवन रह सकते हैं, जो सरकारी दल में हों या सरकार विरोधी दल में।<sup>१२</sup>

(७) इससे भारतीय राजनीति में बड़ी स्वतंत्रता आ गयी है। न सिर्फ यहाँ नए दल बनाने और दल परिवर्तन की स्वतंत्रता है बल्कि सत्ताधारी दल के विभिन्न गुटों से विरोधी दलों का परस्पर संबंध बना रहता है। जब कोई दल बहुत दिनों तक सत्ता में बना रहता है, जैसे कि कांग्रेस, तब उसमें कई स्पष्ट गुट बन जाते हैं। ऐसा होने पर विरोधी दलों का प्रभाव बढ़ जाता है। विरोधी नेता विधान सभा के भीतर और बाहर आलाचना द्वारा, या सत्ताधारी दल के गुटों या सदस्यों पर अपने व्यक्तिगत प्रभाव के द्वारा (कई नेताओं का कांग्रेस से अलग हो जाने पर भी कांग्रेस जना पर बड़ा प्रभाव है) सरकारी नीतियाँ और निष्पत्ति का प्रभावित कर लेते हैं। १९६७ तक विरोधी दलों का बहुत कम प्रभाव था और कांग्रेस के अंदर विरोधी गुट विरोधी दलों का काम करते थे, उनमें से अनेक तो अक्सर विरोधी दलों की नीतियाँ और विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते थे और कांग्रेस दल के अंदर विरोधी दलों की भाषा में बात करते थे। इन गुटों के द्वारा सरकार और विरोध पक्ष में कड़ी जुड़ी रहती थी और उनमें काफी खुल कर राजनैतिक व्यवहार चलता था।<sup>१३</sup>

(८) जब सरकारी दल का स्थिर और स्पष्ट बहुमत रहता है तब विरोधी पक्ष उसकी नीतियाँ को ज्यादा प्रभावित कर पाते हैं, वनिस्वतः उन समय का जब

१२ अनन्त अत्यंत प्रभावशाली नेता कांग्रेस या अन्य दलों को छोड़ने के बाद अस्त हो गए। कांग्रेस ने दल छोड़ने वालों के साथ बड़ी कड़ाई का बर्ताव किया। ऐसे लोगों में चम्बरवीर राज गोपालाचारी, आचार्य कृष्णलाल, एन बी रंगा, हरेकृष्ण महापात्र, कृष्ण मेनन और टी टी कृष्ण माचारी हैं, यद्यपि कृष्णमाचारी कांग्रेस से अलग नहीं हुए। जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ने के बाद दूसरे दल स्थापित किए, उनका प्रभाव बना रहा, जैसे नवय मुत्तजी, चरणसिंह और गुरनाम-सिंह। पार्टी का महत्व इससे सिद्ध है कि निर्दल सदस्यों का, उनकी छोड़ कर जिनका सरकार से संबंध है, कोई राजनैतिक महत्व नहीं।

१३ दॉय, मेरा 'पार्टी सिस्टम'। डब्ल्यू एच मारिस जेम्स ने, गवर्नमेंट ऐंड अपोजिशन १ स ४, अगस्त १९६६ में अपने निबंध 'डामिनेंस ऐंड डिसेंट' में यही मत प्रकट किया है। विरोध पक्ष के सुत्रे या बद रूप के बारे में देखिए, एडवर्ड शिम्स का निबंध 'अपोजिशन इन द न्यू स्टेट्स ऑफ एशिया ऐंड ऑस्ट्रेलिया', गवर्नमेंट ऐंड अपोजिशन, १, स २, फरवरी १९६६।



सरकारी बहुमत अस्थिर हाता है। कारण जब सरकार मजबूत होती है, तो दल के भीतर विरोध को छूट दी जाती है। विरोधी दल भी इस स्थिति में लोकतन्त्रीय पद्धति से चलते हैं लेकिन जब सरकार का बहुमत बहुत थोड़ा रहता है, तब विरोधी दल की प्रवृत्ति तोड़फोड़ करके सरकार को उलटने की रहती है। अस्थिर बहुमत से सत्ताधारी दल में ज्यादा एकता और अनुशासन जाने के बजाय, गुटबंदी और फूट को प्रोत्साहन मिलता है। विरोध के ये दोनों ही रूप भारत में देखने का मिलते हैं।

(८) यहाँ केवल राजनैतिक दल का संगठन करने और चुनाव लड़ने की ही छूट नहीं है, बल्कि सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने की भी छूट है। राष्ट्रीय आंदोलन के दिनों से ही इस प्रकार के विरोध, सीधी कारवाही, सत्याग्रह, अनशन आदि की परंपरा चली आई है। लोकतन्त्र के सिद्धांत से जनता के नाम पर आंदोलन करने का समर्थन किया जाता है। साधारणतः ऐसे आंदोलन को उचित समझा जाता है और सरकार भी इन पर ध्यान देती है। इनकी उपेक्षा करना सरकार के लिए कठिन हो जाता है।<sup>१४</sup>

(१०) साधारणतः कुछ उग्रवादियाँ को छोड़ कर सरकारी दल के अन्दर विरोध और जन आंदोलन का उद्देश्य सरकार को उलटना नहीं बल्कि उसमें प्रवेश पाना रहता है। इसलिए उन्नत या अमीर देशों के ऐसे आंदोलनों के विपरीत यहाँ ये आंदोलन छिटपुट और असंगठित रहते हैं और तात्कालिक उद्देश्य सिद्ध होने के बाद ये खतम हो जाते हैं।

(११) विरोधी तत्वा का उद्देश्य सत्ता या व्यवस्था को उलटना नहीं, उस पर कब्जा करना है। अक्सर विरोधी दल सत्तारूढ़ दल के सिद्धांतों या लक्ष्यों का विरोध नहीं करते, बल्कि यह कहते हैं कि सत्ताधारी दल उन पर अमल नहीं करता। इसका एक कारण यह है कि विरोधी दल के नेता भी उसी बग के हैं जिसके कांग्रेस वाले हैं। उल्लेखनीय है कि १९६७ के आम चुनाव के बाद, देश के जाड़े राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकार कायम हुई, किंतु ८ में ६ मुख्यमंत्री भूतपूर्व कांग्रेसी थे। इस तरह न केवल व्यक्तियों में, बल्कि विचारधारा और कार्यक्रम में भी कांग्रेस और विरोधी दल में कड़ी बनी रही। इस प्रकार विरोध को राजनीतिक व्यवस्था में मायता मिली।

(१२) व्यवस्था की घुरी सरकार है। पार्टी की अधिकतर गतिविधि सरकार या शासन के जरिये चलती है। सरकारी शक्ति और साधना, खास कर विकास कार्यक्रमों के साधना के जरिए सत्ताधारी दल अपने संगठन को फैलाता है। इसलिए

<sup>१४</sup> संसदीय लोकतन्त्र में सरकार के लिए अपनी प्रतिष्ठा के नाम पर कड़ा रुख अपनाना संभव नहीं होता। देखिये, मेरा 'डाइरेक्ट ऐक्शन - ५ पैटर्न ऑफ पोलिटिकल बिहेवियर', क्वेस्ट (१९६६), नं. २४, जनवरी १९६०।

विरोधी दल भी सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। राजनैतिक व्यवस्था, अधिकांशतः सरकारी नौकरशाही और विकास की मशीनरी पर चलती है, इसलिए राजनैतिक अस्थिरता या एक दल के सत्ताच्युत होने पर भी काम चलता रहता है। राजनैतिक अस्थिरता या सरकार के पतन की स्थिति में काम चलाने के लिए संविधान में व्यवस्था है। इस के अलावा अंगरेजों के समय में जब दलतंत्र नहीं था, प्रशासन का जो ढांचा बना था, वह राजनैतिक अस्थिरता के समय में काम करता रहता है। कांग्रेस के हाथ में जब सत्ता आई तो उसने सरकार और राजनैतिक तंत्र को समाज व राष्ट्र के विकास का मुख्य साधन बनाया। केन्द्रीय सरकार की सत्ता राष्ट्र के अस्तित्व का आधार बनी। इसलिए न सिर्फ केन्द्रीय सरकार को दब बनाया गया, बल्कि उसके अधिकार और शक्ति को बहुत बढ़ाया गया। राष्ट्रीय सरकार के प्रति निष्ठा, राजनीति का मुख्य सिद्धांत और कसौटी बन गई और सरकार तथा सरकारी दल राष्ट्र और राष्ट्रीयता के प्रतीक बन गये। सरकार के नेता छोटी के राष्ट्रीय नेता थे, इससे स्थापित व्यवस्था को जनता की निष्ठा और समर्थन मिला। बाद में जब विरोधी पक्ष का उदय हुआ तब विरोध का अर्थ सरकार का विरोध हो गया। इस प्रकार चुनाव का उद्देश्य सरकार का विरोध या समर्थन हो गया।

(१३) इसका यह अर्थ नहीं कि प्रचलित राज्यव्यवस्था का बुनियादी विरोध नहीं किया गया या इसकी बुनियाद को चुनौती नहीं दी गई। प्रत्युत भारत के अनेक प्रमुख व्यक्तियों ने भी इस व्यवस्था की उपयोगिता पर शका प्रकट की है। फिर भी इससे इस व्यवस्था के चलने में कोई गहरा व्याघात नहीं आया। लेकिन अभी इस व्यवस्था की जड़ बहुत गहरी नहीं गई है, और आर्थिक क्षेत्र में इसका कार्य सतोपजनक नहीं रहा है। इस भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है और जैसे जैसे राष्ट्रीय प्रश्न स्पष्ट होते गए हैं, इस व्यवस्था की जांचोचना भी बढ़ती गई है। खास कर शहरी बुद्धिजीवी वर्ग इसकी बहुत टीकाटिप्पणी करता है और इसके प्रति अनाम्य प्रकट करता है। शहरी बुद्धिजीवी वर्ग की यह जांचोचना मौखिक विरोध तक ही सीमित है।

(१४) व्यक्ति का महत्त्व राजनीति में अभी भी बहुत है। व्यक्तिविशेष को लेकर गुट बनते हैं। एक और बात यह है कि एक ही संगठन के विभिन्न अंग अलग अलग काम करते हैं। एक ही दल की राष्ट्रीय और राज्य शाखाएं विपरीत दिशाओं में चलती हैं और ऐसे गुटों और तत्त्वों से हाथ मिलाती हैं, जो विचारधारा और नीति में उनसे भिन्न हैं। इस प्रकार व अवसरवादिता का परिचय देती हैं। प्रदेशों या राज्यों की स्थिति और समस्याओं में भिन्नता होने के कारण एक ही दल को भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न ढंग से काम करना पड़ता है। वही दल एक जगह सरकार बनाता है और दूसरी जगह विरोधी दल के रूप में काम करता है। इससे दल

का एक निश्चित स्वरूप और नीति नहीं निखर पाती। केवल कांग्रेस ही अपने लंबे इतिहास और देशव्यापी संगठन के कारण अपनी एक तस्वीर या स्वरूप बना पाई है। कुछ और दल जो ऐसा कर सके हैं, महज प्रांतीय दल हैं, जैसे मद्रास में द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम्, पंजाब में अकाली दल और असम तथा उड़ीसा में आदिम जातियों के दल। कम्युनिस्ट दल भी जो बड़ा अनुशासित माना जाता है, बजाय एक अखिल भारतीय दल के, बंगाल और केरल के प्रांतीय दल के रूप में ही काम कर सकता है। राजनैतिक सरगर्मों बढ़ने के साथ साथ राष्ट्रीय दला के प्रांतीकरण का प्रवृत्ति भी बढ़ी है, घटी नहीं, और स्थानीय दलों तथा व्यक्तियों का महत्त्व भी बढ़ा है।

(१५) इससे राजनीति में व्यक्तियों का महत्त्व बहुत बढ़ा है यद्यपि गांधी और नेहरू जैसे महान और चमत्कारी व्यक्तियों की परंपरा खतम हो रही है, फिर भी समय समय पर कुछ व्यक्तियों ने राजनीति को प्रबल रूप से प्रभावित किया है, और अक्सर प्रभावशाली व्यक्तित्व के हटने पर दल की हालत बिना पतवार की नाव जसी हो जाती है, जैसी डॉ॰ राममोहन लोहिया के देहांत के बाद स. सो. पा. की हुई। यद्यपि कम्युनिस्ट दल का अनुशासन कठोर रहा है, फिर भी उसमें, पी. सी. जोशी, रणदिवे और डांगे के सत्ताच्युत होने से फूट पड़ी है। स्वतंत्र पार्टी तो शुरू से ही संगठित नहीं रही और शायद राजाजी के न रहने पर वह इस रूप में जीवित भी न रह सके। जनसंघ राष्ट्रीय रूप ग्रहण करने की काशिश कर रहा है, मगर इस फेर में, उसका वन राज्या में कम हो रहा है। कांग्रेस में भी उसके बड़े नेताओं के चले जाने के बाद टूट फूट शुरू हो गयी। १९६६ में उसमें सर्वोच्च स्तर पर खुले आम गहरी फूट पड़ गई। फिर भी जय दला की अपेक्षा अपनी स्थिति को संभालने में कांग्रेस ने ज्यादा क्षमता दिखाई है। साथ में सत्ता होने के कारण भी, कांग्रेस को आंतरिक फूट और झगडा के घबके संभालने में मदद मिली है और संभवतः इसी कारण केरल और बंगाल में माक्सवादी कम्युनिस्ट दल भी अपने संगठन की एकता को कायम रख सका है।<sup>१५</sup>

(१६) गर कांग्रेसी दला में भी काफी फूट रही है, मगर १९६७ के बाद उन्हें भी सत्ता ग्रहण का मौका मिला है और इससे उनकी शक्ति बढ़ी है। यद्यपि उनमें से अधिकांश बहुत दिना तक सत्ताछूट नहीं रह पाए, फिर भी उनका पुनः सत्ता प्राप्ति की आशा उतनी क्षीण नहीं है, जितनी सन १९६७ के पहले थी। कांग्रेस अब उतनी अजेय और अटल नहीं रही जितनी पहले समझी जाती थी। इससे दूसरे दलों में भी प्रचलित व्यवस्था के प्रति लगाव पैदा हुआ है और उनका रुख भी

१५ मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी के संगठन के नियम रहने का एक कारण नवदरीवाद और ज्योति बसु जैसे नेताओं का प्रभावशाली व्यक्तित्व भी है। इसी प्रकार अन्नादुरे के व्यक्तित्व के कारण मद्रास में द्र. मु. क. भा. इ. ड. है। राजनैतिक दलों के संगठन और नेता की भूमिका पर इस पुस्तक के अध्याय ८ में विस्तार से विचार किया गया है।

पहले जैसा उग्र और अव्यावहारिक नहीं रहा। एक तरफ कांग्रेस की शक्ति घटने से, भारतीय राजनीति में अब उन प्रश्नों और समस्याओं पर बहस होने लगी है, जिनको अब तक टालने की कोशिश की जाती थी। इससे एक बात राजनैतिक दलों के सामने और स्पष्ट हो गई कि अब केवल सत्ता ग्रहण करने से काम न चलेगा, कुछ करके दिखाना भी होगा। इसका यह अर्थ है कि अब यह परीक्षा हो जाएगी कि वर्तमान राज्यप्रणाली चल सकती है या नहीं।

### प्रणाली का विकास

अब हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद से वर्तमान प्रणाली में क्या परिवर्तन या विकास हुआ है। राजनैतिक सत्ता के लिए दलों में किस प्रकार गठजोड़ हुए हैं और इससे किस हद तक नई परंपराएँ स्थापित हुई हैं।

### शुरुआत का अध्याय

गांधीजी की मृत्यु के बाद सत्ता नेहरू और पटेल दो आदमियों के हाथों आई। यह गठजोड़ अजीब था। इन दोनों के विचार, स्वभाव, राजनैतिक सबब, सब बिल्कुल अलग अलग थे। नेहरू की बौद्धिकता, जनता पर गहरा प्रभाव और प्रगतिशीलता के मुकाबले पटेल की ठोस व्यावहारिकता और संगठन-कुशलता थी। यद्यपि दोनों एक-दूसरे की जरूरत और महत्त्व अनुभव करते थे और आपस में टक्कर बचाने की कोशिश करते थे, फिर भी दोनों का अंतर इतना स्पष्ट था और कांग्रेस के सामने नीति के ऐसे आवश्यक प्रश्न उपस्थित थे जिन पर निर्णय लेने में देर नहीं की जा सकती थी, कि इस द्वंद्व का निपटारा होता ही था। सन १९५० में कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव के प्रश्न पर नेहरू और पटेल का द्वंद्व खुल कर सामने आया, जब पटेल के उम्मेदवार पुराने खेव के कांग्रेसजन पुरुषोत्तमदास टंडन ने प्रगतिशील समर्थन देने वाले कृपालानी को हरा दिया। इसके थोड़े ही दिनों बाद पटेल की मृत्यु हो गई और केंद्रीय सरकार में नेहरू का एकछत्र अधिकार हो गया। कांग्रेस संगठन अर्थात् टंडनजी से नेहरूजी की टक्कर होने में देर न लगी। कृपालानी और उनके कांग्रेस डेमोक्रेटिक फ्रंट को कांग्रेस से हटना पड़ा। कांग्रेस की रीतिनीति से नेहरू असंतुष्ट थे। उनका आरोप था कि संगठन पक्ष केंद्र और राज्य सरकारों के काम में अनुचित हस्तक्षेप कर रहा है। न सिर्फ कांग्रेस सरकार के बीच में यह विरोध नेहरू को असह्य था, वे यह भी चाहते थे कि १९५२ के चुनाव में सही किस्म के आदमी चुने जाएं और विधान मंडल तथा सरकार में जाएं।

अतः नेहरू ने संगठन को हाथ में लेने का निश्चय किया। उन्होंने टंडन से यह कहा कि या तो मुझे कांग्रेस कार्यकारिणी का पुनर्गठन करने दो, वरना मेरा इस्तीफा लो। इस अल्टिमेटम के फलस्वरूप स्वयं टंडन जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद

से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष बन गए और अगले चार वर्ष तक वह सरकार और संगठन दोनों के प्रधान बने रहे।<sup>१६</sup> इस बीच उनका एकछत्र प्रभाव हो गया। पहले आम चुनाव में उनके नेतृत्व में कांग्रेस की पूर्ण विजय मिली। घरेलू और विदेशी नीति के मारे महत्वपूर्ण निश्चय उन्हीं के थे। इस प्रकार उन्होंने तैयार कर दिया कि देश किस रास्ते पर चलेगा। इसके बाद उन्होंने दूसरा को कांग्रेस का अध्यक्ष बनने दिया, परन्तु लगाम अभी भी उनके हाथ में थी।<sup>१७</sup>

कांग्रेस संगठन और कांग्रेस सरकार के बीच इस द्वंद्व को समझना जरूरी है। अधिकांश नव स्वतंत्र देशों में अधिकार प्राप्त करने के बाद राष्ट्रीय नेताओं में इस प्रकार का द्वंद्व उठता है। जहां इस द्वंद्व का जल्दी निपटारा कर लिया जाता है, वहां विकास का क्रम जल्दी शुरू हो जाता है। भारत में नेहरू के नेतृत्व में यह काम १९५० के बाद ही शुरू हो गया। अगले दस वर्षों तक नेहरू का प्रताप-सूय मध्याह्न पर रहा। उनके जीवन के दो उद्देश्य थे—लोकतंत्र और आर्थिक विकास, और उन्होंने सारी शक्ति से देश को इन लक्ष्यों की ओर ले जाने का यत्न किया। पिछले अध्याय में पचासवें राज आदि जिन सस्याओं का जिक्र किया गया है, उनका उद्देश्य यही था और वे इसी अवधि में विकसित की गईं।

### चुनाव द्वारा जनता में प्रवेश

इन सस्याओं की स्थापना का उद्देश्य जनता में प्रवेश करना था। महत्त्व केवल कांग्रेस महासमिति के प्रतिनिधियों का न था, जो हर साल नेहरू और उनके आदरियों का समर्थन कर दिया करते थे, वरन् देश के जनसाधारण का था। कांग्रेस संगठन पर नेहरू के कब्जा करने के थोड़े ही दिनों बाद देश का पहला आम चुनाव फरवरी सन १९५२ में हुआ जिसमें प्रत्येक बालिग स्त्रीपुरुष को वोट देने का अधिकार था। ज्यादातर राजनीतिक चेतना शहरों तक ही सीमित थी और वही कांग्रेस को विरोध का सामना करना पड़ा। कोई भी निश्चयपूर्वक यह नहीं कह सकता था कि गांधी की अशिक्षित जनता का क्या रुख होगा और वह चुनाव की इस नई विधि में कितनी दिलचस्पी लेगी। इतने बड़े चुनाव का प्रबंध करना और सांप्रदायिक तथा कम्युनिस्ट तत्त्वा को, जो उस समय काफी सक्रिय थे, उपद्रव करने से रोकना, कोई छोटा काम न था। कांग्रेस भी हाल के आंतरिक संघर्ष से

---

१६ दूसरे देशों में भी इस प्रकार शक्ति का सभा स्रोतों को एक ही हाथ में लेने के प्रयत्न हुए, जैसे धाना में एन.क्यू.एम. और इंग्लैंड में सुकाणों द्वारा। एक इतना ही था कि नेहरू इन दोनों की तरह तानाशाह नहीं बने।

१७ यद्यपि १९५४ में नेहरू ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ दिया, लेकिन जो भी अध्यक्ष चुने गए वे सब उन्हीं की मर्मा से चलते थे। दूसरी ओर राज्यों में उन्होंने संगठन और कांग्रेस मंत्रिमंडलों में प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा दिया।

हिल चुकी थी और कहा नहीं जा सकता था कि यह एकताबद्ध होकर चुनाव क  
मदान में उतर सकती या नहीं। १९२ पाटिया और १७०० उम्मेदवार मैदान में  
और करीब १७३० लाख मतदाता १८६००० मतदान कक्षा में जट हुए थे। इनक  
रन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था।

चुनाव व नतीजा ने उा तागा को ल्भिन कर लिया जा वाला त्नापितार की  
सफलता में सहाय करत थे। १९ वाप्रेस का ५२ और राज्या में नारी बहुमत प्राप्त  
हुआ। १९ लाखभा में ७८ ४८ मीटा में स ३६८ अर्थात् ७८४ प्रतिशत सीटें  
मिली। राज्या की विधान सभाया की ३२८३ सीटा में स उस २२४६ अर्थात्  
६८४ प्रतिशत सीटें मिला। अगने १५ वर्षा तक ३ आम चुनाव और अनेक छाटें  
या मध्यावधि चुनाव म भी समावण रात्रे को इसी प्रकार सञ्चता मिली।  
१९६७ के बाद भी, जब अनेक राज्या में दूसर दला की सरकार बना, वाप्रेस ही  
देश का प्रधान और सबसे गम्भीरता दल है, जिगका प्रभाव इस तरह में है (दखिए  
सारणी पाच १, २ और ३)

लेकिन यह कहना गलत होगा कि भारत म सत्ता पर कांग्रेस का एकाधिकार  
रहा है। सन १८६७ के पहले भी यह था तही नहीं थी। इसका एक कारण यह  
है कि कांग्रेस का विराप करने वाली पाटिया अनेक थीं और उनम स कुछ ने कांग्रेस  
को अपदस्थ भी किया। सारणीया स यह भी पता चलेगा कि तराप्रेसी पाटिया  
को मिले सब वोटो को जोड़ दिया जाए तो उनकी सख्या वाप्रेस का मिले वोटो स  
हमेशा अधिक रही। सीटा म भी हर राज्य म कांग्रेस का पूण बहुमत नहीं रहा।  
१९५२-५३ और १९६३-६४ म दो बार वोटो धोडे समय को छाड़ कर कांग्रेस  
ने जकेले सारे देश पर राज्य नहीं किया। १८५२ म उसे चार राज्या म पूण बहु  
मत नहीं मिल सका। ये थे - मद्रास, प प सू, उड़ीसा और तिरुवापुर-कोचीन।  
राजस्थान म उसे किसी तरह बहुमत मिल गया। मद्रास म उसकी स्थिति इसलिए  
बन गई कि आंध्र प्रदेश उसस अलग हो गया। आंध्र म कम्युनिस्टा ने १८५४ के  
नरबर म कांग्रेस सरकार को गिरा दिया और वहा राष्ट्रपति का शासन लागू करना  
पना। पे प सू (१८५४), तिरुवापुर-कोचीन (१८५४) और आंध्र (१८५४)  
म फिर से चुनाव कराने पडे क्योंकि वहा कांग्रेस सरकार अपना बहुमत वापस न  
रख सकी। पे प सू म कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल गया जार आंध्र म भी उसने  
कम्युनिस्टा की शक्ति तोड़ दी, किंतु तिरुवापुर-कोचीन मे वह ऐसा न कर सकी  
१८ द दायस आक इधिया, परवरी ६ १९५३।

१९ मद्रास, पे प सू और तिरुवापुर कोचीन म कांग्रेस को पूण बहुमत नहीं प्राप्त हो सका।  
लेकिन दूसरे दलों की हालत और भी खराब थी। इसलिए अंत में इन रात्रा में भी कांग्रेस की  
सरकार बन गई। केरल को छोड़ कर दोष सभी राज्या में तथा केन्द्र में १९६७ तक कांग्रेस सत्तारूढ  
रही। उड़ीसा में १९५७ से १९६१ तक कांग्रेस ने गणनत्र परिपद से मिल कर सरकार बनाई और  
करल में १९६० स १९६४ तक उपाय प्र मो था तथा मुस्लिम लीग से गठजोड़ रहा।



बाद वह अनेक पार्टियो में महज एक पार्टी रह गई। यह ठीक है कि १९६७ में कांग्रेस की प्रतिद्वंद्वी पार्टियां तगड़ी हो गईं पर इसके पहले भी कांग्रेस को बड़े मुकाबले का सामान करना पड़ रहा था और १९६७ के बाद भी यह भारतीय राज्यव्यवस्था में सबसे बड़ी ताकत है। दूसरे अब कांग्रेस को अपना सही 'केन्द्र' या 'मध्य' का स्थान मिल गया। यह दो अर्थों में। एक इस अर्थ में कि इसी केन्द्र से जय पार्टियां निकली हैं और दूसरे, इस अर्थ में कि यह दक्षिण और वामपथ के बीच या मध्य में है। भारत का यह अकेला मध्यवर्ती दल है।

तीसरे, कांग्रेस को महज सत्ताधारी या प्रधान दल के रूप में नहीं देखना चाहिए जैसा कि मारिस दुवर्जे आदि ने किया है। उसे समाजीकरण या समाज के परिवर्तन की एजेंसी और दूसरे दलों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने वाले के रूप में देखना चाहिए। इस दृष्टि से कांग्रेस के आंतरिक संघर्ष भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जितना बाहर से उसके विरोधी दलों का विकास। १९६७-६९ में भारत में एक खास तरह का घुबोकरण हुआ। कांग्रेस बनाम गैर-कांग्रेसी दल, सरकार बनाम सरकार विरोधी दल। इस घुबोकरण में विरोध की शक्ति बढ़ी। दूसरी ओर अब भी सारी जिम्मेदारी कांग्रेस नेताओं पर धरी जाती है और उसे सरकार समझा जाता है, यद्यपि अनेक राज्यों में वह सरकार नहीं है। इसका एक नतीजा यह हुआ है कि सरकार से कुछ ठोस काम करने की अपेक्षा की जाती है और केन्द्र से अधिक मांग की जाती है।

### १९६७ के पहले के विरोधी दल

कांग्रेस की आन्तरिक फूट से विरोधी दलों का विकास हुआ। हम देख चुके हैं कि कांग्रेस एक दल नहीं अपितु एक राष्ट्रीय मारचा थी। एक ओर इसके हाथ में सत्ता आ गई जिससे इसके हाथ में केन्द्रीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर बहुत साधन आ गए। दूसरी ओर इसके संगठन का विस्तार हुआ और उसके अंदर बहुत से विचर्चार्थी नेता तथा साधारण लोग भी आए। पद और अधिकार की आकांक्षा से कांग्रेस के अंदर गुटबाजी और सौदेबाजी की प्रवृत्ति बढ़ी। परिणामस्वरूप हर स्तर पर विविध प्रकार के संगठन कायम हो गए। इनमें दल के अंदर के गुट, जातबिरादरी के संगठन प्रांतीय, क्षेत्रीय और आदिमजातीय संगठन तथा विभिन्न वर्गों और पेशों के संघ, सभी थे। ये सभी कांग्रेस तंत्र के भीतर अधिकार चाहते थे। इनकी अपनी शिकायतें और मांगें थीं। ये गुट और फिरके समाज के मुख्य हिस्से और वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे, तथा कांग्रेस के अंदर के गुटों और कांग्रेस के बाहर विरोधी दलों के जरिये ये संगठित हुए।

कांग्रेस के अंदर की गुटबंदी राज्य और जिला स्तर पर भी कायम रही। राज्य और जिला कांग्रेस में सरकारी और संगठन गुट बन गए। संगठन गुट सरकार के



विरोधा दल के रूप में काम करता था और कई बार सरकारी गुट का अपदस्थ भी कर देता था। १९५६ में मद्रास राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष कामराज ने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जैसे प्रमुख नेता का मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और अपनी सरकार बनाई। इसी प्रकार यू पी में चंद्रभान गुप्त, उड़ीसा में बीजू पटनायक, मैसूर में निजलिंगप्पा तथा गुजरात में मन्निमडल विरोधी गुट ने पहले सगठन पर कब्जा किया, फिर विधानसभा के बहुमत को अपनी ओर करके इन्होंने सरकारी गुट का अपदस्थ कर दिया। हर राज्य में (केरल को छोड़ कर) कांग्रेस सरकार के होते हुए भी नेतृत्व में, जिसमें मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री पद भी शामिल थे, काफी हेरफेर होता रहा (सारणी पांच ४)। मतभेद तो नीति को लेकर होत थे, कभी यह पुरानी और नई पीढ़ी का द्वंद्व हो जाता था और कभी विचारा का, मगर यह सब राजनैतिक जोड़तोड़ और गुटबंदी का रूप ले लेता था। कांग्रेस हाईकमान बीच-बचाव करके कभी कभी अपने मन के व्यक्ति का नेता चुनवा देती थी, मगर अधिकतर यह उसीका समर्थन करता था, जिसका दल ज्यादा होता था, और महज नेता परिवर्तन की क्रिया का खूबमुरती से सपना करा देता था<sup>२२</sup>

### नेतृत्वपरिवर्तन

कांग्रेस के सगठन पक्ष के सरकारी पक्ष पर दबाव का एक उदाहरण १९६१ में मिला जब कांग्रेस अध्यक्ष सजीव रेड्डी ने यह प्रस्ताव किया कि जो लोग लगातार १० वर्षों से मंत्री रहे हैं, वे पदत्याग कर सगठन में काम करें। इसके बाद कामराज योजना के अंतर्गत कांग्रेस के कुछ उच्चपदस्थ नेताओं को अपने पद से हटाना पड़ा। इस योजना से नेहरू को उच्चपदस्थ लोगों को खिसकाने का बहुत अच्छा मौका मिला, साथ ही इसके द्वारा यह दिखाने की कोशिश भी की गयी कि सगठन और सरकार पक्ष का दर्जा बराबर का है।

मगर इस योजना का एक नतीजा यह भी हुआ कि जब नेहरू बीमार पड़े उस समय से १९६६ तक, जब कि इंदिरा गांधी ने एक बार फिर सगठन के सरगना पर प्रधानमंत्री के पद की उच्चता स्थापित की, कांग्रेस के सर्वोच्च नेताओं में पद और शक्ति के लिये बड़ी गद्दी लड़ाई चलती रही। इस बीच इस योजना ने सग

२२ उत्तरप्रदेश में सपूर्णानंद आर चंद्रभान गुप्त के द्वंद्व में नेहरू ने गुरु से दिलचस्पी दिखाई और कुछ समय तक सपूर्णानंद का समर्थन करते रहे परंतु अंत में उन्हें वास्तविकता स्वीकार करना पड़ी और चंद्रभान गुप्त को मुख्यमंत्री बनाने की राखी होना पड़ा। इसी तरह गुजरात के मुख्यमंत्री डा. जवाहर मेहता से गहरी सदानुभूति होने पर भी हाईकमान को गुजरात कांग्रेस सगठन दल द्वारा उनकी पदच्युति को मानना पड़ा। देखिए, माकस फ्रांटा 'द आगना इजेशनल डेवलपमेंट आफ इंडियन कांग्रेस पार्टी', पैसिफिक अपेक्स, ३५ फाल्गु, १९६२। ए. कोचा नेक, 'द कांग्रेस पार्टी आफ इंडिया द इन्फ्लुएंस आफ दन पार्टी डेमोक्रेसी' (प्रिंटिंग, १९६८)।

ठन और सरकार को बराबरी के दर्जे पर ला दिया और नेहरू के उत्तराधिकारी के चुनाव में संगठन के नेताओं की निर्णायक भूमिका रही (इस विषय पर अध्याय ८ में विस्तार किया जाएगा)। इस प्रकार एक ही दल के सत्तारूढ़ होते हुए भी उसमें नेताओं के परिवर्तन का काम चालू रहा।

## अन्य दल

कांग्रेस के अंदर के शक्तिसंघर्ष पर अन्य दलों का भी प्रभाव पड़ता था। जब कांग्रेस के बाहर के वामपक्ष की शक्ति बढ़ती थी तो कांग्रेस के अंदर भी वामपक्ष की ताकत बढ़ जाती थी। शुरू में जब समाजवादी दलों का प्रचार बढ़ा तब कांग्रेस में भी समाजवाद का जोर बढ़ा। बाद में जब स्वतंत्र पार्टी ने जमींदार वर्ग का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की और सहकारी खेती जैसी वामपंथी कांग्रेस नीतियों का विरोध किया तो कांग्रेस के अंदर भी दक्षिण पक्ष को दल मिला। इस प्रकार मध्यवर्ती दल कांग्रेस के अंदर के संतुलन पर बाहर के दलों का दबाव पड़ता रहा।<sup>१३</sup> दूसरे, कांग्रेस के असंतुष्ट लोग दूसरे दलों में शामिल होकर, उनके जरिये सत्तारूढ़ गुट से संघर्ष करते थे और अक्सर अपने विरोधियों के पतन के बाद कांग्रेस में लौट भी जाते थे।<sup>१४</sup> तीसरे, कभी कभी किसी विशेष या तात्कालिक प्रश्न का ले कर नए दल खड़े हो जाते थे, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात के अलग राज्य बनाने के प्रश्न को लेकर हुए। ये दल अस्थायी होते थे और प्रश्न के तह हो जाने के बाद इनको कांग्रेस में स्थान मिल जाता था।<sup>१५</sup> इसके अलावा ऐसे लोग जिनको कांग्रेस के अंदर कोई आशा नहीं रह गई थी, लगातार उससे अलग हो कर विरोधी दलों में मिलत गए। ऐसे लोगों में जे बी कृपालानी, राजगोपालाचारी और कृष्ण मेनन उल्लेखनीय हैं। प्रमुख व्यक्तियों के अलावा गुजरात में क्षत्रिय और राजस्थान में जाट और हरियाणा में अहीर जैसे वर्ग भी कांग्रेस से अलग हुए।

१९६२ और १९६६ के बीच कांग्रेस से व्यक्तियों और समूहों के अलग होने की प्रवृत्ति जादा रही। यह समय बड़ी कठिनाई का था। इसी अवधि में चीन और पाकिस्तान से युद्ध हुए, जिससे देश का बहुत धन-जन नष्ट हुआ, नेहरू और लाल-बहादुर शास्त्री का देहांत हुआ और उनके उत्तराधिकार के मामले पर कांग्रेस के सर्वाच्च स्तर पर बड़ी खिंचतान और जोड़ताड़ हुई। दो बार सूखा पड़ने के कारण

<sup>१३</sup> कोठारा, 'द कांग्रेस सिस्टम इन इंडिया'।

<sup>१४</sup> देखिए - बशीरुद्दीन अहमद, 'कांग्रेस डिफाई इन अमरोहा - ए वेम स्ट्रेंग इन वन पार्टी डामिनेंस', पार्टी मिल्म एंड एलेक्शन स्टडीज।

<sup>१५</sup> ऐसे दल राजनीति में नया खून ल आते हैं। जिस प्रश्न को लेकर वे खड़े होते हैं उनके तह होने के बाद वे पतन हो जाते हैं, लेकिन कुछ नए आदमी राजनीति में बने रहते हैं। अक्सर कांग्रेस इनको अपने अंदर खींच लेती है जमा बहाण के नेतृत्व में महाराष्ट्र कांग्रेस ने किया।

जनसाधारण को घोर वृष्ट, अभाव और महंगाई का सामना करना पड़ा, भारत को सहायता देने वाले देशों के दबाव के कारण रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा और कांग्रेस नेताओं का जिल्लत उठानी पड़ी। इस स्थिति में कांग्रेस नेताओं की स्थिति कमजोर हुई और उसके लिए कांग्रेस सगठन में एकता और अनुशासन बनाए रखना कठिन हो गया, फलस्वरूप कांग्रेस त्यागने वालों की संख्या बढ़ी।

१९६७

कांग्रेस दल की इस फूट के सदृश में फरवरी १९६७ का आम चुनाव हुआ। चुनाव के बाद भी कांग्रेस की फूट जारी रही। जबकि चुनाव में ५ राज्यों में कांग्रेस की हार हुई, चुनाव के बाद दलबदल की क्रिया शुरू हुई, जिसके कारण तीन राज्यों में कांग्रेस सरकार का पतन हुआ।<sup>२५</sup> इस दलबदल में दो बातों का मुख्य हाथ रहा। चुनाव के पहले टिकट का बंटवारा और चुनाव के बाद मन्त्रिमंडल का गठन। ये कोई नए कारण न थे। नई बात सिर्फ यह थी कि १९६७ में और बाद में जितनी आसानी से लोग कांग्रेस छोड़ देते थे, उतनी पहले कभी नहीं देखी गई थी। कांग्रेस में उनको बाध कर रखने की शक्ति बहुत कम हो गई थी। अब तक चुनाव का टिकट या मन्त्रिमंडल में स्थान न मिलने पर भी असंतुष्ट गुट कांग्रेस के अंदर ही बने रहते थे, अब वे कांग्रेस से अलग होने लगे।<sup>२६</sup> अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ कि ये लागू स्थायी तौर पर कांग्रेस में अलग हुए थे या स्थायी तौर पर। दोनों ही प्रवृत्तियाँ दीख पड़ती हैं।<sup>२७</sup>

२६ चुनाव में कांग्रेस की हार मद्रास (यहां अनेक एक दल द्रमु क की जीत हुई), बंगाल, बिहार, पंजाब और उड़ीसा में हुई। (इन्हीं विरोधी दलों के साथ मोरचा की जात हुई। इन मोरचों में कम्युनिस्ट मार्क्सवादियों से लेकर जनसम तक थे)। चुनाव के बाद हरियाणा, उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश में दलबदल के कारण कांग्रेस सरकार का पतन हुआ। हरियाणा और उत्तरप्रदेश में संयुक्त दल की सरकार भी न चल सकी और मध्यावधि चुनाव हुए। हरियाणा में कांग्रेस सरकार कायम है, किंतु उत्तरप्रदेश में पुनः कांग्रेस में फूट हुई और पहले नई कांग्रेस और भारतीय क्रांतिदल और बाद में पुरानी कांग्रेस, भा. का. दल, जनसम, सतोषा की संयुक्त सरकार बनी।

२७ कांग्रेस दल में चुनाव टिकट बंटने के समय जो खींचतान होता है, वह कभी कभी चुनाव से भी ज्यादा महत्व की होता है। इसमें चुनाव से भी ज्यादा जनसाधारण में प्रसार का मौका मिलता है। देखिए रा. राम, 'सेलैक्शन आफ कॉन्ग्रेस कैंडिडेट्स - द्रुनामिक एंड पोलिटिकली, दिसम्बर, ३१, १९६६, जन ७ और १८, पर ११ और १८, १९६७। १९६७ में उम्मेदवारों के चुनाव के ऊपर राय और मारिस् चोन्स का अध्ययन अभा. अप्रकाशित है।

२८ गैर कांग्रेसी संयुक्त सरकारों के गिरने के बाद अनेक भूतपूर्व कांग्रेसी कांग्रेस में या कांग्रेस से संबंधित दलों में लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार और मध्यप्रदेश में ऐसा ही हुआ। मध्य-प्रदेश में तो कांग्रेस टाड़ने वालों का पूरा गुट कांग्रेस में लौट आया और कांग्रेस की सरकार [अगले पृष्ठ पर]

फूट की प्रवृत्ति कांग्रेस में ही नहीं आय दता म नी ह। कुछ राज्या म कांग्रेस के असंतुष्ट गुट ने प्रतिद्वंदी कांग्रेस बना लिया है। २९ इसी प्रकार कम्युनिस्ट पार्टी भी दो और वही तीन तीन है। समाजवादी पार्टी भी टूट कर समोपा और प्रसोपा म बंट गई है और समापा म भी कई गुट हो गए है जो एक दूसरे स बग डते रहते हैं। जनसंघ म भी उग्र और नरम दा घड हा गए हैं और स्वतंत्र पार्टी म तो लगातार आंतरिक झगडे मच है और जनक लोग दल नी छाड गए हैं। पिछडे वर्गा हरिजना और जादवासिया म भी अनेक घडे हैं। इसके अलावा १८-६७ के बाद गैर-कांग्रेसी दला म गठजाड होत रहे हैं। अनेक बार ये गठजोड बिल कुल विरोधी और विपरीत दला म भी हुए है। य गठजाड नानमती के कुनवे जंस हैं। फलस्वरूप ये गैर-कांग्रेसी सयुक्त सरकारें ज्यादा दिन न चल सची और एक क बाद एक गिरती चली गई। ३०

स्वतंत्रता क बाद शक्ति ग्रहण करने क लिए कांग्रेस सभी तरह के लोगो को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती थी। सन १९६७ स १८६८ क बीच गैर-कांग्रेसी दला की भी यही नीति थी। हिंदू समाज की भाति कांग्रेस भी भिन्न और विराधी विचार और रीतिरिवाज वाले समूहा को एक साथ लाने की कोशिश करती थी और विचारा की एकत्पना क वजाय विचार-वर्धन को सहन करती थी। कांग्रेस शुरू स समूचे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करती आई है और भारतीय राष्ट्र क अधिकांश तत्व उसम पाए भी जात थे। विराधी दला ने देखा कि सयुक्त मोचा बना कर व कांग्रेस का हरा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस को कभी भी देश के ४५ प्र स अधिक वाट नहीं मिने। इस नीति के मुख्य प्रतिपादक

[ पिछले पृष्ठ स ]

बनाने में उसने सहायता दी। कांग्रेस छोने वाल जो लोग मुख्यमन्त्रा बने उनमें से अनेक का केन्द्र सरकार और कांग्रेस नेताओं से बड़ा अच्छा संबंध रहा। दूसरी ओर कांग्रेस दार्शनिकान विद्रोहियों को वापस लेने की बहुत इच्छा न था, क्योंकि इससे नया गठजाड उल्टने का डर था। २९ १९६४ म केरल कांग्रेस की स्थापना हुई और १९६६ में बंगाल म बागला कांग्रेस बना। १९६७ के चुनाव से पूर्व उत्तर के कई राज्यों में नन कांग्रेस बना। बिहार और उत्तरप्रदेश में असंतुष्ट कांग्रेसियों ने भारतीय भाति दल बनाया और बिहार में असंतुष्ट कांग्रेस जनों के एक दल ने विनोदानंद झा के नेतृत्व में जनतांत्रिक कांग्रेस बनाइ। ३० दिसंबर १९६७ से फरवरी १९६८ के बीच हरियाणा, पश्चिम बंगाल पंजाब, उत्तरप्रदेश और बिहार म पांच राज्यों में सयुक्त सरकारें गिरा। बिहार में दो बार ऐसा हुआ। सयुक्त सरकार के टूटने पर बिहार और बंगाल म कांग्रेस के समर्थन से सयुक्त मोरचे क अध्यक्ष दल ने सरकार बनाइ किंतु वह चल न सती। पश्चिम बंगाल में तो कांग्रेस खुद मिली जुली सरकार म शामिल हुए। मगर ठिक न सगा। न पप्रदेश म मार्च १९६६ में सयुक्त दल की सरकार से कांग्रेस विद्रोहियों का गुप्त निम्न कर फिर कांग्रेस म आ गया और सयुक्त सरकार गिर गई।

ये डा राममनोहर लोहिया। लोहिया जन्मजात विद्रोही थे और उनका व्यक्तित्व चमत्कारी था। उन्होंने शीघ्र ही समझ लिया कि थाये विद्रोह से कुछ होना जाना नहीं, इसलिए उन्होंने का सत्ता पर एकाधिकार खतम करने के लिए विरोधी दला को एक साथ लाने की कोशिश की। कांग्रेस के विरोधी किसी भी तत्त्व से वह हाथ मिलाने को तयार रहते थे। कांग्रेस को उखाड़ने के तात्कालिक लक्ष्य में उन्हें सफलता मिली, किन्तु इसका कोई स्थायी नतीजा नहीं निकला। यह बात उन्हें १९६७ में अपनी मृत्यु के पहले खुद स्वीकार की थी।

### दला में फूट और पुनर्गठन

१९६७ और १९६९ के बीच राजनीतिक दला ने अपने अनुभव से नए सबक सीखे और जो जाव उसको ले लेने की नीति में परिवर्तन किया। इस अवधि में दलबदल और अवसरवादिता का जो जोर रहा, उससे लोग विरक्त हुए और नए गठन करने के समय और नए लागा को दल में लेंते समय कुछ अधिक सावधानी बरतने लगे। १९६७ के बाद से कांग्रेस की नीति यह रही है कि पार्टी से विद्रोहियों का जाने दो और वह एक स्पष्ट नीति और विचारधारा ग्रहण करने तथा दल में अनुशासन रखने की बात करने लगी है।<sup>३१</sup> इस नीति से कांग्रेस को १९६८ के हरियाणा के मध्यावधि चुनाव में अच्छी सफलता मिली। और १९६९ में उत्तर प्रदेश के मध्यावधि चुनाव में भी लाभ हुआ।

दूसरी ओर यह भी स्पष्ट हो गया कि गैर-कांग्रेसी दलों के मोर्चों में १९६७ के बाद केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट मोर्चा, मद्रास में द्र मु क का मोर्चा और उड़ीसा में स्वतंत्र जन कांग्रेस मोर्चा ही टिकाऊ रहा क्योंकि ये दल अपने क्षेत्र में ज्यादा संगठित और एकरूप थे और इनको काफी स्थानीय समर्थन भी मिला।<sup>३२</sup>

३१ कांग्रेस ने अपना आंतरिक स्थिति को दृढ़ करने के लिए क्या प्रयत्न किए इसके लिए देख मारिस् जोन्स 'द इंडियन कांग्रेस पार्टी-ए लिसेना इन डेमिनेंस माडर्न एशियन स्टेट्स' १ नं २, १९६७।

३२ केरल में नवदुरावाद और बंगाल में ज्योति बसु के नेतृत्व में मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी अपने प्रदेश में बड़ा ताकत रखनी है और अपनी अखिल भारतीय पार्टी या अ य राज्यों का मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से भिन्न तरीके से काम करता है। यद्यपि इन राज्यों में वे मिलानुसार सरकार में हैं लेकिन प्रधानता उन्हीं की है। उदाहरण के लिए स्वतंत्र पार्टी पुरानी गणतंत्र परिषद का ही दूसरा रूप है। असतुष्ट कांग्रेसजनों के दल कांग्रेस से मिल कर उसने टिकाऊ सरकार बना ली है। बास्त्रव में यह पुराने कांग्रेस-गणतंत्र परिषद के गठबंधन का ही दूसरा रूप है जिसने १९५७ से १९६१ तक उड़ीसा में राज्य किया और जिसे विजयानंद पटनायक के नेतृत्व में कांग्रेस के नए गुट ने अपदस्थ किया। पुराना गुट कांग्रेस से निकल कर जन कांग्रेस बन गया और गणतंत्र परिषद राज्य की स्वतंत्र पार्टी बन गई। सबसे ज्यादा मार्क्सवादी मद्रास का द्र मु क (टा एम के) है। यह एक प्रान्तीय आंदोलन का राजनैतिक रूप है। इसे दूसरे दल के समर्थन का जरूरत नहीं। अतः है कि पंजाब में अवाला दल भी ऐसा ही स्थिति प्राप्त कर ले।

इनके मुकाबले खिचड़ी दलों और भूतपूर्व कांग्रेसियों की संयुक्त सरकारें टिकाऊ नहीं मिळी हुई। १९६९ में चार राज्यों में मध्यावधि चुनाव हुए (जिसे छाटा थाम चुनाव भी कहा गया) इसमें क्षेत्रीय पार्टियाँ के मजबूत मोर्चे बंगाल और पंजाब में विजयी हुए और खिचड़ी दलों का मोर्चा बिहार और उत्तरप्रदेश में हार गया (सारणी पांच - १)

पश्चिम बंगाल में कांग्रेस-विरोधी संयुक्त मोर्चे (युनाइटेड फ्रंट) का उल्लेखनीय सफलता मिली। चुनाव के पहले ही इस मोर्चे के सदस्य दलों ने आपस में बातचीत करके चुनाव समन्वित कर लिया था। इससे बोटरा को एक स्पष्ट विकल्प मिला गया। पश्चिम बंगाल में तथा अनेक अन्य राज्यों में भी, कांग्रेस को कभी बोट का पूरा बहुमत नहीं मिल सका था। उसका विरोधी बोट कई दलों में बंट जाय करते थे। इस बार विरोधी दलों ने तगड़ा मोर्चा बना कर कांग्रेस की कमजोरी का लाभ उठाया। ध्यान रहे कि १९६९ के मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त बोटों की संख्या में कमी नहीं हुई फिर भी उसको भीटें बहुत कम मिलीं। इस प्रकार पश्चिम बंगाल का संयुक्त मोर्चा ७५ राज्यों के लिए नतीजामूलक बन गया, यद्यपि इसमें संदेह है कि और जगह ऐसा मारचा बन सकना है या नहीं।<sup>३३</sup> पंजाब में अकाली दल ने अपने आपसी छंडों को मिला कर अपना तगड़ा मोर्चा बनाया। इसमें उसके पुराने प्रतिद्वंद्वी जनसंघ ने भी उसका साथ दिया। केरल में १८६७ में केम्पु-निन्टा ने भी इसी प्रकार अपने आपसी छंडों को एक करके अपना मोर्चा बनाया था।

इस समय १९६७ की स्थिति बदल चुकी है। एक तो अधिकांश राज्यों में खिचड़ी या परस्पर विरोधी दलों के मोर्चे टूट चुके हैं। मद्रास में एक ही दल की सरकार है। उड़ीसा में स्वतंत्र और जन कांग्रेस का गठजोड़ भी गढ़बढ़ा रहा है। पंजाब में अकाली जनसंघ जोड़ टूट चुका है और अकाली दल में भी फूट पड़ गई है। सबसे अधिक अस्थिरता मध्यप्रदेश, बिहार और उत्तरप्रदेश जैसे कांग्रेस प्रभुता वाले राज्यों में ही देख पड़ती है। समग्र है कि यहाँ कांग्रेस और भागद जसे क्षेत्रीय और जनसंघ जैसे राष्ट्रीय दलों की राज्य शाखाओं में घुसीकरण हो जाए और फिर से चुनाव होने पर स्थिति अधिक साफ हो जता पश्चिम बंगाल, केरल

३३ १९६९ में बंगाल में दो विरोधोत्पन्न लक्षित हुए। एक तो संयुक्त मोर्चे के विभिन्न दलों के अपने-अपने अलग-अलग प्रभाव क्षेत्र बना लिये थे जिससे दलों के बीच साटा-के बटवार में भागीदारी हुई। दूसरे, बंगाल में संयुक्त मोर्चे का विचार बहुत दिनों से चल आ रहा था और जनता में १९६० और १९६९ के बीच इसका जोर बढ़ा। इस कारण विभिन्न दलों को भी जनता की इच्छा का आदर करना पड़ा। केरल में भी यही प्रवृत्ति १९६५ और १९६७ के बीच काम पर रही थी। दूसरी ओर जहाँ विभिन्न दलों के प्रभाव क्षेत्र बड़े नहीं हैं और संयुक्त मोर्चे का विचार जनता में जोर नहीं पकड़ पाया है वहाँ संयुक्त मोर्चे की उतनी सफलता नहीं मिल सकती। बंगाल और केरल में भी संयुक्त मोर्चा अंत में टूट गया।

हरियाणा और पंजाब में १९६६ के चुनाव में हुआ।<sup>३४</sup> भारतीय जनता ने ज्यादा राजनैतिक समर्थनदात्री दिखाई है और १९६६ के मध्य चुनाव में कांग्रेस तथा उत्तर-प्रदेश और बिहार में जनसंघ और संसोधन जैसे गैर कांग्रेस दलों का स्थिर सरकार बनाने का दंड दिया है।

चुनाव परिणामों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि गैर कांग्रेसी दलों के उम्मेदवार बजाय एक दूसरे के कांग्रेस के बाटों को ज्यादा काटते हैं। यद्यपि जहाँ अधिक उम्मेदवार खड़े होते हैं वहाँ कांग्रेस को फायदा होता है और उसका उम्मेदवार जीत जाता है लेकिन उसका बाटों की संख्या घिर जाती है। दूसरी ओर जहाँ कांग्रेस का दूसरे दल या संयुक्त उम्मेदवार से सीधा मुकाबला होता है, वहाँ उसके बाटों तो बढ़ जाते हैं मगर जरूरी नहीं कि उसका उम्मेदवार जीत जाए। इस प्रकार केरल में १९६६ में और बंगाल में १९६६ में जहाँ कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिलीं, वहाँ उसके बाटों कम नहीं हुए और केरल में तो बढ़ भी गए। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने अपने बाटों ३५ से ४० प्रतिशत तक कायम रखे हैं। केरल और पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों को और मद्रास में द्रमुक छोड़कर शेष गैर कांग्रेसी दलों का बाटों इतना स्थिर नहीं रहा है। इसी बात पर निम्न हागा कि अगले चुनावों में राज्यों में किस दल या दलों के जुटों की जीत होती है और टिकाऊ सरकार बनती है या नहीं।

### भविष्य का रस

लेकिन यह भी स्पष्ट है कि कांग्रेस अपने स्थिर ४० प्रतिशत बाटों के बल पर हमेशा सत्ता कायम नहीं रख सकती। केन्द्र में भी इसके बल पर उसकी सत्ता सुरक्षित नहीं है। जिस प्रकार विरोधी दलों ने उसकी इस दुबलता का लाभ उठाकर राज्यों में उसे हराया है उसी प्रकार केन्द्र में भी वे इसे हराने का यत्न करेंगे, और विधानसभाओं के साथ-साथ संसद के चुनावों में भी साझे उम्मेदवार खड़े करेंगे। इसमें उन्हें इस बात से सहायता मिलेगी कि विधानसभा और संसद के चुनाव साथ-साथ होते हैं। जाये राज्यों में हारने पर भी केन्द्र में कांग्रेस की जीत हुई इसका कारण यह था कि उसकी विरोधी अधिकांश पार्टियाँ उसका मुकाबला केवल

३४ देखिए मेरा 'इंडियन पोलिटिकल टाईमिंग', इका ० एंड पोलि ० वाक्य विशेष अंक, अगस्त १९६७। इसमें मैंने राजनैतिक अस्थिरता को दूर करने के लिए मयावि चुनाव का समर्थन किया है।

३ यह विश्लेषण ऐन हावर मिशिंगन में हुए टाटा कन्फ्रेंस सेमिनार (अप्रैल, १९६९) में हुआ था। इसके लिए आक्टो सेंटर फार स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, दिल्ली ने प्रयत्न किए थे। मारिस जोस और बा दासगुप्त ने भी यहाँ निष्कर्ष निष्काशित था। 'इंडियन पोलि एरियाज इटिराम रिपोर्ट्स ऑन एन इकोनॉमिकल एलेक्टरल इन्वेस्टिगेशन' एशियन सर्वे ९ नं ६, जून १९६९।

होगा, जितना देश में परिवर्तन लाने की उपेक्षा करना। यह काम आसान नहीं है और यदि इसमें समझदारी से काम न लिया गया और देश के इतिहास के सबक को भुला दिया गया, तो या तो देश में अस्थिरता पैदा हो जाएगी और प्रगति रुक जाएगी या ऐसा वैचारिक संघर्ष होगा, जिसमें अराजकता मच जाएगी।

इसलिए राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में देश तभी अच्छी तरह काम कर सकता है, जब देश की राजनैतिक विभिन्नता के ऊपर केन्द्र में एक सुदृढ़ शक्ति हो। फिन्हाल अगले दशक तक कांग्रेस के अलावा और कोई ऐसी केंद्रीय शक्ति नहीं नजर आती। कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती है। एक तो ऐसी नीति ग्रहण करना, जिससे उसे शहर और दहात के अब तक पिछड़े हुए, और अब राजनैतिक रूप से सचेतन तथा उत्थित के इच्छुक वर्गों का समर्थन मिल सके। दूसरा काम कांग्रेस सगठन को ऐसा रूप देना है जिससे उसकी शाखाएं निर्वाचन क्षेत्रों में जनता के बीच में पहुंच जाए और चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस को सिर्फ बड़े या प्रभावशाली लोगों के भरोसे न रहना पड़े।<sup>३०</sup> पहला काम केंद्रीय सरकार के नेताओं का है और दूसरा काम सगठन के नेताओं का। तात्पर्य यह है कि कांग्रेस को नीति और सगठन दोनों मोरचों पर काम करना है और इसके लिए केन्द्र में एकता और एक राय जरूरी है।

यदि अगले एक दो साल के भीतर सरकार और सगठन दोनों क्षेत्रों में ठोस काम न हुआ तो कांग्रेस के लिए आसार अच्छे नहीं। पहले तो जमा ऊपर कहा, यदि गैर कांग्रेसी दला ने लोकसभा के चुनाव में भी मांचा बनाया तो कांग्रेस की हालत खस्ता हो जाएगी। दूसरी संभावना यह है कि दक्षिण और वाम पक्ष के दला की स्थिति राज्यों की विधानसभा में दब हा जाएगी। वाम पक्ष में पश्चिम बंगाल और केरल में कम्युनिस्टों के मोरचे और मद्रास में द्रमुक तथा दक्षिण पक्ष में उत्तर में जनसंघ, उड़ीसा में स्वतंत्र और पंजाब में अकाली। सन १९६७ में मजबूत केन्द्र का राज्या में विपरीत विचारों के दला की खिचड़ी में मुकाबला करना था। इस से ज्यादा खतरनाक स्थिति होगी जब केन्द्र कमजोर व अस्थिर हो और राज्या में दक्षिण या वाम पक्षी मजबूत मोरचे या गठजोड़ हो। तीसरे, यदि ऐसा मुकाबला हो और राजनीति नीतिसंबंधी प्रश्नों पर केन्द्रित होने लगे तो संभावना यह भी है कि कांग्रेस के भीतर भी वाम और दक्षिण पक्ष का घर्षोर्षण हा जाए और फूट हो जाए। १९६६ में वाम के राष्ट्रीयकरण के ऊपर और डा० जाकिर हुसैन के दहात के बाद राष्ट्रपति के चुनाव को ले कर कांग्रेस के अंदर जो मतभेद पैदा हुआ, उस से अब भी कांग्रेस के दो टुकड़े हा गए। इस मतभेद में इंदिरा गांधी

<sup>३०</sup> मद्रास में द्रमुक के चुनाव आंदोलन में हमारा परिचय मिला। द्रमुक का यह नारा था कि वोट के पास वोट दलने वाले हैं, और इनारे पास वोट हैं। इस विषय पर दोस्ति रामाश्रय राय और चन्द्रावत, 'क्रेकम् आफ एन्क्वायरिंग बैन' (सेंटर फॉर स्टडी डेव लो)।



असम की गीटा पर बर रही थी, मसूर की गीटा पर नहीं। बाटा व विद्वान् से पना घना बि बरीब ३३ प्र स माराताआ ने मगर में एक दल का बाट दिया और राज्य विधानमभा में दूसरे दल को। लेकिन द्रमुक ने मद्रास में ताब समा की ये सब सीटें जीत ली, जिन्हें लिए उगने उम्मावार गये किए ये और स्वतंत्र पार्टी को भी मोक्ष ममा व चुनाव में सफलता मिली। इससे पना घना है कि मगर व चुनाव में भी बांग्रग उगी ही मगदार है जिनकी विधानसभा के चुनाव में।

राष्ट्रीय क्षेत्र में कांग्रेस व पक्ष में कई बने हैं। राज्य के स्तर पर दला की जाम्बिनि है यह राष्ट्रीय स्तर पर गहा है। एक ताभिन्न भिन्न राज्या म भिन्न भिन्न स्त हैं। दूसरे, राज्या म ओष छाटे छाटे दल और निम्न उम्मावार हैं, जिन ता राष्ट्रीय स्तर पर काम करने व इच्छा है। उन म मगर का चुनाव लड़ने की क्षमता है। दूसरे कई राज्या म क्षेत्रीय दला न अनिज भारतीय दला को चुनमान पाचाया है। उग हरण व लिए उग प्रदेश में घणमिह के भा नी द ने जनमष का दूर नवर से हटा दिया। ग मा पा ने नी बिहार और उत्तर प्रन्ग म अपने बल्ल-म म्पान रखी लिए। एक ओर कम्युनिस्ट दला ने बगान और बरन म अपनी म्पिनि गुड बर ली ता मूरी आर उत्तर प्रन्ग पञ्जा आर अज राचा म उनकी ताकत घट भी गद। दला व इस क्षेत्रीयकरण के कारण जमा कुछ निना तक कांग्रेस की प्रधानता बनी रहगी। तीसरे, गैर कांग्रेसी दला म आपस म ही मूरी प्रतिद्विधा है, इससे भी कांग्रेस को फायदा होता है। चौथे, अनेक क्षेत्रीय दल केन्द्र में कांग्रेस की प्रधानता स्वीकार करने को तैयार हैं, बाते कांग्रेस नी उनसे क्षेत्री म उनकी प्रधानता स्वीकार कर और राज्या में उनके साथ सहयोग करे। यह स्वाभाविक है, बचा कि भारत की मष प्रणानी म केन्द्र के हाथ में बहुत शक्ति और साधन हैं।

फिर भी यह स्पष्टतर होता जा रहा है कि महुज ४० प्रतिशत वोट के बल पर कांग्रेस की स्थिति सुरक्षित नहीं रह सकेगी। इस म केवल सख्या का ही प्रान नहीं है, नीति और विचारधारा का भी है। कांग्रेस धीरे धीरे शानि या पम्बिन की पार्टी से यथास्थितिवादी पार्टी बन गई है। धीमे धीमे इसम गहर और दहात के अधिपारप्राप्त वग का जोर बढ़ता जा रहा रहा और वह प्रगतिशीलता कम होती जा रही है जा आजादी के पहले इसमें थी। जब तक इसम कुछ पुरानी जान बापस नहीं आती, इसकी पुरानी स्थिति बनी रहनी कठिन है। कांग्रेस के पक्ष में यह बात है कि इसकी परंपरा विभिन्न वर्गों को एक साथ ले आने की और विभिन्न मता मे समन्वय की रही है और अभी भी इसका स्थान लेनेवाली दूसरी पार्टी नजर नहीं आती। मगर किसी नई क्रांतिकारी नीति या विचारधारा को अपनाने के साथ साथ कांग्रेस को देश के विभिन्न क्षेत्रीय दला को अपने साथ ले आने का भी उपाय करना पड़ेगा। देश की एकता की उपेक्षा करना उतना ही सतरनाक

होगा, जितना दश म परिवर्तन लाने की उपक्षा करना । यह काम जासान नहीं है और यदि इसमें समझदारी से काम न लिया गया और देश के इतिहास के सबक को भुला दिया गया, तो या तो देश में अस्थिरता पैदा हो जाएगी और प्रगति रुक जाएगी या ऐसा वैचारिक सघप होगा, जिससे अराजकता मच जाएगी ।

इसलिए राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में देश तभी अच्छी तरह काम कर सकता है, जब देश की राजनैतिक विभिन्नता के ऊपर केन्द्र में एक सुदृढ़ शक्ति हो । फिनलैंड अगले दशक तक कांग्रेस के अलावा और कोई ऐसी केन्द्रीय शक्ति नहीं नजर आती । कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती है । एक तो ऐसी नीति ग्रहण करना, जिससे उसे शहर और दहात के अब तक पिछड़े हुए, और अब राजनैतिक रूप से सचेतन तथा उन्नति के इच्छुक वर्गों का समर्थन मिल सके । दूसरा काम कांग्रेस सगठन को ऐसा रूप देना है, जिससे उसकी शाखाएँ निर्वाचन क्षेत्रों में जनता के बीच में पहुँच जाएँ और चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस को सिर्फ बड़े या प्रभावशाली लोगों के भरोसे न रहना पड़े । <sup>36</sup> पहला काम केन्द्रीय सरकार के नेताओं का है और दूसरा काम सगठन के नेताओं का । तात्पर्य यह है कि कांग्रेस को नीति और सगठन दोनों मोरचा पर काम करना है और इसके लिए केन्द्र में एकता और एक राय जरूरी है ।

यदि अगले एक दो साल के भीतर सरकार और सगठन दोनों क्षेत्रों में ठोस काम न हुआ तो कांग्रेस के लिए आसार अच्छे नहीं । पहले तो जसा ऊपर कहा, यदि गैर कांग्रेसी दला ने लोकसभा के चुनाव में भी भाग्य बनाया तो कांग्रेस की हालत खस्ता हो जाएगी । दूसरी संभावना यह है कि दक्षिण और वाम पक्ष के दला की स्थिति राज्या की विधानसभा में दब हो जाएगी । वाम पक्ष में पश्चिम बंगाल और केरल में कम्युनिस्टों के मोरच और मद्रास में द्रमुक तथा दक्षिण पक्ष में । उत्तर में जनसंघ, उड़ीसा में स्वतंत्र और पंजाब में अकाली । सन १९६७ में मजबूत केन्द्र का राज्या में विपरीत विचारों के दलों की गिचड़ी से मुकाबला करना था । इस से ज्यादा खतरनाक स्थिति होगी जब केन्द्र कमजोर व अस्थिर हो और राज्या में दक्षिण या वाम पक्षी मजबूत मोरचे या गठजोड़ हो । तीसरे, यदि ऐसा मुकाबला हो और राजनीति नीतिसंबंधी प्रश्नों पर केन्द्रित होने लगे तो संभावना यह भी है कि कांग्रेस के भीतर भी वाम और दक्षिण पक्ष का घर्षण हो जाए और फूट हो जाए । १९६६ में वका के राष्ट्रीयकरण के ऊपर और डा० जाकिर हुसैन व दहात के बाद राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कांग्रेस के अंदर जो मतभेद पैदा हुआ उस से जत में कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए । इस मतभेद में इंदिरा गांधी

<sup>३६</sup> मद्रास में द्रमुक व चुनाव आंदोलन में इसका परिणाम मिला । द्रमुक का यह नारा था कि कांग्रेस के पास वोट बढ़ाने वाले हैं और हमारे पास वोट हैं । इस विषय पर दोषिण रामा राय और चण्दास, 'कैम्ब्रिज ऑफ एन्कगोरल चेंज' (संग्रह फार स्टूडेंट्स डेव सो) ।

ये नेतृत्व म 'यंग तुन' हैं, जो चाहते हैं कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ें, और दूसरा पक्ष उन लोगों का है, जो कांग्रेस संगठन की शक्ति को कायम रखना चाहते हैं। ये लोग इस बात की उपेक्षा कर रहे हैं कि अक्सर उपेक्षित और अधिनास्त्वित वर्गों में राजनीति जाग्रत है। चुनाव के रूप को देखने में पता चलता है कि इस उपेक्षित वर्ग का — जिस में नव गिम्न और छोटे किसान तथा खेत मजदूरों का बाहुल्य है — समय-समय पर कांग्रेस के यहाँ दूसरे दल को मिल रहा है। ३० कांग्रेस के सामने यह प्रश्न है कि वह कम अपना मध्य में कुछ काम पक्ष की ओर रुख कायम करें।

यदि कांग्रेस उन वर्गों में नहीं प्रवेश कर पायी, जो अक्सर उसमें अलग रहे हैं, तो क्या होगा? ऐसा लगता है कि भविष्य में राज्या ही नहीं केन्द्र में भी मिनीजुली सरकार बनेगी। हो सकता है कि कुछ राज्या में एक ही दल की, या एक दल के प्रभुत्व में संयुक्त सरकारें रहें और केन्द्र में मिनीजुली सरकार बने। इसमें भी संदेह नहीं कि केन्द्र की मिनीजुली सरकार में अभी कुछ जिना तथा प्रधान भागीदार कांग्रेस ही रहेगी क्योंकि अब दल अभी इतना सावधानीपूर्वक नहीं ग्रहण कर पाए हैं कि मजदूरों में अधिक सदस्य भेज सकें। यह भी संभव है कि राज्या में ये अधिक सदस्य भेज सकें। यह भी संभव है कि राज्या में जो साक्षी सरकार बनें उनमें प्रधान भागीदार कांग्रेस से भिन्न कोई दल हो, जैसे बंगाल और केरल में माकमल कम्युनिस्ट, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में जनसंघ और पंजाब उड़ीसा, मद्रास में वहाँ के प्रांतीय दल। या दल में सबसे बड़ा दल कांग्रेस ही रहने की संभावना है, भले ही वह सभी स्तरों पर सरकार न बना सके। यदि वह पुनः अपने संगठन में एकता स्थापित कर सकी और अपनी गति प्राप्त कर सकी तो उस की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होगी।

### सविद सरकारों का दौर

जल्द ही नहीं कि सविद या संयुक्त सरकारें एक दल की सरकारों से कम कारगर और सोद्देश्य हैं। केरल की साक्षी सरकार आंध्र की एकदली सरकार से, उड़ीसा की आसाम में या पंजाब की हरियाणा से कम कारगर नहीं रही। बहुत कुछ सरकार में शामिल गुटों या तत्त्वों पर निर्भर होता है। आखिर कांग्रेस में भी अनेक गुटों का ही मेल हुआ था, और ये गुटों का गहरा और कांग्रेस से अपना सौदा

३७ चार चुनावों में जनमत का वर्गों और वोटों के विवरण में तथा सेंटर पर स्टनी आफ डेवलपिंग सोमास्टीन द्वारा १९६६ और १९७७ में वोटों की पट्टाल से पता चलता है कि जहाँ कांग्रेस के समर्थकों का अनुपात स्थिर रहा है और १९६७ में कुछ गिरा है, वहाँ अन्य दलों के समर्थकों की संख्या बढ़ी है और इनमें अधिकांश उपेक्षित वर्गों के लोग हैं। मई १९६७ की पट्टाल के कुछ आँकड़े हमें आशय में दिए हैं। किंतु विस्तृत आंकड़े बाद में प्रकाशित होंगे।

पटाया करने थे। प्रतिद्वंद्विता के जमाव और लगातार सत्तारूढ़ होने से सरकार में लागा की मांग के प्रति उगसीरता की प्रवृत्ति आ जाती है। और जब दूसरे दला सं मुखावना रहता है और चुनाव म हारने का डर रहता है तो सरकार ज्यादा सावधान होती है और लागा की दान पर अधिक ध्यान देती है। भारत म जहा सरकार और सरकारी साधना का इतना महत्त्व है आर जाता की बुनियादी जरूरत का पूरा करने के लिए बहुत कुछ करना है, विभिन्न संयुक्त सरकारें निष्क्रिय हो कर रही बँट सकती।

इसलिए हो सकता है कि एक बार जब संयुक्त सरकार की पद्धति स्थापित हो जाए, और विभिन्न दला का उसम काम करने का अनुभव हा जाए तो सरकारें विदेशी नमूनों की नकल करने के बजाय दश की जाता की जरूरत को समझने और उह पूरा करने पर अधिक ध्यान देने लगे, और ठोस काम करने लगे। यह स्वीकार करना होगा कि जब सरकार म नेहरू की तृती वालनी थी, उस समय से अब सरकार अधिन सचेत हो गई है और जरूरत के अनुसार नीति बनाने और ठोस काम करने पर ज्यादा ध्यान देने लगी है। गुरु म सागी या मिलीजुनी सर वारें भले ही ठीक से काम न कर पाए, पर धीरे धीरे जँस मिल कर काम करने की परंपरा स्थापित हाने लगेंगी, ये सरकारें जनता के ज्यादा संपर्क म रहेंगी और ज्यादा काम करने को बाध्य हानगी। इस बिताम में इस मत का प्रतिपादन किया गया है कि बालिंग मताधिकार की प्रणाली और फलस्वरूप राजनैतिक अधिकारों में जनता के ज्यादा भाग लेने और सत्ता के विकेंद्रीकरण मे सरकार की नीतिया अधिक ययायवादी और जनता की इच्छा व जरूरतों के अनुकूल बनेंगी। १९६७ और १९६९ के चुनाव इसी दिशा में बढम हैं।

### सरकार ही केन्द्रबिंदु

ऊपर बताया गया है कि भारत में राजनैतिक दला की बढती हुई विभिन्नता में एकता की बिंदु सरकार है। सरकार को ले कर ही सारी राजनीति घूमती है। विरोध का अर्थ सरकार का विरोध है, चाहे वह दल के भीतर हो या बाहर, चाहे सरकारी दल कांग्रेस हो या अन्य पार्टी। विरोध का यह रूप काफी पहले से रहा है। सन १९५४ से १९६७ तक कांग्रेस अंदर विरोधी गुटा का लक्ष्य सरकारी या सत्तारूढ़ गुट था। केरल में १९५९ में कम्युनिस्ट-विरोधी आंदोलन कम्युनिस्ट सरकार के विरुद्ध था। १९६७ के बाद सरकार-विरोधी आंदोलन कांग्रेस के ही नहीं, गैर कांग्रेस सरकारों के विरुद्ध भी रहा है। जैसे १९६८ में केरल के म्युनिमिल चुनाव में विरोध का लक्ष्य कम्युनिस्ट दल की संयुक्त सरकार थी, और उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में भ्रष्टाचारी चुनाव में जनसंघ तथा

के नेतृत्व में 'युग तुक' है, जो चाहते हैं कि सामाजिक और जायिक क्षेत्र में कांग्रेस जागे बढ़े, और दूसरा पक्ष उन लोगों का है, जो कांग्रेस संगठन की शक्ति का कायम रखना चाहते हैं। ये लोग इस बात की उपेक्षा कर रहे हैं कि अब तक उपेक्षित और अधिकारवंचित वर्गों में राजनैतिक जाग्रति हो रही है। चुनाव के रख को देखने से पता चलता है कि इस उपेक्षित वर्ग का — जिस में नव पिथित और छोटे किसानों तथा खेत मजदूरों का बाहुल्य है — समर्थन कांग्रेस के वजाय दूसरे दल को मिल रहा है। ३० कांग्रेस के सामने यह प्रश्न है कि वह कैसे अपना मध्य से कुछ वाम पक्ष की ओर रख कायम रखें।

यदि कांग्रेस उन वर्गों में नहीं प्रवेश कर पायी, जो अब तक उससे अलग रहे हैं, तो क्या होगा? ऐसा लगता है कि भविष्य में राज्यों ही नहीं केन्द्र में भी मिलीजुली सरकार बनेनी। हो सकता है कि कुछ राज्यों में एक ही दल की, या एक दल के प्रभुत्व में संयुक्त सरकारें रहे और केन्द्र में मिलीजुली सरकार बने। इसमें भी संदेह नहीं कि केन्द्र की मिलीजुली सरकार में अभी कुछ दिना तक प्रधान भागीदार कांग्रेस ही रहेगी, क्योंकि अन्य दल अभी इतना सावदशिक रूप नहीं ग्रहण कर पाए हैं कि संसद में वे अधिक सदस्य भेज सकें। यह भी संभव है कि राज्यों में वे अधिक सदस्य भेज सकें। यह भी संभव है कि राज्यों में जो साक्षी सरकारें बनें उनमें प्रधान भागीदार कांग्रेस से भिन्न कोई दल हो, जैसे बंगाल और केरल में माक्स० कम्युनिस्ट, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में जनसंघ और पंजाब उड़ीसा, मद्रास में वहाँ के प्रांतीय दल। जो देश में सबसे बड़ा दल कांग्रेस ही रहने की संभावना है, भले ही वह सभी स्तरों पर सरकार न बना सके। यदि वह पुनः अपने संगठन में एकता स्थापित कर सकी और अपनी गति प्राप्त कर सकी तो उस की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होगी।

### संविद सरकारों का दौर

जरूरी नहीं कि संविद या संयुक्त सरकारें एक दल की सरकारों से कम बार गर और सोद्देश्य हो। केरल की साक्षी सरकार आंध्र की एकदली सरकार से, उड़ीसा की आसाम से या पंजाब की हरियाणा से कम कारगर नहीं रही। बहुत कुछ सरकार में शामिल गुटा या तत्त्वों पर निर्भर होता है। आखिर कांग्रेस में भी अनेक गुटा का ही मेल हुआ था और ये गुट व घग बराबर कांग्रेस से अपना सीना

३७ चार चुनावों में जनसंघ के वर्गों और वोटों के विश्लेषण से तथा सेंटर पर स्थानीय आफ डेवलपिंग सोमाश्नीज द्वारा १९६६ और १९६७ में वोटों की प्रणाली से पता चलता है कि जहाँ कांग्रेस के समर्थकों का अनुपात स्थिर रहा है और १९६७ में कुछ गिरा है, वहाँ अन्य दलों के समर्थकों की संख्या बढ़ी है और इनमें अधिकांश उपेक्षित वर्गों के लोग हैं। सन १९६७ की पड़ताल के कुछ आँकड़े हम आयाय में दिए हैं। किंतु विस्तृत आँकड़े बाद में प्रकाशित होंगे।

पटाया करत थे। प्रतिद्वंद्विता के अभाव और लगातार सत्तामंड होने से सरकार में लोगो की भावो के प्रति उदासीनता की प्रवृत्ति आ जानी है। और जब दूसरे दला से मुकाबला रहता है और चुनाव में हारने का डर रहता है तो सरकार ज्यादा सावधान होती है और लोगो की दान पर अधिक ध्यान देती है। भारत में जहाँ सरकार और सरकारी साधना का इतना महत्व है और जनता की बुनियादी जरूरतों का पूरा करने के लिए बहुत कुछ करना है, विभिन्न संयुक्त सरकारें निष्प्रिय हो कर नहीं बठ सकती।

इसलिए हो सकता है कि एक बार जब संयुक्त सरकार की पद्धति स्थापित हो जाए, और विभिन्न दलों को उसमें काम करने का अनुभव हा जाए, तो सरकारें विदेशी नमूना की नकल करने के बजाय देश की जनता की जरूरतों को समझने और उन्हें पूरा करने पर अधिक ध्यान देने लगे, और ठोस काम करने लगे। यह स्वीकार करना होगा कि जब सरकार में नेहरू की तृती बोलती थी, उस समय से अब सरकार अधिक सचेत हो गई है और जरूरत के अनुसार नीति बदलने और ठोस काम करने पर ज्यादा ध्यान देने लगी है। शुरू में साथी या मिलीजुती सरकारें थले ही ठोक से काम न कर पाए, पर धीरे धीरे जैसे मिल कर काम करने की परंपरा स्थापित होने लगेगी, ये सरकारें जनता के ज्यादा संपर्क में रहेंगी और ज्यादा काम करने को बाध्य होंगी। इस विताव में इस मत का प्रतिपादन किया गया है कि बालिंग मताधिकार की प्रणाली और फलस्वरूप राजनैतिक अधिकारो में जनता के ज्यादा भाग लेने और सत्ता के विकेंद्रीकरण से सरकार की नीतियां अधिक यथार्थवादी और जनता की इच्छा व जरूरतों के अनुकूल बनेंगी। १९६७ और १९६९ के चुनाव इसी दिशा में कदम हैं।

### सरकार हो के द्विबिंदु

ऊपर बताया गया है कि भारत में राजनैतिक दलों की बढ़ती हुई विभिन्नता में एकता की बिंदु सरकार है। सरकार को ले कर ही सारी राजनीति घूमती है। विरोध का अर्थ सरकार का विरोध है, चाहे वह दल के भीतर हो या बाहर, चाहे सरकारी दल कांग्रेस हो या अन्य पार्टी। विरोध का यह रव सच है। सन १९५४ से १९६७ तक कांग्रेस अंदर विरोधी दलों का एक सरकार की या सत्तारूढ़ गुट था। केरल में १९५९ में कम्युनिस्ट-मिलिटेंट अदीन कम्यनिस्ट सरकार के विरुद्ध था। १९६७ के बाद कांग्रेस के ही नहीं, गैर कांग्रेस सरकारों के विरुद्ध भी है। १९६८ में केरल के म्युनिसिपल चुनाव में विरोध का रूप कम्युनिस्ट दल की नुकुल सरकार थी, और उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में मजदूर दलों में जनमय तथा

विहार में ससोपा और उसके साथी दल थे। १८ १९६७ के बाद कांग्रेस और अन्य दलों के प्रति प्रबुद्ध वग का जो रुख बनता या बदलता रहा और चुनावों में इनको जा सफलता या विफलता मिली, उनमें इस बात का बहुत हाथ था कि इन दलों की सरकार के प्रति जनता का क्या रुख रहा। यद्यपि अभी पक्की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, फिर भी आसार यही है कि अगले चुनाव में वोटरो का रुख सरकार के काम से निर्धारित होगा। सरकार ने कैसा काम किया है विभिन्न दलों ने मिलीजुनी सरकार में कसा व्यवहार किया है, किन दलों पर भरोसा किया जा सकता है कि वे टिकाऊ साथी सरकार बना पाएँगे और किस दल की जनता में कहा तक पहुँच है, इन बातों पर भविष्य में चुनाव का परिणाम बहुत निर्भर होगा। इस बीच कांग्रेस के द्र में सत्ताह्व है और देश की सबसे बड़ी तथा तात्कालिक राष्ट्रीय पार्टी है और राज्या की राजनीति को प्रभावित करने के उसके हाथ में बहुत स ज़रिये हैं। जब राज्य में कोई साथी सरकार टूट जाती है तो केन्द्रीय कांग्रेस के नेता राष्ट्रपति-शासन राज्यपाल और सदन के ज़रिये राज्य में हस्तक्षेप करत ह। इसने अनेक राज्या की गैरकांग्रेस सरकार के साथ बहुत अच्छे संबंध रखे हैं, कभी कभी राज्या की कांग्रेस सरकार से भी अधिक अच्छे।

### सम्यक्स्थिति में शिरकत

दला क प्रातीयकरण का एक प्रभाव यह हुआ कि देश के शासन में अब कांग्रेस के अलावा अन्य दलों का भी भाग लेने का मौज़ा मिला और इस प्रकार सध-प्रणाली के वे भी जग बन गए। प्रायः प्रत्येक प्रमुख दल की सरकार कही न कही है। हमने देखा है कि जब कांग्रेस भी सब जगह सत्ताह्व थी, तब भी उसकी जातरिक गुटबंदी के ज़रिये बाहरी अन्य दल उसकी नीतियों को प्रभावित कर पाते थे और इस हद तक राज्य तथा केन्द्र की सत्ता की राजनीति से वे विलकुल कटे नहीं थे। फिर भी पराभ रूप से प्रभाव डालना एक बात है और सत्ता में भाग लेना, चाहे साझीदार क रूप में ही, और बात है। पहली स्थिति में मजबूरी का भाव रहता है जबकि दूसरी स्थिति में अधिकार का। सत्ताग्रहण से सरकार की समस्याएँ

३८ कुछ रायों में कांग्रेस ने पुनः शक्ति प्राप्त की। इसका कारण मतदानार्थों का वर्तमान सरकार से अमनोप और सरकारी दलों में घूट रही। कम्युनिस्टों के गढ़ केरल में १९६८ के स्थानियल चुनावों में कांग्रेस की सफलता मिथी। उत्तरप्रदेश और गुजरात तथा राजस्थान में जयपुर की महाराजों के क्षेत्र में उपचुनाव में प्रतिष्ठा की रक्षा में कांग्रेस की सफलता मिथी। १९६९ के मध्यावधि चुनाव में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का स्थिति में गुधार हुआ और उसकी सरकार बन गई, उसके मुख्य प्रतिद्वंद्वी जनमत की पार्टी नुरमान हुआ। बिहार में कांग्रेस की सीटें और कम हो गईं किंतु उमने विरोधी दल उरी तरह से कटे हुए थे, इसलिए उसने सरकार बना ली लेकिन प नेपाल और पनाब में हमरी उरी तरह हार हुई यद्यपि हमकी बोट सरथा में कभी नहीं आई।

और कठिनाइयाँ की जानकारी होती है। इससे जिम्मेदारी और यथावत्वादिना बचती है और लगातार अल्पमत में रहने के कारण जो विरोध की प्रवृत्ति आ जाती है, वह दूर हो जाती है।

दूसरे, विभिन्न दल द्वारा सरकार बनाने से समझौते और एक दूसरे के मत का आदर करने की प्रवृत्ति पैदा होती है। १९६७ के बाद एक उल्लेखनीय बात यह हुई कि केन्द्र तथा राज्य की गैरकांग्रेसी सरकारों में समझौते की भावना बढ़ी है और वे शासन की सामान्य समस्याओं को मिल कर सुलझाने की कोशिश करने लगे हैं। १९६७ में राज्या में कांग्रेस और गैर-कांग्रेस सरकारों की स्थापना के बाद ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और गृहमंत्री श्री चव्हाण आदि न गैर कांग्रेसी मुख्य मंत्रियों से ऐसे सन्ध स्थापित किए जिससे शासन के मामले में दोनों में सहयोग हो सके। वास्तव में गैर कांग्रेसी मुख्य मंत्रियों से बरतना केन्द्रीय कांग्रेस सरकार के लिए ज्यादा आसान सिद्ध हुआ, बजाय कांग्रेसी मुख्य मंत्रियों के जो कांग्रेस दल और रा्ट्रीय सरकार के मामलों में भी दखल देने की कोशिश करते थे क्योंकि वे अपने को महज मुख्यमंत्री नहीं कांग्रेस के अगिल भारतीय नेता भी मानते थे। श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री चव्हाण को मद्रास के श्री अन्नदुराई, उड़ीसा के आर. एन. मिहदेव, उत्तरप्रदेश के चरणसिंह और पंजाब के गुरनार्तसिंह जैसे गैर-कांग्रेसी मुख्य मंत्रियों का विश्वास प्राप्त करने में सफलता मिली। यहाँ तक कि अक्सर ये मुख्यमंत्री अपनी कठिनाइयाँ में और अपने साथीदारों से मतभेद पदा होने पर इनमें सलाह लेते थे। इससे उनके दल वाले और उनके कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी दल को सकोच होता था। जो लाग यह समझते थे कि राज्या में भिन्न दलों की सरकारों के बनने से दल या पार्टियाँ प्रणाली टूट जाएगी, उन्होंने एक ता कांग्रेस और प्रतिपक्षी दलों के नेताओं के पुराने संबंधों का मुला दिया और इस बात की भी उपस्था कर दी कि भारत की दल-प्रणाली में इतनी परिवर्तनशीलता है कि वह नए नेताओं और नए दलों को भी अपने अंदर स्थान दे सकें।

यही नहीं कि विपक्षी दलों के नेता और कांग्रेस के नेता पहले राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस में साथ काम कर चुके थे, बल्कि विपक्षी दल की सरकारों का नीति और कार्यक्रम भी—स्वतंत्र और कम्युनिस्ट जैसे भिन्न दलों के भी—कांग्रेस सरकार से ज्यादा भिन्न नहीं थे। इन सरकारों ने भी अपनी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की तरह बीच की नीति अपनाई। यही नहीं इनमें कुछ ने—मद्रास में द्रमुक और केरल में कम्युनिस्ट—यह दावा किया कि वे उही नीतियों पर चल रही हैं जो कांग्रेस की हैं, मगर जिनको कांग्रेस पूरा नहीं कर सकी। ३९ इन संयुक्त सरकारों

३९ कांग्रेस के श्री सी. सुब्रह्मण्यम की इस आलोचना का भी द्रमुक सरकार की कोई अपनी नीति नहीं है और वह कांग्रेस की ही नीतियों पर चल रही है श्री अन्नादुरे ने यह बचाव दिया

[अगले पृष्ठ पर] ।



का आधार एक न्यूनतम कार्यक्रम था, जो उस न्यूनतम कार्यक्रम से भिन्न न था, जिस पर कांग्रेस के दक्षिण और वाम पक्ष सहमत हुए थे। इन गैर-कांग्रेसी दलों की राजनीति और दूसरे दलों से जोड़तोड़ का तरीका भी वही था जो कांग्रेस वालों का था। नतीजा यह हुआ कि जब साक्षी सरकार के टूटने पर कांग्रेस वापस आई तो उसे स्थिति और सरकारी कामकाज का तरीका वैसा ही मिला, जैसा उस समय था, जब वह अपदस्थ हुई थी।

लेकिन कांग्रेस और भिन्न दलों की यह सहमति नेहरू या लालबहादूर शास्त्री के समय से बहुत भिन्न है। नेहरू के समय कांग्रेस के अंदर ही विरोधी विचारधाराओं का समन्वय हुआ था। लालबहादुर शास्त्री कोई बड़ा फैसला करते समय विरोधी दलों से सलाह करते थे। अब इंदिरा गांधी के समय न केवल विभिन्न दलों की राज्य सरकारों, राज्य कांग्रेस के नेताओं और काफी सशक्त सदस्यों से ही मशविरा किया जाता है, बल्कि ऊँचे और अनुभवी सरकारी अधिकारियों की राय भी बहुत वजन रखती है। ४० अब राजनैतिक तंत्र के ये विभिन्न अंग राजकाज में ज्यादा प्रत्यक्ष भाग लेते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।

## सहमत नीतियाँ

सर्वस्वीकार्य कार्यक्रम और नीतियों की खोज अभी भी जारी है। हमने देखा है कि यद्यपि कांग्रेस का झुकाव कुछ वाम पक्ष की ओर रहा है ४१ फिर भी समय समय पर दक्षिण और वाम दोनों पक्षों का प्रभाव घटता बढ़ता रहा है। इधर एक

[ पिछले पृष्ठ से ]

४० कांग्रेस को चाहिए कि वह द्रमुक को धन्यवाद दे कि वह उसकी नाति को प्रायश्चित्त कर रहा है। (हिंदू वीक्ली रिव्यू जुलाई २२ १९६८) केरल के माक्स मुरयमन्ना नवदूरीपाद का भी यही दावा था। ध्यान रहे कि १९६७ के चुनाव की नमूने की पटताल में जब लोगों से पूछा गया कि विभिन्न दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में क्या अंतर है तब ६५ प्र.श. ने श्रम उत्तर दिया और इनमें से ४१ प्र.श. ने कहा कि कोई अंतर नहीं है।

४० देखें, अध्याय ८।

४१ जोत आर शहरी संपत्ति की अधिकतम सामा निधारण सहजाण खेना और गुन निर पेभना की नीति पर जनसाधारण और विशिष्ट लोगों की राय लेने स श्रम बान की पुष्टि होती है।  
 ४१ प्रथम लोकसभा के ६० से ८० प्रतिशत सदस्य और स्वतंत्र पार्टी को छोड़ कर देश दलों के समर्थक इन नीतियों के पक्ष में थे। ससद सदस्यों के मत थे बारे में देखिए - गुरिंदर मूरी, 'पेपिंग फेस आफ लोकसभा' लिख (नईदिल्ली, अगस्त, १५, १९६१) और अलबर्ट एम कट्टिल, 'द इन्डियन परमेयन ऑफ द सिनो इन्डियन बोटल क्वेश्चन - ऐन इनक्वायरी इनटु पोलिटिकल साइजोलाजी (प्रिन्सटन १९६३)। जनमत के बारे में देखें - 'इंडि हिस्ट्री आफ पब्लिक ओपीनियन अथॉरिटी पब्लिक ओपीनियन सर्वे (नई दिल्ली, जन १९६४)। इस सत्यान द्वारा जनमत की पटताल के विवरण के लिए देखें - सैमुअल जे एल्टमैन्टेन्ट, डेवॉपिंग पैटर्न आफ पार्टी प्रेफरेंसेज - अथॉरिटी पब्लिक ओपीनियन सर्वे (जन १९६४)।

तो राष्ट्रीय स्तर पर जिन दलों का जोर बढ़ा है वे दोनों कम्युनिस्ट पार्टियाँ हैं, दूसरे बहुत से राष्ट्रीय प्रश्नों पर क्षेत्रीय दलों ने कोई निश्चित रुख नहीं ग्रहण किया है। इससे कांग्रेस की नई पीढ़ी के वामपक्षी झुकाव को बल मिला है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो संभव है कि देश में कुछ प्रश्नों पर एक निश्चित नीति को सहमति मिल जाए।

इस सिलसिले में दो बातें ध्यान योग्य हैं। एक तो दक्षिण पश्चिमी दल कोई स्पष्ट दक्षिणपन्थी विचारधारा या नीति पर जोर नहीं दे रहे हैं। जनसंघ ऐसा दल भी घमनिरपेक्ष और राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण करना चाहता है और उसने अनेक प्रश्नों पर, जैसे गोरक्षा और भाषा पर अपना पहले का कटु रुख नरम कर दिया है। साथ ही स्वतंत्र दल का जोर भी राजस्थान, बिहार, गुजरात आदि में गिर रहा है, और उड़ीसा में स्वतंत्र दल की सरकार अनेक प्रश्नों पर केन्द्रीय नीतियों के समीप है। दूसरे, भारत जैसे देश में जहाँ विकास के लिए सरकार को इतना काम करना है वामपक्षी नीतियों के बिना काम नहीं चल सकता।

इस वामपन्थी झुकाव में बड़ा हाथ राज्यों और प्रदेशों के दलों और जनता के स्थानीय मुक्तियों तथा निंदल या स्वतंत्र विधायकों और संसद सदस्यों का रहा है। जैसे जैसे राजनैतिक व्यवस्था का जनता में प्रवेश और विस्तार होता है अब तक उपेक्षित वर्ग राजनीति में आते हैं। मद्रास में द्रमुक, पंजाब में अकाली, उत्तरप्रदेश में भा० का० द०, उड़ीसा में पुरानी गणतंत्र परिषद और केरल तथा पंजाब में कम्युनिस्टों के क्षेत्रीय दल, सभी काफी मजबूत और टिकाऊ सरकार बनाने में समर्थ हैं, और भारत के दल-तंत्र में उनके अधिक भाग लेने की संभावना है। यद्यपि अभी कुछ दिनों तक केन्द्र में कांग्रेस की सरकार बनी रहने की पूरी संभावना है, किंतु राज्यों में भिन्न दलों की सरकार होने के कारण भारत की संघीय व्यवस्था में अकेले कांग्रेस का ही नहीं सभी दलों का भाग हो गया है और इस प्रकार उसे सभी दलों की स्वीकृति मिल गई है।

### राजनैतिक व्यवस्था के स्वरूप की ठीक परख

इस प्रकार जो बहुदली व्यवस्था विकसित हो रही है उसमें केन्द्र को या कांग्रेस को राज्यों में भिन्न दलों की सरकार के साथ बँसा व्यवहार करना चाहिए, जहाँ इसकी परिपाटी या नियम नहीं बन पाए हैं। संघीय व्यवस्था अथवा केन्द्र-राज्य संबंध को ठीक ढंग से बनाए रखना आसान नहीं सिद्ध हुआ। केन्द्र का राज्यों से व्यवहार भी हमेशा उचित और यायपूर्ण नहीं रहा। जबकि इसने राज्य के बगड़े में अपने दल या गुट का पक्ष लिया है। सन १९५६ में केरल में कम्युनिस्ट सरकार की बर्खास्तगी और केन्द्र का शासन लागू करने में और १९५७ में बंगाल में राजनैतिक संकट के समय गर कम्युनिस्ट दल का समर्थन करने में केन्द्र सरकार

का आधार एक 'यूनितम कार्यक्रम था, जो उस 'यूनितम कार्यक्रम जिस पर कांग्रेस के दक्षिण और वाम पक्ष सहमत हुए थे। इन की राजनीति और दूसरे दलों से जोड़तोड़ का तरीका भी वालों का था। नतीजा यह हुआ कि जब साथी सरकारा के टू आई तो उसे स्थिति और सरकारी कामकाज का तरीका उस समय था, जब वह अपदस्थ हुई थी।

लेकिन कांग्रेस और भिन्न दलों की यह सहमति नेहरू या समय से बहुत भिन्न है। नेहरू के समय कांग्रेस के अंदर ही का समन्वय हुआ था। लालबहादुर शास्त्री कोई बड़ा फैसला से सलाह करते थे। अब इंदिरा गांधी के समय न राज्य सरकारों, राज्य कांग्रेस के नेताओं और काफी सँ किया जाता है, बल्कि ऊँचे और अनुभवशील सरकारी अधिकारियों वजन रखती है। ४० अब राजनैतिक तंत्र के ये विभिन्न प्रत्यक्ष भाग लेते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते

## समयन और विरोध

भारत की राजनीति कांग्रेस के इदगिद घूमती रही है। कांग्रेस की प्रधानता का कारण उसके हाथ में सरकार की शक्ति होना तथा उसका प्रभावशाली नेतृत्व रहा है। इसके साथ ही उसके संगठन की जनता में भी पहुँच रही है। इस प्रकार सरकार की शक्ति और जनता में पहुँच दोनों उसकी प्रधानता की जड़ में हैं। राजनीति में भाग लेने के इच्छुक मुख्यतः कांग्रेस में ही प्रवेश करते थे। अय दलों का प्रभाव तो अभी ही पड़ना शुरू हुआ है। १९६७ के चुनाव के दौरान किये गये एक राष्ट्रीय अध्ययन से यह पता चला कि ७० प्रतिशत लोग किसी न किसी राजनीतिक दल को पसंद करते थे (और ३४ प्र० श० निंदल या स्वतंत्र उम्मेदवारों के पक्ष में थे।) और इनमें से ४३१ प्र० श० कांग्रेस के पक्ष में थे, बाकी अय दलों के। (देखिए सारणी ४-६।)

यदि यह भी मान लिया जाए कि सत्तारूढ़ दल के पक्ष में कुछ लोग ने या ही नाम लिखा दिए होंगे और कांग्रेस-समयक प्रतिशत में कुछ कमी कर दी जाए और भिन्न दलों के समयका की संख्या कुछ बढ़ा भी दी जाए, तब भी इस पड़ताल से कांग्रेस ही सबसे परिचित और समर्थित पार्टी सिद्ध होती है। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि इस प्रकार की पड़ताल से वास्तविक मतदान काफी भिन्न होता है, क्योंकि मतदान पर बहुत-सी बातों का प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर यह भी ध्यान रहे कि २६७ उत्तरदाताओं ने या तो किसी पार्टी के पक्ष में राय नहीं दी, या इस प्रश्नका उत्तर नहीं दिया जबकि चुनाव में वोट न देने वाला की संख्या ३८ प्र० श० थी। वोट न देने वाले भी बहुत-से लोग किसी पार्टी की ओर होते हैं। मजे की बात यह है कि केवल ११८ प्र० श० लोगों ने बताया कि उन्होंने वोट नहीं दिया। लोग यह कहने से हिचकते हैं कि हमने वोट नहीं दिया।<sup>४५</sup> यह भी उल्लेखनीय है कि पड़ताल करने वाले ने स्वयं किसी दल का नाम नहीं लिया था, उत्तरदाताओं ने ही बताया कि वे अमुक दल के पक्ष में हैं। इससे यह पता चला कि लोगों को विभिन्न दलों के बारे में काफी जानकारी थी और सबसे ज्यादा उत्तरदाता कांग्रेस के पक्ष में थे।

मगर कांग्रेस के समयन के साथ साथ उससे असंतोष भी अधिक है। शासक दल की हैसियत से कांग्रेस के काम की काफी आलोचना की गई और इस कारण लोगों ने इसके विरोध में वोट दिए। उपर्युक्त पड़ताल में कांग्रेस के विरुद्ध जो शिकायतें

४५ यह पड़ताल सेंटर फार स्टडी आफ डेव सोसा की ओर से की गई थी। हमें देश भर के ४७ समूहों के और ९४ विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र चुने गए और उनमें २२८७ व्यक्तियों से प्रश्न किए गए (ऊपर जो विवरण दिया गया वह सब पुरुषों के उत्तर हैं। स्त्रियों के उत्तरों का विवेक्षण अभी नहीं हुआ।) हम पड़ताल का विवरण हो रहा है। हमके निष्कर्षों का प्रकाशन शीघ्र होनेवाला है।

के नेताओं पर पक्षपात का आरोप किया गया है। कांग्रेस के नेता अभी इस बात को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाए हैं कि उन्होंने देश में संसदीय या प्रतिनिधि शासन की जो व्यवस्था स्थापित की है वह तभी सत्र की स्वीकृति या सवेगी और जड़ जमा सवेगी जब सभी दलों को सरकार में भाग लेने का मौका मिले। इसी से गैरकांग्रेसी दलों का भरोसा होगा कि वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था में उनका साथ भी दिया जाएगा और उन्हें भी सत्ता ग्रहण करने का पूरा मौका मिलेगा।

दूसरी ओर मन १९६७ के बाद से कांग्रेस की सर्वोच्च या केन्द्रीय नेता मञ्ची में जो फूट दिखाई पड़ी है, उससे केरल और पश्चिम बंगाल के कम्युनिस्टों की हिम्मत बढ़ी है और वे के द्र से मुकाबला करने और वर्तमान व्यवस्था को जड़ से खाला करने में लगे हैं। वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था में प्रवेश पाने और उसे जनता की आकांक्षाओं के अधिक अनुकूल तथा क्रांतिकारी बनाने की बात करने में कोई बुराई नहीं। मगर यह कहना कि इस व्यवस्था को उलट करके या ध्वस्त करके ही जनता का भला किया जा सकता है, खतरनाक बात है और इस खतरे का बचाव, इसे अधिक प्रतिनिधि और सबसे अधिक बनाने से अर्थात् इसमें सभी दलों को मौका देने से किया जाना चाहिए।

लक्ष्य करने की बात यह है कि भारत में एक दल की प्रधानता का स्थान अनेक दलों की स्पर्धा या प्रधानता के लिए स्पर्धा ले रही है।<sup>४२</sup> इसका एक रूप सच के क्षेत्र में देखने का मिलता है जहाँ केन्द्र में कांग्रेस की प्रधानता है और राज्यों में भिन्न दलों के जुटा की। दूसरा रूप है राज्य बनाम राज्य। अर्थात् एक ओर महाराष्ट्र, आंध्र आदि में कांग्रेस की सत्ता है और दूसरे राज्यों में कम्युनिस्ट या द्रमुक (मद्रास) या अकाली (पंजाब) प्रधान है।<sup>४३</sup> तीसरा रूप निर्वाचन क्षेत्रों में देखने का मिलता है। अब ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कम होती जा रही है जहाँ एक पार्टी का ही सब दलों से मजबूत पड़ती है। फिर भी अभी औसत निर्वाचन क्षेत्र में एक दल की प्रधानता बनी है, अर्थात् जहाँ सफल उम्मेदवार को करीब ४५ प्र स वाट मिलने ह और दूसरे नंबर को उससे १२ से १६ प्र स कम।<sup>४४</sup>

४२ मन १९६७ में राजनीति में जो सहसा परिवर्तन दिखा पड़ा वह एक तरह से १९६२ में हा आरम्भ हो गया था, यह बात वोटों के वितरण से पता चलता है। सन १९६२ के चुनाव के महत्त्व के बारे में देखिए—मेरे 'द्वितीय पोलिटिकल टेक अप' और 'द टेक अप प्रोब्लम,' द इकनामिक बावली वार्षिक अंक परवरा १९६२ और विशेषांक जुलाई १९६२।

४३ बंगाल आदि में १३१ कम्युनिस्ट दलों की बात हुई है, उन्हें अनेक छोटे दलों से समझौते करने पड़े हैं। इनमें छोटे दलों की भा नीति रहने का मौका मिला है। कांग्रेस की सफलता में भी यही बात है। कांग्रेस का बल भा उम्मेदवार अनेक वर्गों या गुणों को स्थान देने में है। यहाँ भी प्रधान गुण के चारों ओर अनेक छोटे छोटे गुण बने रहते हैं।

४४ पाटर मैक डोनो का निबंध दलों के बारे में (युनिवर्सिटी आफ मिशिगन डिस्टेंशन १९६०)।

## समयन और विरोध

भारत की राजनीति कांग्रेस के इदगिद घूमती रही है। कांग्रेस की प्रधानता का कारण उसके हाथ में सरकार की शक्ति होना तथा उसका प्रभावशाली नेतृत्व रहा है। इसके साथ ही उसके संगठन की जनता में भी पहुँच रही है। इस प्रकार सरकार की शक्ति और जनता में पहुँच दोनों उसकी प्रधानता की जड़ में हैं। राजनीति में भाग लेने के इच्छुक मुख्यतः कांग्रेस में ही प्रवेश करते थे। जय दलों का प्रभाव तो अभी ही पड़ना शुरू हुआ है। १९६७ के चुनाव के दौरान किये गये एक राष्ट्रीय अध्ययन से यह पता चला कि ७० प्रतिशत लोग किसी न किसी राजनीतिक दल को पसंद करते थे (और ३४ प्र० श० निदल या स्वतंत्र उम्मेदवारों के पक्ष में थे।) और इनमें से ४३१ प्र० श० कांग्रेस के पक्ष में थे, बाकी अन्य दलों के। (देखिए सारणी ५-६।)

यदि यह भी मान लिया जाए कि सत्तारूढ़ दल के पक्ष में कुछ लोग ने जो ही नाम लिखा दिए होंगे और कांग्रेस-समयक प्रतिशत में कुछ कमी कर दी जाए और भिन्न दलों के समयका की सख्या कुछ बढ़ा भी दी जाए तब भी इस पड़ताल से कांग्रेस ही सबसे परिचित और समर्थित पार्टी सिद्ध होती है। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि इस प्रकार की पड़ताल से वास्तविक मतदान काफी भिन्न होना है, क्योंकि मतदान पर बहुत-सी बातों का प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर यह भी ध्यान रह कि २६७ उत्तरदाताओं ने या तो किसी पार्टी के पक्ष में राय नहीं दी, या इस प्रश्नका उत्तर नहीं दिया जबकि चुनाव में वोट न देने वालों की सख्या ३८ प्र० श० थी। वोट न देने वाले भी बहुत-से लोग किसी पार्टी की आर होते हैं। मजे की बात यह है कि केवल ११८ प्र० श० लोगों ने बताया कि उन्होंने वोट नहीं दिया। लोग यह कहने से हिचकते हैं कि हमने वोट नहीं दिया।<sup>४५</sup> यह भी उल्लेखनीय है कि पड़ताल करने वाले ने स्वयं किसी दल का नाम नहीं लिया था, उत्तरदाताओं ने ही बताया कि वे अमुक दल के पक्ष में हैं। इससे यह पता चला कि लोगों को विभिन्न दलों के बारे में काफी जानकारी थी और सबसे ज्यादा उत्तरदाता कांग्रेस के पक्ष में थे।

मगर कांग्रेस के समयन के साथ साथ उससे असंतोष भी अधिक है। शासक दल की हैसियत से कांग्रेस के काम की काफी आलोचना की गई और इस कारण लोगों ने इसके विरोध में वाट दिए। उपयुक्त पड़ताल में कांग्रेस के विरुद्ध जो शिकायते

<sup>४५</sup> यह पड़ताल सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव सोसा की ओर से की गई थी। इसमें देश भर के ४७ समूहों के और ९४ विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र चुने गए और उनमें २२८७ व्यक्तियों से प्रश्न किए गए (ऊपर जो विवरण दिया गया वह सब पुरुषों के उत्तर हैं) जिनके उत्तरों का विश्लेषण अभी नहीं हुआ।) इन पड़ताल का विश्लेषण हो रहा है। इसके निष्कर्षों का प्रकाशन आगे होनेवाला है।

है उनका उल्लेख करके पूछा गया कि आप उनसे सहमत हैं या नहीं ? उल्लेखनीय है कि ७० स ६० प्र० श० उत्तरदाताओं ने इस पर अपनी राय दी और अधिकांश ने कांग्रेस के काम को असंतोषजनक बताया । (सारणी पाच-७) ।

मगर फिर याद रहे कि इस विषय में पड़ताल के नतीजा पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता और कांग्रेस से इतना असंतोष होने पर भी १९६७ के चुनाव में उसको प्राप्त वोटों में कोई खास कमी नहीं हुई । फिर भी यह बात महत्व की है कि उत्तरदाताओं ने कांग्रेस के काम के बारे में निश्चित राय दी और उसके विरुद्ध शिकायतों का सही या गलत होने के बारे में काफी समझबूझ कर उत्तर दिये । शासक दल के रूप में कांग्रेस के काफी समर्थन के साथ साथ उसके काम से इतना असंतोष भी होने से पता चलता है कि जनता की दृष्टि में सरकार और दल का कितना घना संबंध है ।

यह भी उल्लेखनीय है कि शिक्षा की इतनी कमी हाते हुए और चुनाव तथा पार्टी राजनीति का अधिक ज्ञान का अनुभव न होत हुए भी, ६० प्र० श० से अधिक जनता को पार्टियों और उनकी रीति नीति के बारे में जानकारी है । फिर भी याद रखना चाहिए कि पार्टी, सरकार और राष्ट्र के प्रतीक अभी जनता के मन में बहुत गहराई से नहीं प्रतिष्ठित हो सके हैं । अभी राजनीति में जनता की अधिक दिलचस्पी नहीं हुई है और राष्ट्र, सरकार या दल को जनता स्थानीय नेताओं या अधिकारियों के ही माध्यम से जानती है ।<sup>४६</sup> अधिकांश जनता अपने रोज के घरे से ही मतलब रखती है और उसका लगाव अपने परिवार और बिरादरी से है, दल या सरकार से नहीं । इस अध्याय में और इससे पहले के अध्याय में राजनीति, सरकार और दल तथा जनता में उसके प्रवेश के बारे में जो कहा गया है, उसे राजनैतिक विकास के इस सीमित सदन में ही समझना चाहिए ।<sup>४७</sup> परन्तु इसमें कोई सदेह नहीं कि इस सीमा के भीतर दल और सरकार दोनों परिवर्तन और विकास के शक्तिशाली माध्यम के रूप में सामने आ रहे हैं, और उनके जरिये जनता राजनैतिक व्यवस्था तथा सरकारी कार्यों में दिलचस्पी ले रही है तथा चुनाव में सरकार के काम से अपना असंतोष भी जाहिर करने लगी है ।

### दल का सामाजिक गठन

इन दलों के नेता और पदाधिकारी लोगों की सामाजिक स्थिति क्या है और

<sup>४६</sup> उपर्युक्त पड़ताल में केवल १७ ८ प्र श उत्तरदाता अपने राज्य के मुख्यमन्त्री का सही नाम बता सके । लेकिन २४ १ प्र श ने मुख्यमन्त्री के दल का नाम ठीक बताया । इसमें पता चलता है कि जनता स्थानीय नेताओं को ज्यादा जानती है । राज्य या केन्द्र के नेताओं की सरकार बहुत धुंधली है ।

<sup>४७</sup> अध्याय ८ में राजनैतिक व्यवस्था के जटिल जमाने के विषय में विचार किया गया है ।

समाज के किस वर्ग या वर्गों से उनकी समझ मिलता है ? पहले हम दल के नेताओं और जनता के प्रतिनिधियों की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करेंगे फिर उनके समयका की ।

### समय सदस्य

अभी हाल में समय सदस्य की सामाजिक स्थिति का एक अध्ययन किया गया है जिससे पता चलता है कि उनमें वकीला की संख्या घट रही है और उनका स्थान कृषक और जमींदार वर्ग के लोग ले रहे हैं<sup>४८</sup> । पहली लोकसभा में वकीला की संख्या ३५ प्र० ६० दूसरी लोकसभा में ३० प्र० १० तीसरी में २४ ५ थी और चौथी में १७ ५ प्र० ६० है । इसके मुकाबले कृषक की संख्या २२ ४ प्र० ६०, २८ १ प्र० ६०, २७ ४ प्र० ६० और ३१ १ प्र० १० रही । कृषक वर्ग में बड़े जमींदारों व सरदारों से लेकर छोटे जमींदार व किसान सभी हैं, लेकिन वे उस शहरी पेशेवर वर्ग के मुकाबले, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन का भी नेतृत्व किया था और स्वतंत्रता के बाद सरकार का भी, देहाती जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

कांग्रेस के अंदर बहुत से वर्गों और पेशों के लोग हैं, जबकि अन्य दलों का आधार इतना व्यापक नहीं है, और इसीलिए उसमें भिन्नता भी कम है जैसे (सारणी पांच-८) । स्वतंत्र दल और दोना कम्युनिस्ट दल में । स्वतंत्र दल में एक जोर बड़े जमींदार और भूतपूर्व राजा हैं, तो दूसरी ओर व्यापारी और रिटायर्ड ऊंचे सरकारी अधिकारी । स्वतंत्र दल में बड़े जमींदार और भूमिपति का जमघट है जबकि मध्यम वर्ग के किसान कांग्रेस, जनसंघ, द्रमुक और दोना समाजवादी पार्टियों में अधिक हैं । इसी तरह यद्यपि जनसंघ और द्रमुक दोना में व्यवसाय और उद्योग के लोग हैं, जो अधिकतर दूकानदार हैं, किंतु स्वतंत्र पार्टी में बड़े व्यवसायी और उद्योगपति हैं ।<sup>४९</sup> दूसरी ओर कम्युनिस्ट पार्टियों में अधिकांश ट्रेड यूनियन और पेशेवर राजनीतिक तथा पत्रकार आदि हैं ।

जनसंघ और द्रमुक की शुरुआत शहरी और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों से हुई, किंतु धीरे धीरे ये भूमिधारी या कृषक तथा अन्य वर्गों में भी फैले । सद्धर्मता से देखने से पता चलता है कि अधिकांश राज्यों में जहां इसका प्रभाव है जनसंघ मुख्यतः शहरी पार्टी है, किंतु उत्तरप्रदेश में इसने गांवों में भी प्रवेश किया है और कांग्रेस को धक्का दिया है । जनसंघ के आधे समयक उत्तरप्रदेश के हैं और वहां उसका आधार काफी व्यापक हुआ है । इसी तरह द्रमुक की शुरुआत मद्रास के नगरों से हुई, पर इसने बाद में देहाती इलाकों में भी कांग्रेस को अपदस्थ कर दिया

<sup>४८</sup> रत्ना दत्त, 'द पार्टी रिप्रेजेंटेटिव इन फोथ लोकसभा,' एक ऐंड पोलि वार्षिकी ४, संख्या १ व २, जन १९६६ ।

<sup>४९</sup> वही ।



और राज्य भर में फैल गई। जनसंघ और द्रमुक की विचारधाराएं विपरीत हैं, परंतु दोनों की शक्ति का स्रोत भाषा और प्रदेश की भावना है और दोनों के समर्थक मध्यम और निम्न मध्यवर्ग के लोग हैं।<sup>५०</sup>

ससोपा और प्रसोपा दोनों ही पुरानी समाजवादी पार्टियाँ से निकले हैं किंतु दोनों की विचारधारा और सामाजिक आधार भिन्न है। प्रसोपा ने मूल समाजवादी पार्टी की लोकतांत्रिक समाजवाद और कट्टर धर्मनिरपेक्षता की परिपाटी को बनाए रखा। इसके अधिकतर कार्यकर्ता ट्रेड यूनियन वाले, वकील (जमी भी इसमें सबसे बड़ा वर्ग यही है) और पत्रकार हैं और यह महाराष्ट्र, मैसूर, उत्तरप्रदेश तथा आसाम के कुछ देहाती क्षेत्रों में काम करता है। दूसरी ओर डा. राममनोहर लोहिया के नेतृत्व में ससोपा ने अधिक क्रांतिकारी कार्यक्रम अपनाया और जनता में प्रवेश किया। देहाती इलाकों में इसने पिछड़ी जातियों का पक्ष लिया और शहरों में इसने भाषा जैसे प्रश्नों को उठा कर राष्ट्रीय स्वाभिमान को नई दिशा दी। नतीजा यह है कि जबकि प्रसोपा में अनेक वर्गों के लोग हैं और उसका सामाजिक आधार अधिक विस्तृत है, ससोपा में समाजवादी कार्यकर्ताओं और छोटे व मध्यम श्रेणी के किसानों का बाहुल्य है। बहुत-सी बातों में इसका और जनसंघ का रूख मिलता है और दोनों का प्रभाव भी एक ही इलाकों में है।

भारत की संसद में बहुत से निदल सदस्य भी हैं। इनके बारे में भ्रातृ धारणा है कि ये सब रईस और धनवान वर्ग के हैं। वस्तुतः यह बात नहीं है। इनमें सज्जनों की भूमि वाले हैं वे रईस या राजा वर्ग के हैं, परंतु ७० प्र. श. लोग अथवा विविध वर्गों से आए हैं।

### पूर्व अनुभव

संसद के सदस्यों के बारे में देखने की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि संसद में आने के पहले राजनीति में उनका क्या अनुभव रहा है। सारणी पांच ६ में चौथी लोकसभा के सदस्यों के बारे में ऐसी सूचना दी गई है।

इससे पता चलता है कि केवल २६३ प्र. श. सदस्य ऐसे हैं, जिनको पहले किसी भी स्तर पर विधानसभा का कोई अनुभव नहीं रहा। नए या अनुभवहीन सदस्यों की संख्या कांग्रेस में कम और अन्य पार्टियों में ज्यादा है। कांग्रेस में केवल १५६ नए सदस्य थे जबकि प्रसोपा में ३०८ प्र. श. और द्रमुक में ३३३ प्र. श. ससोपा में ४२१ प्र. श., माक्स कम्युनिस्ट दल में ४५ प्र. श., कम्युनिस्ट पार्टी में ४७४ प्र. श., जनसंघ में ४८४ और स्वतंत्र पार्टी में ६४३ प्र. श.।

दूसरी ओर दोनों कम्युनिस्ट दलों और दोनों सोशलिस्ट दलों के सदस्यों का स्वयंसेवक ट्रेड यूनियनों से ज्यादा रहा। कांग्रेस के केवल २२२ प्र. श. सदस्य मजदूर

सभा से सबधित थे। परन्तु सहकारी आंदोलन में कांग्रेस के प्रतिनिधियों का अधिक योग रहा है, यद्यपि सिवा महाराष्ट्र जैसे कुछ इलाकों को छोड़ कर शेष भारत में यह आंदोलन कमजोर है। यद्यपि स्वतंत्र दल के कुछ सदस्य सहकारी समितियों से सबधित रह चुके हैं और जनसंघ के कुछ सदस्य गांव और जिले की राजनीति में भाग लेते रहे हैं, फिर भी सब मिला कर इन दोनों दक्षिण पंथी दलों के सदस्यों का राजनैतिक अनुभव कम रहा है। इससे मुकाबले कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट समूहों का राजनैतिक अनुभव अधिक रहा है। खासकर कम्युनिस्ट और समाजवादी सदस्यों का राज्य स्तर पर राजनीति का काफी अनुभव है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट दल के ४० प्र० श० सदस्यों को राज्य स्तर का राजनैतिक अनुभव था। साधारण तौर पर समझा जा सकता है कि वामपंथी दलों में नए आंदोलनों की सराया अधिक हानी चाहिए थी, परन्तु चूंकि ये दल काफी दिनों से सक्रिय रहे हैं और इनमें राजनैतिक अध्ययन और मंथन में काम करने पर ज्यादा जोर दिया जाता है, इसलिए इनके सदस्यों का काफी राजनैतिक अनुभव रहा है।

### दलों के अनुपात

यह सन्नविदित है कि नए राष्ट्रीय राजनैतिक नेता और विचारक साधारण जनता से कई श्रेणी ऊंचे वर्गों से आते हैं। नेताओं और प्रतिनिधियों की सामाजिक स्थिति के साथ ही यह देखना भी जरूरी है कि उनके दलों में समाज के किन वर्गों का प्रतिनिधित्व हुआ है और निर्वाचन क्षेत्रों में उनको कितना और किस प्रकार का समयन प्राप्त है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सबसे पहली बात यह है कि कांग्रेस का स्वरूप अखिल भारतीय है और करीब ४० प्र० श० मतदाता हमेशा इसके साथ रहे हैं। ग्रामीण वर्गों की शक्ति प्रदेश या क्षेत्र विशेष में है। इसलिए विभिन्न दलों के समयन के आकड़ों पर विचार करते समय कांग्रेस से भिन्न दलों के क्षेत्रीय स्वरूप को ध्यान में रखना चाहिए।

सारणी पांच-१०-११ में यह बताया गया है कि विभिन्न दलों को किन पेशों से कितना समयन मिला है। कांग्रेस के साधन-शक्ति के रूप को देखते हुए, इसमें आश्चर्य नहीं कि उसे सभी पेशों का समयन मिला है। व्यवसायिक भी कांग्रेस को ४० प्र० श० के बरीय बोट मिले हैं। परन्तु सफेद पोश घमा में, और खासकर बेरोजगार वर्ग में कांग्रेस कमजोर दिख पड़ी है। परन्तु खेतियार तथा कुशल और अनुशासित मजदूर वर्गों में यह सब से ज्यादा मजबूत है।

सारणी पांच-११ से पता चलता है कि सफेदपोश तथा ग्रामीण वर्गों में जनसंघ का काफी जोर है और गांव वाला भी, खासकर भस्वामी किसानों में भी इसका बल बढ़ा है। मगर शहरी और ग्रामीण दोनों प्रकार के श्रमिकों में यह बहुत कमजोर है। कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट दलों का श्रमिकों में ज्यादा जोर है

और गहरी श्रमजीवी वर्गों में दक्षिण के मुकाबले वामपंथी कम्युनिस्टा का प्रभाव ज्यादा है। दक्षिण कम्युनिस्टा का मुख्य प्रभाव किमाना और ग्रेत मजदूरों में है।  
 द्र० मु० क० का भी यही हाल है।

ससोपा गरीबों और पिछड़े हुए लोगों की पार्टी जान पड़ती है। इसके ४४ प्र० श० से अधिक समयक खेत-मजदूर, अकुशल शहरी मजदूर और बेरोजगार लोग हैं। यह इस दल की क्रांतिकारी विचारधारा के अनुरूप है और इसने हम हम से सत्ताही सरकार में हमने साथी दल को काफी परेशानी हुई है।

इन सारणियों में यह भी पता चलता है कि स्वतंत्र पार्टी का सामाजिक आधार बहुत सखीण है। इसका सबसे अधिक समयक भूस्वामी वर्ग में मिला है और थोड़ा खेत मजदूरों से। इन खेत मजदूरों ने अपने मालिकों के प्रभाव में आकर स्वतंत्र दल को वोट दिये होंगे, ऐसा माना जा सकता है। प्रायः सभी दलों का ध्यान से वोट मित्र हैं पर स्वतंत्र और जनसंघ के समयक मुख्यतः अमीर किसान हैं जबकि वामपंथी दल ने समयक छोटे या गरीब किसान और भूमिहीन वर्ग। जनसंघ अपने प्रभाव का विस्तार साधारण लोगों में कर रहा है, जिनमें स्वतंत्र का प्रभाव अभी भी वर्ग विरोध में सीमित है। इसका एक नतीजा यह हुआ है कि इसके राष्ट्रीय नेताओं—महानी या रंगा—तथा इसके विधायकों में संघर्ष अच्छे नहीं हैं।

निर्दल समस्या का भी अनेक वर्गों से समयक प्राप्त हुआ है पर स्वतंत्रपक्षी लोगों से कम छोटे दलों को भी शहरों से ही अधिकतर समयक मिला है, क्योंकि गांवों से वोट लेने के लिए काफी अच्छे संगठन की जरूरत होती है। अविकारा छोटे दल किसी तात्कालिक या अस्थायी प्रश्न को लेकर खड़े होते हैं और उनका प्रभाव टिकाऊ नहीं होता फिर भी सत्त मिलकर वे दूसरे दलों से काफी वोट खींच ले जाते हैं।

## दलों की विचारधारा

ऊपर के विश्लेषण से विभिन्न दलों के रूप और विचारधारा का मोटे तौर पर पता चलता है। यह सही है कि एक कृषिप्रधान देश में दक्षिण, वाम और मध्य शब्दों का उतना महत्व नहीं जितना उद्योगप्रधान देश में। इसका प्रमाण यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऐसे वाम दल को अधिक समयक भूस्वामी किसानों से मिला और स० सो० पा० जैसे क्रांतिकारी दल का भाषा के प्रश्न पर जो रुक है, वह दक्षिण पंथी दलों से मिलता है। द्र० मु० क० की शुरुआत प्रांतीयवादी और उत्तर विरोधी दल के रूप में हुई थी किंतु इसने अनेक मामलों में समाजवादी नीति का अपनाया है। इसके अलावा जरा हम पहले कह चुके हैं इन दलों के स्थानीय और राज्य सरकारों में भाग लेने के कारण सरकारी कार्यक्रम और नीतियों के मामले पर

सत्ताधारी कांग्रेस दल से इनका मतैक्य भी हुआ है। फिर भी अपने समयको और नेताओं की सामाजिक स्थिति की भिन्नता के अनुसार इन दलों में स्पष्ट भेद दिखाई देता है।

ऊपर के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अपनी विचारधारा और समयका की सामाजिक स्थिति, दोनों के अनुसार स्वतंत्र पार्टी दक्षिणपथी पार्टी है। यह आर्थिक नीति में निजी या गैरसरकारी उद्योग का समयन करती है, पश्चिमी लोकतंत्री शक्तियाँ से घनिष्ठ संबंध रखना चाहती है और उदार या लिबरल राजनीति के पक्ष में है। इसका समयन बहुत ही छोटे वर्ग, भूस्वामी और उद्योगपतियों में है। जनसघ हिंदुआ और शहर के छोटे दूकानदारों और व्यापारियों का दल माना जाता है और इस रूप में दक्षिणपथी है, किंतु यह अखिल भारतीय दल बनना चाहता है और इसलिए यह दक्षिण के राज्यों में और उत्तर में मुसलमानों में भी प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है तथा उत्तरप्रदेश के गाँवों में इसे काफी समयन भी प्राप्त हुआ है। ऐसा लगता है कि जागे चलकर जनसघ कांग्रेस के मुकाबले अधिक दक्षिण नहीं होगा और इसका कार्यक्रम भी उससे अधिक भिन्न न होगा तथा अनेक राज्यों में यह कांग्रेस का स्थान लेने में सक्षम हो सकेगा। इसी प्रकार द्रमुक, अकाली दल और अन्य ऐसे प्रादेशिक दलों को भी दक्षिण वाम की परिभाषा में फिट करना कठिन होगा। फिर भी यह महत्व की बात है कि गैर कांग्रेसी दलों में सबसे अधिक सफलता दोनों कम्युनिस्ट दलों को ही प्राप्त हुई है। उन्होंने श्रमिक वर्ग, बढ़ते हुए निम्न मध्यम वर्ग और शहरी बेरोजगारों में तथा गाँवों में छोटे और भूमिहीन किसानों में अपना स्थायी प्रभाव स्थापित किया है। इनकी मुख्य समस्या यह है कि इनका मुख्य प्रभाव कुछ ही राज्यों में है — जैसे, बंगाल, केरल और आंध्र प्रदेश में। बिहार के औद्योगिक क्षेत्रों में भी इनका कुछ प्रभाव है। हो सकता है कि उद्योगों के विस्तार के साथ साथ उनकी शक्ति और कुछ राज्यों में भी बढ़े, बशर्ते वे अपनी आपसी फूट दूर कर सकें, अपने कार्यक्रम को अधिक स्वीकार्य बना सकें और वे दूसरे वाम पथी दलों के समयकों को अपनी ओर खींच सकें। इस काम में हो सकता है कि वे कांग्रेस के ज्यादा निकट आवें और उनके वामपथी कार्यक्रम को स्वीकार कर लें और इस प्रकार देश में वाम पक्ष का बल बढ़ाएँ। ५१

### रहितों या वर्गों का संगठन

जब हम विभिन्न आर्थिक वर्गों और हिन्ना के संगठन और उनकी राजनीति पर विचार करते हैं तो हम स्थिति पश्चिमी देशों से भिन्न पाते हैं।

५१ कम्युनिस्टों के खिलाफ 'दूरे देगा के प्रति निष्ठा' का आरोप बढ़ा मूखतापूर्ण है। इस आरोप का आधार बड़ा कमजोर है। लेकिन सद्भावना प्रदर्शन पर यह वाद-विवाद करके कम्युनिस्टों ने स्वयं इस आरोप का मौज दिया है।

(१) जैसा कि पहले कहा जा चुका है राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास का मुख्य माध्यम यहाँ सरकार रही है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण या प्रमुख हिता का प्रतिनिधित्व राजनीतिक दला, सरकारी नौकरियों और सरकारी पार्टी के विभिन्न गुटों के द्वारा हुआ है। वस्तुतः इस देश में इतने अधिक और विविध प्रकार के हित आर वग है कि उनकी अभिव्यक्ति विभिन्न दला और उनके क्षेत्रीय व स्थानीय गुटा के द्वारा ही हो सकी है। इन दलों का आधार चाहे व्यापक हो या सीमित, फिर भी विभिन्न वर्गों का राजनैतिक प्रतिनिधित्व इही दला के द्वारा होता है अलग संगठना के द्वारा नहीं।

(२) इसका एक नतीजा यह है कि इन वर्गों का संगठन स्वतंत्र और अलग अलग नहीं बल्कि राजनैतिक दलों के गठजोड़ों की तरह मिलाजुला होता है। यद्यपि हिंदी या व्यवसायों के प्रादेशिक और सांदेशिक मण और मस्याएँ भी हैं, किंतु राजनीतिक स्तर पर वे मिलेजुले संगठना या दला में शामिल होते हैं। वाणिज्य सघों मजदूर सघा या अध्यापक सघा आदि की राष्ट्रीय मस्याएँ भी हैं, किंतु राष्ट्रीय राजनीति में वे कारगर नहीं, उनके सदस्य भी विभिन्न राजनैतिक दलों में ही शामिल होते हैं।

(३) वर्गों या हिंदों की इस मिलावट में पुराने पारिवारिक और रिस्तेदारी या धिरादरी के मणधों का भी हाथ रहा है। जब कि अधिकांश नए देशों में व्यापार और उद्योग पर परदेशिया का कब्जा रहा है, भारत में इनका विकास परंपरागत व्यापारी परिवारों और समूहों के द्वारा हो हुआ है। इन परिवारों ने अपनी पुस्तनी व्यापारी प्रतिभा को आधुनिक व्यापार-उद्योग में लगाया है। मनेजिंग एजेंसी की प्रणाली के द्वारा आधुनिक व्यापार व उद्योग पर इही पुराने व्यापारी परि वर्गों का कब्जा रहा है, इस कारण यहाँ पश्चिमी देशों जसे पूँजीपति या उद्योगी वर्ग का विकास नहीं हो पाया। ५२

ट्रेड यूनियनों का अध्ययन करने पर इनमें भी पुरानी पारिवारिक और जाति-धिरादरी की भावना काम करती दिखाई देती है। यद्यपि आधुनिक ढंग के सह-हारा आर पूँजीपति वर्ग के सघों का विचार यहाँ भी उदय हुआ है, फिर भी पश्चिमी देशों के ढांचे पर अलग वर्ग या शक्ति के रूप में इनका संगठन अभी नहीं हुआ है। इसी तरह राजनैतिक दला ने भी अभी वर्ग विशेष का स्वरूप नहीं ग्रहण किया है। पश्चिम के विपरीत यहाँ जालिग मताधिकार और राजनैतिक अधिकार शुरू में ही द दिए गए, इससे हर वर्ग और हित को राजनैतिक व्यवस्था में स्थान

५२ देखिए-हेलेन बा लेम्ब 'द इंडियन बिजिनेस कम्युनिटी ऐंड द पब्लिसेशन आफ ऐन इंडस्ट्रियल क्लास पैमिफिकल अवेयरनेस' पृ. २, जून १९५५ और बर्नार्ड ई. माउन 'आगना इज बिजिनेस इन इंडियन पालिटिक्स' द इंडि जर्नल आफ पोलि सायंस २३-२ अप्रैल-जून, १९६२।

मिल गया और भारतीय राजनीति का स्वरूप एकवर्गी न होकर अनेकवर्गी हो गया ।

(४) मुख्य बात यह है कि भारत में वग या हित का संगठन आर्थिक या सामाजिक आधार पर न होकर पुरानी जाति-पाति के आधार पर हुआ है ।

(५) स्मरण रहे कि यहाँ सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की प्रेरक सरकार है, इसलिए यहाँ आर्थिक और सामाजिक हितों की अभिव्यक्ति राजनैतिक दलों और सरकारी तंत्र के जरिए हुई, अलग सत्था या सघटनों के द्वारा नहीं । दूसरे, वग विशेष या हित विशेष के संगठना का राजनैतिक महत्त्व नहीं दिया जाता और राजनीति में उनका भाग लेना भी पसंद नहीं किया जाता । व्यापार या उद्योग और किसान सघ, यहाँ तक कि मजदूर सघा से भी राजनैतिक मोलभाव या समझौता करने को उचित नहीं समझा जाता । यदि इन वग विशेष के संगठनों को राजनीति में भाग लेना हो तो वे राजनैतिक दला के जरिये ले, स्वतंत्र रूप से नहीं । तीसरे, परिवर्तन और आधुनिकीकरण का माध्यम सरकार है, इसलिए विभिन्न हित या वग राजनैतिक दला या गुटा के जरिए ही सरकार को प्रभावित कर सकते हैं । इनका यह अर्थ नहीं कि सरकार या राजनैतिक दल से विभिन्न वर्गों का सबंध स्थापित करने वाली मध्यस्थ संस्थाओं का यहाँ कोई स्थान नहीं । उल्टे ऐसी संस्थाओं की बहुत बड़ी संख्या है । मगर ये सब राजनैतिक ढंग से काम करती हैं । पश्चिम की भांति वग या संगठन के ढंग से नहीं (इसीलिए जहाँ पश्चिम में राजनैतिक मागा के लिए आर्थिक कारवाई या हड़ताल की जाती है वहाँ भारत में आर्थिक शिकायतें व मागें राजनैतिक हड़ताल या प्रदर्शनों के जरिए प्रकट की जाती हैं ।)<sup>५३</sup>

(६) इससे नुकसान भी होता है । क्योंकि आर्थिक मागा को तभी माना जाता है जब वे राजनैतिक ढंग से उठायी जाए, इस कारण ये आंदोलन उग्र और हिंसात्मक रूप ले लेते हैं । जिन हितों को कोई राजनैतिक दल उठाने को नैयार नहीं होता, वे प्रत्यक्ष कारवाई और उपद्रव करने लगते हैं । यह खुला प्रश्न है कि सरकार के लिए अधिक सुभीता इसमें है कि कभी कभी उपद्रव हो जाए, या इसमें कि वग संगठना का बल बड़े जोर से सरकार से सौदा कर और उसे अपनी माग मानने को बाध्य करें और इस प्रकार उस पर स्याई बोझ बढ़ाएँ ।<sup>५४</sup> लगता है कि भारत में पहले ही रास्ते को कम अनिष्ट कर समझा जाता है ।

### विरोध का स्थान

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भारत की राजनीति में विरोध के आंदोलना का एक खास स्थान है । यह विरोधी ससद या विधान सभा आदि के जरिये नहीं

<sup>५३</sup> राल्फ जेम्स, 'पार्लियामेंट में डेट डेट यूनिफ़ॉर्म इन इण्डिया' फार ईस्टर्न सर्वे ३७, नं. ३, मार्च १९५८ ।

<sup>५४</sup> देखिए माइरन वीनर - 'द पार्लियामेंट आफ स्वेडिशमिटी, पब्लिक प्रेशर ऐंड पोलिटिकल रेस्पॉन्स इन इण्डिया' (शिकागो, १९६२) ।

सीधे आदोलन जर्थात् हड़ताल, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, बंद, घेराव, घरनो आदि का रूप ले लेता है। इनमें से अनेक स्वतंत्रता आदोलन के युग की विरासत है। ये आदोलन कभी राज्य सरकार के विरोध में होते हैं तो कभी के द्र सरकार के और कभी किसी विशेष अधिकारी या प्रबंधक वर्ग के विरुद्ध। इनका आधार कोई खास शिकायत होती है, जैसे राशन पूरा न मिलना, कम मजदूरी या सरकारी दफ्तर, कारखाना या कारखानों में काम की खराब स्थिति आदि। अक्सर वे अपने आप गुरू हो जाते हैं फिर इनको छात्र संघ, ट्रेड यूनियन, राजनैतिक दल और कभी कभी स्थानीय और राज्य सरकारों का भी समर्थन मिल जाता है। इसका एक नाटकीय उदाहरण प्रधानमंत्री की बोटी पर केरल के कम्युनिस्ट मंत्रियों का घटना था। अधिकांश ये आदोलन कांग्रेस सरकार के विरुद्ध होते हैं, यद्यपि कांग्रेस ने भी भिन्न दलों की सरकारों के खिलाफ इस प्रकार के आदोलन चलाए हैं और प्रमुख कांग्रेसिया ने इनको उचित बताया है। ५५

ऐसे प्रदर्शन या आदोलन को यहाँ अनुचित नहीं समझा जाता। यद्यपि जब ऐसे आदोलन उग्र या हिंसात्मक रूप लेने लगते हैं तब बंगाल और केरल की वामपंथी कम्युनिस्ट सरकारें भी इन के विरुद्ध कारवाइ करने में नहीं हिचकिचाती मगर अपक्षा यह भी जाती है कि इनके खिलाफ ज्यादा कड़ाई न करती जाए और जहाँ ऐसा होता है, वहाँ पुलिस व अधिकारियों की कड़ी निंदा की जाती है और अक्सर इन की अदालत या मजिस्ट्रेटी जांच कराई जाती है। यह साधारणतः स्वीकार किया जाता है कि स्वतंत्र देश में इस प्रकार के प्रदर्शन व आदोलन का स्थान है और इनको दबाने या सभालने में समय से काम लिया जाना चाहिए। ५६ इन आदोलनों का कड़ाई से दमन किया जाए ऐसा कहने वाले लोग कम हैं।

५. ही गुप्तवाच्यम्, अथवा तमिलनाडु कांग्रेस कमेटि ने द्रमुक सरकार के विरुद्ध १० ००० आदर्शियों के प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। उन्होंने इस आधार पर इसे उचित बताया था कि हमने जनता को अपना शिकायतों को दूर कराने के लिए आदोलन करने का शिक्षा मिलती है। उनका कहना था कि अमेरिका जैसे उन्नत देश में रडियो टी वी के प्रचार के बजाय साधन है, किंतु भारत में जलून आर प्रदर्शन ही सामूहिक अभि यक्ति के उपाय हैं। हिंदू बाकला रिव्यू, अगस्त १२, ६८।

५६ भारत में पुलिस को नागरिक जिम्मेदारी की शिक्षा देनी जरूरी है। दूसरे राजनैतिक आदोलनों और गुप्त तत्वों के कारण उस पर भारी दायित्व भी आ गया है। पुलिस में भी इसमें क्षोभ हुआ है और उन्होंने भी आंग्ल और हड़ताल का सहारा लिया है। सन १९६९ के अगस्त में पश्चिम बंगाल सरकार की कुछ कारवाइ से क्षुब्ध होकर पुलिस वालों ने विधान सभा पर हत्या कर दिया था। सब मिला कर पुलिस ने दंगा प्रस्ताव के अवसरों पर काफी धारण से काम लिया है, परंतु उनकी भी कुछ शिकायतें हैं जिन पर ध्यान न दिये जाने पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। भारताय पुलिस व्यवस्था का बहुत अच्छा अध्ययन डेविड एच बेन्सी ने अपनी पुस्तक 'द पुलिस ऐंड पोलि डेवलपमेंट इन इंडिया' (प्रिन्सटन १९६९) में किया है।

ये आदालत बहुत खतरनाक रूप नहीं ले पाते इसके कई कारण हैं। एक तो देश इतना बड़ा है कि सारे देश में उग्र आंदोलन सगठित करना कठिन है। दूसरे सरकार के हाथ में इतनी शक्ति है कि वह इन का काबू स बाहर न होने दे (सरकार इनका खाना न चाहे, जैसे उगाल में १९६७ और बाद में १९६९ में हुआ, ता खान और है)। तीसरे, देश से लोग आम तौर पर हिंसा को पसंद नहीं करते। इस कारण जा दल या नेता हर बात पर आदालत छेड़ दिया करते हैं, उनसे लाभ विरक्त हो जाते हैं। फिर भी घेराव, बंद या घरेलू भारतीय राजनीति से बहिष्कृत नहीं किए जा सकते।

कांग्रेस के असंतुष्ट वग आर मित्र राजनैतिक दलों के भी सत्ता में आने से और खास तिकायता या भ्रमला का लेकर आंदोलन होने से कांग्रेस पर भी बड़ा दबाव पड़ा और इसका एक नतीजा यह हुआ कि राजनीति में वास्तविक प्रश्न पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। नेहरूजी के जमाने में हवाई बातें ज्यादा होती थीं और आयाजन को जादू की छड़ी समझा जाता था, मगर एक ओर कांग्रेस के अंदर और बाहर विरोध बढ़ा और दूसरी ओर आर्थिक और विशेषकर कृषि के क्षेत्र में सरकार का काम असंतोषजनक रहा। इस के साथ ही देश की राजनीति में गांव के लोग का जार बढ़ा और उन में स नए नेता सामने आए। इन सब बातों के कारण सरकार से कुछ ठोस काम कर दिखाने की मांग बढ़ी, और सत्ताहल नेताओं को भी डर हुआ कि सत्तापजनक काम न करने का नतीजा चुनाव के समय भुगतना पड़ेगा। इसलिए जब सरकार के काम पर ज्यादा कड़ी नजर रखी जाने लगी है।<sup>५७</sup>

### बौद्धिक वग में शक्ति

जिस प्रकार समूह सरकारें टूटती रही हैं और दल बदल की प्रवृत्ति बढ़ी है तथा सरकार की बचनी और करनी में जितना अंतर है और जनता के असंतोष का दवाने के लिए सरकार को जिस प्रकार दमनकारी कार्रवाई करनी पड़ी है इसको देखकर देश के कुछ बौद्धिक वर्गों को यह शका होने लगी है कि बालिग मत-धिकार पर आधारित लोकतन्त्र की यह प्रणाली देश की आर्थिक समस्या सुलझाने और एकता कायम रखने में समर्थ हो सकेगी या नहीं। अभी ऐसे लोग कम हैं, जो लोकतन्त्र का हटाकर सैनिक शासन स्थापित होने का स्वागत करें। मगर कुछ लोग इस के पक्ष में हैं कि वर्तमान मजिदडली शासन प्रणाली के बजाय अमेरिका या फ्रांस जैसी राष्ट्रपति शासन की प्रणाली देश के लिए ज्यादा उपयोगी होगी। कुछ लोग 'पश्चिमी' ढंग की प्रणाली और पार्टियाँ या दल प्रणाली में बहुत विरक्त हो गए हैं। देश में हमेशा से एक उच्च शिक्षित, स्वतंत्रता प्रेमी वर्ग रहा है जो यह

<sup>५७</sup> देखिए - अध्याय ९।



कहता है कि सरकार के बजाय प्रतिभाशाली निंदल या दलपदी से अलग व्यक्ति या की सरकार हानी चाहिए। दूसरा वग है जो जनता का सीधा शासन चाहता है। वास्तव में इन विचारा के पीछे गदी राजनीतिक दलपदी से विरक्त और शुद्ध, ईमानदार शासन की इच्छा है। इस प्रकार की बात करने वाले बड़े आदर्शवादी और सम्मानित व्यक्ति हैं, किन्तु न तो उनके पीछे कोई सगठन है, न उनका कोई राजनैतिक प्रभाव है। ५८

देश में राजनैतिक विरोध और आलोचना करने वालों का बहुत बड़ा दल है। किन्तु वे सगठित नहीं हैं। वे वर्तमान प्रणाली की टीका-टिप्पणी करते हैं, किन्तु कोई विकल्प नहीं प्रस्तुत करते। वे या तो सरकारी या सरकार-विरोधी दला में शामिल होते हैं और अपने विचारा और आलोचनाओं से उन्हें प्रभावित करते हैं और उन्हें अपनी रीति-नीति सुधारने का प्रेरित करते हैं। इस से नुकसान यह होता है कि विराध जोर अमतोष दलों या प्रतिनिधि संस्थाओं के माध्यम से न प्रकट होकर कभी कभी गडबडी जोर अस्थिरता पैदा कर देता है। दूसरी ओर लाभ यह है कि राजनीति में नए तत्व जोर नए रक्त के लिए रास्ता खुला रहता है, व्यवस्था में ग्रहणशीलता बनी रहती है और राजनीति बहुत गरम नहीं होने पाती। मूल प्रश्न यह है कि जैसे जैसे अब तक उपेक्षित या व्यवस्था के बाहर रह चुके राजनीति में प्रवेश करते हैं और सरकार का साविका ठोस समस्याओं से पड़ता है वैसे वैसे वर्तमान प्रणाली नए वर्गों को अपने में खपा सकेगी और उनकी निष्ठा प्राप्त कर सकेगी या राजनैतिक छद्मोत्थरण और वग मध्यम स्तर हागा।

---

५८ इनमें सब में सम्मानित पुराने क्रांतिकारी और समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण हैं जो अब 'संवाद' विचारधारा के समर्थन हो गए हैं और आमस्वरान पर आधारित लोकतंत्र चाहते हैं। जयप्रकाश बाबू ने नागालैंड कश्मीर और भारत-पाक विवादों में मध्यस्थता की भी कोशिश की। उनके विचार उनका पुस्तक 'प्ली फार रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पोलिटिक्स' में देखें।

## सामाजिक ढाचा

हमने देखा कि भारतीय लोकतन्त्री प्रणाली का प्रादुर्भाव समाज के आधुनिकतावादी प्रमाण में हुआ और यही से विकसित होकर जनसाधारण में विस्तृत हुआ। देखना यह है कि यह प्रणाली किस प्रकार परंपरागत समाज में जड़ पकड़ती है। इस समाज की जड़ें उस पुरानी सम्यता में हैं, जिसमें विविध जीर विभिन्न तत्त्वों, वर्गों और जातियों का समावेश हुआ है और इसके आचार-विचार और मूल्यों की अपनी परंपरा है। दूसरी ओर ससदीय शासन, तथा सत्तास्व जीर विरोधी दला का द्वंद्व आधुनिक युग की चोजें है। इन दोनों का मेल कैसे होगा ? यह ऊपर से थोपी हुई विदेशी और विजातीय व्यवस्था है, या दोनों में समन्वय के आसार दिखाई पड़ रहे हैं ? सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इस नई राजनीतिक प्रणाली और परंपरागत जाति प्रथा की एक दूसरे पर क्या क्रिया-प्रतिक्रिया हुई है ? इस विषय पर विस्तार से विचार करना जरूरी है।<sup>१</sup>

### प्रचलित धारणाएँ

जाति और राजनीति विषय पर विचार करते समय अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या जाति प्रथा खतम हो रही है ? इस प्रश्न के पीछे यह धारणा है कि जाति और राजनीति परस्पर विरोधी सस्थाएँ हैं। ज्यादा सही सवाल यह होगा कि जाति-प्रथा पर राजनीति का क्या प्रभाव पड़ रहा है और जातिपाति वाले समाज में राजनीति क्या रूप ले रही है। जा लोग राजनीति में जातिवाद की शिकायत करते हैं वे न तो राजनीति के प्रवृत्त स्वरूप को ठीक समझ पाए ह न जाति के स्वरूप को (कुछ लोग जाति-प्रथा और राजनीति दाना को खतम करना चाहते हैं)। राजनीति की प्रक्रिया से प्रचलित सस्थाओं के जरिये जनता का समन्वय या स्वीकृति प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। चूँकि देश की जनता जातियों

<sup>१</sup> इस अध्याय का प्रारम्भिक रूप रचना शोठारा के लेख 'कास्ट इन इंडियन पालिटिक्स' (नई दिल्ली - १९६९) का भूमिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

मे सगठित है, इसलिए राजनीति को जाति-संस्था का उपयोग करता ही पड़ेगा। अतः राजनीति में जातिवाद का अर्थ जाति या राजनतिकीकरण मात्र है। जाति को अपने दायरे में खींचकर राजनीति उसे अपने काम में लाने का प्रयत्न करती है। दूसरी ओर राजनीति के द्वारा जाति या विरादरी को देश की व्यवस्था में भाग लेने का मार्ग मिलता है। राजनैतिक संगठन और जातीय संगठन दोनों के असली पात्र वे लोग हैं जो सत्ता और अधिकार चाहते हैं। राजनैतिक नेता सत्ता प्राप्त करने के लिए जातीय संगठन का उपयोग करते हैं। जातियों के रूप में उनको बना बनाया संगठन मिल जाता है जिससे राजनैतिक संगठन में आसानी होती है। जहाँ और प्रकार के समूह हों वहाँ राजनैतिक लोग उनका भी उपयोग करते हैं और इस क्रम में वे पुराने संगठन या संस्थाओं को नया रूप देते हैं। इसी प्रकार जाति संस्था का भी रूप बदल रहा है।

सामाजिक और राजनैतिक विचारका का एक बग है जो राजनीति का ऐसा अस्त या साधन मानता है जिसके जरिये कोई बग या जाति अपनी प्रधानता और शक्ति को कायम रखने का प्रयत्न करता है।<sup>१</sup> वह यह भूल जाता है कि राजनैतिक शक्ति या प्रभुता के द्वारा भी आर्थिक और सामाजिक ढाँचे को बदला जा सकता है। ये विचारक अपनी एक धारणा बना लेते हैं और राजनैतिक व आर्थिक प्रवृत्तियों के घात-प्रतिघात से होने वाले परिवर्तनों की उपेक्षा कर देते हैं। जहाँ जाति स्वयं एक राजनैतिक तत्त्व का रूप धारण कर लेती है वहाँ यह प्रश्न बेकार हो जाता है कि जाति राजनीति का उपयोग (अपनी प्रधानता बनाए रखने का) कर रही है या राजनीति जाति का उपयोग कर रही है।

दूसरी ओर कुछ ऐसे विचारक हैं जो जाति-संस्था के बारे में कोई दुराग्रह नहीं रखते, किन्तु वे भी राजनीति के द्वारा जाति-संस्था के कार्यापालन होने की बात करते हैं। एक अमेरिकन विचारक ने इसे जाति का लोकतन्त्री अवतार कहा है।<sup>२</sup> ये सब विचारक जाति और राजनीति को परस्पर विरोधी तत्त्वों के रूप में देखते

१ केवल भारत और पश्चिम के मार्क्स शास्त्रा ही नहीं बल्कि सोवियत रूस, चीन और पूर्वी यूरोप के कम्युनिस्ट राजनीति के बारे में यह गलत धारणा नहीं रखते, अमेरिका के कुछ समाजशास्त्रा भी यहाँ सोचते हैं। यथा बैरिंगटन मूर जर्मन - सोशल ओरिजिन ऑफ डिक्टेटरशिप ऐंड डेमोक्रेसी (बोस्टन १९६७)। भारत में राजनीति को बग या जाति की प्रतिष्ठा मानने वाले विचारकों में मुत्तार - ए. आर. देसाई - सोशल बकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म।

२ लायड अंडर वुड्स - 'द माउन्टी ऑफ ट्रेडिशन - द डेमोक्रेटिक इनकारनेशन ऑफ कास्ट इन इंडिया' - द अमेरिकन सोशल रिव्यू-दिस १९६५। जाति और राजनीति सम्बन्धों के विरोधी स्वरूपों की ओर इंगित लायड वुड्स और सुजन हेनर वुड्स ने अपने पहले अपने निबंध 'द पोलिटिकल राउंड ऑफ इंडिया कास्ट असोसिएशन्स - पैसि अन्ड सिलेब ३३ से १, मार्च १९६० में किया था। इन लेखकों का विरोध अन्य विचारकों से ज़ादा सही है। हमारा कहना यही है कि उन्होंने अतिशयोक्ति की है।

है। व यह नहीं समझ पाते कि यहाँ राजनीति और जाति में पूरा छद्मीकरण कभी नहीं हुआ और भारत में जो परिवर्तन हो रहा है, उसका यह अर्थ नहीं है कि नई लानतनी प्रणाली के रूप में पुरानी जाति-प्रथा और ऊँची जातियाँ की प्रधानता और नीची जातियाँ की अधीनता का ढाँचा ही कायम है अथवा पुरानी जाति-प्रथा का स्थान नई राजनैतिक प्रणाली ने ले लिया है। जाति-प्रथा और ऊँच-नीच की धारणा में कुछ परिवर्तन हुआ है, जैसे अब जाति की ऊँचाई या निचाई छुआछूत के ऊपर उतनी निम्न नहीं रही और पुरानी जजमानी प्रथा भी टूट रही है, किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इससे जाति की प्रथा टूट रही है। केवल सामाजिक विचारों में कुछ परिवर्तन हुआ है।

जाति का राजनीति से क्या संबंध है, इस विषय पर विचार करते समय हम इस बात पर ध्यान देंगे कि राजनैतिक कार्य में इसका कितना और किस प्रकार हाथ है न कि इस बात पर कि राजनैतिक कार्य में भाग लेने से जाति प्रथा में क्या परिवर्तन हुए हैं। यद्यपि इस प्रश्न की हम बिल्कुल उपेक्षा भी नहीं कर सकते, क्योंकि राजनैतिक उद्देश्य से जातियों के सघ आदि कार्य हुए हैं, और इस प्रकार राजनीति ने उनके ढाँचे को प्रभावित किया है।

### जाति का राजनैतिक रूप

हमें जातिप्रथा के तीन रूपों पर ध्यान देना है। एक है इसका लौकिक रूप। जातिप्रथा की कुछ बातों पर सबका ध्यान गया है — जैसे जाति के अंदर विवाह, छुआछूत और रीतिरिवाजों के द्वारा जाति की पृथक् इकाई को कायम रखने का प्रयत्न। लेकिन इस बात को उपस्था कर दी जाती है कि जातियों में आपस में प्रतिद्वंद्विता भी रहती है और वे लगातार अपनी प्रतिष्ठा और पद बढ़ाने का भी प्रयत्न करती रहती हैं।

जाति के लौकिक संगठन के दो रूप थे — एक शासकीय रूप यानी जाति की ओर गाव की पचायत और चौधराहट। दूसरा रूप राजनैतिक था यानी जाति की आंतरिक गुटबंदी और अंग जातियों से गठजोड़ और प्रतिद्वंद्विता। इन संगठनों का बलवर्धन या बलह्रास इस बात पर निर्भर था कि स्थानीय नेताओं के समाज की वैद्वस्थ सत्ता से किस प्रकार के संबंध थे। घम, व्यवसाय और प्रदेश के आधार पर जातियों की स्थिति बनती या बिगड़ती थी। अब भी इन बातों का महत्त्व है, यद्यपि सदन बदल गया है। जाति या संप्रदाय को किसी राजा से संबंध रखना पड़ता था और स्थानीय मामलों का प्रबंध जाति या गाव की पचायत स्वयं करती थी। अब राजा के स्थान पर राष्ट्रीय सरकार है और जातीय पचायतों के बजाय स्थानीय और प्रांतीय विधायक सभाएँ हैं। यह परिवर्तन एकदम से नहीं बल्कि क्रमशः हुआ है।

अनेक स्थानों में पहले ब्राह्मणों ने अंगरेजी शिक्षा को अपनाया और नई प्रगति-  
निक और राजनैतिक व्यवस्था से लाभ उठाया। धीमे धीमे शिक्षा का और बाट  
का प्रसार और लोगों में भी हुआ। कुछ प्रदेशों में ब्राह्मणों के बजाय अन्य जातियाँ,  
मुख्यतः जमींदार और बड़े किसान वर्ग प्रबल थे और नई राजनैतिक व्यवस्था का  
लाभ उन्होंने उठाया और उनके जरिये अन्य लोगों में उसका प्रसार हुआ। इसलिए  
देश की राजनीति पर किसी एक जाति का प्राधान्य नहीं हो सका।<sup>४</sup> कुछ प्रदेशों  
में जैसे गुजरात और मारवाड़ में जैन, वज्जव जैसे संप्रदायों के हाथ में आर्थिक शक्ति  
थी, इसलिए नई व्यवस्था को पहले इन्होंने ग्रहण किया।

अंग्रेजी शासन के पहले भी जातियों के नए संबंध या जोड़ बनते थे और अपक्ष  
वृत्त नीची जातियाँ अपना व्यवसाय या स्थान घटलती थी और ऊँची जातियों में  
मिल जाया करती थी। इसका एक जरिया था अनुलोम विवाह यानी नीची जाति  
या कुल की कन्या का अपने से ऊँची जाति में विवाह। उदाहरण के लिए सौराष्ट्र  
की पशुपालक जाति गुजरात में आकर खेती करने वाली कुनबी जाति बन गई और  
अपनी लड़की अपने से ऊँची पाटीदार जाति में देने लगी। इस संबंध से उसका पद  
भी बढ़ा। इसी तरह सौराष्ट्र की माची जाति गुजरात में आकर दर्जी जाति बन  
गई। एक और उदाहरण है, महाराष्ट्र की देशमुख जाति का, जो मालगुजारी की  
वसूली और भूमि व्यवस्था से संबंधित होने के कारण अन्य मराठा जातियाँ स कुछ  
ऊँची हो गईं। इस प्रकार नई उपजातियों के जन्म और अनुलोम विवाह की प्रथा  
के कारण जातियों के ढाँचे में परिवर्तन होते रहे। इससे एक ओर नई जातियों की  
संख्या बढ़ी तो दूसरी ओर जातियों का तीक्ष्ण अंतर कम हुआ। अनुलोम-प्रतिलोम  
विवाह के आधार पर जातियों की तुलनात्मक ऊँचाई-निचाई निर्धारित होती रही  
और इससे बाद में राजनीतिक और लौकिक क्षेत्र में जातियों के परस्पर संबंध  
बनने और संगठन कायम होने में मदद मिली।

जाति का दूसरा पहलू व्यक्ति को समाज से बांधने का है। जातिप्रथा न केवल  
जन्म के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति का समाज में स्थान नियत कर देती है इससे ऊँचे  
से ऊँचे से लेकर नीचे से नीचे व्यक्ति का अपने समाज में लगाव पैदा हो जाता है  
और वह आपस में भी एक दूसरे से बंधा रहता है। अवश्य ही व्यक्ति का लगाव  
और निष्ठा अपने छोटे से समूह, विरादरी या जाति से रहती है। बड़ी निष्ठाओं  
की प्रेरणा भी उस जाति के ढाँचे से ही होती है। जातिप्रथा पर लाकतबी राष्ट्रीय  
निर्माण के प्रभाव को समझने के लिए उपयुक्त बात को ध्यान में रखना चाहिए।  
लोकतंत्र के अंदर विभिन्न समूहों में शक्ति के लिए प्रतिद्वंद्विता होती है, साथ ही

<sup>४</sup> देखिये—कोठारी संपादित - 'कास्ट इन इण्डियन पॉलिटिक्स' में कैरोलान इलियट का  
आंध्रप्रदेश के बम्मा और रेड्ड जातियों पर निबंध।

<sup>५</sup> देखिए—शरावता कर्वे—'हिंदू सोसाइटी-एन इंट्रोडक्शन' (पूना, दक्कन कॉलेज, १९६१)।



या सत्सृतीयकरण की है और दूसरी पारचात्यीकरण और लौकिकीकरण की ।<sup>७</sup> आर्थिक उन्नति, राजनैतिक एकता और बुद्धिवाद की सावजनीन प्रवृत्तियों के प्रभाव से अक्सर अब्राह्मण जातियाँ ब्राह्मणों की नकल करनेकी प्रवृत्ति का छोड़ देती हैं और अन्य अब्राह्मण जातियाँ से मिलकर राजनैतिक व सामाजिक अधिकार प्राप्त करने और अपनी स्थिति सुधारने की चेष्टा करती हैं । इसके अलावा कभी कभी कोई जाति अपनी उच्चता सिद्ध करने के लिए अपना संप्रदाय पौराणिक पुरुषों से जोड़ने का प्रयत्न करती है जैसे गुजरात के पाटीदार, बंगाल के माहिष्यजोर राजस्थान आदि के जाट । कुछ इराक़ में जहाँ ब्राह्मणों ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का नेतृत्व नहीं किया, अधिकार सीधे कुछ शक्तिशाली कृषक जातियों के हाथ में आए । इसलिए यहाँ ब्राह्मणीकरण या अब्राह्मणवाद की जरूरत नहीं पड़ी और ये जातियाँ सीधे आधुनिक राजनीति में भाग लेने लगी और इस प्रकार इन्होंने समाज में भी उच्च स्थिति प्राप्त की । जाय प्रदेश और बिहार इसके उदाहरण हैं । यहाँ राजनीति जातियों की गुटबंदी या गठजोड़ पर आधारित है ।

सत्सृतीयकरण की प्रवृत्ति कुछ सामाजिक तनाव और अस्थिरता भी उत्पन्न करती है । जैसे यहूदी और निग्रो गोरे या यूरोपीय लोगों की नकल करते हुए भी मन में उनके प्रति विरोध ईष्या या नफरत का भाव रखते ह, उसी प्रकार छोटी जातियाँ भी ब्राह्मणों के प्रति रखती हैं । दूसरे, जब तक उनका उच्च पद का दावा स्वीकार नहीं कर लिया जाता, उनकी स्थिति सदिग्ध रहती है । अक्सर ऊँची जातियों की ओर से उनका विरोध भी होता है । वास्तव में हिंदू समाज में प्रतिष्ठा की आकांक्षा बड़ी क्षात्रकारी और दुपदायी सिद्ध होती है ।

फिर भी छोटी या नीची जातियों के ऊपर चढ़ने की यह क्रिया जारी रहती है और यह हिंदू समाज की शक्ति की द्योतक है । ऊपर चढ़ने में सफलता सामाजिक, राजनैतिक या आर्थिक क्षेत्र में सफलता पर निर्भर होती है । वास्तव में हिंदू समाज में लौकिक शक्ति के आधार पर जातियों की स्थिति उठती और गिरती रहती है और इस प्रकार उसमें परिवर्तनशीलता बनी रहती है ।

इस प्रकार जातिप्रथा की लौकिक, सामाजिक और भावनात्मक परंपरा ने इसे आधुनिक प्रभावों और परिवर्तनों को ग्रहण करने योग्य बनाया ।

७ एम एन श्रीनिवास ने ये नाम दिए हैं । सत्सृतीयकरण में छोटी जातियाँ सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों के रानिस्त्रियों की नकल करने लगती हैं । देखिए—श्रीनिवास 'सोशल चेंज इन मायन इंडिया' (वर्ष १९६६) तथा 'द कोडेमिव रोल आफ सत्सृतीयकरण और पारचात्यीकरण' (दिएन यूनिवर्सिटी १९६९) । लौकिकीकरण की प्रवृत्ति के अंदर सत्सृतीयकरण और पारचात्यीकरण दोनों प्रवृत्तियाँ जिस प्रकार दब जाती हैं, उनके लिए देखिए—'कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स' । श्रीनिवास की पुस्तक में भी एक अध्याय लैस्त्रियकरण पर है ।

## आधुनिकता का प्रभाव

भारतीय समाज पर आधुनिकता का प्रभाव धीरे धीरे पड़ा। नई शिक्षा, सरकारी नाकरिया, बालिग मताधिकार और व्यवसाय के विस्तार का प्रभाव पुरानी जातपात वाली समाजव्यवस्था पर पड़ा। नई शासनव्यवस्था के अन्तर्गत सरकारी नौकरी, व्यापार, डाक्टरों, वकालत आदि व्यवसाय तथा प्रतिष्ठा व अधिकार के जो अवसर प्रसन्न हुए, उनका लाभ समाज के शिक्षित और प्रभु वर्गों ने उठाया और उनमें आधुनिकता का प्रभाव हुआ। नए सामक वर्ग ने भी स्थानीय भावनाओं का आदर किया और ऊँची जातियों के प्रभाव का स्वीकार किया और उनको राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्था में भाग दिया। इस प्रकार पुराना समाज नई राजनैतिक व्यवस्था के करीब आया।

इस प्रक्रिया को तीन चरणों में बाँटा जा सकता है। सबसे पहले शक्ति और प्रभाव को स्वयं समाज की प्रतिष्ठित या जमी हुई जातियाँ तक सीमित रही। 'शुरू में नई शिक्षा का लाभ थाड़े में ऊँची बुद्धिजीवी जातियों के लोगों ने उठाया। ये जातियाँ परंपरा से विद्या और मन्त्रों में अग्रणी रही। जहाँ नई शिक्षा और समान प्राप्त होने वाली पदप्रतिष्ठा केवल एक जाति या उपजाति तक सीमित रही, वहाँ अन्य ऊँची जातियों में, जो पहले समाज में प्रतिष्ठित और प्रभावपूर्ण स्थान रखती थी, उनमें प्रति ईर्ष्या पैदा हुई। और इन ऊँची जातियों ने अधिकार और पद प्राप्त करने के लिए अपना राजनीतिक संगठन किया। इससे दो ऊँची जातियों में प्रतिद्वंद्विता खड़ी हो जाती है।' यह प्रतिद्वंद्विता बड़ा नहीं उठती जहाँ प्रतिष्ठित जाति अन्य सब जातियों से बहुत ऊँची होती है या जहाँ अन्य जातियाँ भी अलग अलग क्षेत्रों या स्तरों में प्रतिष्ठित रहती हैं, और इस प्रकार मिल कर शक्ति और प्रभाव का उपयोग करती हैं।

दूसरा जब्याय वह ह जब पद और शक्ति के आकांक्षियों की संख्या बढ़ जाती है और भिन्न जातियों में स्वार्थ के साथ साथ जाति के अदर भी प्रतिस्पर्धी गुट बन

८ 'प्रतिष्ठित या जगह' (इन्स्टीट्यूट) जाति शब्द का प्रयोग हम एक आनिवास ने किया। यह प्रधान (टैमिन) जाति से भिन्न है। प्रधान जाति न केवल राजनैतिक और आर्थिक दृष्टि से ही शक्तिशाली होती है, बल्कि संस्था में भी गांव या इलाके में ज्यादा होता है। ('२ टैमिनेंट कास्ट इन रामपुरा' - अमेरिका पत्रिका, १९५६ फरवरी)। प्रतिष्ठित जाति ऊँची और राजनैतिक रूप से प्रभावशाली होने पर भी संस्था में होती होती है। इन शक्तियों में दृढ़मूलक वर्गक जातियों प्रतिष्ठित होती है वहाँ 'प्रतिष्ठित' और 'प्रधान' का अंतर स्पष्ट नहीं रहता।

९ मद्रास और महाराष्ट्र में ब्राह्मण-अब्राह्मण, गुजरात में बनिया आहवा-पार्श्व और में बम्हा-रेड्डी और केरल में पन्था-नायर द्वंद्व इसके उदाहरण हैं। इस विधा में अन्तर्गत एक जाति के प्रधानता प्राप्त कर लेने पर दूसरे से उभरे द्वंद्व गढ़े हो जाते हैं। जैसे गुजरात में पार्श्व-अब्राह्मण और महाराष्ट्र में ब्राह्मण-अब्राह्मण द्वंद्वों के परिणामस्वरूप नए और पुराने संगठन बन जाते हैं।



जाते हैं।<sup>१०</sup> प्रतिद्वंद्वी नेताओं के पीछे गुट बन जाते हैं। इन गुटों में विभिन्न जातियों के लोग होते हैं। अपना गुट मजबूत करने के लिए उन जातियों की भी सहायता ली जाती है, जो अब तक दायरे से बाहर थी। जाति व्यवस्था की शक्ति और पद का ढाँचा अब ज्यादा जटिल हो जाता है। पारम्परिक आर्थिक साहाय्य जैसे अपने परिजन को काम धंधा या नौकरी दिलाना या विपत्ति में सहायता करना, आश्रय — आश्रित सबंध तथा जातियों के सघ और महासघों का संगठन इस नई व्यवस्था के अंग होते हैं।

जिन इलाकों में जमीन या अन्य आर्थिक आधार पर कई जातियाँ पहले से सबंध रहती हैं या आश्रय-आश्रित सबंध मौजूद रहते हैं, या अनुलोम विवाह का सबंध रहता है जहाँ एक वर्ण की अनेक उपजातियों का आपस में सबंध रहता है, वहाँ राजनीति को बना बनाया रास्ता मिल जाता है और नए जातीय संगठन बनाने की आवश्यकता उतनी नहीं रहती। पहले से बतमान जाति-शृंखलाएँ ज्यों की त्यों राजनीतिक क्षेत्र में आ जाती हैं। दूसरी जातियों से प्रभावशाली लोगों को दल या संगठन में लेने में आसानी होती है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक शृंखला को विस्तार के लिए पहले से बनी शृंखलाएँ मिल जाती हैं, या नई शृंखलाएँ आसानी से बन जाती हैं।

नई राजनैतिक संस्थाओं की स्थापना से जातियों की गुटबंदी और प्रतिद्वंद्विता नए नए रूप लेती है। जिले और प्रांत की राजनीति में प्रभावशाली जातियों में प्रतिद्वंद्विता प्रकट होती है जैसे, आंध्र में कम्मा और रेड्डी, गुजरात में पाटीदार और अनाविल, मैसूर में लिगायत और वोक्कलिंग, तथा मद्रास और बिहार की विभिन्न जातियों में। हर स्तर पर राजनीतिक गुटबंदी और जाति या वर्ण संघों के कारण नए संगठन जन्म लेते हैं। इनके कारण नेताओं और प्रमुख व्यक्तियों का प्रभाव बढ़ता है।

मगर शक्ति और प्रभाव की यह होड़ थोड़ी सी ऊँची जातियों तक ही सीमित रही। छोटी जातियाँ ऊँची या शक्तिशाली जातियों के प्रभाव में बनी रहीं। किंतु दूसरे चरण में प्रतिस्पर्धी नेताओं ने अपना गुट मजबूत करने के लिए नीची जातियों को भी राजनीति में खींचा। चुनाव में समय प्राप्त करने के लिए इन नीची जातियों के प्रमुख लोगों को छोटे राजनैतिक पद और लाभ में कुछ हिस्सा दिया गया। जहाँ इस प्रकार मुखिया को इनाम और पद देकर इन जातियों का समय प्राप्त करना संभव नहीं हुआ, वहाँ विभिन्न जातियों और उप-जातियों में आपसी तिस्पर्धा पैदा कर के, उनका संगठन बनाने की ओर उन संगठनों से मध्यस्थ या

<sup>१०</sup> यह गुटबंदी जाति के अंदर प्रचलित पुराना खानदाना गुटबंदी से भिन्न है। यह नई गुटबंदी लौकिक या राजनीतिक आर्थिक शक्ति के लिए होता है और इसमें अनेक व्यक्तिगत गुट प्रतिस्पर्धी होते हैं।

विचित्रता द्वारा समझीता करने की काशिश की गई। अर्थात् जहाँ कुछ मुखिया को साथ लेने से काम चल गया, वहाँ जनता 'या जाति के' साधारण लोगो की परवाह नहीं की गई। जहाँ यह तरीका नहीं चल सका वहाँ सगठन के नए तरीके निबाले गए। यह भी मंजूर है कि कानावर में ये नवादित नेता आपस में मिल कर पुरानी जाति के नेताओं का अपदस्य कर दें। यह उनकी आर्थिक शक्ति और कुशल सगठन पर निर्भर है। इस के साथ उनमें राजनीतिक चेतना और ऊँची जातियाँ द्वारा छोटी जातियों का शापण व प्रति क्षोभ और अलग अलग जाति के बजाय वग की भावना भी होनी जरूरी है।

यह भी कहना जरूरी है कि राजनीति के इस सामाजिक सगठन में कुछ भिन्न प्रकार के नेतृत्व और सगठन शक्तों की जरूरत है और इस क्रम में अक्सर ऐसी स्थिति आएगी जब नए नेता पुराने नेताओं को या समाज का एक वग दूसरे वग को अपदस्य करेंगे। जैसे राजनीति का प्रथम चरण बौद्धिक जागरण और शहरा में सगठन का था। इस युग में राजनीति और सावजनिक कार्य में ऐसे लोगों की जरूरत थी, जो अगरज अधिकारियों से व्यवहार कर सकें वानूनी बहस मुवाहसल में पटु हों तथा विरोध उद्देश्य के लिए जादालन करने के हेतु सावजनिक वक्ति के लोगो का सगठन कर सकें। ऐसे लोग ब्राह्मण और कायस्थ आदि जातियों में उपलब्ध थे, जिनके पास विद्या और प्रशामन की पुरानी परंपरा थी, और जिन्होंने नई अंगरेजी शिक्षा, कानून और विज्ञान आदि में कुशलता प्राप्त की थी। जब आंदोलन का जन साधारण में प्रसार हुआ तब ऐसे नेताओं की जरूरत पड़ी जो सामूहिक सगठन में कुशल हों। इसलिए पुराने ब्राह्मण और कायस्थ आदि प्रशासनिक जातियों के नेताओं के बजाय व्यवसायी और कृषक जातियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की सहायता बढ़ी। ये नेता सौदा पटाने में कुशल थे, ज्यादा व्यावहारिक थे और अपने वग या जाति के लोगों का नेतृत्व कर सकते थे। अपनी जातियों का सगठन करने में अक्सर ये जात्यभिमान और ऊँची जातियों की प्रधानता के विरोध की भावना का सहारा लेते थे।

ये लोग राजनीति के नए व्यवसायी थे। ये पुराने ऊँची जातियों के राजनीतिक नेताओं से जिन का इलाका ने अपदस्य किया, विचारों में कम आधुनिक थे और पुरानी जातीय भावना से काम लेते थे। परंतु उन में जो व्यावहारिकता, जोखिम उठाने की प्रवृत्ति, सगठनपटुता और आधुनिक शिल्प या टेक्नीक और सगठन की प्रवृत्ति थी। वह उनकी जातिगत विशेषता थी न कि नई सृष्टि या राजनीति से उधार ली गई थी। एक बार जब यह नया सामाजिक वग और नई राजनीति और सगठनात्मक कुशलता आगे आई तब न केवल राजनीतिक प्रवृत्तियाँ ने नया आयाम ग्रहण किया और समाज की अन्य प्रवृत्तियों से अलग हो गई, बल्कि अपना एक स्वरूप और जीवन भी ग्रहण कर लिया। परिवर्तन की यह प्रक्रिया तीसरे

चरण म पूणता पर पहुँची, जब राजनीति का आधार बहुत व्यापक हा गया और जाति के अलावा अन्य बहुत-सी बात भी उस में जा गई ।

प्रभावशाली और प्रतिष्ठित जातियों में फूट और गुटबंदी, दूसरी जातियों से भेद और उनके मुखिया को अधिकार में भाग देने से जातिव्यवस्था में काफी बिखराव आया, फिर भी जाति का आधार बना रहा । यद्यपि इसने राजनैतिक और व्यक्तिगत शक्ति की प्रवृत्ति को भी जन्म दिया । तीसरे अध्याय या चरण में एक ओर राजनैतिक मूल्यों की प्रधानता हुई और जातिपाति से लगाव कम हुआ, दूसरी ओर शिक्षा, नये शिल्प प्रतिष्ठा के परिवर्तित पैमाने और शहरीकरण के कारण समाज में परिवर्तन आया । नई आकांक्षाओं और भौतिक उन्नति की नई धारणाओं का जोर बढ़ा, पुराने परिवार टूटने लगे और लोग कामधंदे के लिए देशांतर जा कर बसने लगे । इस के साथ जातिविरादरी की भावना ढीली पड़ने लगी । सामाजिक व्यवहार अपनी जाति तक सीमित न रहा । राजनीति में भी व्यापकता आई । नई शिक्षा और नये सामाजिक व्यवहार से उत्पन्न होने वाली नई प्रवृत्तियाँ फैलने लगी । देखने में आया कि एक ही जाति के अंदर आर्थिक अंतर या विषमता के कारण अनगण्य पैदा हुआ और जाति का बंधन ढीला पड़ा । यह प्रवृत्ति केरल के एजवा या हरिजना में भी लक्षित हुई । आधुनिकता का एक आवश्यक तत्त्व है, विभिन्न क्षेत्रों और कार्यों का स्पष्ट पथकरण । पहले राजनैतिक, नैतिक और बौद्धिक संचार के कार्य सामाजिक वर्ग या जाति के अंदर ही होते थे अब इन का अलग अलग क्षेत्र बन गया है ।

राजनीति अभी भी प्रभावशाली तत्त्व है परन्तु अब इस को आधुनिकता के एक साधन के रूप में देखा जाता है । इसे जाति को नष्ट करने या उसका स्थान लेने वाली शक्ति के बजाय नए समाज की स्थापना में सहायक के रूप में देखा जाना है । जब राजनीतिक समस्याओं का ढाँचा व्यापक होता जा रहा है, जिसमें जाति की भावना को नया रूप मिलता है और उस का पुराना रोटी-बेटी संबंध का आधार कमजोर हो गया है । दूसरी ओर राजनीतिक प्रवृत्तियाँ ने नए सगठनों और नई निष्ठाओं को जन्म दिया है, जो पुरानी निष्ठाओं का काटती हैं । जाति अब राजनीतिक समर्थन या शक्ति का एक मात्र आधार नहीं रही, यद्यपि राजनीति में इसका अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है । यह एक व्यापक सबंध गृहस्था का अंग बन गई है । काम के विभाजन के हिसाब से हर व्यक्ति की समाज में पदमर्यादा निर्धारित करने पहले जमाने में जातिप्रथा ने समाज को बाँधे और बनाए रखने का काम किया था । आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने के कारण पहले तो जातिप्रथा पर पुनर्वृत्ति की प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ा, बाद में जाति भावना का सामंजस्य हुआ और इसने राजनैतिक सगठन में सहायता दी ।

आधुनिक राजनीति में भाग लेने में जाति की दृष्टि में परिवर्तन हुआ और

उह उन्नति के नए माके मिले। इसके साथ उनको यह भी समझ में आ गया कि आज के युग में केवल जाति और संप्रदाय में काम नहीं चल सकता। जहां जाति बड़ी होती है, वहां भी उसमें एकता नहीं होती। उसमें उपजातियों के भेद होते हैं, और जब सग्या में छाटी होती है, तब तो अपने बल पर वह चुनाव जीत नहीं सकती। फिर यदि कोई मदस्य या उम्मीदवार अपनी ही जाति का पक्ष करता है तो दूसरी जातियाँ उसके खिलाफ हो जाती हैं। इसलिए चुनाव की राजनीति में अनेक जातियों का गुट बनाना पड़ता है। इसमें विभिन्न जातियों में एका होता है। तीसरे, राजनैतिक दल की शक्ति सभी कायम रहती है, जब समाज के सभी प्रमुख वर्ग ज्यों-ज्यों सभी जातियों के लोग उसका समर्थन दे। अन्तु राजनीति में आने के कारण जाति की भावना ढीली पड़ जाती है और अनेक नई निष्ठाओं का उदय होता है। इस प्रकार जाति लोकिा राजनैतिक व्यवस्था का एक अंग बन जाती रही है।

### एकीकरण या समुच्चयन के नए रूप

आजकल राजनीति में जातिवाद और संप्रदायवाद का जोर बढ़ने की शिकायत की जाती है। समाजशास्त्री भी इस भ्रांति में पड़ जाते हैं। ऐसा समझा जाता है कि शिक्षाप्रसार, गृहरो के विस्तार और औद्योगीकरण के कारण संप्रदाय और जाति के जा बंधन ढीले पड़ रहे थे, वे चुनाव की राजनीति के कारण फिर से जोर पकड़ रहे हैं और इससे देश में फूट बढेगी जिससे धमनिरपक्ष लावनन का ढाचा खतर में पड़ जाएगा। इसके समर्थन में उदाहरण दिया जाता है कि किस प्रकार विभिन्न राजनैतिक दल संप्रदाय और जाति के नाम पर बाट लेने की कागिश करते हैं। इसमें शक नहीं कि ऐसा किया जाता है, किंतु इससे जो निष्पन्न निकाला जाता है, वह उपयुक्त नहीं। वास्तव में जाति और राजनीति के मिश्रण से दूसरे ही परिणाम निकलते हैं।<sup>११</sup> बजाय राजनीति पर जाति के हावी होने के जाति का राजनीतिकरण हो जाता है। राजनीति ने जाति को लीक से हटा कर नया सद्भन दे दिया है, जिसमें उसका पुराना रूप बदल रहा है। जब किसी विशेष जाति को ही राजनैतिक सत्ता का अधिकारी नहीं माना जाता इसलिए प्रतिद्वंद्वी दला का उम्मेदवार चुनने में यह देखना पड़ता है कि किम जाति का कितना सख्या बल है, किस जाति में कितने गुट हैं, उसका आर्थिक सवध किन जातियों से है आदि। यह बात किसी भी राजनैतिक पद्धति और किसी भी सामाजिक व्यवस्था के लिए

११ इसके विपरीत दृष्टिकोण के लिए और सामाजिक एकीकरण में जाति का भूमिका के विषय में देखें - गुरनात मिन्हा, 'कास्ट एन इन्डिया' इन्स एसेन्शल पेन्स आफ सोशियो - कल्चरल इन्वेस्टिगेशन । एगोना ड रियूक संपादित - 'कास्ट ऐंड रेस कम्पेरेटिव अप्रोचेज' (लंदन - १९६७)।

स्वाभाविक है। जाति का विचार उस अवस्था में ज़रूरी नहीं था, जब राजपूत कुछ विशिष्ट जातियाँ के लिए सुरक्षित होत थे। अब राजनैतिक अधिकार और पद सब जातियों के लिए खुल गए, इसलिए राजनीति में अर्थ जाना व साथ जाति का विचार भी आ गया। हरल्ड गोल्ड के शब्दों में — राजनीति का आधार होने के बजाय, जाति उसको प्रभावित करने वाला एक तत्त्व है।<sup>१२</sup>

वास्तव में यह भी कहा जा सकता है कि जाति के बंधन का स्वीकार बल और राजनीतिक सौदवाजी और गठबंधन में उनकी सहायता लेने के कारण उसका देश की राजनैतिक व्यवस्था में स्थान देना तथा उसे राजनैतिक संगठन का साधन बनाना आसान हो गया। अगर ऐसा न करके उनकी उपेक्षा की जाती और उनका मान को स्वीकार किया जाता तो राजनैतिक संगठन में बाधा पड़ती। स्वतन्त्रता के पहले कांग्रेस ने इसी तरह मुसलमानों के अपने समाज के प्रति लगाव को महत्व नहीं दिया था, और यह मान लिया था कि राष्ट्रीय भावना जातीय और साम्प्रदायिक भावना से अलग बलवती है उसकी यह भूल सिद्ध हुई। आधुनिकतावादी नेता जातिपाति पर भले ही नाक सिक्काड़ें परंतु इसके द्वारा राजनैतिक शक्ति उन वर्गों या समूहों के हाथ में पहुँच सकी जो जब तक उससे वंचित थे।

इस अध्याय में हमने सामाजिक राजनैतिक संगठन की बड़ी पचीदा प्रक्रिया का वर्णन किया है। इसके दो रूप हैं। पहले रूप में उच्चवर्ग के नेता सामने आते हैं। भिन्न भिन्न जातियों के हाते हुए भी इनके राजनैतिक या लौकिक विचार एक स होते हैं। ये समाज के उच्च या प्रतिष्ठित वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वभावतः ये वर्ग आधुनिकता को पहले ग्रहण करते हैं। इस बीच समाज के साधारण या कम उन्नत वर्गों को धीमे धीमे नए विचारों और नई बातों को अपनाने का मौका मिलता है।

दूसरे रूप में लौकिक या राजनैतिक उद्देश्यों से जाति अपना संगठन करती है। जैसे जाति विशेष के बलब छात्रावास आदि संस्थाएँ, पूरे प्रांत या भाषा क्षेत्र के जातियों के सम्मेलन या संस्थाएँ, तीसरे एक—से सामाजिक स्तर या वर्ण की विभिन्न जातियों के संघ या एक खास प्रयोजन के लिए विभिन्न जातियों का एक संघ। यह विशेष उद्देश्य या प्रयोजन ही इन संघों को विशुद्ध जातीय संघों से पृथक् करता है।<sup>१३</sup> यह प्रयोजन आर्थिक या शिक्षा संबंधी भी हो सकता है या यह भी हो

१२ देखें इसकी — 'बैजिंग पोलिटिकल डिरेक्टरी इन रूलिंग श्रियन सोमाइन्स', एक ऐंड पालि वावर्ली २, स ३३-३५ विशेषक, अगस्त १९६७।

१३ जातीय संगठनों के बारे में काफ़ी साहित्य संसार हो रहा है। रडारफ़ का 'द पोलिटिकल रोल ऑफ़ श्रियान कास्ट अमोसिएशन' अभा भी इस विषय का सबसे अच्छा निबंध है। जाति-संगठनों के बारे में और देखें 'कास्ट इन इण्डिया पालिटिक्स' में रचना कोठारी और मधुकेश [ १९६४ पर ]



सत्या वल तथा जाति बिरादरी की भावना के महत्त्व को गमयन थे जानीय सग ठनो को राजनीति में लाना चाहत थे। शिक्षा-प्रभार आदि के उद्देश्य से विभिन्न जातियो के जो अलग अलग सगठन थे, उनका ये राजनैतिक उद्देश्य के लिए सग बनाना चाहते थे, जिससे राजनीति में उनका प्रभाव बढे और व्यक्तिता के बनाव पूरे समूह का फायदा पहुच सके।<sup>१८</sup> कालान्तर में इसी प्रवृत्ति ने जार पकडा, यद्यपि अभी भी देश की सभी मुख्य जातिया का इस प्रकार सगठित नहीं किया जा सका है। मगर जो जातिया इस प्रकार सगठित नहीं हो सकी, वे राजनैतिक सोदेबाजी में सफल नहीं रही और उनके सदस्या को अपनी आवाज उठाने के लिए उपद्रव और तोडफाड का सहारा लेना पडा।<sup>१९</sup> सब मिला कर जातीय सगठना ने भारत में राजनीति में बही भाग लिया है जो पश्चिमी देशों में विभिन्न हिता व वर्गों के सगठना ने।

### अथ जातीय समूह

भारतीय राजनीति के ढांचे में जातिव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण म्यान का हमन ऊपर वणन किया। दो और इससे सवधित विषय हैं। एक है अनुसूचित जातियो और आदिम जातिया की स्थिति, जिन पर भारतीय सविधान के निर्माताओं ने विशेष ध्यान दिया है और दूसरा अल्पसंख्यक सप्रदाया, खासकर मुसलमाना की स्थिति।

यद्यपि हरिजना और अनुसूचित आदिम जातिया की आर्थिक और सामाजिक स्थिति अभी भी बहुत खराब है किन्तु राजनीति में उनकी भूमिका, अथ छोटी जातियो से भिन्न नहीं है, जिनका ऊपर जिक्र किया गया। उनको समद व विधान सभाजा और सरकारी नौकरिया में जा सुरक्षित स्थान दिये गये हैं।<sup>२०</sup> उससे उनका राजनैतिक सगठन में बहुत प्रेरणा मिली है। सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में भी राजनैतिक दल व ऊंची जाति के नेता या उम्मेदवार इनका समर्थन लेने के लिए इनमे सौदा व समझौता करत है। मन्त्रिमंडला व दला के नेतवग में इनके आदमी साग्रह लिये जात है। इस प्रकार सामाजिक स्थिति हीन होते हुए भी

१६ वरा।

१७ आश्चर्य नहीं कि पश्चिम बंगाल तथा बने नगरों में उपद्रव और तोडफोड की राजनाति का उशादा जार रहा है बनिस्वन उन रायों के पहा जाति के आधार पर राजनैतिक गुट या गठजोड बने हैं।

१८ कसा ५ वें अयाय में बताया गया है, भारत के सविधान में अनुसूचित जातियों व आदिम जातियों के लिए अनेक विशेष व्यवस्था की गई है। सरकार ने इनमें विस्तार किया है। सबसे महत्त्वपूर्ण व्यवस्था समद आदि सब निराबित सम्पाओं में स्थान सुरक्षित करने की है। सभी सभी तो सुरक्षित स्थान इनके अनुपात से अधिक डोने है।

अनुसूचित जातियाँ व आदिवासियों का राजनैतिक महत्त्व बहुत है।<sup>१९</sup> इन अनुसूचित जातियों ने राजनैतिक उद्देश्य से अपने संगठन बनाए हैं और अपने लिए विशेष स्थान प्राप्त किए हैं, जैसे आसाम में आदिम जातियों ने।<sup>२०</sup> इनकी विशेष संवैधानिक स्थिति होने के कारण इनके संगठनों को 'जातीय' या 'सांप्रदायिक' नहीं समझा जाता। बल्कि प्रायः सभी प्रमुख राजनैतिक संगठनों ने अपने विशेष 'हरिजन' और आदिमजाति विभाग खोल रखे हैं। इस प्रकार राजनैतिक मायता मिल जाने से संकीर्ण या जातीय भावनाएँ लौकिक रूप ग्रहण कर लेती हैं और समाज के अन्य वर्गों के साथ मिल जाती हैं।

मगर यह बात मजहबी अल्पसंख्यकों पर लागू नहीं होती, खासकर मुसलमानों पर (अथ गैरहिंदू संप्रदाय बहुत छोटे हैं और जहाँ उनकी संख्या अधिक है, जैसे केरल में कैथोलिक या पंजाब में सिख, वहाँ उनको वही राजनैतिक महत्त्व प्राप्त है, जैसा ऊपर उल्लिखित जातियों को)। अध्याय दो में हमने देखा कि किस प्रकार कांग्रेस के नेता मुसलमानों के पृथक् राजनैतिक संगठन और सांप्रदायिक राजनीति के विरुद्ध थे। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के दो राष्ट्रों के सिद्धांत का विरोध किया और स्वयं सभी संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया, परंतु उसने संप्रदायों के अलग-अलग संगठनों के द्वारा इनको एक मंच पर लाने का प्रयत्न नहीं किया और सांप्रदायिकता का मुकाबला करने में सफल नहीं हुई। पाकिस्तान की स्थापना के कारण सांप्रदायिक संगठनों के विरुद्ध भावना और मजबूत हुई। इसलिए जब लोकतन्त्र की राजनीति ने समाज के बड़े समूहों को संगठित होने की प्रेरणा दी तो मुसलमान दुविधा में पड़े। उनमें दो प्रवृत्तियाँ दीख पड़ीं। एक की प्रतिनिधि जमीयत उलमा है, जो मुस्लिम संगठनों को राजनैतिक उद्देश्यों के बजाय शिक्षा और सामाजिक और मजहबी कार्यों तक सीमित रखना चाहती है। दूसरी विचारधारा जमाते इस्लामी, और मजलिस मुशव्वरात की है, जो राजनीति में भाग लेने के पक्ष में है और जो चुनावों में अपने उम्मीदवार खड़े करती है तथा अपनी राजनैतिक मांगें पेश करती है।

इस प्रकार का मतभेद ऊपर उल्लिखित जातीय संगठनों में भी प्रकट हुआ था, यद्यपि राजनैतिक नैराश्य के कारण मुसलमानों में इस मतभेद ने कटुता धारण

१९. रॉबर्ट ए. डार्ल ने इसको विषमता के बिरावा या अंतर का नाम दिया है। पहले ये जातियाँ एकत्रित या पुनः एकत्रित विषमताओं में पीड़ित थीं। देखिए 'हू गवर्न्स' (न्यू हेवेन—१९६१)।

२०. सर्वदल पंजाबी नेता सम्मेलन के आंदोलन के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार ने आसाम के अंतर्गत उनके उपराज्य की स्थापना का निर्णय किया। अब 'मेघालय उपराज्य को पूरे राज्य का दर्जा स्वीकार कर लिया गया। नागाओं का भी अलग राज्य बन गया। बिहार और उड़ीसा में आदिम जातियों को सभी वर्गों की सरकार में महत्वपूर्ण हिस्सा दिया गया। मध्य प्रदेश में उन्हें संसद में नहीं मिला है और मंत्र मिला कर आदिवासी अभी भी बहुत गरीब व पिछड़े हैं। अर्थात् ८ में इस विषय पर और विचार किया गया है।



कर ली है और राजनीति में भाग लेने के समर्थक हमेशा वैधानिक उपायों की बात नहीं करते। लेकिन जहाँ मुसलमानों ने राजनीति में भाग लिया है, वहाँ उनकी सकीर्णता व पृथक्ता कम हुई है और अन्य जातियों की तरह उन्हें भी राजनैतिक जोड़तोड़ में भाग मिला है। उदाहरण के लिए केरल में मुस्लिम लीग राजनीति में बनी रही और उसे राजनैतिक गठबंधनों में स्थान प्राप्त हुआ, राजनैतिक पदाधिकार में हिस्सा मिला और उसका दृष्टिकोण अन्य राज्यों के मुस्लिम संगठनों के मुकाबले ज्यादा असाप्रदायिक और लोकिक है। दूसरे तीसरे और चौथे चुनावों में देश के अन्य भागों में भी मुस्लिम राजनैतिक संगठन राजनीति में सक्रिय हो उठे हैं और इस प्रकार घेरे घेरे के लोकिक क्षेत्रों में आ रहे हैं। यद्यपि मुसलमानों के लिए स्थान सुरक्षित नहीं किए गए हैं, किंतु कांग्रेस तथा अन्य राजनैतिक दलों ने उनको कुछ स्थान देने की परिपाटी बना ली है। इससे मुस्लिम संप्रदाय राष्ट्रीय राजनीति की ओर खिंच रहा है। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में मुसलमानों की काफी संख्या है, वहाँ मतदान का अध्ययन करने से पता चलता है कि मुसलमानों के अंदर भी बड़फिरके हैं तथा उन्होंने दूसरे संप्रदायों और संगठनों के साथ भी मिल कर काम किया है अर्थात् मुस्लिम भावना का बनाए रखत हुए भी उन्होंने लोकिक या असाप्रदायिक प्रवृत्ति दिखाई है।<sup>२१</sup> यद्यपि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में अभी भी गिरावटें और गिरावटें बनी हैं फिर भी राजनैतिक स्तर पर उनका सहयोग और सक्रियता बढ़ रही है। राजनैतिकीकरण के क्रम में चुनाव और विवाद भी होते हैं परंतु यह सद्यः अधिकारप्राप्ति और नए उठने वाले वर्गों में भी होता है। इस प्रकार, जातियों के राजनीति में प्रवेश करने की जिस प्रक्रिया का विश्लेषण ऊपर किया गया, वह कुछ अंतरों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय और अनुसूचित जातियों और जादिस जातियों पर भी लागू होती है।

### नव्य एकीकरण की प्रक्रिया

मुख्य प्रश्न जिस पर हमने विचार किया यह है कि किस रूप में विभिन्न जातियों और संप्रदायों में राजनीति में भाग लेने के फलस्वरूप सामूहिक या राष्ट्रीय

२१. माइरा बीर और रत्नी बोठारी संपादित—'इंडियन वोटिंग बिहेवियर' (वर्ग १९६५) में रत्नी बोठारी और सहज शर्मा 'पुनर्गठित पेंडिंग सिस्टम और वस्तुनिष्ठ वोटिंग के बीच अंतर' बतलाते हैं। पृष्ठ १५५—'फेडरल पोलिटिक्स इन द इंडियन स्टेट—द वर्तमान चरण' इन उत्तर प्रदेश (बकले, १९६६)। अथवा ६-७, 'वर्तमान चरण' इन अमरोहा—ए के एम स्टडी ग्रुप वल पार्सी टाभिनेस' (पार्टी सिस्टम एवं पोलिटिकल स्टडी, अमेरिकन प्रेस) सेंटर फॉर स्टडी ऑन द सोसायल स्ट्रक्चर १९६७। इनके साथ के विश्लेषण के लिए 'पेंडिंग सिस्टम और पेंडिंग सिस्टम' इन इंडिया' में 'पेंडिंग सिस्टम पार्सीसोशियल पेंडिंग सिस्टम' (नरसिंह) सेंटर फॉर स्टडी देव सोसा १९६९)।

भावना का उदय हुआ है और उसकी पृथक्ता कम होकर उनका राजनैतिक एकीकरण हुआ है। अक्सर राष्ट्रीय भावना से और जाति या संप्रदाय की भावना के द्वंद्व या टकराव की बात की जाती है। लेकिन हमने देखा कि जहाँ जाति या कबीले की भावना का दबाने के बजाय उनको राजनैतिक दिशा देने की काशिश की जाती है, वहाँ राजनैतिक एकीकरण की संभावना बढ़ती है और जहाँ जाति या संप्रदाय के संगठन की अनुमति नहीं दी जाती वहाँ ये गलत रास्ते पर जाती हैं। हमने देखा कि किस प्रकार जाति के संगठन राजनैतिक रूप धारण कर लेते हैं और समाज व राजनीति में संघर्ष जोड़ते हैं।

समाज और राजनीति में संघर्ष जोड़ने की इस प्रक्रिया को लोकीकरण का नाम दिया जा सकता है। राजनीति के प्रभाव से भारतीय समाज में जो जबरदस्त परिवर्तन हुआ है, वह इसी प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। जिस प्रकार 'संस्कृतीकरण' की प्रक्रिया के द्वारा समाज के दबे हुए समूह आगे आए और संस्कृत जातियाँ पाश्चात्यीकरण के द्वारा आधुनिकता के ढाँचे में आईं, उसी प्रकार लोकीकरण की प्रवृत्ति उन दोनों वर्गों को राजनीति में खींच रही है, जिन्होंने पुरानी व्यवस्था खत्म हो रही है और नये लोकिक संगठनात्मक आधार पर पुनर्गठित हो रही है। नई व्यवस्था का रूप अभी भी अस्पष्ट और विकासशील है।<sup>२२</sup> परिवर्तन की इस प्रक्रिया में स्थानीय या सर्वोपयोगी और व्यापक निष्ठा का नया मिश्रण तैयार होता है, पुरानी जातिपरक, व्यक्ति और समूह के हित में बाधक सिद्ध होती है और अशिक्षित जनसमूह को बोध होता है कि वह एक राजनैतिक पद्धति का अंग है और उसका उगम लगाव पैदा होता है।

दूसरी ओर कोई भी राजनैतिक व्यवस्था या पद्धति तभी स्थिर हो सकती है जब जनसमूह उसकी प्रक्रिया और प्रतीका का त्याग या काम निभालने के लिए नहीं, बरन वास्तव में अच्छा और उपयोगी समझकर अपनावे। अर्थात् नई विधियाँ और नए मूल्य परंपरा का रूप धारण कर लें। बिना रूढ़ियों या परंपरा के कोई समाज जीवित नहीं रह सकता और आधुनिकता के लिए वास्तविक चुनौती यह नहीं है कि वह परंपरा को कैसे नष्ट करे, बल्कि यह कि कैसे स्वयं परंपरा बन जाए।<sup>२३</sup> जाति और राजनीति के प्रसंग में इसके दो अर्थ हैं। एक यह कि जाति के जो तत्त्व अनुपयोगी और मकीलता बढ़ाने वाले हैं वे खत्म हों और वे तत्त्व

<sup>२२</sup> पुनर्गठन की प्रक्रिया और जाति या फिर के भी भावना के सैद्धांतिक विवेचन के लिए देखें, डी एल मेठ और रजनी कोठारी 'सोशल चेंज पोलिटिकल इंटिग्रेशन ऐंड द वैल्यू प्रोसेस' इन्टरनेशनल राउटledge ऑन वैल्यू इन पोलिटिक्स में विषय दुर्भावना, सुगोस्लाविया (मीमियो, १९६५)।

<sup>२३</sup> रजनी कोठारी, ट्रेडिंग ऐंड माइनिटी रिवाइटेड - गवर्नमेंट ऐंड अपोनिशन, ३, स ३ (मार्च १९६८)।



## राजनैतिक संस्कार और सामाजिककरण

पिछले अध्यायों में हमने राजनीतिक विवरण की तुलनात्मक प्रणाली द्वारा भारत के ऐतिहासिक एवं साम्प्रतिक आधुनिकीकरण की व्याख्या करने का प्रयत्न किया। किंतु बिना ही राष्ट्र का राजनीतिक अनुभव उसकी परंपरा एवम प्रवृत्ति में निहित होना है। उसके स्थायी राजनीतिक संस्कार और उसकी बदलती हुई राजनीतिक असंतुलन के परस्पर मध्य की व्याख्या करने पर ही हमें देश के विकासक्रम में योग देने वाली दृष्टि की समझने का सारा मिल सकता है और उसकी सफलता या विफलता को ठीक से जानने में सहायता मिल सकती है तथा और अच्छे ढंग से उसकी भावी संभावनाओं का अनुमान किया जा सकता है।

हमें ये प्रश्न पूछने हैं — क्या देश के आधुनिक विकास से इसका युगा पुरानी कुछ समस्याएँ हट जा सकेंगी? क्या इसका युगा पुराने देश की अपनी कमजोरियाँ दूर करने और आधुनिक संसार में स्थान ग्रहण करने में सहायता मिलेगी या इसकी सांस्कृतिक और मानसिक स्थिति इसमें बाध होगी। हमें एक ओर व्यक्तिगत और सांस्कृतिक परिवर्तन की दृष्टि है और दूसरी ओर यह दृष्टि है कि आधुनिक राजनीति और आर्थिक प्रवृत्तियों से क्या साम्प्रतिक परिवर्तन हो रहे हैं और व्यवहार की क्या परिपाटियाँ बन रही हैं और क्या आवश्यक समस्याएँ सामने आई हैं जिनका मुलभूत जगह है।

हम भारत में होने वाले राष्ट्रनिर्माण के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर एक नजर डालेंगे और इसके विशिष्ट राजनीतिक संस्कार के बारे में कुछ सिद्धांत उपस्थित करेंगे तथा इनका मूल सामाजिक और सांस्कृतिक संस्कारों से जोड़ेंगे। इसके साथ ही विचार करेंगे कि किस प्रकार एक नयी राजनीतिक सत्ता के उदय से प्राचीन परंपरा की नयी व्याख्या की जा रही है और प्राचीन व्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन हो रहा है।

## ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

भारत शायद एकमात्र देश है, जिसने बिना किसी विशिष्ट राजनैतिक व्यवस्था का सहारा लिए अपनी सांस्कृतिक परंपरा को कायम रखा है। अथ प्राचीन सम्य ताओं के विपरीत भारत की एकता किसी राजनैतिक सत्ता या व्यवस्था पर आश्रित नहीं रही, प्रत्युत वह इस बात पर आश्रित रही कि उसके सांस्कृतिक प्रतीक, आध्यात्मिक मूल्य और आचारविचार जनसाधारण के जीवन में व्याप्त हो गए। भारत की आत्मा राजनैतिक नहीं सांस्कृतिक रही। अवश्य ही भारत के सांस्कृतिक रूप के साथ साथ उसका एक लौकिक या राजनैतिक रूप भी रहा। सांस्कृतिक और राजनैतिक आध्यात्मिक और लौकिक अंगों की परस्पर प्रतिक्रिया के द्वारा ही वह बदरते युग के साथ अपने का बदलता रहा। फिर भी भारत के इतिहास में सरकार और समाज के बीच सदा एक पाथक्य रहा और भारतीयता का भाव राजनैतिक नहीं सांस्कृतिक रहा।

कौन-से ऐसे ऐतिहासिक तत्त्व हैं जिनके कारण लगातार राजनैतिक उथलपुथल के बावजूद भारत की संस्कृति अविच्छिन्न चलता रही, इसका ठीक पता नहीं।<sup>१</sup> परन्तु एक बात स्पष्ट है कि बहुत पहले ही भारत में आध्यात्मिक और लौकिक या शासकीय क्षेत्र अलग जलन हो गए थे। साथ ही यहां धर्म और राज्य में वह संघर्ष नहीं हुआ जो पश्चिम के देशों में इतना देरने को मिलता है। साथ ही दोनों में बराबर व्यवहार और परस्पर संघर्ष भी रहा। इसका कारण कुछ तो यह था कि यहां राजसत्ता विदगिया की रही और साधारण जनता अपने रास्ते चलती रही। साधारणतः विदेशी विजेता भी यहां सामाजिक और धार्मिक रीतिरिवाज में दखल नहीं देते थे।

राजनैतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र एक दूसरे का प्रभावित करते थे और शासका तथा धर्मगुरुओं में संघर्ष रहता था। इस प्रकार भारतीय सम्यता ने तत्त्वों को ग्रहण करती रही। कुछ मूल तत्त्वों को बनाए रखते हुए, विशिष्ट क्षेत्रों में परिवर्तन का विरोध यहां कभी नहीं किया गया। सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में बौद्ध, वैष्णव, सिख मत के साथ साथ पुरानी परंपरा के समर्थन के शक्राचार्य के जैसे आंदोलन यहां होते रहे। इन दोनों प्रकार के आंदोलनों के द्वारा भारतीय संस्कृति के कुछ मूल तत्त्वों का पुनः प्रतिपादन होता रहा। इस कारण जब १९वीं शताब्दी में यहां सुधार के आंदोलन चले तो उनकी समाजकी व्यवस्था में उथल-पुथल लाने के प्रयत्न के बजाय हिंदू समाज में धुम आइकुरीतिया का दूर करने का प्रयत्न समझा गया, जैसे पुराने जमाने के धार्मिक आंदोलन थे।

पुरानी जड़ समाज व्यवस्था की टक्कर जब जाधुनिकता की गतिविधि से होनी

<sup>१</sup> फिर भी देखें 'इंडियन नेशन', 'द क्वेश्चन ऑफ कल्चरल कंटिनुइटी इन इंडिया', जर्नल ऑफ एशियन स्टडीज, २० अगस्त १९६१।

है, तो उथलपुथल होना स्वाभाविक है। परन्तु भारत में परंपरा और परिवर्तन की प्रवृत्तियाँ बग़ल-साथ-साथ चलती रही हैं और परंपरा नए तत्त्वों का ग्रहण करती रही है। एक विदेशी पक्षधर का कहना है कि भारत की आधुनिकता को उसकी परिवर्तनशील परंपरा के सदृश में देखना पड़ेगा।<sup>१</sup> भारत की सांस्कृतिक परंपरा की अविच्छिन्नता के कारण ही यहाँ लांकिंग क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन होने में कठिनाई नहीं हुई। क्योंकि यहाँ की मस्तिष्क किसी विशिष्ट राजनैतिक व्यवस्था के साथ बंधी नहीं थी। दूसरे, तीक्ष्ण या राजनैतिक परिवर्तन के बीच भी यहाँ की संस्कृति अविच्छिन्न बनी रही। तीसरे राज्य व्यवस्था के परिवर्तन का यहाँ महत्त्व न देने की प्रवृत्ति रही। इस कारण राजनैतिक परिवर्तन का विरोध करने के बजाय, उनका स्वीकार करने और उनके जनरल हरे फेर-वर लेने की प्रवृत्ति रही। इन परिवर्तन का भारतीयता के लिए खतरनाक नहीं समझा जाता था, क्योंकि भारत तीयता का मूल तत्त्व राजनैतिक नहीं था। दूसरी पुरानी सभ्यताओं में जहाँ राजनैतिक व्यवस्था की लंबी परंपरा रही और जहाँ सभ्यता राज्यव्यवस्था में अभिन्न रही, वहाँ राजनैतिक परिवर्तन का विरोध बहुत समय तक चला और जब विरोध विफल हुआ, तो परिवर्तन के साथ राष्ट्रीय अपमान और पराजय की भावना भी आयी।<sup>२</sup> दूसरी ओर भारत में आधुनिक समय में भी विदेशी राजनैतिक और आर्थिक संस्थाओं और विधियों का ग्रहण राष्ट्रीय स्वाभिमान के विरुद्ध नहीं समझा गया।

भारत में सांस्कृतिक और राजनैतिक क्षेत्रों को अलग रखने के साथ विभिन्नता को स्वीकार करने की भी परंपरा थी। जाचार-विचार की विभिन्नता को यहाँ बरा नहीं समझा जाता था। इसलिए लोकतंत्र की विचारधारा, यहाँ की सामाजिक क्षेत्र में स्वतंत्रता, स्थानीय रीतिरिवाज को बनाए रखने की आजादी, तथा सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र में स्वतंत्रता की परंपरा से मेल खाती है।

अब नए देश में लोकतंत्र और चुनाव के कारण कबीलों और जातियों में द्वंद्व को प्रोत्साहन मिला है। लेकिन भारत में यह नौबत नहीं आई, क्योंकि जहाँ जाति विरादरी या संप्रदाय के प्रति निष्ठा काफी समय तक राजनैतिक निष्ठा में भिन्न रही। जब अंत में यहाँ राष्ट्रीय राजनैतिक व्यवस्था स्थापित हुई, तो यह एक नई अखिल भारतीय व्यवस्था थी, किसी पुरानी जाति या क्षेत्रीय व्यवस्था का

१ जे सी हेस्टर मान, 'ट्रैडीशन इन माडर्न इंडिया'। इस लेखक का कहना है कि पश्चिमी विचारक अपने यहाँ के अनुभव को भारत पर लागू करते हैं, "संसार के परंपरा और आधुनिकता में विरोध या द्वंद्व की कल्पना करते हैं।

२ ज्ञान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। देखें- लुशियन डब्ल्यू पाद- 'सिपरि आफ चारनीज पोलिटिक्स ए माइक्रोलाजिकल स्टडी आफ अगारिटी क्रॉमिनि इन पोलिटिकल टेक्नोपैट (केंब्रिज-मैसा १९६८)।

विस्तार नहीं थी, जैसा कि अग्रे कुछ नए दशों में हुआ।<sup>४</sup> बाद में जब इस नयी राजनैतिक व्यवस्था का विस्तार और विवेकीकरण हुआ तब प्रात और भापा की भावना विकसित हुई। किंतु तब तक नयी अखिल भारतीय व्यवस्था भी अच्छी तरह स्थापित हो चुकी थी। नयी प्रातीय या भाषिक निष्ठा पुरानी जातीय और सांप्रदायिक निष्ठा से भिन्न है। पहली निष्ठा नेताओं की राजनीति को प्रभावित करती है, जबकि दूसरी जनसाधारण का राजनीति को। जो पर्यवेक्षक प्रात और भापा के आग्रह को राष्ट्रीय एकता की भावना में बाधक मानते हैं वे पश्चिम की स्थिति का दृष्टि में रखते हैं जहां राष्ट्रीयता के अलावा और कोई निष्ठा स्वीकार नहीं की जाती।<sup>५</sup> जबकि भारत में राष्ट्रीय निष्ठा संप्रदेश या भाषा के प्रेम या निष्ठा का विरोध नहीं समझा जाता।

भारत में व्यापक निष्ठा राजनैतिक नहीं सांस्कृतिक थी, इस कारण नयी राजनैतिक व्यवस्था को अपनी जड़ जमाने में आसानी हुई। नयी व्यवस्था ने नए नेतृत्व को जन्म दिया जो नये युग के विचारा और आदर्शों से प्रभावित थे और अपने देश या उन्नी के अनुसार पुनर्स्थापना करना चाहते थे। परन्तु भारत के ये आधुनिक मस्कर्ता पुरानी परंपरा के शत्रु या विरोधी न थे। गांधी का शहर का बौद्धिक वर्ग को यही संदेश था कि गांधी में जाओ और गांधी का शहर से, नई व्यवस्था से संबंध जोड़ो। आज भी इस बात का महत्त्व कम नहीं हुआ है। आर्थिक विकास और बालिग मताधिकार ने इसमें महत्त्व को और बढ़ा दिया है।<sup>६</sup> भारत के परंपरागत उच्चवर्ग ने सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र की आजादी को कायम रखते हुए, नयी राजनैतिक व्यवस्था को स्वीकार किया है।

पुरानी रीढ़-बेटी के संबंध पर आधारित जाति की पंचायत का स्थान नए जातीय संगठनों और सभा ने लिया। इस प्रकार पुरानी व्यवस्था का रूप धीरे धीरे व्यापक बना। इसके फलस्वरूप देश में एक लौकिक या राजनैतिक व्यवस्था विक

४ इसका कारण यह था कि अंगरेजों ने भारतीय नेताओं से व्यवहार रखा और सत्ता उन्होंने सौंपी, जब कि अफ्रीका में उन्होंने कवायली सरदारों का दावा माना। यदि भारत में भी पुराने रानाओं के भंडार को सत्ता सौंपी जाती तो यहाँ भी पुराने झगड़े फिर शुरू हो जाते। १९३५ के ऐक्ट में अंगरेजों ने यही करना चाहा था।

इस ऐक्ट की व्यवस्था को अस्वीकार करके कांग्रेस ने सही काम किया और देश की एकता का रक्षा की।

५ लु. डब्लू. पाइ 'द पोलि कल्चर ऑफ इंडिया फ्रॉम चारना-क्रासमिस ऑफ आर्येडिटा टेंड अथॉरिटी ऑफ़ीवेंश मारु और रजनी कोठारी संपादित 'इंडिया फ्रॉम चारना क्रासमिस इन डेवलपमेंट'।

६ नेहरू के शब्दों में राष्ट्रनिर्माण के काम में गांधीजी की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि शहर के शिक्षित लोगों की सुदृग्गी को वहाँ दूर करे। देखें-आर्द्रे मार्लवम, 'एंगी-मेमायस' (न्यूयाक १९६८)।

सित हो रही है, जो जाति या मप्रदाय की गीण व्यवस्थाओं के बीच में दखल नहीं देती। इस प्रकार भारत उम उथल-पुथल से बच गया जो उन देशों में हुई, जहाँ राजनैतिक क्षेत्र को सबसे ऊँचा स्थान दिया गया और अन्य क्षेत्रों के महत्त्व को खतम करने की कोशिश की गयी।

परन्तु स्थानीय और जातीय निष्ठाओं का अधीनता में रखने वाली एक व्यापक राजनैतिक निष्ठा के अभाव में कुछ नुस्खे भी हुआ। सांस्कृतिक क्षेत्र को महत्त्व देने और राजनैतिक क्षेत्र में उदासीन रहने के कारण भारत में ग्रामीण कृषिप्रधान व्यवस्था का बहुत महत्त्व दिया गया। (बाबरजुद पुराने बड़े नगरों की उपस्थिति के) केन्द्रीय राजनैतिक सत्ता के न होने से नाग स्थानीय और जातीय निष्ठाओं का दावे से निराल कर मावदेशिक निष्ठा का विकास करने में असमर्थ रहे। उनमें नागरिक या राजनैतिक जिम्मेदारियों का स्वीकार करने, राजनैतिक व्यवस्था को समायन देने की ओर जानिपाति और गांव में ऊपर उठकर राष्ट्र या देश की बात मानने की प्रवृत्ति न पैदा हो सकी। हमारे माथ ही सामाजिक और निर्व्यक्तिक सत्ता के प्रति उनके मन में गंवा और अविश्वास भी बना रहा। जय तोकिव राजनैतिक सम्मताओं की तरह यहाँ राष्ट्रीय इतिहास के प्रति गौरव और हमसे उत्पन्न होने वाले राष्ट्रीय स्वाभिमान के भाव की भी कमी रही। हम देखेंगे कि यहाँ पारिवारिक जीवा और आध्यात्मिक तथा धार्मिक परंपरा में यह प्रवृत्ति कैसे बढ्मूल रहा।

नागरिकता की कमजोर भावना के साथ साथ यहाँ न तो राजसत्ता से अधिक अपेक्षा की जाती है और न उसकी समायन देने की प्रवृत्ति है। इसी से यहाँ सरकार और राजनैतिक व्यवस्था की श्रुटियाँ की साधारणतः अपेक्षा की जाती है।

सरकार के प्रति उदासीनता का एक और परिणाम यह भी होता है कि सत्ता के बाहर के वर्गों में मधम सुलगता रहता है और इन संघर्षों और विवादों का सुलझाने की राजनैतिक मशीनरी नहीं स्थापित होती। विवादों और मतभेदों का सुलझाने के उजाय उनका सहन करने की भारतीय प्रवृत्ति हानिकर सिद्ध होती है।

जब ऐसे समाज पर आधुनिक राष्ट्रीय और आंतरराष्ट्रीय प्रभाव पड़ने लगते हैं तो राष्ट्र के विभिन्न अंगों में, जो अब तक काफी स्वायत्तता का उपभोग करते रहे हैं सामाजिक वैधाने और एकता लाने की समस्या तीव्र रूप धारण कर लेती है। अर्थात् जहाँ भारत में ऐसी राजनैतिक व्यवस्था का निमाण सरल है, जिसमें विभिन्न अंगों को काफी आजादी रहे वहाँ राजनैतिक एकता और दश की सरकार के प्रति वक्तव्य की भावना का विकास कठिन हो जाता है।<sup>७</sup> साथ ही यह लक्षण

<sup>७</sup> एस एन आर्सेनस्टाट, ट्रेडिशन ऐंड मोडर्न आफ रेस्पान्स टु माजिनिंग - 'इन्डिया ऐंड चाइना', पृ. १७५।



भी दिखाई दे रहे हैं कि जातिव्यवस्था में जो परिवर्तन हो रहे हैं, राजनैतिक दल तथा अन्य मध्यवर्ती संस्थाओं का जो विकास हो रहा है और राजनैतिक नेताओं और मुखियाओं की जो परपरा कायम हो रही है, उससे देश के राजनैतिक क्षेत्र का बल मिले। तथा इस बीच जाति-विरादरी जैसी आदिम संस्थाओं के स्वतंत्र अस्तित्व और उसने फलस्वरूप सरकार पर कम दबाव के कारण नयी व्यवस्था को जड़ जमाने में सहायता मिले।

### राजनैतिक संस्कार के तत्त्व

हमने देखा है कि इस विशाल देश में एकता का मूल सांस्कृतिक समानता और उससे उत्पन्न होनेवाले आचारविचार रहे हैं। हम अब यह देखना है कि इस सांस्कृतिक और सामाजिक समानता में कौन से तत्त्व हैं जिनका राजनैतिक महत्त्व है और जो आधुनिक राजनैतिक प्रवृत्तियों को प्रभावित कर सकते हैं।

### (१) विचारभेद और अस्पष्टता के प्रति सहिष्णुता

भारत में विचार-व्यभिचारी की स्वीकार करने की प्रवृत्ति रही है। भारतीय समाज में बहुत-से विरोधी विचार वाले और भिन्न भिन्न रीतिरिवाज वाले तत्त्वों को स्थान दिया गया है। विभिन्न तत्त्वों को समाज में स्थान देने के लिए यहाँ विभिन्न जातियों या वर्गों के विभिन्न धर्म या कायों को स्वीकार किया गया है और उसी हिसाब से समाज में उनका पद निर्धारित किया है। आध्यात्मिक या दार्शनिक रूप से यहाँ यह सिद्धांत माना गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म के बल पर आत्मविकास करता है और मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करता है। भारत पर विभिन्न विचारों द्वारा जो राजनैतिक जीवन का आक्रमण होता रहा है और फलस्वरूप यहाँ विचारों की भिन्नता को स्वीकार किया गया। यहाँ नये मत और विचारों का प्रवर्तन होता रहा और भिन्न भिन्न राजनैतिक व्यवस्थाओं का भी प्रचलन होता रहा। इसके फलस्वरूप यहाँ व्यक्तियों और समूहों को आचार विचारों की काफी स्वतंत्रता रही। यहाँ नविकृति और धर्म को देशकालसापेक्ष माना गया। यहाँ यह बात नहीं मानी गई कि सब गम्य और सब श्रेणी व्यक्ति के लोगों के लिए एक ही धर्म या नैतिक नियम है। इसके बजाय यहाँ यह माना जाता है कि विभिन्न स्थिति और व्यवसाय अर्थात् विभिन्न वर्ण और जाति का विभिन्न नैतिक कर्तव्य या धर्म है।<sup>८</sup> इस दृष्टिकोण के कारण विचारों के संघटन में बड़ी अस्पष्टता रही है और इस अस्पष्टता तथा द्वैधता का सहन और स्वीकार करने की प्रवृत्ति रही है। वास्तविक जगत की अनिश्चितता और वैविध्य के परिप्रेक्ष्य में जीवन को टालने

<sup>८</sup> एमरी द रेनकोर्ट - 'द सोल ऑफ इंडिया' (१९६१)



या सामाजिक स्थिति का घम माना गया। जब ऊँच-नीच का स्वाभाविक समझा गया तो नीची जातियों के लिए ऊँची जातियों का सम्मान करना, समाजव्यवस्था को स्वीकार करना और बिना विरोध या विद्रोह किए, अपना ठोठा या नीचा काम करते जाना भी स्वाभाविक हो गया। इससे सामाजिक विप्लव की रोक हो गई परन्तु इसका परिणाम यह भी हुआ कि सामूहिक जिम्मेदारी की भावना न रही। लोग भाग्यवादी और अयमण्य हो गए। साधारण आदमी का रुख यह रहा कि 'कोउ नप हाय हमें का हानी।' राज्य या राष्ट्र के प्रति वक्तव्य की भावना न विकसित हो सकी। समाज के अधिकारियों या व्यवस्था के प्रति उदासीनता और अनास्था उत्पन्न हुई। लोग का भाव था कि 'समय को नाह दोस्त गुसाईं'। राजनैतिक उल्लसपुल्ल के समय यह भाव स्पष्ट हो उठता था।

ऊपर कहा जा चुका है कि यहाँ विचारों की स्वतंत्रता और समाजव्यवस्था की कठोरता रही। परन्तु जब आधुनिक युग के प्रभाव से जातिपाति का ढाँचा और आचार की कट्टरता टूटने लगते हैं तब विचारों की सहिष्णुता, चाहे अस्थायी तौर पर ही सही, भी टूटने लगती है और सब पर एक विचारधारा लादने की प्रवृत्ति उभरती है। भारत में शहरी शिक्षित और राजनैतिक रूप से मचेतन वर्ग में यह प्रवृत्ति लक्षित हो रही है।

फिर भी, ऐसा लगता है कि विचारों की सहिष्णुता की प्रवृत्ति नए राष्ट्र के विकास को भी प्रभावित करेगी। अल्पसंख्यकों के प्रति उचित व्यवहार, भिन्न-दलों से जोर और राजनैतिक मतभेद और विरोध की स्वतंत्रता देने में यही प्रवृत्ति काम कर रही है। हो सकता है कि पुरानी व्यवस्था के परिवर्तन और नयी राजनैतिक संस्थाओं और प्रथाओं के निर्माण के कारण अस्थायी रूप से लोगों में अरक्षा और अस्थिरता की भावना उत्पन्न हो और इस कारण असहिष्णुता की प्रवृत्ति प्रकट हो, पर अंत में सहिष्णुता और अपने-अपने ढंग पर चलने की स्वतंत्रता की पुरानी परंपरा की ही जीत होगी, जिसके कारण भारतीय सभ्यता युग के चपड़े साकर भी जीवित रही है। वास्तव में आधुनिक राजनैतिक परिवर्तन को स्वीकार करने में यही प्रवृत्ति सहायक हुई है। एक सम्माय सहयोगी के शब्दों में—देखना यह है कि लोगों को राजनैतिक परिवर्तन का जो ऐतिहासिक अनुभव रहा है, वह इस नयी राजनैतिक व्यवस्था को अपनाने में वहाँ तक सहायक होता है और उनकी जातिविवादों और संप्रदाय आदि के प्रति निष्ठा कैसे राष्ट्रीय निष्ठा में परिणत होती है। परिवर्तन की चुनौती का किस प्रकार सामना किया जाता है यही राजनैतिक संस्कार का तत्त्व है।<sup>१२</sup>

<sup>१२</sup> आशीस नन्दा, द कान्फ्रेंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट एरन्ड टुर्विंग पाहुणिपि (दिल्ली-सेंटर फार द स्टडी ऑफ डेव सोसा १९६८)।

## (२) विखंडित अधिकार

जीवन की इस पद्धति का एक आवश्यक तत्त्व यह माना गया है कि सत्ता विखंडित, विवेचित और अस्थायी या आवतक है। भारतीय कुटुंब, नातेदारी, जाति और गांव के जीवन में यही बात लागू होती है। भारत की समाजव्यवस्था में ऊँच-नीच की श्रेणियाँ बनी हुई हैं और हर श्रेणी के अधिकार और वक्त य वटे हुए हैं। जब अधिकार क्षेत्र के तार में संशय या विवाद पैदा होता है तभी किसी बाहरी सत्ता को इसके निणय के लिए बुलाया जाता है। बाहरी सत्ता का यह हस्तक्षेप इस प्रकार स्थिति विशेष में और अस्थायी होता है लगातार नहीं।

सत्ता का काम निणय या निपटारा करना है। (जिसका अर्थ यह होता है कि विचार या नियमनिणय का कार्य राजनीति का सार तत्त्व है)। यह वारणा राज्य के क्षेत्र में भी लागू की गयी। राजा या उसके प्रतिनिधि का मुख्य राजकीय काम परियाना को सुनना और उनका फैसला करना था। शेष वाता म वह दंगल न दता था और समाज अपने रास्ते चलता था। मुखिया या नेता का भी यही काम था<sup>१३</sup> अर्थात् विवाद का निपटारा करना, चाहे वह मुखिया धर्मगुरु हो या विरादारी या गांव का चौधरी। गाँव के अंदर और दूसरे गाँव से जो झगड़े होते रहते हैं, उसको देखते हुए यह काम बड़े महत्त्व का था लेकिन इस सत्ता या अधिकार का प्रयोग लगातार नहीं होता था और इमने सस्यागत रूप नहीं धारण किया था।<sup>१४</sup> समाजव्यवस्था अर्थात् जातिविरादरी और गांव के विधि विधान लोगों के जीवन में ऐसे अंगीकृत हो चुके थे कि रोजमर्रे के झगड़े बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के निपटते रहते थे। जब कभी स्थिति हाथ के बाहर हो जानी थी या विधि विधान के बारे में अनिश्चय या संदेह रहता था, खास कर परिवर्तन के काल में तभी बाहरी सत्ता की दुहाई दी जाती थी।

ऊँचे अधिकारी या सत्ता के हस्तक्षेप की परंपरा आधुनिक युग में भी चली आई है और राजनीति में जिलाधीश या कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जैसे राजनीतिक नेताओं की मध्यस्थता का काफी महत्त्व है।<sup>१५</sup> अंग्रेजों के जमाने में भी यही स्थिति थी और आज भी है। इसी परंपरा के कारण औद्योगिक विवाद सबंधी कानूना में भी

<sup>१३</sup> सेमूलर अंगरेजी में प्रयुक्त 'लीडर' शब्द का भारतीय भाषाओं में कोई पर्याय नहीं। अर्थशास्त्री 'नेता' शब्द को छोड़कर इसके अन्य पर्यायवाची शब्द आदिम विरादरी या धर्म से संबंधित हैं।

<sup>१४</sup> भारतीय गाँव की दलबंदी या भगना—तम्बरा के बारे में देखें—बनाइ ने सींगल और अलन बाल्म, 'द पर्वनिव फैक्शनलिज्म' अमेरिकन एन्थ्रोपॉलॉजिस्ट, ६२ स ३, जून १९०० और भी, अलन बाल्म, 'गोपालपुर—ए माउथ इन्विजन विलेज' (न्यूयार्क १९६२)।

<sup>१५</sup> देखिए—माइरन बानर 'टेडिशनल रोल परफार्मेंस ऐंड द डेवेलपमेंट ऑफ माइन पॉलि पांरि—द इंडियन कैम चनल ऑफ पॉलि २६ स ४ १९६४।

मध्यस्थता को ऊँचा स्थान दिया गया है।<sup>१६</sup>

अशत इसी परंपरा या मनावृत्ति के कारण ऐसे मामला का निपटाने में भी सरकार या सरकारी नेताओं के पाम गुहार की जानी है, जो अन्य देशों में सरकार के कार्यक्षेत्र के बाहर समझे जाते हैं।<sup>१७</sup> चूंकि सरकार की कल्पना मध्यस्थ या मायाधीश के रूप में की जाती है इसलिए स्थानीय विवादों को ऊँचे अधिकारियों के सामने पेश किया जाता है और उनके फैसले को स्वीकार किया जाता है। इसलिए यह उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के जदर लगातार झगड़े—लड़ाई बजाय ऐसा बहुत कम हुआ है कि स्थानीय विवादों में ऊँचे स्तर के नेताओं का फैसला न माना जाए (झगड़ा को इस प्रकार निपटाने की पूरी मशीनरी है)। इससे स्थानीय समुदायों को व्यापक राजनीतिक क्षेत्र में आने का मौका मिलता है। ऊँचे नेता भी ऊपर से फसल लादने के बजाय समझौता कराने पर ज्यादा और बजाय एक पक्ष को दबाने के, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। संगठित वर्गों और हिता के संघर्ष के बजाय दो पक्षा में समझौता कराने की यही प्रवृत्ति भारत में मौलभाव या सौद बाजी का स्थान लेती है।<sup>१८</sup>

कौन-से झगड़े कहा ले जाए जायें, इस विषय में काफी छूट है। इस कारण सत्ता बिखरी रहती है और उसका प्रयोग भी लगातार नहीं होता। इससे सरकार के क्षेत्र का विस्तार भी चुपचाप होता रहता है। इस प्रकार वर्तमान व्यवस्था के जदर ही काम करते हुए और बिना जबदस्ती किए सरकार काफी परिवर्तन लाने में सफल होनी है। सत्ता बिकेंद्रित या बिखरी रहती है और समाज की वास्तविक स्थिति के अधिकाधिक अनुरूप बनी रहती है।

### (३) आदेश और राजनीति

झगड़ा को निपटाने के साथ साथ प्रमुख वर्ग की समाज में एक भूमिका रही। उसका काम नैतिक मानदंडों की प्रतिष्ठा करना भी था। चीन जैसी अधिक केंद्रित व्यवस्था में राज्य का नैतिकता का सरभूक और नागरिकों को नैतिक मार्ग पर

१६ चार्ल्स ए. मायर्स—'लेबर प्रावल्स इन इन्डियाना' (नेत्रिज मसा १९५८)। अमेरिकी के विचारों में मध्यस्थता के महत्व के बारे में बी. वा. गिरी—'लेबर प्रावल्स इन इन्डियाना' (वर्ग १९५८) और अशोक मेहता—'द मीडिएटिंग रोल ऑफ द ट्रेड यूनियन इन अमेरिकन इकोनॉमी' (इकोनॉमिक टेक्नॉलॉजी एंड कल्चरल चेंज अक्टू १९५७)। झगड़ों के सामान्य कानूनी पक्ष के बारे में बर्नार्ड एस. कोहन—'एथ्रोपॉल नोट्स ऑन डिस्प्यूट्स ऐंड ला इन इन्डिया' अमे. एथ्नो ६७ स. ६ दिस १९६५।

१७ अशत इसलिए कि सत्ता की गार देखने की आदत के कारण स्थानीय मामलों में उच्चतर नेताओं का प्रभाव बड़ा है। सरकार और ऊँचे स्तर के नेताओं ने जो महत्वपूर्ण भाग लिया है उस पर यहाँ विचार किया गया है।

१८ मादरन चीनर।

चलाने वाला माना गया है। १° लेकिन भारत में समाज की राजा या शासन स्वतन्त्रता की परंपरा रही है और यहाँ राज्य को नैतिक मामला में इतनी शक्ति नहीं दी गई ( कौटिल्य के बावजूद )। २° इसके बजाय यहाँ एक विशेष प्रमुख वर्ग अर्थात् ब्राह्मण वर्ग को नैतिकता या धर्म का संरक्षक व प्रवर्तक माना गया। इसके साथ ही शासक या राजा से भी अपेक्षा की गयी कि वह ऐसे महान और वीरता के कार्य करे, जिस से उसकी प्रतिष्ठा अवतार या देवताओं के समान हो। ऐसे राजा या लोकनायक की प्रतिष्ठा और प्रभाव ब्राह्मणों या ऋषियों से कम नहीं होता था। ऐसे राजपति ब्राह्मण ऋषियों के समकक्ष होते थे।

उल्लेखनीय यह है कि आज के राजनीतिक नेताओं के रूप में परंपरागत ब्राह्मण और आधुनिक लौकिक नेताओं के तत्त्वा का मिलन देखने को मिलता है। आज के राजनीतिक नेता एक अर्थ में आधुनिक भारत के ब्राह्मण हैं। इनकी इस प्रतिष्ठा का कारण कुछ तो यह है कि इन्होंने महान परिवर्तनों को लाने में क्रान्तिकारी भूमिका अदा की है। दूसरे, महात्मा गांधी और नेहरू जैसे नेताओं का महान व्यक्तित्व है। तीसरे, आज के सामाजिक जीवन में इन नेताओं का अप्रतिम प्रभाव है। इसका एक परिणाम यह है कि नेता को नैतिकता का भी संरक्षक माना जाता है और उसे उपदेश की भाषा में ऊँची ऊँची बात करनी पड़ती है और ऐसे लंबे चौड़े आश्वासन देने पड़ते हैं, जो सभी जानते हैं कि असंभव हैं। भारतीयों की दृष्टि में आदर्श नेता वह है जिसमें ज्ञान और क्रम दोनों का संगम है जो विचारक होने के साथ साथ कमठ भी हो। इसीलिए यहाँ नेहरू जैसे व्यक्तियों की इतनी प्रतिष्ठा और प्रभाव है। इसलिए यहाँ आज के नेताओं से ऐसी बातों की अपेक्षा की जाती है जो राजनैतिक क्षेत्र के लोगों से नहीं की जानी चाहिए। दूसरी ओर इसके कारण आदर्श और यथार्थ में नेता की कथनी और करनी में जो अंतर है उस पर ज्यादा चिंता नहीं की जाती। इसीलिए हर क्षेत्र में गुटबंदी और फूट हाने पर भी ऊपर से सहमति या आम राय पर जोर दिया जाता है। इसीलिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध बेहद शोरगुल मचाने पर भी उसके खिलाफ कार्रवाई करने की या उसे रोकने की कोई खास कोशिश नहीं की जाती।

१९ रीनकोट-पूर्वोक्त। पृष्ठ - 'द स्प्रिट ऑफ चारनाज पालिटिक्स'।

२० कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राजा को सर्वशक्तिमान जैसा माना है। यदि रचना चाहिए कि मित्रों के हमले के बाद फैला अराजकता में मानव शासन का आवश्यकता बहुत अधिक थी। इस अर्थ में अर्थशास्त्र की तुलना हॉमर के 'ओडिससी' से की जा सकती है। परंतु हॉमर का कल्पना, जिसमें राज्य एक सशक्त मनुष्य है, जो अपने अंगों से भा स्वतंत्र है, प्राचीन भारत में जोर नहीं पकड़ पाया। पृष्ठ बाइबल - 'द ब्रदर ट्रेड वाज इंडिया' (१९५४)। रत्नसामी - 'एम्प्रायल ऑफ एशियन स्टेट्स - क्राफ्ट' (१९६२)।



नैतिक बल से सबधित एक प्रश्न यह भी है कि समान उद्देश्य से एक साथ काम करने में व्यक्ति और समूह एक दूसरे पर कहा तक भरोसा कर सकते हैं। यहाँ हिंदू मनोवृत्ति की एक विचित्र विशेषता है, एक दूसरे पर सदेह और अविश्वास की। मिल कर कोई काम किया जा सकता है, इसमें हिंदू के मन में हमेशा दूसरे के प्रति संशय रहा है, पास कर सरकार या शासन के प्रति शका और अविश्वास।<sup>२३</sup> ऊँचे तबू के लोग भी चाह राजनीति में या अन्य ऊँचे पेशा में लोग को अपने सहायिगियों की ओर से शक रहता है। यहाँ लोगों के लिए बराबरी के दर्जे पर दूसरे सहयोगियों के साथ काम करना कठिन है, मातहत या ऊपर रह कर काम करने में उन्हें आसानी रहती है। सहयोगी दलों के साथ गठबंधन में हमेशा अविश्वास और अनिश्चय बना रहता है कि कब तक यह सहयोग चलेगा, सहयोगी या दूसरा व्यक्ति अपना करार पूरा करेगा या नहीं। इस परस्पर अविश्वास व कारण एक बड़े या श्रेष्ठ व्यक्ति, नेता और गुरु के अनुगत होने की प्रवृत्ति रहती है।

लेकिन आधुनिक युग की आवश्यकताओं, और बड़े पैमाने पर चलन वाले सामूहिक कार्यक्रमों के कारण यह मनोवृत्ति बदल रही है। फिर भी यह ध्यान योग्य है कि सहयोग और मिलकर काम करने की भावना ज्यादातर वही प्रकट हुई है, जहाँ एक चमत्कारी या महान व्यक्ति के नेतृत्व में काम किया जाता है, वजाय वहाँ जब एक बराबर के लोग मिल कर काम कर। गांधी और नेहरू के नेतृत्व में यही स्थिति देखने को मिलती है। गांधी को अपना स्थान छिने का भय नहीं था। मगर नेहरू दूसरे नेताओं का प्रभाव बढ़ते देख कर, उनसे अपना स्थान छिने के प्रति शक्ति हो जाते थे।<sup>२४</sup> नेहरू के बाद जब सामूहिक नेतृत्व का दौर आया तब ऊँचे से ऊँचे नेताओं में परस्पर अविश्वास और एक दूसरे से शंका की यही प्रवृत्ति दीख पड़ी। वास्तव में केन्द्रीय नेतृत्व के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है कि वे बराबर के साथी और सहयोगी के रूप में एक दूसरे का कहा तक भरोसा कर सकते हैं।

आज के भारत में सामूहिक मनोवृत्ति के विकास की चर्चा हम आगे फिर करेंगे। यहाँ हमें यह देखना है कि बचपन में घर और समाज के संस्कारों से और बड़े होकर शिक्षा-दीक्षा से किस प्रकार उस विशिष्ट भारतीय मनोवृत्ति का विकास होता है जिसकी चर्चा हमने ऊपर की है।

२३ इस मनोवृत्ति का चित्रण फोस्टर के प्रसिद्ध उपन्यास 'ए पैमेज डु शडिया' में हुआ है। और भी देखिए-मारिस् कार्टेयर्स- 'द टूनाम वान' (लंदन १९५७)।

२४ टटनजी के कायेस अ यक्ष चुने जाने पर नेहरू की नाराजी और उनका विरोध और अपने अंतिम दिनों में कामराज योजना द्वारा सम्भावित प्रतिद्वंद्वियों की सफाई, इसके प्रमाण हैं, यद्यपि दोनों ही बार नेहरू की स्थिति की कोश वास्तविक खतरा न था।



लकी चौड़ी वाते करने की यह प्रवृत्ति आज सिद्धान्त बधारने की प्रवृत्ति के रूप में प्रकट हुई है। याद रखना चाहिए कि भारतीय परंपरा में ऊँचे आदर्शों पर हमेशा जोर दिया गया है, भले ही वे चरितार्थ न हो सकें, और आदर्शों को व्यवहार में न ला सकने के कारण लोगो को ज्यादा दोष भी नहीं दिया जाता। इसके फल स्वरूप सावजनिक जीवन में जो ढोंग और पाखंड आ गया है, नेताओं को कहने और करने में, जादश और व्यवहार में, जो अंतर है, उसकी भारतीय लोग ज्यादा परवाह नहीं करते। व्यक्तिगत जीवन में भी व्यवहार के मानदंड बहुत ऊँचे रखे जाते हैं, परंतु उनका पालन न कर पाने पर ज्यादा परगानी नहीं अनुभव की जाती। इसी कारण भारतीय राजनीति में बात तो लकी लकी की जाती है, मगर उन पर जमल करने की ज्यादा कोशिश नहीं की जाती और इस पर कोई शम और विफलता या निराशा का बोध नहीं होता।

#### (४) विश्वास और अविश्वास

जादश और व्यवहार के बीच इस अंतर और भारतीय मानस की इस द्वधता से एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि जनसमाज ने सामाजिक और राजनैतिक मानदंडों को कहा तक ग्रहण किया है और सामूहिक प्रयत्न में कहा तक एक दूसरे पर विश्वास या अविश्वास किया जा सकता है। ध्यान रह कि मनुष्य के स्वभाव के प्रति भारतीय दृष्टि ईसाई और कनफ्यूसी दृष्टि से भिन्न है। न तो यहाँ ईसाइया की तरह मनुष्य को स्वभाव से बुरा माना गया है, न कनफूसे की भौतिस्वभाव से अच्छा। इसलिए यहाँ यह नहीं समझा जाता कि समाज को व्यक्ति की स्वभावगत दुष्ट प्रवृत्तियों पर अकुश रखना चाहिए न यह कि समुचित सामाजिक संस्कार से मनुष्य की स्वाभाविक सद्प्रवृत्तियों के प्रकट होने का अवसर मिलेगा। भारतीय दृष्टि में धर्म या नैतिकता का सबंध मुख्य रूप से व्यक्ति से स्वयं है और उसका उद्देश आत्मोन्नति या मोक्ष है। यहाँ पाश्चात्य धारणा के अनुसार नैतिक कर्तव्य दूसरा के प्रति नहीं बल्कि 'मिल' के शब्दा में अपने प्रति है। २१ कम के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक मनुष्य का कल्याण या मोक्ष उसके कर्मा पर निर्भर है इसलिए यहाँ कोई ऐसा कर्तव्य नहीं जो दूसरा के प्रति हो, सभी नैतिक कर्तव्य अपने ही प्रति हैं। २२

२१ पाश्चात्य दार्शनिक काट ने अवश्य अपने प्राणि नैतिक कर्तव्यों की चर्चा की है, परंतु सब मिला कर, जैसा कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है, पश्चिम में नैतिक कर्तव्य की धारणा मुख्यतः सामाजिक है। इस विषय पर आधुनिक विचार के लिए देखें पॉल डी आइसनबुर्ग, 'जूडीन डू वनने' एंड द कमेन्स आफ मारोलेटी एनक्वायरी, २, स २, ग्रीष्म १९६८।

२२ इस सिद्धान्त का सम्यक् विवेचन एस के मेन के एथिक्स आफ द हिन्दू (कलकत्ता-१९२५) में देखें। राजनीतिक सरकार के लिए कर्म-सिद्धान्त की उपयोगिता के लिए देखें- नंदी, पूर्वोक्त।

नैतिक वृत्ति से सबधित एक प्रश्न यह भी है कि समान उद्देश्य से एक साथ काम करने में व्यक्ति और समूह एक दूसरे पर कहा तक भरोसा कर सकते हैं। यहाँ हिंदू मनोवृत्ति की एक विचित्र विशेषता है, एक दूसरे पर सदेह और अविश्वास की। मिल कर कोई काम किया जा सकता है, इसमें हिंदू के मन में हमेशा दूसरा के प्रति सशय रहा है, ग्यास कर सरकार या शासन के प्रति शका और अविश्वास।<sup>२३</sup> ऊँचे तबके के लोगो में भी चाहे राजनीति में या अन्य ऊँचे पेशों में लोगो को अपने सहयोगियों की ओर से शक रहता है। यहाँ लोगो के लिए बराबरी के दर्जे पर दूसर सहयोगियों के साथ काम करना कठिन है, मातहत या ऊपर रह कर काम करने में उन्हें आसानी रहती है। सहयोगी दलों के साथ गठबंधन में हमेशा अविश्वास और अनिश्चय बना रहता है कि कब तक यह सहयोग चलेगा, सहयोगी या हमारा व्यक्ति अपना करार पूरा करेगा या नहीं। इस परस्पर अविश्वास के कारण एक बड़े या श्रेष्ठ व्यक्ति, नेता और गुरु के अनुगत होने की प्रवृत्ति रहती है।

लेकिन आयुनिक युग की आवश्यकताओं, और बड़े पैमाने पर चलन वाले सामूहिक कार्याक्रमों के कारण यह मनोवृत्ति बदल रही है। फिर भी यह ध्यान योग्य है कि सहयोग और मिलकर काम करने की भावना ज्यादातर वही प्रकट हुई है, जहाँ एक चमत्कारी या महान व्यक्ति के नेतृत्व में काम किया जाता है, बजाय वहाँ जब एक बगबर के लाग मिल कर काम कर। गांधी और नेहरू के नेतृत्व में यही स्थिति देखने को मिलती है। गांधी को अपना स्थान छिनने का भय नहीं था। मगर नेहरू दूसरे नेताओं का प्रभाव बढ़ते देख कर, उनसे अपना स्थान छिनने के प्रति चिन्तित हो जाते थे।<sup>२४</sup> नेहरू के बाद जब सामूहिक नेतृत्व का दौर आया तब ऊँचे में ऊँचे नेताओं में परस्पर अविश्वास और एक दूसरे से शंका की यही प्रवृत्ति दीख पड़ी। वास्तव में केन्द्रीय नेतृत्व के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है कि वे बराबर के साथी और सहयोगी के रूप में एक दूसरे का कहाँ तक भरोसा कर सकते हैं।

आज के भारत में सामूहिक मनोवृत्ति के विकास की चर्चा हम आगे फिर करेंगे। यहाँ हमें यह देखना है कि बचपन में घर और समाज के सत्कारों से और बड़े होकर शिक्षा-दीक्षा से किस प्रकार उस विशिष्ट भारतीय मनोवृत्ति का विकास होता है, जिसकी चर्चा हमने ऊपर की है।

२३ इस मनोवृत्ति का चित्रण फोस्टर के प्रसिद्ध उपन्यास 'ए पीनेन टु शडिया' में हुआ है। और भी देखिए-मॉरिस कार्टेयस- 'द टू वाश्म बान' (लंदन १९५७)।

२४ टल्हनजी के वॉशिंग्टन अग्रश्रेष्ठ चुने जाने पर नेहरू की नाराजी और उनका विरोध और अपने अंतिम दिनों में कामगार योजना द्वारा समाजवादी प्रतिद्वंद्वियों की सहाई, इसके प्रमाण हैं, यद्यपि दोनों ही बार नेहरू की स्थिति को कोई वास्तविक खतरा न था।



परिवार में बच्चे पर केवल माता-पिता का ही नहीं नाना, मामा, चाचा, बुआ, मौसी आदि अनेक रिश्तेदारों का प्रभाव पड़ता है, बल्कि पिता के लिए बच्चे में बहुत अधिक दिनचर्या लाना उचित नहीं समझा जाता। पश्चिम की सभ्यता में पिता का आधुनिक अधिनार के फलस्वरूप पिता-पुत्र में प्रतिद्वन्द्विता की जा भावना उत्पन्न हो जाती है, वह भारत में अधिक दमने का नहीं मिलती। यहाँ अधिनार जताने के बजाय एक दूसरे का प्रति वतव्य का बोध रहता है।

दूसर, बच्चे के मामने एक पिता का ही नमूना नहीं रहता, चाचा नाना, दादा, मामा आदि अनेकों रिश्तेदार रहते हैं, जिनसे वह स्नेह पाता है और जिनको वह नमूना बना समझता है। इससे भी अहं भाव के बजाय जादशवादा का ज्यादा प्रभाव मिलता है।

तीसर, जहाँ एक ओर बच्चे को बहुत प्यार किया जाता है और जहाँ वह रोया उसे दूध पिलाया या गाना सिलाया जाता है और उसकी जरूरतें पूरी की जाती हैं, वहाँ यह भी है कि हर वक्त उसको नेकर परगान भी नहीं हुआ जाता। वह पालने पर पड़ा रहता है। जब रोया तो उसकी जरूरत पूरी कर दी गयी, फिर उसे अकना छोट दिया गया।<sup>२८</sup> बच्चा कभी एकमात्र ध्यान का केन्द्रबिंदु नहीं रहता।<sup>२९</sup> घर में बहुत से लोगो के रहने से बच्चे का ज्यादा आश्वस्ति और सुरक्षा का बोध होता है, किन्तु इसी के साथ किसी एक ही व्यक्ति से उमका बहुत अधिक लगाव या तादात्म्य नहीं होता।<sup>३०</sup> बड़े होने पर बच्चा दूसरों को दखना और सीखना शुरू करता है। यहाँ ऐसा मान्यता है कि बच्चा सिखाने से उतना नहीं सीखता जितना दूसरा को देखकर स्वयं सीखता है। इससे बच्चे को अधिक छूट और आजादी रहती है, साथ ही उसके ऊपर अधिकार और अनुशासन का अकुश भी डीला रहता है।

चौथे भारत में एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी में या बड़ा छोटा में बड़ा अंतर या पाथक्य नहीं है। जैसे ही बच्चे कुछ बड़े हात हैं, जो चलने फिरने और बातने लाते हैं, वे वयस्को के क्रियाकलाप में भाग लेने जाते हैं। पश्चिमी समाज की तरह उह जल्दी मुनाने और बड़ा की गोष्ठियाँ से जलग रखने की कोशिश नहीं की जाती। जसा कि एक भारतीय अफसर ने एक विदेशी मनोशास्त्री से कहा — आप लोग बच्चा का पालन करते हैं, हम उनके साथ रहते हैं।<sup>३१</sup> यहाँ बालक को ऐतिहासिक चक्र की सनातन क्रिया का जग माना जाता है, और उसे जीवन के जादश और मूल्य चुनने की बहुत आजादी रहती है। दूसरी सभ्यताओं के देशकाल से

२८ मिर्नर ऐंड हिचमक-पूर्वोक्त पृ १७।

२९ वही-३१।

३० नारायण, पूर्वोक्त पृ १७०।

३१ गर्फी-पूर्वोक्त पृ ५१। उक्त अधिकारी भूतपूर्व शिक्षा सचिव श्री प्रेम कृपाल थे।

## राजनैतिक-सामाजिक संस्कार

भारतीय समाज में व्यक्तित्व का विकास और सामाजिक संस्कारों के बारे में बहुत न अध्ययन हो रहा है। १५ यहाँ हम कुछ निष्कर्षों को प्रस्तुत करेंगे।

(१) हर आलोचक ने यह बात लक्ष्य की है कि भारत में बच्चा को उनकी माता ही नहीं कुटुंब के और लोगों की ओर से भी बहुत-ताड़ प्यार और छट मिलती है। इससे बच्चा को निराशा और धक्का नहीं लगते, इस कारण उनमें सधप की प्रवृत्ति, सत्ता या अग्रिम के प्रति विद्रोह या प्रतिरोध की वृत्ति नहीं पैदा होती और बलिष्ठ व्यक्तित्व या अहं का विकास नहीं होता। दूसरी ओर उस में आत्मविकास की सबन प्रेरणा होती है कि उसकी नैतिक गति का स्रोत वह अपराध या कुछ इसका यह नतीजा होता है कि उसकी नैतिक गति का स्रोत वह अपराध या कुछ भावना नहीं होती जो सबल व्यक्तित्व प्राप्त न कर पाने के कारण उत्पन्न होती है। उसे नैतिक शक्ति मिलती है एक व्यक्तिगत आदर्श से जिसका विकास वह स्वयं करता है। उस कार्य की प्रेरणा समाज और बाहरी सत्ता का प्रति दायित्व के भाव से नहीं बल्कि आत्मविकास और अपने से ग्रहण किया आदर्श से मिलती है। इससे आसत आदर्शों को ऊँचा काम करने के लिए प्रेरणा अधिक नहीं होती।

पूणता का उसका आदर्श वह स्वयं स्थिर करना है कोई बाहरी सत्ता नहीं। उसके नैतिक पमाने उसका अपन विकसित किए होते हैं। दूसरी ओर भारतीय संस्कृति कुछ सावजनीन ऊँचे आदर्शों का भी विकास करती है जो उच्चावसाही और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को प्रेरित करते हैं। जीवात्मा परब्रह्म परमात्मा से अभिन्न है १६ यह धारणा उस ऊँच से ऊँचा उठने और पूणता प्राप्त करने को प्रेरित करती है। इससे यह भाव उत्पन्न होता है कि उस ऊँचाई और पूणता को प्राप्त करना मामूली आदमी का बस की बात नहीं है १७ इसी कारण यहाँ गुरु, सयासी या महान पराक्रमी और चमत्कारी व्यक्तियों का इतना महत्त्व और प्रभाव पड़ता है जिससे उपयुक्त प्रवृत्तियों को बल मिलता है। एक तो यह है कि नयुक्त या बड़े

- १५ देखें - पी एम नाथ 'मिस्ट्रान आफ द माइ' (आध्यात्मिक १९४४)। गार्नेर मर्फी - 'इन द माइंड ऑफ मैन्' (न्यूयार्क १९५३) अथवा ५, बर्डी मार्लिन वार्टेयर्स। थॉमस नारायण - 'हिंदू केल्चर एंड द न्यू मिनिस्ट्री' (बर्क १९५७) अध्याय ७, बीट्रिस वॉलिंग, स्यान्ति - 'मिक्स कल्चर एंड द न्यू मिनिस्ट्री' (न्यूयार्क १९६३) में - द राजपूत ऑफ द लापूर - से मिन्ने और नान दिव्यन तथा मिनिस्ट्री (बर्क १९६६)।
- १६ स्प्रेट श्मे 'बहिमुली निज' (प्रोपेडिक्चर एंड प्रोपेडिक्शन) पड़ता है अथवा स्वयं का सारे विश्व से तात्पर्य की प्रवृत्ति।
- १७ वार्टेयर्स-पूर्वोक्त पृ ५५।

परिवार में बच्चे पर केवल माता-पिता का ही नहीं नाना, मामा, चाचा, दूआ, मौसी आदि अनेक रिश्तेदारों का प्रभाव पड़ता है, बल्कि पिता के लिए बच्चे में बहुत अधिक दिलचस्पी लेना उचित नहीं समझा जाता। पश्चिम की सभ्यता में पिता के आक्रमक अधिकार के फलस्वरूप पिता-पुत्र में प्रतिद्वंद्विता की जो भावना उत्पन्न हो जाती है, वह भारत में अधिक देखने को नहीं मिलती। यहाँ अधिकार जताने के बजाय एक-दूसरे के प्रति कृतव्य का बोध रहता है।

दूसरे, बच्चे के सामने एक पिता का ही नमूना नहीं रहना, चाचा, नाना, दादा, मामा आदि अनेकों रिश्तेदार रहने हैं, जिनसे वह स्नेह पाता है और जिनको वह नमूना बना सकता है। इससे भी अहंभाव के बजाय आदर्शवाद का ज्यादा बल मिलता है।

तीसरे, जहाँ एक ओर बच्चे को बहुत प्यार दिया जाता है और जहाँ वह रोया उस दूध पिलाया या खाना खिलाया जाता है और उसकी जरूरतें पूरी की जाती हैं, वहाँ यह भी है कि हर वक्त उसको लेकर परेशान भी नहीं हुआ जाता। वह पालने पर पड़ा रहता है। जब रोया तो उसकी जरूरत पूरी कर दी गयी, फिर उस अकेला छोड़ दिया गया।<sup>२८</sup> बच्चा कभी एकमात्र ध्यान का केन्द्रबिंदु नहीं रहता।<sup>२९</sup> घर में बहुत से लोगों के रहने से बच्चे का ज्यादा आश्वस्त और सुरक्षा का बोध होता है किंतु इसी के साथ किसी एक ही व्यक्ति से उसका बहुत अधिक लगाव या तादात्म्य नहीं होता।<sup>३०</sup> बड़े होने पर बच्चा दूसरा का देखना और सीखना शुरू करता है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि बच्चा सिलाने से उतना नहीं सीखता जितना दूसरों को देखकर स्वयं सीखता है। इससे बच्चे को अधिक छूट और आजादी रहती है, साथ ही उसके ऊपर अधिकार और अनुशासन का अकुल भी डीला रहता है।

चौथे भारत में एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी में या बड़ा छोटा में बड़ा अंतर या पाथक्य नहीं है। जिस ही बच्चे कुछ बड़े हाथ हैं, जार चलने फिरने और बोलने लगते हैं, वे बयस्का के क्रियाकलाप में भाग लेने जाते हैं। पश्चिमी समाज की तरह उन्हें जल्दी मुलाने और उड़ा की गोष्ठियाँ में जनग रखने की कोशिश नहीं की जाती। जैसा कि एक भारतीय अफसर ने एक विदेशी मनोशास्त्री से कहा — आप लोग बच्चा का पालन करते हैं, हम उनके साथ रहते हैं।<sup>३१</sup> यहाँ बालक का ऐतिहासिक चक्र की सनातन क्रिया का अंग माना जाता है, और उस जीवन के आदर्श और मूल्य चुनने की बहुत आजादी रहती है। दूसरी सभ्यताओं के देसकाल से

२८ मिटर्न ऐन् दिचनक-पूर्वोक्त पृ १७।

२९ वडा-१९८।

३० नारायण, पूर्वोक्त पृ १७९।

३१ मार्क-पूर्वोक्त पृ १। उक्त अधिकारी भूतपूर्व शिक्षा सचिव श्री प्रेम कृष्ण थे।

सीमित प्रतीकोक्त कारण जो रोक या सीमाएँ रहती हैं, भारत में उनका अधिक प्रभाव नहीं रहता। इस कारण भी यहाँ आक्रमक व्यक्तित्व या अहं का विकास नहीं होता।

(३) बालक के पूर्वोक्त संस्कारों में भारतीय व्यक्तित्व की एक और विशेषता लक्षित होती है। यह है अनेकता और विभिन्नता का स्वीकार करने की प्रवृत्ति। चूंकि आक्रमक अहं और महत्वाकांक्षा कम होती है, इसलिए एक ही मूल्यों और मानदंडों के अनुरूप बनने की मजबूरी या दबाव नहीं होता। चूंकि मुख्य नतिक आदर्श आत्मविकास होता है इसलिए किसी एक आचार या नमूने पर चलने की मजबूरी भी नहीं होती। बचपन में जो संस्कार पड़े होते हैं उससे भी इस विश्वास को बल मिलता है कि प्रत्येक व्यक्ति का उद्धार और मोक्ष उसके ही हाथ में है। इसीलिए आदर्श और व्यवहार में जनर होने पर आकांक्षा या छद्म में विफलता या भ्रष्ट हो जाने पर अविनम्य ध्यान नहीं दिया जाता। आखिर सभी मनुष्य एक समान तो नहीं। इस प्रकार बचपनी और तरुणी की दृढ़ता, आदर्श और आचार की भिन्नता मोचने-विचारने के अन्तर, को स्वीकार किया जाता है। कुटुंब में व्यक्तित्व के जो अनेक नमूने बच्चे के सामने रहते हैं उससे भी इस प्रवृत्ति को बल मिलता है।

(४) दूसरी ओर इस विभिन्नता और अनिश्चितता में एकरूपता और निश्चितता स्थापित करने की प्रवृत्ति भी लक्षित होती है। इसके लिए विधिविधान और कर्म-कांड के कठोर नियम बनाए गए हैं और बड़े-छोटे आचार्य-अनुगम सब स्थापित किए गए हैं। यहाँ भी कौटुंबिक और सामाजिक संस्कार महामय होते हैं। मध्य वर्ग के हिंदू घरों में बालक को माता और बड़ी बूढ़ियाँ स इतना प्रेम और सार सभाल मिलती हैं कि बड़े होने पर भी उसमें दूसरों पर आश्रित रहने की आदत पड़ जाती है। इसके साथ ही उनमें माँ बाप और बड़ा के आज्ञापालन की भी आदत पड़ जाती है। जब वह समाज में आता है तब वहाँ भी उसकी यह आदत बनी रहती है। बजुर्गों और बड़ा की बात मानने, उनकी इज्जत करने और निर्धारित विधिविधान और रीतिरिवाज पर अमल करने की उसमें सहज प्रवृत्ति होती है। विदेशी आलोचकों ने लक्ष्य किया है कि भारतीय अधिकारियाँ और राजनीतिका के साथ मातृहता अनुगता उपरासिया, कर्तव्यों का कितना बड़ा लवाजमा रहता है और जीवन के हर क्षेत्र में वरिष्ठ या सीनियर का कितना अदब किया जाता है। इससे फलस्वरूप ऊँचे अधिकारियों की क्षमता में अधविश्वास—सा उत्पन्न हो जाता है।<sup>१२</sup> और अपने स ऊँचे अधिकारों पर जिम्मेदारी और नियंत्रण टालने

१२ इंग्लैंड भारत में महान नेताओं की छद्म प्रवृत्ति है और उसमें अनेक गुणों का आरोप कर दिया जाता है। यहाँ नेता का कार्य क्षेत्र नहीं बल्कि अतिमानुष योगी या अवतार का है, जिसमें साधारण जन की कमजोरियाँ नहीं होतीं। जबकि बाहर गांधी को सहज शान्तिवादी समझा जाता था, यहाँ वह चमत्कारी पुरुष माने जाते थे जिन्होंने बड़े दम शक्तिशाली भिक्षु साम्राज्य से छोड़ा लिया।

की प्रवृत्ति रहनी है तथा अपने बराबर के आदमियाँ से व्यवहार करते समय एक खटका-सा लगा रहता है। (भारतीय कुटुम्ब में मादया-बहना में प्रतिद्वन्द्विता देखने को नहीं मिलती। क्योंकि अपने में बड़े भाई या बहन का अदब सहज स्वभाव बन जाता है। इसी बड़े-छोटे सम्बन्ध और अदब-लिहाज के कारण बराबरी का व्यवहार करने में अननुस लगता है)।

(५) इससे एक बात यह निम्निलती है कि कौटुम्बिक और बड़े-छोटे सम्बन्ध को छोड़कर बाकी सब व्यवहार में भारतीय दूसरा का शक और अविश्वास की निगाह से देखते हैं। यह सब इस बात से उत्पन्न होता है कि एक ओर भारतीय समाज में बालक को बेहद प्यार दिया जाता है और हाथ हाथ लिया जाता है और दूसरी ओर वयस्क जीवन का आदम आत्ममयम और आत्मविकास का है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है इस आदम पर जोर दिया जाता है और वयस्क लोगों का सब उसके प्रति अप्रत्याशित रूप में नज़र और कठोर होता जाता है। इससे उसके मन में अरक्षा और अस्थिरता का भाव पैदा हो जाता है।<sup>३३</sup> पहले तो बहुत दिनों तक बालक पर माता की छाया रहनी है, फिर एकदम वह हट जाती है। पहले तो वह दूध पिलाना बंद कर देती है पिता की आर या उससे छोटे बहन-भाई की आर ज्यादा ध्यान देने लगती है, और कामा में फँस जाती है। लेकिन यह स्थिति तो सभी समाज में आती है। विशेष बात यह है कि भारत में वयस्क के जीवन में यह स्थिति काफी देर में आती है, जिसमें वह बहुत परेशान हो जाता है। जिस दुनिया पर वह राजा की तरह शासन करता था, वह एकदम से बदल जाती है। इससे मन में अस्थिरता, अविश्वास और ऐस प्रतीक और सहारा ढूँढ़ने की प्रवृत्ति आ जाती है जिस पर भरोसा किया जा सके।

बचपन में हाथ हाथ लिए जाने के कारण जीवन में आशावाद का दृष्टिकोण उत्पन्न होता है जो अकस्मर यथाय में परे होता है। (इसी आशावादी दृष्टिकोण के कारण विदेशियों को यह प्रतीत होता है कि भारतीय व्यवहार में बड़े उदार और भल होते हैं, मगर इसमें साथ ही उनमें अपने का सही समझने और दूसरों का उपदेश देने की आदत भी होती है)। वयस्क होने पर माता का आश्रय सहसा छिन जाने पर उसके मन में निराशा का भाव आ सकता है। आत्मा की उन्नति का अत्यन्त ऊँचा आदम भी उसमें, विशेषकर अधिक प्रतिभाशाली और भावक व्यक्तियों में अपनी अपूर्णता और निराशा का भाव भर देता है। इस कारण आत्मालोचन और आत्मनिग्रह की प्रवृत्ति पैदा होती है। यहाँ तो व्यक्ति का सबसे ज्यादा स्वस्ति या तो अपने कुटुम्ब से मिलती है या अपने निकट के नातेदारों और बिरादरी से। परिवार के बाहर जाने पर भी वह लोग से कौटुम्बिक सम्बन्ध स्थापित करने की कोशिश करता है। गांधीजी का 'बापू' का रूप इसका उदाहरण है। बड़े-छोटे



का सबध भारतीया के सस्वार में ऐसा मिला हुआ है कि यह समानता के आदम के चरिताय होने में बाधक बन गया है।

मगर इसक साथ ही हम यह भी मानत हैं कि वचपन क सस्वार ही सब कुछ नहीं है। हमने साथ ही ध्यपित अपने अनुभव स और सामाजिक जीवन से लगातार सीखता रहता है। भारतीय सस्वृति की विशेषता नए तत्वा को ग्रहण करने की रही है। इसी स यह जीवित रह सकी है। अस्तु हमें देखना यह है कि आधुनिकता की महान चुनौतिया का इसने किम प्रकार सामना किया है।

### परपरा का आधुनिकीकरण

हमने दया है कि किस प्रकार विभिन्नतामयी जार राजनीतिनिरपेक्ष भारतीय सस्वृति न आधुनिक राज्य-व्यवस्था को अपनाया। अब हमें यह देखना है कि आधुनिक राज्यव्यवस्था और उसके निर्माताओं ने किस प्रकार इस राजनीति-निरपेक्ष सस्वृति की परपराओं या रूढ़ियों का सामना किया। भारत जैसी प्राचीन सस्वृति का थार वार नयी चुनौतिया और नयी सम्यताओं के हमलों का सामना पडा। इसक लिए उसने जरूर कुछ ऐसी परिपाटियों का विकास किया होगा जिनके बल पर वह इन चुनौतियों को खेल सकी। इनने अधिक विविध तत्वा को वह एक सांस्कृतिक सूत्र में बाध सकी इसस सिद्ध है कि विविधता को पूरा स्थान देते हुए भी उसन कुछ ऐसे मानदंडों का विकास किया होगा, जिह सब स्वीकार करते ह। एकता क ये मानदंड भारतीय मनीषा क अंग बन गए हैं। किस प्रकार आधुनिकता क प्रतिपादकों ने इन मानदंडों को ग्रहण किया या बर्ला इसे समझने के लिए हम पहल उन मानदंडों की चर्चा करगे जा आधुनिकता की राह में बाधक प्रतीत होत ह।

### परपरा की नयी व्याख्या

भारतीय सम्यता की मायता है कि विभिन्न जाति, लिंग, धर्णी और पद के अनुसार हम या नतिक मानदंड भी भिन्न भिन्न होते ह। इसलिए मतभेद या क्रांतिकारी आंदोलनों का विरोध या दमन करने के बजाय उनको सहन करने का रुख रहता था। यह समझा जाता था कि प्रत्येक गया या भिन्न मत उसी एक मूल सत्य की भिन्न भिन्न अभिव्यक्ति है। इस धारणा के कारण अपन ही मत को सही और बाकी सबको गलत समझने की कट्टरता नहीं आती थी और समझौता व सह-मति को अच्छा समझा जाता था। राजनीति में यह प्रवृत्ति अच्छी नहीं सिद्ध हुई, क्योंकि इसक कारण यहाँ चाणक्य क एकतन्त्र और प्राचीन गणराज्या के लोकतन्त्र, या कि इसक कारण यहाँ चाणक्य क एकतन्त्र और प्राचीन गणराज्या के लोकतन्त्र, प्रवृत्तियों को स्थान दिया गया। पिछली दो शताब्दियों की क्रांतिकारी राजनतिक विचारधारा के बावजूद प्राचीनता

और परंपरा को भी मान्यता देने की उक्त प्रवृत्ति समाप्त नहीं हुई। इस स्थिति का सामना आधुनिकता के प्रवर्तकों ने किस प्रकार किया ? पहले तो राजा राममोहन राय से लेकर गांधीजी तक सुधारका ने पुरानी मान्यताओं को नया रूप देने की कोशिश की और व्यक्ति के विवेक तथा राजनैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी व कर्तव्य की भावना का प्रतिपादन किया। भारतीय संस्कृति की परंपरागत ग्रहणशीलता के बल पर पाश्चात्य संस्कृति के तत्त्वा का भी ग्रहण करने की कोशिश की गयी।

पुरानी परंपरा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के अलग मूल्य और मानदंड स्वीकार करने की थी। इस प्रवृत्ति के बल पर राजनीतिक क्षेत्र के अलग मूल्य और नैतिक मानदंड निर्धारित किए गए। इस प्रकार पहले ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता के वाद नयी राजनैतिक सत्ता का जन स्वीकृति और मान्यता मिली। देश में सांस्कृतिक विभिन्नता की परंपरा चली आ रही थी, इससे भी नयी राजनैतिक सत्ता नए राष्ट्रीय राजनैतिक संस्कारों का प्रतिनिधि और प्रतिष्ठापिका के रूप में स्वीकृत हुई। इस प्रकार नयी लौकिक सत्ता, देश का विभिन्न प्राचीन संस्कृति धाराओं को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। इस प्रक्रिया में आधुनिकता के नए नेताओं की विचारधारा और मूल्य नयी राजनैतिक व्यवस्था में सबद्ध हुए और जनता में फैलने का मौका पा सके। दूसरी ओर ये नए नेता पश्चिम की भौतिकतावादी संस्कृति से अनेकता में एकता की पुरानी भारतीय परंपरा का ऊँचा वतावत रहे और इस प्रकार भारत की महानता बखानते रहे। श्रद्धा की इस भावना में पश्चिमी राजनीति अथ और समाज तंत्र के विधिविधान को ग्रहण करने में जो अपमान या छोटेपन का भाव होता, वह घुल सा गया। ३४

विरोधाभासों में एकता स्थापित करने की अद्वैतवादी परंपरा राजनीति में भी सहायक हुई। नयी राजनीतिक व्यवस्था समाज के विभिन्न तत्त्वों के बीच मध्यस्थता और बीचबिचाव की भूमिका अदा करने लगी और इस प्रकार समाज में फैलने लगी। एक ओर गांधी में पंचायत की परंपरा थी जो स्थानीय मतभेदों का निपटाती थी, दूसरी ओर व्यापक सांस्कृतिक एकता की परंपरा थी। इन दोनों के बीच अब मध्यवर्ती राजनीतिक व्यवस्था विकसित हुई, जो क्षेत्रों और अनेक समूहों को

३४ लुसिफन पाठ - द रिपोर्ट ऑफ चान्सीज पालिटिक्स - में कहा है कि चान को इस बात से बहुत अपमान का बोध हुआ कि उसे राजनैतिक और आर्थिक क्षेत्र में परिश्रम की भेदना की स्वीकारना पड़ा। पश्चिम में अथ और राष्ट्र में विधियों को ग्रहण करने में भारत के परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों पर उसका असर नहीं पड़ा इसलिए राष्ट्रीय अपमान की वह भावना यहाँ नहीं बोध हुई।



मनमोहा के प्रति सहिष्णुता की पुरानी परंपरा नए नेताओं के हाथ में भिन्न भिन्न भाषा और धर्म के अनुयायियों के बीच एकता स्थापित करने और सेकुलर ( धर्म-निरपेक्ष ) समाज की रचना में सहायक बनी ।<sup>३०</sup> इसी प्रकार पुरानी त्याग और माध्यवाद की प्रवृत्ति के द्वारा जनता को कष्टसहन, अपनी आकांक्षा का दमन और आवश्यकताओं को सीमित करने का प्रेरित किया जा सका । इतिहास के प्रति उदासीनता की पुरानी प्रवृत्ति नए इतिहास के निर्माण में सहायक हुई, क्योंकि इससे नेताओं को देश के निमाण का, अपनी आर्थिक व राजनीतिक नीतियों का कार्यान्वित करने का और जनता पर अपना प्रभाव जमाने का समय मिला । धीमे धीमे जैसे राजनीतिक और आर्थिक नीतियाँ फलित होने लगी, पुरानी मनावृत्ति और दृष्टि को बदलने में भी आसानी होने लगी । इसके लिए पुरानी परंपरा की नयी व्याख्या की जाने लगी । आध्यात्मिक क्षेत्रों के बजाय आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भारत की गानदार सफलता पर जोर दिया जाने लगा प्राचीन भारत के गौरवशाली साम्राज्य और उद्योग-व्यापार में समृद्धि का वर्णन किया जाने लगा । भिन्न भिन्न जाति और भाषा वर्गों ने अपनी उच्चाकांक्षा का सहारा देने के लिए अपने गौरवमय अतीत के इतिहास की शोध की । इस प्रकार भारत के मानस में परिवर्तन हुआ और लोगों का इस बात का बोध होने लगा कि हम एक नए युग का, इतिहास का निमाण कर रहे हैं ।<sup>४०</sup>

धर्म और धर्म के दो सिद्धांत भारतीय जीवन के आधारस्तम्भ थे । आधुनिक काल में इनके भी सदस्य बदले । जबकि प्रत्येक जाति, वर्ण या पेशा के धर्म या कर्तव्य निश्चित थे, धर्म के सिद्धांत में मनुष्य को पूर्वनिश्चित कर्तव्य या धर्म के वर्णन से स्वतंत्रता की गुंजाइश थी, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का प्रारब्ध उसके कर्मों से ही निर्मित होता है । नए युग के विचारों के प्रभाव से व्यक्ति के कर्तव्य और अधिकारों पर जोर दिया जाने लगा और पुरानी जाति-व्यवस्था के वर्णन ढीले हुए और धर्म या कर्तव्य की पुरानी धारणा बदली ।

पुरानी ऊँची जातियों का प्रयत्न यही था कि राजनीति उन्हीं के अधिकारक्षेत्र में रहे । किंतु बहुसंख्यक छोटी जातियों के लिए राजनीतिक कार्य ऊपर चढ़ने का साधन हो गया । गांधीजी तथा अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने विदेशी शासन के साथ सामाजिक अत्याय, ऊँचनीच, छुआछूत के विरोध को दबी हुई जनता का धर्म माना । इस प्रकार धर्म के सिद्धांत का प्रयोग उस पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने

१९ नदी-पूषाकृत ।

४० भारतीय मानस के इस परिवर्तन में नैतिक कर्तव्य का पुरानी धारणा भी बदल गई । जैसा हम पहले कह चुके हैं, भारत में नैतिक कर्तव्य या धर्म का संबंध स्वयं अपने से था दूसरों से नहीं । धर्म या नैतिकता का ध्येय आत्मोन्नति या मोक्ष था । अब गांधीजी ने इस सिद्धान्त का प्रवर्तन किया कि समाज या लोकसेवा आध्यात्मिक उन्नति का द्वार है ।

जाड़ती है।<sup>३५</sup> इस प्रकार विगधी पन्ना म समर्थ लाने की प्रवृत्ति जारी रही। आधुनिक राजनतिक दना की पद्धति में इसी प्रवृत्ति का निदशन है। इन दला म सहमति का आधार नीति या कायन्म नही गुटा या घडा मे समधीता बरान की आवश्यकता हाती है। बहुमत और जनता क प्रतिनिधित्व के नए सिद्धान्त, समझात आर सौत्वाजा की नयी राजनीति क तत्त्व है। विरोधी तत्त्वा म एकता स्थापित करने का पुरानी प्रवृत्ति नयी राजनीति म भी आयी है और इस प्रकार आधुनिक लोकतन्त्रा राजनीति भारतीय समाज म स्वीकृति पा सकी ह। स्वीकृति पान क दूसरा कारण इसकी उपयोगिता और त्काल अनुसृतता भी है।<sup>३६</sup>

अद्वन या अनकता म एकता की इस धारणा के साथ इतिहासचन और समय चन का भारतीय धारणा भी ह। इस धारणा क अनुसार इतिहास और समय का चन निरतर धूमता रहता ह आर भून भविष्य और वतमान काल के निरतर धूमने वाल चन क जाने जम है। उत्थान पतन और परिवर्तन के इस अनादि और अनत क्रम को राकने की शक्ति मनुष्य म नही। मनुष्य इतिहास का बना नही सकता, वह इतिहासचन की अनिवाय परपरा का मूक और विवश दशक है। इसलिए निवृत्ति और याग का माग जेयम्बर है। भाग्यवाद की इस प्रवृत्ति का आधुनिक भारत के नताजा ने स्वीकार नही किया क्वाक व तो इतिहास का निर्माण करना चाहत थ आर भारत को महान राष्ट्रा क बराबर स्थान लिलाना चाहते थे। परंतु जब गांधी ने इस निवृत्ति और याग का प्रवृत्ति को अपने सत्याग्रह म स्थान दिया तब भारतीय राष्ट्रीयता म एक नयी शक्ति आयी। गांधी ने त्याग और तपस्या का प्रयोग इतिहास को बदलने वाल अपन आदोलन में किया।<sup>३७</sup> विदेशी राज्य की कठार वास्तविकता की निष्क्रिय उपेक्षा के स्थान पर गांधी ने सत्य और अहिंसा पूर्वक उसम अमृत्याग का रास्ता अपनाया। अपन आत्मबल और त्याग तथा सवामय जीवन स उहान राष्ट्र के समक्ष बहुत ऊचा आदर्श प्रस्तुत किया और अपने आदोलन का बहुत नतिक शक्ति और उच्चता प्रदान की।<sup>३८</sup>

३५ अयाय ४-५ म बाणत 'मध्यवता व्यवस्था'।

३६ इन प्रसंगों में मने आशीस नदी के निषध का उपयोग किया ह और इसके लिए में उनका आभारी ह।

३७ गांधीजी का समयपालन का आग्रह, कालचन की इस गति को प्रभावित करने की रूछा का प्रदान ह। गांधी हर चीज की समय से नापते थे। उनकी कमर से हर समय घण्टी छटवती रहती थी। प्रो. निर्मल वगु के कथनानुसार, समय पालन को गांधीजी सत्य का साधना का अनिवार्य अंग मानते थे।

३८ देखें- एरिक एच. एरिक्मन 'गांधीज आटोबायोग्राफ - द सीनर एन ए चाइल्ड' द ७न स्कायर ३५ स ४- शरद १९६६। तथा सुमित्रा होवर स्टाला - द न्यू करेज - एन दम आन गांधीज सायकोलाजी' वर्ल्ड पात्रिक्स १९ न १ अक्टू १९६३।

मतभेदा के प्रति सहिष्णुता की पुरानी परंपरा नए नेताओं के हाथ में भिन्न भिन्न भाषा और धर्म के अनुयायियों के बीच एकता स्थापित करने और सेकुलर ( धर्म-निरपेक्ष ) समाज की रचना में सहायक बनी ।<sup>39</sup> इसी प्रकार पुरानी त्याग और भाग्यवाद की प्रवृत्ति के द्वारा जनता को कष्टसहन, अपनी आकांक्षा का दमन और आवश्यकताओं को सीमित करने को प्रेरित किया जा सका । इतिहास के प्रति उदासी-नना की पुरानी प्रवृत्ति नए इतिहास के निर्माण में सहायक हुई, क्योंकि इससे नेताओं को देश के निर्माण का, अपनी आर्थिक व राजनीतिक नीतियों को कार्यान्वित करने का और जनता पर अपना प्रभाव जमाने का समय मिला । धीमे धीमे जैसे राज-नतिक और आर्थिक नीतियां फलित होने लगी, पुरानी मनोवृत्ति और दृष्टि को बदलने में भी कामांसी होने लगी । इसके लिए पुरानी परंपरा की नयी व्याख्या की जाने लगी । आध्यात्मिक क्षेत्रों के बजाय आर्थिक और राजनतिक क्षेत्रों में भारत की गानदार सफलता पर जोर दिया जाने लगा प्राचीन भारत के गौरवशाली साम्राज्या और उद्योग-व्यापार में समृद्धि का वर्णन किया जाने लगा । भिन्न भिन्न जाति और भाषा वर्गों ने अपनी उच्चाकांक्षा को सहारा देने व लिए अपने गौरवमय अतीत के इतिहास की शोध की । इस प्रकार भारत के मानस में परिवर्तन हुआ और लोगो को इस बात का बोध होने लगा कि हम एक नए युग का, इतिहास का निर्माण कर रहे हैं ।<sup>40</sup>

धर्म और धर्म के दो सिद्धान्त भारतीय जीवन के आधारस्तम्भ थे । आधुनिक काल में इनके भी सदृश बदले । जबकि प्रत्येक जाति, वर्ण या पक्षों के धर्म या कर्तव्य निश्चित थे, धर्म के सिद्धान्त में मनुष्य को पूर्वनिश्चित कर्तव्य या धर्म के बंधन से स्वतंत्रता की गुंजाइश थी, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का प्रारब्ध उसके कर्मों से ही निर्मित होता है । नए युग के विचारों के प्रभाव से व्यक्ति के कर्तृत्व और अधिकारों पर जोर दिया जाने लगा और पुरानी जाति-व्यवस्था के बंधन ढीले हुए और धर्म या कर्तव्य की पुरानी धारणा बदली ।

पुरानी ऊँची जातियों का प्रयत्न यही था कि राजनीति उही के अधिकारक्षेत्र में रहे । किंतु बहुसंख्यक छोटी जातियों के लिए राजनीतिक काम ऊपर चढ़ने का साधन हो गया । गांधीजी तथा अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने विदेशी शासन के साथ साथ सामाजिक अत्याय, ऊँचनीच, छुआछूत के विरोध को दबी हुई जनता का धर्म माना । इस प्रकार धर्म के सिद्धान्त का प्रयोग उम पुरानी व्यवस्था का बनाए रखने

<sup>39</sup> नदा-पूर्वान्त ।

<sup>40</sup> भारतीय मानस के इस परिवर्तन में नैतिक कर्तव्य की पुराना धारणा भी बदली । जैसा हम पहले बत चुके हैं, भारत में नैतिक कर्तव्य या धर्म का संबंध स्वयं अपने से था दूसरों से नहीं । धर्म या नैतिकता का अर्थ आत्मोन्नति या मोक्ष था । अब गांधीजी ने नए सिद्धान्त का प्रदर्शन किया कि समाज या लोकसेवा आध्यात्मिक उन्नति का द्वार है ।

क वजाय, उसे नष्ट करने व लिए किया गया जिसके नीचे लागू सदिया से दबे हुए थे। ४१ इन दलीलें हुई और उन्नति की आर उमुच जातिपा ने ऐसे प्रय और जातीय इतिहास खोज निराले जिससे उनके ऊच पद क दावा का समर्थन होता था। ४२ पुरानी चीजा का पुनर्जीवित करने की इस प्रवृत्ति को आधुनिकतावादी अच्छा नहीं समझते, किन्तु इस क्रम म पुराने प्रतीका के अर्थ और मूल्य भी बदल रहे हैं। ४३ इससे पता चलता है कि पुरानी परंपरा की किस प्रकार नए प्रयोजन के लिए इस्तमान किया जा सकता है और नए विचार व मूल्य किस प्रकार पुरानी बातों को प्रभावित कर रहे हैं।

एक बात यह ध्यान देने की है कि राष्ट्रीय आंदोलन व दौरान और स्वतंत्रता व बाद भी पुराने पारंपरिक रंग म रंगे नेताओं का स्थान प्राचीनतावादी आधुनिकतावादी नेता ले रहे हैं। अध्याय ५ म हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। गांधी और उनके महान अनुयायी भारतीय परंपरा के प्रेमी होने के साथ साथ पुरातनत्व-प्रतिक्रियानुसीलन से मुक्त थे, इसका साथ ही व अंगरेजियतपक्ष बौद्धिक नेताओं व भाति जनता से दूर दूर नहीं रहते थे। इसी कारण वे राष्ट्र को प्रभावित कर सक और एक ही दशक के अंदर समूचे राष्ट्र की विचारधारा और उसके इतिहास का बदल सके।

स्वतंत्रता के बाद वालिग मताधिकार दिए जाने के फलस्वरूप पुरानी पीढ़ी के नेताओं के हाथ से निकल कर शक्ति राज्य, जिला और गांव स्तर के नेताओं, जातीय मवा ग्राम पंचायतों और सहकारी संघों के हाथ में चली गयी। ये नए नेता भी नेहरू की ही भाषा में बोलते हैं और लोकतंत्र व समाजवाद की दुहाई देते हैं, परंतु उनका संगठन और बोलने का ढंग जनता के ज्यादा करीब है। धार्मिक और जातीय प्रतीकों की उनकी व्याख्या जनता को ज्यादा प्रभावित करती है। वे धार्मिक और लौकिक धर्मों का जोड़ते हैं और इस प्रकार राष्ट्रीय राजनैतिक संस्कार का साधन हैं। ४४

~  
४१ स्वतंत्रता के बाद नेहरू ने बार बार "व बात पर जोर दिया कि गांधीजी पहले कह चुके थे, अर्थात् भारत को स्वयं अपना गुरुओं से मुक्त करना है।

४२ इस प्रवृत्ति में पुराने माट और चरणों की रथाएँ सशयक हुईं। देखें-ए एम शा और थाफ 'द वरीदाचा वारोठस आप गुनरात-ए वास्ट आप जीनियालजिस्ट्स एंड माइ वीथार्फर्स मिल्टन सिंगर संपादित- 'दैनिकानल इंडिया स्ट्रिचर ऐंड चर्च' (फिलिडेल्फिया १९५९)।

४३ इसी प्रकार पुरानी न्याय की धारणा की भी नयी व्याख्या का गद। इसका अर्थ मनुस्मृतियों की समालोचना और वक्रण माना गया। सनातन गुरुओं ने भूतदया और धरोहर या दृष्टी के सिद्धांत का भी प्रयोग सामाजिक न्याय के प्रतिपादन के लिए किया।

४४ देखें- मारिम जोस 'शिवान पोलि शिविम' - फिलिप्स संपादित - पालिटिक्स एंड सोसाइटी इन इंडिया' (एदन १९६३)

## नए केंद्र का निर्माण

नेतृत्व में इस परिवर्तन के साथ साथ उससे भी बड़ा परिवर्तन सस्यागत और समाज व राज के ढांचे में है। हमने देखा है कि विभिन्नता से भरे इस देश में एकता का मूल समाज की बड़े छोटे की सोपानपरंपरा और उससे संबंधित विधिविधान रहे। अध्याय दो से पांच तक हमने इस ढांचे में जो परिवर्तन आए हैं, उनकी चर्चा की है। पहले तो ब्रिटिश शासन ने पुगने ऊँच-नीच के सामाजिक ढांचे में परिवर्तन किया, फिर राष्ट्रीय आंदोलन ने और भी अधिक परिवर्तन किए। स्वतंत्रता के बाद नयी सरकार ने जो कदम उठाए उससे पुरानी व्यवस्था और उसके विशेषाधिकार को गहरा धक्का लगा।

ये परिवर्तन प्रत्यक्ष हैं। पुराने सामंती अधिकार और ऊँच नीच संबंध खतम कर दिए गए। गांवों का एकाकीपन या राष्ट्रीय जीवन में अलगाव दूर कर दिया गया और नयी अधिकारयुक्त संस्थाओं का निर्माण किया गया।<sup>४५</sup> पुरानी व्यवस्था, जिसमें हर जाति या समूह के काय, अधिकार और मानमर्यादा निश्चित थी, नष्ट हो गयी और उसके बजाय हजारों लाखों समूहों व समुदायों को सरकार, चुनाव, राजनीतिक दल और शासन के अधिकारीवर्ग में शामिल होने का मौका मिला।

बालिंग मतधिकार और समय समय पर होने वाले चुनावों ने ऊँचनीच की धारणा को नष्ट करके सबको बराबरी की श्रेणी में ला दिया। एक विख्यात विद्वान व गूढ़ा में—

“ बिना संपत्ति या शिक्षा की शर्त के हर बालिंग को वोट देने का अधिकार आधुनिक राजनीतिक समाज की स्थापना का सबसे जबदस्त साधन है। इसके साथ और परिवर्तन भी जरूरी हैं, लेकिन जब बार बार देश की पूरी बालिंग जनता को देश की सरकार को बनाने या बदलने का मौका मिलता है, तब उनमें अपनी शक्ति का भान होता है और पूरे राष्ट्र के प्रतीकों से अपनेपन का भी बोध हाता है। ”<sup>४६</sup>

मारिम काम्टेंस ने भारत की ऊँची जानिया के बारे में महत्वपूर्ण अध्ययन किया है। देवली गांव के अध्ययन से उन्हें पता चला कि राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों का गांव की जातीयवस्था की मानमर्यादा की धारणा पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने लिखा है कि केवल सभा समितियों में ही नहीं, हाट-बाजार में भी लोग नित्य पुरानी और नई बातों की तुलना करते हैं और लड़ते हैं कि

४५ प्राचीन ग्राम पंचायतों की परंपरा और प्रथाओं पर आधारित होते हुए भी नयी पंचायतें उनमें एकदम भिन्न हैं।

४६ एडवर्ड शिम—‘पोलि डेव इन द न्यू स्टेट्स’—कम्प्रेहेंसिव स्टडी इन सोमाली एंड हिंदी—ने. म. ३ अप्रैल १९६० पृ. २८७।



कितना परिवर्तन हो गया है। हर जाति के बड़े और बच्चे सब इस परिवर्तन से प्रभावित हुए हैं।

परिवर्तन की इस व्यापक प्रक्रिया की चार बाता पर लक्ष्य करना चाहिए। प्रथम, पुरानी व्यवस्था के इन परिवर्तन के समर्थन में पुराने प्रमाणों और प्रतीकों का हवाला देने के साथ, नयी लौकिक (सेकुलर) विचारधारा या तर्कों का भी हवाला दिया जाता है। दूसरे, नये परिवर्तन चलन में तो आ ही रहे हैं, इसके साथ साथ लोग पुरानी बाता से नयी बाता की बराबर तुलना भी करते हैं और इस प्रकार उनका सोच समझ कर ग्रहण कर रहे हैं। तीसरे—इस तुलना से यह धारणा पक्की होती है कि पुरानी व्यवस्था में जड़ता और सड़ाघ अगयी थी और उसे बदलने की जरूरत है। चौथे—इस नए परिवर्तन का भान। पहले जा परिवर्तन हुए थे, वे मत या विचार के क्षेत्र में हुए थे। समाज का छोटी बड़ी जातियों का ढाचा ज्या का त्या बना रहा और हर नया तत्त्व उसी ढाचे में स्थान पा जाता था। अब सब का इस बात का भान है कि इसी ढाचे में परिवर्तन आ रहा है, भले ही वह बहुत धीमे हो। इस परिवर्तन से सब को प्रसन्नता नहीं है। कुछ लोग तो इसके धीमेपन से असंतुष्ट हैं। फिर भी यह परिवर्तन फैल रहा है और आधुनिक भारत के विचारों का और सामाजिक गतिविधि को प्रभावित कर रहा है।

इस परिवर्तनबोध को फैलाने में सरकार और उसकी एजेंसिया का मुख्य हाथ रहा है। न केवल सामाजिक विकास में सरकार का अधिकाधिक हाथ रहा है और जीवन के हर क्षेत्र में सरकारों तंत्र का प्रवेश हुआ है बल्कि लोगों के मन पर भी सरकार छा गयी है। इस विषय में अध्ययन करने के लिए कुछ लोगों से प्रश्न किए गए कि अकाल आदि विपत्ति पड़ने पर किस हद तक रिश्तेदारों से और सरकार से मदद की आशा है और आप किससे मदद लेना पसंद करेंगे। ४० स्वभाविक यही था कि लोग रिश्तेदारों से ज्यादा उम्मीद करें और उनको पसंद करें, लेकिन वास्तविकता इससे उमटी थी, जैसा कि सारणी सात १ और सात २ से मालूम होगी।

४१ यह अध्ययन, सत्र फार स्टडि डेब सोसा दिल्ली टोकियो वि वि, स्टैनफोर्ड युनि और नाइजरिया की इबादान युनि का और से किया गया। भारत में यह ५ बगाल, उ प्र, गुजरात और आंध्र में किया गया। प्रश्न ये थे - (१) मान लानिए आपके परिवार पर सकुट आ जाए और उसे भरण-पोषण के लिए मदद दरकार हो। आप किससे मदद मंगिगे? क-ऐसे रिश्तेदार हैं, जो मदद कर सकें। ख-क्या सरकार या कोई सरकारी पैसा है, जो ऐसी स्थिति में मदद दे? (२) इस स्थिति में जब आपने पैसे की कमी हो और रिश्तेदार और सरकारी पैसा दोनों का एक-सी मदद देने को तैयार हो आप किससे मदद लेना पसंद करेंगे?

सारणी सात - १ क - अनग रहने वाले रिश्तेदारों से मदद की अपेक्षा ।  
ख-सरकार से मदद की अपेक्षा ।

	प्रतिशत		
	हा	नही	पता नही
<b>स० रा० अमेरिका</b>			
क-रिश्तेदार	६५ ४	३२ ०	२ ६
ख-सरकार	६६ ४	२० ३	१० ३
<b>जापान</b>			
क-रिश्तेदार	६८ ७	२४ १	६ २
ख-सरकार	४१ ४	४० ०	१४ ६
<b>भारत</b>			
क-रिश्तेदार	३१ ८	६६ ६	१ ६
ख-सरकार	५० १	४२ ४	७ १
<b>नाइजीरिया</b>			
क-रिश्तेदार	५४ २	४१ ०	४ ६
ख-सरकार	४३ ८	३६ १	०० ०

भारतीय लोग रिश्तेदारों के बजाय सरकार से ज्यादा मदद की आशा करते हैं और सरकार से ही मदद लेना पसंद करते हैं । इसका एक कारण यह है कि रिश्तेदारों से मदद लेने में हेठेपन का बोध होता है जब कि सरकार से मदद लेने में ऐसा कोई भाव नहीं होता । दूसरे, सरकार से तकाबी जार सहाय्यता से ऋण लेते रहने के कारण उनका सरकारी ऋण लेने में सुभीता मालूम होता है । जो भी हो ऊपर की पड़ताल से इतना तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता सरकार को विश्वास के साथ देने लगी है ।

सारणी सात - २ सरकार और रिश्तेदार किससे मदद लेना पसंद है - प्र० ग०

	रिश्तेदार	सरकार	दानों	किमी से नही	पता नही
स रा अमेरिका	४२ ६	५३ १	—	—	४ ३
जापान	४७ ८	३१ ०	३ ३	४ ८	६ १
भारत	२४ २	६६ ००	२ ५	१ ४	२ ८
नाइजीरिया	३३ ३	५३ ०	७ १	० ७	५ ५

जनता व दल भाषित परिवर्तन को हट सरकारोत्तरण का नाम दे सकते हैं। दल बाग का भग्न नाति लक्ष्य दिया जा सकता है कि सागा को मनायुति, मामा जिंक जीयन तथा सायाभा म सरकार का हाथ बागना जा रहा है। सरकार राज-नतिक और आर्थिक वायवमा जीम मन्त्रा का निर्धारित करती है तथा क्षति तथा परिवार के रायवमा को प्रभावित करती है।

सरकारीकरण की यह प्रवृत्ति एक तद चीज नहीं है। राजा या सरकार मार्द बाप है यह पारणा बहुत पुरान जमान म भारत में रही है और इसी कारण सरकार दान कम समय में दल एते व्यापक परिवार कर सती है। दूसरी ओर राजनीति विराग की मुख्य बा यही नहीं है कि जनता सरकार का स्वीकार कर और उग पर नगणा करे, बल्कि यह अनुभव भी कर कि सरकार स अपना काम रगाया जा सकता है और उगा उगा काम का जवाब तत्तय दिया जा सकता है। जनता व राजनीति में अधिराजिक भा लन व जनस्वरूप उगमें यह भावना ला हा रही है और यह बड़ा भारी परिवर्तन है।

प्रश्न यह है कि इस परिवर्तन का कहां तक लक्ष्य दिया गया है। भारत में परिवर्तन प्रमग बिना किसी प्राधिकारा उपलभ्युक्त व हा रह है। यही नहीं बागा व मत म यह विचार भी बहुत पढ़ल ग जमा है कि यही परिवर्तन टिकाऊ हाता है जो घाम घीम जाता की रजामनी स हा। जार जबदस्ती स किए गए परिवर्तन बहुत स्थायी नहीं हात। ४८ तबिन बाहरी लोग इस प्रमिक परिवर्तन की प्रक्रिया का लक्ष्य नहीं कर पात और यह समज बैठते हैं कि भारत में कुछ हो ही नहीं रहा है। ४९ इस भ्रामक पारणा की फलत में कुछ हद तक हमार अगरेजीता रोदिक और कुछ अप्रगामी बग का भी हाथ रहा है। हमार सत्कार भी ऐसे हैं कि परिवर्तन की प्रक्रिया में भी स्थिरता का अन्वयास होना है जबकि कुछ देश एस हैं जहाँ काद प्रगति नहीं हो रही है फिर भी आभास परिवर्तन का होना है। इगलिए जब तक हमार यहाँ सामाजिक और राजनैतिक पर्यवेक्षण और विस्लेषण पर जार नहीं दिया जाता, हमार अप्रगामी बग भी राजनैतिक परिवर्तन की गति और रत को नहीं समझ पाएंगे और जनस्वरूप अनिश्चय में पड़े रहने। इस विषय में हमार समाजशास्त्रिया पर विशेष जिम्मेदारी है।

४८ इस विचार का फैलाव में नेहरू या बहुत हाथ रहा। यद्यपि वह दूसरे देशों में हुए परि वना से बहुत प्रभावित थे, फिर भी उनका लोकतंत्री तरीकों में अल विश्वास था। उन अगमरो न पचायता राज का मन्त्रना में सहे प्रफ दिया और कहा कि इसमें विकास का काम भासा पड़ जायगा तो नेहरू ने यही कहा कि अत में इसमें उदात्त प्रगति होगी।

४९ अल्बर्ट आ दर्शमान अर्रेवेवल्पमेंट, आर्म्मेन्सिन्ग ड द पर्सनल आफ जेन रेंड लीनर शिन, बी हात स १७७ न १, सार १९६८।

कुछ प्रवृत्तियाँ बनी रहें

आधुनिकता के प्रवर्तकों ने अनेकान्तवाद की पुरानी भारतीय प्रवृत्ति का सहारा लेकर नए विचारा और सस्याआ का प्रवर्तन किया फिर भी कुछ पुरानी प्रवृत्तियाँ बनी रही। इनमें से कुछ नए परिवर्तन में बाधक हैं।

भारतीय जनता का स्वभाव शास्त्रीय या निर्धारित विधिविधान पर आल मूढ़ कर चलने का है। इसका नतीजा यह हुआ है कि सरकारी कामकाज में नियम-कायदा को महत्त्व दिया जाता है कार्यकुशलता का नहीं। नौकरशाही या दफतरशाही के शिक्के में सामाजिक आर्थिक और प्रशासनिक गतिविधि कुठित हो गई है।

भारतीय समाज में भिन्न भिन्न वर्गों या श्रेणियों का स्थान जोर अधिकार निश्चित रहा। यह प्रवृत्ति आधुनिक काल में भी कायम है। अभी आधुनिक सस्याआ का रूप स्थिर नहीं हुआ है। इस संक्रांतिकाल में आधुनिक शिक्षा या अर्थ क्षेत्रों में भी पुराने ऊँचे नीचे वर्गों की तरह स्थानीय श्रेणियाँ बन गई हैं। विरोधी तत्त्व भी अधिकार और पद की श्रेणी में स्थान पाने की काशिश करते हैं। इस प्रकार अधिक और कम अधिकार और मानमर्मादायक नए वर्ग या नयी 'जातियाँ' उत्पन्न हो रही हैं।

दूसरी जोर जसा कि पहले कहा जा चुका है, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्रों में सामूहिक रूप से काम करना भारतीयों के लिए कठिन होता है। इन क्षेत्रों में भी पुरानी जाति उपजाति की तरह गुट बन जाते हैं जैसे स्थानीय राजनैतिक और अधिकारी वर्ग के गुट। इस प्रकार विकेंद्रीकरण व्यवहार में छोटे छोटे स्थानीय गुटों या उपसमूहों का रूप धारण कर लेता है जो बड़े हुए ढंग से काम करते हैं।

बड़े पैमाने पर संगठन को चलाने का अनुभव न होने और पुराने जमाने से कुटुंब और विरादारी जैसे छोटे समूहों में रहने की आदत के कारण, भारतीयों को बहुत बड़े सामूहिक संगठनों में रहने और उनके अनुशासन में चलने से स्वाभाविक विरक्ति है। इसलिए जसा हम कह चुके हैं जब तक कोई चमत्कारी व्यक्ति का नेतृत्व न हो, भारतीय लोग सामूहिक या बड़े पैमाने पर काम करने से बचते हैं।

इस कारण भारतीयों की मनोवृत्ति ऐसी बन गयी है कि वे अपने बग़ल वाले के साथ व्यवहार करने में असुविधा अनुभव करते हैं। इसी प्रकार वे विरोध या संघर्ष की स्थिति का फ़रियाने के बदले लीपापोती करने या टालने की कोशिश करते हैं। यह भी सभी विचारा और मतांतरों को स्थान देने की पुरानी प्रवृत्ति का ही अंग है। इसका नतीजा यह होता है कि ऊपर से समझौता या एकता के पदों के नीचे मतभेद और विरोध सुलगते रहते हैं। ५० इस के फलस्वरूप हारने

१० भारत में एक प्रभावशाली वर्ग समझौते को बहुत महत्त्व देता है। यह वर्ग प्रत्यक्ष चुनाव को नापसंद करता है क्योंकि इससे झगड़ा और विरोध पैदा होता है और इसके बजाय [अगले पृष्ठ पर]

वाले या अल्प मत वर्ग में बड़ी कटुता और अनास्था भर जाती है और उनका क्षोभ भीतरही भीतर सुलगता रहता है।

हमारी इस चर्चा का निचोड़ यह है कि जहाँ भारतीय लोगों में आधुनिक युग की विभिन्न समस्याओं को चलाने और मतभेद और आलोचना को सहन करने की अच्छी क्षमता है, वहाँ बहुत बड़े सामूहिक उद्यमों का चलाने में जिस सगठन और अनुशासन की जरूरत होती है, उसमें वे कमजोर पड़ते हैं।

## निष्कर्ष

सम्यता का एक प्रकार यह है जहाँ केन्द्रीय सत्ता की समस्या प्रधान रहती है और तगातार चली आती है। दूसरे प्रकार की सम्यता यह होती है, जिसमें केन्द्रीय सत्ता जनता से दूर होती है और लगानार संपर्क में नहीं रहती है और जहाँ स्थानीय समस्याएँ स्वायत्त होती हैं तथा राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र अलग रहते हैं।

पहली सम्यता में जब आधुनिकता की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसका प्रभाव सत्ता के पूरे ढाँचे पर पड़ता है जिसमें व्यक्ति और उसके समूह का सबब होता है। दूसरी सम्यता में केन्द्रीय सत्ता में परिवर्तन होता है पर पूरी व्यवस्था पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। पहली सम्यता ज्यादा लौकिक होती है और मनुष्य मुरयत राजनैतिक व्यक्ति होता है और उसका मुख्य तगाव केन्द्रीय या राज्यसत्ता में होता है। दूसरे में व्यक्ति का लगाव अपने समूह से और आत्मविकास से होता है। यहाँ सत्ता बँटी रहती है और राज्यसत्ता जो अस्थायी होती है तथा संस्कृति जो स्थायी होती है दोनों में काफी दूरी होती है। यहाँ व्यवस्था या समष्टि अपनी व्यक्तिगत इच्छा का जोड़ या इकाइया से ऊपर नहीं समझी जाती बल्कि एक सबब शृंखला की प्रक्रिया समझी जाती है।

भारत में राजनैतिक नेतावर्ग ने देश में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भाग लिया है। फिर भी सामाजिक जीवन में राजनीति ही सबसे मुख्य तत्त्व नहीं है। अब तक जो काम समाज या बिरादरी में मुखिया करते थे, वह काम अब राजनैतिक नेता करने लगे हैं। इस प्रकार समाज के जीवन में राजनीति का प्रवेश हुआ है।

लौकिक या केन्द्रीय सत्तावाली सम्यताओं के मुकाबले गैरलौकिक सम्यता में राजनीतिका प्रवेश आसान होता है। यह प्रवेश लोगों का लाभ पहुँचा कर होता है

[ पिछले पृष्ठ से ]

एकमत या आम राय या नेपाल की तरह के अप्रत्यक्ष चुनाव को पसंद करता है। त्रयप्रकाश नारायण - एका पार रिक् सलूकेशन आफ द दियन पालिटि ( दिल्ली १९५६ )। ससेन होवर रुग्गल ने कानफ्रिक्लट ऐंड कानमे-शम इन एशिया पालि में इस पर विचार किया है ( वर्ल्ड पालिटिक्स - अप्रैल १९६१ )।

उन पर सरकारी मशीनरी लाद कर नहीं । इस प्रकार की सम्यता में राजनैतिक तन्त्र को लोगो की भावनाओं का ख्याल रखना होता है जबकि केन्द्रीय सत्तावाली सम्यताओं में सरकार लोगो को जबदस्ती अपने रास्ते पर चला सकती है । ५१ गैर राजनैतिक सम्यता में सरकार को लोगो की भावना का ख्याल रखने के साथ साथ परिवर्तन लाने में सक्रिय हाथ लेना पड़ता है । यदि यह दोनों में से किसी भी काम में विफल हो, तो उसका विराध होने लगता है ।

---

५१ ज्ञान में यही हुआ । देखिए-जूमिन पाद-रिपार्टि आफ चाइनीज पोलिटिक्स ।

## राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण और राष्ट्रीय एकता

पिछले अध्याय में भारत में होने वाले राजनितिक परिवर्तन का विस्तारपूर्ण प्रस्तुत किया गया। इसका बताया जा महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका संबंध इसमें है कि यह व्यवस्था किस प्रकार काम कर रही है।

हाल के वर्षों में राजनितिक विकास का मूल्यांकन के लिए कुछ सिद्धान्त प्रस्तुत किए गए हैं।<sup>१</sup> किन्तु साधारणतः राजनितिक विचारों ने इस बात की व्याख्या की है कि राजनितिक व्यवस्था क्या काम कर रही है और समस्याओं को हल करने में इस कितनी सफलता मिली है। जहाँ वही मूल्यांकन करने की कोशिश की भी गयी है वहाँ भी आर्थिक विकास, समाजमुधार, रूढ़ियों टूट-बीट, अक्षर आदि साधनों के प्रसार के उपायों का ही वर्णन कर दिया है। इस प्रकार उन्नत देशों की कुछ विशेषताओं को राजनितिक विकास की बसोटी बना लिया गया है। अधिकतर विश्लेषक समाजशास्त्र की मुख्य विचारधारा से प्रभावित हैं, जिसमें यह समझा जाता है कि राजनितिक परिवर्तन, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों से प्रभावित होता है तथा पश्चिमी देशों के इतिहास को दृष्टि में रखते हैं, जहाँ अधिकतर (हमारा नहीं) राजनितिक विकास समाज की मांग और दबाव का फलस्वरूप होता है। इसलिए इन लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि राजनितिक निर्माण का समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है।<sup>२</sup> अभी हाल तक राजनितिक विकास अर्थात् राजनितिक

<sup>१</sup> नेमिथल ए. आल्मड-‘पालि सिस्टम्स ऐंड पोलि जेन’ (द अमेरिकन विट्रियल साइ-टिस्ट ६ स १० जून १९६३ और आल्मड-‘ए डेवलपमेंटल अप्रोच टु पोलि सिस्टम्स’ (वर्ल्ड पालि ८ स २ जनवरी १९६५)

<sup>२</sup> ऐसे ही लेखकों का सब क्षेत्रों में भार है उदाहरण के लिए रमेलसर विलियम बार्नहार्ट सर, एस एम लिनने, काल्डवेल डेनियल लनर, वैरिगटन मूर। हेले-जोसफ ए. पालोम्बरा ‘मैक्रोथियरी ऐंड माइक्रो-अर्थिकी’ इन कम्परेटिव पालिटिक्स-ए वाइडरिंग चान्स’ (कम्परेटिव पालिटिक्स १ स १, अक्टू १९६८)। सामाजिक सिद्धान्त की दृष्टि से राजनीति और अधिकार के महत्व के लिए-‘रॉबर्ट डी. बेनविक्स-‘नेशन बिल्डिंग ऐंड मिडिजनशिप’ (‘यूएस १९६४)।

केन्द्रीय सत्ता की स्थापना और उसका फौलाव, नयी राजनैतिक पद्धति की जनता द्वारा ग्रहण होने में सफलता या विफलता, राजनैतिक भाषा को गूँग करने में उसकी क्षमता, या सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में हुए विकास से सन्तुष्ट जाड़ने या तुलना करने की कोई विधियत कोशिश नही की गई। इन प्रश्नों पर और आर्थिक क्षेत्र में हुए काम पर ग्रहण बहुत हुई है, फिर भी प्रवृत्ति दोनों को अलग अलग देखने की है। जैसा काम हुआ है, इस प्रश्न पर ध्यान न देने का परिणाम यह हुआ है कि राजनीति की गमीना गुटबंदी और उखाड़ पछाड़ का घणन घन कर रह गयी है।

अस्तु हमने भारत का राजनैतिक परिवर्तन को समझने के लिए, परपरा और परिवर्तन अर्थात् प्राचीनता और नवीनता के तत्वा का मिश्रण का विद्वेषण किया है। नयी राजनैतिक व्यवस्था अमल में और समझाया जा सके मान में जैसी रही इस पर हम इस अध्याय और अगले दो अध्यायों में विचार करेंगे। नयी राजनैतिक व्यवस्था के जड़ जमाने और राष्ट्रीय एकता की समस्याओं और आर्थिक विकास की समस्याओं तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों की समस्याओं पर हम प्रथम इस अध्याय और अगले दो अध्यायों में विचार करेंगे। इसमें हम भूतकाल की और वर्तमान प्रवृत्तियों पर विचार करते हुए, कुछ धाना में निष्पत्ति की ओर संकेत करेंगे। पर यह संकेत हागा, भविष्यवाणी नहीं।

### एकीकरण की समस्या

राजनैतिक विकास की बुनियादी समस्या एकीकरण की है जयान नये राजनैतिक केन्द्रविन्दु की स्थापना और दृढीकरण, उसका बहिर्मुख प्रस्तार, विभिन्न समस्याओं का पल्लव, विविधता को एक सूत्र में ग्रहण कर एक राष्ट्र का निर्माण अर्थात् एकीकरण की क्षमता का विकास। यही समस्या हमारे राष्ट्र निर्माताओं का सामने सबसे बड़ी समस्या रही है। जैसा कि नेहरू ने कहा था मेरे जीवन का मुख्य काम भारत का एकीकरण है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि भारत एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया से गुजर रहा है। मगर मुख्य बात यह है कि एकीकरण के लिए तरीका क्या अपनाया गया। इस तरीके में दो बातें हैं। एक सरकार और सरकारी या शासन दल की गतिविधियों के द्वारा देश में एकता की स्थापना और उसका दृढीकरण। दूसरे देश के विभिन्न तत्वों के अधिकारों और हिता का संरक्षण और मान्यता देकर उनको राष्ट्रीय जीवन और राजनैतिक व्यवस्था में शामिल करना। भारत की राजनैतिक एकता में राष्ट्रीय सरकार की प्रधानता और अन्य हिता का व अल्पसंख्यकों के प्रति समन्वित और निष्ठा की भावना इन दो प्रवृत्तियों का मुख्य योग है।

इस तरीके से समाज के राजनैतिकीकरण का बड़ा महत्व है। इसमें राजनैतिक



गतिविधि के द्वारा समान का बदलने की कोशिश की जाती है। इसमें भारतीय नेताओं को जो सफलता मिली उसका श्रेय कुछ अंश में इस बात को है कि यहाँ जनसाधारण राजनीति से उदासीन था और नेताओं तथा राष्ट्रीय सरकार से ज्यादा मांग नहीं करना था। इसके साथ ही यहाँ का प्रशासनिक, नेता तथा कांग्रेस दल भी अत्यन्त प्रभावशाली और शक्तिशाली था। लेकिन नेताओं के प्रयत्न का उद्देश्य जनता की राजनीति की ओर से उदासीनता को दूर करना था। परिवर्तन की प्रक्रिया का प्राप्ताह देना था और नये दल और हिता का मैदान में लाना था।

जब सत्ताधारी दल परिवर्तन लाने का प्रयत्न करता है तो उसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि उसके विरोधी या प्रतिपक्षी दलों का उदय हो। राजनैतिकीकरण की सफलता को आते समय इस बात का विचार करना होगा कि यह प्रक्रिया कितनी शांतिपूर्ण और सोद्देश्य रही। सत्ता के टाबे में देश के विविध तत्त्वों का कितना प्रतिनिधित्व मिला और उनमें जड़ जमाने और दशक लोगों द्वारा अंगीकरण में कितनी मदद मिली।

### दलों की समस्या

भारत में सत्ताह्व दल ने नए राजनीतिक ढाँचे के लिए संसदीय लोकतंत्र का नमूना स्वीकार किया। इस पद्धति में दो प्रतिद्वंद्वी दलों का होना जरूरी है, जिनमें अपने समर्थक बग हों। परन्तु देश में ऐसे प्रतिद्वंद्वी दलों का अभाव था। यहाँ एक कांग्रेस दल की प्रधानता थी। इसलिए प्रतिद्वंद्विता का तत्त्व इसी दल के भीतर से जाना था। इसके लिए कांग्रेस दल को अपनी रीति नीति में परिवर्तन करना पड़ता था। अब तक दल में अनुशासन और एकमत पर जोर दिया जाता था। अब विरोध या मतभेद और नेतृत्वपरिवर्तन की गुंजाइश करनी पड़ी। अवश्य ही कांग्रेस का संगठन पहले से ही काफी व्यापक था और उसमें अनेक विचारों और बगों का लोग थे। फिर भी मोटे तौर पर ये एक श्रेणी के अर्थात् अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे। अब तक इस बग से ही कांग्रेस की नेता मंडनी आती थी। बालिग मताधिकार से राजनीति जो सामूहिक रूप धारणा करती है और जिससे पद और अधिकार के नए दावेदार पैदा होते हैं, इस स्थिति से अब तक इसका सावधान नहीं पड़ा था।

देश में दूसरे मजबूत प्रतिद्वंद्वी दल के अभाव के कारण कांग्रेस को अपने संगठन के भीतर गुटबंदी को सहन करना पड़ा। यह गुटबंदी किसी सिद्धान्त या कार्यक्रम के आधार पर नहीं थी। जब तक कांग्रेस की सत्ता निर्वाह रही तब तक इससे देश की राजनीति में निरंतरता और एकता बनी रही। लेकिन जहाँ तक व्यापक व्यवस्था का प्रश्न है, कांग्रेस की आन्तरिक गुटबंदी, कांग्रेस के दूसरे दलों द्वारा सत्ताच्युत कर दिए जाने में ज्यादा हानिकारी है। इसी प्रकार की आन्तरिक गुटबंदी, पद की यही लड़ाई अनेक नए देशों में लोकतंत्री व्यवस्था के टूटने का कारण सिद्ध हुई है।

शुरू से ही भारतीय राजनीतिज्ञों ने अल्प या भिन्न मतों से समझौता करने और विभिन्न तत्त्वों को साथ लेकर चलने पर जोर दिया। कांग्रेस के नेता यह जानते थे कि अभी बहुत दिनों तक कांग्रेस की एकछत्रता कायम रहेगी, इसलिए उन्होंने देश की एकता और स्थिरता की खातिर राजनैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सभी समझौतों का साथ लेकर चलने का प्रयत्न किया और समझौते की भावना से काम लिया। भारत का संविधान त्रिपक्ष अपने अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ में ग्रेनविल आस्टिन ने लिखा है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान की रचना मंदार सिद्धांत से काम लिया। एक यह है कि सभी निर्णय सहमति से किए जाएं, बहुमत के जोर पर नहीं। दूसरा, समझौते की भावना अर्थात् अल्पमत या भिन्न मतवालों का अधिकार से अधिक रखा। ये दोनों बातें भारत की मौलिक देन हैं।<sup>३</sup> राजनैतिक फट का दुःख परिणाम देश के नेता दब चुके थे। उनको यह भी समझ थी कि बहुमत के जार से फैसला लादना नए लोकतंत्र के लिए अच्छा न होगा। इसलिए दुनिया की मुद्दा पर कांग्रेस के नेताओं ने विरोधियों की सहमति प्राप्त करने की काशिश की। किन्तु अल्पमत की भावनाओं का उचित ग्याल रखा हुआ भी उन्होंने आनुपातिक प्रतिनिधित्व अप्रत्यक्ष चुनाव अल्पसंख्यक मजहूजों को विशेष प्रतिनिधित्व और स्विटजरलैंड जैसे मजिस्ट्रेट आदि अल्पमतों के संरक्षण के विशेष उपायों को नहीं अपनाया क्योंकि वे ऐसी मुद्दों व्यवस्था करना चाहते थे जो भारतीय समाज की अनगढ़ वाली प्रवृत्तियों को काबू में रख सकें।<sup>४</sup> भारतीय नेताओं के सामने यह बात स्पष्ट थी कि राज्य का जो ढांचा उन्हें विरासत में प्राप्त हुआ, उसीके भीतर उन्हें एक राष्ट्र का निर्माण करना है और उन्होंने अपनी सांस्कृतिक परंपरा और राजनैतिक साधन दोनों का उपयोग इस उद्देश्य से किया कि जिस नाकतन की रचना की जा रही हो, उस लोग दिल से स्वीकार करें।

कांग्रेस पार्टी की रीति नीति में भी इसी प्रकार समझौते की भावना और देश की स्थिरता और दृढ़ता का ध्यान रखा गया। कांग्रेस का मुकाबला करने वाला कोई मजठन देश में न था इसलिए भी उसे जल्द मतों का ख्याल रखना जरूरी हो गया जिससे देश में क्षोभ और असंतोष के कारण फूट और अलगाव की प्रवृत्ति न पैदा हो। प्रांतीय और स्थानीय कांग्रेस में जहां प्रतिस्पर्धी गुटों और नेतृत्व के लिए प्रतिद्वंद्विता का स्थान दिया गया, वहां इस बात पर भी जोर दिया गया कि नेतृत्व में कोई भी परिवर्तन हाइकमांड या सर्वोच्च नेतागण की अनुमति के

<sup>३</sup> ग्रेनविल आस्टिन—'द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कानर रंगेन आफ ए नेशन' (लंदन १९६६)—अध्याय १८।

<sup>४</sup> ग्रेनविल आस्टिन—'द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कानर रंगेन आफ ए नेशन' (लंदन १९६६)—अध्याय १३।



परिणाम यह होगा कि कुछ समय बाद उसको चुनाती देने वाले दल उत्पन्न हो और राजनैतिक विचारधाराओं के आधार पर विरोधी दल का संगठन हो। दखने की बात यह है कि सत्तारूढ़ दल इस प्रतिद्वंद्विता को बिना बढ़ता के स्वीकार करता है और सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार होना है या नहीं, और नए सत्ताधिकारी राजनैतिक व्यवस्था की बुनियादी बातों का स्वीकार करने है या नहीं। यदि सत्ता का परिवर्तन बिना झगड़ा झझट के हाता है तो राजनैतिक व्यवस्था और संवैधानिक प्रणाली मजबूत होगी और लोगों के जीवन में घर करेगी। यदि ऐसा नहीं होता और सत्तारूढ़ तथा विरोधी दल लोकतंत्री परंपरा का पालन नहीं करते तो राजनैतिक और संवैधानिक ढांचे के टूटने की क्रिया शुरू हो जाएगी।

इस प्रकार की स्थिति भारत में १९६२ और १९६७ के बीच उपस्थित हुई। दो लड़ाईयां, और आर्थिक संकट के बाद चुनाव हुआ जिसने कांग्रेस की एकछत्रता और स्थिर सरकारों के युग का अंत कर दिया। ५ वर्षों के अंदर इतनी घटनाओं के घटने से एक संकट का सा वातावरण मालूम पड़ा।

१९६७ के चुनाव एक बड़े राजनैतिक परिवर्तन का द्योतक समझा गया। इसने इतने दिनों से चली आयी कांग्रेस की प्रधानता का अंत कर दिया। परंतु राज्यों में निर्वाचन के रुख और आम चुनाव के बाद की घटनाओं का हमारा विश्लेषण इस धारणा की पुष्टि नहीं करता। फिर भी यह समझने के लिए कि राजनैतिक व्यवस्था में नई स्थिति के अनुसार चलने की क्षमता है या नहीं, हम यह मान लेते हैं कि १९६७ में जिस प्रक्रिया का आरंभ हुआ वह बाद के चुनावों में भी कायम रहेगी और हम यह देखेंगे कि यदि कांग्रेस की प्रधानता सचमुच समाप्त होगी, तो राजनैतिक व्यवस्था किस ओर जाएगी।

(१) चुनाव में विफलता होने और शक्ति घट जाने के बाद भी कांग्रेस खतम नहीं हुई बल्कि अनेक राज्यों में मयावधि चुनाव और स्थानीय संस्थाओं के चुनावों में इसने खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त कर ली। इसने समान विचारधारा वाले दूसरे दलों से समझौता करने और स्थिति के अनुसार रीति नीति बदलने की तत्परता दिखाई है। अभी भी कांग्रेस दल की सबसे संगठित पार्टी है जिसका संगठन देश भर में फैला है। परिणामस्वरूप केन्द्र में इसका बहुमत बना रहेगा और संयुक्त सरकार या अल्प दल के साथ गठजोड़ में इसका पल्ला भारी रहेगा। दूसरे जिन राज्यों में इसकी सरकार नहीं भी रहेगी, वहां भी स्थानीय संस्थाओं में इसके हाथ में काफी शक्ति और लोगों को लाभान्वित करने के अवसर रहेंगे।<sup>५</sup>

(२) जहां जय वामपंथी या दक्षिणपंथी दल या संयुक्त दलों की सरकार है वहां भी इन्होंने कांग्रेस द्वारा स्थापित की गयी बुनियादी संवैधानिक और राजनैतिक

<sup>५</sup> माइल वाइसर - 'पार्टी विविंग इन ए नेशन - द इन्डियन नेशनल काँग्रेस (शिमागो - १९६७)।

बिना न हो। कांग्रेस के जदरूनी सगडो को निपटाने के लिए दोना पक्षों में समझौता कराने के साथ साथ ऊपर से मध्यस्थता या निणय की बाकायदा व्यवस्था की गई। यद्यपि कानून में यहा प्रारंभिक चुनावों की कोई व्यवस्था नहीं है फिर भी जिला और प्रांतीय कांग्रेस और अन्त में सर्वोच्च मंडली द्वारा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन की विस्तृत पद्धति बनी, जिससे बाहरी दलों की स्पर्धा न होते हुए भी कांग्रेस के भीतर लोकतंत्री स्पर्धा की पूरी गुंजाइश रही।

हम देख चके हैं कि कांग्रेस जैसे व्यापक संगठन को दल का रूप देने के कारण इसमें दो विशेष प्रवृत्तियाँ दीख पड़ी। एक तो कांग्रेस के अंदर के गुटों में बाहर के मुख्य दलों का प्रतिनिधित्व हुआ। कांग्रेस के अंदर स्वतंत्र गुट, जनसंघी गुट, कम्युनिस्ट गुट आदि अनेक घड़े बन गए। दूसरी प्रवृत्ति थी स्थानीय लोकतंत्र पर कांग्रेस नेताओं का आग्रह। पंचायती राज और विकास कार्य के लिए स्थानीय सलाहकार समितियाँ आदि की पूरी प्रणाली की स्थापना ऊपर के नेताओं द्वारा की गई। इसके फलस्वरूप न केवल कांग्रेस का प्रभाव बढ़ा और उसे अपने समयका को अधिकार और लाभ के पद वाटने के अवसर मिले, बल्कि इसके साथ ही सर्वोच्च नेताओं और नीचे के लोगों के बीच संपर्क की कड़ियाँ बनीं, और असंतोष व फूट की प्रवृत्ति को अकुशित करने की व्यवस्था हुई। जमींदारी उन्मूलन और दबी व पिछड़ी जातियों की विशेष संरक्षण देकर असंतोष और सघर्ष की जड़ वाटने की कोशिश की गयी और राजनैतिक व्यवस्था की दृढ़ता और स्थिरता बढ़ाने का उपाय किया गया।

कांग्रेस की प्रधानता के साथ साथ उसका जदरू प्रतिद्वंद्विता की गुंजाइश में एक बात और नक्ष्य करने की है। यह है नेताओं के व्यक्तिगत अनुयाइयों का जाल। जहाँ इन व्यक्तिगत गुटबंदियों से राजनीति में कुछ स्थिरता आई वहाँ इसका एक अच्छा नतीजा यह हुआ कि इनके माध्यम से स्थानीय गुटबंदी को राजनैतिक रूप मिल गया और वे खतरनाक या घातक रूप न धारण कर सकीं। इनके धारण ऊपर के नेताओं को स्थानीय हालतों की सही सूचना भी मिलनी रही और ऊपर की बात नीचे तक फलती रही।

इस प्रकार प्रतिस्पर्धी पार्टियाँ दल के अभाव में भी एक दशक तक ससदीय लोकतंत्र चलता रहा और कांग्रेस दल के अंदर के गुट प्रतिद्वंद्वी दलों की भूमिका बढ़ा करते रहे। तथा व्यापक अगिदा और असवार आदि जानकारी के बहुत कम साधनों के बावजूद जनता और नेता में संपर्क कायम रहा।

चुनाव की प्रणाली

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है जब मतदाता और शक्तिशाली दल लोकतंत्री प्रवृत्तियाँ और गतिविधियाँ का पूरा प्रोत्साहन और छूट देता है, तो इसका स्वाभाविक

परिणाम यह होगा कि कुछ समय बाद उमको चुनौती देने वाले दल उत्पन्न हो और राजनैतिक विचारधाराओं के आधार पर विरोधी दल का संगठन हो। दबने की बात यह है कि सत्ताह्व दल इस प्रतिद्वंद्विता का विना बटुता के स्वीकार करता है और सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार होता है या नहीं, और नए सत्ताधिकारी राजनैतिक व्यवस्था की बुनियादी बातों का स्वीकार करने हैं या नहीं। यदि सत्ता का परिवर्तन बिना षगडा झगट के हाता है तो राजनैतिक व्यवस्था और संवैधानिक प्रणाली मजबूत होगी और लोगों के जीवन में घर करगी। यदि ऐसा नहीं होता और सत्ताह्व तथा विरोधी दल लोकतंत्री परंपरा का पालन नहीं करते तो राजनैतिक और संवैधानिक ढांचे के टूटने की क्रिया शुरू हो जाएगी।

इस प्रकार की स्थिति भारत में १९६२ और १९६७ के बीच उपस्थित हुई। दो लड़ाईयाँ, और आर्थिक संकट व बाद चुनाव हुआ, जिसने कांग्रेस की एकछत्रता और स्थिर सरकारों के युग का अंत कर दिया। ५ वर्षों के अंदर इतनी घटनाओं के घटने से एक संकट का सा वातावरण मालूम पड़ा।

१९६७ के चुनाव एक बड़े राजनैतिक परिवर्तन का द्योतक समझा गया। इमने इतने दिनों से चली आयी कांग्रेस की प्रधानता का अंत कर दिया। परंतु राज्यों में निर्वाचन के रुख और आम चुनाव के बाद की घटनाओं का हमारा विश्लेषण इस धारणा की पुष्टि नहीं करता। फिर भी यह समझने के लिए कि राजनैतिक व्यवस्था में नई स्थिति के अनुसार चलने की क्षमता है या नहीं, हम यह मान लेते हैं कि १९६७ में जिस प्रक्रिया का आरंभ हुआ वह बाद के चुनावों में भी क्रियम रहेगी और हम यह देखेंगे कि यदि कांग्रेस की प्रधानता संवमुच समाप्त होगी, तो राजनैतिक व्यवस्था किस ओर जाएगी।

(१) चुनाव में विफलता होने और शक्ति घट जाने के बाद भी कांग्रेस खतम नहीं हुई बल्कि अनेक राज्यों में मध्यावधि चुनाव और स्थानीय संस्थाओं के चुनावों में इसने खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त कर ली। इसने समान विचारधारा वाले दूसरे दलों से समझौता करने और स्थिति के अनुसार रीति नीति बदलने की तत्परता दिखाई है। अभी भी कांग्रेस देश की सबसे संगठित पार्टी है जिसका संगठन देश भर में फैला है। परिणामस्वरूप केन्द्र में इसका बहुमत बना रहेगा और संयुक्त सरकार या अन्य दलों के साथ गठजोड़ में इसका पल्ला भारी रहेगा। दूसरे जिन राज्यों में इसकी सरकार नहीं भी रहेगी, वहाँ भी स्थानीय संस्थाओं में इसके हाथ में काफी शक्ति और लोगों को लाभान्वित करने के अवसर रहेंगे।<sup>५</sup>

(२) जहाँ जय वामपंथी या दक्षिणपंथी दल या संयुक्त दलों की सरकार है, वहाँ भी इन्होंने कांग्रेस द्वारा स्थापित की गयी बुनियादी संवैधानिक और राजनैतिक

<sup>५</sup> सादरन वाइनर - 'पार्टी विडिंग इन ए नेशन - द इंडियन नेशनल कांग्रेस (गिगागो - १९६७)।

परपरा और नियम का अस्वीकार नहीं किया। इनके कार्यक्रम और नीतियाँ भी कांग्रेस ने कोई खास भिन्न नहीं हैं। बल्कि अनेक पार्टियों का तो यह भी दावा है कि वे कांग्रेस की नीतियों को कांग्रेस की अपेक्षा ज्यादा अच्छी तरह से कार्या-  
वित कर रही ह।

(३) कांग्रेस की प्रधानता के युग में जो दलबन्दी और गुटबन्दी दिखाई पड़ी, वे १९६७ के बाद भी कायम रही। अनेक राज्यों में कांग्रेस में फूट पड़ने पर कांग्रेस के दलबन्दी की महायत्ना से नई सरकारें बनीं। द्र० मु० व०, जनसंघ और वामपक्षी दला में भी कांग्रेस जैसी ही दलबन्दी दोख पड़ी। जिस प्रकार कांग्रेस के अंदर दक्षिण और वाम पक्ष थे उसी तरह गैर कांग्रेसी दला या संयुक्त दला में भी कांग्रेसी गुट या पक्ष देखने में आए। दक्षिण और वाम पक्ष के बीच का मांग पकड़ने की प्रवृत्ति लक्षित हुई जिसमें दला की परिधि के बाहर जाकर सीढ़ा करने और नए गठजोड़ करने की क्रिया चालू रही। इस प्रकार राजनीतिक स्थिति बदलने और नए दला तथा नई राजनीतिक पीढ़ियाँ के आगे आने पर भी पुराना राजनीतिक लहजा कायम रहा।<sup>६</sup>

(४) कुछ नई प्रवृत्तियाँ दोख पड़ी जिससे पता चलता था कि राजनीतिक परि-  
पाटियाँ जड़ पकड़ रही हैं। पहले कांग्रेस के नेता सभी मता और हिता को संगठन में स्थान देने को तैयार रहते थे। अब उद्देश्य और संगठन की एकता पर जोर दिया जाने लगा और मतमिन्नता के कारण पार्टी छोड़ने वाला को रोका नहीं जाता था।<sup>७</sup> इसी अवधि में भिन्न मत वाले गैर कांग्रेसी दला में जा गठबन्धन हुए व टिकाऊ नहीं सिद्ध हुए और उन्होंने यह अनुभव किया कि सिर्फ कांग्रेस-विरोध की राजनीति से कोई नतीजा नहीं निकलेगा और उ ह निर्वाचित क्षेत्रों में या जनता के बीच में काम करना चाहिए। अनेक दला ने विशेष क्षेत्रों में अपने पांव जमा लिए और उन्होंने धीरे धीरे अपना प्रभावक्षेत्र बढ़ा कर कांग्रेस से टक्कर लेने की नीति अपनाई।

(५) राज्यों में गैरकांग्रेसी सरकारों की स्थापना से यह आशंका हुई थी कि वेदों की कांग्रेस सरकार से इनका संघर्ष हागा और सघीय व्यवस्था टूट जायगी। यह आशंका गलत सिद्ध हुई। देखने में यह आया कि जिन राज्यों में अपेक्षाकृत टिकाऊ गैर कांग्रेसी सरकारें थी उनसे बरतने में केन्द्रीय सरकार को ज्यादा आसानी हुई, बजाय कांग्रेसी राज्य सरकारों से। हा, जहां वामपक्षी मोरच की सरकार थी

६ उदाहरण के लिए मद्रास में द्र० मु० व० के अतर्कित उठने पर वहां भी मांग हुई कि कुछ मंत्री नेतापद त्याग करके पार्टी का काम करें जैसा कांग्रेस में कामरान प्था में हुआ था।

७ १९६७ के चुनाव के पहले भी शम बान को लक्ष्य किया गया था - डब्लू. एच. मारिस को - द इंडियन वॉशिंग पार्टी - ए डिप्लेमा आफ टैमिनेस - मार्वन प्रशियन स्प्रीन १ स १ १९६७।

जैसे बेरल और बगाल में, वहाँ ज्यादा उग्र दला को बावू में रखने में कठिनाई हुई। किंतु मोरचे की इन सरकारों ने एक आर ऐसी रियायतें दी जिससे उग्र-पणियों को कुछ सन्तोष हो और प्रीवेगेडा या प्रचार का लाभ हो। दूसरी ओर इन्होंने केन्द्र से बातचीत में यथासंभव दृष्टिकोण अपनाया। समुक्त दल या मोरचे में सकट आने या उनके भंग होने की स्थिति में केन्द्र ने हस्तक्षेप किया और अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग किया। आर्थिक क्षेत्र में बैंक के राष्ट्रीयकरण और पूजा नियोजन व ऋण का नियमन करके केन्द्र सरकार ने बड़े कदम उठाए। आर्थिक शक्ति और साधन केन्द्र के हाथ में ह, और राज्या की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति, केन्द्र के द्वारा होगी इस बात का अनुभव किया गया। इसके साथ ही यह भी प्रत्यक्ष था कि ठीक काम न करने पर चुनाव में हार खानी पड़ेगी। इन सबमं केन्द्र की शक्ति की पुष्टि हुई और गैरकांग्रेसी दल की सरकारों ने भी केन्द्रीय सरकार के मन्त्र का स्वीकार किया।

(६) जहाँ इन प्रवृत्तियों से राजनैतिक व्यवस्था और लोकतंत्री पद्धति को बल मिला वहाँ कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ भी दोग पड़ी जो इसका कमजोर करती हैं। ऐसी एक प्रवृत्ति है सरकार की अस्थिरता। सीमावर्ष राजनैतिक दलों ने यह अनुभव कर लिया कि बार बार दल बदलने का जनता पसंद नहीं करती और इससे चुनाव में दल बदलने वाला को पुनरावृत्ति उठाना पड़ सकता है। राज्यपाल और केन्द्र सरकार दलबदल और सरकार टूटने की हालत में हस्तक्षेप कर सकते हैं, और राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, इससे भी सरकार उलटने वाला को निरुत्साह मिला। फिर भी समुक्त दल की सरकार की अस्थिरता की समस्या बनी हुई है। गैर कांग्रेसी दल अभी भी अपने पर नहीं जमा पाए हैं। प्रश्न यह है कि यदि मध्यावधि और आम चुनाव के बाद भी टिकाऊ सरकार न बन सके और मजबूत दल आगे न जा सके तो क्या होगा। ऐसा लगना है कि यदि हरियाना की तरह मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस वापस न आ सके या मद्रास उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बेरल की भाँति मजबूत गैरकांग्रेसी सरकारें न कायम हो सकी, तो राज्या में अस्थिरता, नए गठबंधन और बीच बीच में राष्ट्रपति शासन का दौर चलता रहेगा।\*

८ देखें अ. वा. २ में दलों की सारणी। ध्यान रहे कि भारत में गैरकांग्रेसी दलों का गठन (कीआल्लिशन) यूरोप की समुक्त दल सरकारों से भिन्न है। फ्रान्स आदि यूरोपीय देशों में मोरचे में शामिल विभिन्न दल अपने अपने क्षेत्रों में काफी मजबूत हैं, भारत के दल अभी भी पक्की तरह पर नहीं जमा पाए हैं, और चुनावों में उनकी शक्ति घटता बढ़ता रहती है। कम्युनिस्ट और कुछ हद तक जनसम के छोड़ कर कांग्रेस ही ऐसा दल है जो मतदाताओं के प्रति जिम्मेदारी अनुभव करता है या जिसे निर्वाचकों की नाराजी का भय है।

९ केरल में मध्यावधि चुनावों में स्थिति बदली है। यहाँ कांग्रेस और कम्युनिस्ट मोरचे ने [अगले पृष्ठ पर]



दूसरी बात यह है कि गैर कांग्रेसी सरकारों के टिक न सकने के कारण, सब दलों में निराशा उत्पन्न हो सकती है और वे अगवैधानिक तरीकों पर उतर सकते हैं। इंदिरा गांधी के बढ़ते हुए प्रभाव से यह निराशा और तीव्र हो सकती है। जब तक यह दल सत्ता में नहीं आ सकने में तब तक ये विधान सभा में कांग्रेस की टीका टिप्पणी और चुनौती में उस हराने की आशा से मनोप कर सकने में पर एक बार सत्ता में आकर पुनः उससे वंचित होनेसे इनमें गहरी निराशा और कुठाग्र उग्रवादिता उत्पन्न होती है। भारत में दल पद्धति की प्रवृत्ति मजबूत क्षेत्रीय दल का विकास में है जो केन्द्र में मत्तारूढ़ दल के विरोधी हैं। इससे जनता के राजनैतिक संगठन में सहायता मिली है। साथ ही इसमें खतरा यह है कि यदि इन क्षेत्रीय दलों की सरकार में म्यान न मिला तो ये उग्रता का रूख अस्तिपार कर सकने हैं।

तीसरे, राज्या में संयुक्त दल की सरकारों की अस्थिरता इसी तरह बनी रही और बार बार केन्द्रीय सरकार का हस्तक्षेप करना पड़ा तो सारा ध्यान सरकार की स्थिरता और राजनैतिक एकात्मता की हिफाजत पर ही केन्द्रित हो जाएगा और आर्थिक समस्याओं तथा सामाजिक प्रश्नों की उपेक्षा हो जाएगी यद्यपि अभी तक इसका कोई निश्चित सबूत नहीं है।<sup>१</sup> इस प्रश्न पर हम अगले अध्याय में विचार करेंगे।

इससे एक प्रश्न और उठता है। क्या विभिन्न दल राजनीति के बुनियादी नियमों का पालन कर रहे हैं? राजनैतिक दलों को जिस प्रकार आचरण करना चाहिए, क्या वे उस ढंग से आचरण कर रहे हैं? संविधान में दलों की प्रतिद्वंद्विता निहित है। शुरू में मजबूत प्रतिद्वंद्वी दलों का अभाव था। १९६७ के बाद कांग्रेस के विरोधी दलों ने जोर पकड़ा और दल या पार्टी पद्धति संविधान के नजदीक आती दिखाई पड़ी। किंतु अभी भी एक पार्टी की प्रधानता प्रबल नहीं हुई थी। इससे संविधान और राजनैतिक प्रक्रिया के द्वार में कुछ विवाद खड़े हुए। कांग्रेस के केन्द्रीय नेताओं में फूट के लक्षण दिखाई पड़ने से केन्द्रीय सरकार का स्थायित्व संदिग्ध हो गया और इससे तोड़फोड़, दलबदल आदि की अनुचित प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिला।

विवाद के मुख्य मुद्दे ये थे—विधान सभा में बहुमत और सरकार बनाने का दावा करने वाले दलों की शक्ति की परीक्षा किस प्रकार हो, काम कर जब दलबदल

[ पिछले पृष्ठ से ]

माकमनादी कम्युनिस्टों की अपेक्षा कर दिया है। १९७१ के चुनाव में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने पुनः काफी दूर तक शक्ति प्राप्त की है, और उसकी प्रतिद्वंद्वी स्वतंत्र और प. बंगाल में माकस कम्युनिस्ट संयुक्त सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है।

१० इंदिरा गांधी ने राजनैतिक दलगत आर्थिक प्रश्नों को आधार देने की काशिश की। यद्यपि उनकी यह चाल राजनैतिक थी और इसका उद्देश्य राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस के पुराने नेताओं को मात देना था।

की घटनाएँ हाँ रही हैं, राज्य का शासन संविधान के अनुसार चल सकता है या नहीं और राष्ट्रपति का शासन लागू हो या नहीं इन विषय में सत्ताह देने का राज्य पाल का अधिकार, विधानमंडल के अध्यक्ष के अधिकार, विधानसभा किस स्थिति में भंग हो और सत्रों से बड़ा प्रश्न संवैधानिक सत्र के समय राष्ट्रपति के अधिकार इन सब विषयों पर संविधान में कुछ न कुछ कहा गया, परंतु इन पर स्पष्टीकरण होना और एक परिपाटी का स्वरूप होना आवश्यक है। इन प्रश्नों पर अभी अनिश्चित की स्थिति है।

### राजनैतिक परिवर्तन की स्वीकृति

राजनैतिक विकास की एक कसौटी यह है कि सरकार का परिवर्तन कितनी आसानी से होता है। अनेक देशों में राजनैतिक परिवर्तन के समय बड़ी उथल-पुथल मची और इस प्रश्न पर अनेक राज्य-व्यवस्थाओं का भाग्य निर्भर है।<sup>११</sup> छोटे ही देश ऐसे हैं जहाँ सत्तापरिवर्तन की प्रकृति सुस्थिर हो गई है और लोगों में ग्राह्य हो चुकी है। भारत के लिए भी कहा गया कि इस प्रश्न पर संविधान का भविष्य निर्भर है। जब तक कांग्रेस की प्रधानता और जवाहरलाल नेहरू जैसे चमत्कारी व्यक्तित्व मौजूद हैं तब तक राजनीतिक स्थिरता को कोई खतरा नहीं। किंतु इसके बाद क्या होगा? नेहरू और उनकी पीढ़ी के प्रभावशाली नेता एक एक करके उठने लगे और कांग्रेस हाइवमान में फूट और बगड़े पैदा होने लगे। इससे १८५० के दशक के उत्तरार्ध से लेकर ६० के दशक तक, भारत में क्या होता है, इस पर ध्यान लगा रहा और अनिश्चित बना रहा।<sup>१२</sup>

१९६४-६७ के बीच तीन बार उत्तराधिकार का प्रश्न उठा। इन्हीं वर्षों में देश को विषम बाहरी और आंतरिक संकट भी झेलने पड़े। इस विषय में कुछ बातें ध्यान योग्य हैं जिनसे भारतीय व्यवस्था के परिवर्तन कर सकने की क्षमता और परिपाटी पर प्रकाश पड़ता है।

११ सोवियत संघ, युगोस्लाविया, फ्रांस, चीन, क्यूबा, पाकिस्तान और मिश्र इन सब देशों की अर्ध-रक्त कमीठी पर गिरा उतरना बाका है, यद्यपि और तरह से इनकी राजनैतिक व्यवस्था काफ़ी सफल सिद्ध हुई है। लोकतन्त्र देशों में मलेशिया, तानिआ, फ़िलिपाइन और कुछ हद तक श्रीलंका का भी अभी परीक्षा बाका है। इजरायल में बैन गुरियन के बाद लेवी इस्रकोव और उसके बाद गोल्डा मायर का चुनाव इसका चोकर है कि वह इस परीक्षा में खरा उतरा। मेक्सिको में भी उत्तराधिकार या सरकार बल्ले की अपनी एक प्रकृति बन गयी है।

१२ नेहरू के बाद क्या? इस प्रश्न पर विदेशी लेखकों ने काफ़ी अटकल-बातियाँ कीं। द्रॉपे-आफ्टर नेहरू हू' (न्यूयार्क १९८३) के बेलम हैंगेन। भारत में नेहरू की बामरा के बाद १९६३ में जनमत की पड़ताल की गई। 'आफ्टर नेहरू हू?' मधली प्रब्लिम ओपीनियन सर्वे न १०१, १९६३ (इंडियन इस्टीमेटिक ओपीनियन)।

नेहरू ने अपना उत्तराधिकारी चुनने से दबतापूर्वक इन्कार किया। उनका कहना था कि मुझे लोकतंत्री पद्धति पर पूरा विश्वास है और मैं नेता के चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। मुझे विश्वास है कि भारत की राजनैतिक व्यवस्था इतनी प्रौढ़ हो चुकी है कि वह मेरी सति को सहन कर लेगी और कांग्रेस पक्ष में इतनी समझदारी है कि वह इस ऊँचे पद के उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव कर लेगा। यही नहीं यदि मैं किसी व्यक्ति का अपना उत्तराधिकारी बनाऊँगा, तो लोग उससे जलज, उसका विराय करेंगे और वह कदापि प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा।<sup>१३</sup> इसीलिए नेहरू ने कोई उपप्रधान मंत्री भी नहीं नियुक्त किया और मंत्रियों की वरिष्ठता का श्रम भी निर्धारित नहीं होने दिया।<sup>१४</sup> इससे प्रतिकूल गांधीजी ने स्पष्ट रूप से नेहरू का अपना उत्तराधिकारी धारित किया था। इन दोनों नेताओं के व्यवहार के इस अन्तर से देश में राजनैतिक पद्धति का विकास का क्रम स्थानित होता है।

(२) लेकिन नेहरू को उत्तराधिकार के बारे में चिंता थी। उत्तराधिकारी नियुक्त न करने में उनकी यह भावना भी थी कि दल में जोर के द्रीय सरकार में गहरी फूट न पड़ जाए। वह देश और कांग्रेस दल के सघीय या सावधानिक रूप को समझते थे और यह भी समझते थे कि बिना सब लोगों की राय लिए ऊपर से कोई निश्चय लागू करना पतनोक्त है। उनका प्रभाव दल पर इतना अधिक छा गया था कि उसमें स्वतंत्र विचारविनिमय की प्रिया रुक सी गई थी और वह उनका ही उलगा बन गया था। इसीलिए उन्होंने कामराज योजना का सक्रिय समर्थन किया जिसका उद्देश्य यह था कि प्रमुख मंत्री अपना सरकारी पद छोड़ कर दल का कार्य में लग जाय पर जिसका असली उद्देश्य कांग्रेस के सघीय ढाँचे को फिर से गिराणी करना था। उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के महत्त्व और खास कर सक्त या आवश्यकता के समय उस के अधिकार की पुनर्स्थापना की। उन्होंने इस सिद्धांत को स्वीकार किया कि देश के प्रधानमंत्री के चुनाव में राज्या के मुख्यमंत्रियों में राम नेता जरूरी है। उन्होंने कामराज को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया और श्री लाल बहादुर शास्त्री को बीमार प्रधानमंत्री को सहायता देने के लिए अविभागीय मंत्री

१३ नेहरू के साथ अनाज्ज माथेरेस की दलाधिकार मुलाकात। माथेरेस आचार्य नेहरू नेहरू-शांतिद्विस्त और सम्मेलन इन शब्दों (न्यूमार्क १९६६)।

१४ सन १९४७ से १९५० तक सरदार वल्लभभाई पटेल उपप्रधान मंत्री थे और नेहरू के साथ सत्ता की साझादार थे। उनकी मृत्यु के बाद वह पद खाली रहा। १९६० में इस प्रश्न पर कांग्रेस समन्वय दल में चर्चा लिये गये किंतु इस पर सत्ता तीव्र मतभेद प्रकट हुआ कि नेहरू ने किसी को इस पद पर नहीं नियुक्त किया। नेहरू की बीमारी के समय, उपप्रधान मंत्री की नियुक्ति की मांग की गयी, किंतु नेहरू ने से स्वाकार नहीं किया। क्योंकि वह समझते थे कि इस समय ही उपप्रधान मंत्री होगा, वह स्वतः प्रधानमंत्री बन जाएगा। इस विषय में देखिए-पूर्वोक्त पृ. १४-१०३।

नियुक्त किया। इस प्रकार उन्होंने दल की आम राय से प्रधानमन्त्री के चुनाव का पथ प्रशस्त किया। उन्होंने अतः अपनी पसन्द नहीं जाहिर की और लालबहादुर शास्त्री को उपप्रधानमन्त्री का पद नहीं दिया।

नेहरू की मृत्यु के बाद नेता या प्रधानमन्त्री के चुनाव का कोई नियम नहीं हुआ था। किन्तु यह सिद्धांत मान लिया गया था कि ऐसा तरीका निकाला जाना चाहिए जो सवधान स्वीकार्य हो। दल के नेताओं ने यह तरीका तुरत ही निकाल लिया। यह समझा जाता हुआ कि दल के मुख्य लागा की जो आम राय हो, उसी को दल का नियम माना जाए। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस कार्यकारिणी, ससदीय दल के पदाधिकारी दल के अन्य नेता और ससदीय दल के २०० सदस्यों से मशविरा करके लालबहादुर शास्त्री के पक्ष में आम राय घोषित की।<sup>१५</sup> यह नियम वास्तव में दल के सबसे शक्तिशाली लोगों का नियम था और इसका कराने में कांग्रेस अध्यक्ष का मुख्य हाथ था। इस प्रकार उन्होंने इस प्रश्न पर पार्टी में फूट को टालने का यत्न किया। इसके बाद कांग्रेस ससदीय दल की बैठक में रस्मी तौर पर हाइकमान के फैसले पर मुहर लगा दी गयी। कांग्रेस अध्यक्ष की सदारत में ससदीय दल की बैठक हुई, इसमें शास्त्री सवमत से नेता चुने गए और राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने का निमन्त्रण दिया। आम राय की सारी कारवाइ बहुत कम समय में पूरी हो गयी यद्यपि उसमें इतने आदमिया से मशविरा किया गया।

२ जून १९६४ को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के केवल ५ दिन और १६ घंटे बाद ससद के वैधानिक पक्ष में कांग्रेस ससदीय दल की असाधारण बैठक में लालबहादुर शास्त्री सवसम्मति से दल के नेता चुने गए। सात घंटे बाद राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने उन्हें नयी सरकार बनाने का योता दिया। इसके साथ नेहरू के उत्तराधिकारी के चयन की कारवाइ पूरी हो गई। जिन लोगों ने इन ६ दिन की घटनाओं में भाग लिया और जिन्होंने इसका देखा, उन सब के लिए एक युग का यह बड़ा शांतिपूर्ण अन्त था। ससार में बहुत से लोग थे जिन्होंने नेहरू के बाद भारत में होनेवाली अव्यवस्था का बड़ा डरावना चित्र खींचा था। उनकी आशंकाएँ निराधार सिद्ध हुई। लेकिन जिन लोगों ने ऐसी आशंका नहीं की थी उन्हें भी सत्ता के इतनी सरलता और शांतिपूर्ण परिवर्तन से सुन्दर आश्चर्य हुआ।<sup>१६</sup>

१५ शास्त्रीजी के मुख्य प्रतिस्पर्धी मुरारजी देसाई थे, जिनका नेहरू से मनभेद सर्वविदित था। वह दक्षिणपथी समर्थक थे और अधिकतर मुख्यमन्त्री उनके विरुद्ध थे। कामराज और शास्त्री दोनों दक्षिण और वाम पक्ष के बीच के समर्थक होते थे और उनमें आशा की जाती थी कि वे नेहरू के कार्यक्रम को चालू रखेंगे। कामराज ने आग के दो चुनावों में भी प्रधानमन्त्री निर्वाचन का पार्टी भेदा किया और वह तटस्थ माने जाते थे। ग्रेटिफ, पूर्वोक्त अध्याय दो, तीन तथा आर जे वेंकटरवराज, 'कैबिनेट गवर्नमेंट इन इंडिया' (लंदन १९६७) अ १०।

१६ श्रीराम-पूर्वोक्त, पृ ६ में आम राय मान्य करने के कामराज के तरफे पर विचार किया गया है।

इस प्रकार उत्तराधिकार का पहला सकट समाप्त हुआ। इस समय कांग्रेस के नेताओं का सबसे अधिक ध्यान इस बात पर था कि कांग्रेस की ओर देश की एकता बनी रहे और नेता का चुनाव लोकतंत्री तरीके से हो, साथ ही नेतृत्व का दृढ़ या सघन अनुचित रूप न धारण करने पाए। इस प्रश्न का निपटारा कांग्रेस के मुखिया ने सगठन और दल के सदस्यों की आम भावना को रपाल में रखते हुए किया। नेतृत्व का निपटारा इस तरीके से हुआ, इसमें नेहरू को भी श्रेय था।

(३) १६ महीने प्रधानमंत्री रहने के बाद जब लालबहादुर शास्त्री का निधन हुआ, तब पहले जैसी सकट की स्थिति नहीं थी। देश की एकता भग होने का डर न था। यह सिद्ध हो चुका था कि देश में नेता के शून्य स्थान को भरने की क्षमता है। जिस प्रकार नेहरू का निधन एक युग के अंत का द्योतक था उस प्रकार शास्त्री का देहांत नहीं। बल्कि नए नेता के चुनाव का प्रश्न एकाएक पहले से आम राय या समझौते की कोशिश का बिना मौका दिए आ खड़ा हुआ था। शास्त्री की मृत्यु भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ताश्कंद सम्मेलन के बाद अचानक हो गयी। शास्त्री के बाद क्या होगा इस पर विचार की जरूरत ही नहीं हुई थी और शास्त्रीजी ने अपने उत्तराधिकारी के लिए रास्ता बनाने की कोई कारवाई ही नहीं की थी। उत्तराधिकारी कौन है यह स्पष्ट न था, क्योंकि शुरू में इंदिरा गांधी का नाम सामने आया ही नहीं था। चव्हाण, मोरारजी, नंदा, श्रीमती गांधी, जगजीवनराम, स्वयं कामराज अनेक नाम आए। कांग्रेस की हाइकमान में किसी भी नाम पर सहमति न थी सिवा इसके कि मोरारजी न हो। नई प्रश्न उठाए गए, जैसे अगले चुनाव में दल का सबसे अच्छी तरह कौन नेतृत्व कर सकता है। पर कुछ निश्चय न हो पाया।

इस बार पहले वाला तरीका काम में नहीं लाया गया। अब खुले सघन से उतना डर न था। अंत में मामले पर ससदीय पार्टी में गुप्त मतदान हुआ। इस मतदान पर मुख्य मंत्रियों ने बहुत प्रभाव डाला। उनकी साधारण राय इंदिरा गांधी के पक्ष में थी। फिर भी मुकाबला सख्त हुआ। इंदिरा गांधी के पक्ष में, ३५/ और मोरारजी के पक्ष में १६६ वोट आए। मुकाबला शिष्टता के साथ हुआ और अनेक सदस्यों ने अपने राज्य के मुख्य मंत्री की राय न मान कर मोरारजी को वोट दिया। इस प्रकार इस बार चुनाव की पद्धति ज्यादा सुव्यवस्थित और सुसंस्थित थी और यह बात स्पष्ट हो गयी कि व्यवस्था में नेता का शून्य स्थान भरने की क्षमता है। इसके साथ ही चुनाव में सब दलों या राज्यों की ओर कांग्रेस सगठन की इच्छा का ध्यान रखने का महत्त्व भी स्पष्ट हो गया। अंत में आम राय में ही फैसला हुआ पर यह आम राय खुले तरीके से स्थिर हुई, गुप्तचुप नहीं।

(४) जब तक नेहरूजी जीवित थे, हर चुनाव के बाद नेता का निर्वाचन एक रस्म अदायगी थी। परंतु सन १९६७ के आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा

गांधी का फिर से इस पद पर चुना जाना तब मान्य नहीं माना जा सकती थी। सन् १९६६ में जब यह नेता चुनी गयी थी, उस समय यह स्पष्ट था कि आम चुनाव के बाद इस प्रश्न पर फिर से विचार होगा। इस बार राजनैतिक स्थिति यह न थी, जो नेहरूजी और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद थी। इस बार कांग्रेस की शक्ति बहुत कम हो गयी थी। १२१ सदस्यों के मदन में उसका बहुमत केवल ४४ का था। कांग्रेस दल में कोई भी फूट पड़ने से सरकार उलट सकती थी। मात राज्या में कांग्रेस की पराजय हो चुकी थी। मद्रास में स्वयं वामराज हार गए थे, और कांग्रेस की गहरी हार हुई थी। इसका यह था कि सन् १९६६ की तरह इस बार कांग्रेस मुख्यमंत्रियों की मंडली नेता के चुनाव को प्रभावित न कर सकती थी। कांग्रेस के उत्तरग गुट के सास सास आदमी हार गए थे। कांग्रेस अध्यक्ष वामराज पहले की तरह आम राय या सहमति को लागू कराने की स्थिति में न थे।

१९६६ के नेता के चुनाव से पता चल गया था कि अल्पमत काफी गतिशील था। चूंकि चुनाव कांग्रेस समर्थी दल का करना था, इसलिए यह भी आशंका थी कि यदि फूट पड़ गयी तो कांग्रेस की सरकार ही उलट सकती थी। दलबदल की जितनी घटनाएं चुनाव के पहले और बाद में हो रही थी, उसका दखते हुए यह आशंका निराधार न थी।

नतीजा यह हुआ कि मुख्य प्रतिद्वंद्वियों में गहरी सीढ़ियां चली। वामराज और कुछ मध्यस्थ लोगों ने वांछित की कि वाट लेने की नीयत न आए। इस समय एक नया आरंभ हुआ सामने आया। यह नेहरू के अनुयायियों का था। यह नहीं चाहता था कि इंदिरा देवी का चुनाव से हटें। दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों को अंत में कुछ दबना पड़ा। तब हुआ कि इंदिराजी नेता रहें और दूसरा स्थान मोरारजी को मिले। उन्हें उपप्रधान मंत्री का पद दिया जाए, पर उनको यह विभाग नहीं मिला। यह विभाग च हाण के पास रहा। मोरारजी ने बड़ी उदारता और सदाशयता दिखाई तथा न तो मंत्रिमंडल के चुनाव में इंदिरा पर कोई बहिष्कार लगाने की कोशिश की, न उपप्रधानमंत्री के अधिकारों का स्पष्टीकरण मांगा।

नतीजा यह हुआ कि जो मंत्रिमंडल बना, उसमें सभी मंत्रियों का प्रतिनिधित्व था। दल की एकता बनी रही और उसने सामूहिक नेतृत्व स्वीकार किया। मोरारजी अनुशासन के पात्र थे और सरकार के अधिकार पर किसी विस्मय की बहिष्कार लगाने के विरोधी थे। उन्होंने प्रधान मंत्री को पूरा समर्थन दिया। दूसरे इंदिराजी को भी अपने गुट (किचन कैबिनेट) या दल के प्रमुख व्यक्तियों पर निर्भर रहने की उत्तरी जरूरत न थी। देश में राजनैतिक स्थिरता के वातावरण में केन्द्र में एक

मजदूर और मजदूर नेतृत्व की स्थापना कोई मामूली बात न थी। १७

१९६७ के प्रधानमंत्री या नेता के चुनाव की एक बात उल्लेखनीय है। प्रति द्वादी गुटा का सारा मोलभाव या सौदेबाजी मुले खजाने हुई। दोनों प्रतिद्वंद्वी कई बार मिले और दोनों ने अपनी बातें स्पष्ट रूप से एक दूसरे के सामने रख दी। दूसरे लोग भी बीच बिचाव कर रहे थे, किन्तु इन्होंने मध्यस्थता को यह मौका न दिया कि वे जबरदस्ती अपनी शर्तें मनवाए या जिच पैदा कर दें। इस प्रकार की मुली बातचीत और विचार विनिमय पहले की अपरत्यक्ष या गुप्त सौदेबाजी से भिन्न था और इससे धात्रे की आपसी गुटबंदी या मतभेद को निपटाने और समझौता करने की शक्ति बढ़ी। १८

राजनैतिक पद्धति के विकास में भी यह एक महत्वपूर्ण अध्याय था। पहले की तरह एक चमत्कारी व्यक्तित्व के नेतृत्व का स्थापना अब एक सामूहिक नेतृत्व ने लिया। १९

साथ ही राजनैतिक पद्धति के विकास की क्रियाओं भी जारी थी, और स्थिति अस्थिर तथा परिवर्तनशील बनी रही। चौथे चुनाव के पहले और बाद भी कांग्रेस के नेता अपनी जोड़ताड़ बिठाने में लगे रहें। १९६७ के चुनाव के लिए उम्मीदवारों को छांटने में नेताओं का ध्यान नेता व प्रधानमंत्री पद के चुनाव की तयारी

१७ इस सम्प्रति के सरकार का मजदूरी १९६७ के राष्ट्रपति के चुनाव में प्रगट हुई। निवाचक मंडल में गर कांग्रेस दलों का बहुमत था। ( इसमें राज्यों के विधान मण्डलों और संघ के निवाचित संसद होते थे ) इन लोगों ने सवाच्च न्यायालय के जन श्री सुबाराव को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि कांग्रेस ने रा. पाकिर हुसी को। कांग्रेस और खासकर इंदिरा गांधी ने एक मुसलमान को खूब करके बना जोरिम उठाया था। उसने भूमिनिरीक्षण के सिद्धांत को कमीटी बनाकर कांग्रेस के सभी गुटों को एकजुट किया और चुनाव जीत लिया। इसमें कांग्रेस की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गया। दूसरी ओर गर कांग्रेस दल की पूर जादिर हो गई।

१८ भारत के अउरारों में समझौते की प्रत्येक गतिविधि की पूरी खबर छपती रही। कौन किससे किसके घर पर मिला, उस समय कौन से लोग उपस्थित थे। साधारणतः धारणा यह थी कि भारतीय लोग साफ और साधे बात करने में कतराते हैं। इस बातचीत में यह बात नहीं दाख पड़ी। पूरे विवरण के लिए देखें - मारनेल डीकर - 'सुसंज्ञन इन इंडिया १९६७ - द रोलिनाइशन ऑफ पोलि चेंज' ( पब्लिशिंग सर्वे, सात, स ७ जुलाई १९६७ )।

१९ दूसरी ओर सामूहिक नेतृत्व में परस्पर अविश्वास भा रहना है और सरकार तथा दल के कार्य में बाधा पड़ती है। इसी कारण १९६७ के दो वर्ष बाद इंदिरा गांधी ने अपने हटाए जाने के आशयित प्रयत्न को विफल करने के उद्देश्य से कुछ राजनैतिक और आर्थिक कदम उठाए। उन्होंने मोरारजी देसाई को अपदस्थ कर दिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और दल तथा सरकार से विरोधी गुट का सफाया करने का प्रयत्न किया। १९७१ के मध्याचम चुनाव से 'धरमार्ती व्यक्तित्व' का नेतृत्व फिर से स्थापित होता लपित होता है।

में ही लगा था २० और इस प्रक्रिया में काफी गहरे मतभेद प्रकट हुए। १९६६ में सामूहिक नेतृत्व में दल पड़ने लगी आर सत्ता का सघन शुरू हुआ। इस समय अविश्वास और सदेह का वातावरण था, इसलिए दोनों पक्षों में वह खुला विनिमय न रहा जो १९६७ में देखने में आया और केन्द्रीय नेतृत्व में फूट पड़ गई।

### १९६६ का राष्ट्रपति का चुनाव

भारतीय दल पद्धति में सरकार और सगठन का द्वंद्व निहित है। परन्तु यह द्वंद्व नीचे के स्तर पर देखने में आता था। कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व (हाइकमान) दल की एकता को बनाए रखता था और नीचे के झगड़ों को निपटाता रहता था। लेकिन प्रधानमंत्री के उत्तराधिकार के दो सघर्षों से आरंभ होकर सरकार और सगठन का द्वंद्व ऊपर तक पहुंच गया और १९६६ के बंगलोर कांग्रेस अधिवेशन में इसकी पराकाष्ठा हो गई जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष निजलि गप्पा तथा सगठन के मुखियों में खुली टक्कर हुई। इस सघर्ष में व्यक्तिगत, क्षेत्रीय और कार्यक्रमगत स्पष्ट मतभेद देखने में आया। परिणामस्वरूप नेतृत्व के लिए जो सघर्ष हुआ, उससे तीन बात सामने आयी। एक तो कांग्रेस सगठन में प्रधानमंत्री और उसकी सरकार के स्थान और शक्ति का प्रश्न, जिसे कामराज याजना द्वारा टालने का प्रयत्न किया गया था। दूसरे, प्रतिद्वंद्वी गुटों ने बाहर से शक्तिसंचय का प्रयत्न किया। श्रीमती गांधी ने वामपक्ष, द्रमुक और अन्य क्षेत्रीय दलों का समर्थन लिया और सगठन के नेताओं ने स्वतंत्र और जनसघर्ष का। तीसरे, इस द्वंद्व ने क्षेत्रीय रूप ग्रहण किया। उत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, केरल और मद्रास इंदिरा गांधी के साथ रहा और पश्चिम भारत राजस्थान और मैसूर सगठन नेताओं के साथ। इस मोर्चेबंदी ने कांग्रेस को एकजोर दिया। दक्षिण और वाम पक्ष के बीच कांग्रेस की मध्य स्थिति को खतम कर दिया और देश में नई राजनैतिक गुटबंदी और मोरचेबंदी को जन्म दिया।

कांग्रेस की अदरुनी खींचतान राष्ट्रपति पद के उम्मेदवारों के चुनाव पर सीमा पार कर गई। श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस ससदीय बोर्ड में अल्पमत में आ गई। श्रीमती इंदिरा गांधी ने समझा कि यह उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने की चाल है। जवाब में उन्होंने मोरारजी भाई का हटा दिया, जिन्हें उन्होंने खुद कांग्रेस की फूट बचाने के लिए उपप्रधान मंत्री बनाया था। इसके बाद उन्होंने अध्यादेश के जरिए बैंका का राष्ट्रीयकरण कर दिया और आर्थिक नीति को वामपक्षीय तथा क्रान्तिकारी रूप दिया। फिर उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस सदस्या को अपने अंत-

२० १९६७ के चुनाव के उम्मीदवारों की छटाई के बारे में देखो - रत्न की कोठारी - 'कांग्रेस मिथम आनंदराय' (एशियन सर्वे साप्ताहिक २ फरवरी १९६७) तथा स्टेनली ए. कोबेनर - 'द कांग्रेस पार्टी आफ इंडिया - द डायनेमिक ऑफ वन पार्टी डेमोक्रेसी' (प्रिन्टन १९६८)।



परण के अनुसार वोट देने की आजादी की मांग थी, अर्थात् प्रतिपक्षी उम्मीदवार श्री गिरि का वोट देने की आजादी। कांग्रेस अध्यक्ष ने इसका विरोध किया और दोनों ओर से प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों के लिए जोर लगाया। यह चुनाव अभूतपूर्व था। इसमें दल का विभाजन रेखा टट गई और अधिवृत्त कांग्रेस उम्मीदवार श्री सतीश रेड्डी की हार हुई। पहली बार राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई। यह कांग्रेस गठन और प्रधानमंत्री के गुटा की टक्कर थी। इसमें प्रधानमंत्री की विजय हुई और वह गठन के मुकामले तत्काल या सरकारी गुट की प्रधानता स्थापित करने में सफल हुई। साथ ही कांग्रेस में वामपंथी प्रवृत्ति की प्रधानता स्थापित हुई।

साथ ही १९६६ के राष्ट्रपति के चुनाव ने भारतीय दल पद्धति के नुस्खे रूप को भी प्रकट किया। एक ओर कांग्रेस के छोटी के नेताओं में परस्पर वमनस्य इतना बढ़ गया था कि उनमें बातचीत बंद हो गई, दूसरी ओर राष्ट्रपति के चुनाव के आंदोलन में सभी प्रमुख दल और कांग्रेस के गुट बूढ़ पड़े। जिस प्रकार कांग्रेस के अंदरूनी गुट दल के अंदर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बाहरी दल का सहारा लेते उसी तरह एन आर कम्युनिस्ट और दूसरी ओर स्वतंत्र और जनसंघ दल ने भी कांग्रेस की गुटबंदी का सहारा लेकर नई राजनैतिक मोर्चेबंदी कायम करने की कोशिश की। दोनों ओर में पूरा जोर लगाया गया और खुल कर संघर्ष हुआ। यह मोर्चेबंदी राजनैतिक और वैचारिक मतभेद के साथ साथ क्षेत्रीय और सांप्रदायिक भेद के आधार पर हुई। यद्यपि इस फूट का कारण केन्द्रीय कांग्रेस के डटने की आसका उपस्थिति हुई, किंतु राजनैतिक व्यवस्था के टूटने की आसका नहीं उठी। चुनाव के बाद कांग्रेस में फूट को दबाने की कोशिश हुई और कांग्रेस कायम समिति में एकता का प्रस्ताव पास हुआ।

साथ ही दूसरे दल में भी बहुत फट दिवाई पड़ी। मध्यावधि चुनाव और संयुक्त मोर्चा सरकार की स्थापना और पतन के समय यह फूट उभर कर सामने आयी। भरवाग्रेसी दल के गठजोड़ का चयन या टिकना बड़ा बठिन सिद्ध हुआ। व्यक्तिगत सद्भावना और वगृहीता पर विरोध सामने आए। इन दोनों में भी उत्तराधिकार के संकट उपस्थित हुए। संयुक्त समाजवादी पार्टी में रंगबाग्रेसी दल में सबसे गतिशील थी। डा० लोहिया की मृत्यु से इसका गहरा धक्का लगा और इस में फूट पड़ गयी। सन ६० के बाद सद्भावना मतभेद के कारण कम्युनिस्ट पार्टी की एकता और संगठन छिन्न भिन्न हो गया। जयप्रकाश नारायण के सर्वोदय में चले जाने और असार मेहुता के 'पिछड़ी अल्पव्ययता की मजदूरिया' अनुभव करने (और कांग्रेस में जाने) के बाद प्र सो पा भी नेतृत्वविहीन हो गयी। स्वतंत्र पार्टी तो ऐसा जान पड़ता है, अखिल भारतीय नवत्व में विश्वास ही नहीं करती। कांग्रेसवादी गुटा में भी नेता अधिक और अनुयायी कम दीचते हैं। केवल जनसंघ

में कुछ एकता और अनुशासन दीख पड़ता है यद्यपि उसमें भी कांग्रेस व ही समान नरम और गरम गुट मौजूद हैं। परंतु जनसघ मुख्यत उत्तरभारत का संगठन है, जैसे द्र मु व केवल दक्षिण का। इससे पता चलता है कि नेहरूवाद और कांग्रेस हास के युग में दला की स्थिति कितनी कच्ची और अस्थिर है। इस अस्थिरता के युग में भी राजनैतिक व्यवस्था को बनाए रखने में कांग्रेस सहायक हुई। नेहरू और अय महान नेताओं के उठ जाने के बाद भी उमने टिके रहने और पुन शक्ति प्राप्त करने की क्षमता प्रदर्शित की है।

### नौकरशाही की भूमिका

भारतीय राज्यव्यवस्था को बनाए रखने में नौकरशाही या प्रशासन तंत्र का भी बड़ा हाथ है। राजनैतिक परिवर्तन के समय तो न केवल नौकरशाही सरकार या शासन की निरंतरता को बनाए रखती है, वरन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम कर दिखाने की जिम्मेदार होती है जिम पर सरकार की सफलता या विफलता निर्भर होती है। राजनैतिक नेता अर्थात् मंत्रियों का सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ के निकट सहयोग से काम करना होता है और ऊंचे स्तर पर नीतिनिर्णय में अधिकारिया या सचिवों का हाथ बढ़ता जा रहा है। लालबहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के अत्यंत महत्वपूर्ण राजनैतिक निर्णयों में भी उच्च अधिकारियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। पाकिस्तान से युद्ध और ताश्कंद समझौते के समय यह बात स्पष्ट हो गई, <sup>२१</sup> और अब भी यही स्थिति है। लक्ष्मीकांत या, लल्लनप्रसाद मिह और पी एन हक्सर जैसे उच्च अधिकारियों का महत्वपूर्ण सरकारी निर्णयों में बहुत अधिक हाथ रहा है। मंत्रिमंडल सचिवालय और प्रधानमंत्री के सचिवालय का बढ़ता हुआ महत्व किसी से छिपा नहीं। ये प्रधानमंत्री के आख और कान हैं। इनके द्वारा उनकी पूरी राजनैतिक जानकारी मिलती है। उच्च स्तर की समितियों में इन अधिकारियों की उपस्थिति सरकारी निर्णयों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका की परिचायक है। इस स्थिति का मुकाबला उस जमाने से करिए जब मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की भी नेहरूजी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी।

अब तक हमने केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय राजनैतिक नेतृत्व, राजनैतिक गठजोड़ या योग, राजनैतिक उत्तराधिकार, वैचारिक या सैद्धांतिक सहमति की समस्याओं पर विचार किया है। यह सर्वविदित है कि जैसे जैसे राजनैतिक व्यवस्था जड़ पकड़ती है और इसकी पद्धतिया या संस्थाओं का विकास होता है, नयी समस्याएँ पैदा होती हैं। विकास के द्वारा देश की एकता को किस प्रकार बढ़ाया जाए, राजनैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करके और सत्त्वों प्रशासन का लाभ पहुंचा कर किस प्रकार राज्यतंत्र या व्यवस्था को मजबूत बनाया जाय, स्थानीय या

<sup>२१</sup> याचर-नेहरू मंडल-पुस्तक पृ ११५-२०, १६७-६८।

वरण के अनुसार वोट देने की आजादी की मांग की, अर्थात् प्रतिपक्षी उम्मीदवार श्री गिरि का वोट देने की आजादी। कांग्रेस अध्यक्ष ने इसका विरोध किया और दोनों ओर से प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों के लिए ओर लगाया। यह चुनाव अभूतपूर्व था। इसमें दल की विभाजन रेखा टूट गई और अविष्टन कांग्रेस उम्मीदवार श्री सतीश रेड्डी की हार हुई। पहली बार राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई। यह कांग्रेस मगठन और प्रधानमंत्री के गुटा की टक्कर थी। इसमें प्रधानमंत्री की विजय हुई और वह मगठन के मुकाबले मत्ताबद्ध या सरकारी गुट की प्रधानता स्थापित करने में सफल हुई। साथ ही कांग्रेस में वामपक्षी प्रवृत्ति की प्रधानता स्थापित हुई।

साथ ही १९६९ के राष्ट्रपति के चुनाव ने भारतीय दल पद्धति के खुले रूप को भी प्रकट किया। एक ओर कांग्रेस के चोटी के नेताओं में परस्पर वैमनस्य इतना बढ़ गया था कि उनमें घातचीन बद हो गई, दूसरी ओर राष्ट्रपति के चुनाव के आंदोलन में सभी प्रमुख दल और कांग्रेस के गुट बूंद पड़े। जिन प्रकार कांग्रेस के अदरुनी गुट दल के अंदर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बाहरी दल का सहारा लेने के उसी तरह एक ओर कम्युनिस्ट और दूसरी ओर स्वतंत्र और जनसंघ दल ने भी कांग्रेस की गुटबंदी का सहारा लेकर नई राजनैतिक मोर्चेबंदी कायम करने की कोशिश की। दोनों ओर से पूरा जोर लगाया गया और खुल कर संघर्ष हुआ। यह मोर्चेबंदी राजनैतिक और वैचारिक मतभेद के साथ साथ क्षेत्रीय और सांप्रदायिक भेद के आधार पर हुई। यद्यपि इस फूट के कारण केन्द्रीय कांग्रेस के उठने की आसका उत्पन्न हुई, किंतु राजनैतिक व्यवस्था के टूटने की आसका नहीं उठी। चुनाव के बाद कांग्रेस में फूट को घटाने की कोशिश हुई और कांग्रेस काय समिति में एकता का प्रस्ताव पास हुआ।

साथ ही दूसरे दल में भी बहुत फूट निर्वाह पड़ी। मध्यावधि चुनावों और संयुक्त मोरचा संघारों का स्थापना और पतन के समय यह फूट उभर कर सामने आयी। गैरकांग्रेसी दलों के गठजोड़ का चाना या टिकना बड़ा बठिन सिद्ध हुआ। व्यक्तिगत नैदातिक और वगहिका पर विरोध सामने आण। इन दोनों में भी उत्तराधिकार के संकट उपस्थित हुए। संयुक्त समाजवादी पार्टी गरकांग्रेसी दलों में सबसे गनिशील थी। डा० लोहिया की मृत्यु से इसको गहरा धक्का लगा और इस में फूट पड़ गयी। सा० ६० के बाद संदातिक मतभेद के कारण कम्युनिस्ट पार्टी की एकता और मगठन छिन्न भिन्न हो गया। जयप्रकाश नारायण के सर्वोदय में चले जाने और अशाक मेहता के 'पिछड़ो अययवस्था की मजबूरिया' अनुभव करने (और कांग्रेस में जाने) के बाद प्र मो या भी नेतृत्वविहीन हो गयी। स्वतंत्र पार्टी तो ऐसा जान पड़ता है, अखिल भारतीय नेतृत्व में विश्वास ही नहीं करती। कांग्रेसत्यागी गुटा में भी नेता अधिक् और अनुयायी कम दोखते हैं। केवल जनसंघ

में कुछ एकता और अनुशासन दीख पड़ता है यद्यपि उसमें भी कांग्रेस के ही समान नरम और गरम गुठ मौजूद हैं। परन्तु जनसंघ मुख्यतः उत्तरभारत का संगठन है, जैसे द्र मु क केवल दक्षिण का। इससे पता चलता है कि नेहरूवाद और कांग्रेस हास के युग में दलों की स्थिति कितनी बची और अस्थिर है। इस अस्थिरता के युग में भी राजनैतिक व्यवस्था को बनाए रखने में कांग्रेस सहायक हुई। नेहरू और अन्य महान नेताओं के उठ जाने के बाद भी उमने टिके रहने और पुनः शक्ति प्राप्त करने की क्षमता प्रदर्शित की है।

### नीकरशाही की भूमिका

भारतीय राज्यव्यवस्था को बनाए रखने में नीकरशाही या प्रशासन तंत्र का भी बड़ा हाथ है। राजनैतिक परिवर्तन के समय तो न केवल नीकरशाही सरकार या शासन की निरंतरता को बनाए रखती है, वरन् महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम कर दिखाने की जिम्मेदार होनी है, जिम पर सरकार की सफलता या विफलता निर्भर होती है। राजनैतिक नेता अर्थात् मंत्रियों का सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ के निकट सहयोग से काम करना होता है और ऊँचे स्तर पर नीतिनिर्णय में अधिकारियाँ या सचिवों का हाथ बढ़ता जा रहा है। लालबहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के अत्यंत महत्वपूर्ण राजनैतिक निर्णयों में भी उच्च अधिकारियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। पाकिस्तान से युद्ध और ताश्कंद समझौते के समय यह बात स्पष्ट हो गई, <sup>२१</sup> और अब भी यही स्थिति है। लक्ष्मीकांत वा, लत्तनप्रसाद सिंह और पी एन हक्सर जैसे उच्च अधिकारियों का महत्वपूर्ण सरकारी निर्णयों में बहुत अधिक हाथ रहा है। मंत्रिमंडल सचिवालय और प्रधानमंत्री के सचिवालय का बढ़ता हुआ महत्व किसी से छिपा नहीं। ये प्रधानमंत्री के आस और बाँव हैं। इनके द्वारा उनकी पूरी राजनैतिक जानकारी मिलती है। उच्च स्तर की समितियों में इन अधिकारियों की उपस्थिति सरकारी निर्णयों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका की परिचायक है। इस स्थिति का मुकाबला उस जमाने से करिए जब मंत्रिपरिषद् के मंत्रियों की भी नेहरूजी के सामने बाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी।

अब तक हमने केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय राजनैतिक नेतृत्व, राजनैतिक गठजोड़ या योग, राजनैतिक उत्तराधिकार, वैचारिक या सैद्धांतिक सहमति की समस्याओं पर विचार किया है। यह सबविदित है कि जैसे जैसे राजनैतिक व्यवस्था जड़ पकड़ती है और इसकी पद्धतियाँ या संस्थाएँ का विकास होता है, नयी समस्याएँ पैदा होती हैं। विकास के द्वारा देश की एकता को जिस प्रकार बढ़ाया जाए, राजनैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करके और सत्तों को शासन का लाभ पहुँचा कर जिस प्रकार राज्यतन्त्र या व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए, स्थानीय या

<sup>२१</sup> आचर-नेहरूज मैटल'-पुस्तक पृ ११५-२०, १६७-६८।



और इंडोनीशिया में सुकानों, अधिकारमंद ने उदाहरण है। इसी तरह पश्चिम एशिया में नासिर का प्रभाव इस बात का द्योतक है कि ऐतिहासिक घटनाओं का राष्ट्रीय भावना पर जो प्रभाव पड़ता है वह स्थायी नहीं होता। दूसरी ओर कागो और नाइजीरिया में जो गहयुद्ध हुए उससे संभवतः उन देशों को समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रीय एकता का बनाए रखने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है और कितनी सावधानी रखनी पड़नी है। जो हा, भारत में विभाजन के फलस्वरूप राष्ट्रीय एकता का महत्त्व और उसका बनाए रखने के लिए सभी वर्गों का ख्याल रखने की आवश्यकता राजनीतिज्ञों का समय में आ गयी।

स्वतंत्र भाग में जाति और भेदों के बहिष्कार और राजनैतिक संगठन या गठजोड़ के अंग हैं। इनके मुकाबले भाषा या प्रांत के विभाजन से राष्ट्रीय एकता को ज्यादा खतरा है।

राष्ट्रीय एकता और भाषागत विभिन्नता

भारत में भाषा की समस्या निराली है। ब्रनाडा, बेलजियम, स्विटजरलैंड या मावियत रूम का उदाहरण यहाँ लागू नहीं होता। १९ वीं सदी के यूरोप में भाषा का आधार पर जिस प्रकार जर्मनी, इटली आदि राष्ट्रीय राज्या का उदय हुआ, वह बात भी भारत पर लागू नहीं हो सकती।<sup>२२</sup> यह समझना चाहिए कि भारत में सदा से अनेक भाषाएँ रही हैं किन्तु इन भाषाओं को जोड़ने वाली सम्स्कृत जैसी सावदेशिक भाषाएँ रही हैं। स्थानीय वाजिया, प्रादेशिक भाषाओं और सावदेशिक भाषाओं में निरन्तर आदान-प्रदान और घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। इतिहास के विभिन्न युगों में भाषा का विकास अनेक तत्त्वों से प्रभावित हुआ है। श्रेष्ठ या शासक जाति की मस्त्रुति का अनुकरण, राजनैतिक सुविधा और जातीयता सभी बातों ने विभिन्न युगों में विभिन्न सावदेशिक भाषाओं के उदय और प्रातीय भाषाओं के विकास में योग दिया है। इस समय भी भाषासबधी नीति में जो अनिश्चितता देखने में आ रही है उसका कारण यह है कि सबकी सहमति से भाषा समस्या का समाधान करना आसान नहीं है।<sup>२३</sup>

राष्ट्रीय एकता के लिए एक राष्ट्रभाषा या सावदक्षिक भाषा आवश्यक है यह सिद्धान्त भारत पर लागू नहीं होता। यह बात अब कांग्रेस, स. सो. पा. जी. र. जन-संघ तथा दूसरी ओर द्र. मु. क. के कट्टरवादी भी अनुभव कर रहे हैं। भाषा की समस्या भारतीय एकता के लिए निस्संदेह एक कसौटी या चुनौती है, किंतु इधर

२२ देखिए-एली वेदूरी- नेशनलिज्म (लंदन १९६०)।

२३ गजेन्द्रगडकर 'ए प्ली टुकमिडर प्राच्यम रेशनली, टिसादड वारजली पेंड हेसेन स्लोली (कवोकेशन भाषण, बर्दादा, अक्टू १४ १९६७ मीडियम आफ एजुवेशन, बर्दादा युनि, प्रकाशित।)

व्यगत्त मागो का किस प्रकार संतुष्ट किया जाए और उनको भी राजनैतिक व्यवस्था और राष्ट्रीय जीवन में शामिल किया जाए, ये व्यावहारिक समस्याएँ हैं, जिनके समाधान से राजनैतिक व्यवस्था की परीक्षा होती है। ये राजनैतिक तंत्र के नेताओं की योग्यता की कमीटिया है। जैसे जैसे राज्यतन्त्र अनेकता में एकता की एक एक मजिल पार करता है उसे अपने राजनैतिक माघन और शक्ति नाजुक समस्याओं को सुलझाने में लगानी पड़ती है।

### अनेकता में एकता की स्थापना

भारतीय सम्यता को प्रभावित करने वाले तत्त्व हैं देश की विशालता, प्राचीनता और यहाँ अनेक जाति या नृवश की विद्यमानता। भजहब या संप्रदाय, जाति भाषा और प्रात यहाँ राजनीति के आधार रह है। बालिग मताधिकार के प्रभाव से जाति ने क्या राजनैतिक रूप ग्रहण किया है, इसका विश्लेषण हम पूरे एक अध्याय में कर चुके हैं। अध्याय दो में हमने यह देखा कि किस प्रकार नए भारत का जन्म सांप्रदायिक विभाजन से हुआ और उस समय कितनी खून खराबी मची। हमने सांप्रदायिक समस्या पर भी काफी विस्तार से विचार किया है। यहाँ हम यह देखेंगे कि राष्ट्र के निर्माण के लिए इसका क्या महत्त्व है।

जहाँ देश के बंटवारे से इतनी हानि हुई वहाँ इससे कुछ सपन भी मिला। पहला सबक यह है कि देश ने एकता के महत्त्व का समझा और यह अनुभव किया कि चाहे जैसे भी हो, राष्ट्रीय या केन्द्रीय सत्ता का बनाए रखना है और देश के विविध तत्त्वों को एक सूत्र में बाँधे रखना है। संविधान सभा के विचारविमर्श में इन सिद्धान्त का प्रभाव स्पष्ट है और इसीलिए हमारे संविधान में केन्द्रीय सत्ता की प्रधानता और राज्य की एकात्मकता को कायम रखने के साथ साथ दश के विभिन्न भागों को पूरी छूट और अधिकार देने का यत्न किया गया है। फलतः हमारी राजनीति में एकता को महत्त्व गुरु से दिया जा रहा है। बंटवारे का दूसरा प्रभाव और भी व्यापक रहा। दश का बंटवारा और उसके फलस्वरूप हाने वाली हिंसा या सामान्य और राष्ट्र की राजनैतिक इमारत सड़ी करने की जिम्मेदारी ने हमारा राजनीतिज्ञों में राजनैतिक समझदारी या नीतिगता का संचार किया और उन्हें यह अनुभव कराया कि देश की राजनैतिक स्वतंत्रता और गरिमा कायम रखने के लिए क्या करना पड़ता है।

राष्ट्रनिर्माण के लिए एकता की समस्या बड़ी महत्त्वपूर्ण है। एगिता और अमीना के अनेक नव स्वतंत्र देशों को अपने विभिन्न भागों से बना बनाया एकीकृत राज्य मिल गया। उन्हें राष्ट्रनिर्माण के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ा, इसलिए उन्होंने एकता ऊपरी सिद्ध हुई। इन नेताओं को जो अधिकार मिल गया, उससे उनका दिमाग हो गया। उन्होंने देश के विभिन्न तत्त्वों को गाय ने घालने या उनको राजमंदी व समायन प्राप्त करने की चिंता नहीं की। घात में एनर्मा

और इंडोनीशिया में मुकानों, अधिकारमंद के उदाहरण है। इसी तरह पश्चिम एशिया में तासिर का प्रभाव इस बात का द्योतक है कि ऐतिहासिक घटनाओं का राष्ट्रीय भावना पर जो प्रभाव पड़ता है वह स्थायी नहीं होता। दूसरी ओर कांगो और नाइजीरिया में जो गहरे हुए उसका सम्भवतः उन दशा का समय में आ जाएगा कि राष्ट्रीय एकता का बनाए रखने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है और कितनी सावधानी रखनी पड़ती है। जो हा, भारत में विभाजन के फलस्वरूप राष्ट्रीय एकता का महत्त्व और उसका बनाए रखने के लिए सभी वर्गों का ख्याल रखने की आवश्यकता राजनीतियों का समझ में आ गयी।

स्वतंत्र भारत में जाति और मजदूर वर्गों के राजनैतिक संगठन या गठजोड़ों के जग हैं। इनके मुकाबले भाषा या प्रांत के विभाजन से राष्ट्रीय एकता को ज्यादा खतरा है।

### राष्ट्रीय एकता और भाषागत विभिन्नता

भारत में भाषा की समस्या निराली है। बड़ा बेलजियम, स्विटजरलैंड या नार्वे का उदाहरण यहाँ लागू नहीं होता। १९ वीं सदी के यूरोप में भाषा के आधार पर जिस प्रकार जर्मनी, इटली आदि राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ, वह बात भी भारत पर लागू नहीं हो सकती।<sup>२२</sup> यह समझना चाहिए कि भारत में सदा से अनेक भाषाएँ रही हैं किन्तु इन भाषाओं को जाड़ने वाली संस्कृति जैसी सावदेशिक भाषाएँ रही हैं। स्थानीय बोलियाँ, प्रादेशिक भाषाओं और सावदेशिक भाषाओं में निरन्तर आदान-प्रदान और घनिष्ठ सम्पर्क रहा है। इतिहास के विभिन्न युगों में भाषा का विकास अनेक तत्त्वों से प्रभावित हुआ है। श्रेष्ठ या शासक जाति की संस्कृति का अनुकरण, राजनैतिक सुविधा और जातीयता सभी बातों ने विभिन्न युगों में विभिन्न सावदेशिक भाषाओं के उदय और प्राचीन भाषाओं के विकास में योग दिया है। इस समय भी भाषासंबंधी नीति में जो अनिश्चितता देखने में आ रही है उसका कारण यह है कि सबकी सहमति से भाषा समस्या का समाधान करना आसान नहीं है।<sup>२३</sup>

राष्ट्रीय एकता के लिए एक राष्ट्रभाषा या सावदेशिक भाषा आवश्यक है, यह सिद्धांत भारत पर लागू नहीं होता। यह बात अब कांग्रेस, स. सो. पा. और जन-संघ तथा दूसरी ओर द्र. मु. क. के कट्टरवादी भी अनुभव कर रहे हैं। भाषा की समस्या भारतीय एकता के लिए निम्नलिखित एक कसौटी या चुनौती है, किन्तु इस

२२ देखिए—एली वेदूरी—नेशनलिज्म (लंदन १९६०)।

२३ गजेन्द्रगडकर 'एली ड्रु कनिंघम प्राइमरी रिसर्च, टिप्पणियाँ वाइली प्रेंस हेसेन स्लोडी (कॉन्फेक्शन भाषण, बंगाल, अक्टूबर १४, १९६७ मीडियम आफ एजुकेशन, बंगलूरु, प्रकाशित)।



एसी प्रवृत्ति लक्षित होती है कि एक भाषा के बजाय कई भाषाओं को स्वीकार कर लिया जाएगा।

१९२७ में भारत की भाषाओं की पड़ताल (निम्बिस्टिक सर्वे) का विवरण प्रकाशित हुआ था। इसमें १७६ भाषाओं और १४४ उपभाषाएँ या बोलियाँ (कुल १६५२ मातृभाषाएँ) गिनाई गई थी। भारत की जायिरी जनगणना में १०१८ भाषाओं का उल्लेख है। (सारणी आठ - १) में सब भाषाएँ चार मुख्य वर्गों में आती हैं (भारतीय-आर्य, द्रविड, तिब्बती-चीनी और आस्ट्रो-एंग्गोई)। इनमें भी ७३३ प्र. १ आर्य और २४४ प्र. १ द्रविड वर्ग में हैं। शेष दो प्रतिशत ही बाकी दो वर्गों में आती हैं। प्रथम दो वर्गों में भी निरंतर आदान प्रदान होता रहा और ये एक ही भाषा क्षेत्र में आती हैं।<sup>२४</sup> दूसरे, एक प्रदेश के भीतर भी गाँव की बालियाँ, उपलब्धीय भाषा और प्रादेशिक भाषा एक दूसरे के भीतर चक्र की तरह चलती रही हैं। उपलब्धीय भाषा में कभी साहित्य होता है कभी नहीं। प्रादेशिक भाषा साहित्यिक व्यवसायी भाषा होती है।<sup>२५</sup> भारत के संविधान में भी इसी बात का ध्यान में रखकर १६ भाषाओं की सूची दी गयी है। (आठवीं अनुसूची) १८६१ की जनगणना से ज्ञात जाता है कि ८७ प्र. १ लोग ने इन्हीं भाषाओं का अपनी मातृभाषा बताया था। पिछले २०० वर्षों में राज-नैतिक विकास, शिक्षा के प्रसार और नगरीकरण के फलस्वरूप इन प्रादेशिक भाषाओं की बड़ी उन्नति हुई है। इनका स्वरूप निरंतर और बढ़ता है और इनमें साहित्य की नगर्की हो रही है। भारत की भाषागत विभिन्नता के साथ साथ प्रादेशिक रूप से भाषा के एकीकरण की इस त्रिपा पर बहुत थोड़े भाषाशास्त्रियों और मानवशास्त्रियों ने ध्यान दिया है।

तीसरे, इन स्थानीय बोलियाँ और प्रादेशिक भाषाओं और उपभाषाओं के साथ साथ भारत में पुराने जमाने से ही एक या दो भाषाएँ रही हैं, जो सारे देश में

२४ भारत का 'भाषा क्षेत्र' का नाम भाषाशास्त्रों में ही लगाया गया है। उसका कहना है कि भारतीय और द्रविड भाषाओं में इतना आदान प्रदान हुआ है कि आज द्रविड भाषाएँ भारतीय भाषाओं के इतनी निकट आ गयी हैं कि जितना यूरोपी भाषाएँ नहीं। 'इंडिया में एंग्गो-एरिया परिवार', लैंग्वेज, ३२, १९५६। भाषाओं के इस आदान प्रदान पर भाषाशास्त्रियों ने कहा है—यह आदान प्रदान भारतीय सभ्यता के साधारण स्वरूप का प्रतीक है। यहाँ दसमें में जो बातें बहुत भिन्न सादृश्य देती हैं, उनमें भी यदि फरक नहीं तो सत्य है। बोहल-इंडिया सोलज एंग्गो-एरिया भाषा परिवार निम्नलिखित (चुर्चा १९९९)।

२५ जेम्स हॉर्नो में एंग्गो-एरिया हिन्दी, मराठी, गुजराती, उर्दू आदि उपभाषाओं की सामान्य एकता का व्यवहार भाषा के इतिहास में नगरीय भाषाओं के भी सामान्य साहित्यिक भाषा के साथ साथ प्राचीन या स्थानीय बोलियाँ जाती हैं। इन क्षेत्रीय भाषाओं के राज-नैतिक क्षेत्रों या प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए देखें—'एंग्गो-एरिया परिवार' १९९९।

व्यवहार में चलती रही। (मारणी जाठ-१)। पहले संस्कृत, फिर फारसी, फिर उर्दू और १६ वीं शती से अंग्रेजी और बाद में हिंदुस्तानी (हिंदी उर्दू की लिचडी)। इस समय विवाद इस बात पर है कि राजभाषा अंग्रेजी हो (जो ब्रिटिश हुकूमत की देन है) या संविधान में स्वीकृत हिंदी।

आधुनिकता के प्रसार का शुरु में असर यह हुआ कि शिक्षित या उच्चवर्ग और जनसाधारण के बीच गहरी खाई पैदा हो गई। अंग्रेजी शिक्षा सरकारी नौकरी, डाक्टरों, वकालत, अध्यापन आदि संकेदपेशों में तथा राजनैतिक क्षेत्र के लिए प्रवेश थी। मगर अंग्रेजी पढ़े लोग भाषा और संस्कृति की उपेक्षा करने लगते थे और देश के लोगों से बट जाते थे। बाद में गांधी के प्रभाव और राजनीतिक आंदोलन के जन आंदोलन का रूप धारण करने के कारण, हिंदी और प्रादेशिक भाषाएँ भी आगे आईं। इन भाषाओं में साहित्य की रचना होने लगी। इनके माध्यम से जनता में राजनैतिक विचारों और शिक्षा का प्रसार होने लगा और गाँवों से उच्च वर्गों का संबन्ध जुड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अंग्रेजी की जगह हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं की प्रतिष्ठित करने की माँग उठी। सिद्धांत रूप में ये माँगें स्वीकार की गयीं, किंतु इनका व्यवहार में लाने की समस्याओं पर न उस समय ध्यान दिया गया न स्वतंत्रता के बाद। बल्कि नेहरू तथा अन्य नेताओं ने तथाकथित 'प्रांतीय या संकीर्ण प्रवृत्तियों' का जो अनुचित विरोध किया, उसके कारण इन समस्याओं का समाधान टल गया। बाद में दबाव और आंदोलन के कारण केन्द्रीय नेता इन समस्याओं का सुलझाने को बाध्य हुए।

हम पहले देख चुके हैं कि यद्यपि कांग्रेस भाषा के आधार पर प्रांतों की रचना के सिद्धान्त को मान चुकी थी, पर जब एक आदमी ने अनशन करके प्राण दे दिए और गहरा उपद्रव हुआ, तभी कांग्रेस सरकार इस सिद्धान्त पर अमल करने का तैयार हुई। इसके फलस्वरूप देश का बहुत बड़ा पैमाने पर राजनैतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन हुआ। इससे राजनैतिक एकीकरण हुआ, स्थिरता बढ़ी और सरकार और जनता में संपर्क बढ़ा। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त उच्चवर्ग और जनसाधारण में जो खाई थी, वह कम हुई, गाँव के लोगों में राजनैतिक चेतना बढ़ी, उनको सरकार की नीति नीति की ज्यादा जानकारी हुई। प्रांतों का यह विभाजन जनसंख्या के स्वाभाविक वर्गीकरण या विभाजन से मिलता था। इससे विकास के कार्यक्रमों और सरकार की कार्यविधि और पद्धति के बारे में भी सहमति पैदा हुई।

पर भाषा के अनुसार प्रांतों का पुनर्गठन तो समस्या का एक पहलू था। इतना ही महत्वपूर्ण सवाल यह था कि सारे देश के लिए व्यवहार और संपर्क के लिए एक भाषा क्या हो। अंग्रेजी का स्वीकार करना राष्ट्रीय भावना के प्रतिकूल पड़ता था। दूसरा विकल्प हिंदी ही हो सकती थी। परंतु संविधान में हिंदी का चानू करने के लिए १५ वर्ष की जा अवधि रखी गयी थी उसमें गैरहिंदी क्षेत्रों में हिन्दी



कांग्रेस सरकार और कांग्रेस दल के विभिन्न गुटा में लम्बी बातचीत के बाद त्रिभाषा सूत्र अपनाया गया। इसका मतलब यह था कि प्रत्येक राज्य अपने राज्य की भाषा में काम करने के लिए स्वतंत्र होगा। राज्य के विश्वविद्यालयों में यही भाषा पढ़ाई का माध्यम होगी। अन्तरराज्य व्यवहार में अंग्रेजी भाषा से काम लिया जायेगा, यदि यह व्यवहार हिंदी में होगा तो उसके साथ अंग्रेजी अनुवाद भी भेजा जायेगा।

अहिंदी भाषी राज्य केन्द्र से अंग्रेजी में लिखा पढ़ी करते रहेंगे। केन्द्र में और ससद में अंग्रेजी में कामकाज चलता रहेगा। सरकारी नौकरियों की परीक्षाएँ अंग्रेजी, हिंदी तथा सभी प्रादेशिक भाषाओं में ली जायेंगी और हिंदी के विकास के लिए त्रिभाषा कार्यक्रम बनाया जायेगा। यद्यपि इस समझौते से कोई बग पूरी तरह सन्तुष्ट नहीं हुआ फिर भी यह भाषा के प्रश्न पर धीरे धीरे सहमति का आधार बना। उपर्युक्त बातों की घोषणा राष्ट्रपति ने ससद में अपने अभिभाषण में और कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने अपने प्रस्ताव में की।

मतभेद इस बात पर था कि ये आश्वासन संविधान में संशोधन करके लागू किये जाय या ससद में केवल एक प्रस्ताव द्वारा। पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ जाने से यह प्रश्न इस समय टल गया। अन्त में ससद में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें ये सब आश्वासन शामिल किए गए थे। यद्यपि मद्रास विधान सभा ने इसके बाद भी एक प्रस्ताव द्वारा हिंदी का किसी भी काम के लिए स्वीकार करने से इनकार किया। पर यह अनुभव किया गया कि यह प्रस्ताव उपद्रव या आदोलन रोकने के लिए किया गया। द्रमुक नेताओं ने इसके बाद तीन भाषा सूत्र को अमल में लाने के बारे में दूसरे दला से बातचीत करना स्वीकार किया। जनसंघ ने भी, जो हिंदी का कट्टर समर्थक था, दक्षिण और पूर्व (बंगाल) में अपने पैर जमाने के लिए अपने रुढ़ को नरम किया। सत्ता में आने के बाद द्रमुक का रुख भी समझौते का हो गया। इससे पता चलता है कि सत्ता के साथ ज्यादा नरमी या परिपक्वता आ जाती है।

सन ५० के दशक में भाषावाद प्रायः के निर्माण और ६० के दशक में राजभाषा के प्रश्न पर जातिवाद छिड़ा, उससे लगता था कि देश की एकता भग हो जाएगी। पर इससे मतभेद खुले में आ गया और खुलकर वादविवाद से एक रास्ता निकल आया। देश दोनों सक्लों को पार कर गया और आगे भाषावाद से पैदा होने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए ज्यादा तैयार हो गया। इस बीच हुए अध्ययन से पता चला कि शिक्षा, व्यापार, रेडियो, मिनेमा, पत्र पत्रिकाओं आदि साधनों से अहिंदी भाषी क्षेत्रों में द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी काफी फैली है (१९६१ की जनगणना के अनुसार द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी व उर्दू अंग्रेजी से कुछ जागेरी) अंग्रेजी भी तेजी से बढ़ रही है (माध्यमिक विद्यालयों में यह अनिवार्य

विषय है केन्द्रीय शिक्षा सस्थाओं में और इनकी सरया बढ रही है—यह शिक्षा का माध्यम है, जोर पुस्तका तथा समाचारपत्रा मे इसकी प्रधानता है । सभी उन्नति वाक्षी समूह इन दोनो भाषाजा का प्रयोग कर रह हैं । २० यह स्थिति भारत म नयी नही है । यहा हमेशा से विशिष्ट या उच्चवर्ग की एक भाषा रही है ( जस अंग्रेजी ) साधारण बोलचान की एक भाषा देश मे काफी व्यापक रूप मे चलती रही है, इसके प्रादेशिक रूपों में अतर हो सकता है ( जैसे हिंदी ) और विभिन्न प्रदेशों में छोटी छोटी स्थानीय बोलियों के ऊपर परिनिष्ठित प्रादेशिक भाषाए रही ह । फर इतना है कि प्रादेशिक भाषाए अब राज्य के व्यवहार की भाषा के रूप में और महत्व प्राप्त कर रही ह तथा स्थानीय बोलिया इनमें समाती जा रही ह । अब ऐसा लगता है कि सावदेशिक भाषाआ के रूप म अंग्रेजी और हिंदी दोना ही हमेशा चलती रहगी ।

### प्रादेशिकता और विघटन का खतरा

देश के सामने एक खतरा राज्यों के सघ से अलग हो जाने का था । कुछ लोगो ने आशका प्रकट की थी कि प्रातीयता की भावना या प्रदेश के लिए अधिक अधिकार या स्वायत्ता की माग बढती गई ता इससे या तो देश अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्या मे बट जाएगा या यहा तानाशाही कायम हो जाएगी । २० पहले भी देश मे ऐसे आंदोलन हुए ह और वर्तमान में भी हो रहे हैं । कुछ हद तक पुरानी क्याआ के आधार पर और कुछ उत्तर-दक्षिण, ब्राह्मण-अब्राह्मण, आय-द्रविड के भेदभाव के आधार पर । दक्षिण मे, मुख्यतः पुराने मद्रास राज्य मे स्वतंत्रता या स्वायत्ता का बौद्धिक आंदोलन जोर पकडता रहा है । सन १९१७ में द्रविडियन असोसिएशन और साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन (जस्टिस पार्टी) ने मद्रास में सरकारी नौकरिया और राजनीतिक क्षेत्र में ब्राह्मणा के एकाधिकार के विरुद्ध आंदोलन छेडा था । इसी ब्राह्मण विरोधी आंदोलन की नींव पर सन १९४१ में द्रविड कजगम की स्थापना हुई जिसने द्रविड लोगो का आह्वान किया कि वह अंग्रेजों के हाथ से सत्ता आर्थों के हाथ में न जाने दें । उसने भारत स एकदम अलग द्रविडस्थान की स्थापना की माग की । २०

लेकिन १९५४ तक राजनैतिक अधिकार ब्राह्मणा के हाथ से निकल कर अब्राह्मण तमिल नेताआ के हाथ में आ गये और राजगोपालचारी के स्थान पर कामराज नाडार मुख्यमंत्री बने । तब द्र० क० ने कांग्रेस मनिमंडल का समर्थन किया । इस नीति से असंतुष्ट लोगो ने तब अलग होकर द्रविड मुन्नेत्र कजगम की स्थापना की ।

२६ देर - बल्लभराव नायर - ' लंबेज एनार्निंग इन इण्डिया ' ( न्यूयार्क १९६९ ) ।

२७ सेमिग हैरिमन - ' इण्डिया - द मोस्ट उंजरस मिनेडम ' ( प्रिंसटन १९६० ) ।

२८ राबर्ट एल हांग्रेव - ' द द्रविडियन मुवमेंट ' ( बर्र १९६९ ) ।

इसने द्रविडस्तान का आंदोलन जारी रखने का प्रण किया। लेकिन एक जोर कांग्रेस में तमिल (अब्राह्मण) प्रभाव बढ़ा और दूसरी ओर द्र० मु० क० की शक्ति बनी। १९५६ में द्र० मु० क० ने मद्रास कारपोरेशन और अय नगरों की शासन सम्वत्थों पर कब्जा कर लिया और १९६२ के चुनाव में यह सब से बड़े विराधी दल के रूप में आया। सत्ता के स्वाद ने द्र० मु० क० की उग्रता का कुछ नरम कर दिया। इसने आंदोलन का मार्ग छोड़कर चुनाव जीत कर सत्ता प्राप्त करने की नीति अपनायी। २० इस पर ई० वी० के सम्पत के नेतृत्व में एक पथक्तावादी गुट इससे अलग हो गया। अब्राहमुरे के नेतृत्व में द्र० मु० क० की शक्ति बढ़ी और इसका प्रभाव गांवों में फैला। इसने पथक्ता के बजाय जाति और जाति-पाति की विपरीतता को दूर करने और भाषा के मामले में स्वतंत्रता का नारा लगाया और अंत में १९६७ के चुनाव में मद्रास राज्य में विजयी हुई। द्र० म० क० सरकार ने भाषा के मामले में केन्द्र से भिन्न रुख अपनाया है, किंतु मद्रास (जिसका नाम बदल कर तामिलनाडु हो गया है) सबसे व्यग्रस्थित, शांत और भारत सघ का वफादार राज्य साबित हुआ है। ३०

सन १९६७ में सत्ता में आने के बाद द्र० मु० क० के भीतर भी उन्नी प्रकार की गुटबंदी प्रकट होने लगी जैसी कांग्रेस में थी। तमिलनाडु में द्रमुक सत्ता में है और कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी दल के रूप में काम कर रही है। इस प्रकार जानीबूझा अथात् अब्राह्मण-अब्राह्मण की भावना ने राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता का रूप धारण कर लिया ३१ और प्रश्न या प्रात की भावना पर आधारित प्रतिद्वंद्वी दल ने देश की लोकतंत्री सचीय पद्धती को चलाने में योग ही दिया। प्रादेशिक निष्ठा का इस प्रकार संगठन और बाद में उसका राष्ट्रीय राजनैतिक व्यवस्था का अंग बनना, राजनैतिक संगठन और मोरचेबंदी की ही प्रक्रिया सिद्ध हुई।

दूसरी ओर यह भी ध्यान रहे कि पथक्ता की भावना उन में ज्यादा चलवान और चतुरनाक है, जहां ऐसी आर्येतर जातियाँ हैं, जो भारतीय संस्कृति की धारा में पूरी

२९ देश के दूसरे भागों के जनमत ने भी द्रमुक के रुख पर प्रभाव डाला। पृथ्वना की प्रवृत्ति को रोकने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद की उपसमिति का मिशन पर सविधान में संशोधन किया गया। इसका उद्देश्य प्रातायता और भाषा की वरता से देश की एकता, अखण्डता और प्रभुता की रक्षा करना था। इस संशोधन ने भी द्रमुक को अपना नाति बदलने को बाध्य किया, जिसमें वह देश के सविधान के दायरे में रहकर काम कर सके।

३० सन १९७१ के मध्यावधि चुनाव में द्र मु क ने इंदिरा गांधी की कांग्रेस से समर्थन किया और राज्य में पहले से भी अधिक बहुमत से पुन सत्तारूढ़ हुई। केन्द्राय समर्थ में और राष्ट्रीय राजनीति में द्र मु क सामान्य रूप से इंदिरा गांधी के साथ रहा है।

३१ हान्धेव-दंडा धम के दंड द पाण्डिक्कस आक तमिल नेगल्लिज्ज पमि अरे, मैत्राम न ५, १९६४-६५।

तरह मिल नहीं पाई है। जैसे उत्तरपूर्व की आदिम जातियाँ का इलाका।<sup>३२</sup> वहाँ भी भारतीय लोकतंत्री व्यवस्था और सरकारी विकास कार्यक्रमों का प्रभाव पड़ा है और धीमे धीमे इन क्षेत्रों के नागरी देश की राजनीति में भाग लेने लगे हैं। पर राजनैतिकीकरण की यह प्रवृत्ति अभी शुरू हुई है। दूसरी ओर आनुवंशिकता के प्रसार से अपने पथक अस्तित्व की भावना उभरती भी है। इसलिए इनको समालने के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। इस प्रकार की व्यवस्था की भी जा रही है। इसी उद्देश्य से नागालैंड का अलग राज्य बनाया गया और नागा विद्रोहियों के प्रति नरमी का रुख अपनाया गया। इसी तरह आसाम के अतगत पहाड़ी इलाकों का मेघालय नामक उपराज्य स्थापित किया गया। जम्मू-काश्मीर को विशेष दर्जा भी इसी उद्देश्य से दिया गया था।

कुछ क्षेत्रों में अभी भी असन्तोष है जैसे—उत्तरपूर्व में मीज़ो जाति, बिहार में छोटा नागपुर तथा मध्यप्रदेश के आदिवासी इलाकों और गुजरात व ओडिसा में आदिवासियों का स्वायत्तता का आंदोलन। राजनैतिक गतिविधि बढ़ने और शिक्षा तथा आर्थिक विकास के फलस्वरूप छोटे समूहों में जो अब तक दबे या पिछड़े हुए थे, अधिकार और स्वायत्तता की आकांक्षाओं का उठना स्वाभाविक है। समस्या इस बात से उत्पन्न गयी है कि कुछ आदिवासी इलाकों चीन और पाकिस्तान से लगे हुए हैं और वहाँ से असंतुष्ट तत्त्वों को छापासार युद्ध की ट्रेनिंग देने की कोशिश की गई है। यह सतर्कता काफी दिनों तक रहने वाला है और सीमांत इलाकों की राजनैतिक समस्या के समाधान के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा। गृहमंत्रालय इस मामले में समझदारी से काम ले रहा है, परन्तु यह समस्या—सीमांत इलाकों में असंतोष और सीमा पार से इस असन्तोष को प्रोत्साहन—ऐसी नहीं, जिस का हल आनन फानन निकल आए।<sup>३३</sup>

इस प्रकार देश के एकीकरण की समस्या अभी बनी है। राज्यों के भीतर विशिष्ट क्षेत्रों के अलगाव के आंदोलन उठ रहे हैं। दबे हुए वर्गों और समूहों के

३२ इस विषय के लिए अध्ययन के लिए—आर्थर जे डोनावन का लेख 'सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज इन इस्टर्न इंडिया'—एशियन सर्व—सात स १०, अक्टू १९६७।

३३ गर आदिवासी इलाकों के अलावा भी राज्यों के अंदर कुछ क्षेत्रों में एकात्मता की मांग उठी है। जैसे आंध्रप्रदेश में तेलंगाना के अलगाव का आन्दोलन। आंध्रप्रदेश का स्थापना के समय किए हुए वायदा के पुराने नियमों के अंतर्गत काम के मातल की गुणवत्ता की रोकने में मुद्रास्त्र की विफलता के कारण तेलंगाना के कुछ नेताओं ने १९६९ में अलगाव का आंदोलन किया। इस आंदोलन ने काफी उग्र रूप धारण किया। अभी तक तेलंगाना के पृथग्तावादियों को संतुष्ट नहीं किया जा सता है। सम्भव उनको काफी रियायतें देना पड़े और मुद्रास्त्र को बदलना पड़े। १९७१ के सम आध्यात्मिक चुनाव में तेलंगाना पृथग्तावादियों को उस क्षेत्र में अधिपतित सार्वमिली। महाराष्ट्र और मैसूर में भी इसी प्रकार के आंदोलन हुए हैं यद्यपि वे इतने उग्र नहीं थे।

राजनैतिक क्षेत्र में आने से अधिनार के लिए उनकी आकांक्षा से नयी समस्याएँ खड़ी हो रही हैं तथा केन्द्रीय सरकार का इन समस्याओं से निपटने के लिए नयी नीति और उपाय निकालने पड़ते हैं।

### अल्पसंख्यकों का सवाल

एक समस्या राज्यों के भीतर भाषागत अल्पसंख्यकों और अल्पसंख्यक संप्रदायों की है। औसतन राज्य में १८ प्र० १० लोग ऐसे हैं, जिनकी मातृभाषा राज्य की भाषा में भिन्न है। केरल में यह संख्या केवल ५ प्र० १० है ताँ मसूर में ३५ प्र० १० और आसाम में ४४ प्र० १०। जहाँ शासन या उद्योग व्यापार में इस प्रकार के 'बाहरी' लोग की प्रधानता होती है वहाँ इससे काफी असुविधा होता है और इन लोगों का शोषण समझा जाता है जैसे महाराष्ट्र में गुजराती और दक्षिणियों को, आसाम में ओडिसा में बंगालियों को और बंगाल में मारवाड़ियों को। इनके खिलाफ शहरों में शिवसेना (महाराष्ट्र) और ललित सेना (आसाम) जैसे उग्र आंदोलन उठ खड़े हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महाराष्ट्रीय तत्त्वा ने भी इस प्रकार की भावना का उभाड़ा है। पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मारवाड़ियों के खिलाफ भावना जोर पकड़ रही है। शिवसेना जैसे उग्र संगठन खतरनाक हैं, ये फासिस्ट मनोवृत्ति के छातक हैं। ये मध्यमवर्ग की निराशाओं और कुठारा का दुरुपयोग करके बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वर्गों में स्वाभाविक प्रतिद्वन्द्विता का स्थायी शत्रुता और हिंसा में बदलने का प्रयत्न करते हैं। इनके खिलाफ सरकार को कड़ी कार्रवाई करना आवश्यक है।

इसी प्रकार स्थानीय चण्डा के कारण हिंदू-मुस्लिम विद्वेष भी भड़क उठता है। १९६७ में उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे नगरों में हिंदू-मुसलमानों में झगड़े हुए। १९६९ में इनसे ज्यादा गंभीर दंगे अहमदाबाद और गुजरात में हुए, जिनमें कई सौ आदमी मार गए और काफी लूटपाट व आगजनी हुई। यह समस्या स्थायी रूप से तब हल होगी जब सभी वर्गों में धर्मनिरपेक्षता की भावना का विकास होगा, लेकिन तात्कालिक रूप से न केवल सरकार को कड़ाई और सावधानी बरतनी होगी, अपितु राजनैतिक दलों और शिक्षा तथा सांस्कृतिक संगठनों का भी सांप्रदायिक भावनाओं को निमूल करने की कोशिश करनी होगी (अलीगढ़ में विश्व-विद्यालय में ही सांप्रदायिक चण्डे हुए हैं)। राजनैतिक दल इस ढर्रे से सांप्रदायिकता से बचने की कोशिश करते हैं कि वे दूसरे संप्रदायों के वोट खो देंगे परंतु उनके स्थानीय संगठन स्थानीय चण्डा का लाभ उठाने के प्रलोभन में पड़ जाते हैं। सांप्रदायिक झगड़े भले ही छिटपुट और स्थानीय हों, लेकिन उनसे देश की बदनामी होती है और उसका लोकतंत्रीय धर्मनिरपेक्ष स्वरूप कलंकित होता है।





है, उसमें पता चलेगा कि लोकतंत्री तरीके से विविध तत्त्वा का लेकर सघीय व्यवस्था के विकास में क्या समस्याएँ उठती हैं। इनसे पता चलता है कि वैद्रीय राजनैतिक सत्ता के विकास में केन्द्रगामी और केन्द्रघाती दोनों प्रवृत्तियाँ किस प्रकार सामने आती हैं।

भारत की राजनीति में प्रांतीय जोर वगैरह मागों ने राष्ट्रीय राज्यव्यवस्था के सामने नई समस्याएँ खड़ी की हैं। राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास कोई आसान बात नहीं। जैसा कहा जा चुका है भारतीयता का रूप व्यापक होगा। इसमें अनेक प्रकार की पद्धतियाँ आपस में गुथी होंगी। इस सबब शकला के निमाण में राजनैतिक व्यवस्था का मुख्य हाथ होगा। इसमें जनता को राजनैतिक गतिविधि में खींचना होगा और राजनैतिक समस्याओं को जनता में फैलाना होगा विशेष प्रश्न व समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करनी होगी और सत्ता का विकेंद्रीकरण करना होगा। इससे जनता के विभिन्न वर्गों को आकर्षित करेंगे और उनको संतुष्ट करने में राजनैतिक व्यवस्था की बड़ी परीक्षा होगी।

इस अध्याय में और पूरी पुस्तक में हमारा कहना यही है कि भारत जैसे विशाल देश में जहाँ इतने विविध प्रकार के लोग रहते हैं, एकता की स्थापना इसी से हो सकती है कि सब तत्त्वा को राजनैतिक सत्ता व अधिकार में भाग दिया जाए और सब का साथ लेकर चला जाए (नई दिल्ली से सारे भारत का शासन करना असंभव है)। इसके लिए जरूरी है कि समाज के सब वर्गों में राजनैतिक समस्या का प्रवेश हो। राजनीति को इस रचनात्मक भूमिका से ही एकीकरण की प्रवृत्तियों को बल मिलता है।

[ पिछले पृष्ठ में ]

‘विश्व रीति’ प्रो. ड. एन. चौधरी, अक्टूबर १९५०। १९५७ में नई दिल्ली में इंडिपेंडेंट क्लब द्वारा और इन्होंने मोशल साइम फाउंडेशन की ओर से प्रादेशिक और सामाजिक विषयों के विषय में एक सम्मेलन हुआ था। इस में पठित निबंध ‘विश्व रीति’ इस्टीमेटेड के प्रो. रामचंद्र गुप्ता से मिल सकते हैं।

### विक्रम की राजनीतिमूलक अर्थनीति

राजनित्य व्यवस्था के संस्थापन में सामाजिक और आर्थिक तन्त्र बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं की पूर्ति पर व्यवस्था की सकलता निर्भर रहता है। यह व्यवस्था जैसे जैसे जनता में प्रचलन करती है, आर्थिक और सामाजिक प्रगति स्पष्ट रहती है और जनता की आकांक्षाओं का जन्म देती है। वास्तव में भारत में जहाँ वास्तविकता और जनता की उपनिधि का तन्त्र अपनाया गया है। राष्ट्रीय एकता और शांति का सहयोग प्राप्त करने पर यहाँ जा जाकर दिया गया है उपाय आर्थिक विकास और महत्त्वपूर्ण बन गया है।

आर्थिक विकास और राजनीतिक विकास में पारस्परिक संबंध का प्रश्न जोई सरल नहीं है। जा राजनैतिक प्रणाली गरीबी और अभाव का समस्या का मुन मानने का मुनियोजित ढंग से प्रयत्न नहीं करती वट स्पष्ट य सत्य नहीं बहो जा सकती। विचारवान अर्थशास्त्री आर्थिक विकास में राजनैतिक प्रतिशब्दों का महत्व समझने लगे ह और उस आर्थिक विकास की राजनीति का नाम "डि। इसी तरह राजनीति शास्त्री भी राजनैतिक व्यवस्था का आर्थिक पक्ष का महत्व अनुभव करत और राजनैतिक विकास की अवधारिति का नाम "डि। भारत में ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे से मिले हुए हैं और इस पर चालाचरण जनसभा, समाजी कार्य आदि बर्दे और यात्रा का प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस विषय को विकास की राजनैतिक अवधारिति का नाम देना उचित होगा।

आर्थिक विभाग की साधारण म.वि.

इस समय भारत का जिन विविध मुद्दों पर है। १९५५ में ११/१३ जन  
वर्गों का एक सत्र अन्तर्गत रहा और इसका कारण नीतिगत है। यदि,  
वर्तमान में लक्ष्य के कारण भारत में अन्तर्गत लक्ष्य के एक सत्र।  
१९५३ के भारत के भारत विविधता के कारणों का एक सत्र और लक्ष्य के  
कारण का है कि विविधता के कारणों के नीतिगत मुद्दों पर है और

सबे प्रयत्न के बावजूद भी बदलने की वागिंग की जा रही है। इन सबके फलस्वरूप विकास की गति एक सी गई है और वहीं वहीं पीछे हटी है। १९६७-६८ के बीच कुछ प्रगति हावी दीत पड़ी है और विकास का काम फिर चल पड़ा है, मगर हम यहाँ दस पाच बष के काम पर ही विचार करने नहीं बैठे हैं। प्राकृतिक आप-  
 नाए भारत में आती ही रहती हैं और हमें यह मान कर चलना चाहिए कि यह साधारण बात है। इसके साथ ही हाल में आर्थिक नीति और राजनितिक बावें जो परिवर्तन किए गए हैं उनसे भविष्य का कुछ संकेत मिल सकता है और हम आर्थिक क्षेत्र में भारत के काम का कुछ कामचलाऊ मूल्यांकन कर सकते हैं।

आर्थिक विकास के राजनितिक पहलू से सबसि सबसे बड़ा सवाल है सामाजिक काम का—एक ओर उत्पादन और सचय और दूसरी ओर 'यामपूण और समान रूप से वितरण का। ये दोनों पहलू एक दूसरे के विराधी नहीं हैं ये दोनों ही लक्ष्य एक साथ सिद्ध होने चाहिए। पहले कहा जा चुका है कि नव स्वतंत्र देशों को एक साथ कई काम करने हैं। 'गुरु से ही भारत के सामने चार निश्चित लक्ष्य रह हैं। वेदेशों से बुनियादी वस्तुओं के आयात और विदेशी सहायता पर निर्भरता को दूर करना (स्वयं सपोषित विकास), साधना और पूँजी को जुटाना, जिससे ज्यादा पूँजी बचाकर उत्पादन व विकास में लगायी जा सके (विकास की दर बढ़ाना), समाज के विभिन्न वर्गों में विषमता घटाना (समता), जीवननिर्वाह के लिए न्यूनतम साधन प्रस्तुत करना ('याम), इन लक्ष्यों के साथ साथ देश में एकता बढ़ाना, झगडा को रोकना और विविध वर्गों को राष्ट्रीय व्यवस्था में शामिल करना।

इन लक्ष्यों की पुष्टि राष्ट्रीय आंदोलन में और स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के प्रस्तावों में बार बार की गयी थी। कांग्रेस सरकार इनके लिए प्रतिबद्ध थी। इनकी दिशा में कई कदम उठाए गए। गांधी में अधिक 'यामपूण व्यवस्था कायम करने के लिए जमींदारी और सामंती पद्धति का अंत किया गया। विकास के लिए साधन जुटाने और नियोजित प्रयत्न करने के लिए योजना संगठन कायम किया गया। गांधी की उत्पत्ति के लिए और सहकारी प्रयत्न को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक विकास और सहकार के विकास का कार्यक्रम शुरू किया गया। सन ५० के दशक के मध्य तक विकास कार्यों को चलाने का प्रशासनिक ढांचा तैयार हो गया, और भारी उद्योगों में रुपया लगाने तथा बुनियादी मशीनों व सामान के आयात को बरीयता देकर रवावलवी विकास की तयारी की गयी। लेकिन भारी उद्योगों को चालू करने में एक तो समय लगता है दूसरे जा कारणों लगे के पूरी क्षमता से काम न कर सके, इस कारण एक ओर तो विकास की गति मद पड़ी, दूसरी ओर उपभोग्य वस्तुओं की कमी पड़ी जिससे जनता को कष्ट हुआ। परंतु

इस नीति वं पक्ष में यह कहा गया कि औद्योगिक माल के लिए विदेशों पर निर्यात देश की स्वतन्त्रता को कमजोर करेगी। इसलिए आयात की जाने वाली चीजों के बदले देश के माल से काम चलाने और मशीन बनाने की मशीनों को ही आयात करने पर जोर दिया गया।

पर यह नीति यथाथवादी न थी। कलपुर्जों का आयात बढ़ करने के प्रयत्न में हमें सबसे बुनियादी आवश्यक चीज अन्न का आयात करने की जिल्लत उठानी पड़ी। इस नीति की विफलता के कारणों पर हम बाद में विचार करेंगे। यहाँ इतना ही कहना काफी है कि आयोगों ने आर्थिक स्वतन्त्रता और अपने बल पर विकास करने और देश में जल्दी से जल्दी मशीन या पूँजीगत माल बनाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया।

### अपने बल पर विकास

प्रायः एक दशक तक आयोगों को वितरण और लोककल्याण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत न पड़ी। उन्हें पूँजी जुटाने और भारी उद्योगों में उस लगाने का पूरा समय मिला। केवल बीच-बीच में गाँवों की उन्नति के और सूखे या बाढ़ की आपत्ति में कुछ सहायता कर देने के अलावा समाजवाद के समान वितरण के लक्ष्य की सिद्धि के लिए कुछ करने की जरूरत न पड़ी। यद्यपि अभी भी भारी उद्योगों से पूरा उत्पादन नहीं मिल पाया है फिर भी विकास की गति बुरी नहीं रही। यदि सूखे और अकाल के दो वर्षों को छोड़ दिया जाए तो १९५१ (पहली योजना का आरम्भ) और १९६५ (तीसरी योजना का चौथा साल) के बीच (१९६०-६१) के स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय कुल ६६ प्र.श. बढ़ी। वार्षिक मिथ्य दर से यह वृद्धि ३.८ प्र.श. होती है। वृद्धि की दर हर योजना में कुछ बढ़ी है। पहली योजना की अवधि में ३.४ प्र.श. दूसरी योजना में ४ प्र.श. और तीसरी योजना के चार वर्षों में यह ४.२ प्र.श. रही। तीसरी योजना काल में अनेक बाधाएँ आईं - दो वर्ष फसल खराब हुई, दो युद्ध हुए और विदेशी मुद्रा की गहरी कमी पड़ी। प्र.श. औसत वृद्धि कोई बड़ी बात नहीं, पर इसके मुकाबले यह याद रह कि इसके पहले के ५० वर्षों में देश की आर्थिक उन्नति प्रायः रुकी रही (शून्य से करीब ५ से १ प्रतिशत कुल वृद्धि) फिर भी जो उन्नति हुई है भारत जैसा गरीब देश उस पर सताप नहीं कर सकता। इस बीच जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है उसको भी ध्यान में रखना होगा। (सन १९५१ से १९६१ के बीच दस वर्षों में जनसंख्या में २१.५ प्र.श. वृद्धि हुई) इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय में करीब २ प्र.श. वार्षिक वृद्धि हुई।

इस अवधि में अन्न-उत्पादन में ५० प्र.श. वृद्धि हुई अर्थात् औसत ३.५ प्र.श. प्रति वर्ष। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसके पूर्व ५० वर्षों में न केवल

उत्पादन नहीं बढ़ा, बल्कि प्रति व्यक्ति हिसाब से घट गया, <sup>१</sup> यह वृद्धि अच्छी है। पर भारत की गरीबी और जनमर्या के विस्फोट को देखते हुए, यह सताप-जनक नहीं कही जा सकती। योजनाओं के फलस्वरूप उद्योगों में उन्नति ज्यादा हुई। इन १४ वर्षों में औद्योगिक उत्पादन का सूचक एक १९५१ में ७४ से बढ़ कर १९६१ में १८७ हो गया (१९५६ को आधार मान कर) जो १५२ प्र० श० से अधिक होता है। (यह सूचक एक महत्वपूर्ण उद्योगों में हुई चमत्कारी उन्नति को सूचित नहीं करता)। इस अवधि में कोयले में १०० प्र० श०, इस्पात में ४०० प्र० श० और बिजली के उत्पादन में ६०० प्र० श० की वृद्धि हुई। पहले यहां मशीनों और मशीन बिलकुल नहीं बनते थे, अब इनका बहुत अच्छा उद्योग चालू हो गया है। इसी तरह औद्योगिक उपयोग के और माल, मोटर ट्रक और पेट्रोल के उद्योगों में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। इस अवधि में भारत रेल की पटरी बनाने में तीसरे, कपड़ा बनाने में तीसरे, कोयले की खुदाई में सातवें, लोह में नौवें, सीमेंट में नौवें, कोयले में दसवें और बिजली में बाहरवें नंबर पर आ गया। कुल राष्ट्रीय उत्पादन में यह संसार में आठवें नंबर पर था। यहां दुनिया में सबसे बड़ा लोह का खनिज भंडार है, मैंगनीज भंडार में तीसरे नंबर और कोयले में सातवें नंबर पर है। यहां ४१० लाख किलोवाट पनबिजली बन सकती है। (६० प्रतिशत लाइ पर)।

दस की इस क्षमता का उपयोग अभी शुरू ही हुआ है। भारत सरकार ने सरकारी क्षेत्र में बुनियादी उद्योग शुरू किए हैं जो किसी निजी उद्योग की सामर्थ्य के बाहर थे।<sup>२</sup> पहली योजना में सरकारी क्षेत्र में ५५ करोड़ की पूंजी लगी थी जो तीसरी योजना में ५२० करोड़ हो गई। निजी उद्योगों में इसी अवधि में पूंजी नियोजन २३३ करोड़ से बढ़कर १०५० करोड़ हो गया। १९५१-५२ में शुद्ध वृद्धि राष्ट्रीय आय की ५३ प्र० श० हुई जो १९६५-६६ में १०५ प्र० श० हो गयी और विनियोग ५३ प्र० श० से बढ़कर १४ प्र० श०।<sup>३</sup> इसके साथ ही मूल्य

१ के मुताबिक 'लेक्जस आफ इकनामिक ऐक्टिविटी ऐंड पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया' (न्यूयार्क १९६५)। १९०० के मुताबिक स्वतंत्रता के समय खेती के उत्पादन का सूचक अर ६ प्र० श० ऊंचा था और १९३६-३७ के सबसे अच्छे फसल के वर्ष से १२ प्र० श० कम। इस अवधि में अन्न के बजाय नकदी फसलों की खेती बढ़ी और प्रति व्यक्ति खाद्य का उपलब्ध घट गया।

२ इन सरकारी उद्योगों में उद्योगनीय है भारत एलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान मशीन टूल, हिंदुस्तान केमिकल चित्ररत्न कारखाना और पैराम्बर के रेल इंजन कारखाने, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर और बोकारो में विदेशी सहयोग से स्थापित इस्पात कारखाने। यहां निजी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने के बजाय, जो उद्योग नहीं थे, उन्हें स्थापित किया गया।

३ ये आंकड़े चौथा योजना के मसौदे पर आधारित हैं। वर्तमान विनिमय दर— १ करोड़ र = १३,५३, ३३३ डॉलर या ३ करोड़ र = ४० लाख डॉ।

की वृद्धि १४ वर्षों में कुल ४० प्र० श० हुई। जबकि इस अवधि में चीन से युद्ध के कारण सेना का खच बड़ा और सरकार को घाटे की वित्तव्यवस्था करनी पड़ी। वर राष्ट्रीय आय के ७ प्र० श० से बढ़ कर १४ प्र० श० हो गए। इन सबके फल स्वरूप एक साल को छोड़ कर जब फमल खराब हो गई थी, सारी अवधि में राष्ट्रीय आय में लगातार, चाहे थोड़ी ही, वृद्धि होती रही।

यह देखते हुए कि भूमि में भारत का नवर विश्व में सातवा जीर जनसंख्या में दूसरा है, यह प्रगति अधिक नहीं। मगर जिस पिछड़ी हुई हालत में भारत था उसको देखते हुए, इसकी प्रगति बुरी नहीं, खासकर उद्योग में। पूँजी एकत्र करने, और उसे उत्पादन में लगाने, उत्पादन बढ़ाने और महत्वपूर्ण सामान का आयात घटाने में काफी सफलता मिली, यद्यपि योजना के लक्ष्य पूरे नहीं हो सके।

### सोए अवसर

लेकिन अवसर का पूरा उपयोग नहीं किया गया। जमींदारों का उन्मूलन किया गया, लेकिन भूमि का उचित वितरण नहीं किया गया। इसी तरह सिंचाई के साधनों का उपयोग वजाय उपजाऊ क्षेत्रों में करने के सुखाग्रस्त क्षेत्रों में ज्यादा किया गया। निजी और सरकारी उद्योग सबधी विवाद में उबरकर उत्पादन की योजनाएँ रकी रही। अन्न की कमी से खेती की उपज बढ़ाने की प्रेरणा ग्रहण करने के वजाय विदेशों से अन्न मगाने का आसान रास्ता चुना गया।

औद्योगिक क्षेत्र में आयात का विकल्प निवालने की नीति का दुर्हपयोग देश में घटिया उद्योगों को संरक्षण देने में किया गया। बहुत शीघ्रता से बहुत-सी चीजों के कारखाने खड़े करने का नतीजा यह हुआ कि साधन बिखर गए और पूरी अर्थ-व्यवस्था में लागत बढ़ गयी।<sup>४</sup> साधनों को साधक उद्योगों में लगाने और नयी विधियाँ निवालने की प्रेरणा न रही। निहित स्वार्थों के दबाव के कारण साधनों को नए या आवश्यक कामों में न लगाया जा सका। मूल्यवृद्धि या मुद्रास्फीति से अनावश्यक रूप से डर कर यह कोशिश न की गयी कि मूल्यवृद्धि को उत्पादन बढ़ाने का औजार बनाया जाए। जबकि खेती की लागत अधिक पड़ रही थी, पैदावार का दाम नीचा रहा। इससे खेती की प्रगति रुक गई। सूखे के कारण जब मूल्य के बढ़ने की स्थिति पदा हुई तब सरकार ने घबड़ा कर अपनी योजनाओं में धन का नियोजन घटा दिया। इस

जिस माल की मांग हो उसी के उत्पादन में  
कि मशीनी औजारों का उत्पादन होता रहे

<sup>४</sup> एक बरनसन-मैनुफैक्चरिंग माइल्स इन इंडिया  
वर्ष १९६७ में इस पर  
कानून में क्या समझें

क्याकि उद्योगो के लिए कच्चे माल तथा जय आवश्यक सामान की कमी थी। इस कारण मशीनी औजारो की माग न रही। हि० म० टू० के माल के ग्राहक भी नहीं मिलते थे। अस्तु यद्यपि तीन योजनाओ के दौरान काफी तरक्की हुई, परन्तु सबसे जरूरी चीजो को प्राथमिकता नहीं दी गई, और कुछ चुने हुए क्षेत्रो में पूरे साधन और जोर नहीं लगाया गया। दिखावे के चक्कर में जो योजनाएं चालू की गईं उनमें साधनो की काफी बर्बादी भी हुई।

अधिक चिंता की बात थी खेती और उद्योगा के विकास में असंतुलन। खेती में देश की तीन चौथाई जनसंख्या लगी है, और इससे राष्ट्रीय आय का आधा भाग प्राप्त होता है तथा इसी से उद्योगा के लिए कच्चा माल भी मिलता है। इस पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया, जिसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर बुरा पड़ा।

इसका असर दिखाई पड़ा जब दो साल तक लगातार सूखा पड़ा, निर्यात की आमदनी घट गयी, पाकिस्तान में युद्ध के बाद बाहरी महायत्ना रुक गयी और कारखाना के लिए कच्चे माल और कलपुर्जों की कमी पड़ गयी। इसमें दाम बढ़े और मदी आयी, राजनैतिक अस्थिरता और चारो ओर कष्ट बढ़ा। तब उद्योगा के मुनाबले खेती की उपेक्षा करने का परिणाम सामने आया। इसके फलस्वरूप आर्थिक नीति पर पुनर्विचार हुआ, योजनाओं की प्राथमिकता बदली गई, प्रगतिशील तार तरीके सुधारें गए तथा पूरी रीति नीति में परिवर्तन हुआ।

किन्तु असंतुलित विकास से हिम्मत हारने की जरूरत नहीं।<sup>१</sup> इसमें जो सफट आता है उससे आख खुल जाती है और अपने तरीके बदलने का अवसर मिलता है। इससे जो धक्का लगता है, उससे नेतृत्व की गफलत दूर होती है और आगे बढ़ने के लिए नया बल मिलता है। जिन चीजो को पहले असंभव समझा जाता था, वे अब संभव लगने लगती हैं और सभी दल उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। जिन देशों को आलस और अकम्प्यता की आदत पड़ जाती है, उसे इस प्रकार का धक्का लाभ पहुंचाते हैं और काम में लगते हैं।

१९६१-६७ में भारत में जो सफट आया उसके कारण सरकार का विकास कार्यक्रम की दिशा बदल गई। खेती के विकास की नई नीति अपनाई गई। सिंचाई की छोटी योजनाओं पर जोर दिया गया। उपजाऊ जमीन में उन्नत बीज और उर्वरक का प्रयोग करने पर जोर दिया गया। जमीन की जांच पड़ताल करने के साथ वर्गीकरण करने पर जोर दिया गया। याजना की प्राथमिकताओं में परिवर्तन किया गया। नियंत्रणा का ढीला किया गया। जायान का विस्तृत विचारने के बजाय नियंत्रण बढ़ाने पर ध्यान दिया गया और बहुत-सी नई नई योजनाओं

देखिए, पृष्ठ ४६ ओ हश्मान 'स्ट्रेटेजी ऑफ इकॉनॉमिक टेक्नॉलॉजी' (१९६४) तथा 'जर्नी टुवर्ड्स प्रोग्रेस' (न्यूयार्क १९६३)। इसमें लेखक ने कहा कि तब क्या इस प्रकार विकास से भी विकास में मदद मिलती है।



को शुरू करने के बजाय वतमान उपादनप्रणमता का पूरा-पूरा उपयोग करने पर जोर दिया गया ।

तरीका में इन परिवर्तना से ज्यादा महत्वपूर्ण था रुख में परिवर्तन । अनुभव किया गया कि सिर्फ उपदेश देने और हुसम राना देने से काम नहीं चलगा । इसके बजाय किसान और उत्पादन को मालम होना चाहिए कि उत्पादन बढ़ाने से उसको लाभ होगा । भाषण देने के बजाय किसान को खेती के लिए आवश्यक सामान उपलब्ध कराना जरूरी है । सीमित साधना को बहुत बड़े क्षेत्र में छितराने की बजाय उनका प्रयोग उपजाऊ क्षेत्रों में करना चाहिए जिससे उपज तुरंत बढ़े । दामा को स्थिर रखने की बहुत ज्यादा चिन्ता न करनी चाहिए । जिससे दाम बढ़ने से उत्पादक का फायदा हो और वह ज्यादा मेहनत करे । सबसे बड़ी बात यह हुई कि कागजी घोड़े दौड़ाने के बजाय खेती को आर्थिक समस्या के रूप में देखा गया । और विशेषज्ञ तथा सरकारी अधिकारियों पर भरोसा करने के बजाय गांव के कायबर्तियां जार नेताओं को आगे आने दिया गया । गांव के इन नेताओं को भारत के प्रगतिशील किसानों के दृष्टिकोण की ज्यादा जानकारी है और उन्होंने माजना कमीशन के कागजी योजना बनाने वालों को प्रभावित किया ।

गासन अधिकारियों ने भी नई लगन और क्षमता दिखाई । सूबाग्रन्थ इलाका में राहत पहुँचाने में राज्य और केन्द्र के खाद्य मन्त्रालय के अधिकारियों ने जा तत्परता दिखाई वह इसका प्रमाण है । और क्षेत्रों में भी किताबी या कागजी बहस करने के बजाय व्यावहारिक समस्याओं पर ध्यान दिया गया । इस नई नीति और काम करने के नए तरीके की सफलता में अच्छी वर्षा और अच्छे मौसम ने भी योग दिया और इससे अनाज के उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई । पहली बार सरकार में जात्मविश्वास पैदा हुआ और उसने घोषित किया कि १९७० से उसे बाहर से अन्न भगाने की जरूरत न पड़ेगी । यदि ऐसा न भी हो सके, तो इसकी पूरी आशा है कि कुछ ही वर्षों में यह लक्ष्य पूरा हो जाएगा और हम अपने खेत पर विकाम कर सकेंगे । खेती का पिछड़ापन दूर होने के साथ साथ पहले की औद्योगिक योजनाएँ भी आरम्भ बाधाओं का पार करके फल देने लगेंगी ।

### राजनैतिक प्रश्न

वास्तव में सूचा पड़ने से पहले ही विकास की रीति नीति बदलने की गुरात हो गयी थी । लेकिन जब खाद्य संकट उपस्थित हुआ तब सरकार के सोच विचार या हिचकिचाहट का अंत हो गया और दबता से कदम उठाए गए । सरकार पर एक ओर उन राज्यों का दबाव था, जहाँ खाद्य की अधिकता थी और दूसरी ओर उन्हे कमी जाने राज्यों की माग की पूर्ति करनी थी । मोभाग्य से इस समय बि० सुब्रह्मण्यम जैसा कुशल प्रशासक और राजनीतिज्ञ खाद्य मंत्री था । खाद्यसंकट,

पाकिस्तान युद्ध और अमरिका द्वारा सहायता बंद करने से जो स्थिति उत्पन्न हुई उसका लाभ उठा कर उन्होंने लाभकारी निणय कराने में सफलता पाई। यहाँ हमें खाद्य की कमी की तात्कालिक समस्या और खेती की उपज बढ़ाने की लंबे समय की समस्या में भेद करना चाहिए। खेती की उपज बढ़ाने की समस्या तात्कालिक समस्या से कम बठिन थी। उसके लिए केन्द्रीय सरकार की ओर से ज्यादा सक्रिय ब्रदम की जरूरत थी तात्कालिक समस्या वितरण की थी जिसमें राज्यों सहयोग की आवश्यकता थी। इन सबध में जो फैसले किए गए वे राज्या की सहमति से और उ ही की सस्था राष्ट्रीय खाद्य बौमिल द्वारा हुए, जिसमे सभी राज्या के मुग्य मंत्री और केन्द्रीय वित्त, पाद्य और याजना मंत्री सदस्य थे और प्रधान मंत्री अध्यक्ष।

जभी अनेक प्रश्न हल नहीं हुए। राज्यों के स्वायत्त इसमें आडे आत हैं। उदाहरण के लिए अधिकतर मुख्यमंत्री खाद्य क्षेत्र की प्रणाली को खतम करने को तैयार नहीं हैं। इस प्रणाली में एक राज्य या एक क्षेत्र से दूसरे में जन्त नहीं ले जाया जा सकता। इससे मूल्य और वितरण की ठीक नीति निधारित करने में बाधा होती है। १९६४-६६ के सूखे के समय (किंतु १९६६-६७ में नहीं) यह कहा गया कि क्षेत्रीय प्रणाली भी खाद्य संकट का एक कारण है। सरकार द्वारा जन्त की खरीद के लिए ऊँचा दाम देने का भी विरोध उन दला द्वारा किया गया जो शहरवाला को सस्ता जन्त दिताना चाहते थे। इसी तरह उबरक और मिर्चाई की याजनाओं के बारे में भी सरकार असमजस में पड़ी है। कारखाने निजी क्षेत्र में हो या सरकारी क्षेत्र में, इस विवाद के कारण उबरक उत्पादन और जायात की याजनाएँ खटाई में पड़ी हैं।

परंतु खतरा इस बात का है कि खेती में मिनी इस सफलता से आश्वस्त होकर भविष्य में उठने वाली कठिनाइयाँ की उपेक्षा कर दी जाय।<sup>६</sup> दूसरी आशंका यह है कि खेती पर अधिक ध्यान देने में उद्योगों की अपेक्षा हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो इससे खेती के लिए आवश्यक सामान की सप्लाई में भी बाधा पड़ सकती है।<sup>७</sup> १९६६ में बड़े ढोल-ढमाके से बँका का जो राष्ट्रीयकरण किया गया, उसका उद्देश्य भी किसानों और छोटे दूकानदारों का मदद देना अधिक है, बजाय उद्योगों में बचत का धन लगाना। संकट से सबक लेने की जो क्रिया शुरू हुई थी, वह अभी भी जारी है और आता है कि उससे अनेक ब्रुटियाँ दूर हो जाएंगी पर नीति और अमल के सभी क्षेत्रों में ऐसा सुधार होगा यह नहीं कहा जा सकता। फिर भी आर्थिक

६ देखिए-क्याकेश माफ़ 'ग्लानिंग फार फेल्वीर इन एथिकल्स' इकनामिज ऐंड पोलिटिकल थान्ग बाधिफ अफ जून १९६८।

७ मम्म एफ मिलिकन ने यह आशंका प्रकट की है- 'इंडिया इन ट्रांजिशन इकनामिक डेवलपमेंट-परफार्मेंस ऐंड प्रोस्पेक्ट्स फारेन अपेयस, ४६, न ३ अप्रैल १९६८।

नीति में मोटे तौर पर जो परिवर्तन हुआ है, वह शुभ है। हा सक्ता है कि भारत की सरकार फिर सुस्त पड़ जाए और फिर सक्ट पड़े। यदि ऐसा होगा, तो इससे देश में फिर सजगता आएगी। यहां हम विदेशी मुद्रा और विदेशी सहायता की कमी जैसी बाहरी बाधा पर विचार नहीं कर रहे हैं। यह अगले अध्याय का विषय है।

### न्याययुक्त वितरण

आर्थिक विकास सबकी नीति पर विचार करने के बाद अब हम महत्व के प्रश्न पर आते हैं कि किसको क्या मिला। इस प्रश्न के भी दो पहलू हैं। एक तो यह कि स्वयं नेतावग का यह लक्ष्य है कि वितरण न्याययुक्त हो अर्थात् विकास का लाभ गरीब तबके को मिले। दूसरा पहलू है विकास के लाभ के विषम वितरण के कारण वंचित और गरीब तबके का असंतोष और उसकी इस लाभ में उचित हिस्सा बटाने की मांग।

भारत में वितरण का प्रश्न 'गांव बनाम शहर' का सवाल बन गया है। जय बहुत से प्रश्न - बेकारी, जनसंख्या का दबाव, मूल्यनीति, करनीति, यहां तक कि शिक्षानीति भी इसी दृष्टिकोण से देखे जाते हैं। गांव में भी विभिन्न वर्गों में जो विषमता है उसकी भी उपेक्षा कर दी गयी है। राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर कांग्रेस के अनेक प्रस्तावों और संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत, सब में गांवों की उन्नति, और जागृति पर खास जार दिया गया है। योजनाओं में साधारण और भारी उद्योगों के विकास के कार्यक्रम शुरू किए जाने के बाद 'ग्रामीत्यान' पर जोर कम नहीं हुआ।

जैसा कि आम तौर पर होता है, भारत में भी योजना में औद्योगीकरण और श्रमिक शक्ति को खेती से हटा कर शहरों में (उद्योगों में) लगाने का कार्यक्रम बनाया गया। यह उचित भी था, क्योंकि भूमि या खेती पर भार बहुत हो गया था और खेती के बजाय उद्योगधंधा में श्रम और साधन लगाने से ज्यादा और जल्दी लाभ मिलता है। परंतु जनगणना से पता चलता है कि जनशक्ति को खेती के बजाय उद्योगों में लगाने का लक्ष्य सफल न हो सका। १९५१ और १९६१ दोनों बार की गणना में खेती में ७२ प्र.श. जनसंख्या लगी थी (यदि केवल पुरुषों को लें तो अनुपात कुछ घटा, अर्थात् ६९ प्र.श. से ६८ प्र.श. हो गया।) पूंजी की भी यही स्थिति रही। १९५०-५१ में देश की ४० प्र.श. उत्पादक संपदा खेती में लगी थी और १९६०-६१ में भी यही स्थिति थी, जबकि राष्ट्रीय आय में खेती की आय का अंश ४९ प्र.श. से घटकर ४६ प्र.श. हो गया। यह कमी भी खेती की गिरावट का द्योतक है। इस प्रकार श्रमशक्ति, आय और पूंजी के खेती से उद्योग में जाने की आशा पूरी नहीं हुई (स्मरण रह कि प्रतिशत न बढ़ने पर भी कल-

कारवानों में लगे श्रमिका की सख्या और उनमें बनने वाले माल में बहुत वृद्धि हुई)।

**गावा की अधिक**

शुरू से ही सरकार गावा में ज्यादा धन लगा रही है। १९५१-६१ के दशक में गावों से कर की आय ८० प्र श बढ़ी, लेकिन उसी दशक में करो से प्राप्त आय जो गावा में लगायी गयी, १८० प्र श बढ़ी। मूल्यवृद्धि और रहन सहन के सूचक अब का हिसाब लगाने के बाद गाव में लगी करो से प्राप्त शुद्ध आय में १५० प्र श की वृद्धि हुई। दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों से करो से जितनी आय हुई, उससे कम उनमें खर्च किया गया। इन दोनों वर्षों में यह रकम २०० करोड़ रही। योजना के परिव्यय के हिसाब से भी प्रथम दो योजनाओं में ४५ प्र श और तीसरी योजना में ४० प्र श गावा में व्यय हुआ।<sup>८</sup> इस प्रकार यद्यपि सब मिला कर खेती पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया (पहली योजना को छोड़कर) परंतु अब क्षेत्रों पर गावों में काफी रुपया खर्च किया गया।

दूसरी ओर कल-कारखानों और खेती से इतर क्षेत्रों में उत्पादकता अधिक होने के कारण बढ़ती हुई राष्ट्रीय आय का ज्यादा लाभ, प्रति व्यक्ति और प्रति काम गार शहरों में ज्यादा हुआ। लेकिन शहरी क्षेत्रों पर कर का बोझ भी ज्यादा रहा। सरकार कृषक वर्ग पर प्रत्यक्ष कर लगाने से हिचकती है। खेती पर प्रत्यक्ष कर, भूमिकर हा है। द्वितीय महायुद्ध के बाद से इसकी दर नहीं बढ़ायी गयी है। इस लिए इसका वास्तविक बोच काफी घट गया है। इसी बात को ध्यान में रख कर अनेक राज्या ने भूमिकर एकदम समाप्त कर दिया। अप्रत्यक्ष करों का भार भी गावों के मुकाबले शहरों पर ज्यादा है।

इधर खेती के धंधे में मुनाफा बढ़ गया है। इसलिए अब व्यवसायकुशल और साधनसंपन्न लोग भी इस में आ रहे हैं, और अच्छे बीज, खाद, सिंचाई और उन्नत औजारों व यंत्रों में रुपया लगा कर खेती को उद्योग की भांति चलाने में तत्पर हैं। पचायती राज, सहकारी संगठन और राष्ट्रीयकृत बका से ऋण आदि की सुविधाओं के कारण इस प्रवृत्ति को और बढ़ावा मिला है। पुराने राजा व जमींदार, आरकाप्रेसी नेता जो पहले शहरों में ही छाये रहते थे अब गावों में फाम बना रहे हैं।<sup>९</sup> सरकारी और फौजी अधिकारी और ऊंची जातियों के लोग अब खेती के

<sup>८</sup> इसमें नेता तथा सामाजिक सेवा, सम्पन्न संचार और पुनर्वास आदि पर व्यय शामिल है। ये आंकड़े सरकार प्रकाशनों से लिए गए हैं - जैसे - सेंसस आफ इंडिया १९६१- फाइनल पापुलेशन टोटल ( नव दिसंबर १९६२ )। तामरा योजना के परिशिष्ट ( नव दिसंबर १९६१ ) वेसिकल स्टैटिस्टिक्स रिलेटिंग टु इंडियन इकॉनमी १९५०-५१ से १९६५-६६ ( नव दिसंबर १९६६ ) तथा चान रोजन 'मिनोक्रमा पेंन' 'कनामिकु वेंच इन इंडिया' ( अक्टूबर १९६७ )।

<sup>९</sup> टामस आर मे-काफ 'हैंडलार्स विदाउट लैंड द यू पा नर्मोसाम डुडे' ( पैसि अके स १८२, १९६७ )।

आर्थिक और राजनैतिक लाभों का अनुभव कर रहे हैं। भारतीय राजनीति में सबसे नया शक्तिशाली वर्ग बड़े किसानों, 'कुलकों' का है, जो समाज के सभी वर्गों से आए हैं। ये खूब मुनाफे की खेती कर रहे हैं और राजनीति में भी प्रवेश कर रहे हैं।<sup>१०</sup> ये लोग अपना पूरा जोर इसी बात पर लगाएंगे कि खेती पर कर न लगाने और ग्रामीण क्षेत्रों को तरजीह देने की नीति जारी रहे।

इस प्रकार भारत के नेताओं की साधारण नीति यही रही है कि गांवों के विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। राजनैतिक शक्ति भी गांवों के नेताओं के हाथ में होने के कारण इसी नीति की पुष्टि हुई है। इस नीति का औचित्य भी है, क्योंकि सदियों से भारत के गांव उपेक्षित रहे हैं। दूसरे, खेती और गांवों के विकास पर ज्यादा ध्यान देने से भारत की गरीबी की समस्या सुलझाने की भी अधिक आशा है।<sup>११</sup>

### शहरीकरण की प्रवृत्ति

भारत के विकास का एक और रोचक पहलू है नगरीकरण की मद गति। यह कुछ हद तक गांवों के विकास पर अधिक ध्यान देने का परिणाम है। आलोच्य दशक में शहरों में रहने वाली जनसंख्या का अनुपात प्रायः ज्यों का त्यों रहा। १९५१ में १७.२६ प्र.श. जनसंख्या शहरों में रहती थी। १९६१ में यह १७.६७ प्र.श. थी। यद्यपि नगरों की जनसंख्या में १ करोड़ ६५ लाख की वृद्धि हुई (नगरों की पुनर्परिभाषा के फलस्वरूप यह वृद्धि २ करोड़ १२ लाख हो गयी) परन्तु कुल जनसंख्या में उसका अनुपात केवल ०.६८ प्र.श. ही बढ़ा (पुनर्परिभाषा के बाद १.७६ प्र.श.)। शहरीकरण की दर पहले दशक के मुकाबले धीमी पड़ गयी। पिछले दशक में यह २.४८ प्र.श. थी, जबकि इस दशक में यह सिर्फ ३.६ प्र.श. रही।<sup>१३</sup> जैसा कि सारणी नं. १ से पता चलेगा, १९२१ के बाद के दशकों में यह सबसे मद रही।

यह मद गति अधिकारियों की आशा के विपरीत रही और इस धारणा के भी

१०. इस वर्ग में जिस प्रकार के लोग आ रहे हैं, इसके लिए देखिए - जेनेथल पार्नर, 'यू.एस.ए. में जनसंख्या परिवर्तन' (नई दिल्ली-बल्लभ) १-४-१९६७।

११. चार्ल्स डी. लिंडब्लम, 'पोलिटिकल डेवलपमेंट्स इन इंडिया' (नई दिल्ली-बल्लभ) १-४-१९६७।

१२. आशीष बोस 'सिस्टम डेवलपमेंट्स ऑफ इंडिया इन इंडिया १९०१-१९६१' (नई दिल्ली-बल्लभ) १-४-१९६७।

१३. आशीष बोस 'सिस्टम डेवलपमेंट्स ऑफ इंडिया इन इंडिया १९०१-१९६१' (नई दिल्ली-बल्लभ) १-४-१९६७।

विपरीत कि आधुनिकीकरण के साथ नगरीकरण की दर बढ़ती है।<sup>१४</sup> १९५१-६५ के बीच भारत का तेजी से आधुनिकीकरण हुआ और शिक्षा, उद्योग व शिल्प का विकास हुआ। यद्यपि विकास के क्रम में शहरों में काम करने वाले श्रमिका की संख्यावृद्धि स्वाभाविक थी, किंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि जनसंख्या की गति गावों से शहरों की ओर है।<sup>१५</sup> ऐसा प्रतीत होता है कि खेती के धंधे में लाभ बढ़ने से, गावा के आधुनिकीकरण से और राजनीति के विकेंद्रीकरण से नगरीकरण की गति मद रही। (सारणी नौ-१)

नगरों की जनसंख्या बढ़ने में दो कारण होते हैं। एक प्राकृतिक वृद्धि, दूसरा गावा से नगरों में आगमन। सारणी नौ २ और ३ में इस दशक में गावों से नगरों में आगमन का विवरण है। सारणी नौ २ से पता चलेगा कि बहुत कम खेतिहर या किसान नगरों में आए (आकड़े बड़े नगरों के हैं, पर छोटे नगरों में भी स्थिति यही थी)। सारणी नौ ३ से इस धारणा का खंडन होता है कि जहाँ जनसंख्या का घनत्व ज्यादा होता है, वही से सबसे ज्यादा लोग नगरों में आते हैं। इसके विपरीत देखने में यह आया कि उन्हीं क्षेत्रों से ज्यादा लोग नगरों में आए जहाँ आबादी कम घनी थी (मद्रास, पश्चिम बंगाल और राजस्थान इसके अपवाद हैं)।<sup>१६</sup>

इस पक्ष में दो बातें ध्यान योग्य हैं। एक तो जैसा आशीश बास ने कहा है भारत में आबाजाही गयी रहती है, लोग शहरों को जाते हैं और फिर गाव लौट जाते हैं। जबकि १९५१-६१ के दशक में शुद्ध आगमन या प्रवास ६० लाख रहा,

१४ यह धारणा इतनी दृढ़मूल है कि जब भारत में इससे विपरीत प्रवृत्ति साख पड़ी तो फ्रिंस ले वेविस ने इसका कारण यह बताया कि यहाँ आर्थिक विकास की गति अपेक्षाकृत मंद रहा। फ्रिंस ले वेविस, 'अर्बनाइजेशन इन इंडिया पास्ट ऐंड फ्यूचर' (नवंबर १९६२) "सक विपरीत देखें, आशीश बास 'अर्बनाइजेशन इन एस आफ रैपिड पापुलेशन ग्रोथ एंड सरप्लस लेबर इन एस आफ इंडिया', इंडियन पापुलेशन बुलेटिन न ३-१९६४।

१५ बड़े नगरों में नगरीकरण ज्यादा तेज रहा (प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी अर्थात् २० ००० से ज्यादा आबादी वाले नगर) "नर्मै वृद्धि ४२.२ प्र स रही (१५७८ दशक में ५७.६ प्र स)। मध्यम आर छोटे नगरों में ७.२ प्र स की कमी हुई (जबकि पिछले दशक में २०.४ प्र स की वृद्धि हुई थी)। इसमें पता चलता है कि बड़े औद्योगिक नगरों में वृद्धि अधिक होता है और गावों का पत्र अभि भी कम तेज नहीं हुई।

१६ सबसे ज्यादा चम्पान देहात से देहात की ह्रा होता है। १९०१ से १९६१ के बीच २७.५१ प्र स देहात से देहात में गए १३.७१ प्र स शहर से शहर की ६.१० प्र स शहर से देहात और केवल ५.४६ प्र स देहात से शहर में गए। ध्यान रहे कि गाव में गमन ज्यादातर व्यावृत्ता स्थलों का होता है। सेंसस आफ इंडिया १९६१, भाग २ सा माइग्रेशन टेबुल न दि १९६७ तथा - इन्सल माइग्रेशन इन इंडिया (एन एम एस रिपोर्ट न ५३, १९७३)।

वष प्रतिवष गिाती २४० लाख पहुँच जाती है। दूसरी बात यह है कि यहा गमन गावा से शहरा का गही, बलि छोटे नगरा या बस्त्रा से बडे नगरा का होना है।

अत में एा बात यह भी ध्यान योग्य है कि जहाँ १९५१-६१ के बीच गावा की जनगणना २० प्र श बडी, वहा ऐती करने वाला की ४३ प्र श बडी। सन १९५१ म वृषका का प्र ग ७४४० था जत्रवि १९६१ में ७६४४ प्र ग हा गया।<sup>१०</sup> इस प्रकार नगर देहात अनुपात में एक स्थिरता रही। यह प्रवृत्ति ऐसे समय रही, जब राजनैतिक शक्ति शहरा से निक्कन कर गावा में जा रही है।<sup>१८</sup> (सारणी नो-२ और नो-३)।

मगर इस स्थिति में भी अन्तरे हैं। शहरा में जनसंख्या की स्वाभाविक वृद्धि के कारण गावा के लोगो को उनमें स्थान मिलना कठिन हो जाता है। इसके फल स्वरूप गावा में भूमि पर भार बढ जाएगा और विपमता और सघष पैदा होगा। दूसरी ओर शहरा में विशेषकर शिक्षित वर्ग में बेकारी बढेगी। इससे शहर और गाव के बेरोजगार और विपन्न वर्गों का समुक्त मोरचा बन सकता है और वर्ग-सघष की स्थिति उत्पन्न हा सकती है।

### क्षेत्र के अंदर विपमता

वृषक वर्ग में भी व्यापक विपमता है।<sup>११</sup> यह सही है कि जमींदारी के उन्मूलन और भूमि सुधार के कारण, सामंती वर्ग के हाथ से अधिकार छिने हैं और जमीन विमाना के स्वामित्व में गयी है। १९६१ की जनगणना के अनुसार ७७ प्र श वृषक परिवार अपनी जमीन के मालिक थे, ८ प्र श पक्के शिकमी थे और १५ प्र श मिश्रित वर्ग के शिकमी या दर शिकमी। लेकिन कांग्रेस को बडे किसानों के समर्थन की जरूरत थी इसलिए भूमि सुधार (जोत की सीमाबंदी, भूमिहीनों को जमीन वितरण) ठीक ढंग से लागू नहीं किए गए, और विकास काय का लाभ भी बडे और धनी किसानों को ज्यादा मिला। रिजर्व बैंक की एक पडताल से पता

१७ जनगणना और योजना कमिशन के अलावा भारत के बदलने हुए यावसाधिक दांचे के और कई अध्ययन हुए। इनके सारांश के लिए देखें-ने वृत्तमूर्ति 'सेकुलर नेजिज इन आकुरेशनल स्ट्रक्चर आफ द इंडि यूनियन १९०१-६१ (द इंडि इक पैप सोशल हिस्ट्री रिव्यू, दो-स १, जन १०६५)।

१८ देहात के अतगत १०० आदमियों से लेकर १००० तक की आबादी के गांव आ जाते हैं। ये गांव जिलों में वर्गीकृत होते हैं और ये जिले राजनैतिक सत्ता और आर्थिक शक्ति के तथा अनेक प्रकार का प्रशासनिक सुविधा के केंद्र होते हैं। नगर या कस्बे में भी देशान के अनेक तत्व होते हैं। नगरी और देहाता क्षेत्रों में सत्ताबेद जिले के मुख्यालय और राज्य की राजधानियाँ होता हैं।

१९ देखें-पी सी जोशा 'फार्स पैप फू-द प्राक्लम' सेमिनार स ८१, मर १९६६ तथा रिजर्व बैंक और योजना कमिशन के मूल्यांकन संगठन की रिपोर्टें।

चलता है कि २५ प्र श सबसे धनी किसानों के पास ७५ प्र श जमीन है। इन धनी किसानों ने ही विकास कार्यों से सबसे अधिक लाभ उठाया है।<sup>१०</sup> अनेक पड़ताल से पता चला है कि अपने प्रभाव, शिक्षा और प्रवृत्तिलता के कारण इसी वर्ग का विकास सहकारियों से सबसे अधिक गूढ़ मिला और इसी ने कृषि विस्तार सेवा आर सामुदायिक विकास कार्यक्रम से भी सबसे अधिक लाभ उठाया।<sup>११</sup> इधर उपज बढ़ाने के लिए जो वनानिक साधन, सिंचाई उपकरण, बीज आदि खेती में लगाए गए, वे भी अधिकांश इसी वर्ग को मिले। खेती की पैदावार के मूल्य को ऊंचा रखने और सरकारी खरीद की नीति से भी इसी वर्ग को ज्यादा लाभ है।

ध्यान रहे कि जब तक समाज में यह भावना रहती है कि बड़े लोग या बड़ी जाति हमेशा बड़ी रहगी और छोटी जाति छोटी, तब तक असतोष बना रहता है। लेकिन जब एक बार छोटी समष्टी जानेवाली जाति या वर्ग के लोग सरकारी विकास कार्यक्रम और जमींदारी उन्मूलन आदि कारवाइयों का फायदा उठा कर ऊंचे चढ़ जाते हैं, तब जीरा की आकांक्षा भी जागती है और संघर्ष पैदा होता है।<sup>१२</sup> यदि संपन्नता से छोटे किसानों और भूमिहीनों को भी लाभ नहीं पहुँचता तो सामाजिक और राजनीतिक विक्षोभ की स्थिति पैदा होगी। १९६६ में केन्द्रीय गृहमन्त्रालय की एक विशेष रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गई कि उपजाऊ क्षेत्रों में भूस्वामी लोग बटाईदारों को हटाकर उनकी जगह खेत मजदूरों को रोजाता मजदूरी पर रख रहे हैं। इससे गाँवों में बेरोजगारी और असतोष बढ़ रहा है। इस प्रकार दुनियादी भूमि सुधार न हुए तो हरी क्रांति से विपन्नता और बढ़ेगी। कहा जा सकता है कि विकास के साथ विपन्नता ज़रूर बढ़ती ही है।<sup>१३</sup> लेकिन विप-

२० यह पड़ताल था - बाल इंडिया डेट एंड इनवेस्टमेंट सर्वे - रिजर्व बैंक बुले जून ६५ और अक्टू १९६६। हर राज्य में भी अनुरूप था। वितरण की विपन्नता सबसे कम था लम्फुशमोर में, ०.४८ प्र श आर सबसे ज्यादा था आंध्र में, ०.७३ प्र श। भूमि सुधार और आर्थिक विकास के संघर्ष के विश्लेषण के लिए देख, राजदृष्टि का लेख - 'सम ऐस्पेक्ट्स आफ रैड रिकॉम एन्ड्र डेव आफ इंडिया - वास्टर प्रोविंस संपादित - लैंड टेन्पोर, इन्स्टिट्यूटल इन्शेन पेंड सोशल स्ट्रैटेजिज एक्मपारिपस पेंड प्रारैक्त्स इन एशिया' (मिलवाबी १९६१)।

२१ रिजर्व बैंक क्रेडिट फालोअप सर्वे, १९५८-१९५९ (वर्ष १९६१)। एन सी डूवे - 'इन्डियन चर्चिंग विजेजिन' (द्वारा १९५८)। डी और ए थानर - 'लैंड ऐंड लेबर इन इंडिया' (वर्ष १९६२)। डा के एन राज सम फाचम आफ द रन मोथ आफ द लास्ट डिपेंड इन इंडिया - द इक वास्ला १३, एनुअल नंबर १९६१।

२२ खेती में मुनाफा होने देकर हर वर्ग के लोग - व्यापारी, मजदूर, रिटायर्ड शासन और फार्म अधिकारियों ने इसमें प्रवेश किया है। कुछ तो काफी नाची जाति के हैं, जिनसे वे इन्ध्या के पात्र बने हैं।

२३ अल्बर्ट ओ हर्शमैन - 'स्ट्रेटजी आफ इकनामिक डेवलपमेंट'।



मना उहुत बड़ेगी तो न केवल इससे विकास रहेगा बल्कि राजनैतिक विक्षोभ और अस्थिरता भी बढ़ सकती है ।

यदि हम गावा के लोगो का बड़े और मध्यम श्रेणी के किसान, छोटे किसान और भूमिहीन ( जिनमें मजदूर भी है ) में बांट तो पहले वग को ऊपर बताया गए कारणों से सबसे ज्यादा लाभ हुआ । दूसरे वग का भी भूमिसुधार और खेती के विकास की योजनाओं से लाभ हुआ । १९६१ की जनगणना के अनुसार किसानों की संख्या में ४३ प्र० श० की जो वृद्धि हुई, उसका कारण भूमिसुधार, विशेषकर जाति की सीमा बाधना है । यद्यपि इन सुधारों पर अमल में काफी ढील दी गई । १९५०-५१ में १९५६-५७ में हुई दा जाचा में पता चला कि यद्यपि खेत - मजदूरों की आम हालत में सुधार नहीं हुआ, किंतु सरिया घट गई ।<sup>२४</sup> ऐसा जान पड़ता है कि इन मजदूरों में जो कुछ अच्छे थे ( जिनके पास कुछ जमीन थी ) वे कुछ और जमीन प्राप्त करके किसान बन गए । १९६१ की जनगणना में पता चलता है कि खेत-मजदूरों की संख्या बढ़ने के बावजूद उसमें तुलनात्मक ह्रास हुआ है । जब कि गावों की जनसंख्या करीब २० प्र० श० और कृषकों की ४३ प्र० श० बढ़ी, खेत मजदूरों का प्र० श० २० से घट कर १७ हो गया । पंजाब, गुजरात और आंध्र ऐसी संपन्न खेती के इलाकों में तो खेत मजदूरों की संख्या घट गई, खास कर बटाई आदि के समय । चूंकि आधुनिक तरीकों के कारण खेती की उपज बढ़ी है इसलिए भूमिहीनों बटाई पर खेती कराने के बजाय छुट्टा मजदूर रख कर खेती कराते हैं, इससे गावा की सबसे नीची जातियों का कुछ फायदा हुआ है ।

लेकिन जनसंख्या बढ़ने के कारण, मजदूरों चाहने वालों की संख्या भी बढ़ी और खेत मजदूरों की मजदूरी या अन्य फायदों में कोई इजाफा नहीं हुआ । खेत मजदूरों में बढ़ी जाचा से पता हुआ कि उनकी आमदनी १० प्र० श० घट गई है । यद्यपि ये आंकड़े सरासरी के नहीं हैं फिर भी इसमें संदेह नहीं की खेत मजदूरों की हालत खस्ता है ।<sup>२५</sup> महत्त्व की बात यह है कि इनमें से कुछ की हालत सुधरी है इसलिए दूसरों की आकांक्षाएं जगी हैं । खेत मजदूरों ने निवृत्त का वग <sup>२६</sup>, छोटे किसानों का । उनकी हालत भी सुधरी है और इज्जत बढ़ी है । जाति का यह मुनिष्ठ सिद्धान्त है कि जब तक कोई वग लगातार कष्ट में रहता है, जिससे उठने की कोई आशा नहीं दीखती तब तक वह जाति के लिए उद्यत नहीं होना । जाति की चिन्ता तब सुलगती है, जब उसे उन्नति की आशा और संभावना दीख जाती

<sup>२४</sup> रिपोर्ट ऑन द मेकैन्स एंडि लैबर एनक्वायरी १९५६-५७ ( शिमला १९६० ) । विभिन्न कृषक वर्गों के लाभ क्षति की तुलना के लिए देखें आन रोडन, पूर्वोक्त, पृ १६५-१७२ ।

<sup>२५</sup> देखें- डा० वि० क० राव संपादित ' एंडि लैबर इन इंडिया ( वर्ष १९६५ ) में ' न्याय और दाय के धन राज के लिये और ही तथा ५ मार्च ७३ में ' रेवेन्यू इंडिया ' ।

है। २६ अगले १०-१५ वर्षों में सम्भवतः भारत के गांवों में परिवर्तन की भाग तेज होगी। धनी किसानों को बटाईद्वारा तथा खेत मजदूरों को दोनों से संपर्क करना होगा यद्यपि कभी कभी बटाईदार और मजदूर वर्गों में भी विरोध हो सकता है। तब ही सकता है कि भूमि सुधार और खेती की आय पर कर लगाने की जो याजनाएँ सरकारी दफ्तरों में घूल खा रही हैं अमल में लाई जाएं।

सारांश यह है कि शुरू में जब नई जमीन तोड़ी जाती है और भूमिसुधार द्वारा खेती करने वालों का मालिकाना हक दिया जाता है तब पैदावार बढ़ती है। उत्पादन की गति वृद्धि नए तरीकों पर और ऋण आदि की सुविधाओं पर निर्भर होती है जिसके लिए राजनैतिका और सरकारी नौकरों तक पहुंच सहायक होनी है, इस कारण उच्चवर्ग या बड़े लोग सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं, और आर्थिक विकास के साथ साथ विषमता बढ़ती है। इनमें उत्पादन और वितरण दोनों पर बुरा असर पड़ता है। इसे दूर करने के लिए ऊपर के नेता पंचायती राज आदि संस्थाओं को शुरू करके के दहाती जनता को उत्साहित करने और लाभ का भागीदार बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें विफलता होने पर सरकार के विरुद्ध असंतोष बढ़ता है और चुनाव में सरकारी दल की हार होती है। इसके कारण आमूल परिवर्तन के लिए राजनैतिक दबाव बढ़ता है।

परंतु वर्तमान व्यवस्था के प्रति गांववालों का आम विरोध सभावित नहीं। क्योंकि पैदावार के मुकाबले खपत और मांग बढ़ने के कारण अभी कई वर्षों तक अनाज के भाव ऊंचे बने रहेंगे। जनसंख्या की वृद्धि और विदेशों से आने का आयात घटने के कारण भी भाव ऊंचे बने रहेंगे। शहरवालों की गति से समस्त अनाज की मांग उठेगी, लेकिन गांववालों के राजनैतिक जोर के कारण इसका माने जाने की आशा नहीं। इसलिए खतरा यह नहीं है कि गांववालों को सरकार की व्यवस्था से असंतोष हो, बल्कि यह है कि गांवों में ही वगमगम की तीव्रता आ जाए। (नक्सलवादियों का जादोलन इसी प्रवृत्ति का द्योतक है।)

शहरों की स्थिति भी ठीक तौर पर यह है। कंपनी और कारखाने वालों का मुनाफा बढ़ा है। कारखानों में काम करने वालों का वास्तविक वतन भी बढ़ा है। निजी क्षेत्र के ऊंची श्रेणी के कमचारियों की असल आमदनी भी बढ़ी है, और ऐसे पदा की संख्या भी बढ़ रही है। दूसरे वर्ग के कमचारियों की आमदनी तो नहीं बढ़ी लेकिन जगहें बढ़ी हैं। थोके और खुदरा व्यापारियों की आमदनी भी बढ़ी है। दूसरी ओर ऊंची और निचली श्रेणी के सरकारी नौकरों की वास्तविक

---

२६ अर्थशास्त्र में टाकविल ने काम की राजस्वता पर अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में लिखा है कि सदियों तक यह माना रहने पर भी लोगों ने अनुभव नहीं किया कि जिस व्यवस्था में वे पिस रहे हैं वह निरर्थक अत्याचारी है। उन्होंने यह अनुभव तब किया जब आर्थिक उन्नति होने लगी। यही बात अब देशों में भी दाय पड़ी।

आय घटी है। सरकारी प्रतिष्ठानों के श्रमिका का आमदनी में घट-उठ नहीं हुई, क्योंकि वेतन कमिशन की सिफारिश के अनुसार इनका महगाई के साथ उसका मुआवजा बढ़ता जाता है। इनकी सख्या भी काफी बढ़ी है। सामयिक सचिव कण्ट विश्वविद्यालय कालेज और स्कूलों के अध्यापकों को है, यद्यपि इनकी सख्या में भी बहुत वृद्धि हुई है।

निम्न मध्यम श्रेणी की नौकरियों में लगातार बढ़ती विकास का एक ठाम लाभ है। लेकिन दूसरी ओर यह वर्ग मेहनतमजदूरी करने वाले वर्ग के निकट जाता जा रहा है और ऊपर के वर्गसे इसकी दूरी बढ़ती जा रही है। इस प्रकार निम्न मध्यम वर्ग नीचे और ऊंचे दोनों वर्गों की तुलना में घाट में रहा। ऊंची आय वाले वर्ग में यह इष्पा करता है और उसके मुकाबले नीचे जा रहा है। दूसरी ओर यह निचले वर्ग के स्तर पर जा रहा है जिससे यह ऊपर रहना चाहता है। सहरो में सबसे अधिक असंतोष इसी वर्ग में है। तरह-बादिक श्रेणियाँ और मरकागी तीसरा की मान भयादि में भी काफी घटी हुई है और उनमें भी क्षोभ और विरोध है। इस प्रकार भारत में कारखाने के मजदूरों की ओर से वर्गसंघर्ष का स्तर कम है और निम्न मध्यम वर्ग की ओर से अधिक, इसके साथ असन्तुष्ट बौद्धिक वर्ग भी हो गया है।

### बेरोजगारी की समस्या

बढ़ती हुई बेरोजगारी की दखते हुए, खासकर गहरा में विहित बेरोजगारी की बढ़ती सख्या की इस प्रकार के मोरचे की संभावना और बढ़ गयी है। सरकारी अनुमान के अनुसार १९५१-१९६१ के बीच श्रमिक सख्या में २१० लाख की वृद्धि हुई, जबकि बेरोजगार लोगो की सख्या में केवल १७० लाख की वृद्धि हुई। द्वितीय योजना के अंत तक अनुमान है कि बेरोजगारों की सख्या ७० लाख थी। तीसरी योजना में काम करने योग्य लोगो की सख्या में १७५ लाख की बढ़ती हुई जबकि काम में नये लोगो की सख्या केवल १४५ लाख बढ़ी। इस प्रकार तीसरी योजना के अंत तक १०० लाख लोगो का काम नहीं मिल गया था, जिनमें २५ लाख शहरी में थे। ३० (कुछ लोगो का ग्यान है कि बेरोजगारी की सख्या और अधिक, १५० लाख थी) अनुमान है कि चौथी योजना के अंत तक बेरोजगारों की सख्या १४० लाख (सरकारी अनुमान) से २०० लाख के बीच हो जाएगी। बेरोजगारी में इस वृद्धि का कारण कुछ तो जनसंख्या की अत्यधिक बढ़ती है कुछ अवस्था का स्थावली बनने के लिए पूंजीगत संपत्ति बढ़ाने का आर्थिक

२७ बेरोजगारों की समस्या के अन्तर्गत १००-१०० लाख घेमे द, जिनका पूरा काम नहीं मिला है।

नीति है, और कुछ बच्चे माल की कमी आदि के कारण स्थापित उत्पादनक्षमता का पूरा काम न करना है।

रोजगार बढ़ाने के तीन उपाय हो सकते हैं — एक, पूँजी — धन अनुपात को घटा देना, दूसरा, कारखानों में ज्यादा आदमियाँ को रखना और तीसरा, बेकारक्षमता का पूरा उपयोग करना। पहला कठिन है क्योंकि इस समय पूँजी का नियोजन कुछ खास आर्थिक और प्रौद्योगिक लक्ष्य का सिद्ध करने के लिए हो रहा है। दूसरे उपाय से धन की उत्पादकता घटेगी। १९५१-६१ में उत्पादनवृद्धि का ६५ प्रतिशत धनिका की उत्पादकता बढ़ने से आया और ३५ प्रतिशत धनिका की सख्या बढ़ाने से। इसलिए एक सन्ता यही रह जाता है कि वर्तमान उद्योग पूरी क्षमता से काम करे। इसके लिए विदेशों से जरूरी पूँजी और सामान मंगाना होगा, और यह तभी हो सकता है जब निर्मात की जाय बड़े। यद्यपि बेरोजगारी की समस्या विशाल है, पर देश के आयाजकों ने सीधेता से उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने को प्राथमिकता दी है, और उन्हें आशा है कि इससे रोजगार भी बढ़ेगा। २८ इस बीच गाँवों में सावजनिक निर्माण के काम चालू करके कुछ हद तक बेरोजगारों को काम देने की कोशिश की जा रही है।

इधर हाल में इंदिरा गांधी ने आर्थिक नीति को राजनैतिक रुख दिया है और गरीबी तथा विपन्नता घटाने की समस्या पर जोर दिया है। इससे शहरों में बारी-बारी और शिल्पियों की तथा गाँवों में बटाईदारा और भूमिहीन मजदूरों की बेरोजगारी और अथ — बेकारी दूर होने में कुछ मदद मिलेगी।

भारत की अशिक्षित जनता में कष्ट सहने की बेहद क्षमता है। यहाँ परिवार और नाते रिश्तेदार भी बेकार की मदद करते हैं। बहुत से ग्रामीण मजदूर बीच-बीच में काम मिल जाने से और निर्वाहयोग्य मजदूरी मिलने से ही सन्तोष कर लेते हैं, इसलिए यहाँ सामाजिक विस्फोट नहीं हुआ। पर वास्तविक तत्तरा शहरों में शिक्षित बेरोजगारों से है। मगर शिक्षितों को काम देने का प्रबंध नहीं हो पा रहा है। सारणी नौ-४ से पता चलेगा कि अनेक राज्यों में बेरोजगार शिक्षिता की सख्या अशिक्षिता और कम शिक्षितों से ज्यादा है। उदाहरण के लिए पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरल और दिल्ली जैसे अधिक उन्नत क्षेत्रों में। गुजरात और

---

२८ आय और संपत्ति की विधमता की जाँच करने के लिए भारत सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की थी। पर इसका रिपोर्ट से इस समस्या पर कोई खास प्रकाश नहीं पड़ा, क्योंकि कमेटी की आवश्यक आंकड़े नहीं मिल पाए। इसलिए हमने इस प्रश्न पर यहाँ विचार नहीं किया है। 'हमके निष्ठा हमें यह समस्या राजनैतिक दृष्टि से ज्यादा महत्त्व की नहीं प्रतीत हुई। फिर भी देखें — रिपोर्ट आफ द कमेटी ऑन टिस्ट्रीब्यूशन आफ इनकम ऐंड वेल्थ आफ लिविंग' (महाल नवीस कमेटी रिपोर्ट) दिल्ली १९६४ तथा आर के हजारी - द 'स्ट्रक्चर आफ कार्पोरेट प्रा सेक्टर' (बदई - न्यूयार्क, १९६६)।



अधिकांश लोग पन्द्रह से चौतीस वष की आयु के होते हैं (सारणी नौ-६) इसके साथ ही यह ध्यान में रहे कि सबसे ज्यादा बेकारी कम आयु के लोगो में है (सारणी नौ-७)। इससे पता चलता है कि नई पीढ़ी का अस तोय राजनीति पर गहरा प्रभाव डालेगा। हमने देखा है कि भारत में पश्चिम की तरह नई पीढ़ी अपने बड़े-बूढ़ों का निरादर नहीं करती। इसके अलावा भारत के नौजवान प्रस्तुत व्यवस्था को उलटने के बजाय, केवल अपने लिए काम और स्थान चाहते हैं।<sup>२९</sup> खेती में लाभ बढ़ने के कारण हो सकता है कि बहुत से नौजवान शहरों में काम तलाशने के बजाय खेती में लग जायें। यह भी प्रतीत होता है कि स्वतंत्रता के बाद जमीनी पीढ़ी ज्यादा यथार्थवादी है, बजाय पहले की पीढ़ी के जिनका लालन पालन लम्बे चौड़े आदर्श और सिद्धांत के बीच हुआ था।<sup>३०</sup>

मगर यह याद रहे कि आजकल की शिक्षा और अखबार, किताब, फिल्म और रेडियो आदि पुगने मूल्यों की जड़ काट रहे हैं। नई पीढ़ी ज्यादा व्यावहारिक और यथार्थवादी है इसका अर्थ यह भी है कि उसे खयाली पुलावों से बहनाया नहीं जा सकता और वह ठोस चीजें चाहती है — नौकरी और अच्छी आमदनी। यदि इस वग की आशाएं पूरी न हुई तो इसका क्षोभ वर्तमान व्यवस्था को बढ़ा सकता है। इसलिए अधिक से अधिक आदमियों के लिए रोजगार या काम के लिए साधन प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है।

इहीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जनसंख्या की वृद्धि का नियंत्रण करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर परिवार नियोजन का कार्य चलाया है। इसका उद्देश्य जनसंख्या की वृद्धि की दर को चालीस प्रति हजार से घटाकर पचीस प्रति हजार करना है। इस कार्यक्रम के लिए तीसरी योजना में सत्ताईस करोड़ रुपये खर्चे रखे गए थे जबकि चौथी योजना में ३०० करोड़ रुपये खर्चे किए गए हैं। (१) इस कार्यक्रम में लोगो में इस बात का प्रचार किया जा रहा है कि छोटा परिवार अच्छा होता है। (२) लोगो को परिवार नियोजन की विधि बताई जा रही है। (३) इसका सामान दिया जा रहा है तथा डाक्टरों की सहायता दी जा रही है। (४) परिवार नियोजन कार्य के विशेषज्ञ बड़ी संख्या में तैयार किये जा रहे हैं। पर अभी यह कार्यक्रम बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में है और इसका असर केवल शहरों

२९. नोसफ लेन्कीके ड-‘इंडियन स्टुडेंट्स डिमांड एसेस ऑन इन एस्टैब्लिशमेंट’ द न्यूयार्क टाइम्स मैगज़ीन मई १२, १९६८। इसका कहना है कि भारतीय विद्यार्थी पुरानी व्यवस्था को उलटना नहीं चाहता, वह उनमें स्थान पाना चाहता है।

३०. जोसेफ ट-नू एलंडर ने पुरानी पीढ़ी के राष्ट्रवादियों और स्वतंत्रता के बाद की पीढ़ी के देशभक्तों में अंतर किया है। देखें उनकी-‘नेशनल लायब्ररी इन ए न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन’-टविड पेंटर सभा ‘आस्ट्रियोलापा ऐंड डिमंड-टेंट’ (न्यूयार्क १९६४)।

महाराष्ट्र में उच्च शिक्षा माता की स्थिति अच्छी है पर मध्यम दर्जे की शिक्षा माता में बहुत घराबगारी है। १९११ में राजगार दरपरा में दत्त काम कहन माता की मर्यादा १८८८ में १९११ में जयकि १९६१ में छ लाख हा गई। माता की प्रार्थना कि कयाय प्राय ११ आमा हा दरपरा में ताम निशाने है। इसमा आ मा है कि १८६८ में दम माता में अधिक शिक्षा घराबगार में और बहुत मन्मा १२ में बगवत २११ हा जा रही है। ताम में रोजगार दरपरा में दत्त माता का पदता ११ मा मो जिनम पता बता कि इनमें जेद माता लग में जा व्यावसायिक मा प्रार्थना मातायत प्राय ११ मा छ ताम में अधिक हाईस्कूल पाम में और निम्नतर माता में अधिक निम्नविद्यालय की डिग्रीजारी में (दिए गए मारती नो-८)।

माता में जमाता स्थिति का पता प्रतिगन आमा स नहीं लगता। प्रतिगन का निम्नतर माता में जमाता मा का मर्यादा ११ मा जमाता मा की चार प्र० श० में अधिक ११ माता। मा स्थिति माता औद्योगिक में माती पुनता में कुरी नही है परन्तु प्र० माता माती उच्चतर माता माती है। माता की जनमर्यादा ११ आमा प्रतिगन भी पन्वीन लाग हाता है। घराबगार की बचन एक चौबार्द माता माता में रहती है। इनमें स्थिति विस्फाटक माता होने पाई। दूसरी तरफ माता में बेकारी और भीडभाड का कारण माता का माता में आकर राजगार पाता में दिवसत होती है। माता में शिक्षित घराबगार बंद और पेमाम में भाग जत है। पर अभी विराध के ये आदानन असमठित है और सरपार का गान्तिव्यक्त्या कायम रखो का प्रबन्ध भी मजबूत है। इसनिष्ठ स्थिति हाय स बाहर नहीं गई। सेती की प्रधानता, गव और माता की आडने वाली कुटुंब व्यवस्था और राजगार के अवसरा में घीमे पाम बढनी का कारण अभी हालत बहुत बुरी नही हू है। पर जत तक कि कारणानो की क्षमता का पूरा उपयोग नही होता और आर्थिक स्थिति पूरी तरह नही सुधरती स्थिति पारलोक यनी रहगा।

इधर बंका के राष्ट्रीयकरण और एकाधिकार की प्रवृत्तिया की रोक्ने तथा गरीब वग को लाभ पहुचाने की कार्यवाई की गई है उससे आर्थिक नीति में परिवर्तन की सम्भावना है। मगर निधन और वचित वग की माता को सतुष्ट करे का परिणाम यह न होना चाहिए कि निजी उद्यम का उत्साह मारा जाय। जिस हद तक सरकार प्रत्येक क्षेत्र के उन्नतिवासी लोगो को उत्तरादक कार्यों में लगा सकेगी उस हद तक आर्थिक समस्या सुलझाने में मदद मिलेगी।

स्थिति आगे क्या होगी यह बहुत कुछ नीजवान वग पर निर्भर है। सन १९६१ में ५७७ प्रतिशत जनमर्यादा चौबीस वष और उससे कम आयु की थी, ४१ प्रतिशत चौदाह साल से कम आयु की थी। इसी वष की शिक्षा का बेतहाशा विस्तार हुआ है। हर माता वष में माध्यमिक स्कूला के विद्यार्थियों की और हर छ वष में उच्चतर स्कूला के विद्यार्थियों की संख्या दूनी हो जाती है। शहर में आने वाल

अधिकांश लोग पंद्रह से चौतीस वष की आयु के होते हैं (सारणी नौ-६) इसके साथ ही यह ध्यान में रहे कि सबसे ज्यादा बेकारी कम आयु के लोगों में है (सारणी नौ-७)। इससे पता चलता है कि नई पीढ़ी का असंतोष राजनीति पर गहरा प्रभाव डालेगा। हमने देखा है कि भारत में पश्चिम की तरह नई पीढ़ी अपने बड़े-बूढ़ा का निरादर नहीं करती। इसके अलावा भारत के नौजवान प्रस्तुत व्यवस्था को उलटने के बजाय, केवल अपने लिए काम और स्थान चाहते हैं।<sup>२९</sup> खेती में लाभ बढ़ाने के कारण हो सकता है कि बहुत से नौजवान शहरों में काम तलाशने के बजाय खेती में लग जायें। यह भी प्रतीत होता है कि स्वतंत्रता के बाद जमींदारी ज्यादा यथाव्यवस्था है, बजाय पहले की पीढ़ी के जिनका लालन-पालन लम्बे-चौड़े आदर्श और सिद्धान्त के बीच हुआ था।<sup>३०</sup>

मगर यह याद रहे कि आजकल की शिक्षा और अवसर, किताबें, फिल्म और रेडियो आदि पुराने मूल्यों की जड़ काट रहे हैं। नई पीढ़ी ज्यादा व्यावहारिक और यथाव्यवस्था है इसका अर्थ यह भी है कि उसे खयाली पुलावों से बहकाया नहीं जा सकता और वह ठोस चीजें चाहती है - नौकरी और अच्छी आमदनी। यदि इस वर्ग की आशाएँ पूरी न हुई तो इसका क्षोभ वर्तमान व्यवस्था को ढहा सकता है। इसलिए अधिक से अधिक आदमियों के लिए रोजगार या काम के लिए साधन प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है।

इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जनसंख्या की वृद्धि का नियंत्रण करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर परिवार नियोजन का कार्य चलाया है। इसका उद्देश्य जनसंख्या की वृद्धि की दर को चालीस प्रति हजार से घटाकर पचीस प्रति हजार करना है। इस कार्यक्रम के लिए तीसरी योजना में सत्ताईस करोड़ रुपये खर्चे गए थे जबकि चौथी योजना में ३०० करोड़ रुपये खर्चे गए हैं। (१) इस कार्यक्रम में लोगों में इस बात का प्रचार किया जा रहा है कि छोटा परिवार अच्छा होता है। (२) लोगों को परिवार नियोजन की विधि बताई जा रही है। (३) इसका सामान दिया जा रहा है तथा डाक्टरों की सहायता दी जा रही है। (४) परिवार नियोजन कार्य के विशेषज्ञ बड़ी संख्या में तैयार किये जा रहे हैं। पर अभी यह कार्यक्रम बिल्कुल प्रारम्भिक अवस्था में है और इसका असर केवल शहरों

२९. रोमरु लेन्गफेल्ड- इंडियन स्टुडेंट्स टिमाट एसेस बाइ इन एम्प्लिशमेंट 'द न्यूयार्क टाइम्स मैगज़ीन' मई १०, १९६८। इसका कहना है कि भारतीय विद्यार्थी पुरानी व्यवस्था को खत्म नहीं चाहता, वह उसमें स्थान पाना चाहता है।

३०. रोमरु लेन्गफेल्ड ने पुरानी पीढ़ी के राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता के बाद की पीढ़ी के देशभक्तों में अंतर किया है। देखें उनकी 'नेशनल लायटीन इन द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन'-टैबिलेटेड पेपर मस 'आरनियोलॉजिस्ट' डिसेम्बर-१९६४।



में और उन जिला में पडा है जहा जोरो से काम किया गया है।<sup>३१</sup> कायक्रम की जाच पडताल से पता चला है कि अभी भी इसमें बहुत सी श्रुटिया हैं। लोगो को परिवार नियोजन की सामग्री ठीक ढंग से नहीं मिल रही है और अच्छे कायकर्ता भी कम है। राजनीतिक नेताओं से इसे उत्साहपूर्वक समर्थन भी नहीं मिला है। इसका असर देर में होगा जबकि तात्कालिक समस्या का तत्काल समाधान जरूरी है।

## शिक्षा का प्रभाव

आधुनिक युग में शिक्षा का महत्व सामाजिक और आर्थिक विकास में बहुत अधिक है। शिक्षा मनुष्य के जीवन, आकांक्षा और रख को बदल देती है। एक तरफ यह मनुष्य को सामाजिक जीवन के लिए तैयार करती है तो दूसरी तरफ यह पुरानी परम्परा पर भी प्रहार करती है। शिक्षा से जो आकांक्षाएं पैदा हो जाती हैं, वे जब सतुष्ट नहीं होती तो समाज में निराशा का वातावरण बढता है और परिवर्तन की मांग उठती है।

लोकतन्त्र की यह एक बड़ी समस्या है कि यह अपने सब लोगो को शिक्षा का मुक्त अवसर देने के लिए बचनबद्ध है। साथ ही उसे यह ध्यान भी रखना है कि विभिन्न प्रकार के व्यवसायो में जितने आदमी तय करें उससे ज्यादा न प्रशिक्षित किए जावे। लेकिन शिक्षा अच्छी नौकरी और व्यवसाय पाने का साधन है। इसी लिए हर आदमी की यह आकांक्षा होती है कि वह शिक्षा प्राप्त करे और जब शिक्षा प्राप्त करने के बाद काम नहीं मिलता तो निराशा और क्षाम बढता है। भारत में यही सब देखने में आ रहा है।

भारत की मुख्य समस्या शिक्षा का घीमा विकास नहीं, बहुत तेज विकास है। यह सही है कि अभी भी साक्षरता कम है (१९६१ में २४ प्रतिशत) परंतु १९५१ और १९६१ के बीच पढने वाले लड़का की संख्या दुगुनी और लड़कियों की तिगुनी हो गई।<sup>३२</sup> माध्यमिक और उच्चतर स्कूलों में भी हर सात और हर छ बर के बाद विद्यार्थियों की संख्या दुगुनी हो जाती है। अनुमान है कि इस गति से १९८० तक माध्यमिक स्कूलों में ८० प्र श लड़के लड़कियां दाखिल हो जायेंगे और कालेज या विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या कुल जनसंख्या की दस प्रतिशत हो जाएगी।

पढाई जारी रखने की प्रवृत्ति भी बढती जा रही। अनुमान है कि अगले दस-पंद्रह वर्षों में मिडिल कक्षाएं पास करने वाले अधिकांश विद्यार्थी ऊंची कक्षाओं में

३१ महाराष्ट्र में परिवार नियोजन कार्यक्रम में बड़ी सफलता मिली है और वह ज्यादा सताने लक्ष्मि को निरुत्साहित करने के कई उपाय सोच रहा है जैसे जिम्मे लीन से ज्यादा सगान दो उस मुक्त या सती चिकित्सा शिक्षा आदि सुविधाओं से बचित कर देना।

३२ ये सारे आंकड़े, शिक्षा बर्मीशन १९६४-६६ की रिपोर्ट से लिए गए हैं - 'एजुकेशन ऐंड नेशनल टेक्नॉलॉजी' (दिली, १९६६)।

भरती होंगे और हाईस्कूल पास करने वाले साठ प्र श विद्यार्थी कालेजों में नाम लिखाएंगे। जिन लोगों को एक श्रेणी की पढ़ाई समाप्त करने पर काम नहीं मिलता वे आगे की श्रेणी की पढ़ाई में लग जाते हैं। लड़कियों में शिक्षा के अत्यधिक प्रसार का यही कारण है। यदि निचले स्तर की शिक्षा समाप्त करने पर लड़का को रोजगार मिलने लगेगा तो उच्च शिक्षा में भीड़ कम हो सकती है। लेकिन इसके खिलाफ नियोजक वर्ग की प्रवृत्ति यह है कि वह जहाँ जरूरी नहीं है वहाँ भी उच्च शिक्षा या डीग्री वालों को रखना पसंद करता है। उसका नतीजा यह होगा कि जगले तीस वर्षों में हर स्तर पर—प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च—शिक्षा शत-प्रतिशत हो जाएगी।

शिक्षा के वैतहासा विस्तार का नतीजा यह भी हुआ है कि उसका स्तर गिरा है और उसके व्यावसायिक बनाने पर ध्यान नहीं दिया जा सका है।<sup>३३</sup> साधारण शिक्षाप्राप्त लोगों की संख्या बहुत बढ़ी है लेकिन विशेषज्ञ की अब भी कमी है। इसका एक नतीजा यह भी हुआ है कि लड़कियों की शिक्षा पर खर्चा बर्बाद हो रहा है क्योंकि बहुत कम लड़कियाँ काम-धंधा करती हैं।<sup>३४</sup>

फिर भी दो एक क्षेत्रों में विशेषज्ञों की भले ही कमी हो, साधारणतः प्रत्येक विषय में जरूरत से ज्यादा शिक्षित उपलब्ध है। शिक्षा-कमीशन ने इसलिए यह सिफारिश की है कि हाईस्कूल और कालेज में भर्ती कम की जाय। फिर भी अनुमान है कि १९८६ तक हाईस्कूल पास ४० लाख और डिग्रीधारी पंद्रह लाख विद्यार्थी फालतू होंगे। उस समय तक अनुमान है कि कालेजों में भी ७०-८० लाख विद्यार्थी होंगे जो जरूरत से दुगुने होंगे।

शिक्षा का यह विकास सही ढंग से नहीं हुआ है। सारणी नौ-८ से पता चलेगा कि १९५०-५१ में सबधित वय वर्ग के जहाँ ६५ प्र श लड़के मिडिल कक्षाओं

३३ इस विस्तार से गांव और ग्रामीण वर्ग को कम लाभ हुआ है और सबसे मेहनती व अच्छे विद्यार्थी इसी तबके के होते हैं। गांव के लड़कों को व्यावसायिक और टेक्निकल संस्थाओं में केवल ४१.४ प्र श स्थान मिलते हैं जबकि वे ८० प्र श हैं। स्त्री तरह १.१० रु से कम आय के वर्ग के छात्रों को इन संस्थाओं में केवल १०.५ प्र श स्थान मिले जबकि वे भी जन संख्या के ८० प्र श हैं।

३४ प्राइमरी में दाखिल लेने वाली लड़कियों का अनुपात प्रति १०० लड़के १९०१ में १२, १९५० में ३९ और १९६५ में ५१ हो गया। माध्यमिक स्तर पर ये आंकड़े हैं ४, १५, और २६। उच्च शिक्षा में लड़कियों की प्रगति अत्यधिक है, १९०१ में इस स्तर में केवल २६४ लड़कियाँ थीं जो १९५० में ४०,००० और १९६५ में २,४०,००० हो गई। दूसरी तरफ, शिक्षित लड़कियों को काम बहुत कम मिला। १९२१ में वैज्ञानिक और टेक्निकल धर्मचारियों की पट्टा से शान हुआ कि स्त्रियों में बेरोजगारी (३१ प्र श) पुरुषों से (८७ प्र श) बहुत अधिक है। मानविकी में यह अंतर और भी अधिक होगा क्योंकि इस पढ़ाई का उद्देश्य मुख्यतः शारीरिक काम नहीं।

11

सरकार स्थिति को समालने का उपाय कर रही है। गावों के गरीबों को ज्यादा दाखिला, व्यावसायिक और शिल्पक स्कूलों में ज्यादा भर्ती, विभिन्न प्रदर्शों और गावों और शहरों में भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा और उद्योगधंधों की आवश्यकता के मुताबिक शिक्षा। पता चला है कि किसानों के लड़के अब पढ़ कर गावों में खेती व कामकाज करने में प्रवृत्त हो रहे हैं। इस प्रवृत्ति में कृषि विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण योग रहा है। वर्तमान उद्योगों की पूरी क्षमता का उपयोग करने से भी शिक्षितों को काम मिलेगा। सामाजिक सेवाओं के विस्तार से (जिनमें गावों में स्कूलों का खुलना भी शामिल है) बहुत से निम्न मध्यम वर्ग के विद्वान् और मानविकी विद्यालयों के स्नातकों को काम मिलेगा। बड़े पैमाने पर गावों में स्थापित कार्य चालू होने से इजीनियरों का रोजगार मिलेगा। इसके अलावा बहुत से लोगों को लगन या मौसम के समय जो काम मिल जाता है, और बहुत से कामगार शहरों में थोड़े समय काम करके गावों लौट जाते हैं, तथा बर्माई और जाय परिवारों की समझी जाती है एक आदमी की नहीं इससे भी बेकारी का दबाव कुछ कम हो जाता है। फिर भी शिक्षितों की बढ़ती हुई संख्या (स्त्रियाँ भी इनमें शामिल हैं) के राजनैतिक प्रभाव की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।<sup>३६</sup>

खेद है कि अभी तक शिक्षित बेरोजगारों के राजनैतिक खतरे को नहीं समझा गया, न इस शिक्षित जनशक्ति का विकासकार्य के लिए उपयोग किया गया, न आर्थिक योजना में ऐसे परिवर्तन किए गए, जिससे बेरोजगारी घटे। विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम, अध्यापन और प्रशासन का ढांचा भी दक्षिणपूर्व की ओर चला जा रहा है। इससे नवयुवक सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में अपना स्थान लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं।

## निष्कर्ष

जिन समस्याओं पर यहाँ विचार किया गया—उद्योगों की पूरी क्षमता का उपयोग, खेती के साधन जुटाना बेरोजगारों का उपाय करना, जनसंख्या वृद्धि को रोकना, और शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को देश के विकास और परिवर्तन में लगाना—इन सबका धुंधला आभास भारत सरकार को है और वह कुछ कर भी रही है। पर बहुत ढिलाई और सुस्ती से जो योजनाएँ स्वीकृत हो चुकी हैं, उनका काम भी सुस्त है। अभी अव्यवहृत क्षमता का उपयोग की बहुत गुंजाइश है। खाली बैठे शिक्षित युवकों के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं, जिससे विकास में तेजी आ सकती है। प्रशासन को पुराने सड़े गले कार्यदो की सँद से छुड़ा कर उसमें तेजी लायी जा सकती है। विकास कार्य को चलाने वाली मशीनरी में हर

३६ शिक्षा के प्रभाव के बारे में देखें—~~अलेक्स~~ इवेलेस 'पार्टिमिपेंट मिटिजनशिप इन डेवलपिंग कंट्रीज' अमेरिका पोली माइस रिपोर्ट। इसमें भारत पर भी विचार किया गया है।

३७

मे पढते थे वहा १९६५-६६ में उनकी संख्या तिगुनी जयान १९१ प्रतिशत हा गई। मगर निचली माध्यमिक व्यावसायिक कक्षाओं में दाखिला १९५०-५१ में ३ प्र श से गिर कर १९६५-६६ में २२ प्र श हा गया। उच्चतर माध्यमिक व्यावसायिक स्कूलों में दाखिला १९५०-५१ में ४४ प्र श से घटकर १९६५-६६ में ६० प्र श हा गया। यदि शिक्षा कमीशन की यह आशा पूरी हा भी जाए कि १९८६ तक निम्न माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षा में २० प्र श और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में ५० प्र श विद्यार्थी दाखिल हागे, तब भी व्यावसायिक शिक्षा में कुल दाखिला विद्यार्थियों के पूरे दाखिले का केवल १० प्र श ही होगा, जो कि एक आधुनिक व्यवस्था के लिए बहुत कम है। पश्चिम जर्मनी में स्कूल में व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा का अनुपात ७० और ३० है, जबकि जापान में ६० और ४०। भारत में विश्वविद्यालय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का अनुपात १९६५-६६ में कुल दाखिले का २३ प्र श था जो जरूरत से कम है।

लेकिन संस्था के हिसाब से उच्च व्यावसायिक शिक्षा में भारत में उल्लेखनीय उन्नति हुई है—सन १९५०-५१ में ५६००० से १९६५-६६ में २४६००० अर्थात् १५ वर्ष में साठे चार गुनी वृद्धि। (सारणी नं-८)। परंतु समस्या यह है कि अनेक प्रकार के व्यवसाय की शिक्षा की आवश्यकता होत हुए भी, प्रशिक्षित लोगों का काम नहीं मिलता हाल में ४०,००० इंजीनियर बेकार थे। इससे विज्ञान और इंजीनियरी कालेजों में विद्यार्थियों में घबराहट पैदा हुई और उन्होंने हड़ताल व प्रदर्शन किए। कुछ ता बात यह थी कि दो वर्षों के सूखे के कारण १९६७ में उद्योगों में मंदी आई। मगर मुख्य बात यह है कि बिना यह माचे कि कितने इंजीनियरों को काम दिया जा सकता है, अवागुह इंजीनियरिंग कालेज खोल दिए गए। सितंबर १९६६ तक पाली बटे इंजीनियरों की संख्या ६०,००० हो गई और अनुमान है कि दाखिला घटा देने पर भी यह संख्या १,००,००० पहुँच जाएगी। सरकार ने उच्च स्तर के टेक्निकल इंस्टीट्यूट, कृषि विश्वविद्यालय साधनालाए और संस्थान खोल दिए हैं। शिक्षा कमीशन की सिफारिश के मुताबिक विभिन्न विषयों में ऊँचे दर्जे के संस्थान भी खोले जा रहे हैं। मगर समस्या यह है कि इन संस्थानों से निकलने वाला को काम कहाँ दिया जाएगा।

शिक्षा पर इतना जोर देने के बावजूद, उसमें कमी करना तो संभव नहीं। लेकिन शिक्षा के विस्तार के साथ साथ काम देने का प्रयत्न नहीं हुआ तो राजनैतिक स्थिरता खतरे में पड़ जाएगी। यह समस्या बड़ी गंभीर है और इसने कारण सत्ता में अमनोप जन्मा अवश्यभावी है।<sup>३५</sup>

३. सारणी नं ६ और ७ से प्रकट हागा कि शिक्षा, कम आय, बेगारी और शहरी का प्रभाव में उदास सत्ता है।

सरकार स्थिति को समझने का उपाय कर रही है। गांधी के तरीका का ज्यादा दक्षिणा, व्यावसायिक और गिनियव मूल्य में ज्यादा भर्ती, विभिन्न प्रदंगा और गांधी और गहरा में भिन्न भिन्न प्रकार की गिनिया और उद्योगधंधा की आवश्यकता का मुजाबिब गिरा। पता चलता है कि किसानों के लड़के अन्न पट्ट कर गांधी में खेती का कामधंधा करने में प्रवृत्त हो रहे हैं। इस प्रवृत्ति में श्रुति विश्वविद्यालय का महत्त्व पूरा योग रहा है। वनमात उद्योगों की पूरी क्षमता का उपयोग करने से भी गिनिया का काम मिलेगा। सामाजिक संस्थाओं के विस्तार से (जिनमें गांधी में स्त्री का मूल्य भी शामिल है) बहुत से निम्न मध्यम वर्ग के विद्वान और मानविकी विद्याओं के स्नातकों का काम मिलेगा। बड़े पैमाने पर गांधी में स्थापित कार्य चालू होने से इन्जीनियरों की राजगार मिलेगी। हमारे अन्तर्गत बहुत से लोगों की रगत या मोगम के समय जो काम मिल जाता है, और बहुत से कामगार शहर में घड़े समय काम करके गांधी चोट खाते हैं तथा बर्माई और आय परिवार की समझी जाती है, एक आदमी की नहीं, इससे भी बेकारी का दसाव कुछ कम हो जाता है। फिर भी गिनितों की बढ़ती हुई गरबा (स्त्रियाँ भी इसमें शामिल हैं) के राजनैतिक प्रभाव की उम्मा नहीं की जानी चाहिए।<sup>३६</sup>

लेद है कि अभी तक शिक्षित बेरोजगारी का राजनैतिक गतरे का नहीं समझा गया, न इस शिक्षित जनशक्ति का विकासकाय के लिए उपयोग किया गया, न जायिक योजना में ऐम परियत्तन किए गए गिनितों बेरोजगारी घटे। विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम, अध्यापन और प्रशासन का ढांचा भी दक्षिणानुमी चला आ रहा है। इससे नवयुवक सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में अपना स्थान लेने के लिए तयार नहीं हो रहे हैं।

## निष्पत्ति

जिन समस्याओं पर यहां विचार किया गया—उद्योगों की पूरी क्षमता का उपयोग, खेती के माधन जुटाना, बेरोजगारी का उपाय करना, जनसंख्या वृद्धि को रोकना और शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों का देश के विकास और परिवर्तन में लगाना—इन सबका धुंधला आभास भारत सरकार को है और वह कुछ कर भी रही है। पर बहुत ढिलाई और मुस्ती से जा योजनाएँ स्वीकृत हो चुकी हैं, उनका काम भी सुस्त है। अभी अव्यवहृत क्षमता के उपयोग की बहुत गुंजाइश है। खाली बंटे शिक्षित युवकों के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं, जिससे विकास में तजी जा सकती है। प्रशासन का पुराने सड़े गले कायदों की कैद से छुड़ा कर उसमें तेजी लायी जा सकती है। विकास काय को चलाने वाली मशीनरी में हर

३६ शिक्षा के प्रभाव के बारे में देखें—अलेक्जेंडर इन्फेल्ड 'पात्रिस्सिपें' मिडिलनशिप इन दवर्गपिंग कला में अमेरिका में माइल रिडु। इसमें भारत पर भी विचार किया गया है।

धेनी पर ज्वाला योग्य आदमी लाए जाने चाहिए। पर इस ओर ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है।

ऐसा लगता है कि जैसे वृषि त्राति के लिए साक्षसकट जरूरी था, उसी तरह आगे कोई गहरा सकट आने पर ही सरकार चेतेगी। पर खतग यह है कि मूल्य-वृद्धि से मध्यम वर्ग और श्रमिकों की वार्षिक आय बहुत घट जाए, निर्यात का माल महंगा हो जाए और निर्यात घटने से, औद्योगिक उत्पादन के लिए अनिवार्य सामान का आयात न हो सके, इससे कल कारखाना का उत्पादन घटे, परिणाम स्वरूप बेकारी बढ़े और शहरो में असंतोष व उपद्रव हो और स्थिति इतनी बिगड़ जाए कि वर्तमान व्यवस्था ठप हो जाए।

भारत ने अब तक हर प्रकार के सकटा का सामना करने की विलक्षण क्षमता दिखाई है, परंतु इस सबक को हमेशा याद नहीं रखा है और संस्थापित नहीं किया है। तत्त्व की जान यह है कि हमारे नेतावर्ग में कितनी समझदारी और स्थिति के अनुसार अपना रवैया बदल सकने की क्षमता है।

## अंतरराष्ट्रीय स्थिति

अब तक हमने मुख्यतः भारत की आंतरिक स्थिति का ही विवेचन किया है। अब हमें अंतरराष्ट्रीय सदन में भारत की स्थिति पर भी विचार करना चाहिए क्योंकि द्वितीय युद्ध के बाद दो महाशक्तियाँ मे जो स्पर्धा चली और उसके कारण जो अंतरराष्ट्रीय गुटबंदी शुरू हुई उसका प्रभाव राष्ट्र की नीति पर पड़ना अनिवार्य था। प्रश्न यह था कि देश वहाँ तक गुटों में शामिल होने के दबाव का सामना कर सकता था और अपनी स्वतंत्र नीति पर चल सकता था। इधर सत्तार का दो गुटों में विभाजन भी टूटा है और भारत जैसे देशों को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ा है।

यहाँ हम भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर मोटे तौर पर विचार करेंगे। भारत पर विदेशी सत्ता की स्थापना के फलस्वरूप इस पर बाहरी सत्तार की विचारधाराओं, औद्योगिक विधियों और समस्याओं का प्रभाव पड़ा और कुछ हद तक इसका भी बाहरी दुनिया पर प्रभाव पड़ा और वर्तमान में भी यह प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा पड़ोस के देशों की शत्रुता और सत्तार में महाशक्तियों की मोरचेबंदी को देखते हुए देश की रक्षा का भी प्रश्न है। अतः देश के आर्थिक विकास और आर्थिक नीति पर विदेशी आर्थिक सहायता और विदेश से आर्थिक संबंधों का प्रभाव पड़ता है। इन अंतरराष्ट्रीय संबंधों का प्रभाव देश की आंतरिक नीतियों पर भी पड़ता है। जैसे राजनीति में सेना का स्थान, बाहरी देशों से लड़ाई का देश की एकता पर प्रभाव, रक्षा और आर्थिक विकास में संबंध, और विदेशों की सहायता का केवल देश के आर्थिक विकास पर ही नहीं, राजनैतिक रूप और परराष्ट्रनीति पर प्रभाव। इसके अलावा राष्ट्रीय अस्मिता, स्वाभिमान और मनोबल के बुनियादी प्रश्न भी उठते हैं। एक ओर हम अपनी राजनैतिक स्वतंत्रता को बनाये रखना चाहते हैं और अंतरराष्ट्रीय समाज में प्रतिष्ठा और अग्रता प्राप्त करना चाहते हैं, और दूसरी ओर हमें अपनी कमजोर औद्योगिक स्थिति के कारण आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस दृष्टि से हमारी परराष्ट्र नीति का मुख्य





## राष्ट्रीय स्वतन्त्रता

लेकिन यह आदशवाद खोखला न था, न राष्ट्रीय हितों के विपरीत था। नेहरू सत्सार की बदली हुई स्थिति का जोर लोगों से ज्यादा समझते थे। उन्होंने समझा था कि द्वितीय युद्ध ने सत्सार की व्यवस्था बदल दी है। उन्हें इसका भान था कि जिस समय उपनिवेशवाद के शिकार देश स्वतन्त्रता प्राप्त कर रहे हैं, उसी समय उनकी स्वतन्त्रता को सबसे अधिक खतरा है। न केवल नए देशों में अपनी आजादी की रक्षा की शक्ति न थी, बल्कि खतरा यह था कि सत्सार में बड़े राष्ट्रों की गुट-बंदी में पड़ कर वे उनके पुछल्ले बन जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र सभ की रचना भी नए राष्ट्रों के लिहाज से सतोषजनक न थी। इसने ऐसी व्यवस्था नहीं स्थापित की जिसमें प्रत्येक राष्ट्र समान रूप से स्वतन्त्र था, बल्कि इसने सत्सार को दो श्रेणियों में बांट दिया, एक बड़े राष्ट्रों का वर्ग और दूसरा उनके अनुयायियों या पीछे चलने वाला का। भारत को ऐसा लगा कि बड़े राष्ट्र (विशेषतः संयुक्त राष्ट्रों) सत्सार (अमरीका) भूमध्यसागर से लेकर बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी चीन सागर तक के सारे क्षेत्रों पर हावी हो जाना चाहते हैं। इसका गहरा प्रभाव भारत पर पड़ता था।

नेहरू इसका प्रतिरोध करना चाहते थे। पर यह सैनिक ताकत के जोर से नहीं हो सकता था। यह प्रतिरोध वह वैचारिक स्तर पर करना चाहते थे। वह एक नया सिद्धांत प्रस्तुत करके, सत्सार के जनमत को प्रभावित करना चाहते थे। उन्होंने जो विदेशनीति प्रस्तुत की उसके तीन उद्देश्य थे - (१) उन देशों को एक हद तक स्वतन्त्रता दिलाना जो बड़े राष्ट्रों का सामना करने में असमर्थ थे (इसी से उन्होंने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरोध पर जोर दिया)। (२) बड़े राष्ट्रों की शक्तिस्पर्धा से उत्पन्न गुटबंदी को रोकना जो सत्सार की व्यवस्था के कारण उत्पन्न हुई थी (इसीलिए उन्होंने फौजी गुटा का डट कर निरंतर विरोध किया)। (३) जोर उत्तरी अफ्रीका से लेकर इंडोनेशिया तक के भूभाग को बड़े राष्ट्रों के दबाव से मुक्त रखना (इसी उद्देश्य से उन्होंने एशियन कानफरेंस बुलाई और अफ्रीका - एशिया के राष्ट्रों के सम्मेलन शुरू किए)। उनकी यह नीति अमरीका के विरुद्ध जाती थी, इसलिए अमरीका के प्रभाव को रोकने के लिए उन्होंने इस क्षेत्र में एक प्रतिस्पर्धी शक्ति के रूप में रूस के प्रवेश की कांशिश की और भारत की स्वतन्त्रता कायम रखने के लिए पूर्व (रूस) और पश्चिम (अमरीका) की कशम-कश से लाभ उठाने की कोशिश की।

इसकी नीति को विफल करने में नेहरू की सकलता उल्लेखनीय है। अगर राष्ट्रीय नीति का इतिहास जब निष्पक्ष होकर लिखा जाएगा, तो इसे स्वीकार किया जाएगा। उनकी बात की विफलताओं के सामने इस सफलता को भुलाना नहीं चाहिए। नेहरू राजनैतिक स्वतन्त्रता को वास्तविक राष्ट्रीय स्वायत्तता या आत्म-

प्रश्न या प्रयोजन देना की रक्षा और परराष्ट्र संबंध ही नहीं, आर्थिक पिछेपन या विकास की समस्या भी है, जिसके कारण सत्सार में हमारी स्थिति कमजोर होती है।

## नीति का विकास

जिस समय हमें आजादी मिली उस समय सत्सार की स्थिति में यह स्वाभाविक था कि देश जवाहरलाल नेहरू की नीति अपनाए। सत्सार दो गुटों में बटा हुआ था। एशिया और अफ्रीका में नए राष्ट्रों का उदय हो रहा था। हमारे सामने देश की राजनैतिक व्यवस्था को दृढ़ करने और परिवर्तन लाने की भारी समस्या थी। इसके लिए जरूरी था कि हम जहां तक हो सके बाहरी उलझनों से दूर रहें और अपने घर में दीया जला कर मस्जिद में दीया जलाएं। हमारा लक्ष्य विश्वशांति, पराधीन राष्ट्रों की आजादी, पश्चिमी लोकतंत्रों से संबंध और साथ ही अंतरराष्ट्रीय गुटबंदी और झगडा से दूर रहने का था। यद्यपि प्रथम विश्वयुद्ध के समय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पश्चिमी राष्ट्रों का साथ दिया था और उसको सैनिक सहायता देने का समयन किया था, लेकिन दूसरे और तीसरे दशक में इस रुख में परिवर्तन हो गया। कांग्रेस ने अब खुलकर सब देशों की आजादी और आत्मनिर्णय के अधिकार का समयन किया। भारत का युवक वर्ग मार्क्सवाद और कम्युनिस्ट आंदोलन की ओर आकृष्ट हुआ। कुछ प्रमुख भारतीयों ने एशियाई देशों को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में शामिल करने का यत्न किया।<sup>१</sup> नेहरू ने एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों का नेतृत्व करने का भी प्रयत्न किया।

स्वतंत्रता के पहले के दशकों में और बाद के वर्षों में भारत का रत्न, १९ वीं सदी के पुनर्जागरण और उदारता के आंदोलन से प्रभावित था। भारत का विश्व वधुत्व जा अब तक दबा था अब प्रकट हो रहा था। नेहरू के शब्दों में भारत की स्वतंत्रता का आगमन ऐसी घड़ी थी जो सत्सार में कभी कभी ही आती है। यह वह घड़ी थी, जब हम पुराने युग से नए युग में कदम रखते हैं, जब एक युग का अंत होता है और चिरकाल से रुद्ध राष्ट्र की आत्मा बाल पड़ती है। परिणाम स्वरूप भारत ने विश्व और उसकी समस्याओं के प्रति एक आदर्शवाद और आशावाद का रुख अपनाया, जो सत्सार की वास्तविकता और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में व्याप्त अवसरवादिता और स्वाधपत्ता के विपरीत था।

१ हमें प्रमुख थे एन एन राव जो लेनिन के घनिष्ठ सहयोगी थे और एशिया में कम्युनिस्ट गण्डों के स्थापक थे। दोनों-एन एन राव और एन एन राव 'निर्देश-कम्युनिस्ट इन एशिया' (बम्बे १९५६)।

## राष्ट्रीय स्वतंत्रता

लेकिन यह भादशवाद मोखला न था, न राष्ट्रीय हिता के विपरीत था। नेहरू समार की बदली हुई स्थिति को जोर लोका मे ज्यादा समथत थे। उन्होंने समथा या कि द्वितीय युद्ध ने समार की व्यवस्था बदल दी ह। उहे इसका भान था कि जिस समय उपनिवेशवाद के शिकार देश स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे हैं, उसी समय उनकी स्वतंत्रता को सबसे अधिक खतरा है। न केवल नए देशा मे अपनी आजादी की रक्षा की शक्ति न थी, बल्कि खतरा यह था कि समार में बडे राष्ट्रो की गुट-बनी में पड कर वे उनके पुछल्ले बन जाएगे। सयुक्त राष्ट्र सघ की रचना भी नए राष्ट्रा के लिहाज से सतोपजनक न थी। इसने ऐसी व्यवस्था नही स्थापित की जिसमें प्रत्येक राष्ट्र समान रूप से स्वतंत्र था, बल्कि इसने समार को दो श्रेणियों म बांट दिया, एक बडे राष्ट्रा का वग और दूसरा उनके अनुयायिया या पीछे चलने वाला का। भारत को ऐसा लगा कि बडे राष्ट्र (विशेषतः सबशक्तिशाली स रा अमरीका) भूमध्यसागर से लेकर बगाल की खाडी और दक्षिणी चीन सागर तरु के सारे क्षेत्रा पर हावी हो जाना चाहते हैं। इसका गहरा प्रभाव भारत पर पडता था।

नेहरू इसका प्रतिरोध करना चाहते थे। पर यह सैनिक ताकत के जोर से नही हो सकता था। यह प्रतिरोध वह वैचारिक स्तर पर करना चाहते थे। वह एक नया सिद्धांत प्रस्तुत करके, समार के जनमत को प्रभावित करना चाहते थे। उन्होंने जो विदशनीति प्रस्तुत की उसके तीन उद्देश्य थे - (१) उन देशा को एक हद तक स्वतंत्रता दिलाना जो बडे राष्ट्रा का सामना करने मे असमथ थे (इसी मे उहाने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरोध पर जोर दिया)। (२) बडे राष्ट्रो की शक्तिस्पधा मे उत्पन्न गुटबंदी को रोकना जो स रा सघ व्यवस्था के कारण उत्पन्न हुई थी (इसीलिए उहाने फौजी गुटा का डट कर निरंतर विरोध किया)। (३) और उत्तरी अफ्रीका मे लेकर इंडोनेशिया तक के भूभाग को बडे राष्ट्रा के दबाव से मुक्त रखना (इसी उद्देश्य से उन्होंने एशियन वानफरेस बुलाई और अफ्रीका - एशिया के राष्ट्रा के सम्मेलन गरु किए)। उनकी यह नीति अमरीका के विरुद्ध जाती थी, इसलिए अमरीका के प्रभाव को रोकने के लिए उन्होंने इस क्षेत्र में एक प्रतिकारक शक्ति के रूपमें रूस के प्रवेश की कोशिश की और भारत की स्वतंत्रता कायम रखने के लिए पूव (रूस) आर पश्चिम (अमरीका) की कशम कश से लाभ उठाने की कोशिश की।

इलेस की नीति को विफल करने म नेहरू की सफलता उल्लेखनीय है। अंतर-राष्ट्रीय नीति का इतिहास जब लिप्यक्ष होकर लिखा जाएगा, तो इसे स्वीकार किया जाएगा। उनकी बाद की विफलताओं के सामने इस सफलता को भुलाना नही चाहिए। नेहरू राजनैतिक स्वतंत्रता को वास्तविक राष्ट्रीय स्वायत्तता या आत्म-

निभरता में बदलना चाहत थे। यही उनका मुख्य लक्ष्य था। और साथ आनुपातिक थे जैसे पड़ोस और देश में शांति रखना तथा पश्चिम और पूर्व के देशों से आर्थिक सहायता प्राप्त करना।

नेहरू की यह नीति ससार की स्थिति में उनकी गहरी पैठ पर आधारित थी। सबसे पहले नेहरू ने विश्व की बदली स्थिति का समया और इस ऐतिहासिक सिद्धांत का उद्घाप किया कि, उपनिवेशवाद के दिन पूरे हो चुके हैं। नेहरू ही सबसे पहले गैर कम्युनिस्ट नेता थे जिन्होंने ससार का ध्यान सावियत संघ की ठोस सफलताओं की ओर खींचा और १९२७ में ही मोवियत रूस की पहली यात्रा के बाद इस तथ्य का उद्घोष किया कि तकनीकी प्रगति के साथ सावियत रूस में यह मांग उठेगी कि उसकी आंतरिक नीति और व्यवस्था उदार बनायी जाए, दूसरे देशों के प्रति व्यावहारिक नीति अपनायी जाए और स० रा० अमरीका से मन किया जाए। भारत ही पहला गैरकम्युनिस्ट देश था, जिमने मोवियत नेताओं का दूसरे देशों की यात्रा करने का निमन्त्रण दिया और यह यात्रा भारत से ही शुरू हुई। बाद में पश्चिमी देशों ने भी अनुकरण किया। इस बात में तथ्य है कि रूसवोफ ने दूसरे देशों की ओर यात्रा की, उसी के फलस्वरूप रूस के हित में नरमी आयी। इसी तरह दूसरा से बहुत पहले नेहरू ने इस बात को लक्ष्य किया कि मोवियत रूस और चीन के हितों में टक्कर अनिवार्य है, कम्युनिज्म से राष्ट्र बाट ज्यादा शक्तिशाली है और कम्युनिज्म के भी कई रूप हो सकते हैं। अपनी इन्हीं धारणाओं के आधार पर नेहरू ने परस्पर विरोधी व्यवस्थाओं के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया, परमाणु शस्त्रों के निर्माण पर निमन्त्रण (यदि राक संभव न हो तो) का आग्रह किया, गुटों से अलग रहने की नीति का प्रतिपादन किया और कहा कि विकसित देश अविकसित देशों को सहायता देने में राजनैतिक शक्त न लगाए।<sup>२</sup>

### गुटों से पृथक्ता

नेहरू का कहना था कि उनकी गुटों से अलग रहने की नीति बारीक सैद्धांतिक या आदर्शवादी नीति नहीं थी, बल्कि राष्ट्र के हित पर आधारित थी। भारत को पूर्वी और पश्चिमी दोनों देशों की मित्रता की दरकार थी। वह नहीं चाहता था कि उसने धरतू मामलों में बाहर से हस्तक्षेप हो और उसने यह अनुभव कर लिया था कि देश की राजनैतिक स्वायत्तता और पुनर्निर्माण के लिए जरूरी है कि बाहरी शक्तियाँ इस प्रदेश में पैर न जमाने पाए। इसी नीति के अनुसार नेहरू ने भारत के आर्थिक विकास के लिए संपन्न देशों से सहायता हासिल करने का

२ माइकेल अचर - 'नेहरू' पब्लिशिंग हाउस (दुबई १९५०)।

यत्न किया। अपने उत्तर की दो महाशक्तियों चीन और रूस से सघर्ष बचाया, नए देशों से मित्रता की और अंतरराष्ट्रीय परिपदा में उनकी पैरवी की।

इसी नीति के तहत भारत की स्वतंत्रता के छोड़े ही दिना बाद सन १९४८ में नेहरू ने नई दिल्ली में प्रथम एशियाई सम्मेलन किया, जिसमें हालैंड की अधीनता से इंडोनेशिया की आजादी का समर्थन किया गया। १९५५ में बाङ्गु सम्मेलन में भारत ने प्रमुख भाग लिया। १९५६ में चीन के साथ पंचशील संधि हुई। भारत ने १९५५ में स्वेज युद्ध के समय मित्र का प्रबल समर्थन किया और फ्रांस के विरुद्ध अलजीरिया का पक्ष लिया, कारिया में युद्धविराम और युद्धकदिया की बदला बदली कराने में तथा हिंद चीन और लाओस के मामले में जिनेवा सम्मेलन कराने में प्रमुख भाग लिया। कागा में गृहयुद्ध खतम करने के लिए समुक्त राष्ट्रसेना में भारतीय दस्ते भेजे। स० २० संधि में चीन को स्थान दिलाने का निरंतर समर्थन किया। सन १९६१ में बेलग्राड में हुए गुटमुक्त देशों के सम्मेलन में भारत ने मित्र और युगोस्लाविया के साथ मिल कर सम्मेलन की गुटबंदी से बचाया।<sup>३</sup>

तुरत आजाद हुए देशों के लिए विश्व के मामलों में इतना हिस्सा लेना मामूली बात नहीं। भारत ने गुटा से अलग रहने के साथ ही साम्राज्यवादविराधी आंदोलन का सक्रिय समर्थन किया। पश्चिमी देशों के मुकाबले गुटमुक्त और समाजवादी देशों की ओर भारत का झुकाव ज्यादा रहा और उसकी भावनाओं का उसने अधिक ध्यान रखा, इसलिए उसकी नीति में कुछ दुरगमन आ गया और कुछ देशों में गलतफहमी पैदा हुई<sup>४</sup>। बाद में जब सीमाओं पर खतरा पैदा हुआ और विदेशी शक्ति का बोझ बढ़ा, तब इस नीति की कड़ी परीक्षा हुई। फिर भी भारत ने यही कोशिश की कि उसका पल्ला किसी एक गुट से न बंधने पाए। और अंत में जब नीति पर पुनर्विचार का समय आया, तब तक दुनिया की हालत बदल चुकी थी और पुरानी गुटबंदियां बहुत कुछ टूट चुकी थीं।

गुटा से अलग रहने की इस नीति से भारत को लाभ भी हुआ। इसके कारण उसे देशों का एकीकरण करने, दली रियासतों को मिलाने, नेपाल, भूटान, सिक्किम आदि के साथ संबंध मजबूत करने का समय मिला। वह कश्मीर को भी रख सका और पश्चिमी राष्ट्रों की आलोचना के बावजूद १९६१ में गोवा को पुनर्गल

३ बेलग्राड सम्मेलन में इंडोनेशिया माली, गायना और क्यूबा जैसे राष्ट्र बड़ी उग्र नीति के समर्थक थे और नरम रूप वाले देशों को अलग करना चाहते थे। नेहरू और कुछ अन्य लोग सम्मेलन को और व्यापक रूप देना चाहते थे और दुनिया भर के राष्ट्रों को स्थान देने के समर्थक थे। नेहरू के प्रभाव से भिन्न और युगोस्लाविया ने इस रुख का समर्थन किया और इसी की नीति हुई।

४ यह कहना पड़ेगा कि समाजवादी देशों ने शुद्ध नीति का पूरा समर्थन किया जबकि पश्चिमी राष्ट्रों का रुख उपहास और विरोध का रहा।



## सीमा युद्ध

दूसरी समस्या जो सबसे गंभीर है आर जिसके कारण भारत का सबसे ज्यादा जिल्लत उठानी पड़ी है, उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमा की समस्या है। चीन का कहना है कि यह सीमा कभी स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं हुई और वह अंग्रेजों के वक्त की साम्राज्यवादी सीमा संधियों का नहीं मानता।<sup>६</sup> शीतयुद्ध के प्रतिकार के उद्देश्य से भारत ने चीन से मित्रता की नीति अपनायी थी। परंतु एक ओर चीन का व्यवहार कुटिल था, और वह साफ साफ बात नहीं करता था, दूसरी ओर भारत की प्रवृत्ति अप्रिय या कटु यथाय से आस चुराने की थी। इसलिए दोनों में गंजनफहमी घटती गई।

१९५९ में तिब्बत में विद्रोह के बाद विरोध स्पष्ट हो गया। चीन से तिब्बत का सीधा रास्ता बड़ा दुगम था इसलिए उसे एक और रास्ते की जरूरत पड़ी (अक्साई चीन होकर लद्दाख से)। तिब्बत में चीन के अत्याचार के कारण भारत का जनमत चीन के खिलाफ हो गया था। सीमा के मामले में चीन का अब तक जो दुरगम व्यवहार रहा आर जिस प्रकार उसने नक्शा में भारतीय इलाका का अपनी ओर दिखाया, उससे उसके साथ सीमा के मामले में कोई रियायत भारत की संसद को स्वीकार नहीं होती। चीन का कहना था कि तिब्बत के मामले में भारत अंग्रेजों की चाल चल रहा है। घटनाओं पर पुनर्विचार करने से अब ऐसा लगता है कि १९४४ में ही जब तिब्बत में चीन का प्रवेश हुआ था १९५०-५५ में जब चीन लद्दाख में अक्साई चीन के बदले उत्तरपूर्व में मैकमहान रेखा को मानने को तैयार था समझौता हा सकता था। लेकिन चीन ने टेढ़ी चालें चलनी शुरू कर दी, भारतीय प्रदेश को चीन के नक्शे में दिखाना, चुपके चुपके अक्साई चीन से सड़क बनाना और सीमा पर झड़प करना। भारत ने जवाबी कारवाइ देर से शुरू की। उसने धीमे धीमे सीमा पर फाजी प्रबंध बढ़ाना शुरू किया और १९६१-६२ में लद्दाख में अग्रिम चाकिया कायम की। अप्रैल १९६० में दिल्ली में जब चाऊ एन लाई ने नेहरूजी से भेंट की, तभी उन्होंने उपर्युक्त समझौते का (अक्साई चीन के बदले मैकमहान रेखा मानने का) प्रस्ताव किया पर तब तक समय निकल चुका था। सीमा पर झड़पें हा चुकी थी और चीन ने (लद्दाख में भारत के बढ़ाव) और नेहरूजी के 'चीनिया का बाहर धकेल दो' वाले वक्तव्य से बिगड़ कर भारत पर भारी आक्रमण कर दिया। असंभव नहीं है कि मित्रता के दिखावे और भाईचारे के नाटक ने भी व्यावहारिक समझौते के माग में बाधा डाली।

इस अचानक आक्रमण में भारत की हार हुई और चीन से उसकी दुश्मनी हो गई। जिस प्रकार चीनी लद्दाख में विवादग्रस्त सीमा के आगे के इलाके से हट गए

६ च्यांग काइ शेक और उनकी सरकार का भी यही रण है।





## भारत-पाकिस्तान युद्ध

भारत का डर था कि अमेरिका से जो आधुनिक हथियार पाकिस्तान को मिले हैं उनका प्रयोग एक दिन भारत के विरुद्ध होगा। १९६३ में चीन और पाकिस्तान में सीमा समझौता हुआ जो भारत के विरुद्ध गठबन्धन का सूचक था। यह आशका १९६४ में सत्य हुई। अप्रैल में पहली घटना हुई। पाकिस्तान ने कच्छ-सिंध सीमा पर भारत की चौकियाँ पर हमला किया। उसने १६ बटालियन सेना और अमेरिका से मिले टैंक तथा अमेरिका और ब्रिटेन से मिले अन्य हथियारों का प्रयोग किया।<sup>७</sup> तीस जून को ब्रिटिश प्रधान मंत्री की मध्यस्थता में युद्ध-विराम हो गया आर कच्छ की सीमा का विवाद तीन जगहों की अंतरराष्ट्रीय पंचायत को सौंपने का समझौता हुआ। दोनों देशों ने इसका निणय स्वीकार करने का वचन दिया।<sup>८</sup>

पर पांच अगस्त १९६५ को कश्मीर में युद्ध विराम सीमा को पार करके पाकिस्तानी हथियारबंद उपद्रवियों ने घुस-पैठ की।<sup>९</sup> इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने अन्तरराष्ट्रीय सीमा पार करके छत्त पर आक्रमण किया, इसके जवाब में भारतीय सेनाओं ने पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा के पार आक्रमण किया। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर में हाजीपीर दर्रा जीर अन्य पाकिस्तानी चौकियाँ पर भी कब्जा कर लिया। युद्ध पचास दिन चला। पाकिस्तान ने अमेरिकन ब्रिटिश और जर्मन हथियारों आर टैंकों का प्रयोग किया पर भारतीयों ने आक्रमण को पीछे धकेल दिया। भारत की स्थल आर हवाई सेना ने अपने से कहीं ज्यादा अच्छे अमेरिकन विमानों और टैंकों का मुकाबला भारत में बने हथियारों और लड़ाकू विमानों से किया आर उन्हें गहरी मार दी। भारतीय सेनानायकों ने युद्ध-कुशलता दिखाई आर लाहौर पर आक्रमण करके पाकिस्तान को अनचिक्के में डाल दिया।

भारत के नेताओं ने भी बड़ी हिम्मत और धीरज से काम लिया। १६ सितम्बर को चीन ने अन्टीमेटम दिया कि भारत सिक्किम की सीमा पर अपनी मोर्चेबंदी तीन दिन के अन्दर हटा दे वरना वह आक्रमण कर देगा। चीन ने यह भी आराप

७ प्रे. अयूब खान ने इसे ४ मई १९६५ में स्वयं स्वीकार किया। घटनाओं के विवरण के लिए देखें इन्डिया १९६६ (दिल्ली १९६६)।

८ यह निणय घोषित हो गया और भारत ने इसे स्वीकार भा कर लिया यद्यपि दक्षिण पश्चिम द्वारा इसका घोर विरोध किया गया। पाकिस्तान ने भी इसे स्वीकारा।

९ १९४७ में कश्मीर के भारत में मिलने के प्रश्न पर पाकिस्तान से भारत का संधन हुआ। भारत ने इस विवाद को सारा सन्धे में पेश किया और उसकी मध्यस्थता में जन १९४९ को युद्ध विराम हुआ। युद्धविराम-रेखा है तब से दोनों देशों के बीच कश्मीर की विमानन-रेखा हो गयी। इस विषय के सन्निहित वर्णन के लिए देखें शिशिर गुप्त, कश्मीर ए स्टेट इन इन्डिया पाकि रिलेशन्स' (बम्बई १९६६)।

और बाद में नेफा में भी हट और इसके पहले सीमा के बारे में उठाने प्रस्ताव किए थे, इससे पता चलता है कि चीन का इरादा सीमित था परन्तु इस आक्रमण के बाद निवट भविष्य में किसी सम्मानजनक समझौते की आशा न रही।

इस पराजय से भारत को गहरा धक्का लगा और उसकी आँखें खुल गई। जैसा कि नेहरू ने कहा भारत अब पन्ना जैसा बर्फी नहीं हो सकता। भारत को अपनी रक्षा का प्रबंध बनाना पड़ा। १९६२-६३ में उसकी रक्षा का बजट ३०० करोड़ रुपया था जो अगले वर्षों में ५००-६०० करोड़ रुपया हो गया। अब यह १००० करोड़ रुपया है जो बुन राष्ट्रीय उत्पादन का पाँच प्रतिशत होता है। यद्यपि रक्षा संबंधी व्यय में भी कारखाना व उत्पादन की कुछ प्रोत्साहन मिलना है परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि दश की दो हजार मील लंबी सीमा की रक्षा का प्राज्ञ से दूसरे विकास कार्यो में बाधा पड़ी है और मुद्रास्फीति हुई है। इसके अलावा देश को चीन और पाकिस्तान की ओर से हमेशा खटका लगा रहता है और देश के अंदर भी वामपंथी कम्युनिस्टों और अनेक मुस्लिम दला पर चीन और पाकिस्तान का समर्थन होने का सन्देह किया जाता है।

पर चीन के आक्रमण में रात भी हुआ। दश भर में दशप्रम की लहर दौड़ गई। देश की रक्षा के लिए धन और जन देन की होड़ लग गई और राष्ट्र में एकता बढ़ी। देश की परराष्ट्र नीति में वास्तविकता और व्यावहारिकता आई और रक्षा व्यवस्था का मजबूत करने का सक्ल किया गया। देश में सक्ल की स्थिति की घोषणा कर ली गई। मालिका और मजदूरों में औद्योगिक शांति रखने का समझौता हुआ जिससे कारखाने जोग से चल सकें। रक्षा के लिए बचत की योजनाएँ चालू की गई और फौजी महत्व के कारखाने तजी से चले गए।

बाहर भी लोकतंत्रीय और गुटा से अलग दशा में (इंडोनेशिया को छोड़कर) भारत के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। भारत का सबसे जोरो से समर्थन मित्र यूगोस्लाविया और मलाया ने किया। मलाया में लोकतंत्र रक्षा कोष खोला गया। कोनम्बो देशों ने (लका, घाना, बर्मा, इंडोनेशिया और मिश्र) समझौते का प्रयत्न किया। भारत ने उनका प्रस्ताव पूरी तरह स्वीकार कर लिया, पर चीन ने केवल सिद्धांत रूप में पश्चिमी देशों ने खासकर संयुक्त राज्य, ब्रिटेन और कनाडा ने भारत को तुरंत अस्त्रास्त्र की सहायता दी। इन देशों से और सोवियत रूस से भी हथियार और फौजी सहायता लेने के लिए दीघकालिक समझौते किए गए। अधिक सहायता की तरह फौजी सहायता भी दोनों गुटा से लेने की नीति अपनाई गई। भारत ने यह कोशिश की कि उसका विरुद्ध रूस और चीन का गुट न बनने पाए, साथ ही भारत में भी आधुनिक हथियार लड़ाकू विमान बेतार यंत्र और राडार का निर्माण तेजी से बढ़ाया गया और रक्षाउत्पादन का विभाग खोला गया। यह तैयारी १९६५ में पाकिस्तान से युद्ध के समय बहुत काम आई।

## भारत-पाकिस्तान युद्ध

भारत का डर था कि अमेरिका से जो आधुनिक हथियार पाकिस्तान को मिले हैं उनका प्रयोग एक दिन भारत के विरुद्ध होगा। १९६३ में चीन और पाकिस्तान में सीमा समझौता हुआ जो भारत के विरुद्ध गठबंधन का सूचक था। यह आशंका १९६५ में सत्य हुई। अप्रैल में पहली घटना हुई। पाकिस्तान ने कच्छ-सिंध सीमा पर भारत की चौकियां पर हमला किया। उसने १६ बटालियन सेना और अमेरिका से मिले टैंक तथा अमेरिका और ब्रिटेन से मिले अथवा हथियारों का प्रयोग किया।<sup>७</sup> तीस जून को ब्रिटिश प्रधान मंत्री की मध्यस्थता में युद्ध-विराम हो गया और कच्छ की सीमा का विवाद तीन जजा की अंतरराष्ट्रीय पंचायत को सौंपने का समझौता हुआ। दोनों देशों ने इसका निणय स्वीकार करने का वचन दिया।<sup>८</sup>

पर पांच अगस्त १९६५ को कश्मीर में युद्ध विराम सीमा को पार करके पाकिस्तानी हथियारबंद उपद्रवियों ने घुस-पैठ की।<sup>९</sup> इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने अन्तरराष्ट्रीय सीमा पार करके छत्र पर आक्रमण किया, इसके जवाब में भारतीय सेनाओं ने पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा के पार आक्रमण किया। भारतीय मलिका ने पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर में हाजीपीर दर्रा पार अथवा पाकिस्तानी चौकियां पर भी कब्जा कर लिया। युद्ध पचास दिन चला। पाकिस्तान ने अमेरिकन ब्रिटिश और जर्मन हथियारों और टैंकों का प्रयोग किया पर भारतीयों ने आक्रमण को पीछे धकेल दिया। भारत की स्थल और हवाई सेना ने अपने से कहीं ज्यादा अच्छे अमेरिकन विमानों और टैंकों का मुकाबला भारत में बने हथियारों और लड़ाकू विमानों से किया और उन्हें गहरी मात दी। भारतीय सेनानायकों ने युद्ध-कुशलता दिखाई और नाहौर पर आक्रमण करके पाकिस्तान का अनधिकृत में डाल दिया।

भारत के नेताओं ने भी बड़ी हिम्मत और धीरज से काम लिया। १६ सितम्बर को चीन ने अन्टीमेम दिया कि भारत सिक्रिम की सीमा पर अपनी माहौल की तीन दिन के अंदर हटा दे वरना वह आक्रमण कर देगा। चीन ने यह भी जाराप

~~~~~

७ प्रे. अयुक्तों ने इसे ४ मई १९६५ को स्वयं स्वीकार किया। घटनाओं के विवरण के लिए देखें, इण्डिया १९६६ (दिली १९६६)।

८ यह निणय घोषित हो गया और भारत ने इसे स्वीकार भी कर लिया यद्यपि पश्चिम पंथ द्वारा इसका घोर विरोध किया गया। पाकिस्तान ने भी इसे स्वीकारा।

९ १९४७ में कश्मीर के भारत में मिलने के प्रश्न पर पाकिस्तान से भारत का सपना हुआ। भारत ने इस विवाद को सारा सपना में पेश किया और उसकी मध्यस्थता में जन १९४९ को युद्ध-विराम हुआ। युद्ध-विराम-रेखा है। तब से दोनों देशों के बीच कश्मीर की विभाजन-रेखा हो गयी। इस विषय के सम्बन्ध में वर्तमान के लिए देखें शिंदर गुप्त कश्मीर पर १९४७-१९६५ पाकि रिप्लेस ' ( १९६५ ) ।

लगाया कि भारत ने सीमा पार करके उसके कुछ नागरिक का और जानवरों का अपहरण किया है और उन्हें फौरन लौटा दिया जाये। प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री ने चीन की धमकी के आगे मुकने से इन्कार किया और कहा कि सीमा का समुक्त निरीक्षण कर लिया जाय। चीन की यह कोरी धमकी थी और भारत की दृढ़ता से इसकी पोल गुल गई। नई दिल्ली की जनता ने चीन के दूतावास पर जाकर उस भंडा का एक झुण्ड पेश किया पर चीनी अधिकारियों ने चैप क मार इस स्वीकार किया।

जत म समुक्त राष्ट्र के महामंत्री ऊ थाट की वाशिंगटन आर सावियत रूस के बीच म पडने से और ताश्कंद म पाकिस्तान के सदर अयूब खा और भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात का प्रबंध करने के कारण २३ सितंबर १९६५ को दोना देशा म युद्ध-विराम हा गया। इस लेकर १० जनवरी तक ताश्कंद में दाना नताआ म बातचीत हुई आर ताश्कंद समझात पर दस्तखत हुए। इसमें यह तय हुआ कि दोना पाच अगस्त के पहल की स्थिति पर वापस लौट जायगे, एक-दूसरे के मामले म हस्तक्षेप न करेगे। आधिक आर दूतसम्बन्ध फिर से वायम बातचीत से हल करग और हिंसा से काम न लग। इस समझाते में रूस का मुख्य हाथ था। यद्यपि लालबहादुर शास्त्री का देहात अचानक समझाते पर दस्तखत हाने के दूसरे दिन हो गया पर समझाते पर अमल किया गया आर पाकिस्तानी कब्जे के कश्मीर में हाजीपीर की चौकी छोडने का भारत में बहुत विरोध हुआ, फिर भी भारत ने इह छोड दिया। इसी तरह भारत ने दक्षिणपथी दला के विरोध के बावजूद कच्छ निणय को स्वीकार किया यद्यपि यह उसक कुछ खिलाफ जाता था।

दाना दशा की सीमाआ पर अब भी झडपे हा जाती है, लेकिन स्थिति ज्यादा गिगडने नही दी जाती। संचार और व्यापार चालू करने के बार में बातचीत हुई है। दोना आर के फौजी तथा अय अधिकारियों में बातचीत होती है। प्रधानमंत्री न पाकिस्तानी अधिकृत इलाक में मगला बाध का निर्माण पूरा हाने पर सदर अयूब खा का बघाई भेज कर सदभावना का हाथ बढ़ाया है। उनकी इस कारवाई की ससद में गहरी निंदा हुई, किंतु यह इस बात का इशारा है कि सरकार युद्ध विगम रखा के आधार पर कश्मीर का बटवारा मानने को तयार है।

अंतरराष्ट्रीय स्थिति में परिवर्तन

पाकिस्तान से युद्ध में सफलता से भारत का हासला काफी बढा, क्याकि अच्छे अमरीकी हथियारों और टका के बावजूद भारत ने पाकिस्तान का पीछे ठकल लिया लेकिन युद्ध का दाम भी भारी चुकाना पडा। पाकिस्तान से युद्ध के कारण

न केवल देग में हिंदू-मुस्लिम तनाव बढ़ता है बल्कि इससे अंतरराष्ट्रीय पैच भी पदा होते हैं। इस युद्ध का प्रभाव न केवल भारत और पाकिस्तान पर ही पडा बल्कि अमरीका आर रूस को भी अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पडा और काशिंग करनी पडी कि भारत और पाकिस्तान का सतुलन बिगडने न पाए। अमे-रिका ने लडाई के दौरान आर बाद में भी कुछ समय तक आर्थिक सहायता रोक दी। ताइकंद सम्मेलन में तथा उसके बाद रूस ने भारत और पाकिस्तान के बीच ज्यादा तटस्थता का रण अपनाया ताकि दोनों दशा का सतुलन बना रहे और चीन का प्रभाव पाकिस्तान पर न बढ़ने पावे। कश्मीर और अन्य मामलों पर मोटे तार पर और वाता का समर्थन करते हुए भी सोवियत रूस पाकिस्तान के प्रति समान रूप से मित्रता का व्यवहार कर रहा है और उसे फौजी सामान दे रहा है।

इस प्रकार १९६२ के चीन-युद्ध से भी अधिक पाकिस्तान युद्ध ने भारत की परराष्ट्र-नीति की स्वतंत्रता को घटाया जिससे देश में दोनों बड़े दशा की तरफ से विरक्ति का भाव पैदा हुआ। इससे भारत में इस भावना ने जोर पकडा कि हमें दुनिया के झगडा में दूर रहना चाहिए और युद्ध के बाद जा आर्थिक मदी और राजनीतिक समस्याए उत्पन्न हुई उनसे भी उपयुक्त मनोवृत्ति को बल मिला और भारत को अपनी स्थिति के बारे में शका हुई।

पाकिस्तान युद्ध में सफलता पान के बाद भी भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थिति बिगडी, यह बात नहीं। वास्तव में ससार की ही स्थिति बदल गयी है। शीतयुद्ध की स्थिति अब नहीं रही और दोनों महाशक्तियाँ ने 'तीसरे विश्व' (गुटा से बाहर) देशों के झगडा में अपना रुख बदल दिया है और स्वयं एक प्रकार की गुटों से तटस्थता अपना ली है। इस स्थिति में भारत की तटस्थता का महत्त्व नहीं रहा। जब कोई बड़ा राष्ट्र नहीं चाहता कि भारत उसके गुट में शामिल हो और सभी तटस्थता की बात करते हैं तो भारत की तटस्थता का अर्थ क्या रहा। परंतु भारत कोई दूसरी नीति नहीं निकाल पाया है।

यह बात नहीं कि भारत की बाहरी स्थिति कमजोर हुई हो। प्रत्युत उसकी फौजी और औद्योगिक शक्ति बड़ी है, पर उसने अपने आदर्श और लक्ष्य में विश्वास खो दिया है और उसका रुख विश्व की समस्याओं में न उलझने का है। पर इसी समय भारत को विश्व — व्यवस्था के प्रति अपनी जिम्मेदारी स्वीकारने की जरूरत है। अपने क्षेत्र और विश्व के बारे में भारत की नीति सही साबित हुई है। यह नीति न केवल उसकी स्वतंत्रता का कायम रखने (आर दूसरे नए देशों द्वारा उसकी नीति की स्वीकृति) में बल्कि उस के क्षेत्र की स्वतंत्रता में भी सहायक हुई है। इसलिए उसका वर्तमान उदासीनता का रुख अस्थायी और अवास्तविक है। इस रण के दो कारण हैं, एक तो भारत को युद्ध का अनुभव न था। दोनों महा-

लगाया कि भारत ने सीमा पार करके उसके कुछ नागरिक का आर जानबूरा का अपहरण किया है और उन्हें फारन लाटा दिया जाये। प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री ने चीन की धमकी के आगे झुकने से इन्कार किया और कहा कि सीमा का समुक्त निरीक्षण कर लिया जाय। चीन की यह कोरी धमकी थी और भारत की दृढ़ता से इसकी पोल खुल गई। नई दिल्ली की जनता ने चीन के दूतावास पर जाकर उसे भडा का एक घुण्ड पश किया पर चीनी अधिकारियों ने बेंप व मार इसे म्वीकार न किया।

अत मे समुक्त राष्ट्र के महामंत्री ऊ थाट की काशिश आर सावियत म्स व बीच मे पडने स और ताश्कद मे पाकिस्तान के सदर अयूब खा आर भारत क प्रधानमंत्री की मुलाकात का प्रबध करने के कारण २३ सितंबर १९६५ का दाना देशा म युद्ध-विराम हा गया। इसे लेकर १० जनवरी तक ताश्कद में दाना नताजा में बातचीत हुइ आर ताश्कद समवाते पर दस्तखत हुए। इसमें यह तय हुआ कि दाना पाच अगस्त के पहले की स्थिति पर वापस लौट जायेंगे, एक-दूसरे के मामले मे हस्तक्षेप न करेंगे। आर्थिक आर दूतसम्बध फिर स कायम करेंगे और समुक्त राष्ट्र क घोषणापत्र के सिद्धांता के अनुसार आपसी खगडा का वानचीत से हल करेंगे आर हिंसा से काम न लेंगे। इस समझाते में रूस का मुख्य हाथ था। यद्यपि लालबहादुर शास्त्री का दहात अचानक समझात पर दस्तखत हाने के दूसरे दिन हो गया, पर समझात पर अमल किया गया आर पाकिस्तानी काने के कश्मीर में हाजीपीर की चौकी छाडने का भारत मे बहुत विरोध हुआ, फिर भी भारत ने इन्हें छाड दिया। इसी तरह भारत ने दक्षिणपथी दला के विराध के बावजूद कच्छ निणय को स्वीकार किया, यद्यपि यह उसके कुछ खिलाफ जाता था।

दोना देशा की सीमाआ पर अब भी झडपें हो जाती हैं, लेकिन स्थिति ज्यादा गिगडने नहीं दी जाती। संचार और व्यापार चालू करने के बार में बातचीत हुई है। दोना आर के फौजी तथा अय अधिकारियों में बातचीत होती है। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तानी अधिकृत इलाके में मगला बाध का निर्माण पूरा हाने पर सदर अयूब खा का बघाई भेज कर सदभावना का हाथ बढ़ाया है। उनकी इस कारवाई की ससद में गहरी निंदा हुई, किंतु यह इस बात का इंगारा है कि सरकार युद्ध गिगम रखा के आधार पर कश्मीर का बटवारा मानने को तयार है।

अंतरराष्ट्रीय स्थिति में परिवर्तन

पाकिस्तान से युद्ध में सफलता से भारत का हासला काफी बडा क्योंकि अच्छे अमरीकी हथियारा और टका क बावजूद भारत ने पाकिस्तान या पीछे ढकेल दिया लेकिन युद्ध का दाम भी भारा चुकाना पडा। पाकिस्तान से युद्ध के कारण

न केवल देश में हिंदूमुस्लिम तनाव बढ़ता है बल्कि इससे अंतरराष्ट्रीय पंच भी पैदा होते हैं। इस युद्ध का प्रभाव न केवल भारत और पाकिस्तान पर ही पड़ा बल्कि अमरीका और रूस को भी अपनी नीतियाँ परिवर्तन करना पड़ा और जागरण करनी पड़ी कि भारत और पाकिस्तान का संतुलन बिगड़ने न पाए। अमेरिका ने लड़ाई के दौरान जार बाद में भी कुछ समय तक आर्थिक सहायता रोक दी। नाइकन्द सम्मेलन में तथा उसके बाद रूस ने भारत और पाकिस्तान के बीच ज्यादा तटस्थता का रुख अपनाया ताकि दोनों देशों का संतुलन बना रहे और चीन का प्रभाव पाकिस्तान पर न बढ़ने पावे। कश्मीर जाग अथ मामला पर मोटे तौर पर जार बातों का समर्थन करते हुए भी सोवियत रूस पाकिस्तान के प्रति समान रूप से मित्रता का व्यवहार कर रहा है और उसे फौजी सामान दे रहा है।

इस प्रकार १९६२ के चीन-युद्ध से भी अधिक पाकिस्तान युद्ध ने भारत की परराष्ट्र-नीति की स्वतंत्रता को घटाया जिससे देश में दोनों बड़े देशों की तरफ से विरक्ति का भाव पैदा हुआ। इससे भारत में इस भावना ने जार पकड़ा कि हमें दुनिया के झगड़ा से दूर रहना चाहिए और युद्ध के बाद जा अधिक मदी और राजनीतिक समस्याएँ उत्पन्न हुईं उनसे भी उपर्युक्त मनोवृत्ति को बल मिला और भारत को अपनी स्थिति के बारे में शका हुई।

पाकिस्तान युद्ध में सफलता पान के बाद भी भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थिति बिगड़ी, यह बात नहीं। वास्तव में ससार की ही स्थिति बढ़त गयी है। शीतयुद्ध की स्थिति अब नहीं रही और दोनों महाशक्तियाँ ने 'तीसरा विश्व' (गुटों से बाहर) देशों के झगड़ा में अपना रुख बदल दिया है और स्वयं एक प्रकार की गुटों से तटस्थता अपना ली है। इस स्थिति में भारत की तटस्थता का महत्व नहीं रहा। जब कोई बड़ा राष्ट्र नहीं चाहता कि भारत उसके गुट में शामिल हो और सभी तटस्थता की बात करते हैं तो भारत की तटस्थता का अर्थ क्या रहा। परंतु भारत कोई दूसरी नीति नहीं निकाल पाया है।

यह बात नहीं कि भारत की बाहरी स्थिति कमजोर हुई हो। प्रत्युत उसकी फौजी और औद्योगिक शक्ति बढ़ी है, पर उसने अपने आदर्श और लक्ष्य में विश्वास खो दिया है और उसका रुख विश्व की समस्याओं में न उलझने का है। पर इसी समय भारत को विश्व-व्यवस्था के प्रति अपनी जिम्मेदारी स्वीकारने की जरूरत है। अपने क्षेत्र और विश्व के बारे में भारत की नीति सही साबित हुई है। यह नीति न केवल उसकी स्वतंत्रता को कायम रखने (जारी दूसरे नए देशों द्वारा उसकी नीति की स्वीकृति) में, बल्कि उस के क्षेत्र की स्वतंत्रता में भी सहायक हुई है। इसलिए उसका वर्तमान उदासीनता का रुख अस्थायी और अवास्तविक है। इस रुख के दो कारण हैं, एक तो भारत को युद्ध का अनुभव न था। दोनों महा



युद्धों की विभीषिका से बह बचा रहा, इसलिए इन दाना युद्ध में उसको गहरा मानसिक धक्का लगा। दूसरे, भारत की आर्थिक स्थिति अभी भी कमजोर है। बड़े देशों की गिनती में आने की संभावना उम्र में है, किन्तु बड़े देश का पद उसे प्राप्त नहीं, साथ ही वह छोटे देश की सुविधा नहीं भोग सकता। इस कारण उसे अपने में अविश्वास और नकार पैदा हो गया है जो उसे बाहरी दुनिया के प्रति एक प्रभावशाली रण अपना देने में रोकता है। पर 'नीच' हो उसका आत्मविश्वास लौटेगा।

मनिक दृष्टि ने भारत ने लगातार तरक्की की है। उसकी फौजी व्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी है। और संभवतः वह पाकिस्तान और चीन दोनों के आक्रमण का एक साथ सामना कर सकता है। वह चाहे तो परमाणु अस्त्र भी बना सकता है। राजनैतिक दृष्टि से भी उसकी स्थिति पहले से अच्छी है। चीन सारे महासागरों से और एशिया के देशों से दूर होना जा रहा है। उसके एक समय के पक्के मित्र बर्मा और इंडोनेशिया और प्रायः सारे अफ्रीकी देश भी उसके गिराफ हो गए हैं। पाकिस्तान भी प्रायः पूरी तरह चीन पर निर्भर हो गया है। पाकिस्तान के भीतर भी लोग सरकार की आलोचना कर रहे हैं कि उसकी भारत विरोधी नीति से उसको ठोस लाभ नहीं हुआ और उल्टे उसकी आत्मनिर्भरता मारी गयी है।

### भारत स्थिरता की शक्ति

अफ्रीकी-एशियाई देशों का भारत की नीति रीति, चीन के मुकाबले अधिक स्वीकार्य है। भारत का यही रुख है कि 'तीसरे विश्व' का सोवियत रुम और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों से संप्रभु बनाए रखना चाहिए। अपनी सारी कठिनाइयों के बावजूद अंतरराष्ट्रीय मामलों में भारत की आवाज समझदारी की आवाज है।<sup>१०</sup> उसने जिस प्रकार अपना लोकतन्त्री ढांचा कायम रखते हुए अपनी आर्थिक कठिनाइयाँ और अन्य समस्याओं का सामना किया है उससे उम्मीदों की प्रतिष्ठा बढ़ी है। सोवियत रुम और अमेरिका की परमाणु शस्त्र नियंत्रण मधि पर दम्तखत करने से इनकार करके उसने दिखा दिया है कि उसे दबाया नहीं जा सकता और जापान की तरह उसकी भी अंतरराष्ट्रीय मामलों में अपनी राय है जिसकी उपस्था नहीं की जा सकती।

किन्तु भारत के सामने अनेक नयी कठिनाइयाँ आई हैं। एक तो यह कि भारत

<sup>१०</sup> कोरिया और इन्डो-चीन में तथा बांग्लादेश में उसने शांति स्थापना में जो योग दिया उस दूसरे देश मानते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री स्टीन रस्किन ने स्वीकार किया कि भारत ने कई बार संयुक्त राष्ट्रों की ऐसी सेवा की है, जो हम नहीं कर सकते थे। देखें-सेमिन्ट्री फ्रेंच जूनियर, 'द एशियन-इस पैर द थ्रू' (न्यूयार्क १९६५)।

ऐसे प्रदेश में स्थिरता और शांति के लिए यत्न कर रहा है, जहाँ क्रांति की आवाज जोर पर है। सारे एशिया के देश चीन से भयभीत हैं। वह हर जगह क्रांति और मुक्ति के आंदोलन को उबसा रहा है। इन में भारत के सीमांत की आदिम जातियाँ भी हैं। पाकिस्तान घरेलू मामला में परिवर्तन और क्रांति विरोधी है, लेकिन वह कश्मीर में और संभवतः सारे भारत में गड़बड़ करना चाहता है। कहा जाता है कि यदि भारत और चीन में सीमा का विवाद न भी होता तो भी इन दोनों में संघर्ष अनिवार्य था।<sup>११</sup> इसी प्रकार यह भी कहा जाता है कि यदि कश्मीर का विवाद तब भी हो जाए तो भारत और पाकिस्तान में मेल नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान की बुनियाद ही भारत के विरोध पर है।<sup>१२</sup>

साम्राज्यवाद विरोधी हाते हुए भी भारत की नीति स्थिरतावादी है। इस विरोधाभास का कुछ प्रतिकार करने के लिए गुटा से तटस्थ होते हुए भी, व्यवहार में भारत ने दक्षिण एशिया में सोवियत प्रभाव की वृद्धि का समर्थन किया है। लाक-तन में आस्था रखने वाले और पश्चिम से हथियारों पर काफी निर्भर भारत के लिए रूस का समर्थन करना आसान नहीं है, खास कर चेकोस्लोवाकिया और पूर्वी यूरोप में साविएत नीति और पाकिस्तान को उससे हथियारों की मज्जाई को देखते हुए। भारत की तीसरी समस्या यह है कि वह आर्थिक विकास और जरूरी माल की सप्लाई के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। इस निर्भरता का मेल राजनैतिक स्वतंत्रता से कैसे बिठाया जाये ?

इन सब कारणों में और चीन व पाकिस्तान से समझौता न कर सकने के कारण अंतरराष्ट्रीय मामलों में भारत को दब कर और संभल संभल कर चलना पड़ता है। १९६६ में अरब और इसरायल के संघर्ष में उसे बाध्य होकर अरबों का पक्ष समर्थन करना पड़ा। जब कि वियतनाम में अमेरिका के युद्ध और चेकोस्लोवाकिया में रूस की फाजी कारबाई का वह खुल कर विरोध न कर सका। वास्तव में तटस्थता की नीति अब स्पष्ट नीति के अभाव और फूँक फूँक कर कदम उठाने में ही रह गयी है। दो युद्धों से और दोना बड़े देशों से उसके मध्य में तनाव आने से जो सबक मिला है, उसको हृदयगम करने में अभी कुछ समय लगेगा। साथ ही आंतरिक स्थिति जब सुधरेगी तभी भारत का आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस बीच सब से बड़ी समस्या आर्थिक स्वावलंबन और स्वतंत्रता प्राप्त करने की है।

### आर्थिक स्वतंत्रता

तजी से औद्योगीकरण के लिए मशीन और पूँजीगत माल की दरकार होनी है

११ लिओनोव- इंडिया चायना ब्रैंड द अफ्रोएशियन "लाक"-कंटेपोरेरी चायना, १९६७।

१२ देखिए, शिशिर गुप्त, इंडियन रिलेशंस विथ पाकिस्तान १९४७-५७ (न दि १९५८)। शिशिर गुप्त अंतरराष्ट्रीय विषयों के प्रमुख आलोचक हैं।

और जब तक यह दश में नहीं जाने लगने दूह बाहर से मगाना जाता है। इसके लिए कई उपाय करने होते हैं। जहाँ अभावस्थान सामान या आयात राशियाँ बढ़ जायेंगी और कच्चा माल मगाना, जो चीजें आयात हानी थी, उतरे देना में बनाना, अधिक नियात कर के विदेशी मुद्रा कमाना और आयात की अधिकता से होनेवाली विदेशी मुद्रा की कमी की पूर्ति के लिए विदेशों से ऋण और मन्त्र लेना तथा विदेशी व्यवसायों को देश में पूँजी लगाने का प्रेरित करता। भारत सरकार द्वारा सभी उपायों से काम लिया है।

### व्यापारिक घाटे की पूर्ति

आयातोंकीकरण के क्रम में बाहर से आयात अधिक होने में विदेशी व्यापार का मतुलन प्रतिबन्धन हुआ जाता है। भारत में आयात-नियान का यह अंतर आयातोंकीकरण के पहले से ही चला आ रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन में हमारा जो पौड पावना जमा हुआ था, वह खर्च होता जा रहा था। देश जब आजाद हुआ तो हमें अनाज और जट व कपास जैसे औद्योगिक कच्चे माल की कमी पड़ी क्योंकि देश की काफी गव स उपजाऊ जमीन पाकिस्तान में चली गयी थी। दूसरी बार १९५१-५२ में कोरिया युद्ध की अवधि को छोड़ कर निर्माण में कोई बड़नी नहीं हुई थी। पहली योजना में गेनी की उपज बढ़ाने पर जोर दिया गया, जिससे अन्न के आयात का खर्च घटे। इस लक्ष्य में काफी गहनता भी मिली। इसके बाद भारी उद्योगों की स्थापना पर ध्यान दिया गया। इस कारण दूसरी योजना की शुरुआत से ही मशीन, यातायात का सामान, रसायन, धातु और धातु के सामान का आयात बहुत बढ़ गया। योजना के उत्तरार्ध में निर्यात भी कुछ बढ़ा, पर आयात और भी बढ़ गया और विदेशी विनिमय का घाटा १६५ करोड़ से बढ़ कर ४०० करोड़ रुपया हो गया।

तीसरी योजना में औद्योगिकीकरण और बड़े पैमाने पर चालू हुआ और देश में प्राविधिक क्षमता या मशीन बनाने वाली मशीन के निर्माण का यत्न किया गया। इससे आयात और भी बढ़ा। इसी के साथ दो सान सूया पडा और दो युद्ध लडने पडे, जिमसे उत्पादन के लक्ष्य पूरे न हा सके। कारखाना के लिए जरूरी सामान बाहर से आयात न हो सवने के कारण, के पूरी क्षमता से काम न कर सके। एक ओर निर्यात घटा और दूसरी ओर जरूरी और गैरजरूरी दोनों तरह का आयात बढ़ा। फौजी सामग्री का आयात भी बड़े पैमाने पर हुआ। जनसख्या की वृद्धि के कारण सब तरह के माल की माग भी बढ़ी।

उपनिवेशी व्यवस्था में, अधीन दश केवल कच्चा जाय अद्ध निर्मित माल बनाते ह और तैयार माल गामक देश से खरीदते हैं। यद्यपि भारत जम मायासपन देश को, जहा औद्योगिक प्रणिभा की कमी न थी, अफ्रीका की तरह पूणत कच्चा

माल देने वाला देश न बनाया जा सका, फिर भी यहाँ का अधिकतर निर्यात चाय, मसाला, तबाकू, काफी, रनिज सूती वस्त्र, जूट और कायर के बने माल का था। इस प्रकार के प्राथमिक उत्पादन का निर्यात घाटे का सौदा होता है क्योंकि तैयार माल बाहर से मगाना पड़ता है। साथ ही कच्चे माल का दाम भी गिरता गया है।

इसलिए भारत ने नए किस्म के इंजीनियरी सामान मशीनी औजार, पेट्रोल पदार्थ, लोहा, इस्पात का कुछ सामान, रसायन आदि का निर्यात बढ़ाने का यत्न किया। आयात का माल भी देश में बनाने की कोशिश की गयी। मशीनी औजार, धातु का मान, रनिज इंधन और परिवहन सामान और कपास, जूट, कागज दफ्ती, रगई और चमड़ा कमाने की सामग्री का आयात घटा।<sup>१३</sup> यह उल्लेखनीय है कि आबादी बढ़ने से मांग भी बढ़ी, पर यह मांग ज्यादातर देशी उत्पादन से ही पूरी हुई। अनुमान है कि चौथी योजना के अंत तक मशीनी औजार की ७५ प्र० श० मांग और विशेष इस्पात और अलमुनियम की शत प्रतिशत मांग देश से पूरी होगी और शायद निर्यात के लिए भी कुछ बच जाए।<sup>१४</sup>

### नए बाजार

विकासमान देश को अपने नए औद्योगिक माल की बिक्री में कठिनाई होती है। एक ओर उसे औद्योगिक उन्नत देशों का मुकाबला करना पड़ता है, दूसरी ओर चुगी और तटकर की बाधा का सामना करना पड़ता है। बने हुए मान की मांग देश में भी काफी होती है और बाहरी आयात न होने से देशी उद्योग को संरक्षण मिल जाता है इसलिए निर्यात बढ़ाने की गरज भी कम होती है। दूसरी ओर पुराने प्राथमिक उत्पादन का निर्यात भी दूसरे अविकसित देशों के माल के मुकाबले के कारण गिर जाता है। इन सब कारणों से भारत ने अपने माल के लिए नए बाजार खोजने पर विशेषकर पूर्वी यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया अफ्रीका और दक्षिण अम

१३ १९५०-१ में ९१६ प्र श मशीनी औजार बाहर से मगाए गए थे। १९५४-६ में यह ४४५ प्र श हो गया और कुछ माल निर्यात भी होने लगा। शक्कर बनाने की मशीन का आयात इसी प्रकार १०० प्र श से घट कर १४ प्र श हो गया, सूता वस्त्र मशीन का १०० से ५६५ प्र श, ट्रका का ३५७ से ०५ प्र श, पेट्रोल पदार्थ (किरोसीन के अलावा) ०१५ से १६ प्र श और अलमुनियम ७४८ प्र श से २९७ प्र श।

१४ धातु के मामले में आयात पर निर्भरता काफी घटा है। उदाहरण के लिए चौथा योजना के अंत तक देशी उत्पादन का उपयोग तस्ते में ५८ प्र श से बढ़ कर ५३८, ब्लैक कार्बन का ५२ प्र श से ८९३ और तांबे का १२५ से २१४ प्र श हो जाने का आशा है। धातु और इंजीनियरिंग माल का निर्यात एशिया अफ्रीका प यूरोप, रूस पूर्वी यूरोप और अमेरिकी देशों में बढ़ा है और व्यापार का अंतर कम हुआ है। संसार अमेरिका को भी भारत निजल क तार के रंगे और कच्कर तथा अन्य चार्ज भेज रहा है। स्टैटमैन वाकली-जन १८, फरवरी १, १९६८।

रीका को माल बेचने का विशेष प्रयत्न किया है। सोवियत संघ, युगोस्लाविया, हंगरी, चेकोस्लावाकिया, पोलंड, पूर्वी जर्मनी, अर्जेंटीना, चिली, समुक्त अरब गणराज्य, ईराक, वर्मा और जापान से जलम अलग व्यापार करार किये गये हैं। युगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया आदि से सरकारी स्तर पर मापेदारी में व्यापार की योजनाएँ बनाई गयी हैं।

विदेशी और भारतीय फर्मों की साझेदारी के उद्योग भी बढ़ रहे हैं और भारतीय फर्मों ने वेनिया, तजानिया, ईरान, मलयेशिया, फिलीपीन, लका और जायरचेंड में उन देशों के व्यवसायों के साझे में उद्योग खोले हैं। अफ्रीका आदि पिछड़े देशों में भारतीय विशेषज्ञ, प्रशासन अधिकारी (नाइजीरिया पूर्वी अफ्रीका) और फौजी अधिकारी (इथियोपिया) काम कर रहे हैं। कांग्रेस में दक्षिण और वामपक्ष के विवाद के बावजूद भारत में अधिक विदेशी पूँजी लग रही है, खास कर उन उद्योगों में जो अब तक आयात पर ज्यादा निर्भर रहे हैं। साधारणतः यह पूँजी भारतीयों के साझे में लगी है।<sup>१५</sup> इस प्रकार देश की आर्थिक व्यवस्था को फैलाने का और नये नये उद्योग चालू करने का यत्न किया गया है। यद्यपि इनका पूरा फल कुछ समय बाद मिलेगा।

इस बीच आधोमीकरण के लिए अभी भी बाहर से मशीन आदि का आयात जारी है। १९५०-५१ में मशीनरी का आयात कुल आयात का १४ प्रतिशत था जो १९६५-६६ में ३० प्रतिशत हो गया। पर सबसे भारी आयात अनाज का था, जो अब खेती का उत्पादन बढ़ने से कम हुआ है पर उर्वरक और खेती के लिए ज़रूरी और सामान का आयात भी हो रहा है। नए उद्योगों की मशीनरी और पुरानी मशीनरी को बदलने के लिए नई मशीनरी का आयात भी ज़रूरी है। देश में बनने वाली मशीनरी में लगने वाले विदेशी पुर्जों को घटाने की कोशिश की जा रही है, नए बाजार खोजने और नया माल निर्यात करने के साथ साथ यहाँ बनने वाले माल की क्वालिटी अच्छी रखने और उत्पादन खर्च घटाने की भी कोशिश हो रही है। नई विधियाँ निकाली जा रही हैं (जैसे आयातित धातु के बदले देशी धातु का प्रयोग)।

बिज्नी की कला में, चाहे वह अपने पक्ष का प्रचार हो, चाहे अपने मातृका, भारतीय कुछ कमजोर पड़ते हैं। दूसरे, योजनाकारों ने नियामक बढाने के बजाय आयात घटाने और आत्मनिर्भर बनने पर ज्यादा जोर दिया था। मगर तीसरी

१५. विदेशी पूँजी को आकृष्ट करने में वह बाधाएँ हैं। परस्पर संदेह, भारत में विदेशी पूँजी की जोखिम का गलत प्रचार और सरकारी निर्णय में देर आदि के कारण विदेशी पूँजी निरुत्साहित होती है। किंतु भारत की यह शर्त बिल्कुल ठीक है कि विदेशी पूँजी ५० प्रतिशत से ज्यादा न हो। देश की आर्थिक व्यवस्था पर विदेशी पूँजीपतियों का आधिपत्य स्थापित नहीं हो सकेगा, जो अनेक देशों में देखने में आता है।

योजना में विदेशी भुगतान के गहरे घाटे के कारण सरकार को निर्यात बढ़ाने पर ध्यान देना पड़ा। हर माल के लिए निर्यात संवर्धन परिपदें बनायीं गयीं, जो बाहरी वातावरण का अध्ययन करती हैं और माल की विस्म पर कंट्रोल रखती हैं। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन जैसे व्यापारिक संगठनों के काम के नीवरसाही ढंग को सुधारा जा रहा है। कंट्रोल ढीले किए गए हैं। निर्यातकों को ऋण दिलाने और उनकी जोखिम की गारंटी देने का प्रबंध किया गया है, जो विदेशों में अपने माल के विज्ञापन व प्रचार के उपाय किए जा रहे हैं।<sup>१६</sup>

### मुद्रा का अवमूल्यन

इन सब उपायों के अलावा एक महत्वपूर्ण नीति निर्णय भी किया गया। यह था जून १९६६ में रुपये का अवमूल्यन। आशा की गई थी कि इससे निर्यात बढ़ेगा और आयात घट जाएगा। इस कदम की देश में तीव्र आलोचना की गई और कहा गया कि सरकार विदेशी दबाव के सामने झुक गयी। पर इस कारवाई का प्रत्याशित परिणाम नहीं निकला। कुछ इस कारण कि अभी भी हमारा ७० प्रतिशत निर्यात पुरानी प्राथमिक चीजों का था, जिनकी मांग पर दाम का अधिक असर नहीं पड़ता। दूसरे नए उद्योगों को काफी सामान आयात करना पड़ता था और इनका दाम बढ़ गया। तीसरे, अवमूल्यन का ही काफी समझ कर सरकार ने निर्यात वृद्धि की अन्य योजनाएं खतम कर दीं। मगर सबसे बड़ा कारण यह था कि सहायता देने वाले देशों ने और विश्व बैंक ने आसान शर्तों पर सहायता देने का अपना वादा पूरा नहीं किया। इन देशों से पहले से पक्की बात नहीं कर ली गई थी। नतीजा यह हुआ कि बाहर से जरूरी सामान न मिलने के कारण उद्योगों की क्षमता बढ़ाई न जा सकी और अवमूल्यन का फायदा न उठाया जा सका।

सरकार का दावा है कि अवमूल्यन का असर हुआ है, और उन चीजों का निर्यात बढ़ रहा है जिनके बनाने में विदेशी सामान की कम जरूरत पड़ती है तथा देशी कच्चे और औद्योगिक माल की सप्लाई बढ़ रही है। लेकिन अर्थशास्त्री इससे सहमत नहीं हैं। जो हो, अवमूल्यन का निर्णय विदेशी दबाव से और बिना उनसे सौदा पटाए अल्दीबाजी में किया गया और उसके साथ और जो कारवाइयां जरूरी थीं, व नहीं की गयीं। इसके विपरीत सी सुब्रमन्यम द्वारा 'नयी वृत्ति नीति' बनायी और मुस्तीदी से अमल में लाई गयी।

<sup>१६</sup> लेकिन अभी भी निर्यात के मामले में भारत बड़ी सुस्ती और कल्पना का अभाव दिखा रहा है। पश्चिम और अमेरिका आदि सभ्य देशों में भारतीय और एशियाई माल का व्यपन का बृद्धि गुणांश है। भारत में कृषि कौशल की कमी नहीं और कोई कारण नहीं कि वह और देशों से पीछे रहे। नेहरू बैक्रेट की मांग दक्षिण कोरिया, जापान और वेनेजुएला से पूरा हो, और भारत पीछे रह जाए, यह अजीब बात है।

## विदेशी सहायता

देश की राजनैतिक व्यवस्था का निमाण उतना कठिन नहीं जितना उसका आर्थिक व्यवस्था का निर्माण। राजनैतिक निमाण देश के लोग की योग्यता, चरित्रबल, सस्था निर्माण की क्षमता पर निर्भर है, जबकि आर्थिक निर्माण के साधन पिछड़े देश में दुर्लभ होते हैं और उन्हें बाहर से लेना पड़ता है। इस कारण विदेशी सहायता परराष्ट्र नीति की एक नयी शाखा बन गयी है। इसका राजनैतिक और आर्थिक प्रभाव केवल पिछड़े देशों पर ही नहीं पूरी विश्वव्यवस्था पर पड़ता है।

विदेशी सहायता से एक बड़ा प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। यह है राजनैतिक स्वतन्त्रता बनाम आर्थिक परनिर्भरता का। विकसित और अर्धविकसित, या विकासमान देशों को स्वतन्त्र और परनिर्भर, दाता और गृहीता देश भी कहा गया है।<sup>१७</sup> सीधा सवाल यह है कि राजनैतिक स्वतन्त्रता का सामंजस्य आर्थिक निर्भरता से कैसे हो सकता है। विदेशी सहायता से होने वाले लाभ जाहिर हैं। इसमें अभाव की तात्कालिक समस्या में राहत मिलती है, सरकार को मीका मिलता है कि वह राजनैतिक समस्याओं पर कुछ ध्यान दे सके, सामाजिक और आर्थिक सुधारों की योजनाएँ चालू कर सके और इस प्रकार जनता को घोर और आश्वासन दे सके कि भविष्य में उसकी मांगें पूरी हो सकेंगी। दूसरी ओर इससे होने वाले नुकसान भी स्पष्ट हैं। इससे आर्थिक प्राथमिकताएँ गड़बड़ हो जाती हैं और बजाय उन कामों को उठाने के जो ज्यादा जरूरी हैं, वे काम शुरू कर दिये जाते हैं, जिनके लिए सहायता सुलभ होती है, बजाय मेहनत करके उत्पादन बढ़ाने के, बाहरी सहायता से काम चलाने की प्रवृत्ति पैदा होती है। इससे आर्थिक विपन्नता बढ़ती है और विशेष आर्थिक और राजनीतिक वर्गों को अधिक फायदा होता है, साधन विशेष कार्यालयों में फँस जाते हैं और नये काम करने या नीति बदलने की गुंजाइश कम हो जाती है और सबसे बड़ी बुराई यह है कि विदेशी सहायता का कभी भरपूर नहीं कि कितनी मिलेगी या न मिलेगी और उसके लिए गिड़गिड़ाना बजिल्लत उठाना पड़ता है, जिससे राजनैतिक सकट खड़े हो सकते हैं। इस तरह विदेशी सहायता से लाभ हानि दोनों हैं पर किसी भी नए देश का इसके बिना काम नहीं चलता।

भारत का भी विदेशी सहायता पर निर्भरता का कटु अनुभव हुआ है। फिर भी इसने इसे तब तक के लिए स्वीकार किया है जब तक उसकी आर्थिक व्यवस्था

<sup>१७</sup> अल्बर्ट जो इश्मान 'अडरडेवल्पमेंट अव्सुदेविल्म टु द प्रेम्पशन आफ चेंज ऐन्ड कन्ट्रोल' (डेन्हास १९६८ पृ. १२५-३७)। इश्मान स्वतन्त्र और निर्भर (परतंत्र) शब्दों का प्रयोग करता है, जो दक्षिण अफ्रीकी साहित्य से लिए गए हैं। दाता और गृहीता शब्दों के लिए दत्त इश्मान और रिचर्ड एम बर्ग, 'फारेन एड ए ट्रिटिक एंड ए प्रोजेक्ट' (एमे इन इन्टरनेशनल न. ९९-प्रिंसटन, १९६८)।

बनने से विकास करने योग्य नहीं हो जाती। विदेशी अर्थिक सहायता लेने पर प्रायः सभी देश सहमत हैं। मउनेद केवल इस बात पर है कि सहायता पूर्वी नदी देशों से ली जान या बनाकर लेनी है। और सहायता देने वाले देशों को किस हद तक उनके उनका या अन्य होने वाले कामों की देखरेख करने दिया जाए।<sup>१८</sup> भारत ने विदेशी सहायता का अपनी अर्थिक योजना और अपनी निर्यात नीति का एक का समना। सहायता देने वाले देशों को नीचे बना अन्य भी। कुछ हद तक यह अन्तरराष्ट्रीय व्यापार और वित्तनीति से प्रभावित भी तो कुछ हद तक नीति युद्ध से था। कुछ हद तक अन्तराष्ट्रीय नीति की भावना से या अपनी विचारधारा का प्रभाव डालने के उद्देश्य से।

हमने देखा है कि जिस प्रकार द्वितीय विश्वयुद्ध और कोरिया युद्ध के समय भारत ने जो पाठ-पढ़ना उन विषयों पर नये कारखाने सहे करने के लिए बाह्य सहायता लेने में तब हो गया। द्वितीय योजना के समय में विदेशी मुद्रा की बहुत कमी पड़ी और काफी बहस-मुबाहला हुआ कि किन योजनाओं को चालू करा जाय या किन्हीं छोड़ दिया जाय।<sup>१९</sup> अन्त में यह तय हुआ कि देश में भारी कारखाने चार मशीनें बनाने की क्षमता स्थापित करनी चाहिए और इसके लिए ठूसु दत्त से सामान उधार पर और कर्ज लेना चाहिए। यह कर्ज बाद में निर्वार्त बना कर चुका दिया जायेगा।<sup>२०</sup> तब से हिन्दुस्तान ने पर्याप्त अधिक मात्रा में विदेशी सहायता ली है। पहली योजना में ३२२ करोड़ रुपये से बढ़ कर दूसरी योजना में यह २५३१ करोड़ और तीसरी योजना में २८३२ करोड़ रुपया हो गई। अनुमान है कि चौथी योजना में चार हजार करोड़ (नये विनिमय दर पर) की जरूरत पड़ेगी।

विदेशी सहायता का विकास नाम भारत के सरकारी उद्योगों और प्रतिष्ठानों में लगा है। पहली, दूसरी और तीसरी योजनाओं में सरकारी क्षेत्रों में विदेशी

१८ १९४८ से १९६४ तक विभिन्न देशों के प्रस्तावों के विवेचन से पता चलता है कि विदेशी सहायता का चर्चा, विदेश नानि मन्त्री कांग्रेस के केवल २ प्र. श. प्रस्तावों में है, जनमत और स्वतंत्र में विजय नहीं और कम्युनिस्ट पार्टी के केवल १२ प्र. श. प्रस्तावों में मुख्यतः उही मुद्दों पर चिन्तकी चर्चा ऊपर है। देखें, बरेन एन्. एल्बमैन, 'ए. पी. डि. इरानना आफ फारेन एड द केम आफ इंडिया (जनल आफ कामनवेल्थ पोलेटिक्स-नं. २ स. १०६६)

१९ देखें-योजना कमिशन के 'अग्रिम दंड प्रामदेकड्म आफ द सेकेंड पारर इयर प्लान' (मई १९५८) तथा 'रिअग्रेशन आफ द फाइव ईयर प्लान-ए रिजून' (मि. १९५८)।

२० इस नीति के समर्थन के लिए देखें के एन. राय और ए. डे. सन- आर्थनोटिज पैटर्न्स आफ ग्रोथ अउर कंडिशन आफ रीगनेड एक्मरोट आर्नेम, आत्मके ईश्वरनामिक पेपम, बारह स. १, पर १९६१।



सहायता का जश क्रमश १२६, ३७ और ३६ प्र श रहा। देखिए सारणी दस १।

## सारणी दस १ - विदेशी सहायता और सरकारी क्षेत्र

| योजना काल     | कुल खच  | विदेशी सहायता | विदेशी सहायता     |
|---------------|---------|---------------|-------------------|
|               | करोड रु | करोड रु       | कुल खच का प्रतिशत |
| प्रथम योजना   | ११६०    | १६६           | १२६               |
| द्वितीय योजना | ३६५०    | १३५२          | ३७                |
| तृतीय योजना   | ६३००    | २४७६          | ३६                |

भारत सरकार - इकनामिक सर्वे १८६५-६६

कुछ तटस्थता की नीति के खातिर और कुछ अमरिका के बढ़ते हुए प्रभाव की राक करने के लिए विदेशी सहायता अनेक देशों से ली गई। सारणी दस २ से पता चलेगा कि पचास प्रतिशत सहायता संयुक्त राज्य अमरीका से मिली है और सोवियत संघ तथा अन्य देशों तथा अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं से। जबकि पश्चिमी देशों की सहायता अनेक कार्यक्रमों में और शिक्षा आदि लोकहितकारी योजनाओं में लगी है। सोवियत सहायता इस्पात और बिजली जैसी विशेष योजनाओं में लगी। जब अमरीका ने बोकारो में इस्पात कारखाने के लिए सहायता के लिए इनकार किया तब सोवियत रूस ने इसके लिए सहायता दी।<sup>२१</sup>

### कर्जों का बोझ

इस सहायता से जहाँ योजनाओं को पूरा करने में मदद मिली वहाँ इससे कर्ज का भारी बोझ भी बढ़ गया। सहायता शब्द से भ्रम होता है कि यह दान है। वस्तुतः इसका अधिकतर भाग उधार सामान या रुपये के रूप में है। (देखिए सारणी दस ३) इसलिए इस कर्ज की अदायगी की रकम भी बराबर बढ़ती जा रही है। १९६०-६१ में यह निर्यात की आमदनी और विदेशी सहायता की राशि का ७८ प्रतिशत थी और १९६५-६६ में १८४ प्रतिशत तथा चौथी योजना में २८ प्रतिशत होगी। (चौथी योजना में जो विदेशी सहायता ली जायगी उसका

२१ पश्चिमी सहायता में भी प्रवृत्ति यह रही है कि अलग अलग देशों से सहायता की बातचीत के बजाय सभी पश्चिमी देशों और अन्तरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा एक सम्मिलित समझौता हो। तदनुसार 'भारत सहायता क्लब' बना जिमनी नियमित बैठक होती है और इसमें भारत की समस्याओं और पिछड़ी कारगुजारी की रोशनी में आगे सहायता देने पर विचार होता है। इसमें विदेशी सहायता की एक सम्पादक रूप मिश्र है और अलग अलग देशों से राजनैतिक मोनभाव की जरूरत कम हो गयी।

३६ प्रतिगत वज्र और सूद की अदायगी में लग जायेगा) भारत ने वज्र या सूद की अदायगी में कभी आनाकानी नहीं की। उसने केवल यही सुविधा चाही है कि सूद की दर कम रहे और अदायगी के लिए अधिक समय दिया जाय।

बहुत दिना तक विदेशी सहायता निर्दिष्ट कार्यक्रमों के लिए मिलती रही। इसके कारण बहुत से नये कार्य और उद्योग स्थापित हो सके लेकिन स्थापित उद्योगों के लिए कच्चा माल और कल-पुर्जों भगाने में दिक्कत पड़ती थी इस कारण जो उद्योग स्थापित हुए वे पूरी क्षमता से काम न कर पाए। फलतः निर्यात यथेष्ट मात्रा में न बढ़ सका और विदेशी मुद्रा की कमी पड़ने के कारण और विदेशी सहायता लेनी पड़ी जिससे भारत सहायता देनेवाले देशों से बंध गया। इधर दोनों ओर से इस कठिनाई का अनुभव किया गया है और विदेशी सहायता खास कार्यक्रमों के लिए बंधी न होकर भारत की जरूरतों के अनुसार खर्च करने के लिए मिल रही है।

मगर इससे एक नई समस्या खड़ी हो गई। पहले जब सहायता किसी खास कार्यक्रम के लिए दी जाती थी तो देने वाले देशों से उसी कार्यक्रम के बारे में विचार विमर्श होता था अब जो साधारण सहायता दी जाती है उसमें देश की पूरी नीति यहाँ तक कि सामाजिक और राजनतिक ढाँचे पर भी बहस होती है। २२ रूस और अमेरिका दोनों ने बहुत से मामलों में हस्तक्षेप किया है। रूसिया ने बोकारो-योजना में भारतीय इंजीनियरों को शामिल करने पर एतराज किया है और रुपये के अवमूल्यन में अमेरिका और विश्व बैंक के विशेषणों का हाथ भी रखा है। इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह हुई कि १९६१/६६ में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय और बाद में भी अमेरिका ने विदेशी सहायता रोक दी जिससे बहुत-सी योजनाओं का काम रुक गया। आदमी और मशीनें बेकार हो गई जिससे आर्थिक मंदी और कष्ट बढ़ा। हाल में रूस ने ऐसे विमान बेचने की काशिग की जो भारत के लिए उपयुक्त नहीं थे। इससे जाहिर होता है कि बाहरी सहायता लेने में, चाहे वह रूस से ली जाए या अमेरिका से कितना खतरा है।

### सहायता का भविष्य

ऐसा जाना पड़ता है कि विदेशी सहायता के दिन बात नहीं हैं। अब जो अमेरिका में शीतयुद्ध प्रायः बढ़ हो गया है। उनमें देगा की भी निम्नी मुद्रा की कठिनाई पड़ रही है। उन्हें दूसरी अंतरराष्ट्रीय विन्नेटिनी में निम्नी है और उनके देश के अन्दर यह भाग हो रही है कि देगा के सहायता देने के वजाय घर की समस्याओं पर ध्यान दिया जाये। देगा के देगा में यह भावना भी है कि हम दूसरे की सहायता में देगा के देगा देने में निम्नी है



इंडोनेशिया और आस्ट्रेलिया से समझौता करना होगा और चीन के प्रति नया रुख लेना होगा और इसी क्षेत्रीय सदस्य में परमाणु बम बनाने के प्रश्न पर विचार करना होगा। सबसे बड़ी जरूरत यह है कि भारत दोनों महाशक्तियों के दबाव को मना करने और उनकी इस क्षेत्र में नीति को अपने हित के लिए इस्तेमाल करने का तरीका निकाले। ऐसा न होने से इन दोनों महाशक्तियों की इस क्षेत्र में उपस्थिति—यह उपस्थिति हमारे चाहने मात्र से नहीं दूर हो सकती, भारत के लिए एक बंधन बन जाएगी।



### भारत की भूमिका

इन समय सारे सप्ताह में राजनैतिक और वित्तीय स्थितियाँ बदल रही हैं। इससे भारत को कुछ समय मिला है जिसमें वह अपनी राजनैतिक और आर्थिक समस्याओं को सुलझा सके। आंतरिक शक्ति बढ़ने से उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका जमा कर सकेगा। यह भूमिका स्पष्ट है और नेहरू ने इसकी परिभाषा कर दी थी। नेहरू की नीतियाँ विश्व की बदली हुई स्थिति में अनुपयुक्त हो सकती हैं किन्तु इससे भारत की भूमिका नहीं बदलती। भारत एक बड़ा देश है, विचारधारा और भूगोल दोनों दृष्टि से उसकी स्थिति महत्व की है, उसमें बड़े राष्ट्र की संभावनाएँ हैं और उसकी जिम्मेदारियाँ भी उठानी हूँ।

इस भूमिका को अदा करने के लिए जीवोगिक शक्ति और राजनैतिक स्थिरता और दृढ़ता ही नहीं, बड़े पैमाने की योग्य शिक्षा भी जरूरी है अर्थात् परमाणु अस्त्र और स्पेलाइट या अंतरिक्ष कार्यक्रम अपने क्षेत्र में सक्रिय नीति और आत्म विश्वासी तथा निमल दृष्टि वाले नेता जो स्थिति को ठीक से समझकर उपयुक्त नीति निर्धारित कर सकें। यह स्थिति भारत की आंतरिक सफलता से प्राप्त होगी, विदेश नीति के दावों से नहीं। यद्यपि दोनों ही क्षेत्रों में उसे कठिन कार्य करना है।

## भविष्य

विभिन्न अध्यायों में हमने जो विवेचन किए हैं और निष्कर्ष निकाले हैं, उनका उपसंहार करते हुए हमें मुख्यतः इस प्रश्न का उत्तर देना है कि भविष्य की क्या संभावनाएँ हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने में हम इस बात से मदद मिल सकती है कि भारत में जिस राज्यव्यवस्था का विकास हुआ है उसने कैसा काम किया है। किंतु इस में एक कठिनाई यह है कि हो सकता है कि आगे जो समस्याएँ आए वे अब तक की समस्याओं से भिन्न हों। वास्तव में राजनैतिक व्यवस्था ज्यों-ज्यों स्थापित होती है, समस्याओं का दायरा भी उतना ही बढ़ता जाता है।

दूसरे शब्दां में इस प्रश्न को कि समस्याओं को सुलझा सकने की क्षमता व्यवस्था में बढ़ रही है या घट रही है इस प्रश्न से जोड़ना होगा कि समस्याएँ वही होंगी या भिन्न।

इस प्रश्न का उत्तर देने में हमें देखना होगा कि विकास का भारतीय ढांचा कैसा रहा है। भविष्य की समस्याएँ क्या हो सकती हैं और इनका सामना करने में कौन-सी नीतियाँ कारगर हो सकती हैं।

### भारतीय ढांचा

हमने देखा है कि सदियों से भारत की पद्धति यह रही है कि यहाँ एक प्रधान राजनैतिक मता के अधीन अनेक प्रकार की व्यवस्थाएँ चलती रही हैं। इसी आधार पर आधुनिक भारत का ढांचा खड़ा हुआ। इस प्रकार के राजनैतिक केन्द्र के विकास में विदेशी शासन, राजनैतिक विचार तथा आधुनिक शिक्षा के प्रभाव ने भी हाथ बटाया, लेकिन इसकी स्थापना तभी हुई जब देश में एक ऐसे शिक्षित नेता या अग्रणी वर्ग का उदय हुआ जो अपने को सारे भारत का प्रतिनिधि समझता था और इस सावदेशिक भावना का स्थापित करने के लिए उसने एक देशव्यापी संगठन का निर्माण किया, जिसमें हर तरह के लोग शामिल हुए। स्वतंत्रता के बाद इस राजनैतिक केन्द्र को और चल मिला। इस संविधान के द्वारा प्रतिष्ठित

किया गया और इसे हर स्तर तथा हर वर्ग में समाविष्ट किया गया। इस प्रकार भारतीय राज्य-प्रवस्था का रूप निम्नरूप है।

तब से निरंतर विभिन्न विधियाँ, प्रक्रियाएँ और कार्यो से देश के विभिन्न तत्त्वों को इस प्रणाली या सर्वोपरी राजनैतिक क्षेत्र में समाविष्ट करने का यत्न किया जा रहा है। इस में समाविष्ट होने वाले विभिन्न वर्गों और तत्त्वों की अपनी विशेषता या स्वायत्तता का भिन्न-भिन्न नहीं, बल्कि इनको मिलाने की कोशिश की जाती है। केन्द्रीय सत्ता को उनके ऊपर बाहरी और विजातीय सत्ता के रूप में नज़र नहीं आता बल्कि यह वाणिज्य की जाती है कि विभिन्न वर्ग और लोग इस व्यवस्था में स्थान पा सकें। मुक्त या गुनी राजनैतिक व्यवस्था का भारत में यही अर्थ है। यह व्यवस्था प्रतिद्वन्द्विता और सपथ का अभाव ही नहीं है, इसमें विभिन्न वर्ग एक दूसरे से गठजोड़ कर सकते हैं और सत्ताधारी तथा प्रतिपक्षी दोनों दल अपने-अपने पक्ष का समर्थन कर सकते हैं।

**राजनैतिक व्यवस्था में विविध तत्त्वों का स्थान**

हमने विस्तार से बताया है कि दलीय प्रणाली और वाणिज्य सत्ताधिकार का समाज के विभिन्न स्तरों का अनुप्राणित करने और उनके समावेशन में क्या हाथ रहा है। इसमें शिक्षा, नगरीकरण, अस्वार, रेडियो आदि प्रचार के साधन आदि से भी अधिक मदद मिली है विभिन्न वर्गों और समूहों के राजनैतिक व्यवस्था में भाग लेने से। भारतीय समाज के विभिन्न तत्त्वों के एकीकरण में राजनैतिक नेता वर्ग का बड़ा हाथ रहा है। इसने विभिन्न समूहों और वर्गों में समन्वित करके, उनके दावा को मान कर या आश्वासन देकर उन्हें राजनैतिक प्रक्रिया, चुनाव, शासन आदि में भाग लेने का प्रेरित किया है और इस प्रकार विभिन्न तत्त्वों को एक सूत्र में जोड़ा है। इस प्रक्रिया में भारतीय संविधान की व्यवस्था ने बहुत योग दिया है। संघीय शासन और दल की प्रणाली में एकीकरण और विवेकीकरण दोनों प्रक्रियाओं का काम करने की गुंजाइश है। प्रधानता या उच्च सत्ता की कल्पना केंद्रीकरण या एक तंत्र से भिन्न है और इसमें मतभेद और भिन्नता को स्थान है। भारतीय समाज के एकीकरण और आधुनिकीकरण के असंगत साधक हैं, स्थानीय या मध्यम स्तर के नेता। वे सभी प्रतिद्वन्द्वी दल और गठबंधनों में काम करते हैं। हमने अध्याय ५ और ८ में बताया है कि किस प्रकार यह नेतृत्व भारत में राजनैतिक दलों की खुली प्रणाली की मूर्ति बनना है, जिसमें सत्ताधारी और विरोधी दोनों समूह एक-दूसरे के वर्ग में रूपांतरित हो जाते हैं।

शासन या सत्ताधारी नेताओं ने अपनी नीतियाँ और कार्यों द्वारा राज्य व्यवस्था के प्रति विभिन्न वर्गों की निष्ठा प्राप्त करने में योग दिया है। विषमता और अन्धकार दूर करने के लिए विभिन्न कानून बनाये गये, गाँवों में विकास की वृद्धि

वि.५ योजनाएँ चालू की गईं, अनेक प्रकार की सघीय और स्थानीय स्वशासन की समस्याएँ कायम की गयीं। इस प्रकार की व्यवस्था अधिकांश मामलों में स्वतः, नीचे से दबाव पड़ने या भाग उठाने के पहले ही की गई, पर इसका लाभ और श्रेय स्थानीय नेताओं को प्राप्त हुआ।

सरकार की इन कारवाइयों का फलस्वरूप पुराने सामाजिक वर्गों, जातियों और फिरका ने राजनैतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया। एक नये नेता वर्ग का प्रादुर्भाव हो गया, जिन्होंने जातीय सभा, पंचायत और सहकारी संगठनों पर धब्बा करके प्रांतीय और राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश कर लिया। नगरों के कुछ नेताओं को भी मिला कर इन्होंने आधुनिकतावादियों का अपदस्त कर दिया। हमने इसे आधुनिकीकरण के द्वारा आधुनिकतावादियों के अपदस्त किए जाने की प्रक्रिया की सत्ता दी है। इसी अर्थ में सत्ता शहरियों के हाथ से निकल कर गांव वालों के हाथ में गई है। इसे जनता के हाथ में शक्ति का जाना या शहर पर गांव की विजय न समझना चाहिए। वास्तव में जिन मूल्यों व पद्धतियों का प्रसार हो रहा है, वे ग्रामीण न होकर शहरी और आधुनिक ही हैं। यह प्रक्रिया भी देश के जीवन के राजनैतिकीकरण का अंग है।

भारत में ऐसा राजनैतिक ढांचा निर्मित हो सका, जिसमें देश की विभिन्न उप-संस्कृतियों और अल्पसंख्यकों की जीवन-पद्धतियों का समाप्त करने की कोशिश नहीं की गयी और राजनैतिक केंद्र ने विभिन्नताओं में सामंजस्य करके, स्थानीय नेताओं के माध्यम से नीचे तक जड़ जमाने का यत्न किया। इस प्रक्रिया में इस बात से मदद मिली कि नए राज्य की स्थापना के पूर्व ही बुनियादी बातों पर मतभेद हो चुका था। इस मतभेद की स्थापना कांग्रेस आंदोलन द्वारा संभव हो सकी और कांग्रेस दल की रीति-नीति द्वारा इसका क्रियान्वयन हुआ। भारत में समाज, मजहब, नस्ल, भाषा आदि की जो विभिन्नता पाई जाती है और जिन्हें हम फूट और अलगाव और संकीर्णता की प्रवृत्ति समझते हैं, वे भी सहमतिक विकास और केंद्र की प्रधानता में सहायक हुईं। नए भारत ने बहुत से लक्ष्यों को एक साथ सिद्ध करने का प्रयास किया, जैसे समाज का पुनर्गठन, आर्थिक विकास और अंतरराष्ट्रीय मामलों में सक्रिय भाग लेना। इनसे उसकी शक्तियां बिखर तां गयीं परंतु दूसरी ओर राजनैतिक चेतना फैलने से राष्ट्र के विभिन्न वर्गों की ओर से जो मांगें उठीं, उन्हें संभालने में भी मदद मिली।

### लोकतंत्र की भारतीय कल्पना

भारत की लोकतंत्र की कल्पना यह नहीं है कि शासक वर्ग एक अव्यवस्थित जनसमूह से शक्ति प्राप्त करे। भारत कई बातों में ऐसे सामूहिक जनराज्य से भिन्न है। साथ ही भारतीय यह भी नहीं मानते कि भारत जैसे पिछड़े देश के लिए

ऐसी मजबूत और तानाशाही सरकार ज्यादा अच्छी है, जो चुनाव और वोट की वजह से बरी हो। कुछ बुद्धिजीवी व्यक्ति ऐसे हैं जो लोकतंत्री राजनीति की अस्थिरता से ऊपर कर मजबूत सरकार को अच्छा समझने लगते हैं। लेकिन ऐसी समसामयिक तानाशाही और मजबूत सरकारों का जो अनुभव हमें पास पड़ोस में हुआ है उससे पता चलता है कि ये सरकारें लोकतंत्री सरकार से कम अयोग्य नहीं हैं। दूसरी तरफ, ये लोकतंत्री सरकारों की तरह अपने का सुधार नहीं सकती। लोकतंत्र में सरकार या शासक दल का चुनाव में हारने का डर लगा रहता है, और यह एकदम गरजिम्मेदारी और निरकुशता का रख नहीं अपना सकती। दूसरी ओर तानाशाही सरकार बौद्धिक वर्ग के असंतोष के बल पर एक बार सत्तारूढ़ हो जाने के बाद बौद्धिकता का जामा उतार फेंकती है और निहित स्वार्थों की कठपुतली बन जाती है। फलतः जनता की स्वतन्त्रता तो मारी ही जाती है, शासन की कुशलता भी नहीं बढ़ती। घाना इंडोनेशिया और पाकिस्तान में यही देखने में आया है। नेपाल और थाई देग की राजाशाही सरकारों ने भी देश में असंतोष शांत करने के लिए लोकतंत्र की कुछ प्रणालियाँ को ग्रहण किया है। मजबूत सरकार का सबसे बड़ा नमूना चीन है। नातिकारी कम्युनिज्म को सस्थागत रूप देने में उसकी जनता को जो कष्ट उठाना पड़ रहा है वह सबविदित है। भारतीय प्रणाली, इनसे बेहतर भले ही न हो लेकिन वह इनसे खराब भी नहीं है और इनका अच्छा विकल्प प्रस्तुत करती है।

‘तीसरी दुनिया’ में दो प्रकार की नातियाँ हो रही हैं। एक वह है जिसमें एक व्यक्ति या बिचारधारा सभी विरोधों और मतभेदों का कुचल कर मारे देश को अपने ढंग पर चलाने की कोशिश करती है। दूसरा तरीका है भारत का, इसमें वर्तमान ढाँचे का बनाये रखते हुए परिवर्तन का स्वागत किया जाता है और इस प्रकार मूल व्यवस्था की संभावनाओं का विस्तार किया जाता है। इस क्रमिक नाति का नाम दिया जा सकता है। इस व्यवस्था में रचनात्मक परिवर्तनों की ज्यादा गुंजाइश होती है और यह तानाशाही या हिंसात्मक नाति से ज्यादा टिकाऊ होती है।<sup>१</sup>

### व्यवस्था की परीक्षा

इस प्रकार के लोकतंत्री क्रमिक नाति की व्यवस्था की असली परीक्षा १९६२ और ६७ के बीच हुई। जब इसे एक के बाद एक लगातार सक्टा का सामना करना पड़ा। दो बार देग के सर्वोच्च पद के नए उत्तराधिकारियों का चुनाव हुआ। यह

<sup>१</sup> इस प्रकार के परिवर्तन को ‘रोमस क्लॉ’ का नाम दिया जाता है—इसमें परिवर्तन पुरानी व्यवस्था की बनाए रखने में सदायक होता है। देखें—चार्ल्स एफ हैकेट और रॉबर्ट एशर, ‘द धूमन रिवोल्यूशन’ कैंट्र एन्ट्रोपोलॉजि पॉप, न ३, जून १९६४।



न केवल नेता या व्यक्ति का परिवर्तन था, वरन् नतृत्व की शैली और उसकी शक्ति का भी परिवर्तन था। इसी के साथ दो पुरानी और महत्वपूर्ण नीतियाँ भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये थीं खेती और औद्योगिक विकास की नीति और दूसरी बापा नीति। ये दोनों नीतियाँ ठीक से कार्यान्वित न हो सकी थीं और इनकी विफलता को नेमो ने अनुभव किया था। यह विफलता और गंभीर हो गयी, जब इसी के साथ देश में लगातार दो साल सूखा पड़ा, आर्थिक मंदी आई, जीवन की अनिवाय आवश्यकता की वस्तुओं के दाम बढ़े। इसके फलस्वरूप जनता में असंतोष बढ़ा, विरोध और प्रदर्शन हुए और सदन पर भी घावा करने का प्रयत्न हुआ।<sup>२</sup> इन्हीं कठिनाइयों के दौरान देश को चीन और पाकिस्तान के आक्रमणों का भी सामना करना पड़ा। पाकिस्तान युद्ध के बाद विदेशी सहायता बंद हो गयी, आयात में कठिनाई पड़ी और विदेशी शक्तियों के दबाव में आकर रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा। १९६७ में जब सूखे, अकाल और बाहरी आक्रमणों के प्रभाव से कठिनाइयाँ बढ़ रही थीं, देश में आम चुनाव हुआ। इसमें कांग्रेस का एकाधिकार टूट गया और राजनैतिक अस्थिरता का युग आया। देश के नतृत्व की यह कठिन परीक्षा की घड़ी थी।

किसी भी व्यवस्था के लिए इन कठिनाइयों का सामना करना आसान न था, खाम कर एक नयी व्यवस्था के लिए जो भयानक गरीबी और पिछड़ेपन से झूझने में आकठ फंसी हुई थी। फिर भी उसने इन समस्याओं का सफलता से सामना किया। दोनों आक्रमणों का सामना किया गया। खेती और औद्योगिक विकास का नीतिगत परिवर्तन किया गया। बापा के विवाद में भी समझौते से काम निकाला गया। नए प्रधान मंत्रियों का चुनाव शांतिपूर्वक हुआ। सब मिलाकर इन अभूत पूर्व संकटों का सामना करने में व्यवस्था सफल रही और उसका बुनियादी ढांचा टूटा नहीं।

इन समस्याओं पर हम विस्तारपूर्वक पिछले अध्याय में विचार कर चुके हैं। यहाँ हम नेतृत्व की शैली और राजनैतिक व्यवस्था के उन तत्त्वों का विश्लेषण करेंगे, जिनसे इन समस्याओं का मुकाबला संभव हुआ। इससे हमें इसकी कम जोरियाँ और मजबूरियों का पता चलेगा, जो भविष्य के लिए काम देगा (नीचे जो

२ ७ नवम्बर १९६६ को गौहत्या के विरोध में एक जलूम निकला, जिसमें शहर उधर के कई दल शामिल थे। इसमें ऐसे लोग भी थे जो देश में फैलते हुए अमनोप और उपद्रवों का लाभ उठाना चाहते थे। इसने सदन पर आक्रमण किया। स्पष्टतः यह सवधानिक व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश थी। यह प्रयत्न विफल हुआ और प्रतिश्रियावादियों की पोल खुल गयी। गृहमंत्री गुलनारीलाल नन्ना को साधुओं के उपद्रव को रोकने में विफलता के कारण हटना पड़ा। देखें—'कांग्रेस मिस्टम आन ट्रायल', एशिया सर्वे आठ, नं. २ फर १९६२।

कहा गया है, वह मोट तौर पर व्यवस्था की साधारण प्रवृत्तिया का सूचक है ।)<sup>३</sup>

### समस्याएँ अलग अलग

भारत में समस्याएँ विभिन्न क्षेत्रों को न ही एक साथ प्रभावित करती हैं, न ही उनकी तीव्रता एक जैसी होती है। यह उन समस्याओं पर भी लागू होता है, जो साथ साथ उठनी हैं। अलग अलग समस्याओं पर विभिन्न राज्यों व दलों का अलग अलग रुख होता है इससे समस्याएँ एकजुट होकर खतरा पैदा करने के बजाय एक दूसरे को काट देती हैं। उदाहरण के लिए खेती और भापा सबंधी नीति के विषय में राज्यों का अलग अलग रुख था। जब केन्द्र इन दोनों समस्याओं में उलझा हुआ था उसी समय दो युद्धों और दो प्रधान मंत्रियों के सफलतापूर्वक चुनाव के कारण देश में एकता बढ़ी और केन्द्र की शक्ति भी बढ़ी। भापा के विवाद से देश की एकता को खतरा पैदा हुआ, किंतु उसी समय पाकिस्तान के आक्रमण के कारण यह विवाद गौण हो गया। इन दोनों समस्याओं में मुख्य पात्रों ने अलग अलग भूमिका अदा की। एक सकट दूसरे सकट से जुड़ न सका।

### बदलता पक्ष

दूसरी बात यह थी कि हर समस्या या विवाद में मुख्य पक्षों की स्थिति बदलती रही। एक ही बात पर अड़ने की प्रवृत्ति नहीं थी। हर प्रश्न को पुनः पुनः परिभाषित करने का प्रयत्न किया गया जिससे मतभेद कम होता गया। और सहमति का क्षेत्र व्यापक करने को प्रोत्साहन मिला। भापा, खेती और उत्तराधिकार (प्रधानमंत्री के) सबंधी प्रश्नों पर अलग अलग नेताओं ने मुख्य भूमिकाएँ अदा की। हर प्रश्न पर बातचीत के नए ढंग और समझौते के नए सूत्र निकाले गए। और जैसे ही एक सूत्र अव्यावहारिक जान पड़ा, उसे छोड़ दिया गया और दूसरा निकाला गया, जैसे भापा सबंधी विवाद में। हर बार परिस्थिति के अनुसार निणय की नई परिपाटी अपनाई गयी। जैसे प्रधानमंत्री के चुनाव में दो बार अलग अलग तरीके काम में लाए गए। इस विषय में एक रूढ़ परंपरा का न होना लाभप्रद सिद्ध हुआ। समस्या का समाधान ढूँढ़ने में मुख्य प्रश्न को प्रक्रिया सबंधी प्रश्नों से अलग करने की सद्प्रवृत्ति दीख पड़ी।

---

३ देखें-रजना कोठारी और थामस हेड्रिक 'राशस्मिण्ड नानत्राशस्मिण्ड देवलपमेंट इण्डिया १९६२-६७' (जर्मिन्स-मैन्डर फार स्टडी आफ डेव सोसा टिप्पणी और इस्टी आफ पोलि स्ट्रैटेज, स्टैनफोर्ड १९६९)। यह निबंध स्टैनफोर्ड युनि में जैमिन्स आम्बट द्वारा आयोजित राजनैतिक विकास सभा सेमिनार में पढ़ा गया था।

## हठवादिता का अभाव

तीसरी बात यह है कि सौदा पटाने या बातचीत करने में कट्टरता और हठ वादिता का रुख नहीं अपनाया जाता। किसी भी विवाद या संकट के समय विरोधी और सत्तारूढ़ नेताओं में काफी भोलभाव होता है। दोनों ही पक्षों के दावा में, उनके दावा में भी जो हिंसा पर उतारू हा, उनके दावा में भी कुछ औचित्य होता है। सौदा करने वालों के हाथ बंधे नहीं रहते, उनके पक्ष अपरिवर्तनीय नहीं होता। मार्गें बटे और से की जाती हैं पर गीध ही स्वर धीमा हो जाता है। मार्गों के ममथन में प्रदर्शन और उपद्रव भी होते हैं, लेकिन वे व्यवस्था को चुनौती का रूप नहीं लेते। साथ ही यह सादेबाजी और दबाव और उपद्रव एक खास प्रश्न को लेकर होते हैं। अलग अलग प्रश्नों को जोड़ कर सरकार को उलटने के लिए स्थायी मोरचेबंदी नहीं की जाती। वस्तुतः मोरचे और गठबंधन टूटते और बनते रहते हैं। कहा जा सकता है कि किसी एक समय में अनेक संकट हो सकते हैं, मगर ये वास्तविक संकट का रूप नहीं ले पाते।

## दलबदल

इन सभी में अतर्निहित निष्ठा में तीव्रता का अभाव है। किसी दल या मोरचे के प्रति अडिग निष्ठा की आशा या भाव नहीं की जाती। हर श्रेणी के राजनैतिक नेता अपना दल या मोरचा आसानी से बदल देते हैं। विचारधारा या सिद्धांत की उपेक्षा कर दी जाती है। जहां १९६७ में कांग्रेस की शक्ति में कमी का कारण आंतरिक फूट और बहुत से लोगों का उससे अलग हो जाना था, वहां गैर-कांग्रेसी मोरचे में परस्पर विरोधी विचारों के दल भी शामिल थे। दलबदल और विरोधी विचारों के दलों के गठबंधन की क्रिया को इस बात से भी मदद मिलती है कि भारत के गांव में रहने वाली अविभाजित जनता राजनीति से अछूती है और राजनैतिक लोगों के दावपेच से ज्यादा मतलब नहीं रखती। इस कारण यहाँ संकट बहुत गंभीर रूप नहीं धारण करने पाते। जनता के विभिन्न वर्गों या श्रेणियों में काफी दूरी रहती है और किसी प्रश्न पर प्रभावित हिंसा का संगठन करना बठिन होता है। इस प्रक्रिया में मध्यवर्ती समुच्चयकों का भी बड़ा हाथ है। इस कारण राजनैतिक व्यवस्था, सामाजिक दबाव से साधारणतः मुक्त रहती है। दूसरी ओर इस कारण यहाँ एकता पर बहुत जोर दिया जाता है। राजनैतिक नेता एकता की अपील करते थकते नहीं। चाहे युद्ध हो या प्रधानमंत्री का उत्तराधिकारी चुनना हो, या कांग्रेस के सामने संकट हो, सब में एकता की दुहाई दी जाती है और इनसे एकता की प्रवृत्ति होती भी है। इन स्थितियों में राजनैतिक व्यवस्था का वास्तविक चुनौती देना आसान नहीं। सहमति या एकरूपता के आग्रह से मांगें दब जाती हैं। संकटों से परिवर्तन और सुधारों को प्रेरणा मिलती है पर उनसे व्यवस्था के बुनियादी

ढाँचे को ओर उसकी आधारभूत सहमति को नुकसान नहीं पहुँचने पाता। व्यवस्था को कायम रखते हुए उसे परिवर्तित स्थितियाँ के अनुकूल बना लिया जाता है।

### व्यवस्था की नुटियाँ

जिस प्रकार व्यवस्था सड़क को पार कर सकी उससे भविष्य के लिए आशा बधती है। लेकिन ऊपर हमने व्यवस्था की जिन विशेषताओं को देखा, वे ही उसकी कमजोरियाँ भी साबित हो सकती हैं। व्यवस्था पर सामाजिक दबाव न होने का ही यह नतीजा हुआ कि देश के आधुनिकीकरण या नवनिर्माण की समस्या को व्यावहारिक दृष्टि से न देख कर किताबी दृष्टि से देखा गया और उसकी योजनाओं पर अमल करने में नीकरशाही ढंग से काम लिया गया। भारत के इतिहास में फूट और पृथक्ता की जो प्रवृत्ति रही है, उसे देखते हुए हर बात में एकता और सहमति पर अत्यधिक जोर देना उचित था, किंतु इसमें जनता के विभिन्न वर्गों से लगातार संपर्क रखने और उनकी भावनाओं को जानने समझने पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया। राजनैतिक दलों और विशिष्ट हिता की संस्थाओं का मजबूत गठन न होने का नतीजा यह हुआ कि गठबन्धन और मोरचे मजबूत नहीं होते। जनता की मांग का दबाव कम होने का एक नतीजा यह भी है कि यहाँ समस्याओं और मतभेदों का ठट कर सामना नहीं किया गया और प्रशासन तथा अन्य क्षेत्रों में सरकार का काम ढीलाढाला रहा।

अब भारतीय राजनीति के क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, नये समूह और दल मैदान में आ रहे हैं और नए मोरचे तथा व्यूहों की संभावनाएँ पैदा हो रही हैं। इस कारण अब तक जो सामाजिक और आर्थिक संघर्ष नीचे दबे रहते थे, वे अब उभड़ कर ऊपर आएंगे और नीतियों को प्रभावित करेंगे। साथ ही जो शहरी मध्यम वर्ग अब तक राजनीति पर हावी था, वह अपदस्थ हो रहा है और उसका असंतोष बढ़ रहा है। फलस्वरूप राजनैतिक विरोध और विभिन्न वर्गों के असंतोष को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। पुराने ढंग से असंतुष्टों की व्यवस्था में स्थान देकर इस विरोध को नहीं संभाला जा सकता। अब समस्याओं और प्रश्नों पर ध्यान देना होगा। इसी के साथ इन विषयों में ठोस कार्रवाई पर ध्यान देना होगा और देखना होगा कि सरकारी योजनाएँ व नीतियाँ कागज पर न धरी रह जाएँ, बरन ठीक से कार्यान्वित हों। इसके पहले कि शिकायत और समस्याएँ बढ़ कर सामाजिक मांग और आंदोलन का रूप धारण करें, उन्हें देखना होगा और ठोस कारगर कार्रवाई करनी होगी।

हमने ऊपर कहा था कि भारत ने क्रमिक क्रांति का तरीका चुना है। यह तरीका हिंसक क्रांति और तानाशाही प्रतिक्रांति दोनों का विकल्प है। मगर इसकी सफलता हमेशा इस बात पर निर्भर नहीं रह सकती कि राजनैतिक विरोध बढ़ा रहे

और मार्गे उग्र न हा तथा सहमति व मर्तक्य का आग्रह पहले जैसा बना रहे। इसकी सफलता अब इस बात पर निर्भर होगी कि व्यवस्था या सरकार लगातार ( रुक रुक कर नहीं ) अच्छा काम करती रहे नेता बड़ी समझदारी से काम ले<sup>४</sup> और अब तक जा उपलब्ध हुई है, उसको नुकसान पहुंचाए बिना परिवर्तन की गति को तेज कर। भारत में स्थिरता व परंपरा को कायम रखते हुए परिवर्तन की जो प्रतिभा है उसको देखते हुए यह काम असंभव नहीं। पर इसे करने के लिए ऐसी भावना जगानी पड़ेगी और ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा, जिसमें ऐसा मालूम पड़ सकता है कि पुरानी व्यवस्था और परंपरा व स्थिरता के मूल्य नष्ट हो रहे हैं।

### नए प्रश्न

भविष्य में जो समस्याएँ उठेंगी वे पुरानी समस्याओं से बिल्कुल भिन्न होंगी। इनको हल करने में अब तक जो क्षमताएँ उत्पन्न हो चुकी हैं, वे सहायक होंगी पर उनसे पूरी तरह काम न चलेगा।

पिछले अध्यायों में हमने नयी समस्याओं की ओर संकेत किया है। जैसा कि हमने देखा, कांग्रेस को मिलने वाले पक्के वोट ४० प्र० श० हैं, यह स्थिर सरकार के लिए काफी नहीं। अय मुख्य दल का आधार अभी ६ से ८ प्र० श० है। जब तक कि ये दल जनता में और गहरे जाने की कोशिश नहीं करते इस स्थिति में परिवर्तन होना कठिन है। कांग्रेस भी अब दो कांग्रेसों में बंट गयी है<sup>५</sup> एक की नेता इंदिरा गांधी हैं, यह पार्टी को सरकार के प्रभाव में रखना चाहता है, और नयी नीतियों के प्रचार का साधन बनाना चाहता है। दूसरा दल कांग्रेस के पुराने सरदारों का है जो संगठन को सर्वाधिक मानता है। कांग्रेस का यह विग्रह अय दल को भी प्रभावित करेगा और संभावना यह है कि यह देश में दो प्रतिस्पर्धी गठबंधनों को जन्म देगा, जिनकी विचारधारा और कार्यक्रम भिन्न होंगे। जागे चल कर इसका परिणाम अच्छा हो सकता है, क्योंकि इससे प्रश्न और नीतियों में स्पष्टता आ सकती है और देश की शिथिलता दूर हो सकती है, पर तात्कालिक रूप से इसने सत्ताछद्म दल के सामने अपनी सत्ता को बनाए रखने की समस्या खड़ी कर दी है। (१९७१ का मध्यवर्षीय चुनाव स्थिरता में सहायक हुआ है, इसमें इंदिरा गांधी के नेतृत्व की कांग्रेस और उसके साथी दलों की उल्लेखनीय जीत हुई है)।

४ इन मुद्दों पर मुझे अल्बर्ट ओ हर्शमैन और चार्ल्स ई लिन्कन के साथ विमर्श से लाभ हुआ है। ये विद्वान आर्थिक विज्ञान पर राजनैतिक और संस्थागत प्रभावों का अध्ययन करते रहे हैं। देखें-लिंडन लिन्कन 'इंडियन प्रोस्पेक्ट्स' (मीमियो, दिम १०६७)। इन अध्यायों को लिखने में मैने गैरी आन्डर्सन से भी विचारविमर्श किया है।

५ देखें, रजनी बोठारा, 'पोलिटिकल चेंज्स इन इंडिया डिहाइन एंड रीकन्स्ट्रक्शन', इन एंड पोलिटी वीरली चार, स ४१, अक्टू ११, १९६०।



राजनैतिक ह्रास शुरू होने लगता है।<sup>६</sup> लेकिन भारत की समस्या यह है कि यहाँ जो अति आधुनिक और नए तत्वा को ग्रहण करने में सक्षम व्यवस्था निर्मित हुई है, उसी के अनुसार यदि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों का आधुनीकीकरण न हुआ, तो इस राजनैतिक व्यवस्था के टूटने का खतरा है।<sup>७</sup> भारत में राजनैतिक गठबन्धन टूटते और बनते रहे और सरकारें बदलती रहें, पर इसमें हो सकता है कि जनता की मुखसुविधा और सामाजिक व आर्थिक विकास में कोई वृद्धि न हो। जनता के असंतोष बढ़ने और उसका दबाव पड़ने से पहले ही यदि इनमें (जनता की भलाई और आर्थिक विकास में) वृद्धि न हुई तो व्यवस्था का टिकना असंभव हो जाएगा। हो सकता है कि जैसे जसे इस के सीमित साधनों पर भार बढ़ने लगे, व्यवस्था की वे नुटियाँ जाहिर हो जाएँ जो अब तक छिपी थीं।

जसा कि हमने तीसरे और चौथे अध्याय में देखा भारत में बहुत से क्षेत्रों में जनता के दबाव के बिना ही प्रगतिशील नीतियाँ शुरू कीं, इससे राजनैतिक व्यवस्था को जनता का समर्थन भी प्राप्त हुआ। तब से व्यवस्था इसी पूँजी से काम चला रही है। लेकिन पिछड़ी उपनव्वियाँ पर सतोंप करने से काम न चलेगा। अब फिर आगे बढ़ने, नई नीतियाँ शुरू करने, नया समर्थन प्राप्त करने और नये गठबन्धन करने की जरूरत है। निरंतर स्थिति का जायजा लेते रहने और नयी समस्याओं के लिए नई नीति और नये कदम उठाते रहने से ही व्यवस्था कायम रह पाएगी। यदि राजनैतिक स्थिरता नयी सफलता को जन्म नहीं देती और व्यवस्था नए परिणाम नहीं दिखाती, तो यह जनता का समर्थन खो देगी जो अब तक उसे प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ है। राजनैतिक व्यवस्था यदि गतिशील न रही तो इसकी जड़ता अंत में प्रतिक्रिया को जन्म देगी।

६. सेमुअल पी. हार्टिंग्टन, पोलिटिकल आउटर इन चेंजिंग सोसाइटीज़ (न्यू हवें और लंदन १९६८)। उसने भारत को अपवाद माना है और उसकी बड़ी प्रशंसा की है - "राजनैतिक रूप से अत्यंत उन्नत देश भी अन्य बातों में पिछड़ा हो सकता है। भारत को पिछड़े देशों का नमूना समझा जाता था—किंतु राजनैतिक संस्थाकरण में भारत ने केवल एशिया अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका से, बल्कि अनेक उन्नत पश्चिमी यूरोपीय देशों से भी आगे था—भारत की स्थिर, कुशल और लोकतंत्री सरकार अपनी स्वाधीनता के प्रथम २० वर्षों में अपनी विकसित राजनैतिक संस्थाओं की विरासत पर अधिक आश्रित थी, नेहरू के चमत्कारी नेतृत्व पर कम।" ध्यान रहे कि हार्टिंग्टन भूत काल में बात करता है। मानो उसे आशा है कि १९६७ के बाद से स्थिति सगव हो रही है।

७. भारत के अर्थ-अध्ययन से पता चला कि आर्थिक आधुनिकीकरण राजनैतिक संस्थाओं की उन्नति और स्थिरता में सहायक है, जबकि पिछड़ापन राजनैतिक अस्थिरता का कारण बन सकता है और उनके साथ चलाता है। पहला बात का उदाहरण मद्रास और दूसरी का उत्तरप्रदेश है। जेम्स-पॉल और ग्राम, 'पोलिटिकल डिस्टेंसिशन, इन्स्टीट्यूशनल इन्वेन्शन एंड स्टैबिलिटी इन इंडिया'—गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नं. १—विंटर १९६०।

## भविष्य की नीतियाँ

हमें अब भविष्य की नीतियों के मवध में भी विवेचन करना है। हम जानते हैं कि बौद्धिक (या वैज्ञानिक) विवेचन राजनैतिक नेता की सूझ और अनुभवजन्य निर्णय का स्थान नहीं ले सकता। अक्सर यह देखा गया है कि राजनैतिक काय कर्ता या नेता वास्तविकता के अधिक संपर्क में रहता है और लोगों की आवश्यकताओं और भावनाओं को ज्यादा समझता है।<sup>८</sup> फिर भी अक्सर ऐसा हुआ है कि नेता की जानकारी पुरानी पड़ जाती है और उसके निर्णय गलत निकलते हैं, और वह नई परिस्थिति का अनुमान करने में चूक जाता है। इसलिए तटस्थ आलाचक्र का विवेचन भी उपयोगी है।

## सुदृढ़ राजनैतिक केन्द्र

व्यवस्था के सुचारु ढंग में चलने के लिए सुदृढ़ और कारगर केन्द्र का होना जरूरी है। यदि सत्ताहट कांग्रेस को अपनी स्थिति बनाये रखना है तो इसे नए माथियों की तलाश करना है और अपने मतदाताओं की संख्या बढ़ानी है। अध्याय ८ में हमने जा विवेचन किया है उससे दो बातें स्पष्ट होती हैं - एक तो निवाचन क्षेत्र में अपना संगठन बढ़ाना (केवल बोट दिवाने वाला पर भरोसा न करना) और दूसरे, ऐसी नीति अपनाना, जिससे वचित और गरीब जनता आकृष्ट हो। पर १९६७ के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है, उसे देखते हुए कुछ और कदमों की भी जरूरत है। भारत में केन्द्र तभी प्रभावी हो सकता है जब वह सघीय सिद्धांत पर अमल करे, राज्यों के प्रति उचित नीति का पालन करे और राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए समान विचार वाले समूहों और दलों से हाथ मिलाने को तैयार हो। अध्याय ५ में हमने भारतीय व्यवस्था में केन्द्र और राज्यों में सहयोग के महत्त्व पर प्रकाश डाला है। केन्द्र के लिए आवश्यक है कि वह राष्ट्रीय नीतियों और समस्याओं के लिए राज्य या प्रदेश के दलों से साथ या गठ-बन्धन करने का तैयार हो। इससे सत्ता का सघन नीतियों के सघन का रूप धारण करेगा और प्रादेशिक पार्टियाँ और राज्यों की विपक्षी दलों की सरकारें केन्द्र से ऐसे मामलों में सहयोग करने को तैयार हो जाएंगी जिनका सबंध एक राज्य या प्रदेश से न होकर सारे देश से हो। ऐसा होने से केन्द्र और राज्यों के बीच समझौता और लेन देन होगा और राज्यों का केन्द्रविरोधी रुख नरम हो जाएगा। ऐसा न होने से केन्द्र की सत्ता कमजोर हो जाएगी।

<sup>८</sup> राजनैतिक की सूझ के मुकाबले आलोचक के निष्कर्ष का क्या भूय है इस पर विचार के लिए देखें-माइकेल ओकशाट- 'पोलिटिकल एजुकेशन'- लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में उद्घाटन भाषण (वैब्रिज १०५१)।



## राज्यों के प्रति नीति

राज्या का किन बाता पर केन्द्र से विरोध हो सकता है, इसकी काफी जानकारी उपलब्ध है और गृह मंत्रालय या मंत्रिमंडल सचिवालय में एक विशेष विभाग होना चाहिए, जो इन बातों का अध्ययन करके राज्या के प्रति उचित नीति तैयार करें। इसी के साथ ऐसी प्रणाली और सस्थाए बनाने की जरूरत है जिससे सभी प्रमुख दलों को सरकारी प्रक्रियाओं में भाग लेने का अवसर मिले। न केवल इस बात की उपेक्षा की गयी है अपितु अक्सर अपने दल वालों के दबाव से केन्द्र ने राज्या के प्रति विरोध का रुख ग्रहण किया है, जिससे इस प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप किए गए हैं कि अमुक वामपन्थ या दक्षिण पक्ष सविधान की व्यवस्था की जड़ खोदने की कुचष्टा कर रहा है।<sup>१</sup> व्यवस्था को कायम रखने की खातिर भी यह जरूरी है कि चुनाव में सफल होने वाली पार्टियों को संवैधानिक तरीकों से अपदस्थ करने या मत्ता से दूर रखने का प्रयत्न न किया जाए, जैसा १९५६ में केरल में और १९६७ में बंगाल में हुआ। दल के हित का ध्यान न रखने की आशा न करते हुए भी, इतना तो कहा जा सकता है कि विपक्षी दलों की सरकार के प्रति केन्द्र न केवल न्याय और ईमानदारी का बर्ताव करे वरन् ऐसा प्रतीत भी हो कि ईमानदारी की जा रही है। यह आदर्श की नहीं समझदारी की बात है और इसी प्रकार के दलों की शक्ति व प्रतिष्ठा बढ़ सकती है।

भारत की राजनैतिक व्यवस्था में एकात्मक शासन की प्रवृत्ति अतर्निहित है। केन्द्र की कमजारी राज्यों के दबाव के कारण न होगी, वरन् उनकी उपेक्षा करने से होगी। अब तक व्यवस्था ने निचले स्तरों पर नए कार्यकर्ताओं या समूहों को राजनीति में आने का मौका दिया है और इस प्रकार राजनैतिक ढाँचे का विस्तार होता रहा है। इससे भी बड़ा जोर कठिन कार्य है, विरोधी तत्त्वों का व्यवस्था में विभिन्न स्तरों पर स्थान देना। ये विरोधी तत्त्व केन्द्र और राज्या में कांग्रेस व विरोधी गुटों से लेकर 'नक्सली' और दक्षिणपन्थी संप्रदायवादी हैं। भारत की संघीय या सबदल व्यवस्था में, इनको स्थान देने की जितनी शक्ति होगी उतना ही इनसे खतरा कम होगा। भारत की क्रमिक विकास पद्धति की यही असली वसूली है।

इसके लिये ऐसे राजनैतिक केन्द्र की आवश्यकता है जिस प्रदेशों में समयन प्राप्त हो। १९६७ से इस केन्द्र पर दबाव बढ़ता रहा है। कांग्रेस के अंतर्विरोध से यह बात हुई कि उससे नीतियों के स्पष्ट होने का मौका मिला, पर केन्द्र या

१. इसी कारण मार्क्स कम्युनिस्टों ने अपने चुनाव कार्यक्रम में केन्द्र-राज्य संबंध के प्रश्न को भी शामिल किया है। कोई कारण नहीं कि यह समस्या व्यक्तिगत बातचीत और लेखन से हल न हो सके। १९६७ के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गैर-वर्गमयी मुख्य मंत्रियों को सर्वोच्च का आश्रय दिया था। यह प्रस्ताव कुछ ठंडा पड़ गया है, इसे जारी रखना चाहिए।

सर्वाच्च स्तर पर इस प्रकार का विरोध अधिक दिना तक चलता रह तो उससे अनिश्चितता पैदा हो जाती है। इसका सबसे अच्छा उपाय है, समान विचार के या निष्ठा के गुटा व दलो का गठबधन। इससे सरकार में स्थिरता आती है और महत्त्वपूर्ण निणय करने और उनको लागू करने की शक्ति प्राप्त होती है। लाकतनी राजनीति सबन यही गठबधन की नीति है। इसमें कठिनाइया भी आती है। एक तो गठबधन के नेताओं का मिल कर 'टीम' की तरह काम करना, दूसर, इस टीम पर विभिन्न स्तरा और वर्गों से दबाव को समालना। ये कठिनाइया स्वाभाविक हैं और यदि सामूहिक नेतृत्व या टीम की भावना कायम रही, तो दूसरी कठिनाई भी सभल जाती है। इस प्रकार प्रदेशा का मिला कर चलने के लिए एक प्रभावशाली केन्द्र का होना आवश्यक है।

### सामाजिक एकीकरण

यही बात सामाजिक एकीकरण पर भी लागू होती है। भारतीय राजनीति की एक कठिन समस्या जा लोकतन्त्र के विस्तार के साथ साथ और कठिन होती जायेगी, अल्पसंख्यक सप्रदायो की विशेषत मुसलमाना की समस्या है, कि वे बराबरी के दर्जे पर सक्रिय नागरिक के रूप में देश की राजनीति में स्थान ग्रहण करें। गावों के मुकाबले शहरों में यह समस्या ज्यादा कठिन होती है। जैसा हमने अध्याय ४ में दखा मुसलमानों में आत्मविश्वास बढा है और उन्होंने अपना राजनैतिक संगठन करना शुरू किया है। पर इसके प्रतिक्रियास्वरूप सप्रदायिक तनाव और संघर्ष भी बढे हैं। जनसंघ से लेकर कम्युनिस्ट और कांग्रेस के एक वर्ग ने भी इसका लाभ उठाने की कोशिश की है। एक तो अभी मुसलमान स्वयं अपनी स्थिति निश्चित नहीं कर पाए हैं, दूसरे पाकिस्तान का भी उनके ऊपर संचाव पडता है। इस स्थिति से राजनैतिक उच्छेदन हुई है। स्थानीय असंतुष्ट और उपद्रवी गुटों के अलावा कुछ राजनैतिक गुट ऐसे भी हैं, जो राष्ट्रीय एकता का भंग करने और केन्द्र को कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी हालत में अल्पसंख्यका की समस्या का सावधानी से अध्ययन करना, नौकरी आदि के मामला में उनकी उचित शिकायतों को दूर करना और राष्ट्रीय हित के लिए उनका सहयोग प्राप्त करना वाछनीय है।

देश में जा और बुनियादी प्रवृत्तिया चालू हैं उनकी ओर ध्यान देना और उनके संघर्ष में उचित नीतियों को तैयार करना भी जरूरी है। ये प्रवृत्तिया जनसंख्या के वितरण, शहरों और गावा के विकास, युवा वर्ग के उपयोग, आर्थिक नीति और विदेश नीति और विदेशी आर्थिक नीति संघर्षी हैं।

देश की जनसंख्या के नगरा और गावा में वितरण के संघर्ष में सावधानी से एक निश्चित नीति बनाना जरूरी है। भारत में गावा की वर्तमान प्रधानता का बनाव

रखते हुए, आधुनिक साधनों से उनकी उन्नति करनी चाहिए और इस प्रकार उनके जरिये देश का तेजी से आधुनिकीकरण करना चाहिए। इसी के साथ साथ महा नगरा और नगरों का ऐसा विकास करना चाहिए कि वे आधुनिकीकरण और प्रगति के केंद्र बन जाए। आधुनिकीकरण के बारे में कुछ लोगों की धारणाओं के प्रति कूल औद्योगिक समाज से उन्नतिशील और संपन्न ग्राम व्यवस्था का कोई विराघ नहीं है। बल्कि ऐसे ग्राम औद्योगिक व्यवस्था के सुदृढ़ आधार हो सकते हैं। १८ वीं और १९ वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यूरोप में नगरों में अफ्रीका की भीड़भाड़ हो गयी और उसमें उनकी जो दुदगा और आर्थिक शोषण हुआ, और परिणामस्वरूप जो उथल पुथल हुई, उसे यहाँ बचाया जा सकता है, और सरकार को उपलब्ध आधुनिक साधनों से नगरों का ऐसा आयोजन किया जा सकता है जिससे देश की शक्ति बढ़े। अगले दो दशकों में भारत में जनसंख्या के वितरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। यह हमारे ऊपर है कि हम इनको ठीक दिशा में ले जाएँ या इन्हें अपना खतरनाक रास्ता पकड़ने दें।

### गावों का ढाँचा

खेती में जो क्रांति हुई है उससे एक प्रश्न यह उठता है कि क्या अग्रगामी इलाकों से पिछड़े इलाकों में इस क्रांति का प्रसार हो रहा है? दूसरा प्रश्न सामाजिक न्याय का है। क्या विकास के इन कार्यक्रमों से गावों के सभी लोगों का, भले ही कम या ज्यादा फायदा पहुंच रहा है? जहाँ ज्यादा और जल्दी नतीजा निकालने की सम्भावना हो, ऐसे क्षेत्रों में भरपूर खेती के साधन जुटाने की नीति में परिवर्तन न करत हुए भी, ऐसी जागृवाई करनी चाहिए कि गावों में विपन्नता और सघन घटे। छोटे किसानों को बड़े किसानों से कुछ ज्यादा बढ़ावा और साधन देने की नीति अपनाई जानी चाहिए और वितरण की ऐसी नीति चालू करनी चाहिये, जिससे बहुसंख्यक भूमिहीन, मजदूर बनने वाला और अधबेकारों को लाभ हो। समाज के गरीब वर्गों पर विकास का क्या बोझ पड़ता है इस ओर ध्यान न देने और सरकारी नीति पर संपन्न वर्गों का प्रभाव होने से अन्य देशों में घटा जनविरोध और आंदोलन हुए हैं। क्रमिक विकास की नीति पर काम रहत हुए भी सरकार को समझ रहे हैं इस ओर ध्यान देना चाहिए। करना अनेक तल्लगाना और नक़्क़लवाडिया सामने आएंगी,<sup>१०</sup> गावों में क्षुध और वंचित वर्गों की भीड़ गहरा

१० स्वतंत्रता के तुरंत बाद अंधे के तल्लगाना इलाके में कम्युनिस्टों के नेतृत्व में सशस्त्र विद्रोह हुआ था। इसे दबा दिया गया। वर्तमान तल्लगाना आन्दोलन से इसका कोई संबंध नहीं। इस प्रकार १९६७ में वामपंथी मोरचे की विजय के बाद पश्चिम बंगाल के अल्पत उग्रवादी कम्युनिस्टों ने नक़्क़लवाडियों में भूमिहीनों के ऊपर धनी जोगेदारों की ज़बान से उग्रत शोष का काम उठा कर सशस्त्र विद्रोह कर दिया। इसे मयुक्त मोरचा सरकार ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की मदद से दबा दिया।

में आएगी और सामूहिक हिंसा की संभावना बढ़ेगी ।

## नगरों का विकास

नगरों का विकास भारतीय आयोजन का सबसे उपश्रित अंग रहा है । कांग्रेस के ऊपर दुर्ग से ग्राम विकास का आदेश हावी रहा है और उसे गाँवों के बोटों की भी चिन्ता रही है, इस कारण शहरों की निरन्तर बिगड़ती हुई हालत पर वह ध्यान नहीं दे सकी । यह सही है कि गाँवों के मुकाबले शहरों जनसंख्या बहुत थोड़ी है फिर भी यह कम नहीं । दूसरे शहर राजनीतिक गतिविधि के केंद्र हैं । गाँवों के संगठना और जातीय संघों के मुख्य केंद्र शहरों में ही होते हैं । प्रादेशिक पार्टियों के मुख्यालय भी यहीं होते हैं । यहां थोड़ी संख्या के आंदोलन भी बड़ा उग्र रूप और शक्ति प्राप्त कर लेते हैं (जैसे बंबई में गिबमोना) । यह संवेदित है कि कलकत्ता में केन्द्रीय सरकार के विरोध का सबसे बड़ा कारण वहां की भयानक समस्याओं की लगातार उपस्था है । इधर छोटे नगरों में जो सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, उनमें भी बहुत कुछ हाथ उनकी गिरती हुई आर्थिक स्थिति और कामकाज के अवसरों का अभाव है ।

पहले तो जरूरत शहरों के गरीब तबकों की दवा मुधारने की है-निम्न मध्यम वर्ग गरीब घरों के विद्यार्थी, अनुसूचित जाति के लोग और कारखानों के मजदूरों के अलावा अन्य प्रकार के मेहनत मजदूरी करने वाले । इसका भार शहरों के अधिक संपन्न वर्गों पर पड़ना चाहिए । दूसरी जरूरत नगरों की स्वशासन संस्थाओं को बड़ा देना है । इन संस्थाओं को विशेषकर बड़े नगरों की संस्थाओं को राज्य सरकारों से स्वायत्तता मिलनी चाहिए और योजना के साधनों में सीधा भाग मिलना चाहिए । नगरों संस्कृति का विकास तभी हो सकता है जब नगर निवासियों का जीवन की सुविधा हो और उनमें अपने नगर के प्रति प्रेम और गौरव का भाव हो । ऐसी नगर संस्कृति राष्ट्र की उत्थिति में महत्वपूर्ण योग दे सकती है ।

## मुद्दावग

भारत के कालेजा व विश्वविद्यालयों की हानत देखकर बड़ी निराशा होती है । उनमें विद्यार्थियों की भीड़, पढ़ाई, खेलकूद चरित्रगठन के साधनों का घोर अभाव, घटिया और मुर्दाबिल शिक्षक और दक्षिणानसी पाठ्यक्रम और पढ़ाई का नीचा स्तर । शिक्षा कमीशन की भारी भरकम रिपोर्ट को अनग अनग भागों में बांट कर एक एक सिफारिश पर बारंबार करने की चाहिए । इसी से सम्बंधित विषय स्कूलों और कालेजों से निकलने वाले विद्यार्थियों का है (अध्याय नौ) । वास्तविकता की पड़ताल से पता होता है कि साधारणतया नया शिक्षार्थी वर्ग उत्साह और आकांक्षा से परिपूर्ण होता है खास कर गरीब विद्यार्थी । परंतु उसके इस उत्साह और आकांक्षा

का जब कोई दिना नहीं मिलनी तब वह हाथ गेर अगामाजिन कारवाया में लग जाता है। केन्द्र में एक गिन्ना और युवा सेवा मन्त्रालय मौजूद है किन्तु युवाओं की सेवा या उनकी शक्ति के उपयोग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। देश के हित में आवश्यक है कि युवाओं के उत्साह, कमठता और प्रतिभा का उपयोग किया जाए। उनमें राष्ट्रीय व्यवस्था को और बल मिलेगा।

### आर्थिक विकास

मुख्य बात यह ध्यान रखने की है कि भारत की राजनैतिक व्यवस्था के भाग्य का निर्णय कारगराना और नेता में होगा। यह इस बात पर भी निर्भर है कि उसकी आर्थिक नीति के निर्माता राजनैतिक प्रश्नों को कितना समझते हैं।

मुख्य प्रश्न ये हैं - (१) आधुनिक टेक्नीक का किम तरह उपयोग करना कि गाँव और शहरों में एक-सा ढाँचा बना रहे। (२) आर्थिक योजनाओं के जरिये किस प्रकार अधिक से अधिक रोजगार बढ़ाया जाये। (३) शिक्षा के प्रसार के साथ साथ रोजगार के अवसर किम प्रकार बढ़ाए जाए। (४) आर्थिक विकास से गाँव और शहरों में जो विषमता उत्पन्न होनी है उसे कैसे रोका जाए। (५) माधनता का किस प्रकार सचय और प्रयोग किया जाए जिससे ये राजनैतिक उद्देश्य सिद्ध हों।

इन प्रश्नों का बिना बिलब दूरदर्शिता से सुलझाना चाहिए। भारत के अर्थवेत्ता और आर्थिक प्रशासक समार में किसी से कम नहीं। शोध और जानकारी प्राप्त करने का उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयत्न किया है, और विकास कार्य के प्राविधिक ज्ञान का प्रयोग करने के लिए काफी कारगर कदम उठाये गये हैं। बस सिर्फ इस बात की है कि समस्याओं के उठने के बाद उनका उपाय करने के बजाय पहले से सावधि विचार कर लये या दीर्घकालिक विकास की नीति बनायी जाए। साथ ही इन समस्याओं का प्रशासन तंत्र के भरोसे न छोड़ दिया जाए। जब जल्दीबाजी में चालू ढंग का काम होता है तब जफमरा के भरोसे काम छानने की प्रवृत्ति और अधिक रहती है और सोचने या नए उपाय करने का कष्ट नहीं उठाया जाता। इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि हर मुख्य योजना या प्रस्ताव की इस दृष्टि से परीक्षा की जाये कि पूरी व्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। योजना कमिशन के पसपेक्टिव प्लानिंग विभाग में या प्रधानमंत्री के सचिवालय में इसके लिए एक राजनैतिक टुकड़ी होनी चाहिए। इसका अध्ययन आर्थिक विकास के राजनैतिक पक्ष का विशेषण होता है।

### विशेष वर्ग

एक तरीका यह हो सकता है कि जनमस्या के विशेष वर्गों के लिए विशेष योजनाएँ बनायी जाएँ—जैसे शिक्षित युवा और शिक्षित बेरोजगार, शहरों का निम्न

मध्यम वर्ग, छोटे और भूमिहीन किसान, अनुसूचित और अल्प छाटी जातियाँ, आदिवासी और अल्पसंख्यक संप्रदाय। आर्थिक विकास से इन वर्गों पर विशेष दबाव पड़ता है, इनकी विशेष समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, जिनसे असंतोष और विरोध बढ़ता है। इसलिए इन वर्गों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

## गंभीर नुस्खा

देश के विकास की समस्याओं में शिक्षा और सावजनिक प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इन दोनों का हास हो रहा है। सब से बुरा हाल है शिक्षा का। प्रायः हर स्तर पर और हर प्रदेश में दकियानुमी पाठ्यक्रम, अशिक्षित अध्यापक, घोर कुव्यवस्था और कल्पनाशून्य नीति है जो हर नयी बात का विरोध करती है। सुधार के उपाय भी सुज्ञात हैं। शिक्षा कमिशन की रिपोर्ट में बहुत सी सिफारिशें हैं, मगर इनको कार्यान्वित करने का कोई जरिया नहीं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय नौकरशाही और अयोग्यता का नमूना है। विश्वविद्यालयों की हालत भी बुरी है। इनके ऊपर शिक्षा अनुदान आयोग की नौकरशाही हावी है। उत्तम अध्ययन का नमूना के रूप में जो जगह शिक्षा केन्द्र खोले गये थे वे भी विश्वविद्यालय के पिछड़ हुए विभागों के ही विस्तार-में हैं। स्कूली शिक्षा की हालत तो कहने लायक नहीं। इसमें तो आमूल परिवर्तन होना चाहिए। मगर जब तक कि शिक्षा मंत्रालय का ढाँचा और उसके कार्यक्रम की प्राथमिकताएँ एकदम नहीं बदल जाती सुधार की कोई आशा नहीं।

सावजनिक प्रशासन का हाल भी बुरा है। ऊपर से जो नई नीतियाँ और साहसिक प्रयोग किए भी जाते हैं वे नौकरशाही के दलदल में फँस कर ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं हो पाते। उदाहरण के लिए, बैंक के राष्ट्रीयकरण के समयको को भी आशंका थी कि इस कारवाई का लक्ष्य पूरा न होगा, क्योंकि बैंक सरकारी विभागों की तरह सुस्ती से काम करने लगेंगे। विदेशी राज्य के समय का प्रशासनिक ढाँचा देश के नवनिर्माण के लिए अनुपयुक्त है। इसके लिए प्रशासिका में विकास के लक्ष्यों में विश्वास और सेवा की भावना हानी चाहिए। नौकरशाही का पूरा ढाँचा, मनोवृत्ति, प्रशिक्षण का ढंग बदलना चाहिए।

यहाँ भी सुधार के उपाय सुविदित हैं। प्रशासनिक सुधार कमिशन और अन्य अनेक जाच कमेटियों ने दुनियादी सुधारों की ओर इंगित कर दिया है। जल्द ही यही है कि भारत सरकार अपनी पूरी शक्ति से इन में से सबसे जरूरी सिफारिशों को कार्यान्वित करे। गृह मंत्रालय ने कई क्षेत्रों में अच्छा काम किया है किन्तु इस अत्यावश्यक विषय पर उसका ध्यान नहीं गया है। मगर कई दृष्टियों से यह जगह सब चीजों में ज्यादा जरूरी है।

## विदेश नीति

बाहरी दुनिया में देश की प्रतिष्ठा में अन्तर्गत आन्तरिक मामला में तभी नीतिमाया का गुण करने का उद्देश्य या निमित्त बन प्राप्त होता है। इस दृष्टि में परराष्ट्र मन्त्रालय का मन्त्र है।

हमने देश की नीति के युग में परराष्ट्रनीति में देश की स्वतन्त्रता और प्रतिष्ठा बढ़ाने में और पुर्ननिर्माण में विदेश-नीति मन्त्रालय सिद्ध हुई थी, यद्यपि हमारा आर्थिक और प्राविधिक आधार कमजोर था और बड़े राष्ट्रों की सहायता से एक नया उदय हुआ गया था। मगर देश में बाह्य में अन्तराष्ट्रीय स्थिति पर हमारी पकड़ बनी पड़ गयी है। हमारे दम्बता का और अपनी गरिमा देने का हम अपना लिया है। नीति और नीतिमान से विराध, शांत युद्ध में सभी आने के बाद अमरीका और रूस दोनों सहमान मन्त्र में परिवर्तन आरम्भ करी बन्धुता के आवाज के लिए इन पर निर्भरता, स अन्तराष्ट्रीय मामला में देश की स्वतन्त्रता कम हुई है। तबिन्ना धर हमारी आन्तरिक स्थिति सुधरी है। राष्ट्र की समस्या अब इतनी विषम नहीं कि कोई देश हमारे ऊपर दबाव डाले, हमारी रक्षा-अवस्था भी ज्यादा मजबूत हुई है, बड़े राष्ट्रों की ओर से हमारा गुणकहमी दूर हुई है हमें वास्तविकता का बोध हुआ है, और अपने ऊपर भरोसा करने की प्रवृत्ति पैदा हुई है।

मगर वास्तविकता का बाध होने का यह मतलब नहीं कि हम डर डर कर चने। हम आत्मनिर्भरता और परराष्ट्र सहायता में स्वतन्त्रता का मूल्य चुकाने का तयार होना चाहिए और अपना प्रभावशाली बनाने का यत्न करना चाहिए। भारत जैसा देश सबसे अलग तरीके से सतता। हम अभी विदेश-शक्ति का पद प्राप्त न कर पाए हैं, किन्तु हमारी औद्योगिक और सैनिक क्षमता का विकास हुआ है और चारा और जो शक्तिशाली की स्थिति है, उसे दगात हुए, हम अपने क्षेत्र में अपना प्रभाव डाल सकते हैं।

ऊपर हमने कहा है कि बाहरी दुनिया में प्रतिष्ठा से आन्तरिक मामला में बल प्राप्त होता है, उसी तरह आन्तरिक नीतिमाया से भी बाहरी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इसलिए आन्तरिक क्षेत्र में हमें जो काम करने हैं, उनका हमारी विदेश नीति से भी सीधा संबंध है।

## विदेशी सहायता

विदेशी सहायता के बारे में भी हम अपना रुख बदलना होगा। अब तक हमारा रुख दूसरे देशों का मुँह जोहने का रहा है। वास्तव में जापान और टेकनीकी दृष्टि से अब हम इतने परमुग्ध नहीं रहें। हमें देश की प्रौद्योगिक क्षमता के विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए और इसी के बल पर अपना आर्थिक विकास करना चाहिए। इसमें विदेशी व्यापार की आमदनी अवश्य सहायक होगी। इसलिए

हमें विदेशों में अपने माल का बाजार राजना चाहिए । ( इससे आंतरिक व्यापार व उद्योग का भी बल मिलेगा । ) अब तक हम विदेशी सहायता की दृष्टि में अपना पायत्रय बनाते रहे हैं, देश की जरूरत का ख्याल रख कर नहीं । हम यह नहीं कहते कि विदेशी सहायता एवदम से बढ़ कर दी जाए, पर हमारा यह जरूर कहना है कि हमें नीक मांगने की मनावृत्ति छोड़ देनी चाहिए और देश की जरूरत का अनुमान कर के उसी आधार पर विदेशी सहायता के लिए सोदा करना चाहिए, और इस व्यापक अंतरराष्ट्रीय नीति के सदृश में देयना चाहिये ।

विदेशी सहायता लेते समय हमें देश पर पड़ने वाले उस के दूरगामी प्रभावों का भी मोचना चाहिए । विदेशी सहायता से होने वाले तात्कालिक लाभ के फेर में हमें देश पर बज्र का भारी भार न लाद देना चाहिए जिसका चुकाते चुकाते नाक में दम आ जाए । आर्थिक विकास के लिए विदेशी सहायता से भी अधिक महत्त्व आत्मसम्मान का है । भारत का भविष्य बहुत कुछ उच्च वर्ग और नेता वर्ग के मनाया पर निर्भर है । सभी आर्थिक परनिभरता से यह मनोबल और आत्मसम्मान क्षीण होता है । इसलिए विदेशी सहायता के साथ यदि ऐसा शर्तें लगायी जाएं जो हमारे आत्मसम्मान के विपरीत हों तो हमें उसे अस्वीकार कर देना चाहिए । यही बात रहितिया या पुराने पड़े विदेशी हथियारों और मशीनों की खरीद के लिए दबाव पर भी लागू होती है ।

### अगला चरण

ऊपर भविष्य की समस्याओं और उन के सदृश में नीतियों पर जो विचार किया गया है उससे यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि विकास के क्रम में कोई अनिवार्यता नहीं है । यह बहुत-सी बातों पर निर्भर है, यदि अमुक बात न की गयी तो अमुक परिणाम निकल सकता है । जब समस्याओं का इस रूप में देखा जाता है कि हमें क्या क्या काम करने हैं तो पता चलता है कि इन में कोई काम असंभव नहीं । इसलिए हमने जो त्रुटियाँ दिखाई हैं, उससे यह न समझना चाहिए कि हम स्थिति को निराशाजनक समझते हैं । हमारी आलोचना को इस पुस्तक में किए गए व्यापक विवेचन के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिये । हमारे विवेचन में भारतीय व्यवस्था की महान क्षमता की ओर इंगित किया गया है और दिखाया गया है कि किस प्रकार १९४७ में भारतीय समाज ने अपने लंबे इतिहास का एक नया अध्याय शुरू किया है और अब तक काफी कर दिखाया है । मगर इस विवेचन में यह भी जाहिर होता है कि अब हम राजनैतिक विकास के एक नए नाजुक दौर में प्रवेश कर रहे हैं, तथा स्थिति पर नए सिरे से विचार करने और नई नीतियाँ शुरू करने की जरूरत है ।

भारत की राजनैतिक पद्धति बुनियादी तौर पर सही है । भारतीय व्यवस्था की



विशेषता और मजबूती उस की विविधता और विभिन्न वर्गों की विशेषता का काम करते हुए उनका राष्ट्रीय धारा में सम्मिलित करने की नीति है। यह उदारता और मनुष्यता की नीति है। मनुष्य को राज्य की मर्जी का पुर्जा बना देने और एक साथ में ढालने की पश्चिम की नीति का अनुकरण हमारे भारताय जाधुनिक्वर्ताओं को न करना चाहिए उनको अपना रास्ता स्वयं निभालना चाहिए। सरम्पण और नवीनता एक ही त्रिया के दो पहलू हैं। बिना नवीनता लाए और परिवर्तन किए, परंपरा का संरक्षण संभव नहीं।

### विशिष्ट वर्ग की भूमिका

भारतीय राजनैतिक व्यवस्था की जड़ें काफी पुरानी हैं, फिर भी इसका नविष्य इसके राजनैतिक प्रशासित और बौद्धिक नेताओं की रचनात्मक प्रतिभा पर निर्भर है।

इसी विशिष्ट वर्ग का यह काम है कि वह स्थिति को समीक्षा करता रहे और नयी स्थितियों के अनुसार नीतियों को बदले और परिवर्तन की गति को तेज करे, तथा देश के विभिन्न वर्गों को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करे। इस काम में नेताओं को परिवर्तन के लिए जातुर और विद्रोह पर उन्मुख बौद्धिक वर्ग, शिक्षित बेरोजगारों की बहुसंख्या भूमिहीन और छोटे किसान और मजदूरों के दल के अंदर जोड़तोड़, विदेशी शक्तियाँ और बौद्धिकों से परामर्श और साधन की योजना और चुनाव में हार का डर छोड़ कर नेताओं को अधिक आत्मविश्वास के साथ काम करना चाहिए।

हमने देखा है कि समय समय पर उठने वाले सफ़ाई से व्यवस्था को कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिली है, किंतु सफ़ाई के नरामे बँडे रहने से समाज में निराशा और व्यवस्था पर अविश्वास बढ़ेगा। जैसा स्वतंत्रता के पहले कुछ वर्षों में किया गया था, आने वाली कठिनाइयों का पहले से अनमान लगा कर उपयुक्त नीति बनानी चाहिए और उसपर अमल करना चाहिए। इससे जब सफ़ाई उठने लगे तो नीति में व्याधान नहीं आता, और राजनैतिक जुआ खेपने की प्रवृत्ति दबती रहती है।

### नेतृत्व की बसोटी

ऊपर जिन समस्याओं का संकेत किया गया है और उनसे निबटने के लिए जिस सक्रिय नीति का और शासन की रीतियों में परिवर्तन का सुझाव दिया गया है, क्या ऐसा करनेकी क्षमता सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेताओं में है? क्या वे नयी नीतियों के लिए संसद और जनता से समर्थन प्राप्त कर सकते हैं? या कांग्रेस में और फूट बढ़ेगी और इससे सरकार में अस्थिरता आएगी? क्या इंदिरा गांधी नयी



रह है। हर जगह विवेक और परिवर्तन की शक्तियों की टक्कर अविवेक और प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तियों से हो रही है। इस विश्व-सदम में भारत की राजनैतिक चुनौती एक व्यापक महत्त्व प्राप्त कर लेती है। यदि जो व्यवस्था इसने अपनायी है वह इन चुनौतियों का सफलता से सामना करती है तो दूसरे देशों में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार यदि यह विफल होती है तो संभव है कि दूसरे स्थानों में भी विवेक और सुधार के समयका की हार हो जाए।

### आदर्श व्यवस्था की ओर

भारत में जो ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है, उसकी प्रेरक शक्ति लोकतन्त्र का आदर्श है। इस आदर्श के प्रति उत्साह को कैसे जीवित रखा जाए, यही प्रश्न है। भारत के महान नेता जवाहरलाल नेहरू के हृदय में यही आग जलती थी कि किस प्रकार राष्ट्र का नवनिर्माण हो, जिससे वह अपने लक्ष्य को पा सके। उनकी मृत्यु के बाद उनकी मेज पर पायी गयी राइट फ्रास्ट की इन पंक्तियों में उनकी यही भावना प्रतिध्वनित होती है—

बुलाता सघन वन ये सुंदर सुहाना  
मुझे किंतु वादे हैं अपने निभाना  
जो सोने से पहले बहुत दूर जाना  
औ सोने से पहले बहुत दूर जाना ।<sup>११</sup>

पश्चिम ने पहले लक्ष्य को पा लिया है और अब इसे इनकी साधकता पर सदेह हो रहा है, किंतु भारत को अभी बहुत दूर चलना है। मजिल कठिन और दूर है, समय कम है और ठाकरें भी लग सकती हैं, मगर इसमें रुकने या सुस्ताने का समय नहीं। नेहरू के शब्दों में, “हमें भारत के भविष्य का निर्माण करना है। मेरे ऊपर, हमारे ऊपर, और इस संसद के ऊपर इतिहास न यह भार डाले। इसी भावना से मैं इस समस्या का सामना करता हूँ।”<sup>१२</sup>

नेहरू के बाद की पीढ़ी पर भी इतिहास का यह भार है। बुजुर्गों के इस महान स्वप्न का साकार करने के लिए इसको इस रूप में देखना होगा कि क्या काम करना है, किन लोगों को साथ लेना है, और फिर मूल-मूल स इनको कार्यान्वित करना है तथा इस प्रकार देश ने जिस व्यवस्था का अपना भाग्य सौंपा है, उसका सफल बनाना है। अतीत का अनुभव इस कार्य में बहुत सहायक होगा, पर वह भविष्य के लिए पूरी तरह पथप्रदर्शन नहीं कर सकेगा।

<sup>११</sup> कण्वीट पोपमम आव राबर्ट फ्रास्ट, स्टायिंग बाइ उन्स आन ए स्नोइ इयर्निंग' बागी राइट १९२३, होन्, रीनाई एड विंस्टन इन बापीराइट १९५१ राब्ट फ्रास्ट, होन् रीनाई एड विंस्टन इन तथा एरॉस पोर्लिनर लि की अनुमति से पुनमुद्रित।

<sup>१२</sup> 'द न्यू शानिया प्रोग्रेस थ्रू डेमोक्रेसी' (दिल्ली-१९५७)।







सारणी पाच ४-१९५२ से १९६६ तक कांग्रेस सरकारा में मंत्रियों में परिवर्तन

| राज्य         | व्यक्तियों में परिवर्तन<br>मुख्यमंत्री | (क)<br>मंत्रिपरिषद्<br>का मंत्री | अवधि |
|---------------|----------------------------------------|----------------------------------|------|
| आम            | १                                      | ६                                | १०   |
| आंध्र प्र     | ३                                      | २६                               | १    |
| उड़ीसा        | ४                                      | २०                               | १    |
| उत्तर प्र     | ३                                      | १५                               | ३३   |
| बंगाल (ग)     | ४                                      | २६                               | —ग   |
| गुजरात        | ५                                      | १८                               | २६   |
| जम्मू-काश्मीर | ३                                      | १६                               | १२   |
| पंजाब         | २                                      | १८                               | २४   |
| प. बंगाल      | १                                      | १६                               | ३४   |
| बिहार         | २                                      | १५                               | २१   |
| मद्रास        | २                                      | १२                               | —ग   |
| मध्य प्र      | ३                                      | १७                               | २०   |
| महाराष्ट्र    | २                                      | २०                               | ३०   |
| मगूर          | १                                      | १८                               | ८    |
| राजस्थान      | १                                      | १८                               | १८   |

क-संविधान संशोधन अधिनियम १९६० के अन्तर्गत राज्य सरकारों में मंत्रियों में परिवर्तन का आँकड़ा है।  
ग-राज्य में इस दिनांक से अंतिम तक मंत्रियों में परिवर्तन का आँकड़ा है।  
घ-राज्य में इस दिनांक से अंतिम तक मंत्रियों में परिवर्तन का आँकड़ा है।

(१९६६-६७ का आँकड़ा १९६७-६८ के लिए है।)

सारणी पाच ५ - पाच राज्यां मध्ये मध्यावधि च्या नाव १९६७ और १९६८-६९

२०  
२०  
२०

| राज्य           | कांग्रेस | कम्युनिस्ट | सोसलिस्ट | जनसंघ     | अन्यदल    | निर्दल    |
|-----------------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|                 | ६७ -- ६६ | ६७ -- ६६   | ६७ -- ६६ | ६७ -- ६६  | ६७ -- ६६  | ६७ -- ६६  |
| हरियाणा स्थान   | ४८       | ४८         | ४८       | ४८        | ४८        | ४८        |
| बोटा प्र स      | ४१ ३३    | ४३ ८८      | ४४ ० ४६  | ३ ७६ ० ६७ | ३ ७६ ० ६७ | ३ ७६ ० ६७ |
| उत्तर प्र स्थान | १६६      | १४         | ४        | ४४        | ४४        | ४४        |
| बोटा प्र स      | ३२ २०    | ३३ ६८      | ४ ४०     | ३ ४४      | ३ ४४      | ३ ४४      |
| बिहार स्थान     | १२८      | ११८        | २८       | २८        | २८        | २८        |
| बोटा प्र स      | ३३ ०६    | ३० ३०      | ३१ ३१    | ३१ ३१     | ३१ ३१     | ३१ ३१     |
| प दगाल स्थान    | १२७      | ४४         | ४४       | ४४        | ४४        | ४४        |
| बोटा प्र स      | ४१ १३    | ४१ ३१      | ४४ ६४    | ४४ ६४     | ४४ ६४     | ४४ ६४     |
| पजाय स्थान      | ४७       | ३८         | ३८       | ३८        | ३८        | ३८        |
| बोटा प्र स      | ३७ ७४    | ३६ १६      | ३६ ७६    | ३६ ७६     | ३६ ७६     | ३६ ७६     |

नोट - हरियाणा में म ग तुनाव १९६८ में हुए थे। कम्युनिस्ट में मार्क्सवादी तथा सोशलिस्ट में स सो तथा प्र सो दोनों शामिल।

वि विमाल हरियाणा १६ स्थान १४ ८६ बोटा प्र स

रव स्वतंत्र १२ स्थान ४ ७३ बोटा, रिपब्लिकन पार्टी १० स्थान ४ १४ बोटा

भा भास्कर ९९ स्थान २१ २२ बोटा

अ क जन प्रति दल १३ स्थान ३ ३३ बोटा

जन जनता पार्टी १४ स्थान ० २८ प्र स बोटा

पा ४ गारुड ब्लक १३ स्थान ४ ४३ प्र स बांगला कमिज ३४ स्थान १० १६ प्र स

रिव रिबोल्युशनरी सोशलिस्ट पार्टी १२ स्थान

अ अमाली २६ सीट २४ ६८ बोटा

अका अमाली ४६ सीट २९ ५९ बोटा

आफडे - रिपोर्ट फोर्मे जेन एलेक्जान १९६७ खड २

( एलेक्जान कमाना १९६७ नई दिल्ली )

पी आर बी भारत सरकार मध्यावधि चुनाव विधानि।



२ गावों गांव ६- गावों गाव १६६७ (प्रतिगाव)

| वर्ष | जनसंख्या | स्वतंत्र | गांव | म.सं. | अ.सं. | निर्वात | मोट नहीं | गांव नहीं |
|------|----------|----------|------|-------|-------|---------|----------|-----------|
| वर्ष | जनसंख्या | स्वतंत्र | गांव | म.सं. | अ.सं. | निर्वात | मोट नहीं | गांव नहीं |

गा १७ में गाव ४३१ ७१ ५१ ४६ ४१ ३० २५ ३४ २६२ ०५

मोट नहीं दिया

गा १७ में गाव ४३१ ७१ ५१ ४६ ४१ ३० २५ ३४ २६२ ०५

मोट नहीं दिया  
(गाव पुर्ण)

१६९७ में गाव- ४०० ८८ ६८ ८७ ८७ ४४ ६० १६७ -१-

मोट नहीं दिया

(क) (गाव पुर्ण)

क-४४ गावों में दो गावों में

ग- ६६ गावों में दो गावों में मोट नहीं दिया। १६ गावों में ३८ गावों में मोट नहीं दिया।  
मोट नहीं दिया।

सारणी पाच ७ — कांग्रेस के विरुद्ध शिकायत से सहमतिया असहमति  
(१९६७)

| शिकायत                                  | जोर से हाँ | हाँ  | नहीं | जोर से नहीं | नहीं जानता |
|-----------------------------------------|------------|------|------|-------------|------------|
| कांग्रेस मूल्यवृद्धि नहीं रोक सकी       | ६१ ०       | २३ ४ | ६ ८  | १ ७         | ७ १        |
| कांग्रेस खाद्य का वितरण ठीक न कर सकी    | ५१ ८       | २३ ७ | १३ ४ | ३ १         | ८ ०        |
| कांग्रेस भ्रष्टाचार का उन्मूलन न कर सकी | ५४ ५       | २२ ६ | ७ १  | २ ०         | १२ ८       |
| कांग्रेस अमन कानून कायम न रख सकी        | ३६ ६       | २८ ५ | १५ ७ | ४ ५         | १४ ४       |
| कांग्रेस ने किसानों की मदद नहीं की      | ३८ ३       | २१ ६ | २१ ६ | ८ ०         | १० २       |
| कांग्रेस देश को दृढ़ नेतृत्व न दे सकी   | ३५ ४       | २७ ५ | १३ ७ | ३ ७         | १६ ७       |

नोट — ये प्रारम्भिक आँकड़े हैं (अधिकतर उत्तरदाता मर्द थे)।

सूत्र — से रट डेव सोमा दिल्ली 'नेशनल एक्स्प्रेस' १९६७

सारणी पाच ८ - पार्टीवार तथा पेशेवार ससद मदस्यो का विवरण ।  
चौथी लोकसभा, प्रतिशत मे

|            | जमीन | राजनैतिक सामा-<br>जिक मजदूर<br>संगठनवाय | व्यावसायिक | डाक्टर इजीनियर | शिक्षा<br>पत्रकारी | व्यापार उद्योग | भूतपूर्व<br>राजा | प्रशासन सेवा | अन्य |
|------------|------|-----------------------------------------|------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------------|------|
| वाप्रेस    | ३६८  | १७०                                     | २२२        | ३८             | ८८                 | ५१             | २५               | २८           | १८   |
| स्वतंत्र   | ४०५  | २४                                      | १२         | ४८             | २४                 | १६७            | ७१               | ७१           | ७१   |
| जनसंघ      | २२८  | १८४                                     | १३         | ३३             | १२८                | १२८            | ००               | ६५           | ६५   |
| कम्यु इ    | १०५  | ७३७                                     | ००         | ००             | १५८                | ००             | ००               | ००           | ००   |
| कम्यु माकम | ००   | ८००                                     | ५०         | ००             | १५०                | ००             | ००               | ००           | ००   |
| ससापा      | ४२१  | ४२१                                     | १३         | ००             | १०५                | ००             | ००               | ००           | ००   |
| प्रसापा    | २३१  | १५४                                     | ३८५        | ००             | १५४                | ००             | ००               | ७७           | ००   |
| द्रमुक     | ३७५  | ८३                                      | १६७        | ००             | १६७                | १६७            | ००               | ४२           | ८३   |
| अयदल       | १३   | २१७                                     | २१७        | ००             | २६१                | १७४            | ००               | ००           | ००   |
| निदल       | १८३  | १२१                                     | १८४        | ६५             | १२१                | १६१            | १२८              | ३३           | ००   |
| योग        | ३१३  | २११                                     | १७३        | ३२             | ११२                | ७८             | २८               | ३०           | २२   |

सूत्र— सत्ता दल, द पार्टी रिप्रेजेंटेशन इन फोरथ लोकसभा इव ऐंड पोलि बॉयली,  
पार, स १—२ जून १९६९ ।

सारणी पाच ६- पिछले अनुभव के हिसाब से सदस्यों का (४ थी लोकसभा) वर्गीकरण, प्रतिशत में

|                        | वाग्रेस | स्वतन्त्र | जनसघ | कम्यु ई | कम्यु माक | ससोपा | प्रसोपा | प्रमुक | अन्य | निर्दल | योग |
|------------------------|---------|-----------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|------|--------|-----|
| पिछला अनुभव            |         |           |      |         |           |       |         |        |      |        |     |
| विधायक के रूपमें       |         |           |      |         |           |       |         |        |      |        |     |
| कुछ नहीं               | १५६     | ६४३       | ४८४  | ४७४     | ४५०       | ४२१   | ३०८     | ३३३    | ३६१  | ३५५    | २६३ |
| केवल केन्द्रीय स्तर पर | २६२     | ६१        | ६१   | २६३     | १००       | ५३    | २३१     | २१०    | २६१  | २६०    | २३७ |
| केवल राज्य तथा केन्द्र | २०६     | ७१        | १६४  | ११८     | ४००       | ३१६   | २३१     | ८३     | १३१  | २६०    | २०१ |
| गांव जिला / म्युनिसि   |         |           |      |         |           |       |         |        |      |        |     |
| राज्य तथा केन्द्र      | ३४३     | १६०       | २१८  | १०१     | १०        | २११   | २३१     | ३३३    | २१७  | १२६    | २६६ |
| मजदूर संगठन            |         |           |      |         |           |       |         |        |      |        |     |
| नहीं                   | ७६८     | ८८१       | ८७१  | २६३     | ३५०       | ४७४   | ६१५     | ७५०    | ७६८  | ८७१    | ७५१ |
| हाँ                    | २१२     | १२०       | १२६  | ७३७     | ६१०       | १२६   | ३८१     | २५०    | २०२  | १२६    | २४१ |
| सहकारी संगठन           |         |           |      |         |           |       |         |        |      |        |     |
| नहीं                   | ७६४     | ८३३       | ६०३  | ६४७     | ६५०       | ८४२   | १००     | ८७५    | १००  | ६३६    | ८४७ |
| हाँ                    | २०६     | १६७       | ६७   | १३      | ५०        | ११८   | ०       | १२५    | ०    | ६५     | २१३ |

ग्रन्थ — रत्ना दत्त, 'द पार्टी डिस्ट्रिब्यूशन इन फोर्थ लोकसभा' शक ऐड पोनि वीकली, चार, स १-२ जुन १९६९।

## सारणी पाच १०—पेशेवार पार्टीवार वोट (प्रतिशत में)

|               | काँग्रेस स्वतंत्र | जनसम | कम्युनिस्ट | वामपंथी | सत्तापक्ष | प्रसाध | द्रमुक | अन्य | निर्दिष्ट वोट नहीं दिया | मतदान नहीं |
|---------------|-------------------|------|------------|---------|-----------|--------|--------|------|-------------------------|------------|
| पेशेवर        | ३८१ ००            | १३२  | २६         | १३      | ७६        | २६     | २६     | २६   | १३२                     | ७६         |
| ग्यापारी      | ४७० १७            | ७७   | ०८         | १७      | ११        | ३६     | २६     | ६०   | ७७                      | ३४         |
| बुद्धिजीवी    | ३१२ १४            | १२१  | २८         | २८      | २८        | ३५     | ०७     | ७१   | ७१                      | १०६        |
| कुशल कामगार   | ३६६ १३            | ६८   | १८         | १३      | ३६        | ८३     | ५३     | ५७   | ६१                      | ५३         |
| मामूली कामगार | ६२६ २२            | ६६   | ३३         | ३८      | ११        | २७     | २७     | ११   | ७७                      | ६६         |
| खुद वास्त     | ६६१ ८६            | ८१   | ३६         | १३      | २०        | २८     | ५६     | ०७   | ६६                      | ६७         |
| खेत मजदूर     | ६४३ ६७            | ४०   | ३६         | २०      | १६        | ५३     | ५७     | ०८   | ६७                      | ५७         |
| बेरोजगार      | २६६ ३६            | ८८   | २८         | २६      | ६८        | २०     | २०     | ६६   | १४७                     | १४७        |

ग्राम—से पार स्ट डेव सोमा दिशी, 'नेशनल एम्प्लायन स्टडी १९७७'। पृष्ठ ७५६।



# सारणी आठ १ - भारत की भाषाएँ । १९६१

| भाषाएँ         | भाषाभाषी<br>संख्या | वाले वाले    | जनसंख्या<br>का प्रतिशत |
|----------------|--------------------|--------------|------------------------|
| भारतीय आय      | १७४                | ३२,१७,२१,००० | ७३.३                   |
| भीतरी उपभाषा   |                    | २१,२४,८२,००० |                        |
| * हिंदी        |                    | १३,३४,३४,००० |                        |
| * उर्दू        |                    | २,३३,३३,०००  |                        |
| * गुजराती      |                    | २,०३,०४,०००  |                        |
| राजस्थानी      |                    | १,४६,३३,०००  |                        |
| * पंजाबी       |                    | १,०६,४१,०००  |                        |
| पहाड़ी         |                    | ८१,६२,०००    |                        |
| अन्य           |                    | ४६,७४,०००    |                        |
| बाहरी उपभाषा   |                    | १०,६२,३६,००० |                        |
| * बंगला        |                    | ३,३८,८६,०००  |                        |
| * मराठी        |                    | ३,३२,८१,०००  |                        |
| बिहारी         |                    | १,६८,०७,०००  |                        |
| * उडिया        |                    | १,५७,१६,०००  |                        |
| * असमिया       |                    | ६८,०३,०००    |                        |
| अन्य           |                    | ३१,६६,०००    |                        |
| द्रविड         | १५३                | १०,७४,११,००० | २४.५                   |
| * तेलुगु       |                    | ३,७६,६८,०००  |                        |
| * तमिल         |                    | ३,०५,६३,०००  |                        |
| * कन्नड        |                    | १,७४,१६,०००  |                        |
| * मलयालम       |                    | १,७०,१६,०००  |                        |
| अन्य           |                    | ४७,४६,०००    |                        |
| आस्ट्रो-एशियाई | ६५                 | ६१,६२,०००    | १.५                    |
| तिब्बती-चिनी   | २२६                | ३१,८४,०००    | ०.७                    |

\* सविधान की ८ वीं अनुसूची में उल्लिखित संसद आक ३६५१, पार्ट दो सी (२) भाषा सारणी । हजार से कम-ज्यादा संख्याएँ हजार बना ली गई हैं ।

# सारणी नं० १ - भारत में नगरीकरण की दर १९०१ से १९६१

| वर्ष | शहरों में जनसंख्या<br>कुल का प्रतिशत | शहरी प्रतिशत<br>में अंतर | शहरी प्रतिशत में<br>अंतर का प्रतिशत |
|------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| १९०१ | १० ८४                                | -                        | -                                   |
| १९११ | १० २६                                | - ० ५५                   | - ५ ०७                              |
| १९२१ | ११ १७                                | + ० ८८                   | + ८ ५५                              |
| १९३१ | ११ ६६                                | + ० ८२                   | + ७ ३४                              |
| १९४१ | १३ ८५                                | + १ ८६                   | + १५ ५२                             |
| १९५१ | १७ २६                                | + ३ ४४                   | + २४ ८४                             |
| १९६१ | १७ ६७<br>(१६ ०४) व                   | + ० ६८<br>(+ १ ७६) व     | + ३ ६३<br>(+ १० १८) व               |

क-परिभाषा में परिवर्तन के हिसाब से ठीक किया, यह मान पर कि शहरों की परिभाषा १९६१ में वही थी जो १९५१ में थी।

आर्थरस बोस, 'सिक्म डिकेड्स आफ् डेवेलपमेन्ट्स इन इंडिया १९०१-१९६१' - द इंडियन इन वेब सोशल हिस्ट्री रिव्यू, वॉल १, जन १९६५।



# सारणी नौ २ - बड़े नगरो मे प्रवास पेशेवार (प्रतिशत)

| नगर        | कास्तकार | खेतमजदूर<br>खेतिहर, मछुए | पेशेवर, क्लर्क,<br>दुकान विक्रेता | खानिक, परिवहन,<br>व्यापार, कारीगर | सेवा, खेल,<br>मनोरजन | अवर्गीकृत<br>कामगार | गैर<br>कामगार |
|------------|----------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| १ बबई      | ० १०     | ० ६५                     | १७ ८५                             | २७ ०१                             | ८ १०                 | ० ०३                | ४६ २६         |
| २ कलकत्ता  | ० ०१     | ० २४                     | २२ ८०                             | २१ २२                             | ८ ३४                 | ० १७                | ४६ १२         |
| ३ दिल्ली   | ० १७     | ० ४६                     | १८ २६                             | १६ ५८                             | ५ ०१                 | ० ०८                | ५८ ४४         |
| ४ मद्रास   | ० ०१     | ० ७५                     | १८ ०५                             | १६ ०८                             | ६ १२                 | ० ११                | ५७ ८६         |
| ५ अहमदाबाद | ० ०४     | ० ६३                     | ११ ८०                             | २६ ८०                             | ४ ३६                 | ० ०१                | ५६ ३६         |
| ६ हैदराबाद | ० २८     | १ ०८                     | १८ ११                             | १५ ८७                             | ६ ६७                 | ० ०३                | ५७ ८५         |
| ७ बंगलौर   | ० ६१     | १ १३                     | १६ ७३                             | १८ ८४                             | ५ २०                 | ० २२                | ५५ ८७         |
| ८ बान्पुर  | ० २२     | ० ६३                     | १३ २७                             | २७ ६३                             | २ ८६                 | ० ७६                | ५४ ५०         |

स्रोत: आर्य समाज १९९१, १ पार्ट दो सी (३) माइग्रेशन टेबुल।

# सारणी नो ३ - गावों में आबादी की घनता और नगरों को चाला

| राज्य        | गावा में घनता (१९६१)<br>कामगार । १००० एकड़ | शहरों में जानेवाली<br>ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| असम          | ६३५                                        | २०१ (२२०४६०)                                      |
| आंध्र        | ४६७                                        | ६२० (१८४२३२८)                                     |
| उड़ीसा       | ४०५                                        | २०६ (३३८२२१)                                      |
| उत्तरप्रदेश  | ५०६                                        | ३२४ (२०८१७८५)                                     |
| केरल         | ४४०                                        | ३२० (४५६६३३)                                      |
| गुजरात       | २४२                                        | ८४७ (१२६७१६३)                                     |
| जम्मू-कश्मीर | ७०६                                        | २३३ (६६२४२)                                       |
| पंजाब        | २४२                                        | ५७० (६२४७८३)                                      |
| प. बंगाल     | ४६०                                        | ८०१ (२११३१७६)                                     |
| बिहार        | ७३७                                        | २६४ (१२४८६६१)                                     |
| मद्रास       | ६०२                                        | ८०४ (१६२६२७६)                                     |
| मध्य प्रदेश  | ३३०                                        | ४२६ (११८१८५२)                                     |
| महाराष्ट्र   | २८१                                        | १२३४ (३५०४८१६)                                    |
| मैसूर        | २८६                                        | ६६६ (१२२०६८२)                                     |
| राजस्थान     | २२६                                        | ३४४ (५८०८६३)                                      |
| पूरा भारत    | ३८६                                        | ५४६ (१६६७६७६७)                                    |

नोट — गावों में घनता का अर्थ है, बोई हुई भूमि से खेतिहरों का अनुपात । प्रतिशत है शहरों को जाने वाला संख्या का गांवों की कुल संख्या का अनुपात । ये आकड़े सेंसर फार स्ट डेव सोसा दिल्ली में संकलित ।

सूत्र भारत सरकार — इण्डियन ऐग्रिकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, १ ( १९६०—६१ ) ।

संसम आफ इण्डिया १९६१ — यूनिशन प्राइमरी सेंसस एक्स्ट्रेक्ट — इण्डिया पार्ट ० ६ ।

संसम आफ इण्डिया १९६१ एक, पार्ट २ सी ( ३ ) माइग्रेशन टेबुलम् ।

सारणी नो ४ - शिक्षा के हिसाब से बेरोजगारों का (१५ वर्ष और ऊपर) प्रतिशत

| राज्य        | अशिक्षित | शिक्षित | प्राइमरी<br>जूनियर | मैट्रिक<br>और ऊपर |
|--------------|----------|---------|--------------------|-------------------|
| असम          | ५१ ०१    | २२ ५१   | १८ ६०              | ७ ८८              |
| आंध्र प्र    | ६ २७     | १३ २१   | ३३ २८              | ४४ २४             |
| उड़ीसा       | २२ ४३    | ३६ ११   | २६ ६७              | १४ ४६             |
| उत्तर प्र    | २६ ४८    | २२ ७६   | २२ १८              | २५ ५८             |
| केरल         | ७ ५४     | २७ ३४   | २० ६७              | ४४ ४५             |
| गुजरात       | २५ ७५    | १६ ७४   | ४७ २६              | १० २५             |
| जम्मू-कश्मीर | २७ ००    | २१ ७१   | २१ १८              | ३० ११             |
| दिल्ली       | २० ८१    | १६ ६१   | १८ ८३              | ४० ४५             |
| पंजाब        | १६ ६६    | ८ २६    | ३० ६१              | ४४ १४             |
| पश्चिम बंगाल | २६ १३    | २७ ६१   | २६ ६८              | १६ २८             |
| बिहार        | २६ ४२    | २५ ४२   | २२ ६२              | २५ ५४             |
| मद्रास       | ११ ५६    | २४ १०   | ३१ ३७              | ३२ ६४             |
| मध्य प्रदेश  | २७ ६२    | ३२ ६४   | २४ ६२              | १४ ८२             |
| महाराष्ट्र   | २३ ३०    | १६ ३६   | ४० ५७              | १६ ७७             |
| मैसूर        | १६ ५७    | २६ ०७   | १६ ६६              | ३४ ७०             |
| राजस्थान     | ३५ ६६    | ३६ ३७   | ७ ०६               | १७ ६१             |
| भारत         | २२ २५    | २४ ०३   | २८ २१              | २५ ४७             |

स्रोत: माफ इंडिया १९६१, १ पाठ २ बी (३) जनरल इकनामिक टेबुलस।

सारणी नौ ५ - रोजगार दफ्तरो के चालू रजिस्टर में दर्ज उम्मेदवार पेशे के हिसाब से

|                                                   | दिसम्बर १३, १९६६<br>को दर्ज सख्या | कुल का<br>प्रतिशत |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| पेशेवर, शिल्पिक<br>आदि                            | १५३०५८                            | ५ ८               |
| प्रशासन, प्रबंध<br>अधिकारी                        | ४३६४                              | ० २               |
| कलक, विक्रेता आदि                                 | ६४३१६                             | ३ ६               |
| खेतिहर, दूधिया आदि                                | ६७०२                              | ० ४               |
| खनक                                               | २४८१                              | ० १               |
| परिवहन, संचार                                     | ६२११६                             | २ ४               |
| कारीगर, मिस्त्री                                  | १६५३२३                            | ७ ४               |
| रसोइया चौकीदार<br>जमादार                          | ६६५३६                             | ३ ८               |
| भजदूर (अवर्गकृत)<br>किसी पेशे के<br>अनुभव से रहित | १०३३७१                            | ३ ६               |
| क - मैट्रिक से कम<br>तथा अपढ                      | ११७३७६४                           | ४४ ८              |
| ख - मैट्रिक तथा<br>अडर ग्रेजुएट                   | ६५०८०२                            | २४ ८              |
| ग - ग्रेजुएट और<br>ऊपर                            | ७३१६६                             | २ ८               |
| योग                                               | २६२२४६०                           | १०० ०             |

सारणी नं० ६ - बड़े नगरों में प्रवासी उम्र के हिसाबसे ( प्रतिशत )

| नगर        | ०-१४ वर्ष | १५-३४ वर्ष | ३५-५६ वर्ष | ६० वर्ष<br>और ऊपर | उम्र नहीं<br>बताई |
|------------|-----------|------------|------------|-------------------|-------------------|
| १-बंबई     | १५ ०२     | ५१ ४१      | २६ ४६      | ४ ०६              | ० ०२              |
| २-कलकत्ता  | १४ २५     | ४८ ५८      | ३२ ८१      | ४ ३५              | ० ०१              |
| ३-दिल्ली   | १६ ४०     | ४८ ५५      | २६ ४०      | ५ ६३              | ० ०२              |
| ४-मद्रास   | १५ ६२     | ४८ ३५      | ३० १४      | ५ ८८              | ० ०१              |
| ५-अहमदाबाद | १८ ६४     | ४६ २३      | ३० ७२      | ४ ४०              | ० ०१              |
| ६-हैदराबाद | २१ ०२     | ४८ ३०      | २५ ८०      | ४ ८८              | ० ००              |
| ७-बंगलौर   | १८ २१     | ४८ २४      | २७ ६७      | ५ ८७              | ० ०१              |
| ८-कानपुर   | १५ ५०     | ४६ ६०      | २६ ६६      | ४ ६३              | ० ०१              |

संलग्न १९८१ १ पार्ट २ से ( ३ ) माइग्रेशन टेबुलस।

सारणी नौ ७ - उम्र के हिसाब से बेरोजगारों का प्रतिशत १९६१

| राज्य        | १५-३४ वर्ष | ३५-५६ वर्ष | ६० और ऊपर | उम्र नहीं बताई गई |
|--------------|------------|------------|-----------|-------------------|
| असम          | ७५ ६४      | १६ ५४      | ४ ७८      | ० ०४              |
| आंध्र प्र    | ८८ २०      | १० ८२      | ० ६७      | ० ०१              |
| उड़ीसा       | ८२ ४५      | १५ ७२      | १ ७४      | ० ०६              |
| उत्तर प्र    | ८२ ७६      | १४ ६४      | २ २३      | ० ०४              |
| पेरल         | ८६ ६६      | ६ ६४       | ० ६८      | ० ०२              |
| गुजरात       | ७७ ४१      | १६ ६५      | २ ६२      | ० ०२              |
| जम्मू-कश्मीर | ८३ ६७      | १५ ०१      | १ २५      | ० ०७              |
| दिल्ली       | ८५ ५०      | १३ ०३      | १ ४७      | ० ००              |
| पंजाब        | ६० १७      | ७ ७०       | २ १०      | ० ०३              |
| प बंगाल      | ७६ ०८      | २१ २६      | २ ६२      | ० ०१              |
| बिहार        | ८६ ४१      | १२ ००      | १ ५४      | ० ०५              |
| मद्रास       | ८६ ६२      | १२ १३      | १ २४      | ० ०१              |
| मध्य प्रदेश  | ८० ६१      | १७ ०२      | २ ३५      | ० ०२              |
| महाराष्ट्र   | ८१ ०६      | १६ ४३      | २ ४६      | ० ०२              |
| मैसूर        | ८७ ६५      | ११ ५६      | ० ७१      | ० ०८              |
| राजस्थान     | ७१ ८२      | २४ ००      | ४ ०१      | ० १७              |
| भारत         | ८२ ३०      | १५ ६५      | २ ०३      | ० ०२              |

सेंसस ऑफ इंडिया १९६१ १ पार्ट २बी (३) जनरल इकनामिक टेबुलस पृ ५४०-१७६ और ६०१-६२१।

सारणी नौ ८ — माध्यमिक शिक्षा में छात्र-संख्या सामान्य और व्यावसायिक

| वर्ष         | संयुक्त वय वर्ग का प्रतिशत |          |      | कुल छात्र संख्या का प्रतिशत, व्यावसायिक शिक्षा में |          |      |
|--------------|----------------------------|----------|------|----------------------------------------------------|----------|------|
|              | लड़के                      | लड़कियाँ | जोड़ | लड़के                                              | लड़कियाँ | जोड़ |
| वर्षा ८ — १० |                            |          |      |                                                    |          |      |
| १९५०-५१      | १० ६                       | १ ८      | ६ ५  | २ २                                                | ८ ८      | ३ १  |
| १९५५-५६      | १४ ६                       | ३ ३      | ६ ३  | २ ०                                                | ७ ६      | ३ ०  |
| १९६०-६१      | २० ४                       | १ ४      | १३ १ | २ २                                                | ४ ७      | २ ७  |
| १९६५-६६      | २८ ७                       | ६ १      | १६ १ | १ ६                                                | ३ ३      | २ २  |
| १९७०-७१      | ३४ २                       | १२ २     | २३ ४ | ३ ४                                                | ५ ०      | ३ ८  |
| १९७५-७६      | ४० ८                       | १६ ६     | २६ १ | ६ ०                                                | ७ ६      | ६ ४  |
| १९८०-८१      | ४६ १                       | २२ ६     | ३६ ३ | ११ ०                                               | १२ ४     | ११ ४ |
| १९८५-८६      | ६० ४                       | ३० ४     | ४६ ० | २० ०                                               | २० ०     | २० ० |
| वर्षा ११-१२  |                            |          |      |                                                    |          |      |
| १९५०-५१      | ३ ३                        | ० १      | १ ६  | ४२ ७                                               | १३ ६     | ४४ २ |
| १९५५-५६      | ५ २                        | ० ६      | ३ १  | ४१ ६                                               | ४६ ४     | ४२ ७ |
| १९६०-६१      | ८ ०                        | १ ६      | ४ ६  | ४१ ७                                               | ४४ ६     | ४२ २ |
| १९६५-६६      | ११ ५                       | २ ३      | ० ७  | ४० ७                                               | ३८ ५     | ४० ३ |
| १९७०-७१      | १४ ६                       | ३ ५      | ६ २  | ४२ ५                                               | ४० २     | ४२ १ |
| १९७५-७६      | १७ ०                       | ४ ८      | ११ ० | ४६ ३                                               | ४४ १     | ४५ ६ |
| १९८०-८१      | २१ ७                       | ७ ४      | १४ ८ | ४८ १                                               | ४७ २     | ४७ ६ |
| १९८५-८६      | २८ ८                       | ११ ४     | २० ४ | ५० ०                                               | ५० ०     | ५० ० |

स्रोत: आर्य द एजुकेशन कमिशन (मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फार्म ए १०५०-५१ से १९६०-६१ के आधार पर)।

## सारणी दस १ - विदेशी सहायतापर सरकारी क्षेत्र की निभरता

| याजना अवधि  | कुल विनियोग<br>करोड रु में | काम में लगी<br>विदेशी सहायता<br>करोड रु | विदेशी सहायता<br>कुल विनियोग के<br>प्रतिशत में |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| पहली याजना  | ११६०                       | १२६६                                    | १२६                                            |
| दूसरी योजना | ३६५०                       | १३५२                                    | ३७                                             |
| तीसरी योजना | ६३००                       | २४७६                                    | ३९                                             |

गवर्मेण्ट आफ इण्डिया इकनामिक्स सर्वे १०६५-६६।

## सारणी दस २ - विदेशी सहायता के स्रोत

| स्रोत             | तीसरी याजना के<br>अत तक स्वीकृत राशी<br>वास्तविक कुल का<br>करोड रु प्र न |        | तीसरी योजना के अत तक<br>उपयोग<br>वास्तविक कुल का प्र न |        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|--------|
| स रा अमेरिका      | ३०२७ १२                                                                  | ५१ ५५  | २५८८ १८                                                | ५७ ३२  |
| मावियत सघ         | ४८६ २७                                                                   | ८ ३३   | २८७ ०४                                                 | ६ ३६   |
| आइ बी आर डी       | ४६२ ८१                                                                   | ७ ८८   | ३७६ ६८                                                 | ८ ४२   |
| जमन संधीय गणराज्य | ४४६ ६६                                                                   | ७ ६६   | ३४७ ३३                                                 | ७ ६६   |
| ब्रिटेन           | ३६६ ४३                                                                   | ६ २४   | २६३ ५३                                                 | ६ ५०   |
| आइ डी ए           | २७८ ५५                                                                   | ४ ७४   | २०० ६३                                                 | ४ ४४   |
| कनाडा             | २२२ ४३                                                                   | ३ ७६   | १६१ ६१                                                 | ३ ५८   |
| जापान             | १७४ ०१                                                                   | २ ६६   | ११३ ३५                                                 | २ ११   |
| अन्य              | ४०२ ०६                                                                   | ६ ८५   | १४३ ४६                                                 | ३ १८   |
| योग               | ५८७२ ६४                                                                  | १०० ०० | ४५१५ ११                                                | १०० ०० |

गवर्मेण्ट आफ इण्डिया इकनामिक्स सर्वे १०६६-६७।



### सारणी दस ३ - प्राप्त विदेशी सहायता, वापसी के तरीके के अनुसार

| वापसी का तरीका                           | पहली योजना के अंत तक | अवमूल्यन के पहले की दर पर करोड़ रुपए में |                      | योग              |
|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------|
|                                          |                      | पहली योजना के दौरान                      | दूसरी योजना के दौरान |                  |
| क - विदेशी मुद्रा में चुकाए जाने वाले ऋण | १२४.१३ (६१.१४)       | ६०७.६३ (४२५.१)                           | १७५२.०६ (६१०७)       | ३१४६.३८ (५६१.४)  |
| ख - रुपये में चुकाए जाने वाले ऋण         | २.२६ (१.१४)          | ११६.८२ (८.१७)                            | १५६.३६ (५.४५)        | २८३.६६ (५.१०)    |
| ग - अन्य सहायता (अ)                      | १.०७ (२.१५)          | ५४६.८१ (३८.०६)                           | ८५३.२२ (२६.७४)       | १७२४.६० (३१.००)  |
| घ - अनुदान                               | ७०.१८ (३४.८०)        | १६०.६४ (११.२३)                           | १०७.१७ (३.७४)        | ४०६.५२ (७.३६)    |
| योग                                      | २०१.६७ (१००.००)      | १४३०.२० (१००.००)                         | २८६८.८५ (१००.००)     | ५१६४.४६ (१००.००) |

अ - पी. एल. ४८०, पी. एल. ६६५ और थर्ड कट्टी वॉरेंटी बॉसिलेट्स

नोट - वैश्वक की सख्या प्रत्येक योजना की अवधि में कुल सहायता का प्रतिशत है। गवर्नर आफ इंडिया द्वारा जारी किया, १९६७-६८।





पुस्तक की मुख्य स्थापनाएँ हैं— “ राजनीति की स्वतंत्र  
 मता, भारतीय समाज में परिवर्तन लाने में गांधी की  
 सक्रिय भूमिका, भारतीय राजनीति की अपनी अनम  
 गैनी— जो पश्चिमी ढांचे के बाहिर के समुच्चयीकरण  
 और आर्थिक शक्तियों की सावधोमता के मानववादी  
 ढांचे, दावा से निम्न है—, इसके साम्यात्मिक विवेचन  
 की, जिसमें एक दल की प्रधानता की मुख्य स्थापना है,  
 देश में आनेवाले संकटों की चुनौती से राजनीति और  
 गांधी की कार्यप्रणाली में होनेवाले बड़े परिवर्तन,  
 नाकत्तात्मिक पद्धति और राज्य की मुख्य नीति, की  
 संकटता के बारे में आभावादी दृष्टिकोण ।  
 पश्चिमी देशों में विकसित आधुनिकतम राजनीतिक  
 धारणाओं तथा सिद्धान्तों का परीक्षण भारत के माध्यम  
 से किया गया है । तथा भारत जैसे नवीन राष्ट्रों की  
 राजनीति का विवेचन करने में ये धारणाएँ तथा  
 सिद्धान्त निम्न तरह उपयोग हैं इनका विवेचन किया  
 गया है ।